मानव संसाधन विकास मंत्रालय

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

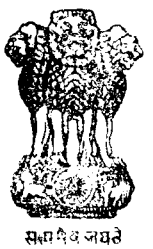

वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

1985-86

NUEPA DC
D13537

भाग–I

PART-I

शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF EDUCATION

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
1986

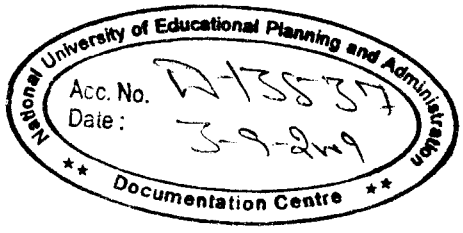
National University of Educational Planning and Administration
Acc. No. D-13537
Date : 3-9-2019
Documentation Centre

विषय सूची

	पृष्ठ सं०
प्रस्तावना	(i)
प्राक्कथन	(v)
अध्याय	
1. संगठन	1
2. स्कूल शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा	3
3. उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान	24
4. तकनीकी शिक्षा	43
5. प्रौढ़ शिक्षा	56
6. संघीय क्षेत्रों में शिक्षा	60
7. छात्रवृत्तियां	68
8 पुस्तक संवर्धन और कापीराइट	72
9 भाषाओं की प्रौन्नति	77
10. यूनेस्को से सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग	96
11. अन्य कार्यकलाप	102
विभिन्न अध्यायों में वर्णित मदों का वित्तीय आवंटन वर्ष 1984-85 के दौरान एक लाख रुपए से अधिक आवर्ती सहायता अनुदान पाने वाले निजी और स्वैच्छिक संगठनों के नाम दर्शाने वाला विवरण।	
प्रशासनिक चार्ट	131

प्रस्तावना

देश के लोग ही देश का मूल्यवान संसाधन, वस्तुत: सबसे अधिक मूल्यवान संसाधन होते हैं, और हमारे विकास की प्रक्रिया नागरिक के समेकित विकास पर आधारित होनी चाहिए और शैशव से शुरू होकर जीवन पर्यन्त चलती रहनी चाहिए, इस तथ्य के प्रति निरन्तर जागरूकता बढ़ रही है। इस बात को भी अब अधिक स्वीकारा जाने लगा है कि उन सभी संबंधित साधनों और अभिकरणों को जो इस विकास कार्य में योगदान दे रहे हैं अथवा ऐसा विकास जिनकी जिम्मेदारी है, उनको इकट्ठा कर दिया जाना चाहिए। अत: यह जरूरी है कि एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला तथा शिल्प, मानविकी और मानव मूल्यों के विकास को एक सूत्र में पिरो दिया जाए । इस सिद्धांत के अनुसार, एक नया मंत्रालय बनाया गया,, और इसका नाम तदनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया । इस मंत्रालय का गठन 26 सितम्बर, 1985 को भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली 1961 में, 174वें संशोधन द्वारा किया गया । मानव संसाधन विकास का नया मंत्रालय जो इस संशोधन के परिणामस्वरूप बना है, उसमें पांच विभाग हैं—अर्थात् शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, कला विभाग, युवा कार्य एवं खेल विभाग तथा महिला कल्याण विभाग। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संकल्पनात्मक ढांचे में मानव के सर्वतोमुखी विकास को ही लक्ष्य के रूप में रखा गया है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन सभी गतिविधियों को एक ही जगह पर लाने का प्रयत्न किया गया है जो इस कार्य के लिए जरूरी है । इसके पीछे उद्देश्य यही है कि उन सभी निवेशों को तैयार किया जा सके जो अपेक्षित है। यह प्रक्रिया मात्र समन्वय की प्रक्रिया नहीं है,, बल्कि वस्तुत: एकजान करने की प्रक्रिया है ताकि सभी घटकों को एक ही सतत् और सामंजस्यपूर्ण कार्यक्रम में पिरोया जा सके। यह प्रक्रिया अभी-अभी शुरू की गई है और आरंभिक कदम उठाए गए हैं। पांच भागों में प्रस्तुत मंत्रालय की रिपोर्ट में उपरोक्त पांच विभागों में से प्रत्येक विभाग की आवंटित गतिविधियों और मदों का एक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

इस वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा किया गया एक विशेष काम है, शिक्षा, संस्कृति, कला, खेल, युवा-कल्याण, महिला और बच्चों से संबंधित कार्यकलापों को एक ऐसी नई दिशा प्रदान करना जिससे इनके विकास के प्रति एक समेकित दृष्टिकोण विकसित हो सके और मंत्रालय को मानव संसाधन विकास में अधिक सहायता और बल मिल सके ।

एक नई शिक्षा नीति तैयार करने की प्रक्रिया पिछले वर्ष शुरू हुई थी। इस वर्ष के दौरान इस प्रक्रिया में और गति आई। आशा है कि इस नीति का प्रारूप बजट अधिवेशन 1986 के अंत से पहले ही संसद में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

बुनियादी स्तरों पर संस्कृति का प्रसार, संस्कृति विभाग के कार्यकलापों का मुख्य लक्ष्य है। अत: संस्कृति विभाग द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों में सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के संबंध में कार्यवाही की गई । इन क्षेत्रीय केन्द्रों में तीन,, उत्तरी क्षेत्र के लिए पटियाला में, पूर्वी क्षेत्र के लिए शांति निकेतन में, और दक्षिणी क्षेत्र के लिए तंजावूर में है। इनका उद्घाटन प्रधान मंत्री महोदय द्वारा क्रमश: 6 नवम्बर, 1985, 5 दिसम्बर, 1985 और 31 जनवरी, 1986 को किया गया। उन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य उन सांस्कृतिक बन्धनों और संबंधों को उजागर करना जो क्षेत्र या भाषा की सीमा में नहीं बंधे हैं।

अपनी संस्कृति के प्रति अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में सूझ-बूझ और परस्पर क्रिया विकसित करने की नीति के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान दो भारतोत्सव आयोजित किए गए, एक

अमरीका में और दूसरा फ्रांस में। कला क्षेत्रों तथा सामान्य नागरिकों में उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा की गई।

संस्कृति विभाग का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो इस वर्ष किया था, वह था, दक्षिण एशियाई पुरातत्वीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो 13 से 20 जनवरी, 1986 तक "साक" के तत्वावधान में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में मालद्वीप को छोड़कर सभी "साक" देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

इसी वर्ष के दौरान सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन का काम सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संस्कृति विभाग को हस्तांतरित किया गया।

कला बिभाग मुख्य रूप से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र के विविध कार्यक्रमों को आरंभ करने के लिए स्थापित किया गया है। कला संबंधी ये कार्यक्रम अनुसंधान,, प्रशासन, प्रशिक्षण, सृजनात्मक कार्यकलापों और प्रक्षेपण से संबंधित हैं तथा सभी कलाएं इनके कार्य क्षेत्र में आती हैं, विशेष रूप से इन कलाओं की पारस्परिक अंतर-निर्भरता के लिहाज से, जो स्वाभाविक मानव पर्यावरण में जो फिर समाज और क्षेत्र के सभी स्तरों पर जीवन शैलियों का एक अभिन्न अंग भी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र कलाओं के लिए एक अग्रणी संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करेगा, तथा यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यकलापों का एक महत्वपूर्ण घटक है। अपनी गतिविधियों के माध्यम से संस्कृति और कला के क्षेत्रों में भारतीय परंपराओं के समेकित बोध की उत्प्रेरणा का कार्य इस केन्द्र द्वारा किया जाएगा तथा इसके साथ-साथ हमारी बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता तथा संवेदनशीलता के साथ-साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर की एक परिकृत रूप-रेखा और सूझ-बूझ को विकसित किया जाएगा । इस प्रकार इसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय परंपराओं की गहराई और विविधता के प्रति व्यापक बोध को पुनः विकसित करना । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कलाकेन्द्र का एक मूल कार्यक्रम है-राष्ट्रीय डैटा बैंक, इस बैंक में कलाओं, मानविकी तथा सांस्कृतिक विरासत के भंडारण और पुनः प्राप्ति की पद्धतियों के लिए एक संगणकीकृत व्यवस्था होगी, और यह बैंक विद्वानों, शोध छात्रों, कलाकारों, स्कूल और कालेज के छात्रों तथा जन साधारण के लिए खुला रहेगा।

महिलाओं और बच्चों का सर्वांगीण विकास देश के मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। यही कारण है कि इन दोनों लक्षित वर्गों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सामान्य विकास कार्यक्रमों में उनका जो हिस्सा बनता है उससे आगे बढ़कर भी यह ध्यान देना अपेक्षित है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित विद्यमान कार्यक्रमों में नई जान डालने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की मशीनरी को गति प्रदान की गई है तथा नवनिर्मित मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक अलग महिला कल्याण विभाग बनाया गया है। इस क्षेत्र में सरकारी और गैरसरकारी प्रयासों को समन्वित करने और उनकी समीक्षा करने के साथ-साथ उनमें मार्गदर्शन के लिए यह विभाग केन्द्रीय अभिकरण होगा।

इस विभाग के कार्यक्रमों में मुख्य जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि महिलाओं और बच्चों के कल्याण को सुनिश्चित किया जाए विशेषरूप से उनका जो समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित हैं। इस काम के लिए सेवाओं को भी समेकित करना होगा। समेकित बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास के लिए एक बुनियादी बात है। इनका उद्देश्य है कि शैशव काल में स्कूल पूर्व अवस्था में गैर-औपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की सेवाएं प्रदान की जाएं ताकि शैक्षिक बरबादी और गतिरोध में कमी आए, बीच में ही पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या कम हो, शिशुओं की अकाल मृत्यु को कम किया जाए तथा उनकी विकलांगता और कुपोषण को रोका जा सके । इसी प्रकार महिलाओं के लिए समाजार्थिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम, प्रौढ़ महिलाओं के लिए शिक्षा के गहन कार्यक्रम इत्यादि हैं। इन सब में इस बात का प्रयास किया जा रहा

है कि न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया जाए बल्कि उनकी जीवन कोटि को भी बेहतर बनाया जाए।

युवा कार्य तथा खेल विभाग के प्रमुख कार्यकलापों में शामिल हैं, 7वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय खेल नीति का कार्यान्वयन । इस उद्देश्य से नई-नई योजनाएं बनाई गयीं हैं और खेल प्रोन्नति की विद्यमान योजनाओं को और आगे बढ़ाया गया है। इन नए कामों को शुरू करने के लिए खेल-कूद के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय कई बार बढ़ाया गया है। यह बढ़ोत्तरी इस संबंध में छठी पंचवर्षीय योजना के परिव्यय की तुलना में आंकी जा सकती है। आशा की जाती है कि कार्यकलाप इस प्रकार बढ़ाने के परिणामस्वरूप खेल-कूद में भाग लेने वालों की संख्या और बढ़ेगी, खेल के स्तरों में सुधार आएगा और इस प्रकार सामान्य रूप से राष्ट्र के स्वास्थ्य और बल को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। युवा कार्यक्रमों में युवकों के व्यक्तित्व और दक्षताओं के विकास पर बल दिया गया है और 7वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में नए-नए उपाय किए गए हैं । युवा वर्ष शानदार तरीके से मनाया गया । इस प्रयास के अंतर्गत एक राष्ट्रीय युवा दिवस तथा सप्ताह निश्चित करना और राष्ट्रीय युवा एम्बलम की घोषणा विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

शिक्षा विभाग की गतिविधियों और सफलताओं का विवरण आगामी पृष्ठों में दिया गया है।

प्राक्कथन

शिक्षा विभाग

नई शिक्षा नीति तैयार करना

अगस्त, 1985 में मंत्रालय द्वारा "शिक्षा की चुनौती-नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य" नामक एक स्थिति दस्तावेज प्रकाशित किया गया था जिसकी प्रतियां संसद में रखी गई तथा सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित की गई। यह 29-30 अगस्त, 1985 को हुए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श का आधार भी बना। इस दस्तावेज का अनुवाद, राज्य सरकारों द्वारा लगभग सभी प्रादेशिक भाषाओं में किया गया और इसे व्यापक रूप से परिचालित किया गया है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा प्राप्त अनुरोधों पर तथा विभिन्न संगठनों को भी, इस दस्तावेज की अंग्रेजी में 5,80,000 हिन्दी में 2,40,000 तथा उर्दू में 4,000 प्रतियां वितरित की गई हैं। इस दस्तावेज का उद्देश्य, शिक्षा नीति तथा विकल्पों से संबंधित विषयों पर व्यापक और गहन राष्ट्रीय परिचर्चा को प्रोत्साहित करना था। नई शिक्षा नीति पर राष्ट्र-व्यापी परिचर्चा के एक भाग के रूप में, भारत सरकार तथा इसकी एजेंसियों द्वारा 12 राष्ट्रीय सेमिनार तथा 17 प्रायोजित सेमिनार आयोजित किए गए। नई शिक्षा नीति पर परिचर्चा के आयोजन में सभी राज्य सरकारों ने गहरी रुचि ली है। राज्य स्तर के सेमिनारों के अतिरिक्त, विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में तथा ब्लाक स्तर पर भी अनेक सेमिनार-विचार गोष्ठियां तथा परिचर्चाएं हुई हैं। नई शिक्षा नीति तैयार करने पर हुई परिचर्चाओं से, अखिल भारतीय स्तर के अनेक शिक्षक संगठनों तथा छात्र संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्बद्ध रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) तथा महाराष्ट्र सरकार के संयुक्त तत्वावधान में, 13-14 दिसम्बर, 1985 को नागपुर में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों तथा स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद सदस्यों का एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया तथा 3-4 फरवरी, 1986 को पूणे में जिला परिषदों के अध्यक्षों और पंचायत समितियों के अध्यक्षों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

नई शिक्षा नीति तैयार करने से संबंधित प्रधान मंत्री की घोषणा की प्रतिक्रिया स्वरूप संगठनों तथा व्यक्तियों से अनेक सुझाव इस मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय में प्राप्त सभी पत्र-व्यवहारों को, जिनकी संख्या 6000 से भी अधिक है और जिनमें पत्र, ज्ञापन, सेमिनारों की सिफारिशें राज्य सरकारों की सिफारिशें भी शामिल हैं, ध्यानपूर्वक संक्षिप्त और वर्गीकृत कर लिया गया है। राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान द्वारा सभी सुझावों का विस्तृत विषय विश्लेषण तैयार किया गया है जिसने राज्य सरकारों, व्यक्तियों तथा संगठनों से प्राप्त शिक्षा पर अवबोधन पर 13 खण्ड प्रकाशित किए हैं।

राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसरण में, नई शिक्षा नीति तैयार करने से संबंधित विभिन्न विषयों की गहराई से जांच करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए नीतियां तैयार करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में, (1) जन-शक्ति प्रक्षेपण और व्यावसायीकरण; (2) वित्तीय संसाधन तथा (3) परीक्षा सुधार पर शिक्षा मंत्रियों के राष्ट्रीय दल बनाए गए हैं।

नई शिक्षा नीति पर परिचर्चा में सभी वर्गों के लोग शामिल हुए हैं और बहुत से उपयोगी विचार तथा दृष्टिकोण उभर कर आए हैं। 23-24 जनवरी, 1986 को हुए राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के विचारार्थ, विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों पर आधारित नई शिक्षा नीति से संबंधित विषय तैयार किए गए

2—759 Deptt. of Edu./85

वर्गों से प्राप्त सुझावों पर आधारित नई शिक्षा नीति से संबंधित विषय तैयार किए गए नई शिक्षा नीति का एक प्रारूप शीघ्र ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रारंभिक शिक्षा

सभी बच्चों के लिए, 14 वर्ष की आयु होने तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना एक संवैधानिक लक्ष्य है। सातवीं पंचवर्षीय योजना की नीति प्रारूप के अनुसार, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का संवैधानिक लक्ष्य प्राप्त करने का वर्ष 1989-90 है। प्रारंभिक शिक्षा योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक अंग भी बनी हुई है।

सर्वसुलभीकरण के कार्यक्रम को इस वर्ष के दौरान, केन्द्रीय तथा राज्य/संघीय क्षेत्र, दोनों स्तरों पर बड़े जोर-शोर से जारी रखा गया। इस संबंध में उठाए गए कुछ के महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं :

— प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में प्रगति की समीक्षा करने के लिए फरवरी, 1985 में शिक्षा सचिवों के सम्मेलन के एक भाग के रूप में 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 पर राष्ट्रीय समिति की बैठक।

— प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण तथा गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयत्नों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में प्रारंभिक शिक्षा पर राज्य कार्य दलों की बैठकें ।

— प्रारंभिक स्तर पर नामांकन बढ़ाने और छात्रों को बनाए रखने के लिए प्रयासों को तेज करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण पर एक राष्ट्रीय अभियान का आयोजना करना। इस वर्ष के अभियान में, स्कूल छोड़ जाने वालों की दर को कम करने पर विशेष बल दिया गया।

वर्ष 1985-86 के दौरान कक्षा पहली से आठवीं में अतिरिक्त नामांकन का लक्ष्य 52·71 लाख है। प्रारंभिक स्तर पर स्कूल छोड़ जाने वालों की ऊंची दरों में कमी लाने के लिए, विभिन्न राज्यों में, एकल शिक्षक स्कूलों को दो शिक्षक स्कूलों में बदलना, प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की भौतिक सुविधाओं में सुधार लाना, अनु. जा. तथा अनु. ज. जा. जैसे असुविधाग्रस्त वर्गों तथा लड़कियों की ओर विशेष ध्यान, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा लेखन सामग्री, निःशुल्क वर्दीयों जैसे प्रोत्साहनों की पर्याप्त व्यवस्था, विशेषकर लड़कियों के लिए, उपस्थिति छात्रवृत्तियां और मध्याह्न भोजन इत्यादि जैसे व्यापक उपाय किए गए।

गैर-औपचारिक शिक्षा

गैर-औपचारिक शिक्षा, शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई नीति का दूसरा मुख्य घटक है, क्योंकि बच्चों की एक बड़ी संख्या या तो स्कूल जा नहीं सकती या स्कूल जाना नहीं चाहती। सातवीं योजना के अन्तर्गत, गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले बच्चों की संख्या 2·5 करोड़ होने का अनुमान है। इस कार्यक्रम ने, शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में काफी जोर पकड़ लिया है और वर्ष 1985-86 के अन्त तक इस कार्यक्रम में लाए जाने वालों की संख्या, लगभग 1·65 लाख केन्द्रों में 41·41 लाख तक हो जाएगी।

उच्चतर माध्यमिक स्तर की समाप्ति तक लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा

निःशुल्क शिक्षा प्रदान करके लड़कियों के बीच शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए, एक ऐसी योजना तैयार की गई है जिसके अंतर्गत भारत सरकार, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों को, माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर पर लड़कियों से शिक्षा शुल्क के रूप में ली जाने वाली आय को छोड़ने की प्रति पूर्ति करेगी। यह योजना, पूरी सातवीं योजना अवधि तक लागू रहेगी।

सातवीं योजना अवधि के दौरान राज्यों/संघीय क्षेत्रों को, शिक्षक प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करने में, और विद्यमान शिक्षकों के पुर्नस्थापन के लिए एक विशाल कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए भी सहायता हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान करने पर ध्यान दिया जा रहा है। विज्ञान शिक्षण में सुधार लाने की एक योजना भी तैयार की जा रही है।

शारीरिक शिक्षा

अब विश्व भर में शारीरिक शिक्षा और खेलों को, शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। नई राष्ट्रीय खेल नीति में, जिसे एक सरकारी संकल्प के रूप में संसद के सम्मुख रखा गया है, अन्य बातों के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा और योग भी शामिल हैं। इसके अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का यह कर्तव्य बन जाता है कि वे बहुमुखी विकास की प्रक्रिया में खेलों तथा शारीरिक शिक्षा की प्रोन्नति को उच्चतम प्राथमिकता दें। इस नीति के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक की, उसकी आयु और लिंग चाहे कुछ भी हो, खेलों और मनोरंजनात्मक कार्यकलापों में भाग लेने की जरूरत को स्वीकार किया गया है। इसलिए, इस नीति द्वारा केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे बड़े पैमाने पर आवश्यक सुविधाएं तथा अवस्थापना प्रदान करके पम्परागत तथा आधुनिक खेलों तथा योग को प्रोत्साहन दें तथा उनका विकास करें। नई नीति में दिए गए निदेशों के अनुसरण में, सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, शारीरिक शिक्षा तथा योग पर काफी अधिक निवेश की परिकल्पना की गई है। शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाने तथा ज. सहभागिता को प्रोत्साहित करने पर विशेष बल देने का भी प्रस्ताव है।

उच्च शिक्षा

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में छात्रों का नामांकन जो वर्ष 1983-84 में 33.59 लाख था, वर्ष 1984-85 में बढ़कर 35.39 लाख हो गया। महिला छात्रों का नामांकन, जो 1983-84 में 9.77 लाख था, 1984-85 में बढ़कर 10.21 लाख हो गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, शिक्षा के स्तरों तथा कोटि के सुधार करने तथा उच्च शिक्षा में विषमताओं और क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने की नीति जारी रखी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कोटि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत विज्ञान शिक्षा, तथा गांधी और नेहरू अध्ययनों की प्रोन्नति पर विशेष ध्यान दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, नाभिकीय विज्ञान, सामग्री अनुसंधान, लेसर और फाइबर आप्टिक्स, खगोल-भौतिकी, खगोल-विज्ञान, जीव-प्रौद्योगिकी तथा जन-संचार और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्वविद्यालय विज्ञानियों के उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुविधाओं के विकास के लिए कदम उठाए हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के बीच उच्च शिक्षा संबंधी विशेष-कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता के जरिए जोर दिया जाना जारी रहा। शिक्षणात्मक तथा अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके ज्ञान के प्रसार तथा प्रोन्नति के लिए सितम्बर, 1985 में दिल्ली में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। यह, ज्ञान तथा दक्षताओं में सुधार लाने और सामान्य रूप से समाज तथा विशेषकर असुविधाग्रस्त वर्गों के शैक्षिक अवसरों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सतत तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल देगा। संघीय क्षेत्र पांडिचेरी की जरूरतों को पूरा करने के लिए, 16 अक्तूबर, 1985 को पांडिचेरी विश्व-विद्यालय नामक एक अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है।

तकनीकी शिक्षा

किसी भी देश की सामाजिक-आर्थिक प्रगति, उचित रूप से प्रशिक्षित तकनीकी जन-शक्ति के उपलब्धता के साथ गहरे रूप से जुड़ी हुई है। अतः हमारे देश ने, स्वतंत्रता प्राप्ति से ही देश में तकनीकी शिक्षा के लिए व्यापक सुविधाओं के विकास को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की है। 1947 में, इंजीनियरी डिग्री पाठ्यक्रमों में केवल 2940 छात्र तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में केवल 3670 छात्र दाखिल करने की सुविधाएं थीं। उत्तरोत्तर योजना अवधियों के दौरान, लगातार प्रयत्नों से हमारे देश ने अब तकनीकी शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यापक सुविधाएं विकसित कर ली हैं तथा यह प्रणाली अब प्रत्येक वर्ष डिग्री पाठ्यक्रमों में लगभग 30,000 छात्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में लगभग 60,000 छात्र दाखिल करने की स्थिति में है तथा इसमें परम्परागत और नए उभरते क्षेत्र दोनों ही शामिल हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय हमारे देश में इंजीनियरी तथा

प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान न होने के बराबर था, परन्तु इस समय हमारी तकनीकी संस्थाएं, प्रत्येक वर्ष लगभग 7,000 छात्रों को सुव्यवस्थित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करने की स्थिति में हैं। सातवीं योजना अवधि के दौरान, विद्यमान सुविधाओं को समेकित करने तथा उनके अधिकतम उपयोग से संबंधित कार्यकलाप जारी रहे। चालू योजना के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ, इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निकों में अप्रयुक्त को दूर करने तथा आधुनिकीकरण लाने, ग्रामीण विकास में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के प्रयोग, तकनीकी शिक्षा प्रणाली तथा विकास क्षेत्रों के बीच संबंध स्थापित करने और तकनीकी संस्थाओं में आकलन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सातवीं योजना अवधि की योजनाओं के कार्यान्वयन से, यह आशा की जाती है कि तकनीकी शिक्षा सुविधाओं के बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कमियों को काफी हद तक दूर कर दिया जाएगा।

प्रौढ़ शिक्षा

सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह कहा गया है कि प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों को इस उद्देश्य के साथ चलाया जाएगा कि वर्ष 1990 तक 15 से 35 वर्ष के आयु-वर्ग में सभी निरक्षरों को शामिल कर लिया जाए। यह सोचते हुए कि प्रौढ़ शिक्षा,, सामाजिक आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है और परिवार कल्याण कार्यक्रम का भी एक निर्णायक भाग है, सरकार ने इसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल करके प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की है। सतत शिक्षा के एक कार्यक्रम के विकास, प्रोत्साहन, जन-कार्यक्रम आरंभ करने, ग्रामीण विकास तथा परिवार कल्याण के विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों के साथ कारगर रूप से जोड़ना, स्वैच्छिक एजेंसियों, नेहरू युवक केन्द्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा आई.एस.डी.एस. का और अधिक शामिल होना जैसे मुख्य क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग में निरक्षरता मिटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, विद्यमान चल रही योजनाओं के साथ कार्यात्मक साक्षरता का एक जनव्यापी कार्यक्रम आरंभ करने का निर्णय किया है। सरकार, राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता दरों वाले जिलों को शामिल करने, समाज के विशेष लक्ष्य वर्गों जैसे कि महिलाओं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य कमजोर वर्गों को शामिल करने, साक्षरता कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय तथा कालेजों के छात्रों और युवाओं की अधिक सहभागिता; स्वैच्छिक एजेंसियों का उपयोग, ग्राम समाज जीवन तथा शिक्षा केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से उत्तर-साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना; लोक परंपरागत तथा आधुनिक जन-संचार माध्यमों का प्रयोग जैसे प्राचलों (पैरा-मीटर्स) से मार्गदर्शन प्राप्त करती रहेगी। 1985-86 में 75.46 लाख प्रौढ़ निरक्षकों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में सितम्बर, 1985 के अंत तक उपलब्धि 70.43 लाख है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को नियमित रूप से मानिटर किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्य की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें सरकार को भेजी जा रही हैं। विदेशों के भी कई दौरे किए गए हैं ताकि प्रौढ़ शिक्षा के उनके कार्यक्रमों का अध्ययन किया जा सके और इस कार्यक्रम को समृद्ध करने के लिए उनकी नीतियां अपनाई जा सकें। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र) तथा विभिन्न राज्यों में स्थित 17 राज्य संसाधन केन्द्रों ने, अपने-अपने कार्यकलापों के नेटवर्क से इस कार्यक्रम को तकनीकी तथा संसाधन सहायता प्रदान करना जारी रखा। नई शिक्षा नीति को तैयार करने में निवेश प्रदान करने के लिए निदेशालय तथा राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा एक राष्ट्रीय तथा कई अन्य सेमिनार आयोजित किए गए।

छात्रवृत्तियां

भारत सरकार छात्रों को देश और विदेशों में और आगे अध्ययन के लिए बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियां प्रदान करती है। ये छात्रवृत्तियां सामान्यतः उन योग्य छात्रों को दी जाती हैं जिनकी आय के साधन पर्याप्त नहीं हैं। राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत, 27,000 छात्रों को मैट्रिकोत्तर स्तर पर अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 33,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। इन 33,000 छात्रवृत्तियों में से 18,000 छात्रवृत्तियां भूमिहीन श्रमिक वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा

अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों को प्रदान की गई। निर्धन परन्तु योग्य छात्रों को पांच सौ छात्रवृत्तियां प्रदान की गई ताकि वे अनुमोदित आवासीय स्कूलों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

यह मंत्रालय, भारतीय छात्रों को विदेशों में अध्ययन के लिए भी छात्रवृत्तियां प्रदान करता है ताकि वे नए विशेषज्ञता वाले विषयों में अनुसंधान कर सकें। पारस्परिक आधार पर, विदेशी छात्रों को 180 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और इस प्रकार विकासशील देशों को अपनी जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के उनके प्रयत्नों में सहायता की जाती है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने राष्ट्रमण्डल देशों के राष्ट्रिकों को 75 छात्रवृत्तियां प्रदान की।

पुस्तक प्रौन्नति और कापीराइट

पुस्तक प्रौन्नति के क्षेत्र में इस मंत्रालय के कार्यक्रमों का उद्देश्य, उचित मूल्यों पर अच्छे साहित्य के निर्माण को सुकर बनाना, भारतीय लेखकों तथा प्रकाशन उद्योग को प्रोत्साहित करना, पुस्तक आयात नीति तैयार करना, भारतीय पुस्तकों के निर्यात को प्रोत्साहित करना और लोगों के बीच पुस्तकों के प्रति रुचि बढ़ाना है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अपना प्रकाशन कार्यक्रम जारी रखा और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों का आयोजन किया तथा इनमें भाग लिया। इस वर्ष के महत्वपूर्ण कार्य को अक्तूबर, 1985 में पटना में 12वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन, नवम्बर, 1985 में इलाहाबाद में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक मेला और फरवरी, 1986 में नई दिल्ली में सातवां विश्व पुस्तक मेला। इस वर्ष के दौरान घोषित उदार आयात नीति, तीन वर्ष की अवधि तक लागू रहेगी। कापीराइट अधिनियम के अंतर्गत जैसी की व्यवस्था है, लेखकों तथा संगीत रचनाओं के संगीतकारों की एक राष्ट्रीय सोसायटी स्थापित करने के प्रयत्न किए गए ताकि उनके हितों की रक्षा की जा सके। कापीराइट कार्यालय ने 1,908 साहित्यिक तथा कलात्मक कृतियां पंजीकृत की।

भाषाओं का प्रसार तथा विकास

भारत सरकार की नीति, सभी भारतीय भाषाओं, जिनमें, प्राचीन, आधुनिक तथा जन-जातीय भाषाएं भी शामिल हैं, के विकास को बढ़ावा देना है। आलोच्य वर्ष के दौरान आरंभ किए गए कार्यकलापों तथा कार्यक्रमों का उद्देश्य, त्रि-भाषा सूत्र के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बल देते हुए वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करना तथा शिक्षण के माध्यम के रूप में अंग्रेजी को क्षेत्रीय भाषाओं में बदलने को सुकर बनाने की दृष्टि से विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तकों का निर्माण है। अहिन्दी भाषी राज्यों को, हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षक कालेजों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए, मैट्रिक स्तर से आगे हिन्दी अध्ययन के लिए छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए सहायता जारी रही। हिन्दी के विकास तथा प्रसार के लिए कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को भी वित्तीय सहायता दी गई ताकि वे हिन्दी शिक्षण कक्षाएं आयोजित कर सकें। हिन्दी शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों के आयोजन, शिक्षण की प्रणालियों पर अनुसंधान संचालित करने तथा हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई। जन-जातीय प्राचीन तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के प्रसार तथा विकास के लिए विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों के माध्यम से इस मंत्रालय द्वारा पुस्तकों, शब्दकोष अनुसंधान तथा अनुदेशात्मक सामग्री तैयार/प्रकाशित करने, शिक्षकों के प्रशिक्षण इत्यादि के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। भारत के विभिन्न भागों में तीस सुलेखन केन्द्र चल रहे हैं।

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली द्वारा भाषा शब्दकोष/वार्तालाप गाइड तैयार की जा रही हैं। विदेशों में हिन्दी का प्रचार नामक योजना के अंतर्गत विदेशी छात्रों को हिन्दी के अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। हिन्दी शिक्षकों को विदेशों में प्रतिनियुक्त किया जाता है और हमारे दूतावासों/मिशनों के माध्यम से हिन्दी पुस्तकें वितरित की जाती हैं। सभी भारतीय भाषाओं के प्रसार तथा विकास के लिए विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान भी दिए जाते हैं।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

भारत ने यूनेस्को से संबंधित मामलों में अपनी अग्रणीय भूमिका निभाना जारी रखा और यूनेस्को के तत्वावधान में आयोजित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/बैठकों में भाग लिया। भारत सरकार ने बैंगकाक में आयोजित शिक्षा मंत्रियों तथा एशिया और प्रशान्त में आर्थिक आयोजना के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पांचवीं क्षेत्रीय सम्मेलन में और सोफिया (बुल्गारिया) में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 23वें अधिवेशन में उच्च अधिकार प्राप्त शिष्टमण्डल भेजे।

वार्षिक योजना और बीस सूत्री कार्यक्रम

आलोच्य वर्ष के दौरान, नए 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16, जो प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, की मानीटरिंग जारी रही।

शैक्षिक सांख्यिकी

भारत में शैक्षिक सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का अनुवर्ती कार्य आरंभ किया।

उत्तर प्रदेश में शैक्षिक सांख्यिकी के संगणीकरण पर एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की गई। इस परियोजना के मार्च, 1986 तक पूरा हो जाने की आशा है।

चालू वर्ष के दौरान 9 प्रकाशन/रिपोर्ट प्रकाशित की गईं।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की शिक्षा

सातवीं योजना 1985–90 तथा वार्षिक योजना 1985-86 के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजातीय उप-योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है। वार्षिक योजना 1986-87 के वास्ते विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप-योजना के प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। 1986-87 के लिए वार्षिक योजना के लिए विभाज्य परिव्यय में से इन दो घटक योजनाओं के लिए कुल विभाज्य परिव्यय का क्रमशः 21.66% तथा 12.69% निश्चित किया गया है।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री के पन्द्रह सूत्री निदेश के अनुसरण में, उन क्षेत्रों में जहां मुसलमान्त भारी संख्या में रहते हैं, सामुदायिक पालिटेक्निकों की योजनाएं, उच्च स्तरीय प्रतियोगिता-परीक्षाओं के लिए शिक्षण कक्षाओं की वि.अनु.आ. योजना, राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा, अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को कार्यान्वित किया जा रहा है।

नई शिक्षा नीति को तैयार करने के संदर्भ में "अल्पसंख्यक तथा शिक्षा" पर, दो दिनों का एक सेमिनार आयोजित किया गया।

निष्कर्ष

भारत सरकार का यह विचार है कि शिक्षा तभी सार्थक और सुसंगत बन सकती है जब शिक्षण प्रक्रिया को बदल कर उसे सक्रिय और प्रभावी रूप से प्रत्येक विकासात्मक कार्यकलाप के साथ जोड़ दिया जाए। अतः यह परमावश्यक हो जाता है कि सभी स्तरों पर शिक्षा की कार्यात्मक सुसंगता को बेहतर बनाया जाए और उत्पादक दक्षताओं तथा बेहतर प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाएं। यह प्रस्ताव है कि विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षा के व्यावसायीकरण पर बल दिया जाए और स्कूल सुधार का एक व्यापक, लम्बी अवधि वाला राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आरंभ किया जाए तथा काफी संख्या में उत्तम कोटि की संस्थाएं शुरू करके जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगी, इसको समर्थन तथा प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। यह भी आवश्यक समझा गया है कि जहां भी संभव हो डिग्रियों को नौकरियों से अलग किया जाए और एक ओर तो शिक्षा की प्रक्रियाओं और सामंजस्य पैदा करने के लिए एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति लाई जाए जिसकी जड़ें सुसंगता तथा अनुपूरकता स्थापित की जाए। यह भी आवश्यक होगा कि राष्ट्रीय एकता और सामंजस्य पैदा करने के लिए एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति लाई जाए जिसकी जड़ें मजबूती से धर्म-निरपेक्षता, लोकतंत्र तथा समाजवाद में गढ़ी हों। सरकार का यह प्रयास होगा कि युवा और प्रगतिशील प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे आने वाली चुनौतियों का सामना किया जाए और शिक्षा को नया रूप दिया जाए जिससे कि संविधान में निहित उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सुदृढ़ आधार उपलब्ध हो सके।

अध्याय I

संगठनात्मक ढांचा

शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक विभाग है, विभाग का कार्य राज्य मंत्री की देख-रेख में होता है और समग्र कार्यभार मानव संसाधन विकास मंत्री के पास है। मंत्रालय के सचिवालय का कार्य सचिव की देख-रेख में होता है जिनकी सहायता के लिए एक विशेष सचिव (उच्च शिक्षा), अतिरिक्त सचिव तथा शिक्षा सलाहकार (तकनीकी) हैं। विभाग में अनेक ब्यूरो, प्रभाग, डैस्क, अनुभाग तथा एकक हैं। प्रत्येक ब्यूरो का प्रभारी एक संयुक्त सचिव/संयुक्त शिक्षा सलाहकार है जिनकी सहायता के लिए प्रभागाध्यक्ष हैं। विभाग का संगठनात्मक स्वरूप रिपोर्ट के साथ संलग्न चार्ट में दर्शाया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय/ स्वायत्त संगठन

पिछले वर्षों के दौरान विभाग के अधीन बहुत से अधीनस्थ कार्यालय तथा संगठन अस्तित्व में आए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समन्वय तथा स्तर निर्धारण के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अलावा, विशिष्ट जिम्मेदारियां निभाने के लिए बहुत से संगठन स्थापित किए गए हैं। इनमें एक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद है, जो देश भर में स्कूल शिक्षा की कोटि सम्बन्धी पहलुओं को उन्नत बनाने की दिशा में प्रयत्नशील है। अन्य प्रमुख संगठन इस प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली।
(2) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला।
(3) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
(4) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
(5) भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली।
(6) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली।
(7) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली।
(8) केन्द्रीय हिन्दी संगठन, आगरा।
(9) केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर।
(10) केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद।
(11) केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली।
(12) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली।
(13) राष्ट्रीय संस्कृत संगठन, नई दिल्ली।
(14) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली।
(15) लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर।

तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में हैं : भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर; भारतीय खनन स्कूल, धनबाद; राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई; राष्ट्रीय ढलाई तथा गढ़ाई प्रौद्योगिकी संस्थान,, रांची,; आयोजना और वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली; भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद; अहमदाबाद, बंगलौर, कलकत्ता और लखनऊ में एक-एक भारतीय प्रबन्ध संस्थान; भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़ और मद्रास में एक-एक तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान; बम्बई, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास में एक-एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और देश भर में फैले पंद्रह इंजीनियरी कालेज हैं। हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) और जालन्धर (पंजाब) में दो और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज खोले जाने की संस्वीकृति दी जा चुकी है।

कार्य

शिक्षा विभाग के मुख्य कार्य हैं : सभी पहलुओं से शिक्षा नीति का विकास करना और उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के स्तरों को समन्वित तथा निर्धारित करना; कापीराइट अधिनियम लागू करना; पाठ्यपुस्तकों की कोटि में सुधार करना; छात्रवृत्तियां तथा अन्य योजनाओं को लागू करना; यूनेस्को के साथ सहायता के कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों को समन्वित करना; संस्कृत तथा अन्य श्रेष्ठ भाषाओं में अध्ययन तथा अनुसंधान को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना; गैर-औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यकलापों का विकास करना और प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करना।

अध्याय–2

स्कूल शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा

स्कूल शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से, इस कार्यक्रम को छठी योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। 1982 से प्रारंभिक शिक्षा को सरकार के नए 20 सूत्री कार्यक्रम में सूत्र 16 में शामिल कर लिया गया है। इस संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य तारीख 1990 अर्थात् सातवीं योजना अवधि के अंत तक है। 1981 के जनगणना अनुमानों के आधार पर 1989-90 तक 6–14 आयु वर्ग में कुल जनसंख्या 1510 लाख हो जाएगी। अधिक आयु तथा कम आयु वाले बच्चों के लिए 10% की गुंजाइश की व्यवस्था करते हुए, 1990 तक इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले बच्चों की संख्या लगभग 1660 लाख होगी। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 1984-85 तक कक्षा पहली से आठवीं में कुल नामांकन 1121·06 लाख तक हो जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, गैर-औपचारिक शिक्षा के माध्यम से 35–40 लाख बच्चों को शामिल किए जाने की आशा है।

प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय अभियान पहली बार 1982 के दौरान आरंभ किया गया था। पिछले वर्षों की भाँति चालू वर्ष में भी एक राष्ट्र व्यापी अभियान आरंभ किया गया था जिसमें समाज की सहभागिता की जरूरत पर प्रकाश डाला गया। विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों में शैक्षिक सत्रों की शुरूआत के साथ-साथ आरंभ होने वाले इस अभियान का लक्ष्य दाखिले के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करना, स्कूलों में उपस्थिति पर नजर रखना, शिक्षकों की रिक्तियों को भरना तथा गैर-औपचारिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना था। बीच में ही स्कूल छोड़ जाने वालों की दरों को कम करने पर विशेष बल दिया गया था। राज्य सरकारों से अब तक प्राप्त हुई पूर्वनिवेशन काफी उत्साहवर्धक है। राज्य सरकारों को, वर्ष 1985-86 के लिए निर्धारित अतिरिक्त नामांकन के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिए जाने की आशा है।

नीचे दिया विवरण नामांकन लक्ष्यों तथा उपलब्धियों को दर्शाता है:—

(कोष्ठकों के अन्दर दिए गए आंकड़े नामांकन अनुपात दर्शाते हैं)

	1979-80 (वास्तविक)	1980-81 (वा०)	1981-82 (वा०)	1982-83 (वा०)	1983-84 (वा०)	1984-85 (वा०)	1985-86 (वा०)
1	2	3	4	5	6	7	8
आयु वर्ग 6—नामांकन कक्षा I—V	710.02	727.16	753.25	775.93	805.97	853.76	906.81
आयु वर्ग तत संख्या की प्रतिशतता की रूप में नामांकन	(83.72)	(85.23)	(87.76)	(89.87)	(93.3)	(91.84)	(101.70)
आयु वर्ग 11-14	194.01	204.31	218.13	235.81	254.78	267.30	285.17
नामांकन: कक्षा VI—VIII							
आयु वर्ग तत संख्या की प्रतिशतता के रूप में नामांकन	(40.16)	(41.72)	(43.96)	(40.90)	(50.7)	(53.07)	(55.2)
आयु वर्ग 6-14	904.03	931.47	971.38	1011.74	1060.75	1121.06	1191.98
नामांकन कक्षा I—VIII	(67.91)	(69.36)	(71.71)	(74.05)	(78.01)	(78.21)	(84.64)

3—759 Deptt. of Edu./85

शिक्षण की कोटि में सुधार लाने की दृष्टि से 1985-86 में शैक्षिक प्रशासकों, शैक्षिक संस्थाओं के अध्यक्षों तथा शिक्षकों के पुर्नस्थापन का एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ करने का प्रस्ताव है और चुनी हुई प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को निधियां प्रदान करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें स्टाफ, उपस्कर और पुस्तकालय सुविधाओं में सुदृढ़ किया जा सके।

नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा

अनुच्छेद 45 में दिए गए संवैधानिक निर्देशों के अनुसरण में अधिकांश राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के सभी स्कूलों में चाहे वे सरकारी, स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे हों अथवा सहायता प्राप्त हों, प्राथमिक स्तर पर (कक्षा 1 से 5 तक) तथा मिडिल स्तर पर (कक्षा 6 से 8 तक) शिक्षा नि:शुल्क है सिवाए उत्तर प्रदेश में जहां सातवीं और आठवीं कक्षा के लड़कों के लिए शिक्षा नि:शुल्क नहीं है। कुछ राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों ने ऐसे कानून बनाए हैं जिनके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा नि:शुल्क तथा अनिवार्य हो गई है। तथापि, विद्यमान सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में ऐसे कानूनों की दण्ड विषयक धाराएं अप्रवर्तनीय ही रही हैं।

यू. के. की वित्तीय सहायता से प्राथमिक स्कूल परियोजना

यू. के. सरकार, आन्ध्र प्रदेश में प्राथमिक स्कूल भवनों के निर्माण के लिए दस लाख पौंड की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है। पहले चरण के पूरा होने की शर्त पर इस परियोजना के बाद के चरण अथवा चरणों के लिए एक करोड़ 40 लाख पौंड के अतिरिक्त विनियोजन को भी सिद्धांत रूप में मान लिया गया है।

स्कूल संभरण (फीडिंग) कार्यक्रम के प्रभाव पर अध्ययन

0-5 आयु वर्ग के बच्चों के बीच तुलनात्मक, स्कूल में बने रहने तथा उपलब्धि स्तर पर, स्कूल संभरण (फीडिंग) कार्यक्रम के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए जुलाई, 1985 में एक अध्ययन, रा.शै.अनु.प्र.परि. की निगरानी में एशियाई संगठन अनुसंधान तथा विकास केन्द्र द्वारा संचालित किया जा रहा है।

प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए गैर-औपचारिक अंशकालिक शिक्षा

उन बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो स्कूल नहीं जा सकते, अथवा जिन्होंने औपचारिक स्कूली शिक्षा की एक विशाल विकल्प सहायक पद्धति के रूप में विकसित हुए बिना स्कूल छोड़ दिया है, यह कार्यक्रम विद्यमान है । इस पर शैक्षिक रूप से पिछड़े उन नौ राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, उडीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से जोर दिया जा रहा है और अधिकतम बच्चों को शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिन्हें गैर-औपचारिक शिक्षा की एक केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रारंभिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता भी प्रदान की जाती थी। इस योजना का मूल उद्देश्य, दाखिल न हुए तथा स्कूल न जाने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए आवश्यक संस्थागत अवस्थापना प्रदान करना तथा केन्द्र और राज्यों, दोनों की पहल के अन्तर्गत गैर-औपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम के लिए शैक्षिक निवेशों को सुदृढ़ बनाना है। इस योजना का व्यय, केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबरी के आधार पर वहन किया जा रहा है। इस वर्ष के दौरान इन राज्यों को 11, 15, 39, 142/- रुपये का कुल अनुदान संस्वीकृत किया गया है।

शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में राज्य सरकार की पद्धति पर गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने वाले स्वैच्छिक संगठनों तथा किसी भी राज्य/संघीय क्षेत्र में गैर-औपचारिक शिक्षा की प्रयोगात्मक और अभिनव परियोजनाओं को शुरू करने वाली सरकारी अथवा प्राइवेट शैक्षिक संस्थाओं को राज्य सरकारों की सिफारिशों पर 100% के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है । चालू वर्ष के दौरान अब तक 55 स्वैच्छिक संगठनों तथा 1 शैक्षिक संस्था को 17.64 लाख रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम ने, विशेषकर शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में अच्छी गति पकड़ ली है । वर्ष 1985-86 के अंत तक शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में 1,65,648 केन्द्रों के माध्यम से जिनमें 20,500 केन्द्र केवल लड़कियों के लिए ही

है, लगभग 42 लाख व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय अनुदान से स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अनौपचारिक केन्द्रों की संख्या 2424 है, जिनमें अनुमानत: 60600 व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

केवल लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक केन्द्र

लड़कियों के नामांकन के बारे में असंतोषजनक स्थिति का वर्ष 1989-90 के अंत तक छात्राओं को शामिल किए जाने के लक्ष्यों की प्राप्ति पर प्रभाव पड़ा है तथा पड़ रहा है। लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के उद्देश्य से, गैर-औपचारिक शिक्षा की इस समय चल रही योजना को वर्ष 1983-84 से उदार बना दिया गया था जिसके अंतर्गत शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों को, केवल लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्र स्थापित करने हेतु 90:10 के अनुपात में केन्द्र-राज्य की साझेदारी के आधार पर वित्तीय सहायता दी जाती है। इस वर्ष के दौरान, ऐसे 20,500 विद्यमान केन्द्रों को जो केवल लड़कियों के लिए हैं, 2,67,75,483/- रु. का कुल अनुदान स्वीकृत किया गया ।

महिला शिक्षकों की नियुक्ति

शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में विशेष रूप से ग्रामीण/पिछड़े/पर्वतीय/जन-जातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूलों में महिला शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 80:20 के अनुपात में, केन्द्र-राज्य की साझेदारी के आधार पर सहायता की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना वर्ष 1983-84 में चालू की गई थी। सातवीं योजना के दौरान, इस योजना को जारी रखे जाने पर विचार किया जा रहा है।

शिशु शिक्षा

बीच में ही अध्ययन छोड़ जाने वाले बच्चों की दर को कम करने तथा बच्चों को स्कूल में ही रोके रखने में सुधार लाने के लिए एक विशिष्ट नीति के रूप में छठी योजना के अंतर्गत ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिशु (स्कूल-पूर्व) शिक्षा, विशेष रूप से प्रथम पीढ़ी के पढ़ने वालों के लिए शिक्षा का सुझाव दिया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में दाखिला कराने के लिए तैयार करने हेतु उनकी संप्रेषण (भाषा) तथा ज्ञानात्मक (सामाजिक, भावात्मक, बौद्धिक एवं वैयक्तित्व विकास) दक्षताओं में सुधार लाना है। इस योजना के अंतर्गत, शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों में स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और वर्ष 1985-86 के दौरान 34.47 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी।

शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने की यह योजना, शिक्षकों की प्रतिष्ठा बढ़ाने तथा प्राथमिक/मिडिल/उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के कार्यरत उत्कृष्ट शिक्षकों को उनकी प्रशंसनीय सेवाओं के लिए सार्वजनिक मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से 1958-59 में आरंभ की गई थी। इस योजना का क्षेत्र बाद में बढ़ा दिया गया था ताकि इसमें परपरागत रूप से चल रही संस्कृत पाठशालाओं, टोला आदि और मदरसों के अरबी/फारसी शिक्षकों को भी शामिल किया जा सके। प्रत्येक पुरस्कार में एक योग्यता प्रमाण-पत्र, एक रजत पदक तथा 1500/- रु. नकद भुगतान, जिसे 1985 से बढ़ाकर 2500/- रु. कर दिया गया है, शामिल है।

वर्ष 1985 में शिक्षकों के लिए 186 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 136 शिक्षकों, 74 प्राथमिक तथा 62 माध्यमिक, के नामों का निर्णय कर लिया गया और घोषित कर दिया गया है। ये शिक्षक, आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, दादरा तथा नागर हवेली, दिल्ली, चण्डीगढ़, गोवा, दमन तथा द्वीप, पांडिचेरी, मिजोरम तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के हैं। शेष राज्यों/संघीय क्षेत्रों से शिक्षकों के चयन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम

शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम का उद्देश्य, शिक्षा में गुणात्मक सुधार करना तथा सभी शैक्षिक प्रौद्योगिकी के समेकित उपयोग द्वारा, जिसमें आकाशवाणी तथा दूरदर्शन भी शामिल हैं, शिक्षा तक व्यापक पहुंच को सुनिश्चित करना है। इस योजना को,

राज्यों/संघीय क्षेत्रों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेलों तथा रा.शै.अनु.प्र.परि. में केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। छठी योजना के दौरान शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए, शैक्षिक प्रौद्योगिकी योजना के अंतर्गत राज्यों/संघीय क्षेत्रों को सहायता देने में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि स्वतःपूर्ण और सम्पूर्ण व्यवस्थित श्रव्य कार्यक्रम निर्माण सुविधाएं तथा संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जा सकें।

इनसेट के संदर्भ में, छः इनसेट राज्यों, अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जा रही है ताकि वे अपनी विशिष्ट जरूरतों के अनुरूप शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के निर्माण का दायित्व संभाल सकें। बिहार तथा उत्तर प्रदेश में शैक्षिक दूरदर्शन स्टूडियो भवन तैयार हो गए हैं और उन्हें राज्य प्राधिकारियों को सौंप दिया गया है। पूना तथा हैदराबाद में भी स्टूडियो भवन तैयार हो चुके हैं। भुवनेश्वर में राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के भवन के निर्माण का कार्य फरवरी, 1986 तक पूरा हो जाने की आशा है। गुजरात में राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के भवन का निर्माण राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है तथा फरवरी-मार्च, 1986 तक इसके पूरा होने की आशा है। केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान एक अलग भवन का निर्माण कार्य भी अन्तरिक्ष विभाग के माध्यम से आरंभ किया जाना है जिन्होंने निविदा संबंधी कार्य शुरू कर दिया है।

केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान तथा 6 राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए उपस्कर का आर्डर मेसर्स जी.सी.ई.एल., बड़ौदा तथा मैसर्स बी.ई.एल, बंगलौर को दे दिया गया है। ये दोनों फर्में सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान हैं। बी.ई.एल द्वारा उपस्कर अब तक नियत समय पर मिल रहे हैं और यह आशा की जाती है कि 3 राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए स्टूडियो उपस्कर मार्च, 1986 तक पूरे हो जाएंगे तथा शेष 3 के लिए, मार्च, 1987 तक। जी.सी.ई.एल. द्वारा उपस्कर की सप्लाई में देरी हो गई है और यह आशा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 1985-86 के अन्दर ही सभी उपस्कर सप्लाई पूरी हो जाएगी। बी.ई.एल. द्वारा स्टूडियो उपस्कर लगाए जाने तथा चालू किए जाने के साथ केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान का सातत्य स्टूडियो अब पूरी तरह से कार्यात्मक हो गया है।

इनसेट शैक्षिक दूरदर्शन सेवा के लिए कार्यक्रमों का निर्माण, दूरदर्शन तथा केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच 50:50 की हिस्सेदारी के आधार पर हो रहा है। यह कार्यक्रम 5 से 8 वर्ष आयु-वर्ग तथा 9 से 11 वर्ष आयु-वर्ग के बच्चों को सामान्य रूप से समृद्ध बनाने के लिए है। शैक्षिक दूरदर्शन सेवा सप्ताह में 5 दिन के लिए प्रातः 40 मिनट प्रतिदिन के लिए उपलब्ध है। प्रत्येक शनिवार इस समय का उपयोग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए किया जाता है। इस वर्ष के दौरान, केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा नवम्बर, 1985, तक 46 कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।

राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्टाफ की भर्ती प्रगति पर है। केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान में स्टाफ के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है, जिन्होंने 22 अप्रैल से 1 जून, 1985 तक, प्रशान्त प्रसारण विकास संस्थान, कुआलम्पुर के सहयोग से, शैक्षिक दूरदर्शन निर्माण में छः सप्ताह का एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 54 व्यक्तियों ने भाग लिया। अप्रैल, 1986 में इसी प्रकार का एक अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केन्द्र, अहमदाबाद में फरवरी, 1986 में, तीन माह की अवधि के लिए, शैक्षिक दूरदर्शन निर्माण के विशिष्ट क्षेत्रों में एक गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। इस पाठ्यक्रम में केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान में पहले से ही प्रशिक्षित राज्य प्रौद्योगिकी संस्थान के कर्मचारियों ने भाग लिया।

स्कूलों में संगणक शिक्षा

सभी राज्यों/संघीय क्षेत्रों के 250 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में इलेक्ट्रानिक विभाग के सहयोग से 1984-85 के दौरान स्कूलों (कक्षा) में संगणक साक्षरता तथा अध्ययन आरंभ करने के लिए प्रायोगिक परियोजना वर्ष 1985-86 में भी जारी रही और इसमें 500 और स्कूल तथा 8 संसाधन केन्द्र शामिल किए गए।

संसाधन केन्द्रों ने, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना तथा स्कूलों को सही और आवश्यक सहायता प्रदान करना जारी रखा। इस परियोजना के लिए आवश्यक निधियां इलेक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गईंजो हार्डवेयर सामग्री अब सेमि-कन्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटिड, चण्डीगढ़ द्वारा देशी रूप में तैयार की जाती है। संगणक प्रणाली को स्थापित करने तथा इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी कम्प्यूटर मेंटिनेंस कार्पोरेशन के पास ही है। इस परियोजना के शैक्षिक तथा प्रबन्ध का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा रा.शै.अनु.प्र.परि. के माध्यम से किया जा रहा है जिसे शैक्षिक निवेश और परीक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक केन्द्रीय एजेंसी के रूप में नामोद्दिष्ट किया गया है ।

इस प्रशिक्षण का पहला दौर जून-जुलाई, 1985 में 41 संसाधन केन्द्रों में आयोजित किया गया और लगभग 700 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया । शेष शिक्षकों के लिए यह प्रशिक्षण सितम्बर, अक्तूबर, 1985 में आयोजित किया गया । नये स्कूलों तथा संसाधन केन्द्रों के लिए संगणक प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं। सी.एम.सी. ने हिन्दी आर.ओ.एम. विकसित किए हैं जो सभी स्कूलों को मुहैया किए जा रहे हैं। सी.एम.सी. द्वारा अन्य भाषा आर.ओ.एम. भी विकसित किया जा रहे हैं, जो स्कूलों को उनकी आवश्यकतानुसार मुहैया किए जाएंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली, क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर, सी.एम.सी., तथा कुछ प्राइवेट एजेन्सियों द्वारा विकसित दस साफ्टवेयर पैकेज वर्ष 1985-86 में उपलब्ध कराए गए । ये, लाइसेन्स अनुबन्ध के अन्तर्गत 14 आयात पैकेजों के अलावा है। साफ्टवेयर पैकेजों के साथ की नियम पुस्तिका का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हो रहा है ताकि उन्हें स्कूलों को मुहैया किया जा सके। आगामी वर्षों में स्कूलों में प्रयोग के लिए, शैक्षिक परामर्शदाता भारत, लिमिटेड तथा राज्य सरकारों के माध्यम से भारी संख्या में देशी साफ्टवेयर पैकेजों के विकास के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

शिक्षा में मूल्योन्मुख अनुस्थापन

नैतिक मूल्यों में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर मूल्योन्मुख अनुस्थापन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने दो कार्यदल नियुक्त किए थे, पहला शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए, विशेषकर छात्रों में नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों को पैदा करने के लिए और दूसरा पूर्णतः पुनर्निर्मित आधार पर सामान्य शिक्षा के एक अंग के रूप में नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए माडल स्कूल स्थापित करने पर विचार करने के लिए। इन कार्यदलों की रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं।

शिक्षा को मूल्योन्मुख बनाने का सामान्य दृष्टिकोण निम्न प्रकार है :—

(क) नई शैक्षिक सामग्री तैयार करना;

(ख) शिक्षा को मूल्योन्मुख बनाने के लिए शिक्षकों को विशेष रूप से तैयार करना; तथा

(ग) इस प्रयास को व्यावहारिक रूप देने के लिए विशेष संस्थाओं की स्थापना करना।

वर्ष 1984-85 के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने रामकृष्ण नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान, मैसूर, श्री सत्य साईं बाल शिक्षा न्यास, बम्बई तथा बंगवाणी, नवद्वीप (पश्चिम बंगाल) को शिक्षक प्रशिक्षण के लिए इन संस्थाओं को चलाने तथा रख-रखाव के लिए अनुदान संस्वीकृत किए। मंत्रालय ने मूल्योन्मुख शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को सहायक-अनुदान देने की एक योजना भी तैयार की है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् नैतिक शिक्षा सम्बन्धी एक माडल योजना पर कार्य कर रही है। रा. शै. अनु. प्र. परि. द्वारा कक्षा— I—XII के लिए स्कूलों के लिए नैतिक शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यचर्या के विकास हेतु पहले से ही एक

गाइड तैयार कर ली गई है। इस प्रयोजन के लिए रा. शै. अनु. प्र. परि. ने एक अलग सैल स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ताकि वे देश में नैतिक शिक्षा लागू करने के लिए एक शैक्षिक खंड के रूप में कार्य कर सकें। इस सैल के स्थापित होने तक, भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद् ने मूल्योन्मुख शिक्षा के क्षेत्र में सेमिनार/कार्यशालाओं के आयोजन का कार्य सम्भाल लिया है ताकि संस्थाओं के लिए सामग्री तैयार की जा सके। रा. शै. अनु. प्र. परि. भी नैतिक शिक्षा पर पूरक पुस्तकें प्रकाशित कर रही है। चार्टों, फिल्मों आदि के रूप में अनुदेशात्मक सामग्री तैयार करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल, 1980 को शुरू किया गया राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहा। यह कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य औपचारिक शिक्षा पद्धति में जनसंख्या शिक्षा को समाविष्ट करना है ताकि युवा पीढ़ी में जनसंख्या सम्बन्धी समस्याओं के बारे में पर्याप्त जागरूकता पैदा की जा सके और वे इस सन्दर्भ में राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को समझ सकें, अब लगभग सभी राज्यों/संघीय क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वियन के लिए भारत सरकार ने, सर्वोपरि अधिकार के साथ एक राष्ट्रीय संचालन समिति गठित की है। अब तक इस समिति की आठ बैठकें हो चुकी हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर श्रव्य-दृश्य सामग्री जिसमें 264 स्लाइडें तथा हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में टेप की हुई टीका टिप्पणी भी शामिल है, तैयार की गई तथा राज्यों में वितरित की गई।

राष्ट्रीय स्तर पर, जनसंख्या शिक्षा पर पाठ्यचर्या विकास के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था, जिसके अध्ययन द्वारा स्कूलों तथा शिक्षक शिक्षा क्षेत्रों दोनों में स्कूल पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों में जनसंख्या सम्बन्धी सामग्री की स्थिति को पहचाना जा सकता है। रा. शै. अनु. प्र. परि. ने "स्कूल पाठ्यचर्या में जनसंख्या शिक्षा के लिए प्लग पाइन्टस" नामक एक दस्तावेज भी प्रकाशित किया था और इसे राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के सामने माडलों के रूप में रखा गया था, जिसके आधार पर राज्यों/संघीय क्षेत्रों ने पाठ्यचर्या विकास के कार्यकलापों को आरम्भ किया। विभिन्न स्कूल स्तरों पर, रा. शै. अनु. प्र. परि. की पाठ्यपुस्तकों में जनसंख्या शिक्षा के विषयों पर पाठ भी शामिल किए गए थे। चार राष्ट्रीय कार्यशालाओं में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी कुछ नमूना पाठ भी विकसित किए गए तथा उन्हें राज्यों के बीच परिचालित किया गया ताकि वे अपनी पाठ्यपुस्तकों के लिए ऐसे पाठों के विकास में इनका प्रयोग कर सकें। "शिक्षकों के लिए "जनसंख्या शिक्षा" नामक एक पुस्तक भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित की गई, जिसमें बी.एड./बी.टी. अर्थात् सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए जनसंख्या शिक्षा में प्रारूप पाठ्यचर्या शामिल है। प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के लिए एक पाठ्यचर्या भी विकसित की गई। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्तर पर बी.एड./एम.एड. के लिए मार्गदर्शी रूप-रेखाएं तथा पाठ्यचर्याएं भी विकसित की गई।

राज्य स्तर पर, 25 राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों ने प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक स्तरों के लिए जनसंख्या शिक्षा में व्यापक पाठ्यचर्या विकसित की है और उनमें से 21, अपने पहले से चल रही पाठ्यचर्या में जनसंख्या शिक्षा के तत्वों को समाकलित कर पाए हैं। 17 राज्यों ने या तो विद्यमान पाठों में संशोधन करके या नए पाठ तैयार करके जनसंख्या शिक्षा पर पाठ्यपुस्तक पाठ विकसित किए हैं। यू. एन. एफ. पी. ए. के सहयोग से "भारत, मेरे बच्चे, मेरा भविष्य" नामक एक अन्य श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम भी तैयार किया गया। उन कक्षाओं को ध्यान में रखते/हुए जिनमें शिक्षा पर पाठों वाली पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग हो रहा है, लगभग 770·1 लाख (77·01 मिलियन) को जनसंख्या विचारों से अवगत कराया जा रहा है, जो कि कुल छात्र जनसंख्या का 66·09% है। विभिन्न लक्ष्य वर्गों के लिए अनुदेशात्मक सामग्री की राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 38 पुस्तकें तथा राज्य स्तर पर 300 पुस्तकें मुद्रित की जा चुकी हैं और अनुलिपियां बनाई जा चुकी हैं

और प्रयोग में लाई जा रही है। राज्यों ने प्रारम्भिक तथा माध्यमिक योजनाओं के लगभग 5,63,261 मुख्य/संसाधन व्यक्तियों तथा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। गैर-औपचारिक शिक्षा में भी उन्होंने काफी सामग्री विकसित कर ली है।

स्कूली पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा

राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा का कार्यक्रम 1981 में शुरू किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाठ्यपुस्तकों से राष्ट्रीय एकता को बल मिले और राष्ट्रीय एकता को हानि न पहुंचने पाए। आरम्भ में, पाठ्यपुस्तकों की यह समीक्षा इतिहास और भाषा की पाठ्यपुस्तकों तक ही सीमित थी। यह समीक्षा, रा. शै. अनु. प्र. परि. द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शी-रूप-रेखाओं पर राज्यों द्वारा विकेन्द्रित आधार पर की जा रही है। यह समीक्षा इस उद्देश्य से की जा रही है कि ऐसी सामग्री और दृष्टिकोणों का पता लगाकर निकाला जा सके जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से छुआछूत, जातपात, साम्प्रदायिकता, धार्मिक असहिष्णुता, भाषावाद, क्षेत्रवाद तथा एंजातिवाद को कायम रखते हैं।

मणिपुर और पश्चिम बंगाल जहां कक्षा VI से आगे तक की कक्षाओं का मूल्यांकन कार्य प्रगति पर है, लगभग सभी राज्यों/संघीय क्षेत्रों में यह कार्यक्रम पूरा हो चुका है।

राज्यों/संघीय क्षेत्रों से अब यह अनुरोध किया गया है कि पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के कार्यक्रम का विस्तार अन्य विषयों तक भी किया जाए। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा विकास की पद्धति के एक भाग के रूप में पाठ्यपुस्तकों के निरन्तर मूल्यांकन के लिए एक अन्तर्निर्मित पद्धति अपनाए।

स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

पहली पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की यह योजना 31 मार्च, 1972 तक चालू रही। 1972 से स्वैच्छिक संगठनों को कोई नया अनुदान नहीं दिया जा रहा है। केवल पुरानी वचनबद्धताओं को ही निभाया जा रहा है।

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत, शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख कार्य कर रहे ऐसे संगठनों को भी विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नियुक्त विशेष पुनरीक्षण समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं।

नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की केन्द्रीय योजना।

भारत सरकार ने, सभी पाठ्यचर्या और पाठ्येत्तर कार्यकलापों के माध्यम से छात्रों के चरित्र निर्माण पर बहुत बल दिया है। सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के संगठनों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दिए जाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने नैतिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक योजना तैयार की है। इस योजना के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को अनावर्ती खर्च का अधिक से अधिक 50% तक वित्तीय सहायता दी जाती है बशर्ते कि यह प्रत्येक अनुमोदित परियोजना के लिए 2.5 लाख रुपये की सीमा तक हो। आवर्ती खर्च के लिए केन्द्रीय सरकार की यह सहायता कुल अनुमानित खर्च के 50% तक होगी बशर्ते कि प्रति वर्ष इसकी सीमा 5.00 लाख रुपये तक हो।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद्

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI (1860) के अन्तर्गत पंजीकृत राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना 1 सितम्बर, 1961 को की गई थी। परिषद् के मुख्य उद्देश्य हैं--स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में नीतियों तथा कार्यक्रमों को तैयार करने तथा कार्यान्वित करने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को परामर्श देना और उसकी सहायता करना। रा. शै. अनु. प्र. परि., पाठ्यचर्या, परीक्षा सुधार, प्रतिभा खोज, गैर-औपचारिक शिक्षा, पाठ्यपुस्तकों, व्यावसायीकरण, मूल्योन्मुख, विकलांगों की समेकित शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान, विकास प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्यक्रम आरम्भ करता है और उनमें सहायता प्रदान करता है।

शिक्षा में उच्च अध्ययन केन्द्र, एम. एस. विश्वविद्यालय, बड़ौदा द्वारा इस परियोजना के प्रथम चरण (1981-84) का मूल्यांकन किया जा रहा है।

विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा

वर्ष 1985 की दूसरी तिमाही के दौरान रा. शै. अनु. प्र. परि. में इस परियोजना के अन्तर्गत कार्यकलाप आरम्भ किए गए। राज्यों/संघीय क्षेत्रों में विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा योजना के समन्वयकों/प्रभारी अधिकारियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 13 राज्यों/संघीय क्षेत्रों ने भाग लिया। कुछ प्रशिक्षण माडयूल तैयार किए गए हैं। शिक्षकों द्वारा दृष्टि तथा श्रवण रोगों से पीडित बच्चों के लिए शिक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विषय-वस्तु के विश्लेषण के लिए एक ढांचा विकसित किया गया।

इसके अतिरिक्त, विकलांगों के लिए समेकित शिक्षा योजना के प्रमुख कर्मचारियों के लिए एक तीन मास का सेवारत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

शिक्षक शिक्षा

शिक्षक प्रशिक्षकों तथा अन्य कार्मिकों के लिए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष के दौरान प्रारम्भिक तथा माध्यमिक दोनों ही स्तरों पर लगभग 266 शिक्षक प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। विषय-वस्तु एवं प्रणाली विज्ञान, मूल्योन्मुख शिक्षक शिक्षा सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य और कालेज शिक्षण से सम्बन्धित पाठ विषयक/संसाधन सामग्री के विकास के लिए कई बैठकें आयोजित की गईं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 71 प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षकों को जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय जीवन, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, जनजातीय की समस्याओं तथा जनजातीय शिक्षा और गैर-औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के आयोजन से अवगत कराया गया।

सामाजिक विज्ञान और मानविकी में विकासात्मक तथा विस्तार कार्य

अंग्रेजी और हिन्दी में "सीखने के लिए पढ़ना" बाल साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता, शिक्षकों के लिए सेमिनार पठन प्रतियोगिता तथा राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से स्कूल पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन पर विशेष परियोजनाएं कार्यान्वित की गईं। राज्यों/संघीय क्षेत्रों में विभिन्न स्कूल विषयों, शिक्षणात्मक सामग्री और शिक्षण के तरीकों के स्थिति सर्वेक्षण आरंभ किए गए। इस वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा ढांचे का विकास, प्राथमिकता के आधार पर आरंभ किया गया। इस संबंध में एक राष्ट्रीय सेमिनार तथा चार क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किए गए और प्रारूप पाठ्यचर्चा ढांचे को अन्तिम रूप दे दिया गया। स्कूल शिक्षा के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों के लिए विभिन्न विषयों में पाठ्यचर्चाओं तथा शिक्षणात्मक सामग्री को तैयार/संशोधन करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 के इलेकटिव तथा कोर विषयों के लिए मातृभाषा के रूप में हिन्दी के लिए पांच पुस्तकें तैयार की गईं। नौसीखियों में लेखन दक्षता के विकास के लिए हिन्दी में तीन कार्य पुस्तकों का एक सैट विकसित किया गया। दो हिन्दी पाठ्यपुस्तकें–एक अरूणाचल प्रदेश में कक्षा 3 के लिए (एक कार्य पुस्तक सहित) तथा दूसरी, कक्षा 4 के लिए, पूरी की गईं। अरूणाचल प्रदेश के लिए कक्षा 12 के लिए एक अंग्रेजी पूरक रीडर (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) का कोर पाठ्यक्रम (तथा न्यू डान रीडर्स 2 और पूरक रीडर 2 तैयार किए गए। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए कक्षा 12 के लिए संस्कृत में एक नई पाठ्य-पुस्तक भी प्रकाशन के लिए प्रस्तुत की गई। कक्षा 5 से 7 तक में संस्कृत पढ़ाने के लिए एक शिक्षक गाइड तैयार की गई। कक्षा 4 के लिए उर्दू में एक पाठ्य-पुस्तक तैयार की गई।

"भारतीय स्वतंत्रता संग्राम : दृश्य तथा प्रलेख" नामक एक प्रकाशन प्रकाशित किया गया जिसमें स्वतंत्रता संग्राम की पूर्ण अवधि तथा विभिन्न पहलू दर्शाने वाले 82 दृश्य पैनल शामिल थे। यह दो रूपों में प्रकाशित किया गया है–एक एलबम के रूप में एक जिल्दबंध खण्ड, और दूसरा शिक्षण के लिए खुले कागजों का एक पोर्टफोलिया।

—759 Deptt. of Edu./85

कक्षा 11–12 के लिए "भारतीय संविधान तथा सरकार" का एक संशोधित रूपान्तर प्रकाशित किया गया। इसके अतिरिक्त कक्षा 11 के लिए भूगोल में दो पुस्तकें तथा कक्षा 9 और 10 के लिए अर्थ शास्त्र में चार पुस्तकें प्रकाशन के लिए पूरी की गईं। "सीखने के लिए पढ़ना" नामक विशेष परियोजना के अन्तर्गत अब तक अंग्रेजी में दस पुस्तकें तथा हिन्दी में 20 पुस्तकें तैयार की गई हैं।

विज्ञान और गणित में विकासात्मक तथा विस्तार कार्य

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 के लिए भौतिकी, रसायन शास्त्र गणित की पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के लिए चार कार्यशालाएं आयोजित की गईं। दो अलग-अलग कार्यशालाओं में कक्षा 9 के लिए भौतिकी तथा जीव-विज्ञान में शिक्षक गाइडों की पाडुलिपियों को भी अंतिम रूप दे दिया गया। कक्षा 10 की जीव-विज्ञान पुस्तक खण्ड 11 को पूरा कर लिया गया। 10 राज्यों की कक्षा 1 से 10 तक के लिए वर्तमान भौतिकी पाठ्यचर्याओं का पुनरीक्षण किया गया। रसायन-विज्ञान तथा गणित पाठ्यचर्याओं में अनुप्रस्थ तथा अनुलम्ब संबंधों/संयोजनों की जांच के लिए एक ऐसी ही कार्यशाला आयोजित की गई।

अल्पसंख्यक स्कूलों के 100 से अधिक शिक्षकों को, पर्यावरणात्मक शिक्षा, शिक्षण की व्यक्तिगत रूप से संचालित पद्धति, संगणक साक्षरता और स्कूल से बाहर के कार्य-कलापों जैसे नए क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया। अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षा कार्य-क्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित भाग लेने वालों की प्रशिक्षणोत्तर कार्यशालाएं, अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षा कार्यक्रम के 18 फेलों का पूर्व-अनुस्थापन भी संचालित किया गया। रा.शै.अनु.प्र.परि. ने, प्रो. पीटर केल्ली, डा. अशोक खोसला, डा. एम. चक्रवर्ती जैसे विख्यात शिक्षाविदों द्वारा सेमिनार आयोजित किए। प्राथमिक तथा मिडिल स्तरों के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव-विज्ञान तथा गणित में बारह पुस्तकें और छः विवरणिकाएं तथा पत्रिकाएं प्रकाशित की गईं।

राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी

नवम्बर, 1985 में, महाराणा भोपाल स्टेडियम, उदयपुर में बच्चों के लिए चौदहवीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी का मुख्य विषय था। "विकास में देशी प्रौद्योगिकी", और देश के सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों लक्षद्वीप को छोड़कर) के प्रदर्शन प्रदर्शित किए गए।

शैक्षिक मनोविज्ञान, परामर्श और मार्गदर्शन

शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन में नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 26 प्रशिक्षणार्थियों ने, जिनमें अनु.जा./अनु.ज.जा. के चार प्रशिक्षाणार्थी भी शामिल हैं, यह पाठ्यक्रम पूरा किया। वे अपने-अपने राज्यों/संघीय क्षेत्रों के स्कूलों में परामर्श-दाताओं के रूप में कार्य करेंगे। अथवा मार्गदर्शन कार्य अथवा मार्गदर्शन और परामर्श में प्रशिक्षण प्रदान कर रही एजेंसियों में तैनात होंगे। रा.शै.अनु.प्र.परि. ने, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित स्कूलों के प्रबंधकों और प्रिंसिपलों की तीन सेमिनार-एवं-कार्यशालाएं आयोजित कीं ताकि उन्हें अपने-अपने स्कूलों में मार्गदर्शन सेवाओं को आरंभ करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में 22 व्यक्तियों को संचार तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग की जानकारी दी गई, अध्ययन तथा विकास के क्षेत्र में महाराष्ट्र तमिलनाडु और उत्तरी पूर्वी राज्यों के प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षकों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद/राज्य शिक्षा संस्थान के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।

15 लेख, जिनमें जन-संचार माध्यम से शिक्षकों के साथ सम्प्रेषण के लिए प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के मार्गदर्शन हेतु तैयार की गई सामग्री शामिल थी, तैयार किए गए और "प्राथमिक स्कूलों में मार्गदर्शन" शीर्षक के अन्तर्गत "प्राथमिक शिक्षक जर्नल" का एक विशेष अंक प्रकाशित किया जाएगा। इसी सामग्री का रेडियो और टी.वी. के प्रदर्शनों में भी प्रयोग किया जाएगा, 1+2 स्तर पर मनोविज्ञान पाठ्यक्रम के लिए एक प्रश्न बैंक जिसमें लगभग 1000 प्रश्न हैं, भी तैयार किया गया।

मूल्यांकन प्रक्रियाओं में सुधार लाना तथा परीक्षा सुधार

खुली पुस्तक परीक्षा पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया जिसमें बोर्डों राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों/राज्य शिक्षा संस्थाओं, शिक्षा निदेशालयों तथा कालेजों के 21 अधिकारियों ने भाग लिया। विभिन्न विषयों तथा विभिन्न कक्षाओं के लिए विषयपरक मुद्दे, प्रश्न बैंक, व्यापक अभ्यास विकसित करने के लिए छः कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों के 679 मास्टर शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों बोर्ड के पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को शिक्षा मूल्यांकन बाह्य परीक्षा सुधार, विषय लेखन, प्रश्न-पत्र तैयार करना, नमूना सर्वेक्षण प्रणालियों जैसे परीक्षा सुधार के विभिन्न पहलुओं से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। सेना, नौसेना तथा वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूलों के शिक्षकों के लिए, शैक्षिक मूल्यांकन में दो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज और रचनात्मकता

कक्षा 10 के उन छात्रों के लिए जिनकी सिफारिश राज्यों/संघीय क्षेत्रों ने की थी, 29 केन्द्रों में राष्ट्रीय स्तर की एक परीक्षा संचालित की गई। इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर लगभग 1500 प्रत्याशियों का साक्षात्कार किया गया। अंत में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए 750 प्रत्याशियों को चुना गया।

प्रारंभिक स्तर पर रचनात्मक क्षमताओं की पहचान, प्रोत्साहन तथा विकास पर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के 32 प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षकों ने भाग लिया। क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित इसी प्रकार के एक पाठ्यक्रम में 20 माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षकों ने भाग लिया।

शिक्षा का व्यावसायीकरण

उद्यान-विज्ञान, वाणिज्य शिक्षण (2), तथा इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकी में व्यावसायिक शिक्षकों के लिए चार अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश के 100 शिक्षकों ने भाग लिया। इनसे उन्हें अपने-अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ाने में सहायता मिली।

विभिन्न राज्यों के 253 व्यक्तियों और प्राधिकारियों के लिए छः प्रशिक्षण कार्यक्रम-व्यावसायीकरण पर चार तथा सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य पर दो-आयोजित किए गए ताकि उन्हें इस योजना की संकल्पना,, उद्देश्यों, वार्षिक योजनाओं, कार्यकलापों के चयन और कार्यान्वयन के लिए नीतियों से अवगत कराया जा सके। विभिन्न संगठनों के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की गईं।

डेरी उद्योग तथा कोशकीट पालन के प्रत्येक क्षेत्र में छः शिक्षणात्मक एवं व्यावहारिक नियम पुस्तकें प्रकाशित की गईं। पादक संरक्षण, पौध खेती तथा प्रबंध, बहु पुर्नवास कार्मिक और नेत्र तकनीशियन में न्यूनतम क्षमता आधारित पाठ्यचर्याएं विकसित की गईं। माइक्रो जीव-विज्ञान तथा संचारी रोगों में पूरक रीडर भी तैयार किए गए।

गैर-औपचारिक शिक्षा

केन्द्रीय प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन से संबंधित क्षेत्रीय समस्याओं पर प्रकाश डालने के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा पर शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों का एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। मंत्रालय के अनुरोध पर गैर-औपचारिक शिक्षा के शैक्षिक पहलुओं का व्यापक अध्ययन आरंभ किया गया। मिडिल स्तर पर छात्रों के लिए तीन विज्ञान पुस्तकों, तीन सामाजिक विज्ञान पुस्तकों तथा तीन भाषा पुस्तकों को अंतिम रूप दे दिया गया। इन तीनों विषयों की संपूर्ण विषय-वस्तु को प्रत्येक समतुल्य कक्षा अर्थात् VI, VII और VIII के लिए एक समाकलित रूप में केवल तीन ही पुस्तकों में शामिल करने का प्रयत्न किया गया है।

समूह-गान

रा.शै.अनु.प्र.परि. ने समूहगान में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शिविरों का आयोजन जारी रखा। देश भर के 860 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। इसके अतिरिक्त, 140 शिक्षक प्रशिक्षकों को, इस आन्दोलन के और आगे प्रसार के लिए प्रमुख

व्यक्तियों के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। "श्रीमती इंदिरा गांधी की बाल्यकाल की स्मृतियां" नामक एक रिकार्ड किया हुआ कैसेट सभी प्राथमिक स्कूलों में वितरित किया जा रहा है।

शैक्षिक अनुसंधान और नवीनीकरण

शै.अनु.नवी.परि. की सिफारिश पर 10 नई अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। चल रही 97 परियोजनाओं को सहायता जारी रही, जबकि सात अनुसंधान परियोजनाएं पूरी कर ली गईं। अनुसंधान के लिए एक नई नीति लागू कर दी गई है।

प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण से संबंधित समस्याओं तथा विषयों पर एक राष्ट्रीय सेमिनार एवं कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित समाज के विभिन्न स्तरों के 57 विशेषज्ञों ने भाग लिया। युवा, प्रतिभाशाली तथा सक्षम व्यावहारिक शोध-कर्ताओं को आकर्षित करने तथा प्रशिक्षित करने के लिए 2 अनुसंधान प्रणाली-विज्ञान पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। इस वर्ष की समाप्ति से पहले ऐसे दो और पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अनुसंधान सूचना के प्रसार के लिए, दो विशेष शै.अनु.नवी.परि. बुलेटिन प्रकाशित किए गए। परीक्षा निर्माण पर सेमिनार, विद्यमान पाठों के पुनरीक्षण के लिए कार्यशालाएं इन परीक्षाओं के सम्पादन के लिए राष्ट्रीय बैठकें आयोजित की गईं।

प्रकाशन

रा.शै.अनु.प्र.परि. ने अब तक 86 स्कूल पाठ्यपुस्तकों, पूरक रीडर, शिक्षक गाइड और छात्र कार्य पुस्तकें प्रकाशित कीं। अन्य प्रकाशित 36 विनिबंध शिक्षा में अनुसंधान से संबंधित हैं। इनमें से कुछेक पुनर्मुद्रण थे। इस वर्ष के दौरान छः पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी रहा। प्रकाशनों के वर्तमान डिजाइनों में सुधार लाने के लिए विचार तथा सुझाव एकत्र करने के लिए एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया।

शैक्षिक प्रलेखन

पुस्तकालय सेवाओं में सुधार लाने के बारे में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में 19 पुस्तकाध्यक्षों ने भाग लिया। स्कूलों तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के पुस्तकाध्यक्षों के सेवारत प्रशिक्षण के लिए एक पाठ्यचर्या विकसित की गई। नए प्रकाशनों से संबंधित सूचना के प्रसार के लिए पांच प्रकाशन प्रकाशित किए गए।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यूनेस्को प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत, प्राथमिक शिक्षा, कार्य तथा शिक्षा, प्रतिकूल परिस्थितियों वाली जनसंख्या की शिक्षा विज्ञान शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के क्षेत्रों में सात महत्वपूर्ण परियोजनाएं/अध्ययन आरंभ किए गए।

स्कूल शिक्षा में नवाचारों पर विचार विमर्श के लिए शि.प्र.सं. में एक क्षेत्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। शैक्षिक नवाचारों पर एक न्यूजलैटर भी समय-समय पर प्रकाशित किया गया।

विज्ञान उपस्कर, शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम आरंभ किए गए। इसके तथा यूनेस्को प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न देशों के 16 शिष्टमंडलों का स्वागत किया गया और अध्ययन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

शैक्षिक पत्रिकाएं

छः पत्रिकाएं प्रकाशित की गईं। शैक्षिक पत्रकारिता के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के लिए तीन राष्ट्रीय सेमिनार एवं कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें 50 विशेषज्ञों तथा अन्य व्यक्तियों ने भाग लिया। उनमें से कुछ ने, शैक्षिक पत्रकारिता की पुस्तिका तथा शैक्षिक पत्रकारिता पर शब्द-कोश के लिए योगदान देना स्वीकार किया।

क्षेत्रीय सेवाएं

रा.शै.अनु.प्र.परि. के 17 क्षेत्रीय एककों ने स्कूलों में प्रायोगिक परियोजनाओं में कार्यक्रम आयोजित किए। उन स्कूलों के लिए अनेक प्रायोगिक परियोजनाओं की जांच

की गई तथा संस्वीकृति प्रदान की गई जिनके शोधकर्ताओं को इस प्रयोजन के लिए प्रशिक्षित किया गया था। अनु.ज./अनु.ज.जाति कार्यक्रमों में उनके शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण शामिल था। स्कूल शिक्षा के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विभिन्न राज्यों द्वारा प्राप्त प्रगति, जरूरतों, समस्याओं का अध्ययन करने के लिए, चार क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की गई।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

''शिक्षा के लिए इन्सेट'' परियोजना के अंतर्गत, उपग्रह को सप्ताह में तीन बार सामग्री प्रदान करने के लिए 5–8 तथा 9–11 आयु वर्ग के बच्चों तथा प्राथमिक स्कूलों शिक्षकों के लिए 46 कार्यक्रम तैयार किए गए। उड़ीया, मराठी, तेलुगू तथा गुजराती में 188 भाषा रूपान्तर तैयार किए गंए। महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा से संबंधित शैक्षिक दूरदर्शन पर तीन अध्ययन आरंभ किए गए।

एशिया पैसिफिक इनस्टीच्यूट आफ ब्राडकास्टिंग डिवल्पमेंट के सहयोग से, शैक्षिक दूरदर्शन निर्माण तथा तकनीकी संचालन में छः सप्ताह का एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 54 अधिकारियों ने भाग लिया।

केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान ने, राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए भवन तथा उपस्कर के लिए योजना समन्वित की। शिक्षाविदों तथा निर्माताओं के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान के लिए बच्चों के लिए शैक्षिक श्रव्य/रेडियो कार्यक्रमों पर एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया।

लोअर प्राथमिक स्कूलों में रेडियो के माध्यम से पृथक भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण पर परियोजना, जयपुर जिला में जारी रही। रेडियो के माध्यम से दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण की एक अन्य परियोजना को उड़ीसा में आरंभ किया गया।

सुदूर शिक्षा तथा शिक्षक शिक्षा के लिए शैक्षिक प्रौद्योगिकी, चार्टों को तैयार करने, टेप स्लाइडें तथा कम कीमत के साधन, साधनों के संकलन आदि के क्षेत्र में कार्य-कलाप जारी रहे।

तीन फिल्मों, अर्थात् गैर औपचारिक शिक्षा, फोटोग्राफी की तकनीकें और सूर्य-ग्रहण पर कार्य प्रगति पर है। नई फिल्में खरीदने के पश्चात् अब इनकी कुल संख्या 8200 से अधिक हो गई है। शिक्षण में फिल्मों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए दो शैक्षिक फिल्म समारोह आयोजित किए गए।

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज

अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों ने एम. एड. तथा पी.एच.डी. स्तरों पर अनुसंधान के अलावा नवीन सेवा-पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्य-क्रम, सेवारत प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्यक्रम आयोजित किए।

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान

राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की स्थापना 1962 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे शिक्षकों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उनके कल्याण को बढ़ावा देना है। शिक्षक कल्याण योजनाओं के वित्त-पोषण के लिए निधियों का एक स्थिर स्रोत प्रदान करने के लिए पांच करोड़ रुपये का कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। पांच करोड़ रुपये का यह लक्ष्य पूरा हो चुका है और अब प्रतिष्ठान निधियां नौ करोड़ रुपये से भी अधिक हैं। इस कोष की निधियों से आरंभ किए जाने वाले कार्यक्रमों को सुझाने के लिए अब एक समिति स्थापित की गई है।

प्रतिष्ठान के कोष में केन्द्र तथा राज्यों/संघीय क्षेत्रों के अंशदान शामिल हैं और राज्यों/संघीय क्षेत्रों द्वारा किए गए संग्रहों का 20% केन्द्रीय कोष में जाता है तथा शेष 80% उनके पास ही रहता है। जुलाई, 1985 में हुई अपनी बैठक में महा-समिति

ने यह निर्णय किया कि राज्यों/संघीय क्षेत्रों द्वारा एकत्र की गई राशि का 90% अपने शिक्षकों को सहायता प्रदान करने के लिए उनके द्वारा ही रख लिया जाएगा और केवल 10% की केन्द्रीय कोष में अंतरित किया जाएगा। शिक्षा विभाग तथा राज्यों/संघीय क्षेत्रों द्वारा निधियां एकत्र करने का अभियान शिक्षक दिवस को आयोजित किया जाता है जो देश भर में प्रत्येक वर्ष 5 सितम्बर को मनाया जाता है। हमेशा की तरह इस बार भी शिक्षा विभाग तथा राज्य/संघीय क्षेत्रों सरकारों द्वारा धन संग्रह अभियान 5 सितम्बर, 1985 को शुरू किया गया था।

प्रतिष्ठान प्रत्येक वर्ष ऐसे तीन अध्यापकों को पुरस्कार भी प्रदान करता है जिन्होंने कम से कम 30 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो। यह पुरस्कार स्वर्गीय प्रो. डी. सी. शर्मा की स्मृति में शुरू किया गया था जो एक विख्यात शिक्षाविद और इस प्रतिष्ठान के एक संस्थापक सदस्य थे। इस पुरस्कार में एक योग्यता प्रमाण-पत्र तथा 1000/- रुपए का नकद पुरस्कार शामिल है। वर्ष 1985 के प्रो. डी.सी. शर्मा स्मारक पुरस्कार के लिए तीन शिक्षक चुने गए हैं।

14 राज्यों/संघीय क्षेत्रों से उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1984-85 के दौरान, राज्यों/संघीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान की कार्य समितियों द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में लगभग 1168 शिक्षकों/आश्रितों इत्यादि को 15,76,237·00 रुपए की राशि वितरित की गई। इन राज्यों/संघीय क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1984-85 के दौरान 27,77,,853·58 रुपए की राशि एकत्र की गई।

स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

यह कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा, रा. शै. अनु. प्र. परि./राज्य सरकारों आदि के परामर्श से कार्यान्वित किया जा रहा है।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत रा. शै. अनु. प्र. परि. द्वारा निम्नलिखित प्रतिनिधि-मण्डल/शिष्टमण्डल विदेश भेजे गए :

— वर्ष 1982-84 के लिए भारत-जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य सांस्कृजिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की मद सं. 23 के अंतर्गत, विज्ञान उपस्कर के डिजाइन तथा विकास, शैक्षिक प्रौद्योगिकी को तथा व्यावसायिक शिक्षा का अध्ययन करने के लिए, 3 सदस्य वाले एक शिष्टमण्डल ने, जिसमें डा. ब्रहम प्रकाश, प्राध्यापक, डी.ई.एस.एम., श्री बी. के दत्त, कार्य अनुभव शिक्षक, क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भुवनेश्वर तथा श्री नरेन्द्र सिंह कार्य अनुभव शिक्षक, क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भोपाल ने 5 से 19 मार्च, 1985 तक जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य का दौरा किया।

— वर्ष 1984-85 के लिए भारत मारिशस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत, शिक्षक शिक्षा, पाठ्यचर्या विकास, द्वितीय भाषा अध्ययन, उपयुक्त अध्यापन तथा भारतीय भाषा के एक कार्यक्रम के विकास के क्षेत्रों में सहयोग से संबंधित समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए, एक सदस्य वाले एक शिष्टमण्डल ने अक्तूबर, 1985 में रा.शै.अनु.प्र. परि. का दौरा किया।

— वर्ष 1985-86 के लिए भारत-सोवियत रूस सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की मद 35 के अंतर्गत भारत में स्कूल शिक्षा के विकास की आधुनिक स्थिति तथा प्रवृत्तियों का अध्ययन करने तथा शिक्षण स्टाफ के लिए उच्च अध्ययनों की पद्धति की जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सोवियत संघ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत तीन सदस्यों के एक रूसी शिष्टमण्डल ने 14 से 23 नवम्बर, 1985 तक रा.शै.अनु.प्र.परि. का दौरा किया।

विकलांग बच्चों के लिए समंकित शिक्षा की योजना

विकलांग बच्चों के लिए समंकित शिक्षा की योजना के अंतर्गत, सामान्य बच्चों के लिए निर्धारित स्कूलों में विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत राज्यों/संघीय क्षेत्रों को, शिक्षकों के वेतन, स्कूलों/संस्थानों के लिए संसाधन कक्षों तथा मूल्यांकन कक्षों की स्थापना तथा उपस्कर, लेखन-सामग्री भत्ते पाठक भत्ते (नेत्रहीन छात्रों के लिए), यातायात भत्ते, मार्गरक्षी भत्ते (गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए) तथा विकलांग बच्चों के लिए छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने के खर्चों को वहन करने के लिए 100% वित्तीय सहायता उपलब्ध है। विकलांग बच्चों के शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षा में पाठ्यक्रम चलाने के लिए चुने हुए विश्वविद्यालयों/संस्थाओं, कालेजों को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। विशेष शिक्षा में प्रशिक्षण की सुविधाएं, रा.शै.अनु.प्र.परि. तथा इसके क्षेत्रीय कालेजों में भी उपलब्ध है।

इस योजना के अंतर्गत अभी तक अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, दिल्ली तथा मिजोरम के संघीय क्षेत्रों को और जम्मू व कश्मीर, मेघालय तथा पंजाब को छोड़कर सभी राज्यों को समय-समय पर अनुदान दिए गए हैं।

युद्ध के दौरान मारे गए अथवा विकलांग हुए अधिकारियों एवं व्यक्तियों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं

केन्द्रीय सरकार और अधिकांश राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों ने 1962 में भारत-चीन युद्ध तथा 1965 और 1971 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान मारे गए तथा स्थायी रूप से विकलांग हुए रक्षा सैनिकों तथा पैरा-सैन्य बलों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं देना जारी रखा। वर्ष 1985-86 में 23 छात्रों ने ऐसी सुविधाएं प्राप्त की।

सामूहिक गायन आन्दोलन

स्कूल के बच्चों में जन आन्दोलन के रूप में सामूहिक गायन के विकास के लिए एक परियोजना 1983-84 में शुरू की गई जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं; (1) बच्चों को विभिन्न भारतीय भाषाओं के गाने, समूह में गाने के लिए प्रेरित करना, इस प्रकार राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाना; (2) बच्चों में राष्ट्रीय भावना पैदा करना; (3) उन्हें विविधता में एकता के महत्व को समझाना तथा उनमें देश की सांस्कृतिक परम्परा के प्रति प्रेम उत्पन्न करना; और (4) स्कूल के बच्चों को संगीत समुदाय में आगे बढ़ाना।

रा.शै.अनु.प्र.प. के माध्यम से परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के अन्तर्गत, रा.शै.अनु.प्र.प. संगीत तथा देश के विभिन्न राज्यों संगीत में रुचि लेने वाले शिक्षकों के लिए सामूहिक गायन से सम्बन्धित राष्ट्रीय एकता शिविरों का आयोजन कर रही है। जून, 1982 से, रा.शै.अनु.प्र.प. ने अब तक देश के विभिन्न भागों में 61 शिविर आयोजित किए तथा 3000 से भी अधिक शिक्षकों को सामूहिक गायन में प्रशिक्षित किया। वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुसार शिविरों में भाग लेने वाले शिक्षकों को संगीत विशेषज्ञों ने विभिन्न भारतीय भाषाओं से चुने हुए 15 गीत सिखाये हैं।

रा.शै.अनु.प्र.प. ने दिसम्बर, 1985 तक सारे देश के 860 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रत्येक शिक्षक से यह आशा की जाती है कि वह अपने स्कूल के कम से कम 1000 बच्चों को ये गाने सिखाए। रा.शै.अनु.प्र.प. इस वर्ष के दौरान देश के सभी राज्यों के 140 शिक्षक प्रशिक्षक तैयार करने में समर्थ हो सकी है। ये प्रशिक्षक अपने सम्बन्धित राज्यों में सामूहिक गायन की परियोजना के आगे बढ़ाने में मुख्य व्यक्तियों के रूप में कार्य करेंगे।

बच्चों को सामूहिक रूप में समूह गानों को सिखाने के लिए शिविरों में भाग लेने वाले शिक्षकों को स्वरलिपि की एक मुद्रित पुस्तिका, 15 चुने हुए गानों का कैसेट, और एक टेप रिकार्ड मुफ्त प्रदान किया गया ताकि वे अपनी कक्षाओं में शिक्षण अध्ययन वातावरण तैयार कर सकें। इस परियोजना के अन्तर्गत "श्रीमती इन्दिरा गांधी की बाल्यावस्था की यादें" शीर्षक का एक कैसेट सभी प्राथमिक स्कूलों को बांटा जा रहा है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

हाई स्कूल और इण्टर मीडिएट शिक्षा बोर्ड, राजपूताना जिसमें अजमेर, मेवाड़, केन्द्रीय भारत तथा ग्वालियर शामिल है, भारत सरकार के संकल्प द्वारा 1929 में स्थापित किया गया। 1952 में बोर्ड को इसका वर्तमान नाम "केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड" दिया गया। समय-समय पर इसके गठन में परिवर्तन किया गया तथा इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया गया ताकि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बोर्ड एक उपयोगी भूमिका निभा सकें। इसका अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण देश तक व्याप्त है। बोर्ड की कुछ मुख्य भूमिकाएं तथा कार्य परीक्षा के उद्देश्य से सारे देश की संस्थाओं को सम्बद्ध करना, स्कूलों के सम्बद्ध करने की स्वीकृति देने हेतु स्कूलों के निरीक्षण का प्रबन्ध करना परीक्षाओं का संचालन करना, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या निर्धारित करना, जब आवश्यक हो तो पाठ्यपुस्तकों का विकास एवं प्रकाशन करना है।

बोर्ड से सम्बद्ध स्कूलों में सभी केन्द्रीय विद्यालय, सभी सैनिक स्कूल, सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमियों, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रबन्धित स्कूल, संरकारी तथा संघीय क्षेत्र दिल्ली, चण्डीगढ़, अरुणाचल प्रदेश और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सहायता प्राप्त स्कूल व साथ ही साथ भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन के अधिकांश सदस्य स्कूल तथा प्राइवेट प्रबन्ध के अधीन स्कूल, तथा विदेशों में लगभग 30 स्कूल, भारतीय दूतावास के स्टाफ के बच्चों का और साथ-साथ विदेशों में कार्यरत अन्य भारतीयों का खान पान, आते हैं। बोर्ड से सम्बद्ध कुल स्कूल नवम्बर, 1985 तक 2047 हैं।

1985 में के.मा.शि.बो. परीक्षा में 2,18,128 छात्र बैठे। प्रश्न पत्रों की सुस्पष्ट सुरक्षा विश्वास दिलाने के लिए, परीक्षाओं का संचालन ध्यानपूर्वक किया गया जिससे कि प्रश्न पत्र खुलने से रोका जा सके तथा परीक्षाओं के स्वच्छ संचालन अथवा परिणामों की प्रक्रिया में बचाव के रास्ते अपना लिए गए हैं। पेपर तैयार करने वालों तथा परीक्षकों को प्रशिक्षण और अनुस्थापन कार्यक्रमों के माध्यम से बोर्ड की परीक्षाओं के औचित्य तथा विश्वसनीयता को अत्यधिक बढ़ाया गया है। सीनियर सैकण्डरी परीक्षाओं के लिए केन्द्रित मूल्यांकन प्रचलित है। इसे माध्यमिक स्तर पर भी प्रारम्भ करने की योजना है। पूर्व और उत्तर दोनों परीक्षा कार्य, प्रवेश-पत्र, अंक-विवरण तथा प्रमाण-पत्र सहित परीक्षा के अनेक पहलुओं का संगणकीकरण तथा संगणक मुद्रित कर दिया गया है।

बोर्ड ने कई प्रकाशन तैयार किए हैं। मुख्यत: पाठ्यचर्या संदर्शिका, माध्यमिक और सीनियर सैकण्डरी स्कूल दोनों के व्यक्तिगत विषयों के अध्ययन उद्देश्य जो विशेष रूप से प्रत्येक शीर्षक/एकक और नमूना प्रश्न पत्रों के अध्ययन परिणाम स्पष्ट करते हैं। इन प्रकाशनों को स्कूलों ने अत्यधिक पसन्द किया तथा इनका उपयोग किया, इनकी बड़ी मांग इस बात का प्रमाण है। अब बोर्ड ने इसे नियामक के रूप में मान लिया है कि प्रत्येक विषय के अध्ययन उद्देश्य रहेंगे। बोर्ड की शैक्षणिक शाखा ने प्रधानाध्यापकों/शिक्षकों और क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।

खुला स्कूल

कार्यरत प्रौढ़ों तथा स्कूल छोड़ जाने वालों की संख्या अत्यधिक हुई तथा बढ़ने के कारण उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 1979 में खुला स्कूल प्रारम्भ किया। पंजीकरण के दो वर्ष पश्चात सामग्री तैयार की गई तथा पहली परीक्षा 1983 में हुई। खुला स्कूल लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है तथा व्यावहारिक रूप से प्रत्येक राज्य और संघीय क्षेत्र में खुले स्कूल के छात्र हैं, जबकि दिल्ली में छात्रों की संख्या अधिक है। हाल ही में स्कूल में 20,000 से भी अधिक छात्रों का नामांकन है। परीक्षाएं साल में दो बार संचालित की जाती हैं। खुला स्कूल होने के कारण, इसका दृष्टिकोण लचीला होता है तथा इसमें श्रेय संचय सुविधा होती है ताकि छात्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पांच विषयों में पास होने के वास्ते 5 वर्षों की अवधि वाली 10 पूर्ण परीक्षाओं में बैठ सकें। मांग की पूर्ति हेतु, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अभी हाल ही में +2 स्तर पर पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी की है।

खुला स्कूल स्थापित शैक्षिक संस्थाओं तथा श्रमिक विद्यापीठों का सहयोग भी प्राप्त कर रहा है। व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम का भी पर्याप्त रूप से संशोधन हुआ है जो कि छात्रों को रविवार तथा अन्य राजपत्रित छुट्टियों जो लगभग 4–5 मास की अवधि से भी ज्यादा की है में अधिक नियमित आधार पर शिक्षण प्रदान करने के लिए चुनिन्दा संस्थाओं में संसाधन-एवं-अध्ययन केन्द्र निश्चित करके लाया गया है। लगभग 6000 छात्रों की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अब तक 15 ऐसे केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

शिक्षा विभाग और यूनेस्को के सहयोग से खुले स्कूल द्वारा सूदूर शिक्षा सम्बन्धी एक राष्ट्रीय प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यशाला 26 अगस्त, से 9 सितम्बर, 1985 तक आयोजित की गई, जिसमें 11 राज्यों से वरिष्ठ स्तर के प्रशासकों एवं अधिकारियों ने भाग लिया।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, साथ ही रक्षा कार्मिकों के बच्चों के लिए सारे देश में शिक्षा की समान सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक ही पाठ्यक्रम तथा शिक्षा माध्यम वाले केन्द्रीय स्कूलों की परियोजना भारत सरकार द्वारा नवम्बर, 1962 में स्वीकृत की गई। प्रारम्भ में शैक्षिक वर्ष 1963-64 के दौरान 20 रेजीमैन्टल स्कूल चलाए गए। तत्पश्चात केन्द्रीय विद्यालयों को स्थापित करने तथा उन्हें चलाने के लिए 1965 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया। 1985-86 के दौरान 41 नए स्कूल खुलने से अब केन्द्रीय विद्यालयों की कुल संख्या 540 है। सभी केन्द्रीय विद्यालयों में (1-4-1985 को) छात्रों की कुल संख्या 3,66,885 थी।

केन्द्रीय विद्यालयों में आठवीं कक्षा तक की शिक्षा मुफ्त है। बड़ी कक्षाओं में पाठ्य-शुल्क की राशि अभिभावकों के वेतन से सम्बद्ध होती है यदि वे केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/स्वायत्त निकायों में काम करते हैं। अन्य मामलों में पाठ्यशुल्क समान दर से लिया जाता है। वैसे भी केन्द्रीय विद्यालयों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों तथा शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ के बच्चों से कोई पाठ्य शुल्क नहीं लिया जाता। यद्यपि केन्द्रीय विद्यालय आवासीय स्कूल नहीं है तथापि 13 स्कूलों में छात्रावास उपलब्ध है।

केन्द्रीय विद्यालय सेवा कालीन पाठ्यक्रमों तथा कार्यशालाओं को आयोजित करके गैर-शिक्षण, शिक्षण और पर्यवेक्षक स्टाफ के सभी वर्गों की व्यावसायिक क्षमता सुधार लाने के लिए संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। 1984-85 के दौरान 58 सेवा-कालीन पाठ्यक्रम संचालित किए गए जिसमें 3176 प्रिंसिपलों, सहायक आयुक्तों, शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों इत्यादि ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली द्वारा आयोजित अनुस्थापन पाठ्यक्रमों में विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों से लगभग 216 शिक्षकों ने भाग लिया। 1985-86 के दौरान लगभग 3460 शिक्षकों के लिए 72 सेवाकालीन शिक्षा पाठ्यक्रम और 4 अनुस्थापन पाठ्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव है। वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों के दो शिक्षकों को शिक्षकों के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय विद्यालय अपने शिक्षकों और गैर-शिक्षक स्टाफ के विभिन्न वर्गों को प्रति वर्ष सात प्रेरणा पुरस्कार भी देते हैं।

के. मा. शि. बो. की अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा में केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों की पास प्रतिशतता 1985 में 86.3% थी जबकि अन्य छात्रों की 77.8% थी। अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा, 1985 में सामान्य छात्रों की पास प्रतिशतता 78.5 की तुलना में केन्द्रीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता 88.7 थी। केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों ने सभी परीक्षाओं में योग्यता सूची में अच्छी श्रेणी

प्राप्त की। अधिकांश छात्रों ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, इंजीनियरी और मेडिकल संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त किया।

शैक्षणिक उत्कृष्टता के अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय संगठन छात्रों के व्यक्तित्व के चहुंमुखी विकास के लिए खेलकूद तथा अन्य कार्यकलापों पर भी बल देता है। स्कूलों में विभिन्न खेल-कूद के कार्यक्रम क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर आयोजित किए गए। विभिन्न खेल-कूदों में शिक्षण शिविर भी आयोजित किए गए। भारत तथा विदेश दोनों में ही विभिन्न विषयों में शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया। खेल कूद में प्रतिभाशाली 90 छात्रों को 50 रुपए प्रति मास, प्रति छात्र की दर से नकद छात्रवृत्ति प्रदान की गई। "स्कूल गेम्स फेडरेशन आफ इण्डिया एथलिटिक मीट" में कांस्य पदक जीतने वाले एक छात्र को 100 रुपए का एक विशेष नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।

अधिकांश विद्यालयों में स्काउटों, गाइडों, क्लबों तथा बुलबुलों के ट्रूप बनाए गए हैं। अध्यापकों के लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण शिविरों को क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित किया गया। संगठन द्वारा उच्च प्रशिक्षण के लिए भारत स्काउट तथा गाइड संस्था के सहयोग से संगठन द्वारा पचमढ़ी में शिविर आयोजित किए गए थे। पैदल चलने तथा पर्वतारोहण के अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गए थे जिसमें छात्रों ने कुशलता से भाग लिया। 10,000 से अधिक छात्रों ने चट्टानों पर चढ़ने से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस समय विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में 209 साहसिक कार्य क्लब काम कर रहे हैं।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने कला तथा चित्रकला प्रदर्शनियां भी आयोजित की थीं तथा कोरिया गणराज्य द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों तथा सोवियत भूमि नेहरू बाल कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने के लिए उत्कृष्ट प्रदर्श भेजे गए थे।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन

भारत में तिब्बती शरणार्थियों के बच्चों की शिक्षा के लिए संस्थानों को चलाने, उनके प्रबन्ध तथा सहायता के लिए केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन की स्थापना 1961 में हुई थी। प्रशासन, डलहौजी, दार्जिलिंग, मसूरी तथा शिमला में चार आवासीय स्कूलों और देश के विभिन्न भागों में 32 दिवस स्कूल (14 शाखा स्कूल सहित) चलाता है। कक्षा IX तथा उससे ऊंची कक्षाओं वाले तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध स्कूल छात्रों को अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल परीक्षा तथा अखिल भारतीय सीनियर स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। रा. शै. प्र. अ. प. की पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों को कक्षा VIII तक पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी के अतिरिक्त छात्रों को हिन्दी तथा तिब्बती भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। प्रशासन तिब्बती शरणार्थी बच्चों के लाभ के लिए कुछेक संस्थानों को अनुदान के रूप में सहायता भी करता है।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 10,212 है जिनमें से 1599 छात्रावास में रहते हैं और 8613 दिवसीय छात्र हैं। आवासीय स्कूलों में भोजन और आवास के अलावा दैनिक जरूरत की वस्तुएं और चिकित्सा सुविधाएं भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। सभी छात्रों को जिनमें दिवसीय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी शामिल हैं, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, लेखन सामग्री इत्यादि भी प्रदान की जाती है। प्रशासन ने तिब्बती छात्रों को उच्च अध्ययन करने के लिए 15 छात्रवृत्तियां भी दी हैं। माध्यमिक स्कूल परीक्षा तथा अखिल भारतीय वरिष्ठ स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा में वर्ष 1985 के लिए केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन के स्कूलों के परिणाम क्रमशः 65.9% तथा 63.3% रहे। अध्यापकों के लाभ के लिए समय-समय पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, सेमिनार और संगोष्ठियां भी आयोजित की जाती हैं। प्रशासन छात्रों के लाभ के लिए खेल प्रतियोगिता शैक्षिक यात्राओं (क्षेत्र वार) का भी प्रबन्ध करता है।

बाल भवन सोसायटी

बाल भवन सोसायटी, भारत, एक स्वायत्त संगठन है। इसका सारा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। बच्चों को खाली घंटों के दौरान ललित-कलाओं, शारीरिक शिक्षा, प्रदर्शन कलाओं, संग्रहालय तकनीकों, फोटोग्राफी इत्यादि में रचनात्मक कार्यकलापों को सीखने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के लिए सोसायटी की स्थापना की गई थी। इन बुनियादी कार्यकलापों के समर्थन में, बाल भवन के माध्यम से रचनात्मक शिक्षा प्रदान करने में शिक्षकों, प्रशिक्षार्थियों, पर्यवेक्षकों इत्यादि को प्रशिक्षित करने के लिए बाल भवन व्यावसायिक प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र चला रहा है। बाल भवन के कार्य-कलापों में भाग लेने के लिए बाहर से आने वाले बच्चों तथा अध्यापकों को बाल भवन छात्रावास सुविधाएं प्रदान करता है।

बाल भवन में 1984-85 में 11,135 बच्चों के नामांकन की तुलना में 1985-86 में 10,684 (अक्तूबर, 1985 तक, केवल 7 महीने के लिए) बच्चों का नामांकन हुआ। 1984-85 में 44 बाल भवन केन्द्रों में 17,943 बच्चों के नामांकन की तुलना में 1985-86 में 47 बाल भवन केन्द्रों में 12,136 बच्चों का (10/85 तक केवल 7 महीनों में) नामांकन हुआ।

जून, 1984 के दौरान, 6–12 आयु वर्ग वाले बच्चों ने सेनफ्रांसिस्को, यू.एस.ए. में भाग लिया तथा "प्यार शान्ति है––शान्ति प्यार है" शीर्षक वाले एक चित्र के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। जुलाई, 1984 में प्रकृति द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कार्यशाला में 41 बच्चों ने भाग लिया और चुनौतीपूर्ण शीर्षक से सम्बन्धित 22 माडल तैयार किये। बाल भवन ने छात्र शिल्पकारों के लिए एक 6 दिवसीय एकता शिविर 9–14 सितंबर, 1984 तक आयोजित किया जिसमें दिल्ली के विभिन्न भागों के 2000 छात्रों ने भाग लिया था। दक्षिण दिल्ली पोलिटेक्नीक शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक विशेष कार्यशाला "संगीत और लय" आयोजित की थी। कार्यशाला का उद्देश्य इसमें भाग लेने वालों को, बच्चों को समझने की आवश्यकता तथा संजीव, वातावरण के लिए उनकी अपेक्षाओं की जानकारी को कराना था जहां वे उन्मुक्त भाव से पढ़ सके तथा अपनी अन्तर्भावनाओं को खुलकर सामने रख सकें। बाल भवन सोसायटी ने जवाहर बाल भवन मंडी में 23–27 मार्च, 1985 तक एक ग्रामीण छात्र रचनात्मकता मेला भी आयोजित किया। 1984-85 के दौरान, राष्ट्रीय प्रशिक्षण संसाधन केन्द्र ने 36 कार्यशालाओं का आयोजन किया।

स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए छात्र को विवेकी, सृजनात्मक तथा रचनात्मक और वैज्ञानिक विचारधारा विकसित करने में सहायता हेतु राष्ट्रीय बाल संग्रहालय ने "पाठ्यक्रमोन्मुख प्रदर्शनियां", "सोद्देश्य प्रदर्शनियां", "बच्चों के कार्य की प्रदर्शनियां" तथा "ग्रामीण बच्चों के कार्य की प्रदर्शनियां" नाम की 4 प्रदर्शनियां आयोजित कीं।

छात्र फिल्म सोसायटी के सहयोग से राष्ट्रीय बाल संग्रहालय ने नौ सप्ताह के लिए एक बाल फिल्मोत्सव आयोजित किया था। उत्सव ने प्रतिदिन लगभग 800 बच्चों को चुनी हुई दुर्लभ फिल्मों को देखने का अवसर प्रदान किया।

शारीरिक शिक्षा

शारीरिक शिक्षा तथा योग:नीति तथा कार्यक्रम

आज विश्व भर में शारीरिक शिक्षा तथा खेल को शिक्षा के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। हाल ही में सरकार द्वारा एक नई राष्ट्रीय खेल नीति, जिसमें शारीरिक शिक्षा तथा योग को भी शामिल किया है, एक सरकारी संकल्प के रूप में अपनाई गई। इसके अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का यह कर्तव्य है कि बहुमुखी विकास की प्रक्रिया में खेलों तथा शारीरिक शिक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाए। नई नीति में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों पर यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कि वे प्रत्येक नागरिक द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने की जरूरत को पूरा करने के लिए आवश्यक खेल सुविधाओं और अवस्थापना कार्यों की व्यापक स्तर पर व्यवस्था करें।

को प्रोत्साहन देने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत योग के निदानात्मक पहलुओं को छोड़कर योग के विभिन्न पहलुओं पर बुनियादी अनुसंधान और अथवा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रोत्साहन के लिए विकास और अनुरक्षण हेतु अखिल भारतीय स्तर की योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है। योग के निदानात्मक पहलुओं की प्रोन्नति के लिए भी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा योग संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

कैवल्य धाम श्रीमान माधव योग मंदिर समिति, लोनावला (एम), को उसके अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास और अनुरक्षण खर्चों के लिए योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान की गई। सरकार के सुझाव पर शारीरिक शिक्षा और योग की राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार निकाय के रूप में एस.एन.आई.पी.ई.एस. (स्निप्स) समिति के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए अवलोकन और आगामी वर्षों में इसके लक्षित विकास के लिए सिफारिश के लिए एक पुनरीक्षण समिति स्थापित की। समिति की प्राप्त रिपोर्ट एस.एन.आई.पी.ई.एस. (स्निप्स) द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

पब्लिक आवासीय केन्द्रीय स्कूलों में एन.सी.सी. जूनियर डिवीजन ट्रूप्स

केन्द्रीय/पब्लिक और आवासीय स्कूलों में एन.सी.सी. के रखरखाव का व्यय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) और रक्षा मंत्रालय द्वारा 40:60 के अनुपात के आधार पर वहन किया जाता है। एन.सी.सी. महानिदेशालय द्वारा मंत्रालय के पक्ष में इस अनुपात में किया गया व्यय मंत्रालय द्वारा वापस लौटा दिया जाता है।

शारीरिक शिक्षा और खेलों के राष्ट्रीय संस्थानों के लिए सोसायटी (एस.एन.आई.पी.ई.एस.)

दो राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा और खेल संस्थाओं, अर्थात लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एन.एस.आई.पी.ई.एस.), पटियाला के प्रशासन की देख रेख के लिए शारीरिक शिक्षा और खेलों के राष्ट्रीय संस्थानों के लिए सोसायटी की स्थापना 1965 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में की गई थी। इस एस.एन.आई.पी.ई.एस. (स्निप्स) के संचालक बोर्ड का नेतृत्व श्री वी. सी. शुक्ला, संसद सदस्य ने किया, जिनको अध्यक्ष के रूप में केबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा दिया गया है। उनका व्यक्तिगत दर्जा है। एस.एन.आई.पी.ई.एस. (स्निप्स) ने वार्षिक साधारण बैठक के अलावा 4 नियमित बैठकें भी आयोजित की। एस.आई.पी.ई.एस. (स्निप्स) की स्थायी समिति और इसके द्वारा गठित अन्य समितियों की भी अपने-2 काम के पूरा करने के लिए समय-समय पर बैठकें हुई।

एस.एन.आई.पी.ई.एस. (स्निप्स) ने शारीरिक शिक्षा और योग पर सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की सलाहकार संस्था के रूप में कार्य करना जारी रखा।

अध्याय–3

उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान

उच्च शिक्षा के स्तरों का समन्वय तथा निर्धारण करना संघ सूची का विषय है और यह केन्द्रीय सरकार का विशेष दायित्व है। यह दायित्व मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से निभाया जाता है जिसकी स्थापना संसद के एक अधिनियम के अधीन वर्ष 1956 में की गई थी। इस समय संसद अधिनियमों के अधीन नौ विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान प्रयासों की प्रोन्नति तथा समन्वय के लिए एजेन्सियों की स्थापना की है। इस समय चार राष्ट्रीय एजेन्सियां हैं अर्थात् भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, भारतीय दर्शन शास्त्र अनुसंधान परिषद् और भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान। केन्द्रीय सरकार उच्च शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत तथा अन्य देशों के बीच शैक्षिक सहयोग से संबंधित अन्य योजनाओं सहित अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं।

क. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उच्च शिक्षा की प्रवृत्तियां तथा विकास

वर्ष 1983-84 को विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में छात्रों का नामांकन 33.59 लाख से बढ़कर 1984-85 में 35.39 लाख हो गया। छात्रों की संख्या विश्वविद्यालय के विभागों में 5.95 लाख तथा कालेजों में 29.44 लाख थी।

कला संकाय में नामांकन कुल नामांकन का 40.4% था। विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय में यह प्रतिशत क्रमशः 19.7 तथा 21.0 था। प्रथम डिग्री स्तर में नामांकन 31.14 लाख (88%), स्नातकोत्तर स्तर पर 3.36 लाख (9.5%), अनुसंधान स्तर पर 0.39 लाख (1.17%) तथा डिप्लोमा तथा सर्टीफिकेट स्तर पर 0.49 लाख (1.4%) था। वर्ष 1983-84 की तुलना में प्रमुख वृद्धि केवल प्रथम डिग्री स्तर में ही थी।

अध्यापकों की संख्या में 2.25 लाख की वृद्धि हुई। इसमें से 0.49 लाख की वृद्धि विश्वविद्यालय विभागों तथा विश्वविद्यालय कालेजों में हुई तथा शेष "सम्बद्ध कालेजों" में। विश्वविद्यालय में 48773 में से 5165 प्रोफेसर थे, 11,159 रीडर थे, 30408 व्याख्याता थे तथा 2001 शिक्षक तथा निदर्शक थे। सम्बद्ध कालेजों में वरिष्ठ अध्यापकों की संख्या 26902 थी तथा 1,42,408 व्याख्याता थे तथा 7,469 शिक्षक/निदर्शक थे।

नए विश्वविद्यालय

आलोच्य वर्ष के दौरान, दो केन्द्रीय विश्वविद्यालय, अर्थात् इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय तथा पांडिचेरी विश्वविद्यालय तथा एक राज्य विश्वविद्यालय अर्थात् मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय, कोडईकनाल स्थापित किए गए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत, दो संस्थाओं अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बम्बई और थापर-इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला को विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया।

महिलाओं में उच्च शिक्षा

महिला छात्रों का नामांकन वर्ष 1983-84 के दौरान 9.77 लाख की अपेक्षा वर्ष 1984-85 के दौरान 10.21 लाख हो गया। स्नातकोत्तर स्तर पर महिलाओं का नामांकन कुल नामांकन का 30.4% था। महिला छात्रों का नामांकन केरल में सबसे अधिक था (49.9%) उस के बाद पंजाब में (43.9%), दिल्ली (43.6%) तथा जम्मू तथा काश्मीर (37.3%) था। सबसे कम (14.7%) बिहार में था।

वर्ष 1984-85 के दौरान कार्यकलाप :

आयोग द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम मोटे तौर पर निम्नलिखित वर्गों में रखे गए :

(1) कोटि सुधार संबंधी विशेष कार्यक्रम
(2) अनुसंधान के लिए सहायता
(3) विश्वविद्यालयों का विकास
(4) कालेजों का विकास
(5) अन्य योजनाएं

टि सुधार के लिए शेष कार्यक्रम

:) उच्च अध्ययन के केन्द्र तथा विशेष सहायता के विभाग

इस समय आयोग कोटि में सुधार लाने के लिए विशेष कार्यक्रम विकास हेतु अध्ययन केन्द्र और विषेश सहायता विभाग विकसित अध्ययन के 19 केन्द्रों तथा विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में 65 विशेष सहायता विभागों तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान में विकसित अध्ययन के 10 केन्द्रों तथा विशेष सहायता के 27 विभागों को सहायता प्रदान कर रहा है।

:) विभागीय अनुसंधान सहायता

इस समय विज्ञान में 45 तथा मानविकी तथा समाज विज्ञान में चार विभागीय अनुसंधान परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

.) कालेज में विज्ञान सुधार संबंधी र्यक्रम (सी. ओ. एस. ाई. पी.) कालेज के मानविकी था समाज विज्ञान सुधार सम्बन्धी र्यक्रम (सी. ओ. एच. एस. ा. आई. पी.) तथा विश्वविद्यालय तुल्य कार्यक्रम (यू. एल. पी.)

इस समय आयोग सी. ओ. एस. आई. पी. के अन्तर्गत 237 कालेजों तथा विज्ञान में यू. एल. पी. के अंतर्गत 40 विश्वविद्यालय विभागों की सहायता कर रहा है। इसी प्रकार सी. ओ. एच. एस. एस. आई. पी. के अंतर्गत 400 कालेजों तथा मानविकी और समाज विज्ञान में यू. एल. पी. के अंतर्गत 16 विश्वविद्यालय विभाग आयोग द्वारा सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

घ) विज्ञापन, मानविकी, तथा समाज वज्ञान-सम्बन्धी पैनल

वर्ष 1984-85 के दौरान विभिन्न पैनलों ने शिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उदाहरणत: प्रतिभाशाली छात्रों का पता लगाना उनके लिए ग्रीष्मकालीन स्कूल, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की अवस्थापना का विकास, अब प्रयोग में आने वाले व्याख्यान की एकल पद्धति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली शिक्षण विधियों को अपनाना तथा शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता में सुधार लाना। उन्होंने विश्वविद्यालयों में पर्यावेक्षण तथा मूल्यांकन में संशोधन करके तथा आयोग द्वारा पर्याप्त अनुश्रवण करके प्रतिभाशाली अध्येताओं को आकर्षित करने एवं पर्याप्त सहायता देने के लिए छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर अनुसंधान में सुधार लाने के वास्ते उपाय भी सुझाए ।

ङ) सामान्य सुविधाएं और सेवाएं

आयोग राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ सुविधाओं का विकास करने की कोशिश कर रहा है।

(1) नाभिकीय विज्ञान केन्द्र :— जवाहर लाल नेहरु परिसर के विश्वविद्यालय क्षेत्र में एक नाभिकीय विकास केन्द्र गठित किया गया है। कार्यवाही की योजना तैयार करने के लिए एक तकनीकी समिति बनाई गई है। पेलेट्रान के आयात के लिए आदेश दिये गए हैं। प्रतिभाशाली युवा वैज्ञानिकों को एक्सेलरेटर भौतिकी के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए कनाडा भेजने का भी प्रस्ताव है।

(2) सामग्री अनुसंधान केन्द्र : विश्वविद्यालय क्षेत्र में सामग्री अनुसंधान के विकास के लिए उठाए गए कदमों पर विचार करने के लिए आयोग ने एक समिति गठित की है। समिति कुछ चुनिन्दा विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय केन्द्र भी खोलेगी तथा भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के विभागों विश्वविद्यालय वैज्ञानिकों को ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री जो उद्योग में व्यापक रूप से प्रयोग हो सके तैयार करने के विचार से परस्पर बातचीत करने में सक्षम करने के वास्ते प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का भी सुझाव देगी।

(3) लेसर एंड फाइबर आप्टिक्स केन्द्र : लेसर और फाइबर आप्टिक्स विषय को यह सोचते हुए कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है तथा मूल और अनुसंधान प्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका अपनाता है आयोग चिन्हित विश्वविद्यालय में, जहां मूल ढांचा उपलब्ध है कुछ राष्ट्रीय क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की व्यावहार्यता को देखने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की। समिति ने लेसर और आप्टिक्स क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा कार्यशालाओं की सिफारिश की विशेषतौर से विविध क्षेत्रों में उनके प्रयोग को ध्यान में रखते हुए। समिति की सिफारिशों पर भौतिक चयनक द्वारा तथा अन्तिम रूप से आयोग द्वारा विचार किया गया।

(4) खगोल-भौतिकी तथा खगोल-विज्ञान केन्द्र :–विश्वविद्यालय के खगोल-विज्ञान और खगोल-भौतिकी के क्षेत्रों में शिक्षा और अनुसंधान की उन्नति के लिए आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की है। विभिन्न पहलुओं की जांच करने तथा कार्यवाही योजना को तैयार करने को ध्यान में रखते हुए खगोल शिक्षा तथा अनुसंधान में भावी विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है।

(5) राष्ट्रीय खगोल-विज्ञान केन्द्र :- आयोग ने रंगापूर वेधशाला, ओस्मानिया विश्व-विद्यालय, हैदराबाद में राष्ट्रीय खगोल-विज्ञान केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति दी है। इस वेधशाला का विकास एक राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में किया जाएगा जिसका प्रयोग विश्वविद्यालय तथा बाहर के खगोलज्ञ द्वारा किया जाएगा।

(6) विश्वविद्यालय विज्ञान सूचना केन्द्र : आयोग ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में विश्वविद्यालय विज्ञान सूचना केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति दी है। केन्द्र भारतीय विश्वविद्यालय में विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों में संगणकीकृत मासिक सार द्वारा तत्काल जानकारी सेवा प्रदान करेगा। यह प्रपत्रों के प्रयोग करने वालों को विश्वसनीय तथा अद्यतन सार सेवा तथा सूचना सेवाएं प्रदान करेगा। यह केन्द्र विश्वविद्यालय प्रणाली में अनुसंधान वैज्ञानिकों की आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय सुविधा के रूप में कार्य करेगा।

(7) जीव प्रौद्योगिकी में बहु विषयक अध्यापन तथा प्रशिक्षण का विकास (राष्ट्रीय जीव-प्रौद्योगिकी बोर्ड-वि.अ.आ.सहयोगात्मक कार्यक्रम) : राष्ट्रीय जीव प्रौद्योगिकी बोर्ड (विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग) द्वारा आयोजित 7 फरवरी 1983 की एक संयुक्त सभा में यह सुझाव दिया गया कि जिन विश्वविद्यालयों जीव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सक्रिय अनुसंधान वर्ग विद्यमान है उनको जीव-प्रौद्योगिकी के भली भांति परिभाषित क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए तथा साथ ही साथ विभिन्न स्तरों पर अपेक्षित प्रशिक्षण जन शक्ति के उद्देश्य से एक चयनात्मक आधार पर विकास किया जा सकता है। 5 वर्षों से अधिक की अवधि में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए छः विश्वविद्यालयों को चुना गया है।

(च) जन-संचार और शैक्षिक प्रौद्योगिक केन्द्र

इन्सैट 1 बी के चालू हो जाने से, उच्च शिक्षा के कार्यक्रमों से संबंधित एक घंटे का एक संचारण समय हररोज दोपहर में सुनिश्चित किया गया है। आयोग ने चुने हुए छः केन्द्रों के तथा जन-संचार अनुसंधान केन्द्र, जामियामिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली; पूना विश्वविद्यालय में शिक्षा माध्यम अनुसंधान केन्द्र (ई.एम.आर.सी.एस.), गुजरात विश्व-विद्यालय और सी.आई.ई.एफ.एल., हैदराबाद, और ओस्मानिया और रूड़की विश्व-विद्यालय में दृश्य-श्रव्य अनुसंधान केन्द्र (ए.वी.आर. सी.) में मानक उपकरणों सहित प्रशिक्षण और उत्पादन सुविधा की व्यवस्था की है। दूरदर्शन के माध्यम से दैनिक प्रसारण के वास्ते उपयुक्त सामग्री के समन्वय और सम्प्रेषण के लिए एक केन्द्रीय कार्यक्रम समिति स्थापित की गई है।

(।) सुदूर शिक्षा (।।) कक्षा विकास (।।।) निरन्तर शिक्षा, के लिए प्रसारण तथा जन माध्यम के प्रयोग के लिए कार्यक्रमों के विषय में सलाह देने के लिए इलैक्ट्रानिक माध्यम/जन-संचार संबंधी एक स्थायी समिति भी गठित की गई है।

(छ) बौद्ध दर्शन अध्ययन का विकास

आयोग ने बौद्ध दर्शन अध्ययन से संबंधित शिक्षण और अनुसंधान के विकास के लिए स्टाफ की नियुक्ति तथा पुस्तकों को खरीदने के लिए तीन विश्वविद्यालयों तथा पूना, आंध्र और सागर को सहायता देना जारी रखा।

(ज) गांधी दर्शन अध्ययन का विकास

शिक्षण और अनुसंधान के स्तर पर विश्वविद्यालयों में गांधी दर्शन अध्ययन की महत्ता दृष्टि से तथा विस्तार कार्यकलापों के माध्यम से, आयोग गांधीवादी विचारों और मूल्यों, गांधी भवनों को बढ़ाने तथा शान्ति अनुसंधान तथा अन्य संबंधित कार्यकलापों के माध्यम से कार्यक्रम प्रारम्भ करने से संबंधित पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों का समर्थन कर रहा है। विश्वविद्यालयों में गांधी दर्शन अध्ययन की प्रोन्नति के लिए आयोग को सलाह देने के लिए एक स्थायी समिति स्थापित की गई है ।

(ज) गांधी दर्शन अध्ययन का विकास

विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग ने विश्वविद्यालयों में नेहरू अध्ययन को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है।

आलोच्य वर्ष के दौरान, नेहरू जी पर गहन अध्ययन के लिए प्रोफेसर एम.एन.दास, कुलपति, उत्कल विश्वविद्यालय को पुरस्कृत किया गया।

नेहरू जी पर उत्तर-डाक्टोरल और पूर्व-डाक्टोरल अध्ययन करने के लिए आयोग ने सामूहिक रूप से पांच अनुसंधान एसोसिएटशिप और 10 कनिष्ट अनुसंधान शिक्षावृत्तियां रखी हैं।

(त्र) द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम

आयोग ने, समय-समय पर भारत सरकार द्वारा सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत इसे सौंपे गए विभिन्न विषयों के कार्यान्वयन को जारी रखा। इन कार्यक्रमों में शिक्षकों का आदान-प्रदान, उच्च शिक्षा संस्थाओं के बीच द्विपक्षी शैक्षिक संबंधों का विकास, छात्रवृत्तियां तथा शिक्षावृत्तियां और भारत में विश्वविद्यालयों को विदेशी भाषा शिक्षकों का आबंटन सम्मिलित है। वर्ष 1984-85 के दौरान, इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत 56 भारतीय शिक्षकों ने विदेशों का भ्रमण किया। इसी समयावधि के दौरान, इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत आने वाले छात्रों की संख्या 74 है।

(ट) प्रौढ़, सतत तथा विस्तार शिक्षा और सुदूर अध्ययन

आयोग, प्रौढ़ तथा सतत शिक्षा और विस्तार कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

31-3-85 तक 74 विश्वविद्यालय और 2080 कालेज इस कार्यक्रम में शामिल किए गए और वि.अ.आ. ने 36974 केन्द्रों को अनुमति प्रदान की।

आलोच्य वर्ष के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत 54 विश्वविद्यालयों और 18 कालेजों को सहायता प्रदान की गई। उतर साक्षरता का सतत शिक्षा कार्यक्रमों के साथ प्रभावी संबंध को सुनिश्चित करने के लिए, आयोग ने 31-3-1990 तक विश्वविद्यालयों और कालेजों को सहायता दिए जाने की सहमति दी है।

आयोग, विश्वविद्यालयों/कालेजों में जनसंख्या शिक्षा क्लबों की स्थापना हेतु सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अन्तर्गत, 31-3-85 तक 49 विश्वविद्यालयों और 814 कालेजों को सहायता प्रदान की गई।

नुसंधान के लिए सहायता

(क) प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं

(ख) लघु अनुसंधान परियोजनाएं

इस वर्ष के दौरान 40.44 लाख रुपए की लागत पर मानविकी तथा समाज विज्ञान में 79 प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं और 316.79 लाख रुपए से विज्ञान इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 235 प्रमुख परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

(ग) छात्रवृत्तियां और शिक्षावृत्तियां

आयोग द्वारा, वर्ष के दौरान 45.59 लाख रुपए की लागत से मानविकी और समाज विज्ञान में 682 लघु अनुसंधान परियोजनाएं तथा 316.79 लाख रुपए की लागत से विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 335 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

आयोग प्रतिवर्ष विश्वविद्यालयों और कालेजों में अनुसंधान के विकास के लिए 2896 कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्तियां, विज्ञान, मानविकी तथा समाज विज्ञानों में 150 अनुसंधान एसोसिएटशिप और इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में 60 शिक्षावृत्तियां देता है। उन श्रेष्ठ अध्यापकों, जो अपने सामान्य कार्यकाल में से एक वर्ष विशेषतया अनुसंधान और अपने अध्ययन के परिणामों को लिखने में लगाते हैं, के लिए 30 राष्ट्रीय शिक्षावृत्तियां उपलब्ध

6—759 Deptt. of Edu./85

हैं। वर्ष 1984-85 के दौरान 12 अनुसंधान शिक्षावृत्तियां प्रदान की गईं आयोग ने वर्षों के लिए जवाहर लाल नेहरू और उनके सहयोग पर अध्ययन हेतु राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति भी प्रदान की है। इसके अतिरिक्त आयोग की राष्ट्रीय एसोसिएटशिप, प्रख्यात शिक्षावृत्तियां शिक्षक शिक्षावृत्तियां आदि देने की योजना है।

(घ) राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 26 अगस्त 1984 को 12 विषयों–भौतिक रसायन, गणित, जीवविज्ञान, प्राणिविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनैतिक विज्ञान, दर्श शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र और इतिहास में कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षावृत्ति प्रदा करने के लिए अर्हता हेतु राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा का आयोजन किया। यह परीक्षा विश्व विद्यालय के 72 विश्वविद्यालय केन्द्रों पर आयोग के तत्वाधान में इसके द्वारा बना गए सभी नियमों और पद्धतियों के पालन करते हुए ली गई। 26 अगस्त, 198 को हुई परीक्षा का परिणाम दिसम्बर, 1984 में निकाला गया और परीक्षा में बै 12,862 छात्रों में से 1205 छात्रों को शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के लिए अर्हक पाय गया।

विश्वविद्यालयों का विकास

आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को विचारात्मक सहायता विश्वविद्यालय के आकार, वृद्धि और विकास का वर्तमान स्तर, लक्ष्यों और उद्देश्यों वित्तीय और मानव संसाधनों आदि जैसे कई घटकों के आधार पर निर्धारित करके प्रदान की जाती है। निरीक्षण समि तियों, जो पंचवर्षीय अवधि के लिए विश्वविद्यालयों की आवश्यकताएं तथा उपेक्षाएं निर्धा रित करती हैं, की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालयों के लिए विशेष आबंटन किए जाते हैं। सातवीं योजना में विश्वविद्यालयों के विकास के प्रति आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखेगा (क) जारी कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय के विकास की आवश्यकता और राष्ट्रीय महत्व के नए उभरते क्षेत्रों के सम्बन्ध में विद्यमान पाठ्यक्रमों को सुदृढ़ करने के लिए निवेश (ख) संरचनात्मक सुविधाओं को पुनः उच्च शिक्षा में विकास के लिए नये संस्थानों को शुरू करना और वर्तमान संस्थानों में दाखिले की क्षमता को बढ़ाना ताकि उपलब्ध ऐच्छिक संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सके।

(1) विश्वविद्यालयों का परिसर विकास आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उन संस्थानों को जो विश्वविद्यालय समझे जाते हैं, के लिए परिसर विकास हेतु सहायता ढांचे को जानने के लिए एक समिति का गठन किया है। विभिन्न विश्वविद्यालयों को, समिति की सिफारिशों के बाद वि.अ.आ. ने परिसर विकास के लिए 143.16 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया। वर्ष 1984-85 के दौरान विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता के रूप में 1456.06 लाख रुपए की राशि दी गई। मानविकी और समाज-विज्ञानों के विकास के लिए 702.35 लाख रुपए की अनुदान राशि प्रदान की गई। विभिन्न विश्वविद्यालयों को (1) वास्तुकला में विकसित सुविज्ञता (2) निष्पादन कलाओं में विकास (3) क्षेत्रक अध्ययनों का विकास; और (4) पुरातत्वीय सैलों को मजबूत बनाना/स्थापना करना।

(2) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी का विकास :

उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए आयोग द्वारा विश्व-विद्यालय अनुदान और प्रौद्यो गिकी में अनुसंधान वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस समय 32 विश्व-विद्यालय समझे जाने वाले विश्व-विद्यालयों, संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस संस्थान में शिक्षा के अवर स्नातक पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रदान की जाती है।

इस क्षेत्र में प्रतिभाशाली अध्येताओं को आकर्षित करने के विचार से आयोग ने इस वर्ष के दौरान स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियों/सीनियर अनुसंधान शिक्षा/वृत्ति के मूल्य में वृद्धि की है। स्नातकोत्तर छात्र वृत्ति की इसमें एक हजार रुपए प्रतिमाह की दर से और सीनियर अनुसंधान शिक्षा वृत्ति 1200 रुपए प्रतिमाह की दर से दी जाती है। सीनियर अनुसंधान अध्येता मकान किराया भत्ता और चिकित्सा सुविधाएं भी देय हैं।

वर्ष 1984-85 के दौरान आयोग ने विश्व-विद्यालयों को इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए 307.96 लाख रुपए की अनुदान राशि मुक्त की।

(3) संगणक सुविधाओं में विकास और जन-शक्ति प्रशिक्षण के लिए संगणक शिक्षा: इलैक्ट्रोनिक आयोग से परामर्श करने के बाद आयोग ने चुनिन्दा विश्वविद्यालयों को मीडियम साइज कम्प्यूटर देने में सहमत है।

विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग की संगणक विकास समिति ने अब तक 58 विश्व-विद्यालयों में संगणक प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की है। 35 विश्वविद्यालयों में पहले से ही स्थापित संगणक प्रणालियां पूर्ण रूप से कार्यरत है। शेष 23 विश्व-विद्यालय, प्रणाली प्राप्त करने और उन्हें स्थापित किये जाने की स्थिति में है।

ालेजों का विकास

समुचित स्तरों को बनाए रखने, उपलब्ध सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने, नए-नए प्रयोगों और परिवर्तनों को बढ़ावा देने, शिक्षा को नई व्यवसाय पद्धति से जोड़ने, व्यावहारिकता तथा समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से देश के शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करने के उद्देश्य से सम्बद्ध कालेजों का विकास उच्च शिक्षा में एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है जो मुख्य रूप से अवर स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए जिम्मेदार है परन्तु कुछ हद तक स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए भी आधार का काम करते हैं।

वर्ष 1984-85 के दौरान कालेजों को सामान्य विकास और अन्य योजनाओं के लिए दिये गये अनुदान निम्नलिखित है :--

मदें	**प्रदान की गई सहायता (लाख रुपये में)**
सम्बद्ध कालेजों का विकास	1778.50
कालेज विज्ञान सुधार कार्यक्रम	22.52
कालेज मानविकी और समाज-विज्ञान सुधार कार्यक्रम	87.87
शताब्दी अनुदान	0.50
मानविकी और समाज-विज्ञान के उत्तर-स्नातक अध्ययनों का विकास	73.27
विज्ञान के उत्तर-स्नातक अध्ययनों का विकास	138.57
अवर-स्नातक शिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	0.90

आयोग ने अगले पांच वर्षों के लिए मद्रास विश्वविद्यालय के स्वायत्त कालेजों को सहायता देने पर सहमति व्यक्त की है। अन्य विश्वविद्यालयों के स्वायत्त कालेजों की समीक्षा पर आयोग विचार कर रहा है। आने वाले वर्षों के दौरान यह प्रस्ताव है कि योजना को एकीकृत और सुदृढ़ बनाया जाए तथा इस योजना के अंतर्गत कई विश्वविद्यालयों को भी लाया जाए।

न्य योजनाएं

इन कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए विशेष सहायता का प्रावधान किया गया है :- (1) अल्पसंख्यक समुदाय के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए (2) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और (3) महिलाओं के अध्ययन से सम्बन्धित कार्यक्रमों का विकास। इसके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :--

ल्पसंख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शिक्षण कक्षाएं

अल्प संख्यक समुदायों के कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आयोग ने विश्वविद्यालयों/कालेजों की प्रशिक्षण कक्षाओं के लिए सहायता देना जारी रखा।

31 मार्च, 1985 तक, 19 विश्वविद्यालय और 15 कालेज, वि. अ. आयोग से अल्पसंख्यकों के लिए प्रशिक्षण कक्षाएं चलाने के लिए सहायता प्राप्त कर रहे थे। और 1984-85 के दौरान, इस कार्य के लिए 23.77 लाख रुपए का अनुदान दिया गया।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए सुविधाएं

आयोग ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए आयोजना मूल्यांकन तथा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए एक उपाय के रूप में विशेष सैलों के सृजन के लिए विश्वविद्यालयों को शत प्रतिशत आधार पर सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। आयोग ने 31 मार्च, 1965 के अन्त तक विशेष सैल स्थापित करने के लिए 65 विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षा-वृतियों में से विश्वविद्यालयों के पास उपलब्ध ऐसी शिक्षा-वृत्तियों की कुल संख्या में से आयोग प्रतिवर्ष 50 कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षा-वृत्तियां प्रदान करता है। आयोग ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए 40 अनुसंधान सह-शिक्षा वृतियां भी आरक्षित की है। आलोच्य वर्ष के दौरान केवल 13 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और उन सभी को अनुसंधान सह-शिक्षा वृत्तियां प्रदान की जा चुकी है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित अध्यापक जो सम्बद्ध कालेजों में अध्यापक हैं, को अपनी अर्हताएं एम. फिल. अथवा पी.एच.डी. करके, बढ़ाने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु इन उम्मीदवारों को प्रतिवर्ष 50 अध्यापक शिक्षा-वृतियां प्रदान की जाती है।

महिलाओं की शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला अध्ययनों के साथ-साथ पाठ्यचर्या विकास तथा सम्बद्ध विस्तार कार्यक्रमों में सुपरिभाषित अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता देने की बात मान ली है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने फोर्ड-फाउन्डेशन द्वारा 1.00 लाख डालर की पेशकश को स्वीकार कर लिया है और इस धनराशि को कुछ चुनिन्दा विश्वविद्यालयों/कालेजों तथा भारतीय विद्वानों द्वारा परामर्शी कार्यों पर खर्च करने के लिए स्वीकार कर लिया है। ये विश्वविद्यालय/कालेज और विद्वान इस पैसे को महिला अध्ययनों के शहरी संग्रहों पर खर्च करेंगे।

इस वर्ष के दौरान पांच अनुसंधान परियोजना को सहायता दी गई और ये परियोजनाएं महिला अध्ययनों से सम्बन्धित थी। इस कार्य पर 0.38 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। आयोग ने एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, बम्बई में महिला अध्ययनों से सम्बन्धित एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है और इस कार्य के लिए 2.15 लाख रुपये का अनुदान दे दिया गया है।

ख. केन्द्रीय विश्वविद्यालय

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

शैक्षिक वर्ष 1985-86 के दौरान दाखिल छात्रों की संख्या 17,421 थी, जिनमें से 7,000 विद्यार्थी 13 आवासीय हालों वाले 55 छात्रावासों में थे। संकायों में छात्रों की संख्या 6,041, कालेजों में 5,511, स्कूलों में 5,750 और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 119 थी।

श्री सैयद हाशिम अली, आई.ए.एस. और उस्मानिया के भूतपूर्व कुलपति ने 8 अप्रैल, 1985 को विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार सम्भाला। विश्वविद्यालय में अध्ययन और अनुसंधान का माहौल सामान्य रूप से बना रहा। विश्वविद्यालय द्वारा अनुसंधान और प्रकाशनों पर अधिक जोर देने के प्रयत्न किए।

आलोच्य वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय द्वारा ये नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए (I) इंजीनियरी में डिप्लोमा (वास्तुकला में सहायता), (II) इंजीनियरी में डिप्लोमा (विद्युतीय विन्यास), (III) इलैक्ट्रानिक इंजीनियरी में डिप्लोमा (दूरदर्शन प्रौद्योगिकी), (IV) अंग्रेजी भाषा और साहित्य में उत्तर स्नातक शिक्षण डिप्लोमा, (V) उर्दू अनुवाद में उत्तर एम. ए. डिप्लोमा, (VI) एम.डी. कुल्लियाते इल्मुल अमराज और (VII) एम.डी. मवालिजात।

चालू वर्ष के दौरान, देश भर में अपनी तरह का एक बायो-टैक्नोलाजी संस्थान ने कार्य शुरू किया। भूख, रोग, जनसंख्या, विस्फोट आदि जैसी मुख्य कठिनाईयों को हल करने के लिए संस्थान जैनेटिक इंजीनियरी, एन्जाइम इंजीनियरी और फरमेन्टेशन टैक्नोलाजी जैसे ज्वलंज क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करेगा।

विज्ञान की प्रोन्नति के लिए विश्वविद्यालय ने, विकासशील वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में, भारतीय मुसलमानों में जागरुकता पैदा करने और वैज्ञानिक अनुसंधान में मुस्लिम प्रतिभाओं को खोजने के विचार से एक केन्द्र स्थापित किया।

विभाग की जीव-रसायन की प्रोटीन अनुसंधान प्रयोगशाला ने प्रोटीन रचना के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। इसने पी.एच.डी. और एम.फिल. डिग्रियों के लिए 73 छात्रों को प्रशिक्षित किया। सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग में अनुसंधान कार्यकलापों की वजह से विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान (रा.सं.रो.सं.) द्वारा इसे सैनिटल केन्द्र के रूप में मान्यता मिल गई है। संसाधन मूल्यांकन और जैव-इंजीनियरी के लिए सुदूरग्राही उपयोग केन्द्र को विकसित करने के लिए विश्वविद्यालय ने आधार भूत ढांचा तैयार किया गया है। प्राणि-विज्ञान विभाग के मत्सय पालन प्रभाग ने "भोज्य सूचना केन्द्रों के नेटवर्क (भो.सू.ने.के.)" के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त की है।

विश्वविद्यालय की केन्द्रीय लायब्रेरी देश भर में एक अच्छी लायब्रेरी है इसमें बहुत मूल्यवान पाण्डुलिपियां और उर्दू, फारसी और अरबी भाषाओं में दुर्लभ पुस्तकें संग्रहीत हैं। लायब्रेरी में, इस समय पुस्तकों का कुल संग्रह 6,13,297 है।

विश्वविद्यालयों के विभिन्न संकायों ने आठ सेमिनारों/सम्मेलनों का आयोजन किया। साउदी अरब, यू.के. और कनाडा से एक-एक प्रोफेसर को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। विश्वविद्यालय ने 17 अक्तूबर को इसके संस्थापक की याद में सर सैयद दिवस के रूप में मनाया।

दिल्ली, विश्वविद्यालय

वर्ष 1985-86 के दौरान विश्वविद्यालय विभागों तथा कालेजों के नियमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का कुल नामांकन 95,186 है। गैर-कालेज महिला छात्रों की नामांकन संख्या 13,175 है जबकि बाह्य छात्र सेल में 16,595 छात्रों को प्राइवेट छात्रों के रूप में पंजीकृत किया। पत्राचार पाठ्यक्रम और सतत् शिक्षा स्कूल में छात्रों का नामांकन 21,355 था। इस प्रकार, विश्वविद्यालय के छात्रों के नामांकन की कुल संख्या 1,46,311 थी यह वर्ष 1984-85 के नामांकन छात्रों की तुलना में 3500 अधिक है। पी.एच.डी. छात्रों के रूप में नामांकन छात्रों की संख्या 2481 है जबकि एम. फिल. पाठ्यक्रमों के लिए 802 छात्रों को दाखिला दिया गया।

विश्वविद्यालय में कुल स्टाफ संख्या निम्नलिखित है :—

प्रोफेसर	228
रीडर	302
लैक्चरर	157
अनुसंधान एसोसिएट	11
कुल	698

विश्वविद्यालय ने जीव-रसायन, इलैक्ट्रानिकी विज्ञान, आनुवंशिकी, सूक्ष्म-विज्ञान और ललित-कलाओं में स्नातकोत्तर जैसे अन्तर विषय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को शुरू किया। इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विपणन में उत्तर स्नातक डिप्लोमा और प्रशासनिक प्रबन्ध में उत्तर-स्नातक डिप्लोमा भी शुरू किया गया।

विश्वविद्यालय के कुछ नये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अर्थात् प्रयुक्त मनोविज्ञान, पर्यावरणात्मक जीव-विज्ञान और सर्टीफिकेट, डिप्लोमा तथा फिनिश तथा स्पेनिश भाषा में उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निश्चय किया है।

वर्ष के दौरान नए अन्तर विषय और प्रयुक्त विज्ञान और प्रौढ़ सतत् शिक्षा एवं प्रसार और पंजाबी विभाग की नई संकाय स्थापित की गई। प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत विश्वविद्यालय का एक इलैक्ट्रानिकी और संचार इंजीनियरी विभाग स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

विश्वविद्यालय ने, व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा दिए जाने वाले कुछ नए पदक, शिक्षावृत्तियां तथा छात्रवृत्तियां भी आरम्भ की हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अनर्राष्ट्रीय खेलों में भाग लेना जारी है। विश्वविद्यालय की कुमारी आशा अग्रवाल ने हांग-कांग में हुई आठवीं अन्तर्राष्ट्रीय महिलाओं की मैराथन में एक स्वर्ण पदक प्राप्त करके विशेष योग्यता प्राप्त की।

प्रोफेसर मुनीस रजा ने विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार सम्भाला।

वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने नेमीफैरट और 73वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस सत्र का आयोजन किया और देश और विदेश से आये प्रख्यात विद्वानों के कई व्याख्यानों का आयोजन किया। विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों को उनके निजी क्षेत्र में काम करने के लिए व्यावसायिक संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया।

हैदराबाद विश्व-विद्यालय

वर्ष 1985-86 के दौरान विश्वविद्यालय ने 928 छात्रों को अधिक दाखिल किया जबकि पिछले वर्ष (1984-85) में वृद्धि 746 की थी। इनमें से, 98 अनुसूचित जाति, 13 अनुसूचित जनजाति और 16 शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणियों के हैं। एम.ए./एम.एस.सी. डिग्री प्रदान किये जाने के लिए 162 छात्रों ने, एम. फिल. के लिए 55 छात्रों ने तथा पी.एच.डी. के लिए 25 छात्रों ने अर्हता प्राप्त की।

वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय की संकाय संख्या 128 की थी, जिसमें 31 प्रोफेसर, 48 रीडर और 49 लेक्चरार थे। कई संकाय सदस्यों ने सक्रिय रूप से सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रमों में भाग लिया और उनमें से कुछ को राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किये गए।

छात्रों को पिछले वर्षों की भांति वित्तीय सहायता के रूप में योग्यता छात्रवृत्तियां, योग्यता एवं साधन छात्रवृत्तियां तथा निशुल्क शिक्षा प्रदान करना जारी रहा। इसके अलावा, 50 छात्रों को 600/- रु. प्रति माह की दर से शिक्षावृत्तियां प्रदान की गईं और वि.अ.आ. किसी नियत समय पर आधारित की योजना के अन्तर्गत 40 विद्यार्थियों ने कनिष्ठ/वरिष्ठ अनुसंधान शिक्षा-वृत्तियों का लाभ उठाया।

वर्ष 1985-86 के दौरान विकासात्मक परियोजनाओं को शुरू किया गया। 300 छात्रों के आवास उपलब्ध कराने के लिए तीन नए छात्रावासों को निर्मित करने का काम पूरा किया गया। 16.18 लाख रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित स्वास्थ्य केन्द्र की इमारत का निर्माण कार्य जोरों पर है। 7.25 लाख रुपये से बनने वाले ओपन एयर थियेटर का निर्माण कार्य शुरू किया गया और यह सुचारू रूप से चल रहा है। वर्ष 1985-86 के दौरान लगभग 31.00 लाख रुपये की लागत से 100 और छात्रों के लिए एक अतिरिक्त छात्रावास बनाने के लिए संस्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस समय चल रही कई परियोजनाओं जैसे प्रशासनिक बिल्डिंग, साइंस स्कूल, काम्पलेक्स, कम्प्यूटर सैन्टर बिल्डिंग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विशेष सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत रसायन स्कूल की इमारत का निर्माण कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

विश्वविद्यालय का पहला दीक्षान्त समारोह दिनांक 6 अप्रैल, 1985 को हुआ। श्री पी. वी. नरसिंह राव, तत्कालीन रक्षा मंत्री जी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। दीक्षान्त समारोह में 1252 छात्रों को डिग्रियां प्रदान की गईं।

जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय

वर्ष 1984-85 से विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में दाखिला, देशभर में 21 केन्द्रों में हुई, एक समान अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर होता है। 15% स्थान अनुसूचित जातियों के लिए, 7.5% अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा 3% शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों के लिए आरक्षित है।

वर्ष 1985-86 में प्रवेश के लिए 16,596 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 7,681 ने वास्तव में परीक्षा दी। और जिन छात्रों को उत्तीर्ण किया गया और दाखिला के योग्य माना गया उनमें से, वास्तव में 856 छात्रों ने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।

इनमें से, 92 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं और 9 शारीरिक रूप से विकलांग हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष के दौरान 1125 छात्रों को डिग्रियां/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र प्रदान किए। इनमें 72 पी.एच.डी., 209 एम. फिल., 149 एम.ए./एम.एस.सी, 689 बी.ए./बी.एस.सी./बी.ए. (आनर्स) डिग्रियां और 6 प्रमाण पत्र/डिप्लोमा शामिल हैं।

तंजानिया के राष्ट्रपति श्री जूलियस के. नैरेरे को डाक्टर आफ ला की डिग्री से सम्मानित किया गया।

संगणक उपयोग कार्यक्रम की एक तीन-वर्षीय मास्टर डिग्री जो संगणक प्रौद्योगिकी में भावी धाराओं को समझने के लिए अपेक्षित सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए तैयार की गई है उसे कम्प्यूटर और सिस्टम साइन्स स्कूल में शुरू किया गया है।

शैक्षणिक वर्ष 1985-86 से पर्यावरण वैज्ञानिक स्कूल में एक द्विवर्षीय एम.एस.सी. जीव-प्रौद्योगिकी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जैनिटिक इंजीनियरी और जीव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में नवीन विकासों से छात्रों को अवगत कराया जाएगा जिसका कि उद्योग, कृषि और औषधियों में महत्वपूर्ण स्थान है।

अगले शैक्षणिक सत्र से विश्वविद्यालय ने गांधी अध्ययन में एम. फिल., स्तर पर "गांधी और विश्व" तथा एम.ए. स्तर पर "गांधी और सर्वोदय" नामक दो नए पाठ्यक्रमों को शुरू करने का निश्चय किया है।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिक उन्नत संगणक प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है। यह अन्तर-विषयक अध्ययनों को और आगे प्रोन्नत करेगा।

एक आनुवंशिक इंजीनियरी तथा जीव-प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन प्रायोजना का काम भारत को सौंपा गया है। यह संस्थान विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित होगा।

प्रौढ़, सतत शिक्षा और प्रसार एकक ने महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों कुम्भकारों (परम्परागत हस्तकरों) और विश्वविद्यालय के वर्ग IV के कर्मचारियों को इस कार्यक्रम में शामिल करके लाभान्वित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भाषा स्कूल के रूसी अध्ययन केन्द्र ने 14 नवम्बर, 1985 को अपनी 20वीं वर्ष गांठ मनाई।

वर्ष के दौरान सरकार और अन्य शैक्षणिकी अनुसंधान एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित पैंतालिस परियोजनाओं का अनुसंधान कार्य प्रगति पर है।

स्पेनिश भाषी देशों के साहित्यिक और सांस्कृतिक पहलुओं और 'हिसपैनिक इन्डो-लेंजिस्ट' की कृति को प्रदर्शित करने के लिए भाषा स्कूल द्वारा स्पेनिश पत्रिका हिसपैनिक होराइजन प्रकाशित की गई है।

नाइट्रोजन यौगिकीकरण परियोजना के लिए प्रयोगशाला हेतु इमारत तैयार हो गई है। 200 छात्रों के लिए छात्रावास से सम्बन्धित निर्माण कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 1985-86 के दौरान विश्वविद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या 3,656 थी। शिक्षकों की कुल संख्या 499 थी जिनमें से 55 प्रोफेसर और 121 रीडर थे।

आलोच्य वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय ने अनेक व्याख्यानों, सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन किया जिनमें भारत और विदेशों के विख्यात शिक्षा-विदों और विद्वानों ने भाग लिया। इनमें से भाषा प्रयोगशाला तकनीकों पर कार्यशाला, प्रमात्रा यांत्रिकी के साठ वर्षों पर राष्ट्रीय सेमिनार, और भारतीय आत्मवाद और राष्ट्रीय एकता पर अखिल भारतीय सेमिनार महत्वपूर्ण थे। वर्ष के दौरान विद्याभवन ने रजत जयन्ती मनाई। विश्वभारती के एक सांस्कृतिक दल ने दक्षिणी-पूर्वी एशिया का दौरा किया और टैगोर के गीतों, नाटकों और नृत्य समारोहों को कई कार्यक्रमों में प्रस्तुत किया। इसने टैगोर द्वारा स्वरचित कलाकृतियों पर एक प्रदर्शनी आयोजित की तथा उनके जीवन पर भी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया।

ग्रामीण पुस्तकालय सेवा ने राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के सहयोग से ग्रामीण लोगों के लाभ के लिए अपने कार्यकलाप जारी रखे। वर्ष के दौरान ग्रामीण प्रसार केन्द्र ने भी सफलतापूर्वक कार्य किया। राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी केन्द्र जो कि वर्ष के दौरान शुरू किया गया है, विश्वभारती द्वारा राष्ट्रीय एकता और सम्बद्धता प्राप्त करना महत्वपूर्ण कदम है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

कुछ संकायों का शैक्षिक सत्र जो समय से पीछे चल रहा था अब लगभग पूर्ण रूप से सामान्य हो गया है। कुछ संकाय अभी भी अपने अन्तराल को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

आलोच्य वर्ष के दौरान संगणक इंजीनियरी, संगणक विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित विभाग स्थापित किए गए।

इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरी विभाग में माइक्रोवेव ट्यूब सम्बन्धी अनुसंधान केन्द्र का समर्थन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किया।

जैव प्रौद्योगिकी स्कूल की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। स्कूल का मुख्य कार्य जैव-प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना तथा विकसित अनुसंधान करना भी है। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय इलैक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी सुविधा प्रायोजना भी निश्चित की। इसके अतिरिक्त, भौतिकी तथा इलैक्ट्रॉनिक इंजीनियरी विभागों को सी.ओ.एस.आई.एस.टी. एवं विशेष सहायता कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के वास्ते विशेष शिक्षा में दो पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए। संगीत-शास्त्र विभाग ने एम.फिल. कार्यक्रम शुरू किया है। विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं की विविध किस्में तैयार की गईं तथा वाणिज्यिक खेती के लिए जारी किया गया। विश्वविद्यालय ने गंगा प्रदूषण सम्बन्धी अनुसंधान कार्य भी ग्रहण किया।

अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के दौरान, विश्वविद्यालय के कुछेक छात्रों ने मास्को में हुए अन्तर्राष्ट्रीय युवा शिविर में भाग लिया।

उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय शिलांग

उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार मेघालय और नागालैण्ड के दो राज्यों में फैल गया है तथा मिजोरम के संघ शासित क्षेत्र शिलांग में इसका मुख्यालय है। इस समय मुख्यालय में 17 स्नातकोत्तर विभाग तथा पांच केन्द्र हैं। जिनमें नागालैंड और मिजोरम परिसरों में प्रत्येक के चार विभाग हैं। मिजोरम परिसर में एक कालेज है तथा नागालैण्ड के कृषि कालेज को कृषि विज्ञान स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया है और प्रिंसिपल को उस स्कूल का डीन बना दिया गया है।

वर्ष के दौरान आनर्स में 292 छात्रों ने तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम पास किया और स्नातकोत्तर तथा अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में 24,752 छात्रों ने दाखिला लिया। 160 शोध अध्येताओं को शोध कार्यक्रमों में दाखिला दिया गया।

शिलांग में मुख्य परिसर का निर्माण कार्य जिसमें अनुमानतः 200 छात्रों के लिए छात्रावास शामिल हैं तथा सेमिनार काम्पलेक्स और गैस्ट हाउस पूर्ण हो गया है। वर्ष के दौरान 41 क्वार्टरों का निर्माण कार्य और सेमिनार काम्पलेक्स तथा गेस्ट हाउस के दो ब्लाक पूरे हो गए ।

विश्वविद्यालय ने शोध अध्येताओं तथा छात्रों के लाभार्थ एक टेलीप्रिन्टर लगाया। वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में एक केन्द्रीय स्कूल की स्थापना की गई। वर्ष के दौरान नागालैण्ड में दो कालेजों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया और कुल सम्बद्ध कालेजों की संख्या बढ़कर 41 हो गई ।

विश्वविद्यालय ने निम्नलिखित सम्मेलन/सेमिनार आयोजित की :—

(1) 14-16 नवम्बर, 1985 तक जीवन विज्ञान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी ।

(2) 2-8 दिसम्बर, 1985 तक निवेश-उत्पादन एसोसिएशन (अंतर्राष्ट्रीय) का 20 वां शताब्दी सम्मेलन।

(3) 10-12 दिसम्बर, 1985 तक उच्च शिक्षा में शिक्षा नीति सम्बन्धी राष्ट्रीय सेमिनार ।

(4) 21-23 नवम्बर, 1985 तक आर.एस.आई.सी. की कार्यशाला।

इन्दिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय विधेयक अगस्त, 1985 में संसद द्वारा पारित किया गया । यह अधिनियम 20 सितम्बर, 1985 से लागू हो गया । प्रोफेसर जी. राम रेड्डी ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला । शैक्षिक परामर्शदाता (भारत) लिमिटिड द्वारा विश्वविद्यालय की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर दी गई है। विश्वविद्यालय के लिए दक्षिणी दिल्ली में 100 एकड़ भूमि मिल गई है। 19-11-1985 को प्रधानमंत्री द्वारा भवन के निर्माणार्थ शिलान्यास किया गया। एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला, जिसमें विश्व के प्रमुख खुले विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया, 20-22 नवम्बर, 1985 तक परियोजना रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई ।

विश्वविद्यालय अपने शैक्षिक कार्यक्रमों की तैयारी के लिए स्टाफ की प्रारंभिक भर्ती कर रहा है। कार्यक्रमों का प्रथम बैच 1986 के मध्य से पहले ही घोषित कर दिया जाएगा। जब तक इसके स्थायी स्थल पर निर्माण कार्य पूरा नहीं होता तब तक विश्वविद्यालय किराए के स्थान में कार्य करता रहेगा ।

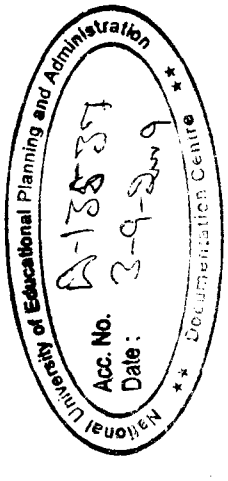

तैयारी कार्य में विश्वविद्यालय के लिए प्रारंभिक अवस्थापना का प्रावधान शामिल है, जिसमें भवनों का निर्माण, उपस्कर की खरीद, शैक्षणिक सामग्री तैयार करना तथा पूरे देश में अध्ययन केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित करना शामिल है।

पांडिचेरी विश्वविद्यालय

सितम्बर, 1985 में संसद द्वारा पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था जिसके द्वारा पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में पांडिचेरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई । यह अधिनियम 16 अक्तूबर, 1985 से लागू हो गया। उसी दिन, डा. के. बैंकटसुब्रामनियम ने इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति के रूप में कार्यभार संभाला। विश्वविद्यालय ने, पांडिचेरी में अपना शिविर कार्यालय स्थापित किया है। विश्वविद्यालय, अपेक्षित भूमि प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है और आशा है कि जून, 1986 तक विश्वविद्यालय को 1,234 एकड़ भूमि प्राप्त हो जाएगी। पांडिचेरी संघीय क्षेत्र के नौ कालेज विश्वविद्यालय के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं ।

7—759 Deptt. of Edu./85

ग. विशिष्ट अनुसंधान संगठन

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला 1965 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था इसे सरकार द्वारा पूर्ण राशि प्रदान की गई थी। इसका उद्देश्य मूल-भूत विषयों और जीवन और चिन्तन की समस्याओं पर निष्पक्ष और रचनात्मक चर्चा करना है। संस्थान एक आवासीय अनुसंधान केन्द्र है तथा विशेष रूप से मानविकी के चुनिन्दा विषयों, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में शैक्षिक अनुसंधान के लिए अनुकूल वातावरण की व्यवस्था करता है।

2. संस्थान ने मई, 1984 में अपने शैक्षणिक कार्यकलाप फिर से शुरू किए और इस समय इसमें 15 फैलों हैं। 1985-86 के लिए शिक्षावृत्ति प्रदान की गई है और शीतकालीन अवकाश के पश्चात दस फैलों आने की सम्भावना है।

3. संस्थान ने 20 से 27 मार्च, 1985 के दौरान "वैकल्पिक आर्थिक ढांचा" तथा 4 से 9 नवम्बर, 1985 को "निजी और सार्वजनिक जीवन में आवश्यकताओं और साधन का स्थान" से सम्बन्धित दो सेमिनार आयोजित किए। "ज्ञान की खोज और मानव की सुख-शान्ति" से सम्बन्धित सेमिनार मार्च, 1986 में होगा। सेमिनार के कार्य विवरण संस्थान द्वारा कार्रवाई खण्ड के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

4. फैलों का सामूहिक चर्चा बैठकों भाग लेना शैक्षणिक कार्यकलापों की एक प्रमुख विशेषता है। ऐसी बैठके सप्ताह में एक बार होती हैं और इससे एक दूसरे अत्यन्त प्रभावित होते हैं।

5. संस्थान ने अपनी पत्रिका निकालने का निर्णय किया है और पहला अंक मार्च, 1986 में निकालने की आशा है।

6. लगभग 22 पाण्डुलिपियों का मूल्यांकन किया गया है तथा उनमें से कुछ चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रकाशित किए जाएगें।

भारतीय दर्शन अनुसन्धान परिषद

भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद ने, जो मार्च 1977 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत की गई थी प्रोफेसर डी. पी. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में वास्तव में वास्तव में जुलाई 1981 से कार्य करना प्रारम्भ किया। परिषद की स्थापना मुख्यत: समय-समय पर दर्शन शास्त्र में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करने, दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों को प्रायोजित करने अथवा उनके लिए सहायता देने, अनुसंधान कार्य में लगी संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों को सहायता देने, तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन प्रदान करने, अनुसंधान कार्यकलापों को समन्वित करने तथा ऐसे सभी उपाय करने के लिए की गई है जिन्हें दर्शन शास्त्र तथा सम्बद्ध विषयों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक समझा जाए।

वर्ष 1985-86 के दौरान परिषद ने एक राष्ट्रीय फैलोशिप, तीन वरिष्ठ फैलोशिप और आठ सामान्य फैलोशिप, प्रदान करना जारी रखा और वरिष्ठ तथा सामान्य फैलोशिप दोनों वर्गों में से प्रत्येक में तीन नई फैलोशिप प्रदान की।

परिषद ने अपने शैक्षणिक केन्द्र, लखनऊ में कुछेक मासिक सेमिनारों के अतिरिक्त लगभग 10 सेमिनार, कार्यशालाएं इत्यादि आयोजित की तथा उनके लिए सहायता प्रदान की। परिषद ने शैक्षणिक प्रकाशनों सहित अपनी विभिन्न विद्वतापूर्ण प्रायोजनाएं भी जारी रखी जिनमें से छः 1985-86 के दौरान पूर्ण कर ली गई।

परिषद ने देश के युवा अध्येताओं में प्रतिभा का विकास करने के वास्ते "युवा और 21वीं शताब्दी" नामक विषय पर युवा अध्येताओं के लिए एक सेमिनार के पश्चात एक अखिल भारतीय निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की।

वार्षिक व्याख्यान कार्यक्रम के अन्तर्गत 1985-86 के दौरान हेलसिंकी (फिनलैंड) के प्रोफेसर जार्ज हैनारिक वान राइट तथा वाराणसी के प्रोफेसर टी. आर. वी. मूर्ति को व्याख्यान देने के लिए चुना गया।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारत और सोवियत रूस के बीच दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में पहला सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम 1985-86 के दौरान कार्यान्वियन के लिए प्रारम्भ हुआ।

परिषद ने 17 अध्येताओं को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सेमिनार इत्यादि में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की।

1985-86 के दौरान आई. सी. पी. आर. पत्रिका की प्रति निकाली गई।

परिषद ने बटलर प्लेस, लखनऊ में विभिन्न प्रदर्शनियां प्रदर्शित करना जारी रखा।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, ऐतिहासिक अनुसंधान को उचित निदेश देने तथा इतिहास लेखन के वस्तुपरक तथा वैज्ञानिक प्रोत्साहन एवं प्रेरणा के लिए 1972 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित कया गया। परिषद इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यक्रम प्रायोजित करके जिनमें सामान्य रूप से कला, पुरातत्व और दर्शन-शास्त्र का इतिहास शामिल है तथा विशेष रूप से उपेक्षित क्षेत्रों जैसे कि सामाजिक और आर्थिक इतिहास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास, सैनिक इतिहास तथा बौद्धिक इतिहास इत्यादि में ऐतिहासिक अनुसंधान के विकास को प्रोत्साहन देकर उपर्युक्त लक्ष्य प्राप्त कर रहा है।

आलोच्य अवधि के दौरान, परिषद ने 22 अनुसंधान परियोजनाएं, 115 फैलोशिप और 66 अध्ययन एवं यात्रा अनुदान की स्वीकृति दी। 32 अनुसंधान विनिबंधों, मोनोग्राफ और पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी। 35 व्यावसायिक संगठनों जैसे कि दक्षिण भारतीय इतिहास कांग्रेस, भारत इतिहास कांग्रेस, भारतीय पुरातत्व सोसायटी, ऐतिहासिक अध्ययन संस्थान, भारतीय मुद्रा-विषयक सोसायटी इत्यादि को सेमिनार/संगोष्ठी इत्यादि आयोजित करने के लिए अनुदान की मंजूरी दी। और अनुसंधान क्षेत्रों को जानने के लिए कांग्रेस शताब्दी समारोह से सम्बद्ध एक पैनल चर्चा आयोजित की गई।

ऐतिहासिक अनुसंधान और लेखन की सुविधा के लिए स्त्रोत सामग्री के प्रकाशन के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक कदम के रूप में परिषद ने एक व्यापक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है जिसमें भारतीय इतिहास के सभी कालों को शामिल करने वाले स्रोतों के कई खण्डों के संकलन की परिकल्पना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत में राष्ट्रीकों का आन्दोलन (1919-20), (1898–1902) और (1922–24) से सम्बन्धित प्रलेख के तीन खण्ड प्रकाशनार्थ प्रैस को भेजे गए। प्रोफेसर वी. एन. दत्ता द्वारा सम्पादित एक खण्ड प्रकाशित किया गया। मध्यावधि स्रोत कार्यक्रम के अन्तर्गत **राज तंरगिणी** और **रूसी दस्तावेजों** के अंग्रेजी अनुवाद के साथ **मुगल प्रलेखों का सूची पत्र** (1526–1627) और **मराठी प्रलेखों का सूची पत्र** का संकलन किया गया तथा शीघ्र ही प्रैस को भेजा जाएगा।

प्रकाशन कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद ने डा. आर. सी. मजूमदार की **द क्लासिकल एज** का हिन्दी संस्करण तथा के. ए. एन. शास्त्री के **चोला राजगान का** उर्दू संस्करण, **मुखरोज और कन्नोज के शिलालेख और तमिलनाडु तथा केरल राज्यों में स्थलाकृतिक शिला लेख** निकाले। विशेष प्रायोजना **स्वतन्त्रता की ओर** के अन्तर्गत दस्तावेजों का प्रथम खण्ड जो जनवरी से दिसम्बर 1937 तक की अवधि तक है, को भी प्रकाशित किया गया इसके अतिरिक्त परिषद ने प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 20 शोध निबन्ध भी प्रकाशित किए गए। परिषद ने 1984-85 में पुस्तकालय में खरीदी अतिरिक्त सामग्री की अधिग्रहण सूची भी प्रकाशित की तथा भारतीय **इतिहास में तत्काल जानकारी सेवा (करेंट अवेयरनैस सर्विस)** प्रकाशित की। **भारतीय ऐतिहासिक समीक्षा** खण्ड VIII (सं. 1-2) प्रकाशित किए गए तथा खण्ड IX प्रैस को भेज दिया गया है।

भारत और सोवियत रूस के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद ने अप्रैल, 1985 में प्राचीन काल से मध्यावधि तक संस्कृति: समाज के आर्थिक और सामाजिक संगठन की समस्या से सम्बन्धित एक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसमें सोवियत संघ से आठ इतिहासज्ञों ने भाग लिया। इन्डो-जर्मन जनवादी गणराज्य और इन्डो-बलोरियन सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत परिषद ने जुलाई 1985 को बर्लिन में तथा नवम्बर, 1985 को सोफिया में हुए सेमिनार में भाग लेने के लिए भारतीय इतिहासज्ञों को भेजा।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद

देश में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को प्रोन्नत करने के लिए भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना सन् 1969 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी।

वर्ष के दौरान परिषद ने 21 अनुसंधान संस्थानों को सहायता देना जारी रखा। परिषद ने छ: क्षेत्रीय केन्द्रों को सहायता देना भी जारी रखा।

दिसम्बर 1985 तक परिषद ने 56 अनुसंधान परियोजनाओं के वास्ते अनुसंधान अनुदान की स्वीकृति दी। परिषद को पहले अनुमोदित 36 परियोजनाओं की पूर्ण रिपोर्ट प्राप्त हुई। महिलाओं के अध्ययन से सम्बन्धित अनुसंधान कार्यक्रम को पुन: सक्रिय किया गया तथा महिलाओं का कार्य एवं पारिवारिक नीतियां इससे सम्बंन्धित सामान्य विषय पर आठ अनुसंधान परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई।

परिषद सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अध्येताओं को विभिन्न प्रकार की शिक्षावृत्तियां प्रदान करती है। दिसम्बर, 1985 तक 86 नवीन पुरस्कार तथा 37 आकस्मिक अनुदान संस्वीकृत किए गए।

3080 प्रकाशन जिनमें 300 शोध प्रबन्ध तथा 598 शोध रिपोर्ट शामिल है प्रकाशित किए गए। 163 पी. एच. डी. अध्येताओं को उनके शोध कार्य हेतु सामग्री संचय करने के लिए पुस्तकालयों के निरीक्षणार्थ अध्ययन अनुदान प्रदान किए गए। 18 ग्रंथ विज्ञानीय तथा प्रलेखन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। अनुलिपिय रूप की 27 प्रलेखन सूचियों का संकलन हो चुका है तथा देश और विदेश में विभिन्न पुस्तकालयों और संस्थाओं को वितरित कर दी गई है।

वर्ष के दौरान, परिषद ने 4 प्रकाशन प्रकाशित किये हैं। वर्ष 1985-86 के दौरान, प्रकाशन अनुदान की योजना के अंतर्गत, प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 16 शोध प्रबन्ध तथा 11 शोध रिपोर्ट अनुमोदित कर दी गई है। वर्ष के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत, छ: पुस्तकें प्रकाशित की गई।

परिषद ने भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, पब्लिक प्रशासन, समाज शास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों में पत्रिकाओं के 11 अंक प्रकाशित किए।

आंकड़े अभिलेखागार ने आई. सी. एस. एस. आर. निधिबद्ध परियोजनाओं में से उत्पन्न 10 आंकड़े, सैट प्रकाशित किए। मशीन सुपाठ्य रूप में 17 आंकड़े सैट आयोजित किए गए और उनकी पुन: प्राप्ति और माध्यमिक विश्लेषणों को सुकर बनाने के लिए प्रलेख दिए।

वर्ष के दौरान, परिषद ने, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेश जाने हेतु 45 भारतीय अध्येताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की।

तीन फ्रेन्च अध्येताओं ने भारत का दौरा किया और भारत फ्रेन्च सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत 10 भारतीय अध्येताओं को फ्रांस के दौरे के लिए भेजा गया। परिषद ने भी भारतीय अध्येताओं के साथ व्याख्यान देने और विचार विमर्श करने के लिए अनेक विशिष्ट विदेशी अध्येताओं के दौरे प्रायोजित किए।

समाज विज्ञान में सहयोग के लिए भारत-सोवियत संयुक्त आयोग के अंतर्गत, दो सोवियत शिक्षा शास्त्रीयों ने संयुक्त आयोग के अंतर्गत चल रहे कार्यकलापों पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया।

भारत-डच वैकल्पिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम (भा. ड. वै. वि. का.) के अन्तर्गत, पांच भारतीय अध्येताओं ने हालेण्ड का दौरा किया और एक डच अध्येता ने भारत का दौरा किया। भा. ड. वै. वि. का. सम्बन्धी संयुक्त समिति अनुमोदित की गई और सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दी गई जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों से सम्बन्धित 10 अनुसंधान परियोजनाएं हैं :—

(1) नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था
(2) तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य एशियाई ग्रामीण परिवर्तन
(3) यूरोपीय सोसायटियों की आधुनिक प्रवृत्तियां

सरकार द्वारा नौ परियोजनाएं अनुमोदित कर दी गई हैं और एक विचाराधीन है।

अंतर्राष्ट्रीय समाज विज्ञान संगठन संघ के सातवें महा सम्मेलन की सह-प्रायोजित परिषद, दिसम्बर, 1985 में नई दिल्ली में आयोजित की गई। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय और यूनेस्को के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त विकसित और विकासशील देशों से अनेक भाग लेने वालों ने इस सम्मेलन में भाग लिया।

अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थाओं के लिए अनुदान योजना

इस योजना का उद्देश्य कुछ स्वैच्छिक संगठनों को जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं और विश्वविद्यालय शिक्षा की परम्परागत पद्धति से अलग हटकर शिक्षा कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं, उन्हें सहायता देना है। यह योजना उन कुछेक संगठनों की सहायता करती है जो विश्वविद्यालय पद्धति में नहीं आते हैं और न ही उनके रख रखाव और विकास के लिए संसाधन उत्पन्न करने में समर्थ हैं परन्तु उपयोगी कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं जो विशेषकर ग्रामीण समुदाय के रुचि के हैं अथवा जो स्वरूप में नवीन हैं। इस समय, इस योजना के अन्तर्गत ऐसी पांच संस्थाओं अर्थात श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी, कन्या गुरूकुल महाविद्यालय, देहरादून, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूणे, लोक भारती, सनोसरा, और श्री अरविन्द अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, आरोविल, को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

यह निर्णय किया गया है कि कन्या गुरूकुल महाविद्यालय की जमा 2 यूनिट (डिग्री पाठ्यक्रम का तीसरा और चौथा वर्ष) को एक संघटक कालेज के रूप में घोषित किया जाए और गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार के दूसरे कैम्पस को एक समझे जाने वाला विश्वविद्यालय घोषित किया जाए। अतः अब से दूसरे कैम्पस का अनुरक्षण तथा विकास-व्यय विश्व.अनु.आ. के अनुदानों में से विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

घ. द्विपक्षीय/विदेशी सहयोग कार्यक्रम

शास्त्री भारत–कनाडा, संस्थान

शास्त्री भारत–कनाडा संस्थान, कनाडा में संस्थापित एक स्वायत्त स्वैच्छिक संगठन है जिसने भारत सरकार के साथ एक सद्भावना ज्ञापन के अनुसरण में नवम्बर, 1968 में भारत में अपने कार्यकलाप शुरू किए। संस्थान के साथ अनुबन्ध का पुनरीक्षण 31 मार्च, 1989 को समाप्त होने वाली अवधि तक कर दिया गया है। संस्थान का उद्देश्य, अध्येताओं तथा छात्रों के बीच एक दूसरे देश का ज्ञान की प्रगति तथा सूझबूझ को प्रोत्साहित करने तथा सहायता देने के प्रयोजन के लिए कार्य करता है।

संस्थान ने, वर्ष 1985-86 के दौरान, कनाडा के 7 अध्येताओं को मानविकी, भारतीय भाषाएं सीखने और प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए फैलोशिप प्रदान की।

भारत में वर्कले व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, औषध, विधि, कृषि और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में अध्ययन/शोध के लिए 13 अध्येता आए।

भारतीय अध्ययनों का अमरीकी संस्थान

यह संस्थान भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन में रुचि रखने वाले अमेरिकी कालेजों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित किया गया एक सहकारी संगठन है। संस्थान ने 1962 में कार्य करना शुरू किया और शैक्षिक वर्ष 1985-86 के दौरान 154 अध्येताओं को सामाजिक-विज्ञानों, मानविकियों, और भाषा प्रशिक्षण आदि में अनुसंधान करने के लिए फैलोशिप (संकाय/जूनियर/तदर्थ अल्पकालिक और भाषा) प्रदान की।

भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान नई दिल्ली

भारत में संयुक्त राज्य शैक्षिक प्रतिष्ठान की स्थापना, भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका सरकार के बीच हुए द्विपक्षीय करार के अंतर्गत फरवरी, 1950 में की गई थी। इसका उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान और व्यावसायिक प्रतिभा का अदान-प्रदान करके परस्पर सूझबूझ को प्रोत्साहित करना है, जिसके लिए धन की व्यवस्था संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार द्वारा की गई थी। प्रतिष्ठान के कार्यक्रम के अंतर्गत डाक्टोरल और उत्तर-डाक्टोरल अनुसंधान के लिए और भारतीय विश्वविद्यालयों में अतिथि प्रोफेसरों के रूप में कार्य करने के लिए 1985-86 के दौरान 66 अमरीकी अध्येता/छात्र भारत आए। इसी प्रकार, अमरीका में अध्ययन/अनुसंधान और अल्पकालिक सेमिनारों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए लगभग 135 भारतीय अध्येताओं को व्याख्यान/अनुसंधान/छात्र फैलोशिप और यात्रा अनुदान प्रदान किए ।

अमरीका के प्रोफेसरों, अध्यापकों, शैक्षिक प्रशासकों सहित 133 शिक्षाविदों के आठ अल्पकालिक दलों ने भारत में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में नवीनतम घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से थोड़े समय के लिए भारत का दौरा किया। इन दलों के कार्यक्रम भारतीय विश्वविद्यालयों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं ।

अमरीकी अध्ययन अनुसंधान केन्द्र, हैदराबाद

अमरीकी अध्ययन अनुसंधान केन्द्र हैदराबाद, अमरीकी अध्ययनों में भारतीय अध्येताओं और छात्रों को सुविधाएं प्रदान करता है। केन्द्र को निकटवर्ती एशियाई देशों के अध्येताओं को सुविधा प्रदान करने की भी अनुमति दे दी गई जिससे कि वे केन्द्र में इन सुविधाओं का लाभ उठा सके बशर्ते कि भारत में अमरीकी रुपयों की निधियों का इस प्रयोजन के लिए उपयोग न किया जाए ।

अलग-अलग अनुसंधान के लिए भारत का दौरा करने वाले विदेशी विद्वान

उपर्युक्त विदेशी एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित विदेशी विद्वानों के अलावा, स्वयं या अपने-अपने विश्वविद्यालयों से अनुदानों के आधार पर डाक्टोरल, और उत्तर-डाक्टोरल अनुसंधान कार्य करने के लिए विभिन्न देशों से 63 अनुसंधान अध्येताओं के आवेदन पत्र प्राप्त हुए ।

ङ. अन्य कार्यकलाप

विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापकों के वेतनमान संशोधित करना

केन्द्रीय सरकार ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में पुस्तकाध्यक्षों और शारीरिक शिक्षा निदेशकों/प्रशिक्षकों के वेतनमान संशोधित करने के सम्बन्ध में अपने पिछले निर्णय की समीक्षा की और उन्हें बढ़ाने के लिए सहमत हो गई। ये बढ़े हुए वेतनमान अब अध्यापकों के बराबर हैं और 1-4-1980 से लागू हो गए हैं। इस निर्णय की सूचना सभी राज्य सरकारों को 1982 में दे दी गई थी। राज्य सरकारों को 1-4-80 से 31-3-1985 तक की अवधि के लिए बढ़े हुए वेतनमान लागू करने पर होने वाले अतिरिक्त खर्चों के 80% तक की वित्तीय सहायता की भी पेशकश की थी । इस निर्याण के अनुसरण में अभी तक पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार वेतनमान बढ़ाने के लिए सहमत हुई हैं, इसी बीच अध्यापकों के वेतनमान संशोधित करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से प्राप्त केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में बकाया दावों को भी केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जा रहा है।

डा. जाकिर हुसैन कालेज, दिल्ली

डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज, (भूतपूर्व दिल्ली कालेज) के प्रबन्ध और रखरखाव की जिम्मेदारी सम्भालने के लिए सन् 1973 में डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास

की स्थापना की गई । कालेज जो दिल्ली विश्वविद्यालय का एक कालेज है, अनुरक्षण खर्च विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और न्यास द्वारा 95:5 के अनुपात में वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के लिए आयोग द्वारा निर्धारित सहायता पद्धति के अनुसार कालेज के विकास खर्च के लिए मंजूरी देता है। ऐसे विकास खर्च के लिए आनुपातिक अंशदान न्यास द्वारा वहन किया जाता है क्योंकि न्यास के अपने कोई संसाधन नहीं है, इसलिए उपरोक्त खर्च मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदानों में से वहन किया जाता है। इन अनुदानों में न्यास का प्रशासनिक खर्च शामिल है ।

न्यास द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय कालेज को इसके वर्तमान परिसर (अजमेरी गेट) से मिन्टो रोड़ क्षेत्र में ले जाना है। आवश्यक भूमि प्राप्त कर ली गई है और नए भवनों का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। विज्ञान खंड का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। आगामी शैक्षिक सत्र शुरू होने से पूर्व रासायनिक शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति विज्ञान और मनोविज्ञान विभाग नए भवन में पहुंच जाएंगे। शैक्षिक और प्रशासनिक खण्ड का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालय समझी जाने वाली एक संस्था है। इसे अपने विश्वविद्यालय खण्ड के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आवर्ती और अनावर्ती अनुदान प्राप्त होता है। जहां तक इसके गैर-विश्वविद्यालय खंण्ड का सम्बन्ध है इसे भारत सरकार से अनुदान प्राप्त होते हैं ।

जामिया मिलिया इस्लामिया के सीनियर माध्यमिक स्कूलों को सुदृढ़ बनाया गया है और +2 स्तर पर वाणिज्य तथा इंजीनियरी विषयों के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। स्कूल की 9वीं कक्षा में विकलांग बच्चों के लिए एक समाकलित योजना शुरू कर दी गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने वर्तमान स्कूल भवन का विस्तार शुरू कर दिया है।

प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ने इलेक्ट्रोनिक्स में डिप्लोमा का एक नया पाठ्यक्रम शुरू कर दिया है।

भारतीय विश्व-विद्यालय एसोसिएशन

भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन देश में विश्वविद्यालयों का एक स्वैच्छिक संघीय निकाय है। यह अनुभवों के आदान-प्रदान और उनके लिए समान हितों वाले क्षेत्रों पर विचार करने, मिलजुल कर काम करने के लिए विश्वविद्यालय समुदाय के लिए मंच की व्यवस्था करती है। यह उच्च शिक्षा के विषय में एक सूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करती है और अनेकों प्रकाशन, शोध पत्र, पुस्तकें तथा पत्रिकाएं प्रकाशित करती है।

एसोसिएशन की अधिकांश वित्त व्यवस्था इसके द्वारा एकत्र की गई सदस्यता शुल्क से की जाती है। सरकार इसके रख रखाव के खर्च के लिए अनुदान स्वीकृत करती रही है। एसोसिएशन ने भी विश्वविद्यालय पद्धति से सम्बन्धित अनुसंधान कार्यकलाप शुरू करने के लिए अनुसंधान सैलों के लिए अनुदान संस्वीकृत किए है। अनुसंधान सैल ने परीक्षा सुधार, स्तरीय रिपोर्ट तैयार करने उच्च शिक्षा की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धी मोनोग्राफों और भा. प्रौ. सं. स्नातकों की व्यवस्था तथा आर्थिक विकास, उच्च शिक्षा आदि में क्षति तथा अवरोध सम्बन्धी अध्ययन आरम्भ कर दिए है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उच्च शिक्षा तथा विश्वविद्यालय वित्तीय सहायता हेतु अवस्थापना सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण स्तरीय पेपर प्रकाशित होने वाला है। एसोसिएशन का प्रश्न बैंकों पर कुछ लोक प्रिय पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद कार्य आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार के अनुदानों तथा सदस्य-विश्वविद्यालयों के अंशदान के अनुदानों के सहयोग से इसका भवन पूरा हो जाने पर एसोसिएशन का विदेशी छात्रों और अनेक अन्य कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए सूचना तथा मार्गदर्शन सेल स्थापित करने का प्रस्ताव है।

अपने खेल प्रोन्नति प्रयासों के अतिरिक्त, एसोसिएशन ने विश्वविद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यकलापों को प्रोन्नत करना शुरू कर दिया है। इसने युवा कार्य तथा खेल विभाग और अन्य संगठनों के सहयोग से 1985 में नामी प्रतियोगिता के आयोजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजना

विख्यात शिक्षाविदों और विद्वानों को अपने-अपने शिक्षा विषयों में ज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान की मान्यता स्वरूप राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजना 1949 में शुरू की गई थी। 1965 से 1981 के बीच किसी राष्ट्रीय प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं की गई थी। 1981 में एक विख्यात पक्षी-विज्ञानी डा. सलीम अली और दर्शनशास्त्र के एक विख्यात प्रोफेसर डा. टी.एम.पी. महादेवन को प्रोफेसरशिप प्रदान की गई। प्रोफेसर वी.के.आर.वी.राव को 3 फरवरी, 1984 से राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। 5 नवम्बर, 1983 को प्रोफेसर महादेवन की मृत्यु हो गई। डा. दुर्गा दास को संवैधानिक कानून में राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। एक और नियुक्ति विचाराधीन है। इस समय केवल दो ही राष्ट्रीय प्रोफेसर हैं।

विश्वविद्यालयों के प्रमुख विषयों में व्यावसायिक संगठन को वित्तीय सहायता की योजना

शारीरिक तथा प्राकृतिक विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकियों के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यावसायिक संगठनों को सम्मेलन तथा सेमिनार आदि आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक नई योजना को छठी योजना में अंतिम रूप दे दिया गया। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों में बेहतर संचार के अवसर उपलब्ध करना है जो अध्यापन, अनुसंधान या विद्वता के अध्ययन में स्वतन्त्र रूप से लगे हुए हैं ताकि वे आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान-प्रदान कर सकें, नए विकासों पर चर्चा कर सकें और नई-नई खोजों में हिस्सा बटाकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान सात संगठनों को वित्तीय सहायता संस्वीकृत कर दी गई है।

पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ़

1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धाराओं के अन्तर्गत पंजाब विश्वविद्यालय को एक अन्तर-राज्य निकाय निगम के रूप में घोषित किया गया। इस समय विश्वविद्यालय का अनुरक्षण खर्च में 40:60 के अनुपात से पंजाब सरकार तथा संघीय क्षेत्र चण्डीगढ़ द्वारा वहन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के विकास खर्च को वि. अनु. आ. द्वारा संस्वीकृत अनुदानों से आंशिक रूप में वहन किया जाता है। इस प्रकार के अनुदानों के बराबर हिस्से और विकास कार्यक्रमों से संबंधित व्यय जो आयोग द्वारा अनुदान पाने के योग्य नहीं है, केन्द्रीय सरकार द्वारा इसको संस्वीकृत वार्षिक ऋण से विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 1985-86 के दौरान इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय को 50 लाख रुपये का ऋण संस्वीकृत किया गया।

अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए विशेष सैल

यह सैल, कालेजों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण से सम्बन्धित नीति की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। यह सैल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुक्त और सांसद को आरक्षण के सम्बन्ध में सूचना भेजने के लिए सम्पर्क एकक के रूप में भी कार्य करता है। कालेजों और विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अध्यापकों/छात्रों/कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को भी सैल द्वारा जांच की जाती है और उन्हें आवश्यक होने पर, सम्बंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

अध्याय 4

तकनीकी शिक्षा

भारत में तकनीकी शिक्षा का विस्तार देश की समाजार्थिक प्रगति को बढ़ाने के लिए किया गया है और आज भारत के पास विभिन्न स्तरों के इंजीनियरों और तकनीशियनों का एक बहुत बड़ा निकाय है। यह विस्तार और विविधता पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए किया जा रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित पर जोर दिया गया है :– (क) विद्यमान सुविधाओं का अधिकतम प्रयोग, (ख) उनका सुदृढ़ीकरण, (ग) कमजोर क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार करना, (घ) उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अवस्थापना का सृजन (ङ) तकनीकी शिक्षा की कोटि और स्तरों में सुधार (च) देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति के एक साधन के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करने तथा उसे लागू करने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देना इत्यादि उपरोक्त क्षेत्रों में आरंभ किए गए कार्यकलाप सातवीं पंचवर्षीय योजना में जारी रहेंगे। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए बल दिया जाएगा : (1) तकनीकी संस्थाओं में अप्रचलन को दूर करने और उनका आधुनिकीकरण करना; (2) ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना; (3) व्यावसायीकरण (4) तकनीकी शिक्षा और विकासात्मक क्षेत्रों में संस्थागत संयोजन, (5) तकनीकी संस्थाओं में संगणक सुविधाओं को उपलब्ध करना (6) क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना।

आलोच्य अवधि के दौरान स्वीकृत योजनाओं के अंतर्गत और केन्द्रीय संस्थाओं के कार्यकलाप निम्नलिखित हैं :–

कोटि सुधार कार्यक्रम

देश में विभिन्न तकनीकी संस्थाओं में दी जा रही तकनीकी शिक्षा की कोटि और स्तरों में सुधार करने के उद्देश्य से वर्ष 1970-71 में कोटि सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है :–

(1) संकाय विकास

(क) एम.टेक. कार्यक्रम और डाक्टोरल कार्यक्रम,

(ख) कोटि सुधार कार्यक्रम केन्द्र में अल्पकालिक पाठ्यक्रम।

(ग) भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी के माध्यम से ग्रीष्म स्कूल कार्यक्रम।

(2) पाठ्यचर्या विकास जिसमें शिक्षण सामग्री पाठ्यपुस्तकें तैयार करना प्रयोगशाला का विकास करना शामिल है और

(3) इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निकों के शिक्षकों को औद्योगिक संगठन में व्यावहारिक प्रशिक्षण।

एम.टेक. और डाक्टोरल कार्यक्रम, 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, रूड़की विश्वविद्यालय, भारतीय खनन स्कूल धनबाद, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, कुछ इंजीनियरी कालेजों, ए.सी. प्रौद्योगिकी कालेज, गुइंडी, मद्रास और जादवपुर विश्वविद्यालय में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। अल्पकालिक पाठ्यक्रमों से संबंधित कार्यक्रम डिग्री स्तर के शिक्षकों तथा चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं और इंजीनियरी तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद की डिप्लोमा स्तर की संस्थाओं के लिए उपर्युक्त चुने हुए केन्द्रों के माध्यम से लागू किए जाते हैं। उद्योग में अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वार

8 —759 Deptt. of Edu./85

और ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन स्कूल भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी द्वारा संचालित किए जाते हैं।

वर्ष 1984-85 तक 940 शिक्षकों को एम.टेक. पाठ्यक्रमों और 1000 शिक्षकों को पी.एच.डी. कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसी प्रकार कोटि सुधार कार्यक्रमों केन्द्रों में डिग्री स्तर के 700 अल्पकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए जिसमें 10,000 शिक्षकों ने भाग लिया और डिप्लोमा स्तर पर 1200 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 22,000 शिक्षकों ने भाग लिया। उद्योग संबंधी अल्पकालीन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1984-85 तक डिग्री स्तर पर 1800 शिक्षक और डिप्लोमा स्तर तक 4000 शिक्षक लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी ने 1100 ग्रीष्म/शीतकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें 20,000 शिक्षकों ने भाग लिया।

यह योजना 1985-86 में जारी रही। आलोच्य वर्ष के दौरान एम.टेक. के लिए 100 शिक्षकों और पी.एच.डी. के लिए 150 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था। यह पिछले वर्षों से प्रशिक्षण पर रहे व्यक्तियों के अतिरिक्त था। ग्रीष्मकालीन स्कूल कार्यक्रमों से 1800 शिक्षकों के लाभान्वित होने की आशा है। विगत की भांति 14 दलों द्वारा कोटि सुधार कार्यक्रम केन्द्रों पर पाठ्यचर्या विकास कार्यक्रम आयोजित किए। आशा है कि उद्योगों में अल्पकालिक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम के और सार्थक रूप में सहायक होंगी और इसके साथ-साथ अपेक्षित जनशक्ति भी उत्पन्न किए जाएंगे।

राष्ट्रीय तकनीकी जन-शक्ति सूचना प्रणाली

यह योजना वर्ष 1983-84 में सतत रूप से अद्यतन लाभप्रद जनशक्ति सूचना प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से शुरू की गई थी ताकि संबंधित शैक्षिक प्राधिकरण इंजीनियरों और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास के क्षेत्रों का पूर्वानुमान लगा सकें और देश में तकनीकी जन-शक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रणालीबद्ध आधार पर योजना तैयार कर सके। इस प्रणाली के अंतर्गत प्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान में एक लीड सेन्टर और चुने गए इंजीनियरी कालेजों तथा प्रौद्योगिकीय संस्थाओं/प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड में 17 प्रमुख केन्द्र शामिल हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान इस प्रणाली की अच्छी शुरुआत हुई है और आशा है कि यह तकनीकी शिक्षा के विकास की समुचित योजना में अत्यन्त और सार्थक रूप में सहायक होगी और इसके साथ-साथ अपेक्षित जनशक्ति भी उत्पन्न होगी।

उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम

यह योजना वर्ष 1981-82 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य डिप्लोमाधारियों के लिए प्रगति के अवसर उपलब्ध कराना था। इस योजना के अंतर्गत उच्च स्तर पर अध्ययन के उच्च पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा रखने वाले तकनीशियन अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से प्रगति कर सकें। इन पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औद्योगिक क्षेत्र के द्वारा बहुत प्रशंसा की गई है। इस समय योजना निम्नलिखित पांच संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

1. वाई.एम.सी.ए. इंजीनियरी संस्थान, फरीदाबाद।
2. सी.एम. कोठारी प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास।
3. एम.आर.एम. पालिटेक्निक, बंबई।
4. इंजीनियरी और ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद।
5. जे.सी.घोष पालिटेक्निक, कलकत्ता।

आने वाले समय में प्रत्येक राज्य में एक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र

प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता की योजना के अंतर्गत 1980-81 से ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र (ग्रा.प्रौ.वि.के.) विभिन्न डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में स्थापित किए जा रहे हैं। 1984-85 के अन्त तक 14 ग्रा.प्रौ.वि. केन्द्र स्थापित किए गए थे। 1985-86 के दौरान एक और ग्रा.प्रौ.वि. केन्द्र स्थापित किया गया है। पिछले वर्षों में

स्थापित किए गए केन्द्रों को जारी रखा गया और ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप प्रौद्योगिकियों को परिवर्तित करने, अपनाने तथा निर्माण के लिए इन केन्द्रों को निर्धारित नियमों के अनुसार आवश्यक अनुदान दिए गए।

सामुदायिक पालिटेक्निक

यह योजना वर्ष 1978-79 में केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत शुरू की गई थी जिसमें 36 पालिटेक्निकों को सामुदायिक पालिटेक्निकों के रूप में कार्य करने के वास्ते चुना गया था। इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करने के अतिरिक्त, इन पालिटेक्निकों से अपेक्षा की जाती है कि ये पर्यावरण से संपर्क बनाए रखें और ग्रामीण के प्रौद्योगिकी के अंतरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य कर सकें। इन पालिटेक्निकों द्वारा आरंभ किए गए कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :—ग्रामीण बेरोजगारों को दक्षताओं में प्रशिक्षण प्रदान करना, ग्रामीण लोगों को तकनीकी सेवाएं प्रदान करना, पहले से ही विकसित तथा अपनाई गई उपयुक्त प्रौद्योगिकी की संबंधित मदों को स्थापित करना तथा उनका अनुरक्षण कराना, सूचना और प्रदर्शन केन्द्रों की स्थापना करना और समग्र विकास के लिए प्रायोगिक आदर्श परियोजनाएं शुरू करना। वर्ष 1984-85 के दौरान निकटवर्ती क्षेत्रों के युवकों को दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र के 10 पालिटेक्निकों को समुदाय पालिटेक्निक की धारा में जोड़ा गया। आलोच्य वर्ष के दौरान "समुदाय पालिटेक्निक योजना" की धारा के अन्तर्गत 61 और पालिटेक्निकों को लाया गया है। इस योजना से सफल परिणामों को ध्यान में रखते हुए आने वालों वर्षों में इस योजना को शेष पालिटेक्निकों में लागू करने का प्रस्ताव है।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान

मद्रास, कलकत्ता, भोपाल और चण्डीगढ़ में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना वर्ष 1966-67 में की गई थी जिनका उद्देश्य पालिटेक्निक शिक्षा के सुधार के लिए विभिन्न कार्यकलापों को भी आयोजित करना है। 12 महीने/18 महीने की अवधि से अधिक के प्रशिक्षण के अतिरिक्त ये संस्थाएं पाठ्यचर्या विकास तथा अन्य संबंधित कार्यकलापों में भाग लेने के अतिरिक्त शिक्षकों को अल्पकालिक प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। भोपाल और मद्रास में स्थित दो संस्थान तकनीकी शिक्षा में स्नातकोत्तर स्तर पाठ्यक्रम प्रदान करने की स्थिति में पहुंच गई है। सामान्य कार्यकलापों के अतिरिक्त ये संस्थाएं यू.एन.डी.पी. परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलाप जैसे शैक्षिक फिल्म निर्माता, राष्ट्रीय प्रशिक्षण सेवाएं, शैक्षिक पैकेज जैसे कुछ कार्यकलाप भी आयोजित करती है। टी.टी.टी.आई मद्रास ने यूनेस्को की एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसका विषय था, "तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा कार्मिकों का प्रारंभिक और सेवारत प्रशिक्षण"।

प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता

यह योजना तकनीकी शिक्षा की कोटि तथा स्तरों में सुधार करने के लिए प्रासांगिक तथा महत्वपूर्ण स्वीकृत परियोजनाओं के वास्ते चुनिन्दा इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निकों को शत प्रतिशत आधार पर केन्द्रीय सहायता देने के उद्देश्य से वर्ष 1976-77 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना आलोच्य वर्ष के दौरान जारी रही। डिग्री और डिप्लोमा दोनों स्तरों पर तकनीकी संस्थाओं तथा योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए उपयुक्त क्षेत्र का चुनाव करने के लिए गठित की गई राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने सहायता स्वीकृत करने के वास्ते 30 इंजीनियरी कालेजों और 41 पालिटेक्निकों को चुना।

समग्र ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं

सातवीं पंचवर्षीय योजना के चालू वर्ष में आरंभ की गई यह एक नई योजना है। इस योजना का उद्देश्य चुनी गई सामुदायिक पालिटेक्निकों को समग्र ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग संबंधी प्रायोगिक परियोजनाओं को आरंभ करने में सहायता प्रदान करना है ताकि शैक्षिक प्रयासों को ग्रामीण जीवन से और अधिक सम्बद्ध बनाया जा सके। वर्तमान योजना में सम्पूर्ण ग्रामीण विकास के लिए 100 गांवों के एक समूह को एक इकाई के रूप में लिया गया है। इस परियोजना को ब्लाक स्तर सामूहिक गांव स्तर और एकल गांव स्तर पर लागू की जाएगी। इस परियोजना का संचालन व्यावसायिक प्रबंधों द्वारा किया जाएगा जिन पर सम्पूर्ण परियोजना के कार्यान्वयन की पूरी

जिम्मेवारी होगी। सम्पूर्ण परियोजना का संचालन कोर प्रबंधकीय कर्मचारियों, सरकारी अधिकारियों, तकनीकी संस्थाओं और ग्रामीण सहकारिताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

उपयुक्त प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास के विशेष संस्थान

चालू वर्ष के दौरान चारों क्षेत्रों में एक-एक परियोजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है। चालू वर्ष का बजट प्रावधान 200 लाख रुपये है। यह भी एक नई योजना है जो कि 7 वीं पंचवर्षीय योजना के चालू वर्ष से आरंभ की जा रही है। ये संस्थान, ग्रामीण परियोजनाओं में अनुसंधान, औपचारिक और गैर-औपचारिक प्रशिक्षण और व्यापक विस्तार कार्यों के जरिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास से संबंधित नए विषयों के विकास के लिए श्रेष्ठता के केन्द्र होंगे। इसके अतिरिक्त यह संस्थान ग्रामीण विकास में लगी हुई संस्थाओं/संगठनों को सहायता प्रदान करने के एक संकेन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करेगा। इस संस्थान के तीन मुख्य खण्ड होंगे अर्थात् उपयुक्त प्रौद्योगिकी का अनुसंधान और विकास केन्द्र, प्रशिक्षण केन्द्र और समेकित ग्रामीण विकास केन्द्र। यह एक स्वायत्त संगठन होगा जिसका वित्त पोषण पूर्ण रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा। क्योंकि सहयोजन और सहयोग ग्रामीण विकास की सफलता की कुंजी है। यह संस्थान प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान और ग्रामीण विकास से संबंधित संगठनों को अद्यतन ज्ञान प्रदान करने में एक मुख्य संस्थान की भूमिका अपनाएगा। चालू वर्ष के लिए 200 लाख रुपये के बजट का प्रावधान है। शुरू-शुरू में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चारों क्षेत्रों में एक-एक संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

नई संस्थाओं का विकास

आलोच्य वर्ष के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्री, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष भी हैं, की स्वीकृति से देश के विभिन्न राज्यों में एक इंजीनियरी कालेज और सात पालिटेक्निक स्थापित किए गए हैं। यह स्वीकृति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा नई तकनीकी संस्थाओं और नए पाठ्यक्रमों को आरंभ करने संबंधी मार्ग-दर्शी रूपरेखाओं को ध्यान में रखकर प्रदान की गई है। नई संस्थाओं को स्थापित करते हुए जहां तक हो सके क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने पर ध्यान दिया गया है।

संस्थागत नेटवर्क योजना

1981-82 में आरंभ की गई संस्थागत नेटवर्क योजना 1985-86 के दौरान भी एक सतत योजना के रूप में जारी रही। इस योजना का उद्देश्य भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे विकसित संस्थानों का कम विकसित संस्थानों जैसे क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज और प्राइवेट स्वायत्त कालेजों से प्रयोगशाला विकास और संकाय विनिमय कार्यक्रम में आन्तरिक तकनीकी सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में सहयोग स्थापित करना था। योजनाओं की व्यवस्थाओं के अनुसार योजना के अन्तर्गत, प्रत्येक स्वीकृत प्रयोगशाला की उन्नति के लिए 2.50 लाख रुपये की सहायक अनुदान स्वीकृत किया गया और 2.5 लाख रुपये की इतनी ही राशि संबंधित संस्था को अपने सामान्य बजट से करनी अपेक्षित थी। छठी योजना अवधि के दौरान 2.50 लाख प्रति प्रयोगशाला की दर से 99 प्रयोगशालाओं पर 247.50 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। प्रयोगशाला की उन्नति के लिए अलग-अलग सहायक अनुदानों का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

वित्तीय वर्ष	प्रयोगशालाओं की संख्या	जारी की गई राशि (लाख रुपए)
1	2	3
1981-82	25	62.50
1982-83	32	80.00
1983-84	20	50.00
1984-85	22	55.00
		247.50

1985-86 के दौरान 100 लाख रुपये की बजट व्यवस्था है जिसका उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।

कमियों वाले क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार

यह योजना छठी योजना अवधि में आरंभ की गई थी जिसका उद्देश्य स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए उसके आधार की अवस्थापना, विविधता और क्रमशः विस्तार को सुदृढ़ करते हुए उपयुक्त और प्रभावी ढंग से राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ चुने हुए क्षेत्रों में अन्तराल को भरना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था संगणक विज्ञान, इलेक्ट्रानिक्स, अनुरक्षण, इंजीनियरी यंत्रीकरण, उत्पादन, विकास तथा जीव-विज्ञानों और प्रबन्ध विज्ञानों आदि के क्षेत्रों में 100% के आधार पर प्रत्यक्ष केन्द्रीय अनुदान प्रदान करके सुधार लाना।

इस योजना के अन्तर्गत, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय संस्थाओं को विभिन्न परियोजनाओं के लिए दिए गए सहायक अनुदानों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :-

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रुपयों में)
1981-82	85.00
1982-83	285.00
1983-84	238.00
1984-85	448.90
	1056.90

वर्ष 1985-86 के लिए 750.00 लाख रुपये की बजट व्यवस्था है जिसका पूर्ण उपयोग चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले किया जाएगा।

नए प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अवस्थापना का निर्माण

यह योजना छठी योजना अवधि में आरंभ की गई थी। इसका उद्देश्य नए प्रौद्योगिकी के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में हो रही प्रगति के साथ-साथ चलना है। इनमें माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग, दूरस्थ ज्ञान, माइक्रोइलेक्ट्रानिकी, वातावरण विज्ञान, ओपटिकल संचार, बाइओ कनवर्शन, लेसर प्रौद्योगिकी, विश्वसनीयता, इंजीनियरी, परिवहन इंजीनियरी, जल संसाधन प्रबंध, संगणक डिजाइन और निर्माण, पर्यावरणात्मक इंजीनियरी, ऊर्जा विज्ञान इत्यादि शामिल हैं। योजना के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थाओं को दिए गए सहायता अनुदान के ब्यौरे निम्नलिखित हैं।

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रुपयों में)
1981-82	115.00
1982-83	384.50
1983-84	350.00
1984-85	582.75
	1432.25

1985-86 के दौरान 550.00 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है जिसका उपयोग वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पूर्ण रूप से किया जाएगा।

इंजीनियरी प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण

यह योजना छठी योजना अवधि में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अद्यतन प्रौद्योगिकीय प्रगति और पाठ्यचर्या परिवर्तन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के आधार पर आधुनिक उपकरणों और यंत्रों को उपलब्ध करना था। विभिन्न इंजीनियरी कालेजों और प्रौद्योगिकीय संस्थाओं को जारी किए गए, सहायता अनुदान के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि (लाख रुपए में)
1981-82	--
1982-83	120.00
1983-84	243.50
1984-85	398.85
कुल	762.40

वर्ष 1985-86 के दौरान 1500.00 लाख रुपये की बजट व्यवस्था है। इस राशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण रूप से किया जाएगा।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान

इंजीनियरी तथा प्रयुक्त विज्ञानों में शिक्षा तथा प्रशिक्षण के प्रमुख केन्द्रों के रूप में कार्य करने तथा अवर स्नातक अध्ययन और स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसंधान के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए खड़गपुर, बम्बई, मद्रास, कानपुर तथा दिल्ली में पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। ये संस्थान इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक डिग्री के लिए अवस्नातक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

ये संस्थान इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातक डिग्री के लिए अवर-स्नातक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ये भौतिक रसायन शास्त्र तथा गणित में पांच वर्षीय समेकित मास्टर्स डिग्री पाठ्यक्रम, विभिन्न विशेषज्ञताओं में डेढ़ वर्षीय एम.टेक. डिग्री पाठ्यक्रम तथा चुने गए क्षेत्रों में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा संस्थान, इंजीनियरी, विज्ञान, मानविकी तथा समान विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में पी.एच.डी. कार्यक्रम प्रदान करते हैं। प्रत्येक संस्थान में निर्धारित विशेषज्ञता क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अनुसंधान के उच्च केन्द्र भी हैं।

आलोच्य वर्ष के दौरान इन संस्थाओं ने, परिष्कृत उपस्करों द्वारा अपनी अवस्थापना सुविधाओं का और विस्तार किया तथा प्रयोक्ता एजेंसियों को प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने में बेहतर सहभागिता दिखाई। इन संस्थानों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं तथा परामर्श कार्यों की संख्या में भी वृद्धि हुई। जिससे संबंधित संस्थानों को काफी मात्रा में आय हुई। विभिन्न कार्यशालाओं/सम्मेलनों सेमिनारों इत्यादि द्वारा तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान के लिए इन संस्थाओं तथा विभिन्न अन्य शैक्षिक और व्यापारिक संगठनों के बीच संबंधों को और अधिक महत्व प्राप्त हुआ।

प्रत्येक संस्थान के मानविकी तथा समाज-विज्ञान विभाग ने इंजीनियरी के छात्रों में आधुनिक प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण सामाजिक पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के अपने प्रयत्न जारी रखे।

भा.प्रौ.सं. खड़गपुर में एम.टेक, स्तर के 67 विशेषज्ञता पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। यह संस्थान 5 विशेषज्ञता विषयों में एम./एम.आर.पी./एम./सी.पी./ और एम.एस.सी. पाठ्यक्रम प्रदान करती है। भा.प्रौ.सं. का क्षेत्रीय दूरस्थ अनुसंधान केन्द्र इसके अनुसंधान केन्द्रों की सूची में जोड़ा गया आठवां केन्द्र है। यह उन केन्द्रों की श्रंखला में है जिनको भारत सरकार ने देश में दूरस्थ अनुसंधान संबंधी प्रशिक्षण और सेवा में अवस्थापना की स्थापित करने के लिए किया है। जैसा कि अंतरिक्ष विभाग द्वारा कल्पना की गई है, ये केन्द्र समय-समय पर अल्पकालीन और दीर्घ कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे, प्रयोक्ताओं को अपनी समस्याओं को सुलझाने में सहायता प्रदान करेंगे और विभिन्न विषयों से संबंधित दूरस्थ अन्वेशज्ञ आंकड़ों का प्रयोग करने के लिए अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों में जुटेंगे। ***

शैक्षिक सत्र 1984-85 से, भा.प्रौ.सं., बम्बई में विश्वसनीयता इंजीनियरी में एक नया अन्तर-विषयक एम.टेक. कार्यक्रम, दृश्य संचार में एक नया दो वर्षीय मास्टर आफ डिजाइन (एम. डिजा.) कार्यक्रम तथा रसायन और मैकेनिकल इंजीनियरी में पांच वर्षीय एक समेकित सहयोगी एम.टेक. कार्यक्रम शुरू किए गए।

भा.प्रौ.सं., बम्बई के इलेक्ट्रानिक उच्च अनुसंधान केन्द्र ने सुरक्षा आवश्यकताओं से सम्बद्ध राडार और संचार के क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य किया, राडार संचार के लिए एन्टीना सिगनल प्रोसेसिंग तथा माइक्रोवेव मैगनेटिक मैटीरियल के क्षेत्र में नौ महत्वपूर्ण परियोजनाएं आरंभ की।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास और भारतीय सीमेन्ट अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने सीमेन्ट और सीमेंट उत्पादन की कोटि नियन्त्रण और आर.एण्ड डी. समस्याओं से संबंधित विषयों पर अध्ययन करने से संबंधित संयुक्त सहयोग एकक स्थापित करने के उद्देश्य से एक करार पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त सहयोग एकक ने, 1 अक्तूबर, 1984 से कार्य करना आरंभ कर दिया है। यह सिविल इंजीनियरी विभाग के संरचनात्मक इंजीनियरी प्रयोगशाला में स्थित है।

भा.प्रौ.सं. के औद्योगिक परामर्शी और प्रायोजित अनुसंधान केन्द्र ने भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की वित्तीय सहायता से संस्थान के एम.एस. उद्यमशील पाठ्यक्रम में प्रवेश होने वाले छात्रों के लिए एक अनुस्थापन पाठ्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और राज्य स्तर के संगठन जैसे आई.टी.सी.ओ.टी., एस.आई.पी.सी.ओ.टी., टी.आई.आई.सी. ने इस पाठ्यक्रम के अपने साधन जुटाकर इस पाठ्यक्रम के आयोजन के लिए सहायता प्रदान की।

भा.प्रौ.सं. कानपुर ने उत्तर प्रदेश के चुने हुए पिछड़े क्षेत्र, जामों जगदीशपुर ब्लाक का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आरंभ किया और उसको पूरा किया जिससे स्थानीय प्राधिकारियों और विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य परिषद के सहयोग से कुछ क्षेत्रीय कार्य करने में सहायता मिलेगी। भा.प्रौ.सं. कानपुर ने विषयक अनुसंधान कार्य जारी रखा जिसका कि राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत योगदान है। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और भा.प्रौ. संस्थाओं की संस्थागत नेटवर्क योजना के सदस्य होने के नाते, भा.प्रौ.सं., कानपुर ने प्रयोगशाला विकास के क्षेत्र में मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद और मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल को सहायता प्रदान करना जारी रखा।

आलोच्य वर्ष के दौरान भा.प्रौ.सं. दिल्ली ने राष्ट्रीय महत्व के कुछ क्षेत्रों में अनुसंधान कार्यों पर अपना ध्यान केन्द्रित किया। इनमें से एक क्षेत्र आंधी तूफान और मौसम की भविष्यवाणी से संबंधित है। बंगाल की खाड़ी में तूफान आने की समस्या को हल कर लिया गया है। मानसून जनरल सरकुलेशन माडल तैयार किया गया है जिनका प्रयोग जलवायु और किसी अमुक स्थान के मौसम की भविष्यवाणी के लिए किया जाएगा। इस माडल का प्रयोग वर्ष 1984 के दौरान मानसून के प्रवाह का सफलतापूर्वक पता लगाने में किया गया इस संस्थान को हाइड्रोलोजी और गणित के क्षेत्र में सोवियत संघ से सहयोग के लिए चुना गया है। भारत-संयुक्त राज्य प्रौद्योगिकी उप-आयोग की योजना के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ विद्यालय से भी सहयोग स्थापित किया गया।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों के दाखिले में सुधार लाने के लिए दस महीने की अवधि का एक विशेष प्रारंभिक पाठ्यक्रम आरंभ किया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वे छात्र जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिले के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफलता प्राप्त नहीं कर पाते, उन्हें प्रारंभिक पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाता है। प्रारंभिक पाठ्यक्रम के अंत में इन छात्रों को एक अर्हक परीक्षा देनी होती है जिसके आधार पर उन्हें संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बैठे बिना पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में बी.टेक. पाठ्यक्रम में दाखिला दे दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम तथा बाद में अर्हक परीक्षा के आधार पर भा. प्रौ. संस्थानों ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश पाने वाले छात्रों के अतिरिक्त अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के 48 छात्रों को दाखिला दिया।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को संस्थानों से निःशुल्क भोजन के अतिरिक्त अंश खर्च, ऋण और विवेकी अनुदानों से वित्तीय सहायता मिलना जारी रहा।

पांचों भा. प्रौ. संस्थानों में शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों को यदि वे संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनके लिए एक-एक अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की जाती है। उन्हें अपने मनपसन्द मर्जी के संस्थान और पाठ्यक्रम में दाखिला दिया जाता है बशर्ते कि वे उस पाठ्यक्रम में प्रवेश की सभी अर्हताएं पूरी करते हों।

1984-85 के दौरान दाखिल और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार रही :—

भा० प्रौ० सं०	अवर-स्नातक	उत्तर-स्नातक और अनुसंधान	उत्तीर्ण छात्र
1	2	3	4
खड़गपुर	1411	1343	874
बम्बई	1439	538	699
मद्रास	1089	970	650
कानपुर	1147	667	622
दिल्ली	1256	1735	680

भारतीय प्रबंध संस्थान

भारत सरकार ने कलकत्ता, अहमदाबाद, बंगलौर और लखनऊ में क्रमशः 1961, 1962, 1972 और 1984 में चार भारतीय प्रबंध संस्थान स्थापित किए जिनका उद्देश्य प्रबंध केन्द्रों और अनुभवी प्रशासक तैयार करने के लिए युवा पुरुषों और महिलाओं को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना, प्रबन्ध और प्रशासन के विकास के लिए अनुसंधान करना और प्रबंध व्यवसाय के क्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों के विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करना था। संस्थान ने प्रबंध में उत्तर-स्नातक और फैलोशिप कार्यक्रम और उद्योगों के प्रबन्धकों के लिए कई कार्यकारी विकास कार्यक्रमों का आयोजन जारी रखा। संस्थान ने सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया। लखनऊ में स्थापित नए संस्थान का शैक्षिक सत्र जुलाई, 1984 से आरम्भ हुआ जिसमें 30 छात्रों को दाखिल किया गया। संस्थान के पूर्ण विकसित होने पर इसके उत्तर-स्नातक कार्यक्रम में प्रत्येक वर्ष 180 छात्र दाखिल किए जायेंगे। संस्थान ने लघु पैमाने के उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयत्न किए हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान संस्थानों और उद्योगों में सहयोजन श्रेष्ठ रहा।

गैर-विश्वविद्यालय केन्द्रों में प्रबंध शिक्षा

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ ऐसे गैर-विश्वविद्यालय शिक्षा केन्द्रों को सहायता प्रदान करना है जो अखिल भारतीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं और दो वर्ष का पूर्णकालिक एम.बी.ए. पाठ्यक्रम और प्रबंध अध्ययन में 3 वर्ष का अंशकालिक स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान करते हैं। यह सहायता अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की सिफारिश पर दी जाती है। इस समय केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित संस्थाओं के पाठ्यक्रमों के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए सहायता प्रदान कर रही है :—

1. पी.एस.जी. प्रौद्योगिकी कालेज, कोयम्बत्तूर।
2. जौक्यर श्रमिक सम्बन्ध संस्थान, जमशेदपुर।
3. बी.आई.टी., रांची।
4. भारतीय समाज कल्याण और व्यापार प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता।
5. एल.एन. मिश्र, आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई

यह संस्थान औद्योगिक इंजीनियरी और सम्बद्ध विषयों में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से स.रा.वि.का. की सहायता से 1963 में स्थापित किया गया था। यह निम्नलिखित का आयोजन करता है :—(i) कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ii) यूनिट आधारित कार्यक्रम (iii) औद्योगिक इंजीनियरी में उत्तर-स्नातक कार्यक्रम, (iv) अनुसंधान द्वारा उत्तर-स्नातक कार्यक्रम. (v) फैलोशिप कार्यक्रम, (vi) परामर्शी सेवाएं, (vii) अनुसंधान कार्यक्रम और (viii) सेमिनार तथा सम्मेलन।

आलोच्य वर्ष के दौरान संस्थान ने इन सभी कार्यकलापों/कार्यक्रमों का प्रभावी ढंग से संचालन किया ।

ए.प्रौ.इ.प्र.सं. ने औद्योगिक इंजीनियरी और सम्बद्ध विषयों के विकास के क्षेत्र से सम्बन्धित 'उद्योग प्रगति'' नामक एक पत्रिका प्रकाशित की । नई तकनीकों और कार्यक्रमों को आरम्भ करके संस्थान ने तीव्र प्रौद्योगिकीय विकास और सामाजार्थिक परिवर्तनों से उत्पन्न बदलती आवश्यकताओं के लिए योगदान दिया है ।

विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र

भारत सरकार ने विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है जो देश में विद्यमान संस्थाओं के नेट-वर्क के माध्यम से संचालित किया जायेगा और यह एक संसाधन केंद्र और सहयोगी अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करेगा यह अंतर्राष्ट्रीय केंद्र विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य समन्वित करेगा जिसके लिए देश में कोई समन्वित प्रयास नहीं किए गए हैं यद्यपि कई संस्थाएं व्यक्तिगत आधार पर सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। यह केन्द्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करेगा और इसका पूर्ण वित्त-पोषण भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। यह केन्द्र विकासशील देशों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और इसको अपने कार्यक्रमों के लिए यूनेस्को यू.एन.डी.पी. जैसी एजेन्सियों की सहायता प्राप्त होने की संभावना है।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान बैंकाक को सहायता

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक, एक स्वायत्त अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान है जो इंजीनियरी, विज्ञान और सम्बद्ध विषयों में उच्च शिक्षा प्रदान करता है। यह 20 से अधिक देशों से 600 छात्रों को दाखिल करता है और इसके अन्तर्राष्ट्रीय संकाय सदस्य है। यह संस्थान भारत सहित विभिन्न देशों के सदस्यों के एक अंतर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अधिशासित है। यह 9 विषयों में शैक्षिक कार्यक्रम, एशियाई देशों से सम्बद्ध समस्याओं पर छात्रों और संकाय सदस्यों द्वारा अनुसंधान, और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों सहित विशेष कार्यक्रमों और सम्मेलनों का आयोजन करता है।

भारत सरकार इस मंत्रालय के माध्यम से ए.प्रौ.सं. को निम्नलिखित सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गई है।

(क) इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्रों के भारतीय शिक्षकों विशेषज्ञों की तीन महीने की प्रतिनियुक्ति और प्रतिनियुक्ति का सम्पूर्ण व्यय का वहन करना।

(ग) भारत में सहयोगी कार्यकलाप करने के लिए 2 लाख रुपए तक का स्करों पुस्तकों और पत्रिकाओं को दान स्वरूप देना।

(ग) भारत में सहयोगी कार्यकलाप करने के लिए 2 लाख रुपए तक वार्षिक अनुदान ।

वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान हर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों के 8 भारतीय विशेषज्ञों की ए. प्रौ. सं. में प्रतिनियुक्ति। 1985-86 के दौरान 8 शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति करने की संभावना है। चालू वर्ष में 8.50 लाख रुपये की योजनेतर बजट व्यवस्था की गई और इसका प्रयोग कर लिया गया है। अगले वर्ष अर्थात 1986-87 के लिए ए. प्रौ. सं. को सहायता प्रदान करने के लिए 10 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज

दूसरी और तीसरी योजना अवधियों के दौरान प्रत्येक मुख्य राज्य में एक-एक करके 14 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की स्थापना की गई ताकि देश में आगामी योजना अवधियों के दौरान प्रशिक्षित कार्मिकों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। सिल्चर (असम) स्थित 15वें कालेज में नवम्बर, 1977 में छात्रों का प्रथम बैच दाखिल किया गया। यद्यपि सभी कालेजों में सिविल यांत्रिकी तथा विद्युत इंजीनियरी में प्रथम डिग्री

पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है तथापि कुछेक कालेजों में रासायनिक "धातुकर्मीय" इलैक्ट्रानिकी खनन और वास्तुकला इंजीनियरी में भी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है। इनमें से 13 कालेज स्नातक-स्नातक पाठ्यक्रम भी संचालित कर रहे हैं। इनमें से 9 कालेज वायलरी व अन्य सहायक उपकरणों का डिजाइन और निर्माण, इस्पात संयंत्रों के लिए भारी मशीनों, परिवहन इंजीनियरी, औद्योगिक तथा समुद्रीय संरचनाओं समेकित ऊर्जा पद्धतियों इत्यादि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में उद्योगोन्मुख पाठ्यक्रमों का भी संचालन कर रहे हैं। दो और कालेजों को स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है और इनको हिमाचल प्रदेश में उधीरपुर, और पंजाब में जालंधर में स्थापित करने सम्बन्धी प्रक्रिया जारी है।

छठी योजना अवधि के दौरान क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों के विकास में विद्यमान सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, चुनिन्दा कालेजों में संगणक केन्द्रों की स्थापना प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण जिसमें अप्रचलित उपस्करों को बदलना भी शामिल है तथा सभी छात्रों (लड़के और छात्राओं दोनों) के लिए छात्रावासों का निर्माण और सभी कालेजों में छात्र कार्यकलाप केन्द्रों के विकास पर बल दिया गया है। आलोच्य वर्ष के दौरान क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों ने अपनी विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की है। भा. प्रौ. सं. के साथ संस्थात्मक कड़ी स्थापित करने की योजना के अंतर्गत इन कालेजों में 82 प्रयोगशालाओं का विकास किया जा रहा है। त्रिची, कुरुक्षेत्र, श्रीनगर, इलाहाबाद, जयपुर, दुर्गापुर, सिल्चर, नागपुर, कालिकट, भोपाल, सूरथकल, वारंगल स्थित 12 संस्थाओं में दूर-संचार और इलैक्ट्रानिकी इंजीनियरी पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं और कमजोर वाले क्षेत्रों के लिए नई योजना के अंतर्गत एन. एन. क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारंगल और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज कालिकट में संगणक विज्ञान में एक बी. टेक पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया है। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज राउरकेला में एक संगणक स्थापित किया है और इलाहाबाद, वारंगल और दुर्गापुर स्थित क्षेत्रीय कालेजों के लिए तीन उपकरण खरीदे गए हैं। वारंगल में उपकरण की स्थापना की जा चुकी है। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में कम से कम एक में "ओ" स्तर का संगणक उपलब्ध कराया है। इलाहाबाद, राउरकेला और तिरुचिरापल्ली स्थित तीन क्षेत्रीय कालेजों में एम.सी.ए. पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा अनुसंधान कार्य का विकास

स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसंधान संबंधी शिक्षा समिति की सिफारिश पर जिसका गठन डा. वाई. नायडम्मा की अध्यक्षता में किया गया था, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अवधि घटाकर तीन सैमिस्टरों की कर दी गई है तथा अनुमोदित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश इंजीनियरी में स्नातक अभिरुचि परीक्षण नामक एक अखिल भारतीय परीक्षा के द्वारा नियंत्रित कर दिया गया है। इंजीनियरी में स्नातक अभिरुचि परीक्षण के अन्तर्गत प्रथम परीक्षा फरवरी, 1983 में आयोजित की गई थी। आलोच्य वर्ष के दौरान स्नातकोत्तर शिक्षा की जांच समिति ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संचालन सम्बन्ध में दिए गए प्रस्तावों की जांच की और इस नए पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की। स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति की दर 600/- रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000/- रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। आलोच्य वर्ष के दौरान इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्य की विकास की योजना के अन्तर्गत, सतत योजना के एक भाग के रूप में मंत्रालय ने उनके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के विकास हेतु 12 राज्य सरकारों की संस्थाओं को तथा 23 गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान की। 19 गैर-सरकारी जिन्होंने, आलोच्य वर्ष के दौरान स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 1.00 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त किया है, के नाम अनुबन्ध में दिए गए हैं।

तकनीकी संस्थाओं में संगणकीकरण और जनशक्ति का विकास

इंजीनियरी तथा प्रद्योगिकी संस्थाओं में संगणकीकरण की अपनी योजना के अंतर्गत मंत्रालय राष्ट्रीय साफ्ट विकास तथा परिकलन तकनीक केन्द्र, बम्बई के माध्यम से स्वदेशी "ओ" संगणकों की जांच करा रहा है। आलोच्य वर्ष के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर चार पद्धतियां संस्वीकृत की। छठी योजना अवधि के दौरान मंत्रालय ने सभी चुनिन्दा इंजीनियरी कालेजों में कम से कम एक "ओ" स्तरीय संगणक प्रदान करने के प्रयास

किए गए हैं। संगणक अनुप्रयोग में 1½ वर्षीय उत्तर-पालिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए इलैक्ट्रानिक्स विभाग के सहयोग से मंत्रालय ने 9 और पालिटेक्निकों का भी चयन किया है जिससे कुल मिलाकर संख्या 25 तक पहुंच गई है। वर्ष 1985-86 के दौरान जयाचमारजेन्द्र इंजीनियरी कालेज, मैसूर और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज वारंगल के लिए 3 वर्षीय एम. सी. ए. पाठ्यक्रम को संस्वीकृति प्रदान की गई है। आलोच्य वर्ष के दौरान अतिरिक्त 4 केन्द्रों को संगणक विज्ञान/इंजीनियरी में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों की संस्वीकृति प्रदान की गई है। इस मंत्रालय और इलैक्ट्रानिकी विभाग के संयुक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत इस क्षेत्र में जन-शक्ति की कमी को पूरा करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

राष्ट्रीय गढ़ाई और ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान रांची

राष्ट्रीय गढ़ाई और ढ़लाई प्रौद्योगिकी संस्थान एक स्वायत्त संगठन है जिसका पूर्ण वित्त पोषण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना यू. एन. डी. पी.-यूनेस्को के सहयोग से 1966-67 में भट्टी और ढलाई में प्रशिक्षित कार्मिकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। इस संस्थान के उद्देश्य इस प्रकार हैं (i) अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षण, दीर्घ-कालीन उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम और उद्योगों की आवश्यकताओं के लिए यूनिट पर आधारित कार्यक्रम संचालित करना (ii) प्रयुक्त औद्योगिक अनुसंधान कार्यक्रमों का मार्ग दर्शन और संचालन करना, (iii) भट्टी ढलाई और सम्बद्ध उद्योगों को परामर्श, परीक्षण, प्रलेखन और सूचना सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करना।

12वां उच्च डिप्लोमा पाठ्यक्रम जून, 1984 में आरम्भ हुआ और 20 नवम्बर, 1985 को समाप्त हुआ। वर्ष 1984-85 के दौरान एक छात्र को ढलाई प्रौद्योगिकी में उत्तर-स्नातक डिप्लोमा के लिए चुना गया। एक छात्र को गढ़ाई प्रौद्योगिकी में पी. एच.-डी. के लिए चुना गया। भारतीय उद्योगों के तकनीशियनों और कार्मिक कर्मचारियों के लिए चार पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 25 व्यक्तियों ने भाग लिया। अखिल भारत उद्योगों को रासायनिक और धातु कर्मीय विश्लेषण, यान्त्रिकी और गैर-विनाश कारी परीक्षण और ढ़लाई के लिए कच्चे धातु का मूल्यांकन सम्बन्धी परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई।

आयोजना और वास्तुकला स्कूल नई दिल्ली

ग्रामीण, शहरी तथा क्षेत्रीय आयोजना में प्रशिक्षण हेतु और शहरी आयोजना के केन्द्रीय, राज्यों तथा स्थानीय विभागों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने के वास्ते यह स्कूल, नगर तथा ग्रामीण आयोजना स्कूल के रूप में जुलाई, 1985 में स्थापित किया गया था। दिल्ली पालिटेक्निक के वास्तुकला विभाग को अक्तूबर, 1959 में इस स्कूल के साथ मिला दिया गया था और तब से इसका नाम आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल रखा गया। 1979 में एक महत्वपूर्ण घटना हुई जबकि इसके शैक्षिक कार्यक्रमों का क्षेत्र विस्तृत करने और अनुसंधान तथा विस्तार कार्यक्रमों को और बढ़ावा देने तथा स्वयं अपनी अवर-स्नातक स्नातकोत्तर और डाक्टरोल डिग्रियां प्रदान करने के उद्देश्य से इसे "विश्वविद्यालय, समझी जाने वाली" एक संस्था का दरजा प्रदान किया गया। स्कूल का पूर्ण वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। यह वास्तुकला में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम का आयोजन करता है जिसमें प्रति दो वर्ष दो पारियों में 68 छात्रों की संस्वीकृत क्षमता है। शैक्षिक वर्ष 1985-86 से सात वर्षीय अंश कालिक पाठ्यक्रम (सांध्य) को दूसरी पारी में पांच वर्षीय पूर्ण कालिक पाठ्यक्रम में परिवर्तित किया गया है। यह स्कूल, शहरी तथा क्षेत्रीय आयोजना, आवास, परिवहन आयोजना, भवन इंजीनियरी तथा प्रबन्ध भूदृश्य वास्तुकला तथा शहरी डिजाइन में मास्टर्स डिग्री प्रदान करता है, जिसमें कुल 82 छात्रों की क्षमता है। 1985-86 से इस स्कूल ने पी.एच.डी. पाठ्यक्रम आरम्भ किया है। इस समय स्कूल में दो अनुसंधान केन्द्र हैं--एक ग्रामीण विकास में और दूसरा पर्यावरणात्मक अध्ययन में/यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कार्यशालाओं और सम्मेलनों का आयोजन करता है।

शैक्षिक परामर्शदाता भारत लिमिटिड

इस मंत्रालय का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, शैक्षिक परामर्शदाता, भारत लिमिटिड, नई दिल्ली, 17 जून 1981 को कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य, चिकित्सा सम्बन्धी कृषि तथा तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत तथा विदेश में संगठनों, एजेन्सियों और सरकारी भागों को बहु विषयक परामर्श सेवा प्रदान करना है।

यह निगम बोर्ड आफ डायरेक्टरस की देख रेख में कार्य करता है जिसमें कालिक गैर सरकारी अध्यक्ष और पूर्ण कालिक प्रबन्ध निदेशक है। बोर्ड के अन्य निदेशक केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

1985-86 की अवधि के दौरान शैक्षिक परामर्शदाता भारत लिमिटिड सात परियोजना रिपोर्ट तैयार की जिनमें इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय खुल विश्वविद्यालय सम्बन्धी रिपोर्ट, जम्मू और कश्मीर में एक इंजीनियरी कालेज और दो महिला पालिटेक्निकों को स्थापित करने संबंधी रिपोर्ट जालंधर में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज स्थापित करने सम्बन्धी रिपोर्ट और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पुनर्गठन सम्बन्धी मास्टर प्लान की एक रिपोर्ट शामिल है।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 (1973 में संशोधित) के अन्तर्गत इंजीनियरी स्नातकों तथा डिप्लोमा धारियों के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन कानपुर, कलकत्ता बम्बई तथा मद्रास स्थित चार प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्डों के माध्यम से जारी रहा। बेहतर सम्पर्क बनाए रखने हेतु बोर्डों की राज्य स्तर की समितियां हैं। प्रशिक्षुओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि का योगदान प्रशिक्षण संगठनों और केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में 31 अक्तूबर और 31 मार्च 1984 और 1985 में प्रशिक्षुओं की कुल संख्या नीचे दर्शायी गई है :—

	31-10-83	31-10-84	31-10-85	31-3-84	31-3-85
1	2	3	4	5	6
कुल प्रशिक्षणार्थी . .	10910	12699	12761	12412	14605
स्नातक प्रशिक्षणार्थी . .	3123	3946	3986	3877	4699
डिप्लोमा धारी प्रशिक्षणार्थी .	7787	8753	8775	8595	9906
अनुसूचित जाति प्रशिक्षाणार्थी .	342	402	420	412	488
अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षाणार्थी	81	65	44	92	05
अल्प सख्यक प्रशिक्षणार्थी .	713	806	756	750	818
विकलांग प्रशिक्षणार्थी .	2	7	7	4	5
महिलाएं प्रशिक्षणार्थी .	339	659	712	453	691

इन बोर्डों द्वारा कुछ इंजीनियरी कालेजों तथा पालिटेक्निकों के अन्तिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रशिक्षुता तथा आजीविका मार्गदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की कोटि सुधारने हेतु कई पर्यवेक्षी विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये बोर्ड कुछ पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहे हैं जिनमें उद्योग-पतियों और शिक्षाविदों के विचार प्रकट किए गए हैं। कुछ बोर्डों ने प्रशिक्षण मैनुअल भी तैयार किए हैं।

राज्य सरकारों के साथ कई बैठकों के पश्चात 10+2 व्यावसायिक विषयों से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को छः महीने का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से 1983-84 में विशेष व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण योजना शुरू की गई है।

भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद

इस कालेज की स्थापना भारत सरकार और उद्योगों के एक संयुक्त उद्यम के रूप में 1957 में की गई थी। भारत तथा अपने निकटवर्ती देशों में प्रबन्ध विकास शिक्षा के लिए एक मार्गदर्शक संस्था के रूप में कालेज इस संबंध में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रहा है तथा साथ ही उन क्षेत्रों को शामिल करने के लिए जो राष्ट्रीय संदर्भ में अधिकाधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं, अपने कार्यकलापों का विस्तार कर रहा है।

कालेज की एक विशिष्ट बात सामान्य प्रबंध तथा साथ ही उत्पादन; विपणन, वित्त कार्मिक सामग्री प्रबन्ध संगणक तथा निवेश आयोजन जैसे कार्यालय क्षेत्रों में उत्तर-अनुभव प्रबन्ध विकास कार्यक्रमों पर विशेष रूप से ध्यान देना है । 1984-85 में कालेज ने 86 पाठ्यक्रम आयोजित किए जिनमें सरकारी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों व अन्य क्षेत्रों से 1927 अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त कालेज ने 20 परामर्शी कार्यों को भी पूरा किया है। इसने फोर्ट फाउंडेशन योजना आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और अन्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के संगठनों द्वारा प्रायोजित 34 अध्ययन कार्य पूरे किए और एक पुस्तक 49 निबंन्ध--लेख प्रकाशित किए। कालेज क्षेत्रीय आर्थिक प्रबन्ध और दक्षिण एशिया सहयोग में अपने अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जारी रखेगा।

वर्ष 1985-86 में शिक्षा विभाग ने कालेज कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और गैर-सदस्यीय संगठनों द्वारा प्रायोजित व्यक्तियों से ली जाने वाली वास्तविक फीस तथा लागत को पूरा करने के लिए 2.5 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया है ।

शैक्षिक अर्हताओं के लिए मूल्यांकन बोर्ड

शैक्षिक अर्हताओं के लिए मूल्यांकन बोर्ड की स्थापना संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा की गई थी । यह बोर्ड केन्द्रीय सरकार के अधीन चिकित्सा तथा सम्बद्ध विषयों को छोडकर विभिन्न क्षेत्रों में पदों और सेवाओं में भर्ती के प्रयोजन के लिये भारतीय तथा विदेशी शैक्षिक अर्हताओं को मान्यता प्रदान करने से संबंधित सभी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देता है । तकनीकी शिक्षा ब्यूरो इस बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है ।

अध्याय 5

प्रौढ़ शिक्षा

सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह संकल्पना की गई है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 1990 तक 15–35 आयु वर्ग के सभी निरक्षरों को इसमें शामिल करना होगा। इस कार्यक्रम की मानव संसाधन विकास और परिवार कल्याण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका होने के नाते देश के सामाजार्थिक विकास में महत्वपूर्ण स्थिति है। यह कार्यक्रम नए 20-सूत्री कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है। वर्ष 1990 तक 15–35 आयु वर्ग के सभी निरक्षरों को दाखिला दिए जाने की संकल्पना की गई है। इस आयु वर्ग में अनुमानित 11 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों में से छठी योजना अवधि में 2.3 करोड़ प्रौढ़ निरक्षरों को शामिल करके सही प्रगति हासिल की गई है, शेष निरक्षरों को सातवीं योजना अवधि में शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए 360 करोड़ रुपये के परिव्यय––केन्द्रीय सेक्टर में 130 करोड़ रुपये और राज्य सेक्टर में 230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1985-86 के लिए निर्धारित 75.46 लाख दाखिले लक्ष्य की तुलना में सितंबर, 1985 तक 70.43 लाख अर्थात 93.33% को दाखिल किया गया।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को तैयार करते समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने छठी योजना में दिए गए मापदण्डों के अलावा सातवीं योजना में निर्दिष्ट मुख्य बातों पर भी ध्यान दिया है, सातवीं योजना की मुख्य बातों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जारी रखने को विकसित करना, सामाजिक संस्थानों, स्वैच्छिक संगठनों, छात्रों, शिक्षकों, नियोक्ताओं, ने.यु.के., एन.एस.एस. और समुदाय को शामिल करके जन-आन्दोलन शुरू करना, अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों का प्रभावकारी सम्बन्ध, लोक परम्परागत और आधुनिक जन-साधनों का तीव्र उपयोग, सभी गांवों में प्रभावी और पर्याप्त उत्तर-साक्षरता कार्यकलापों और प्रेरणात्मक उद्देश्यों के लिए सामुदायिक जीवन तथा सतत शिक्षा केन्द्रों की स्थापना को शामिल करना है। छठी योजना के प्रचलित मापदण्डों में उन जिलों को जहां साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम थी, शामिल किया गया, महिलाओं अ.जा., अ.जन.जा., और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को प्राथमिकता बड़ी मात्रा में स्वैच्छिक एजेन्सियों को शामिल और संघठित करना और विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रों तथा शिक्षकों को शामिल करना।

फिलहाल कार्यरत विभिन्न कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :––

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं (ग्रा.का.सा.प.)

यह एक वृहत् केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अन्तर्गत अनुमोदित वित्तीय पद्धति के अनुसार सभी राज्य सरकारों और सभी प्रशासनों को शत-प्रतिशत आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार ने वित्तीय सहायता की पद्धति को 1 फरवरी, 1984 से संशोधित कर दिया है। इस योजना का उद्देश्य 300 केन्द्रों तक की परियोजना आरम्भ करने का है जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्रों में एक या दो वृहत् विकास ब्लाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 केन्द्रों तक को या कुछ राज्यों में पहाड़ी अथवा दुर्गम क्षेत्रों को शामिल करना है। देश में धीरे-धीरे सभी जिलों को एक ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने की नीति है। फिलहाल 513 ग्रा.कार्या.सा.प.

केन्द्र विभिन्न राज्यों और संघ शासित राज्यों में काम कर रहे हैं। वर्ष 1985-86 के दौरान 35 लाख प्रौढ़ निरक्षरों को दाखिला देने के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 32.74 लाख प्रौढ़ों को सितम्बर, 1985 तक दाखिला दिया गया। वर्ष 1985-86 के लिए इस योजना के अंतर्गत 41.76 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्वीकृत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के अतिरिक्त राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासनों से भी राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (रा.प्रौ.शि.का.) के अन्तर्गत कार्य में तेजी लाने और ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्वीकृत केन्द्रों के बराबर समान संख्या में केन्द्रों की स्थापना करने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया गया है।

स्वैच्छिक एजेन्सिया

मंत्रालय द्वारा इस योजना के अन्तर्गत गैर-साम्प्रदायिक पंजीकृत एजेन्सियों, सार्वजनिक न्यासों और अलाभग्राही कम्पनियों को कार्यात्मक साक्षरता, उत्तर-साक्षरता, संसाधन विकास प्रकाशनों, संगोष्ठियों के आयोजन आदि की परियोजनाओं को संचालित करने के लिए अनुदान संस्वीकृत किए जाते हैं। वर्ष 1985-86 के दौरान 144 स्वैच्छिक एजेन्सियों को 7,845 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों और उत्तर-साक्षरता और अनुवर्ती कार्यक्रमों को दिसम्बर, 1985 तक शुरू किया जा चुका है। इस योजना के लिए वर्ष 1985-86 के लिए 7.00 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

विश्वविद्यालय और कालेज

कालेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं शिक्षकों को शामिल करने के विचार से 15–35 आयु वर्ग में प्रौढ़ निरक्षरता के अन्मूलन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वित्तीय सहायता देना और 82 विश्वविद्यालयों और 18 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 2,131 कालेजों को सहायता देना जारी रखा। संस्वीकृत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 23,721 है।

त्तर साक्षरता और नुवर्ती कार्यक्रम

यह केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1982-83 में उन नव-साक्षरों जिन्होंने प्राथमिक साक्षर पाठ्यक्रमों को पूरा कर लिया है और जो निरक्षर नहीं गिने जाते हैं, को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। 1982 में दी गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन तीन चरणों में किया जाना अपेक्षित है; प्रथम चरण में 300–350 घंटे एक वर्ष में; द्वितीय चरण में 150 घंटे एक वर्ष में; और तीसरे चरण में 100 घंटे एक वर्ष के लिए हैं। इस योजना के उपर्युक्त उल्लिखित कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है और सभी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्रों को नई मार्गदर्शी रूप-रेखाएं जारी कर दी गई हैं। नई मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के अन्तर्गत प्रथम चरण और द्वितीय चरण को जोड़कर सीखने के लिए एकल कार्यक्रम एक वर्ष के लिए है इसमें तीसरे चरण में 100 घंटों का साक्षरता और अनुवर्ती कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम के दूसरे वर्ष के लिए है।

वर्ष 1985-86 के दौरान पन्द्रह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को अनुदान संस्वीकृत किया गया है और 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के आवेदन-पत्रों पर विचार किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में 150 लाख रुपए का प्रावधान है।

मिक विद्यापीठ

ये विद्यापीठ शहरी क्षेत्रों के संगठित और असंगठित क्षेत्रों के कामगारों और उनके परिवारों को समेकित अनौपचारिक शिक्षा की प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन विद्यापीठों के कार्यकलाप लाभार्थियों की पर्याप्त जरूरतों को पूरा करते हुए बहुपयोगी हैं और इसमें प्रशिक्षण और कौशलों का विकास भी शामिल हैं। फिलहाल 36 विद्यापीठ हैं। वर्ष 1985-86 के दौरान तीन नए श्रमिक विद्यापीठों को पारादीप, औरंगाबाद और जोधपुर में स्थापित किया गया है। वर्ष 1985-86 के दौरान 75.00 लाख रुपए का प्रावधान है।

राज्यों/संघीय क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ बनाना

प्रत्येक राज्य/संघीय क्षेत्र में इस कार्यक्रम के उपयुक्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित कर के लिए राज्य तथा जिला दोनों स्तरों पर, इस योजना के अन्तर्गत अनुमोदित वित्ती पद्धति के अनुसार उन्हें आवश्यक प्रशासनिक ढांचे को जारी रखने/सृजन करने के लि वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस समय, इस योजना के अन्तर्गत 26 राज्य, संघीय क्षेत्र वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 1985-86 के दौरान 250.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

राज्य संसाधन केन्द्र

राज्य सरकारों/विश्वविद्यालय क्षेत्र के अन्तर्गत पांच राज्य संसाधन केन्द्रों के अलाव 12 ऐसे राज्य संसाधन केन्द्र जिनका वित्त पोषण इस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। राज्य संसाधन केन्द्र, क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन तथ अध्यापन/अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। राज्य संसाधन केन्द्र इन्दौर (मध्य प्रदेश) की स्थापना 1985-86 में की गई है। राज्य संसाधन केन्द्रों कार्यकरण को और अधिक कार्यकुशल तथा कारगर बनाने के लिए, विद्यमान प्रशासनिक तथ वित्तीय पद्धति को संशोधित किया गया है और नई पद्धति को 1-4-1985 से लाग कर दिया गया है। उत्तर-पूर्वी चारों राज्यों के अतिरिक्त, मणिपुर, त्रिपुरा, अरूणाच प्रदेश तथा सिक्किम के संघीय क्षेत्रों में भी कार्य करने के लिए 1 अप्रैल, 1985 से राज्य संसाधन केन्द्र के रूप में एक विशेष सैल की व्यवस्था की गई है।

मूल्यांकन तथा मानिटरिंग

इस कार्यक्रम की कोटि को सुनिश्चित करने के लिए, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का बाहर मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण निवेश है। उन सुस्थापित समाज विज्ञान संस्थाओं को गहन तथ उद्देश्यपूर्ण अध्ययन सौंपने का विचार है जिनका चयन राज्य सरकारों के परामर्श से किय जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न पहलूओं के अभी तक 59 अध्ययन हो चुके हैं मानिटरिंग की अन्तर्निमित प्रक्रिया है और इस कार्यक्रम को त्रैमासिक रूप से मानिट किया जा रहा है।

व्यापक सार्वजनिक कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम (नई योजना)

इस योजना में, विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के छात्रों, नेहरू युवक केन्द्रों, राष्ट्री सेवा योजना तथा उन व्यक्तियों को जो एक-एक को पढ़ाए, प्रणाली के माध्यम से साक्षरत आन्दोलन में भाग लेने के इच्छुक हैं, को शामिल किए जाने की संकल्पना की गई है यह योजना स्वैच्छा पर आधारित है। तथापि, राज्य संसाधन केन्द्रों द्वारा साक्षरता कि तैयार तथा वितरित की जाएंगी। इस योजना का संचालन तथा मानिटरिंग विद्यमा संरचना द्वारा, इसे सुदृढ़ करके किया जाएगा।

नई शिक्षा नीति

नई शिक्षा नीति को तैयार करने के सन्दर्भ में, मंत्रालय द्वारा परिचालित "शिक्ष की चुनौती-नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य" नामक एक दस्तावेज के आधार पर एक राष्ट्रव्यापी परिचच आरम्भ की गई है। इस सन्दर्भ में, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने 10–12 अक्तूबर, 198 को नई दिल्ली में, प्रौढ़ शिक्षा पर एक राष्ट्रीय सेमिनार का उद्देश्य इसमें भाग लेने वा समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों के लोगों के विचार जानना था ताकि नई शिक्षा नीति में शामि करने के लिए विशिष्ट नीतियों की सिफारिश की जा सके। कुछेक राज्य संसाधन केन्द तथा राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों ने भी सेमिनार आयोजित किए और मंत्रालय को अपनी अपनी रिपोर्टें भेजीं। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करने तथा कार्यात्मक साक्षरता लिए जन-आन्दोलन पर विचार विमर्श करने के लिए 25-5-85 को, तत्कालीन शिक्षा मंत्र की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की बैठक हुई ताकि निरक्षरता उन्मूलन निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विद्यमान प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जन-आन्दोल के साथ जोड़ने की सिफारिश की जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय द्विपक्षी सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम तथा यूनेस्को के कार्यकलापों में भाग लेना

तत्कालीन शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त शिष्टमण्डल ने पेरिस में आयोजित प्रौढ़ शिक्षा पर चौथे अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत के शिष्टमण्डलों ने लोकतांत्रिक जनवाद अल्जीरिया, सोवियत रूस तथा जनवादी क्यूबा को प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र के सम्बन्ध में दौरा किया जनवरी, 1986 में, लोकतांत्रिक जनवादी जर्मन से दो सदस्यों के एक शिष्टमण्डल द्वारा भारत का दौरा करने की आशा है।

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय

प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र का काम करता है, विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करता रहा है, जैसे कि (I) प्रशिक्षण, (II) निरक्षरों तथा नवसाक्षरों के लिए अध्यापन अध्ययन सामग्री तैयार करना, (III) मानीटरिंग, (IV) मूल्यांकन, (V) जनसंख्या शिक्षा, (VI) अनुसंधान तथा (VII) प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रचार साधन सहायता प्रदान करना। वर्ष 1985-86 के दौरान निदेशालय ने, नए स्थापित श्रमिक विद्यापीठ को संसाधन सहायता प्रदान की। निदेशालय ने राज्य संसाधन को मार्गदर्शन तथा नेतृत्व प्रदान करना जारी रखा तथा त्रैमासिक रिपोर्टें प्रकाशित करके इन कार्यकलापों को मानीटर किया। ''महिलाओं और लड़कियों के लिए गैर-औपचारिक शिक्षा'' नामक यूनेस्को सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत 17 सामग्री किटें प्रकाशित की गईं। यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा सहायता प्राप्त परियोजना ''प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा को मिलाना'' के अन्तर्गत 12 राज्य संसाधन केन्द्रों के सहयोग से कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित करके तथा प्रकाशन निकालकर प्रारम्भिक परियोजना कार्यान्वित की गई। नई दिल्ली, लखनऊ तथा पूणे में तीन राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए गए। 23 अक्तूबर, से 4 नवम्बर, 1985 तक नई दिल्ली में एशिया तथा प्रशान्त में शिक्षा के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा निदेशालय द्वारा संयुक्त रूप से साक्षरता में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। निदेशालय ने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन को मानीटर करना जारी रखा तथा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के परामर्श से त्रैमासिक प्रगति रिपोर्टें प्रकाशित कीं। निदेशालय ने मीनीटरिंग प्रणाली को संगणीकृत कर दिया है और संगणक की सहायता से 3 त्रैमासिक रिपोर्टें तैयार की हैं। बाहरी एजेन्सियों द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन रिपोर्टों पर आधारित ''प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन--एक संक्षिप्त लेखा-जोखा'' तथा ''प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण में समस्याएं तथा दृष्टिकोण-निष्कर्षों का एक संश्लेषण'' नामक दो मोनोग्राफ प्रकाशित किए गए। अन्य दो मोनोग्राफ तैयार किए जा रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करने के इच्छुक व्यक्तियों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के अन्तर्गत छः अनुसंधान अध्ययन इस समय प्रगति पर हैं। इस कार्यक्रम के प्रोत्साहनात्मक तथा प्रेरणादायक पहलुओं पर भी निदेशालय ने साफ्टवेयर प्रकाशित किया है। इस वर्ष के दौरान तेरह प्रकाशन प्रकाशित किए गए। तीन और प्रकाशन मुद्रण के विभिन्न चरणों में हैं। इस मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर दस प्रकाशन भी प्रकाशित किए गए।

अध्याय-6

संघीय क्षेत्रों में शिक्षा

संघीय क्षेत्रों में शिक्षा की व्यवस्था करना केन्द्रीय सरकार का एक विशेष दायित्व है। इस वर्ष के दौरान प्रत्येक संघीय क्षेत्र द्वारा जो शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की गईं तथा कार्यकलाप आयोजित किए गए उनका विवरण इस अध्याय में दिया गया है ।

दादरा और नागर हवेली

इस क्षेत्र के 160 प्राइमरी स्कूलों में 16,886 छात्र (10,223 लड़के और 6663 लड़कियां) दाखिल हैं, जिनमें 509 अनुसूचित जाति (279 लड़के और 230 लड़कियां) और 13,759 अनुसूचित जनजाति (8,507 लड़के और 5,252 लड़कियां) शामिल हैं । इस क्षेत्र में 4 हाई स्कूल और तीन उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के छात्र 2,429 (1531 लड़के और 898 लड़कियां) हैं । जिनमें 271 अनुसूचित जाति (138 लड़के और 79 लड़कियां) और 1187 अनुसूचित जनजाति (821 लड़के और 366 लड़कियां) हैं सभी उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक ड्राइंग, सिलाई और तकनीकी और कृषि संबंधी विषय आरंभ किए गए हैं । इस संघीय क्षेत्र में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों के लिए मध्याह्न भोजन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए निःशुल्क कापियां, पाठ्यपुस्तकों जैसी अन्य शैक्षिक सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इसमें 10 समाज कल्याण छात्रवास हैं जिसमें एक आश्रमशाला और छात्राओं के लिए 2 छात्रावास शामिल हैं जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति औा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्र रहते हैं जिनको निःशुल्क भोजन और स्थान उपलब्ध कराया जाता है। 1985-86 के दौरान इन छात्रावासों में 600 छात्र थे। संघीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को नियमित उपस्थिति के लिए कई वित्तीय रियायतें, वार्षिक परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार; कक्षा IX और X में संस्कृत में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन, प्रतिभाशाली छात्रों को एम.एस.सी./एच.एस.एस. परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने के लिए नकद पुरस्कार, छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 1985-86 के दौरान 2,000 प्रौढ़ छात्रों के लिए 66 केन्द्रों को खोलने की संभावना है ।

संघीय क्षेत्र के छात्रों के लिए चिकित्सा, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं । राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना अक्तूबर, 1983 से आरंभ की गई थी और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 412 प्राइमरी/मिडिल स्कूल शिक्षकों और 89 माध्यमिक स्कूल शिक्षकों को शामिल किया गया है । संघीय क्षेत्र की शैक्षिक संस्थाओं के विभिन्न शिक्षकों को संगणक साक्षरता कार्यक्रम/विषय अनुस्थापना कार्यक्रम व्यावसायिक मार्गदर्शन और जनसंख्या शिक्षा सेमिनार इत्यादि के लिए सेवारत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और सेमिनारों में भाग लेने के लिए भेजा गया।

पांडिचेरी

संघीय क्षेत्र पांडिचेरी का शैक्षिक रूप से विकसित राज्यों/संघीय क्षेत्रों में एक गौरवमय स्थान है जिसमें कुल साक्षरता दर 54.23% है। संघीय क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनसंख्या का साक्षरता दर 32.36% है।

गांव वासियों को घर के समीप इतनी शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है कि अब निवास स्थान 1 कि.मी. की दूरी पर हाई स्कूल है, 3 कि.मी. की दूरी पर मिडिल स्कूल और 5 कि.मी. की दूरी पर हाई स्कूल है। संघीय क्षेत्र में 109 प्राइमरी - पूर्व स्कूल है जिनमें छात्रों का नामांकन 5730 है। 356 प्राइमरी स्कूल है जिनमें छात्रों का नामांकन 91053 है, 103 मिडिल स्कूल है जिनमें छात्रों का नामांकन 44521 है,, 64 हाई स्कूल है जिनमें छात्रों का नामांकन 16447 है और 19 उच्चतर माध्यमिक स्कूल है जिनमें छात्रों का नामांकन 5484 है । स्कूलों में पर्याप्त योग्य कर्मचारी, पुस्तकालय पुस्तक शिक्षण सहायक और वैज्ञानिक उपस्करों जैसी सुविधाएं उपलब्ध है ।

स्कूलों में कुछ पाठ्येत्तर कार्यकलापों जैसे विज्ञान कार्नरों और अर्थशास्त्र क्लबों का आरंभ करना, पर विशेष बल दिया जा रहा है जिनके प्रति छात्रों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहवर्धक है। पांडिचेरी में 1 के.डब्ल्यू.डी.पी. केन्द्र को स्थापित होने के कारण स्कूलों में टी.वी. सेट उपलब्ध कराने का कार्य आरंभ हो गया है जिससे बच्चों के लिए शिक्षा बहुत दिलचस्प हो गई है। छात्रों के निःशुल्क वर्दियां पाठ्यपुस्तकों, स्टेशनरी सामग्री, नकद पुरस्कार और योग्यता पुरस्कार और योग्यता छात्रवृत्तियां जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है । प्राइमरी कक्षाओं के छात्रों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराना संघ शासित प्रशासन द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों में से एक है । इसके परिणाम प्रारंभिक स्तर में लगभग शत-प्रतिशत नामांकन हो सका है और इससे प्राइमरी स्तर में बीच में स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में 3.6% और मिडिल स्तर पर 6.2% की कमी हुई है।

चालू वर्ष में पांडिचेरी केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ ही विश्वविद्यालय शिक्षा शिविर पर पहुंच गई है। संघीय क्षेत्र अब अपने छात्रों के लिए सभी मुख्य पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है और इस अवस्था में इसकी पड़ौसी राज्यों पर निर्भरता कम हुई है । काम करने वाली महिलाओं और गृहणियों के लिए सांध्य कालेज खोलने का अभिनव प्रयोग किया गया है जिसकी प्रतिक्रिया उत्साहवर्ती रही है । पिछले वर्षों की तरह समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों को डिग्री स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती रही।

प्रौढ़ शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, एन.सी.सी., खेल और युवा कल्याण जैसे पहलुओं पर संघीय क्षेत्र प्रशासन का ध्यान जारी रहा ।

चालू शैक्षणिक वर्ष से पांडिचेरी इंजीनियरी कालेज में प्रथम वर्ष की कक्षाओं के आरंभ होने से पांडिचेरी में इंजीनियरी कालेज की महत्वपूर्ण मांग पूरी हो गई। विभाग ने पड़ौसी राज्यों के इंजीनियरी कालेज के छात्रों के लिए इंजीनियरी के विभिन्न विषयों जो कि पांडिचेरी इंजीनियरी में उपलब्ध नहीं थे, में कुछ स्थानों का प्रबन्ध किया । अल्प संख्यकों के लिए पूर्व-परीक्षा शिक्षण केन्द्र और अंग्रेजी भाषा के शिक्षण के लिए जिला केन्दों की स्थापना, कुछ ऐसे कार्य है जिनका उल्लेख किया जा सकता है।

अरुणाचल प्रदेश

हरे भरे पर्वतों और घाटियों का अरुणाचल प्रदेश 83,578 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। 1981 की जनगणना के अनुसार 3,000 आवासों में 6,31,839 लोग रहते हैं। इस क्षेत्र की 110 जातियां विभिन्न भाषाएं बोलती है और विभिन्न धर्मों पर विश्वास रखती है ।

2. सरकारी क्षेत्र में 249 प्राइमरी-पूर्व स्कूल 998 प्राइमरी स्कूल, 151 मिडिल स्कूल, 41 माध्यमिक स्कूल 23 उच्चतर माध्यमिक स्कूल और तीन कालेज हैं। इसके अतिरिक्त कई सहायता प्राप्त स्कूल हैं। प्राइमरी-पूर्व स्कूलों में नामांकन 6398, प्राइमरी स्कूलों (I—V) में 85613, मिडिल स्कूलों (VI—VIII) में 20993, माध्यमिक स्कूलों (IX—X) में 5484 और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों (XI—XII) में 2184 हैं। 1985-86 के दौरान कई संस्थाओं को खोला/उन्नत किया गया है।

3. (6-11 आयु वर्ग) के बच्चों के नामांकन का शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। स्कूल जाने वाल आयु के और अधिक बच्चों को आकर्षित करने के लिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण, स्कूली वर्दियां, स्टेशनरी, छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए वस्त्र, प्राइमरी, मिडिल और माध्यमिक/सीनियर माध्यमिक स्कूलों से सम्बद्ध छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को राशन के स्थान पर राशि, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए योग्यता छात्रवृत्तियां और मध्याह्न भोजन इत्यादि विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

4. 1984-85 के अन्त तक आर.एफ.एल.पी. के अंतर्गत 491 केन्द्र खोले गए थे। इस वर्ष के दौरान 300 केन्द्र खोले गए हैं जिससे इसकी कुल संख्या 791 हो गई है। राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत 370 केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिनमें 7491 प्रौढ़ नामांकित हैं। इस समय 13572 प्रौढ़ पुरुष और 7590 प्रौढ़ महिलाएं प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में नियमित रूप से जा रहे हैं। केन्द्रों में और अधिक प्रौढ़ों को आकर्षित करने के लिए कुछ और प्रोत्साहन आरंभ कर दिए गए हैं। महिला प्रौढ़ों के लिए केन्द्रों में सिलाई की मशीनें और बुनने की मशीनें प्रदान की गई। पुरुषों के लिए खेलें और क्रीड़ाएं आरंभ किए गए हैं और संगीत के साधन दिए गए हैं।

5. विद्यमान संख्या में 24 स्काउट ट्रूप, गाइड कंपनियां, बुल बुल फ्लाक और कब पैक जोड़े गए हैं। बंगलौर में राष्ट्रीय जेमबोरी में भाग लेने के लिए 150 स्काउटों और गाइडों को भेजा गया। पैट्रोला/लीडर स्काउटों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। इस वर्ष दो जूनियर डिवीजन एन.सी.सी. यूनिट (लड़कियों) और नौ जूनियर डिवीजन एन.सी.सी. यूनिट लड़कों) खोले गए हैं। एन.सी.सी. केडेट एन.सी.सी. निदेशालय द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग ले रहे हैं।

6. कालेजों में नामांकन 983 है। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को 210/- रु. और 240/- रु. प्रति माह छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। कालेजों को अरूणाचल प्रदेश विश्वविद्यालयों से संबद्ध किया गया है। कालेजों ने 1 अप्रैल, 1985 से कार्य करना आरम्भ किया।

7. शिक्षकों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देते हुए 1983-84 में शिक्षकों के लिए राज्य पुरस्कार की योजना आरम्भ की गई थी। चुने हुए शिक्षकों को 1500/- रु. नकद पुरस्कार और योग्यता प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

8. रा.शै.अनु.प्र.परि. द्वारा तैयार की गई हिन्दी और अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकें संघीय क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप अपनाई जा रही हैं। क्षेत्र में विज्ञान और गणित के शिक्षण को लोकप्रिय बनाने के लिए शिक्षकों को नई तकनीकों में प्रशिक्षित किया गया है।

चंडीगढ़

इस संघीय क्षेत्र में 260 स्कूल हैं, जिनमें राजकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, केन्द्रीय तथा गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल शामिल हैं और इसमें पूर्व-प्राथमिक से लेकर सीनियर माध्यमिक स्तर के छात्र आते हैं। ये सभी स्कूल प्रारंभिक स्तर पर 1,03,700 छात्रों से कुछ अधिक तथा माध्यमिक स्तर पर लगभग 18,400 छात्रों की शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वर्ष 1985-86 के दौरान प्रारंभिक स्तर (I—VIII) में नामांकन 1,03,700 है और माध्यमिक स्तर (IX—XII) में 18,400 है।

2. स्कूल जाने वाली आयु (6-14 वर्ष) के सभी योग्यछात्रों को नामांकित करने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं। जहां तक 6–14 आयु वर्ग के छात्रों का संबंध है इसमें 100 प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है और 6,000 से अधिक छात्रों को दाखिल करने के लिए नए स्कूल खोले गए।

3. संघीय क्षेत्र प्रशासन की उपलब्धियों में से निम्नलिखित कुछ का उल्लेख किया जा सकता है।

(क) यह ऐसे स्कूल हैं जहां प्रत्येक बच्चा आसानी से पहुंच सकता है।

(ख) संघीय क्षेत्र में कोई स्कूल नहीं है।

(ग) स्कूल भवन आकर्षित हैं और उनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि छोटे बच्चों की पढ़ाई को आरामदायक बनाती है।

(घ) समाज के कमजोर वर्गों के हित के लिए अधिकतर ग्रामीण और श्रमिक बस्तियों के स्कूलों में शिशु देख-रेख केन्द्र, बाल वाड़ी और नर्सरी कक्षाएं आरंभ की गई हैं।

4. यहां निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जाते हैं जैसे लड़कियों को उपस्थिति छात्र-वृत्तियां (3,600 लाभ-भोगी) अनुसूचित जाति के बच्चों को उपस्थिति छात्रवृत्तियां (82 लाभ-भोगी), अनुसूचित जाति के छात्रों को निःशुल्क लेखन सामग्री और वर्दियां (10,100 लाभ-भोगी) बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें (10,100 लाभ भोगी) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्रतिभा छात्रवृत्तियां (25 लाभ-भोगी) पढ़ाई में कमजोर अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए विशेष शिक्षण (2,200 लाभ-भोगी)और बच्चों को मध्याह्न भोजन (34,500 लाभ-भोगी) उपलब्ध हैं।

5. इस समय संघीय क्षेत्र में गैर औपचारिक शिक्षा के 20 केन्द्र चल रहे हैं जो कि पिछले वर्ष में 12 थे। ये केन्द्र अधिकतर सरकारी स्कूलों से सम्बद्ध हैं। इन केन्द्रों में लगभग 600 छात्रों को दाखिल किया गया है।

6. 1985-86 के दौरान 2 सीनियर माध्यमिक स्कूलों में व्यावसायिक विषय आरंभ किए गए हैं और आने वाले वर्षों में शेष स्कूलों को भी शामिल किया जाएगा।

7. चंडीगढ़ के स्कूलों में खेल-कूद नियमित कार्यकलाप हैं। स्कूली छात्रों को खेलों के कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा विभाग बड़ी और छोटी-छोटी खेलों में नियमित रूप से प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। छात्र राष्ट्रीय खेलों और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली अन्य खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। संघीय क्षेत्र के स्कूलों में मौके पर कला प्रतियोगिता एक नियमित कार्यकलाप है। वर्ष के दौरान 8,000 से अधिक छात्रों ने प्रतियोगिता के विभिन्न विषयों में भाग लिया। अन्य सह-पाठ्यचर्या और सांस्कृतिक कार्य स्कूल के नियमित कार्यकलापों का एक अंग है।

8. राज्य शिक्षा संस्थान चंडीगढ़, सेवारत पाठ्यक्रमों स्कूलों में मौके पर मार्गदर्शन देना शिक्षण साधनों में अनुस्थापन राज्य स्तर में छात्रों और उनके शिक्षकों के लिए अन्य सहपाठ्यचर्या कार्यकलापों का आयोजन और शैक्षिक निबंधों और लेखें के प्रकाशन के माध्यम से स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार उपलब्ध कराता है।

9. प्रौढ़शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत 6,0८0 सीखने वालों के लक्ष्य के स्थान पर 6,800 सीखने वालों को शामिल किया गया।

दिल्ली

संघीय क्षेत्र दिल्ली एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है और इसका अधिकतर शहरीकरण हो चुका है। वर्तमान कुल जनसंख्या में से स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या 52% से

अधिक है। प्राइमरी, मिडिल, माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक कक्षाओं का स्तर ब्यौ इस प्रकार है :—

(क) प्राइमरी स्तर की कक्षाएं I—V (6–11 आयु वर्ग) 8.02 लाख

(ख) मिडिल स्तर की कक्षाएं VI—VIII (11–14 आयु वर्ग) 4.18 लाख

(ग) माध्यमिक स्तर की कक्षाएं IX—X (14–16 आयु वर्ग) 1.92 लाख

(घ) सीनियर माध्यमिक स्तर की कक्षाएं (16–18 आयु वर्ग) 1.04 ला

दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग को प्रतिवर्ष मिडिल, माध्यमिक और सीनियर माध्य मिक स्तर के लगभग 33,000 छात्रों के अतिरिक्त दाखिले की आवश्यकता को पूरा कर होता है 1985 के दौरान विद्यमान 22443 सेक्शनों में 750 नए सेक्शन निम्नलिखि तरह से जोड़े गए :—

(1) 11 नए राजकीय मिडिल स्कूल खोलकर

(2) 8 शहरी स्कूलों का विभाजन करके

(3) 26 राजकीय मिडिल स्कूलों को माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत कर और

(4) 18 राजकीय माध्यमिक स्कूलों को सीनियर माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्न करके।

क्षेत्र में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों म बालिकाओं के वास्ते निःशुल्क परिवहन (4375 लाभ-ग्राही) स्कूल वर्दियों की निःशु आपूर्ति (50,000 लाभ-ग्राही) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के छात्रों लिए खुली योग्यता छात्रवृत्तियां (682 लाख ग्राही) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए उपचारी/विशेष शिक्षण कक्षाए (4000 लाभ-ग्राही); और रियायती मूल्यों पर कापियां (46,00,000 लाभ-ग्राही) प्रदान क गई है।

मिडिल स्तर पर स्कूलों की संख्या 343, माध्यमिक स्तर पर 238 और उच्चत माध्यमिक स्तर पर 620 है। प्रत्येक माध्यमिक स्कूल में एक मिडिल विभाग है तथ प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक स्कूल में मिडिल विभाग के साथ-साथ माध्यमिक विभाग भ है।

दिल्ली प्रशासन दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में 68 नियमित महिला समान शिक्षा केन्द्र और 25 अंश कालिक पुरूष समाज महिला केन्द्रों को चला रहा है।

शहरी परियोजना के अंतर्गत दिल्ली प्रशासन दिल्ली के शहरी क्षेत्रों में 20 प्रौढ़ शिक्ष केन्द्रों को चला रहा है। प्रत्येक परियोजना में 100 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र है जिसमें प्रत्येक केन्द्र में 20 सीखने वाले है। केन्द्रों में अधिकतम महिलाओं को दाखिल करने का प्रयास किय जा रहा है।

ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना और गैर-औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को भी उप युक्त प्राथमिकता दी जा रही है। वर्ष के दौरान कई प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अनु स्थापन कार्यक्रम आरंभ किए गए और इन कार्यक्रमों से 55 टी.जी.टी. और नए भर्ती किए गए/डी.वी.जी. परामर्शियों को लाभ पहुंचा। वर्ष के दौरान शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान ने प्रशिक्षण देना जारी रखा प्रतिवर्ष 100 शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करते है।

शारीरिक शिक्षा के पहलू पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। दिल्ली खेल परिषद दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में कई खेल कूद कार्यकलापों का आयोजन करती है। साहित्य कला परिषद युवा और प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को अनुदान देती आ रही है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रौढ़ साक्षरता, गैर-औपचारिक शिक्षा, वृक्षारोपण, मध्याह्न भोजन, पाठ्यपुस्तकों की निःशुल्क आपूर्ति वर्दियों की निःशुल्क आपूर्ति जैसे कार्यक्लापों का आयोजन कर रहा है।

गोवा दमन और दीव

गोवा दमन और दीव में वर्ष 1985-86 के दौरान प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा I से VII) में नामांकन 2,21,695 था जो कि 1984-85 में 2,19917 था। 1985-86 के दौरान माध्यमिक शिक्षा में नामांकन 55,250 था जो कि 1984-85 में 54,288 था। उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं का नामांकन 1984-85 के 11,005 की तुलना में 1985-86 में 12,221 रहा।

यहां सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के 18 कालेज हैं जिनमें से 9 सामान्य धारा जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं शेष वास्तुकला, चिकित्सा, फार्मेसी, डेन्टल, इंजीनियरी, ललित कला विधि, शिक्षक प्रशिक्षण कालेज हैं। इन सभी कालेजों में कुल नामांकन 1985-86 में 8,974 रहा जो कि 1984-85 में 8,223 था।

स्कूल पूर्व शिक्षा से संबंधित योजना संघीय क्षेत्र में 1983 में लागू की गई और 1984-85 के अंत तक 68 केन्द्र खोले गए थे जिसमें 1,648 छात्र शामिल थे। वर्ष 1985-86 के दौरान 14,410 को शामिल किया गया। आश्रमशाला जन-जातीय छात्रों के लिए निःशुल्क खाने और रहने की व्यवस्था कर रहे हैं।

गोवा दमन और दीव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए 19 व्यावसायिक विषयों को स्वीकृत किया। 22 उच्चतर माध्यमिक स्कूलों/एककों ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम आरंभ कर दिए हैं। संघीय क्षेत्र के कुछ स्कूलों को संगणक व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है और उनके माध्यम से शिक्षण दिया जा रहा है। बाल भवन बोर्ड का गठन किया गया है और पणजी में एक बाल भवन स्थापित किया जा रहा है।

1985-86 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 390 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिसमें 6847 प्रौढ़ (2571 पुरुष 4276 महिलाएं) शामिल हैं।

प्राइमरी से दसवीं स्तर के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। ग्यारहवीं और बारवीं कक्षा के उन छात्रों जिनके अभिभावकों की आय 4800/- रु. वार्षिक है, को भी निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है।

स्कूल जाने वाले छात्रों (6–11 आयु वर्ग) को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा है और इस योजना से लाभान्वित छात्रों की संख्या 10,000 है। 1984-85 के दौरान प्राइमरी और मिडिल स्कूल स्तर के 15,534 छात्रों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए। 1985-86 के दौरान लगभग, 10,000 छात्रों को शामिल करने की संभावना है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्राइमरी/मिडिल स्तर तक पुस्तक सहायता, और मिडिल/माध्यमिक और कालेज स्तर तक छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

गोवा इंजीनियरी कालेज सिविल मेकेनिकल और इलैक्ट्रीकल इंजीनियरी में पाठ्यक्रम चला रहा है जिसकी प्रत्येक शाखा में 40 छात्रों की क्षमता है।

स्कूलों में शारीरिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है और शारीरिक शिक्षा स्काउट और गाइड एन.सी.सी. और खेल कूद के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए मार्गदर्शन दिया जाता है। सेवारत कार्मिकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और सेमिनार भी आयोजित किए जाते हैं।

मिजोरम

मिजोरम में प्राथमिक शिक्षा कक्षा 1-4., मिडिल शिक्षा कक्षा 5-7 और उच्च शिक्षा कक्षा 8–10 तक है। अभी हाल ही में कुछ मिडिल और उच्च स्कूलों को सरकारी स्कूलों के अधिकार में लिया गया है तथा कई स्कूलों को अनुदान की अभाव प्रणाली के अंतर्गत लिया है। आइजोल और लुंगलेई में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की भरती क्षमता में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। मिजोरम में स्कूल खोलने के लिए पहुंच क्षेत्र, और दूरी इत्यादि जैसी सामान्य कसौटियों का स्थलाकृति की विशेषज्ञता के कारण अन्धानुकरण नहीं किया जाता।

2. शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षित लोगों की संख्या पर्याप्त रूप से बढ़ी है। विज्ञान प्रोन्नति के अंतर्गत, विज्ञान प्रेरणा पाठ्यक्रम विज्ञान और गणित के शिक्षण के विशेष प्रशिक्षण के रूप में भी आयोजित किया गया। जनजातीय अनुसंधान संस्थान, मिजोरम दुर्लभ तथा पुरानी पुस्तकों, नई पुस्तकों के पुनर्मुद्रण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है तथा लोगों को परम्परागत नृत्यों और संगीत इत्यादि में भी प्रशिक्षित कर रहा है। पुस्तकालय सेवाओं को भी अपेक्षित महत्व दिया जा रहा है तथा छोटे ग्रामीण पुस्तकालय मिजोरम में कार्य कर रहे हैं।

3. पिछले वर्षों में पूर्व-मैट्रिक छात्रवृत्तियां, उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्तियां तथा प्रतिभा-खोज छात्रवृत्तियां, सैनिक स्कूल वजीफे तथा छात्रावास वजीफे जैसी छात्रवृत्तियां, छात्रों को प्रदान की गई तथा पिछले वर्षों में लाभान्वित होने वालों की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है।

4. अवधि के दौरान विभिन्न साक्षरता सेमिनार एवं शिविर आयोजित किए गए। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, स्कूल शिक्षा केन्द्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। विभिन्न तरीकों से लोगों की सहायता सेवा पहले से ही स्थापित है। प्रौढ़ (सामाजिक) शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को आवश्यक सहायता अनुदान प्रदान किए गए हैं।

अंडमान और निकोबार

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शैक्षिक संस्थाओं के अंतर्गत सीनियर सैकण्डरी स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, मिडिल स्कूलों, प्राथमिक स्कूलों तथा पूर्व-प्राथमिक स्कूलों के अतिरिक्त एक सरकारी कालेज, एक पालिटेक्निक, एक बी.एड. कालेज, एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान आते हैं। इसके अतिरिक्त संघीय क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्राइवेट नर्सरी स्कूलों और बाल-वाड़ियों की एक बड़ी संख्या कार्यरत है।

2. वर्ष 1985-86 के दौरान, कुछेक नए प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं तथा कुछेक प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूलों तक बढ़ा दिया गया है। कुछ मिडिल स्कूलों को माध्यमिक स्कूलों में तथा कुछ माध्यमिक स्कूलों को सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों तक बढ़ा दिया गया है। विभिन्न स्थानों में नामांकन की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न माध्यमों में अतिरिक्त वर्ग प्रारम्भ किए गए हैं।

3. प्रारम्भिक स्तर के बच्चों को मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें तथा माध्यमिक स्तर के भी कुछ बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान की गई। आठवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को मुफ्त दोपहर का भोजन इसी प्रकार सभी जनजातीय छात्रों की मुफ्त पाठ्य-सामग्री के कमजोर समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों को मुफ्त वर्दियां प्रदान की गई।

4. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान ने बी.एड. और जे.बी.टी. पाठ्यक्रमों को संचालित करना जारी रखा हुआ है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संघीय क्षेत्र में 200 से अधिक केन्द्र कार्यरत हैं। इन प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में वर्तमान नामांकन लगभग 4,500 है।

5. वर्ष के दौरान विभिन्न स्थानों पर विज्ञान से संबंधित सेमिनार कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां आयोजित की गई। समेकित शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के वास्ते चुना गया तथा प्रशिक्षण समाप्त करने के पश्चात् उन्हें विकलांगों को पढ़ाने के लिए स्रोत शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया।

लक्षद्वीप

प्रशासक सभी विभागों का मुख्य है तथा शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग का नियन्त्रण अधिकारी है।

शिक्षा संस्थानों में उच्च स्कूलों तथा सीनियर स्कूलों, जूनियर स्कूलों और नर्सरी स्कूलों के अतिरिक्त दो कालेज हैं।

प्राथमिक शिक्षा सभी द्वीपसमूहों में प्रदान की जाती है। पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्तमान वर्ष में प्राथमिक कक्षाओं और साथ ही उच्च स्कूल में भी छात्रों के नामांकन में पर्याप्त सुधार हुआ है। प्राथमिक और मिडिल स्कूल कक्षाओं में बच्चों को पाठ्यपुस्तकें, लेखन-सामग्री एवं दोपहर का भोजन मुफ्त प्रदान किया जाता है।

उच्च स्कूलों में पढ़ रहे देशी छात्रों को प्रतिमास 40 रु. की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करने की परियोजना जारी की जा रही है। वरिष्ठ श्रेणी एन.सी.सी. तथा कनिष्ठ श्रेणी एन.सी.सी. (नौसेना) संघशासित क्षेत्र में कार्यरत हैं। वरिष्ठ श्रेणी और कनिष्ठ श्रेणी एन.सी.सी. कैडेटों दोनों के लिए शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

जवाहर लाल नेहरू कालेज, कावारती तथा महात्मा गांधी कालेज, एंड्रोथ में लक्षद्वीप द्वीपसमूह के 600 से अधिक छात्र हैं जो मुख्य भूमि के विभिन्न शिक्षा संस्थानों में दाखिल हैं तथा मुख्य भूमि के इंजीनियरी तथा मेडिकल कालेजों इत्यादि में उनके लिए कई सीट आरक्षित है। वर्तमान अनुमोदित छात्रवृत्ति नियमों के अनुसार लक्षद्वीप के अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मुख्यभूमि पर शिक्षा संबंधी व्यय प्रशासन द्वारा वहन किया जाता है।

अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन तथा शिक्षक मंच सभी द्वीपसमूहों में कार्य कर रहे हैं। स्काउट दल तथा बालिका गाइड विभिन्न स्कूलों में कार्य कर रहे हैं। इन दलों को वर्दियां तथा प्रशिक्षण सामग्री प्रदान की गई है। इस समय द्वीपसमूह में 30 से अधिक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र कार्यरत हैं।

अध्याय 7

छात्रवृत्तियां

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन शिक्षा विभाग कई छात्रवृत्ति कार्यक्रमों का संचालन करता है इनमें अन्य देशों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं। विभाग द्विपक्षी आधार पर अथवा अन्यथा अन्य देशों के राष्ट्रिकों को भी छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। लागू की गई मुख्य योजनाओं का उल्लेख नीचे किया गया है :—

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत, राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासकों के माध्यम से छात्रवृत्तियां योग्यता एवं आय के आधार पर दी जाती हैं। वर्ष 1985-86 के दौरान 27,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। 1 जुलाई, 1981 से छात्रवृत्तियों की दरें बढ़ा दी गई थी, ये अध्ययन की अवधि के आधार पर दी जाती हैं अध्येताओं के लिए 60/- रुपए से प्रतिमाह 120/- रु. प्रतिमाह तक और छात्रावासों में रहने वालों के लिए इन छात्रवृत्तियों की दर 100/- रु. से 170/- रु. प्रतिमाह तक अलग-अलग है।

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत, वर्ष 1984-85 में 20,000 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। छात्रवृत्तियां योग्यता-एवं-आय के आधार पर प्रदान की जाती हैं। यह योजना राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के माध्यम से लागू की जा रही है। अध्ययन के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ऋण की राशि 720/- रु. से 1720/- रुपये प्रतिवर्ष तक बढ़ती-घटती रहती है।

स्वीकृत अवासीय माध्यमिक स्कूलों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य प्रतिभावान लेकिन उन निर्धन छात्रों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करना है जो केवल अपने खर्चे पर अच्छे आवासीय स्कूलों में अध्ययन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक वर्ष 11 से 12 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों को जिनके अभिभावकों की आय 500 रुपये प्रतिमाह से अधिक न हो, को योग्यता-एवं-आय आधार पर 500 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। पचास प्रतिशत छात्रवृत्तियां अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर प्रदान की जाती हैं और शेष पचास प्रतिशत राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों को जनसंख्या के आधार पर प्रदान की जाती हैं बशर्ते कि वे निर्धारित मानक को पूरा करते हैं। छात्रों का चयन दो परीक्षाओं-राज्य/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों द्वारा संचालित प्रारम्भिक परीक्षा तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा संचालित अन्तिम परीक्षा के आधार पर किया जाता है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और $7\frac{1}{2}\%$ छात्रवृत्तियां आरक्षित हैं। ये छात्रवृत्तियां माध्यमिक स्कूली शिक्षा की पूरी अवधि जिसमें स्वीकृत आवासीय स्कूलों में शिक्षा का जमा दो स्तर भी शामिल है, के लिए धार्य हैं। अध्येता जब खर्च, वर्दी भत्ता, सरकार द्वारा निर्धारित दरों/सीमा पर भ्रमण प्रभार के अलावा शिक्षा शुल्क की पूरी राशि, आवासीय प्रभार, पुस्तकों और लेखन-सामग्री की लागत के पात्र हैं। अध्येताओं और उनके अनुरक्षकों को निर्धारित दरों पर यात्रा भत्ता भी अनुमत्य है।

हिन्दी में उत्तर-मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

1955-56 में शुरू की गई इस योजना के उद्देश्य,, अहिन्दी भाषी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और इन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों को प्रशिक्षण तथा अन्य पद जहां हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है, के लिए उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराना है। वर्ष 1985-86 के दौरान विभिन्न अहिन्दी भाषी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों को 2500 छात्रवृत्तियां आवंटित की गई हैं। छात्रवृत्ति

की दरें, जो अध्ययन की अवधि तथा राज्य/संघशासित क्षेत्र जिनमें हिन्दी का अध्ययन किया जा रहा है। निर्भर करती है। 50/- रुपए से 125/- रुपए प्रति माह तक अलग-अलग है।

संस्कृत के अलावा अरबी तथा फारसी जैसी श्रेष्ठ भाषाओं के अध्ययन में लगी पारम्परिक संस्थाओं के छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष बीस छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। वर्ष 1984-85 में 20 छात्रों को इन छात्रवृत्तियों के लिए चुना गया था ।

ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के प्रतिभाशाली बच्चों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां

वर्ष 1984-85 में 33,000 छात्रवृत्तियां आवंटित की गई। इन छात्रवृत्तियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

		छात्रवृत्तियों की कुल संख्या
(क) सामान्य वर्ग	प्रति सामुदायिक विकास खण्ड को तीन छात्रवृत्तियां	15,000
(ख) भूमिहीन श्रमिकों के बच्चे	प्रति सामुदायिक विकास खण्ड को दो छात्रवृत्तियां	10,000
(ग) अनुसूचित जाति के बच्चे	प्रति सामुदायिक विकास खण्ड को एक छात्रवृत्ति तथा प्रति सामुदायिक विकास खण्ड जिनकी अनु.जा. की जनसंख्या 20 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हो, को एक अतिरिक्त छात्रवृत्ति।	6,500
(घ) अनु. ज. जा. के बच्चे	प्रति जनजातीय सामुदायिक विकास खण्ड को तीन छात्रवृत्तियां	1,500

योजना, राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्र के प्रशासनों के माध्यम से लागू की जा रही है।

सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के अन्तर्गत, अफ्रीका, एशिया और अन्य देशों के चुनिन्दा राष्ट्रिकों को भारत में उच्च शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 180 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। इनका उद्देश्य भारत और विदेशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बधों को प्रोत्साहित करना और भारत में उच्च शिक्षा के लिए उनके राष्ट्रिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना है। जबकि अधिकांश छात्रवृत्तियां उन छात्रों के लिए, जिस देश के वे हैं, निर्धारित की जाती हैं, कुछ छात्रवृत्तियां उन छात्रों को दी जाती हैं जो मूलत: भारतीय हों लेकिन विदेशों में रह रहे हों।

अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की राशि 600/- रुपए प्रतिमाह है और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 750/- रुपए प्रतिमाह। इसके अतिरिक्त, छात्रों को 500/- रुपए प्रतिमाह ग्रीष्म अवकाश के रूप में दिए जाते हैं। अध्येताओं द्वारा चिकित्सा पर वहन किए गए व्यय तथा अध्ययन दौरों की भी प्रतिपूर्ति की जाती है। जबकि शिक्षा-शुल्क और अन्य अनिवार्य खर्च इस मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है, और छात्रावास तथा मैस का खर्च अध्येताओं द्वारा वहन किया जाता है।

बंगला देश के राष्ट्रिकों के लिए छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत, बंगला-देश के राष्ट्रिकों को प्रत्येक वर्ष 100 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। चयन, ढाका में स्थित भारतीय उच्चायोग के परामर्श से बंगलादेश सरकार द्वारा किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियों के दरों में संशोधन किया गया है। इस समय अवर-स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए छात्रवृत्ति की राशि 600/- प्रतिमाह और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 750/- रुपए प्रतिमाह है। इसके अतिरिक्त

बंगलादेश के छात्रों को इस वर्ष (1984-85) के दौरान संस्कृत और पाली भाषाओं में अध्ययन करने के लिए 10 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं ।

मारीशस के राष्ट्रिकों को छात्रवृत्तियां

भारत सरकार द्वारा मारीशस के राष्ट्रिकों को दी जाने वाली कुल छात्रवृत्तियों की संख्या को 100 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी शामिल हैं। ग्रीष्म कालीन अवकाश, पुस्तक भत्ता तथा संस्थाओं के शिक्षा-शुल्क अनिवार्य प्रभारों के अतिरिक्त तथा उनपर अंतर्राष्ट्रीय आने-जाने की यात्रा के अलावा उत्तर-स्नातक पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति का मूल्य 750 रुपए प्रतिमाह और अवर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए 600 रुपए प्रतिमाह है। चूंकि छात्रवृत्तियों की संख्या में ऐसे समय में वृद्धि कर दी गई है जबकि अधिकांश विश्वविद्यालयों में नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है मारीशस के राष्ट्रिकों को ही वर्ष 1985-86 के दौरान अतिरिक्त छात्रवृत्तियां प्रदान की जा सकेंगी।

विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां

वर्ष 1985-86 में छात्रवृत्ति के लिए 50 अध्येताओं को चुना गया है। ये छात्रवृत्तियां, मुद्रण प्रौद्योगिकी, नौ-सेना वास्तुकला में स्नातकोत्तर अध्ययन और कागज-प्रौद्योगिकी तथा डाक्टोरल और मानविकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्तर-डाक्टोरल अध्ययन के लिए प्रदान की जाती हैं। इन छात्रवृत्तियों के लिए केवल वे ही छात्र पात्र होते हैं जिनके अभिभावकों की आय सामान्य मानक छूट को छोड़कर सभी साधनों से 1000/- रुपए प्रतिमाह अथवा इससे कम होती है।

विदेशी सरकारों/संगठनों, संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां

मंत्रालय ने, निम्नलिखित देशों के लिए नामजदगियां की हैं :—पोलैण्ड-7, सोवियत संघ-8, जर्मन जनवादी गणराज्य-10, चकोस्लोवाकिया 3, बल्गारिया-4, एफ.आर. डी.-11 डेनमार्क-2, फ्रांस-29, जापान-10, मटसूमे अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां (जापान)-8, होशी विश्वविद्यालय शिक्षावृत्ति (जापान)-4, नीदरलैण्ड-4, आस्ट्रिया-2, स्वीडन-1, स्पेन-2, नार्वे-6, इटली-21, मैक्सिको-4, तुर्की-4, कोरिया-1, संयुक्त राज्य संघ अमेरिका-3, इण्डोनेशिया-2, हंगरी-9, त्रिनिदाद और तोबेगो-2, जमैका-3, हांगकांग-1, न्यूजीलैंड-5, आस्ट्रेलिया-4, जवाहरलाल नेहरू मैमोरियल न्यास (यू.के.)-2, विदेशी और राष्ट्र मण्डलीय छात्रवृत्तियां-6. अगाथा हैरीसन मैमोरियल शिक्षावृत्तियां-1, ब्रिटिश तकनीकी सहयोग-7 ।

यू.के./कनाडा की सरकारों द्वारा प्रदान की गई राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्तियां और शिक्षावृत्तियां

138 नामजदगियों में से दिसम्बर, 1985 तक 67 छात्रों का अनुमोदन प्राप्त हुआ था।

राष्ट्रमंडलीय शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम

वर्ष 1985-86 के दौरान नाइजीरिया, माल्टा और न्यूजीलैंड से तीन वरिष्ठ शिक्षाविदों को विजिटरशिप के लिए चुना गया है।

आंशिक वित्तीय सहायता योजना

इस योजना के अन्तर्गत विदेशों में अध्ययन के इच्छुक उन भारतीय छात्रों/शिक्षाविदों को ऋण के रूप में 6,000/- रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिन्होंने, अन्य स्रोतों से छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता पहले प्राप्त कर ली है परन्तु उनके पास धन की कमी है। आलोच्य अवधि के दौरान, इस योजना के अन्तर्गत 4 उम्मीदवारों को सहायता दी गई।

ब्रिटिश विजिटरशिप परिषद कार्यक्रम, 1985

ब्रिटिश विजिटरशिप परिषद् कार्यक्रम के अन्तर्गत उनके निर्धारित विशेष क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास के विनिमय के लिए 150 वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और चिकित्सा विशेषज्ञों को लाभान्वित किया गया।

भारत में अध्ययन/प्रशिक्षण के लिए विदेशी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

आलोच्य वर्ष के दौरान, भारत ने द्विपक्षी सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित देशों को लगभग 300 छात्रवृत्तियों की पेशकश की :—सेनेगल, फ्रांस, जर्मन संघीय गणराज्य, यू.एस.एस.आर.,

फिलिपाइन्स, बेल्जियम, नार्वे, इराक, मिस्र, अरब गणराज्य, पोलैण्ड, तुर्की, चैकोस्लोवाकिया, मैक्सिको, अफगानिस्तान, यूनान, सोमालिया, इटली, युगोस्लाविया, सीरिया, यमन लोकतांत्रिक गणराज्य, हंगरी, वियतनाम, बुलगारिया, तुनिसिया, क्यूबा, पर्तगाल, मलेशिया, कतार, श्रीलंका, बेहरीन, बर्मा, ईरान, केनया, कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य, मारिशस, जापान, अल्जीरिया, यूनाईटेड अरब एमिरेट्स, साइप्रस, सूडान, इथ्योपिया, जोर्डन ।

राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्तियां/ शिक्षावृत्ति योजना/ राष्ट्रमंडलीय शिक्षा योजना

योजना के अन्तर्गत, निम्नलिखित देशों के विभिन्न अध्येताओं को 75 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं अर्थात् आस्ट्रेलिया, बारबोडोस, कनाडा, साइप्रस, बोत्सवाना, फिजी द्वीप, केनया, लेसोथो, मलेशिया, मारिशस, नाइजीरिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साइरेलिओर, सिर्यकेल्लेस, स्वीट्जरलैंड, सेन्ट लूसिया, ग्रेनाडा, डोमिनिका, तंजानिया, टोंगा, नाकरा, मालावी, पापुआ, न्यू गुयाना और पश्चिमी सामोआ, त्रिनिदाद और तोबागो, यूनाइटेड किंगडम, यूगांडा और जाम्बिया को छोड़कर अन्य दक्षिण प्रशान्त महासागर के द्वीप।

डा. अमिलकार काबूल छात्रवृत्ति

अफ्रीकी छात्रों को डा. अमिलकार काबूल छात्रवृत्ति के अन्तर्गत एक छात्रवृत्ति की पेशकश की गई है।

डा. एनूयूरिनबेवन मेमोरियल छात्रवृत्ति

यूनाइटिड किंगडम को डा. एन्यूनिर बेवन स्मारक में फेलोशिप के अन्तर्गत एक छात्रवृत्ति की पेशकश की गई है।

कोलम्बो योजना की तकनीकी सहयोग योजना स्कीम

कोलम्बो योजना के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित देशों के अध्येताओं को वित्तीय सहायता देने की पेशकश की गई है : अफगानिस्तान, बर्मा, बंगलादेश, भूटान, फिजी, ईरान, इण्डोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, नेपाल, फिलीपीन्स, पापुआ, न्यू गुयाना, कोरिया, श्रीलंका, सिंगापुर और थाइलैण्ड ।

विशेष राष्ट्रमंडलीय सहायता योजना

विशेष राष्ट्रमंडलीय अफ्रीकी सहायता योजना के अन्तर्गत विदेशों के अध्येताओं को दी गई सहायता में ये शामिल हैं : बोट्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाबवे।

शिल्प अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रमंडलीय शिक्षा सहयोग योजना

रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय, के नियन्त्रणाधीन विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न ट्रेडो अनुदेशकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के राष्ट्रमंडलीय देशों के राष्ट्रिकों को एक वर्ष की अवधि के लिए दस विशेष छात्रवृत्तियां देने की पेशकश की गई थी । विशेष छात्रवृत्तियां (बर्सरी) किसी विशेष देश के लिए निर्धारित नहीं की गई है।

अध्याय 8

पुस्तक संवर्धन और कापीराइट

पुस्तकें, शिक्षा का एक अनिवार्य साधन हैं। देश में शिक्षा की सुविधाओं के प्रसार से पुस्तकों की मांगों में कोटि और मात्रा दोनों में बढ़ोतरी हुई है। विभिन्न विषयों पर बहुत बड़ी मात्रा में पुस्तकें प्रकाशित की जानी हैं और इन्हें प्रकाशनों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। पुस्तक संवर्धन के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम हैं--सस्ते मूल्यों पर अच्छे साहित्य का निर्माण, स्वदेशी लेखन को प्रोत्साहन, भारतीय पुस्तक उद्योग को उसकी समस्याओं का समाधान तथा लोगों में पढ़ने की आदत को लोकप्रिय बनाना। इस सम्बन्ध में संचालित कुछ कार्यक्रमों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफों में दिया गया है।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना, सस्ते मूल्यों पर अच्छी पठन सामग्री प्रकाशित करने और ऐसी सामग्री के प्रकाशन को प्रोत्साहित करने तथा लोगों में पुस्तकों के प्रति अभिरुचि जागृत करने के उद्देश्य से सन् 1957 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए न्यास, भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में अच्छी कोटि की पुस्तकें प्रकाशित कर रहा है। पुस्तकों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए पुस्तक-लेखन के विभिन्न पहलुओं पर न्यास राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर पुस्तक मेलों और सेमिनार और संगोष्ठी भी आयोजित करता है। न्यास (भारतीय प्रकाशन उद्योग की ओर से) पुस्तक निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए विदेशों में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनियों में भी भाग लेता है। मंत्रालय और न्यास एक दूसरे के निकट सहयोग से कार्य करते हैं। न्यास ने वर्ष के दौरान दो क्षेत्रीय कार्यालय, एक बंगलोर और दूसरा बम्बई में खोला है तथा आठ नये पुस्तक केन्द्र, अमृतसर, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, मैसूर, शान्ति-निकेतन और नई दिल्ली में खोले हैं।

प्रकाशन कार्यक्रम

ऐसी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक मालाएं जिनके अन्तर्गत न्यास द्वारा पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं :--भारत-भूमि तथा लोग, राष्ट्रीय जीवनियां, यंग इण्डिया लाइब्रेरी, भारत की लोक कथाएं, लोकप्रिय विज्ञान और आज का विश्व। अपनी स्थापना से लेकर 31 मार्च, 1985 तक न्यास ने इन पुस्तक मालाओं के अन्तर्गत 2,920 पुस्तकें (543 अंग्रेजी में तथा 2,377 भारतीय भाषाओं में) प्रकाशित की हैं। 1985-86 के दौरान न्यास ने दिसम्बर के अंत तक 95 पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

उपरोक्त पुस्तक मालाओं के अतिरिक्त न्यास के पास राष्ट्रीय एकता की प्रोन्नति के लिए आदान-प्रदान और नेहरू बाल पुस्तकालय नामक दो प्रमुख प्रकाशन कार्यक्रम भी हैं। आदान-प्रदान माला के अंतर्गत, न्यास ने अब तक विभिन्न भाषाओं में 609 पुस्तकें प्रकाशित की हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 18 प्रक्षिप्त प्रकाशनों में से 10 पुस्तकें प्रकाशित की जाने की संभावना है। नेहरू बाल पुस्तकालय माला के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1985 तक 1139 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 15 और पुस्तकें प्रकाशित किए जाने की संभावना है।

पुस्तक मेले

न्यास द्वारा राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तरों पर पुस्तक मेलों तथा पुस्तक समारोहों का भी आयोजन किया जाता है। न्यास ने अब तक भारत के महत्वपूर्ण महानगरों में 12 राष्ट्रीय पुस्तक मेले तथा 102 क्षेत्रीय पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की है। वर्ष 1985 के दौरान

न्यास ने भुवनेश्वर में पुस्तक समारोहों, पटना में राष्ट्रीय पुस्तक मेले, इलाहाबाद में राष्ट्रीय बाल मेले का आयोजन किया और कलकत्ता और नई दिल्ली में केवल बंगलादेश की पुस्तकों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। न्यास ने फरवरी 1986 में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला भी आयोजित किया।

विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की सहायता प्राप्त योजना

स्वदेशी लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय लेखकों द्वारा लिखी गई विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की सहायता प्राप्त प्रकाशन की योजना मंत्रालय के पास है ताकि छात्रों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करायी जा सकें। यह योजना, राष्ट्रीय न्यास के माध्यम से 1970 से कार्यान्वित की जा रही है। मार्च, 1985 तक सहायता प्राप्त पुस्तकों की कुल संख्या 696 है और अप्रैल–दिसम्बर, 1985 तक 46 और पुस्तकों को सहायता प्रदान की गई। 31 मार्च 1986 तक 30 और पुस्तकों को सहायता दी जाने की आशा है।

इस योजना के क्षेत्र में मूल रूप से अंग्रेजी की ही पुस्तकें शामिल की जाती थीं, उसे बढ़ा दिया गया है ताकि इसमें हिन्दी में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें तथा अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में पोलिटेक्निक स्तर की तकनीकी पुस्तकें भी शामिल की जा सकें।

विदेशी मूल की विश्वविद्यालय स्तर की सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन

भारतीय विश्वविद्यालयों के छात्रों को विदेशी-मूल की मानक पुस्तकें, सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए, मंत्रालय द्वारा यू.के., अमेरिका और सोवियत रूस की सरकारों के सहयोग से तीन द्विपक्षीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए पुस्तकों के नवीनतम संस्करणों पर विचार किया जाता है और उनका मूल्यांकन यह देखने के लिए उपयुक्त विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा किया जाता है कि पुस्तकें भारतीय छात्रों के लिए उपयुक्त हैं अथवा नहीं। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक लगभग 720 ब्रिटिश, 1620 अमेरिकी तथा 530 रूसी पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद्

वर्ष 1983 में राष्ट्रीय पुस्तक विकास की स्थापना पुस्तक क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रकार के हितों के एक प्रतिनिधि निकाय के रूप में की गई। अन्य बातों के साथ-साथ इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :—(1) देश की समग्र जरूरतों के संदर्भ में पुस्तक उद्योग के विकास के लिए मार्गदर्शी रूप रेखाएं निर्धारित करना। (2) लोगों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना। (3) लेखन, विशेषकर भारतीय भाषाओं में, को बढ़ावा देना और लेखकों के हितों की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाना। (4) राष्ट्रीय पुस्तक नीति का प्रारूप तैयार करना।

परिषद् द्वारा, कागज की कमी और इसकी अनुपलब्धता, पुस्तक उद्योग में उधार लेने की सुविधा के अभाव, पुस्तक आयात नीति, पुस्तक वितरण की समस्या, एक व्यापक पुस्तक नीति की आवश्यकता और लेखक प्रकाशक संबंध में सुधार की आवश्यकताओं के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए बड़ी संख्या में सिफारिशें की गई। इन सिफारिशों का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है।

राष्ट्रीय पुस्तक नीति, जिसमें सभी क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तक प्रकाशन तथा पुस्तक प्रकाशन से अन्तर-सम्बन्धित पहलू भी शामिल हैं, का प्रारूप तैयार करने के लिए मार्च, 1985 में स्थापित एक कार्य दल द्वारा अप्रैल, 1986 तक अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है।

अन्य पुस्तक प्रसार कार्यक्रम

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1985 के दौरान भारतीय एवं रूसी लेखकों के प्रतिनिधिमंडलों ने विचार विनिमय किया। इस अवधि के दौरान भारतीय लेखकों के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने फ्रांस की यात्रा की।

इण्डो-सोवियत साहित्यिक परियोजना

इण्डो-सोवियत समिति ने दोनों देशों के समकालीन रचनात्मक प्रतियों क प्रकाशित करने के उद्देश्य से एक परियोजना तैयार की, जो 1995 तक भारत औ सोवियत संघ द्वारा 20वीं शताब्दी की साहित्यिक रचनाओं के अनुवादक प्रकाशन करना है।

पुस्तकों का आयात

1985-86 के दौरान, उदार आयात नीति को जारी रखा गया और खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं समाचार पत्रों तथा भाषाओं के सीखने के लिए रिकार्डों के आयात की अनुमति दी गई। इस सुविधा के साथ यह शर्त है कि एक आयातकर्ता एक पुस्तक की केवल 1000 प्रतिय का आयात ही कर सकता है और यदि किसी एक पुस्तक की एक हजार से अधिक प्रतिय को आयात करने का प्रस्ताव है, तो इस मंत्रालय की अनुमति आवश्यक होगी।

मान्यता प्राप्त संस्थाएं खुली आम लाइसेंस पद्धति के अंतर्गत शैक्षिक प्रकृति की शिक्षण सामग्री, लघु फिल्में और लघु फिशें आयात कर सकती है। जिन पुस्तकों के भारतीय पुनर्मुद्रणों के संस्करण उपलब्ध हैं उन संस्करणों के विदेशी आयात की अनुमति नहीं दी जाती है। भारतीय प्रकाशनों के विदेशी पुनर्मुद्रणों की भी अनुमति नहीं दी जाती है।

जो पुस्तक विक्रेता 3 लाख रुपए या इससे अधिक कीमत की पुस्तकें खरीदते हैं, वे अपनी खरीद के 10 प्रतिशत तक की पुस्तकें आयात करने के लिए आयात लाइसेंस वास्ते आवेदन करने के हकदार हैं। यह खुली लाइसेंस नीति के अंतर्गत आयात से अलग है। इसके अतिरिक्त मान्यता प्राप्त स्कूल, कालेज और पुस्तकालय लाइसेंस योग्य वस्तुएं आयात करने के लिए 25,000/- रु. तक की कीमत के आयात लाइसेंस के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई है।

आयातकर्ता को आयात लाइसेंस प्रस्तुत किए बिना पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं वाले डाक पार्सल छुड़ाने के लिए रियायतें वर्ष 1985-86 के दौरान भी उपलब्ध होती रहीं।

पुस्तक निर्यात प्रोत्साहन कार्यकलाप

भारत विश्व के 10 प्रमुख पुस्तक प्रकाशन देशों में एक है और अंग्रेजी पुस्तकों प्रकाशित करने में इसका तीसरा स्थान है। विदेशों में भारतीय पुस्तकों और अनुवाद/पुनर्मुद्रणों की बिक्री को प्रोत्साहित करने और विदेशों से मुद्रण कार्य प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेकर और भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित करके, पुस्तक बाजार का अध्ययन करके और सहटिप्पण सूची-पत्रों, पुस्तिकाओं इत्यादि के परिचालन के माध्यम से वाणिज्यिक प्रचार करके स्वदेशी पुस्तकों को लोकप्रिय बनाने के वास्ते कदम उठाए जा रहे हैं।

वर्ष 1985-86 के दौरान भारत ने, लन्दन, मनीला, टोरन्टो, कुआलालमपुर, सिंगापुर, फ्रैंकफर्ट, मास्को, बेलग्रेड और सीरिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लिया। इण्डोनेशिया, त्रिनीदाद और टोबगो, इथोपिया, सूडान, बंगला देश, जर्मनजनवादी गणराज्य, फ्रांस और केन्या में भारतीय पुस्तकों की विशेष प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। वर्ष 1985-86 के दौरान ईरान और वर्मा में पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने के परिणामस्वरूप 1985-86 के दौरान हमारी पुस्तकों का निर्यात जिसमें पत्र-पत्रिकाओं का निर्यात भी शामिल है, लगभग 25 करोड़ रुपए तक का होने का अनुमान है।

राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक स्रोत केन्द्र

राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक स्रोत केन्द्र की स्थापना जुलाई 1972 में की गई थी। यह केन्द्र एक सूचना एवं अनुसंधान केन्द्र के रूप में कार्य करता है और पुस्तकों के आयात के व्यौरों के संबंध में प्रलेखन और सांख्यिकीय विश्लेषण सुविधाएं प्रदान करता है। केन्द्र में एक ही स्थान पर सन् 1965 से विभिन्न विषयों में सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का एक बहुत बड़ा संग्रह है। केन्द्र, स्वदेशी पुस्तकों का, विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों के लिए उनकी उपयोगिता की दृष्टि से तुरन्त मूल्यांकन करता है और विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों में इन पुस्तकों की प्रदर्शनियां

आयोजित करता है। वर्ष 1985-86 के दौरान, केन्द्र ने जम्मू, सिलीगुड़ी, पटना और कोल्हापुर में ऐसी चार प्रदर्शनियां आयोजित कीं। 31 मार्च 1986 से पूर्व ऐसी दो और प्रदर्शनियां मद्रास और तिरुपति में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक गणना प्रणाली को संचालित करने के लिए एक राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में माना गया है। इस संबंध में, भारत ने बर्लिन में 9-10 अक्तूबर, 1984 तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक गणना एजेंसी की वार्षिक बैठक में भाग लिया। इस प्रणाली के अंतर्गत 130 भारतीय प्रकाशकों को प्रकाशक मान्यता संख्या प्रदान की गई। केन्द्र विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों की ग्रन्थ-सूचियां तैयार करता है और विश्वविद्यालय स्तर पर स्वदेशी प्रकाशन के प्रयोग और प्रकाशन के विभिन्न पहलुओं का नमूना सर्वेक्षण करता है।

कापीराइट

कापीराइट कार्यालय की स्थापना कापीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14वां) की धारा 9 के अनुसरण में जनवरी, 1958 में की गई थी। कापीराइट कार्यालय ने 1985 के दौरान 1908 कृतियां पंजीकृत कीं, जिनमें 1739 कलात्मक कृतियां, 169 साहित्यिक कृतियां पंजीकृत की गईं। इसके अतिरिक्त कापीराइट कार्यालय, कापीराइट के रजिस्टर में दर्ज दो कलात्मक कृतियों के कापीराइट के विवरणों में परिवर्तन पंजीकृत किए।

भारत कापीराइट सम्बन्धी 2 अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, अर्थात् बर्न अभिसमय (1948) और यूनिवर्सल काणीराइट अभिसमय (1952) का एक सदस्य है। इन दोनों अभिसमयों को 1971 में पेरिस में संशोधित किया गया था जबकि विकासशील देशों को विशेष रियायतें प्रदान की गईं ताकि वे शैक्षिक प्रयोजनों के लिए विदेशी मूल की पुस्तकों के पुनर्मुद्रण/अनुवाद के लिए अनिवार्य लाइसेन्स जारी कर सकें। भारतीय कापीराइट अधिनियम, 1957 को, (क) शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक विदेशी कृतियों के अनुवाद और निर्माण के लिए अनिवार्य लाइसेन्स प्रदान करने से सम्बन्धित बर्न अभिसमय और यूनिवर्सल कापीराइट अभिसमय के 1971 के पेरिस पाठ के प्रावधान सम्मिलित करने, (ख) लेखकों के अधिकारों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने और (ग) कापीराइट अधिनियम, 1957 के प्रशासन में पेश आयी प्रशासनिक व अन्य कमियों को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजनों से 1983 में संशोधित किया गया। कापीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1983, 9 अगस्त, 1984 से लागू हो गया।

कापीराइट अधिनियम में 1984 में और संशोधन किया गया ताकि देश में व्यापक पुस्तक तस्करी की समस्या को रोका जा सके। कापीराइट संशोधन अधिनियम, 1984 अधिनियमित कर दिया गया है और विभिन्न अपराधों के लिए दण्ड को और अधिक बढ़ाकर पुस्तक तस्करी को रोकने के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। कापीराइट के उल्लंघन के लिए ज्यादा सजा की व्यवस्था की गई है। अर्थात् तीन वर्ष तक की सजा और कम से कम छः महीने की सजा का दण्ड और 2 लाख रु. तक का जुर्माना व कम से कम 50 हजार रुपये का जुर्माना। यह अधिनियम 8 अक्तूबर, 1984 से लागू हो गया।

वर्ष 1985 के दौरान भारत ने निम्नलिखित बैठकों, सेमिनारों में भाग लिया : वाइपो स्थायी समिति की बैठक 4–8 फरवरी तक जैनेवा। कापीराइट द्वारा संरक्षित कृतियों के सम्बन्ध में विकासशील देशों की परामर्शदात्री समिति की कार्य परियोजना की संयुक्त यूनेस्को/वाइपो बैठक 22–26 अप्रैल, पेरिस। वाइपो की बजट समिति की बैठक 8–10 मई, जैनेवा। साहित्य और कलात्मक कार्यों (बर्न यूनियन) के संरक्षण के लिए अन्तरराष्ट्रीय यूनियन की कार्य समिति का असाधारण सत्र और यूनिवर्सल कापीराइट कान्वेन्शन की अन्तर सरकारी समिति का छठा साधारण सत्र 17–25 जून, पेरिस।

वाइपो की शासी निकाय और वाइपो द्वारा प्रशासित यूनियनों का वर्ष 1985 का सत्र 23 सितम्बर से 1 अक्तूबर तक, जैनेवा।

12—759 Deptt. of Edu./85

अगस्त, 1985 में भारतीय कापीराइट विशेषज्ञों के एक, दो सदस्यीय शिष्टमंडल ने कापीराइट के क्षेत्र में अनुभवों के आदान-प्रदान हेतु चीन का दौरा किया।

कापीराइट में प्रशिक्षण सुविधाएं

वाइपो के वार्षिक कापीराइट प्रशिक्षण कार्यक्रम 1985 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए मलेशिया और फिलीपीन्स से एक-एक प्रशिक्षार्थी 6 से 17 नवम्बर, 1985 तक भारत में आए। वाइपो प्रशिक्षु कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अधिकारी ने स्विटजरलैंड में कापीराइट के प्रशासन और निकटवर्ती अधिकारों में विशेषज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया और एक अन्य अधिकारी ने बुडापेस्ट में आयोजित कापीराइट और निकटवर्ती अधिकारों में सामान्य प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और इसके बाद लन्दन में आयोजित व्यावहारिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया।

वर्ष 1983 से, वाइपो/यूनेस्को द्वारा विकासशील देशों से भाग लेने वालों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भारतीय विशेषज्ञों को सहयोजित किया जा रहा है। वर्ष 1985 के दौरान तीन भारतीय विशेषज्ञों को फिलीपीन्स, चीन और हंगरी में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया था।

राष्ट्रीय लेखक तथा संगीतकार सोसाइटी

मंत्रालय, लेखकों तथा संगीतकारों के कापीराइट सम्बन्धी हितों की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय लेखक तथा संगीतकार सोसायटी स्थापित करने का भी विचार रखता है। इसके स्थापित हो जाने पर यह सोसाइटी, कापीराइट की हुई कृतियों के सार्वजनिक प्रदर्शन इत्यादि के लिए लाइसेन्स प्रदान करेगी तथा कापीराइट मालिकों के लाभ के लिए प्रयोक्ताओं से रायल्टी भी एकत्र करेगी।

अध्याय–9

भाषाओं की प्रोन्नति

भाषाओं के विकास और प्रोन्नति के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का व्यापक रूप में नीचे दिए गए अनुसार विभाजन किया जा सकता है :––

–– हिन्दी की प्रोन्नति

–– आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति

–– अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं की प्रोन्नति

–– संस्कृत तथा अरबी और फारसी जैसी अन्य श्रेण्य भाषाओं की प्रोन्नति ।

इसके अलावा मंत्रालय निम्नलिखित संस्थाओं और संगठनों का सीधा संचालन करता है, जो मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई हैं और भाषाओं के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन से सम्बन्धित हैं :––

–– केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, नई दिल्ली और कलकत्ता, गोवाहाटी, मद्रास और हैदराबाद स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालय।

–– वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, नई दिल्ली।

–– केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा और नई दिल्ली, हैदराबाद और गोवाहाटी स्थित इसके केन्द्र।

–– केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर।

–– उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो, नई दिल्ली।

–– केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद।

–– केन्द्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली।

क. हिन्दी की प्रोन्नति

विभाग ने, स्कूलों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति के लिए, हिन्दी अध्यापकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना करके, मैट्रिकोत्तर स्तर के बाद हिन्दी अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करके और हिन्दी के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों का आयोजन करके अहिन्दी भाषी राज्यों में वित्तीय सहायता प्रदान करके हिन्दी पढ़ाने की सुविधाएं प्रदान करना जारी रखा। हिन्दी आशुलिपि और टंकण पढ़ाने के लिए कक्षाएं शुरू करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए गए। विभिन्न प्रकार के प्रकाशन निकालने के लिए इन संगठनों को सहायता भी दी गई। एक अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत, शैक्षिक संस्थाओं को 2.00 लाख रुपये तक की लागत की हिन्दी पुस्तकें वितरित की गईं। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा ने, हिन्दी शिक्षण प्रणाली में अपना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जारी रखा।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनागत योजना के अन्तर्गत अहिन्दी भाषी राज्यों को 50-50 के आधार पर तथा संघीय क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

अहिन्दी भाषी राज्यों/संघीय क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और शैक्षिक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना

अहिन्दी भाषी राज्यों और संघीय क्षेत्रों को हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना के लिए 100% केन्द्रीय सहायता दी जाती है। अहिन्दी भाषी राज्यों/संघीय क्षेत्रों में केन्द्रीय सहायता से अब तक 19 प्रशिक्षण कालेज स्थापित किए जा चुके हैं।

स्वैच्छिक हिन्दी संगठनों को वित्तीय सहायता

गत वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मांगने वाले संगठनों की संख्या बढ़ गई है। इनमें से कुछेक संगठन महत्वपूर्ण बन गए हैं और एक से ज्यादा राज्यों में एक साथ कार्य कर रहे हैं। जबकि पहले हिन्दी कक्षाओं को चलाने, हिन्दी टंकण तथा आशुलिपि में पाठ्यक्रमों और पुस्तकालयों तथा वाचनालयों की स्थापना के लिए ही अनुदान मांगे जाते थे अब अनेक संगठन शिक्षकों के प्रशिक्षण, हिन्दी पत्रिकाओं के प्रकाशन, हिन्दी परीक्षाओं के संचालन, पुरस्कार रखने तथा हिन्दी में उच्च अनुसंधान के प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। वर्ष 1985-86 के दौरान लगभग 140 संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय

हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय अनेक कार्यकलापों का संचालन करता है। इसमें अहिन्दी भाषी भारतीयों और विदेशियों को पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी शिक्षण, भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं की द्विभाषी और त्रिभाषी शब्दकोषों का निर्माण और वार्तालाप निर्देशिका आदि का निर्माण शामिल है। इस वर्ष के दौरान शुरू किए गए कुछेक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है।

पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी शिक्षण

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों और विदेशियों को हिन्दी पढ़ाने के लिए 1968 से पत्राचार पाठ्यक्रमों का आयोजन करता चला आ रहा है। जबकि आरंभ में यह पाठ्यक्रम अंग्रेजी माध्यम से प्रदान किए जाते थे। परन्तु हाल ही में इस प्रयोजन के लिए तमिल, मलयालम और बंगला भाषाओं का उपयोग भी किया जाता है। इस वर्ष के दौरान, इन पाठ्यक्रमों में 13,394 छात्र दाखिल किए गए। 2853 छात्रों का अंग्रेजी माध्यम, 5120 का तमिल माध्यम, 366 का मलयालम और 760 का बंगला माध्यम में नामांकन किया गया है। निदेशालय प्रवेश और परिचय पाठ्यक्रमों में शिक्षण प्रदान कर रहा है, जो दो-दो वर्षों की अवधि के हैं। प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ एक-एक वर्ष की अवधि के हैं। अंतिम तीन पाठ्यक्रम सरकारी कर्मचारियों के लिए बने हैं और गृह मंत्रालय द्वारा परीक्षा संचालित की जाती है। वर्ष के दौरान इन पाठ्यक्रमों में 5259 छात्र दाखिल किए गए। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ने पूर्वी क्षेत्र में राज्यों और संघ क्षेत्रों के आई.ए.एस. प्रोबेशनरों को पत्राचार माध्यम से हिन्दी पढ़ाने के लिए अक्तूबर, 1984 से एक नया पाठ्यक्रम भी शुरू किया किया है। इन छात्रों के लिए शिक्षण सामग्रियां तैयार की गईं और प्रोबेशनरों के साथ वैयक्तिक संपर्क भी आयोजित किया गया।

इसके पत्राचार पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में, निदेशालय छात्रों को हिन्दी भाषा के उच्चरण और वर्तिनी से परिचित कराने के लिए देश के विभिन्न भागों में वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित करता है। शिलांग, मद्रास, कोहिमा, कोचीन, हैदराबाद, बंगलौर, पांडिचेरी, त्रिवेन्द्रम और दुर्गापुर में 9 संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों के लिए शब्दावलियों, व्याकरण पाठ्य सामग्रियां, उत्तर पत्रों और अन्य साहित्य का प्रकाशन किया गया। एक वृहत् समकालित शब्दावली को प्रकाशित किया जाना है। शब्दावली की पाण्डुलिपि तैयार कर ली गई है। छात्रों द्वारा अध्ययनों में अनुभव की जा रही कठिनाइयों का विश्लेषण कर उन्हें दूर करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं और इस कार्य के लिए फिल्में और हिन्दी अभिलेखों का विकास किया गया है। श्रव्य कैसेट तैयार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। द्विपक्षीय वार्तालाप गाइड (हिन्दी-अंग्रेजी) का दूसरा संस्करण प्रकाशनाधीन है। नवम्बर, 1985 में आयोजित प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षाओं में अधिक से अधिक 5337 छात्रों ने परीक्षा दी। हिन्दी प्रवेश और परिचय परीक्षाओं में एक हजार सत्तावन छात्रों ने भाग लिया और उनमें से 892 छात्र सफल घोषित किए गए।

विस्तार कार्यक्रम

निदेशालय देश के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विस्तार कार्यकलापों का संचालन करता करता रहा ताकि हिन्दी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के विद्वानों, प्रोफेसरों, छात्रों और अन्य नागरिकों को एक मंच पर लाया जा सके। इन कार्यकलापों में अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के अहिन्दी भाषी लेखकों के लिए कार्यशाला, छात्र दौरों, अध्येताओं के लिए यात्रा-अनुदान, अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी लेखकों को हिन्दी में साहित्यिक कृति के लिए पुरस्कार प्रदान करना शामिल है। निदेशालय ने भारतीय साहित्य की दो संगोष्ठियों का भी आयोजन किया।

अहिन्दी भाषी क्षेत्रों/राज्यों के हिन्दी लेखकों के लिए कार्यशाला

इस वर्ष के दौरान वारंगल, कालीकट, हैदराबाद, मद्रास और मणिपुर में ऐसी 5 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। एक और कार्यशाला कलकत्ता में आयोजित की गई। अहिन्दी भाषी राज्यों से 100 से अधिक लेखकों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया। इन कार्यशालाओं में लेखकों को ड्रामा, कथा साहित्य, एकांकी और उपन्यास आदि के सम्बन्ध में सृजनात्मक लेखन की अद्यतन प्रवृत्तियों का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

दौरा और यात्रा अनुदान

अहिंदी भाषी क्षेत्रों से प्रत्येक में 50 छात्रों के दो दल विश्वविद्यालय और हिन्दी भाषी क्षेत्रों के स्वैच्छिक संगठनों के दौरे पर प्रत्येक वर्ष ले जाए जाते हैं ताकि वे दैनिक जीवन में बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी भाषा को समझ सकें और हिंदी साहित्य में अद्यतन प्रयोगों का ज्ञान प्राप्त कर सकें। वर्ष 1985-86 के दौरान दो दौरे आयोजित किए गए।

प्रत्येक यात्रा के लिए 450/- रुपये का यात्रा अनुदान प्रत्येक वर्ष 20 अनुसंधान छात्रों को प्रदान किया जाता है। इस वर्ष भी छात्रों का चयन किया गया है। आठ प्रोफेसरों ने व्याख्यान देने के लिए हिन्दी और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों का दौरा किया। अब तक चार प्रोफेसरों ने अपने व्याख्यान दौरे पूरे किए। जो शेष रह गए हैं उनके द्वारा मार्च, 1986 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

संगोष्ठी

हिन्दी और अहिन्दी भाषी छात्रों के विश्वविद्यालयों में भारतीय साहित्य से सम्बन्धित दो संगोष्ठियों का प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष उदयपुर और उस्मानिया विश्वविद्यालय में दो ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।

पुरस्कार प्रदान करना

इस योजना के अंतर्गत अहिन्दी भाषी लेखकों को उनके द्वारा हिन्दी में लिखी गई पुस्तकों पर प्रति पुरस्कार वार्षिक 2500/- रुपये के 16 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत 1983-84 और 1984-85 में अठारह पुरस्कार एक साथ प्रदान किए गए और 1985-86 के लिए 15 लेखकों का चयन किया गया।

प्रकाशन

निदेशालय एक त्रैमासिक पत्रिका "भाषा" और मासिक पत्रिका "यूनेस्को दूत" का प्रकाशन करता है, यूनेस्को दूत, यूनेस्को कूरीयर का हिन्दी रूपान्तर है और यह विश्व की 28 प्रमुख भाषाओं में प्रकाशित होता है। 1985-86 के दौरान भाषा के चार अंक (अर्थात्--मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर) प्रकाशित किए गए जिनमें से मार्च और जून का अंक "रजत जयन्ती" अंक के रूप में संयुक्त अंक प्रकाशित हुआ। यूनेस्को दूत का अंक दिसम्बर, 1985 तक प्रकाशित किया जा चुका है। निदेशालय "वार्षिकी" भी प्रकाशित करता है, जो प्रत्येक वर्ष में लिखे गए साहित्य के विभिन्न विषयों का विस्तृत सर्वेक्षण है। वर्ष के दौरान वार्षिकी 1982-83 प्रेस में है और वार्षिकी 1984 का कार्य चल रहा है।

"भारतीय साहित्य माला" योजना के अन्तर्गत "भारतीय भाषाओं का संक्षिप्त इतिहास", "भारतीय कहानियां और भारतीय निबंध" नाम की पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। "भारतीय कविता" की पाण्डुलिपि छपने के लिए प्रेस में भेज दी गई है। "भारतीय एकांकी" की पाण्डुलिपि तैयार की जा रही है।

पुस्तकों की बिक्री को बढ़ाने के लिए अनेक कार्यकलाप शुरू किए गए जैसे जनसंचार माध्यमों से विज्ञान, शिक्षण संस्थाओं और पुस्तकालयों के साथ वैयक्तिक सम्पर्क और

पुस्तक प्रदर्शनी आदि। हिन्दी पुस्तकों की नौ प्रदर्शनियां आयोजित की गईं जहां निदेशालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकें प्रदर्शित की गईं। वर्ष के दौरान पुस्तकों की कुल बिक्री एक लाख रुपये से अधिक हुई।

निदेशालय अहिन्दी भाषी क्षेत्रों और विदेशों में उपयोगी हिन्दी पुस्तकें और पत्रिकाएं निःशुल्क उपलब्ध कराता है जिसका मुख्य उद्देश्य हिन्दी भाषा और साहित्य पढ़ने और पढ़ाने में रुचि उत्पन्न करना है। 1984-85 के दौरान खरीदी गई पुस्तकें लाभग्राही संस्थाओं को वितरित कर दी गईं और विदेशों में भारतीय दूतावासों को भेजी गईं।

शब्दकोशों का निर्माण

26 द्विभाषीय शब्दकोश में से छः शब्दकोश अर्थात् हिन्दी-गुजराती, हिन्दी-सिंधी, हिन्दी-मराठी, हिन्दी-असमी, हिन्दी-उर्दू और हिन्दी-तमिल प्रकाशित हो चुकी हैं और हिन्दी-तेलगु, हिन्दी-मलयालय और हिन्दी-उड़िया की सामग्री प्रेस में भेज दी गई है और इस वर्ष में प्रकाशित हो जाने की सम्भावना है। त्रिभाषी शब्दकोश जैसे हिन्दी-गुजराती अंग्रेजी (3 खण्डों) प्रकाशित हो चुकी हैं और हिन्दी-तमिल-अंग्रेजी, हिन्दी-कन्नड़-अंग्रेजी और हिन्दी-मलयालय-अंग्रेजी प्रेस में भेज दी गई है। भारतीय भाषाकोश जिसमें हिन्दी शब्दों के पर्यायवाची 13 भारतीय भाषाओं में दिए गए हैं, प्रकाशित किया जा चुका है।

तत्सम शब्दकोश की प्रेस प्रति शीघ्र ही प्रेस भेजी जाने वाली है। भारतीय भाषा परिचय की पाण्डुलिपि तैयार की जा रही है।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय हिन्दी और विदेशी भाषा शब्दकोश तैयार करने में लगा हुआ है। गत वर्ष से अब तक जर्मन-हिन्दी शब्दकोश की 2800 प्रविष्टियों को अंतिम रूप दिया गया जिसमें 8000 से अधिक प्रविष्टियों का सम्पादन किया गया। चेक-हिन्दी शब्दकोश की स्वच्छ प्रति देवनागरी लिपि में रूपान्तरित कर ली गई। हिन्दी-चेक वार्तालाप गाईड की पाण्डुलिपि प्रकाशन के लिए तैयार है। हिन्दी-रूसी वार्तालाप गाईड प्रेस के लिए तैयार है और इसके प्रकाशन के लिए रूस पक्ष से सम्पर्क किया जा रहा है। हिन्दी-हंगरी-वार्तालाप गाईड की पाण्डुलिपि तैयार कर ली गई है और हंगरी के विशेषज्ञ इसमें संशोधन कर रहे हैं।

हिन्दी-संयुक्त-राष्ट्रसंघ भाषाओं (अंग्रेजी और रूसी को छोड़कर) जैसे स्पेनी, चीनी, अरबी और फ्रेंच के द्विभाषी शब्दकोश तैयार किये जा रहे हैं। प्रत्येक द्विभाषी शब्द-कोश में लगभग 2500 प्रविष्टियां शामिल होंगी जिसमें हिन्दी शब्दों और राजनीति के मूल शब्द शामिल होंगे। हिन्दी-अरबी शब्दकोश की प्रेस प्रति सरकारी प्रेस, फरीदाबाद भेज दी गई है और हिन्दी-स्पेनी और हिन्दी-चीनी प्रेस प्रति शीघ्र ही प्रेस भेजी जाने वाली है। हिन्दी-फ्रेंच शब्दकोश की प्रेस प्रति शीघ्र ही तैयार हो जाने की संभावना है।

सिन्धी में मानक साहित्य का प्रकाशन

इस योजना का लक्ष्य, जो 1975 में आरम्भ हुई थी, दुर्लभ पुस्तकों, श्रेष्ठ पुरातन पुस्तकों और माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्यपुस्तकों के पुनर्मुद्रण सहित सिन्धी में मानक साहित्य का प्रकाशन है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उल्लास नगर में जनवरी, 1985 में सिन्धी प्रेस लेखन पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। एक दूसरा सेमिनार, भोपाल में सितम्बर, 1985 में 'सामी' एक महान सिन्धी कवि पर आयोजन किया गया था। दिल्ली में 1985 में एक नव-लेखकों की कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था जिसमें चर्चा का विषय सिंधी में परालिपि शास्त्र था। नव-लेखकों की एक कार्यशाला का आयोजन आगरा में फरवरी, 1986 में करने का प्रस्ताव है। पुस्तकों के चयन के लिए सिन्धी पुस्तकों की थोक खरीद की योजना करने के अन्तर्गत पुस्तकों के चयन के लिए अगस्त, 1986 में विशेषज्ञों के पैनल की एक बैठक आयोजित की गई। निःशुल्क वितरण के लिए 20,000/- रुपये तक की सिन्धी पुस्तकों का पाकिस्तान से आयात किए जाने की सम्भावना है।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के निम्नलिखित कार्य हैं : भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली तैयार करना, भारतीय भाषाओं में संदर्भ सामग्री तैयार

करना, भारतीय भाषाओं में उपलब्ध शब्दावली का सर्वेक्षण, समीक्षा और संग्रह करना, और अखिल भारतीय शब्दावली विकसित करना, क्षेत्रीय स्तर पर भाषा निकायों की स्थापना करना और पारिभाषिक शब्दकोषों, शब्दावली और निघंटु तैयार करना और प्रकाशित करना है।

1985-86 के दौरान विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा की गई प्रगति निम्न प्रकार है :--

विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का प्रकाशन

आयोग की देख-रेख में इस योजना के अन्तर्गत हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं में 30 विषयों में अब तक 6675 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिसमें लगभग सभी विषय मानविकी, सामाजिक विज्ञान, मूल विज्ञान और प्रयुक्त विज्ञान शामिल हैं। इनमें से 1560 पुस्तकें हिन्दी में विभिन्न ग्रन्थ अकादमियों, विश्वविद्यालयों के सेल और स्वयं तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित की गई। आयोग तथा विभिन्न हिन्दी ग्रन्थ अकादमियों और विश्वविद्यालय पुस्तक निर्माण एककों द्वारा कृषि औषध और इंजीनियरी से संबंधित अब तक 1700 पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित की गई हैं। वर्ष के दौरान उपर्युक्त विषयों में लगभग 14 पुस्तकें प्रकाशित हुई और कुछ प्रकाशनाधीन हैं। इनमें अनुवाद और मूल लेखन दोनों प्रकार की पुस्तकें शामिल हैं। कृषि, इंजीनियरी, औषध आदि विषयों में पुस्तकों का प्रकाशन मुख्य रूप में आयोग द्वारा किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री कम रही है, आंशिक रूप में इसका कारण यह था कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय भाषाओं को लागू करने में अपेक्षित प्रगति नहीं की गई। मार्च 1985 के अंत तक जो पुस्तकें नहीं बिकीं उनका मूल्य 647 लाख रुपये था।

पारिभाषिक शब्दकोश

विभिन्न विषयों में शब्दावली तैयार हो जाने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि इनकी परिभाषा के द्वारा व्याख्या की जाए। तदनुसार मूल विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, औषध विज्ञान, फार्मेसी, कृषि और इंजीनियरी की सिविल, यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरी शाखाओं आदि विषयों में पारिभाषिक शब्दकोष तैयार करने का कार्य जारी रहा। अब तक विज्ञान में 16 पारिभाषिक शब्दकोष, वनस्पतिशास्त्र, रसायन शास्त्र, भूगर्भ विज्ञान गणित और गृह विज्ञान में प्रत्येक में 12 और प्राणी विज्ञान, भूगोल, भूगर्भ और औषधि प्रत्येक में एक और 10 पारिभाषिक शब्दकोश, सामाजिक विज्ञानों और मानविकी में शिक्षा, अर्थशास्त्र, इक्नोमेट्रिक्स, सामाजिक कार्य, वाणिज्य, मनोविज्ञान, पुरातत्व, सांस्कृतिक, मानव-विज्ञान और इतिहास आदि विषयों में प्रकाशित हुए हैं। कुछ शब्दकोशयों शिक्षा अर्थशास्त्र, सामाजिक कार्य, वाणिज्य, मनोविज्ञान, पुरातत्व, इतिहास और दर्शन, सामाजिक विज्ञान, पुस्तकालय विज्ञान और पाश्चात्य संगीत प्रकाशनाधीन हैं। माडर्न अल्जोब्रा में एक पारिभाषिक शब्दकोश इस वर्ष प्रकाशित होने की संभावना है। परिभाषाओं को अंतिम रूप देने और चर्चा करने के लिए विचार-गोष्ठियों का आयोजन किया गया। विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों के मूल पारिभाषिक शब्दकोषों से संबंधित समेकन, समन्वय और समाकलन कार्य चल रहा है।

कापीरहट का अधिग्रहण

ग्रन्थ अकादमियों, आयोग और पुस्तक प्रकाशन बोर्ड द्वारा अनुवाद की जा रही पुस्तकों का कापीराइट प्राप्त करने का कार्य आयोग को सौंपा गया है। अब तक 1580 कापीराइट प्राप्त कर लिए गए हैं। 10 पुस्तकों के संबंध में कापीराइट के नवीकरण में संबंधित कार्य पूरा कर लिया गया है। आलोच्य वर्ष के दौरान 7 विदेशी प्रकाशनों का कापीराइट प्राप्त कर लिया गया है।

शब्दावली

अब शिष्ट शब्दावली के संदर्भ में पशु चिकित्सा विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रबंध में हिन्दी के समानार्थक शब्दों का निर्माण किया गया। पिछले वर्ष अंतरिक्ष विज्ञान शब्द-

कोश प्रकाशित किया गया था। पशु चिकित्सा विज्ञान और प्रबंध से संबंधित कार्य किया जा रहा है।

विभागीय शब्दावली

विभागीय शब्दावली के कार्य में भी प्रगति हो रही है। वर्ष के दौरान आयोग ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ अनेक बैठकें आयोजित कीं और विभिन्न शब्दावलियों को अंतिम रूप दिया। समेकित प्रशासनिक शब्दावली की नई और संशोधित संस्करण तैयार किया जा रहा है। हिन्दी भाषी राज्यों के निदेशकों, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो और राजभाषा विभाग के साथ आयोग द्वारा विभिन्न शब्दावलियों के समन्वय के लिए बैठकें आयोजित की गईं। एक समेकित बैंकिंग शब्दावली विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, राजभाषा (विधायी) के परामर्श से तैयार की जा रही है।

शब्दावली का समन्वय और सरलीकरण

हिन्दी के संपूर्ण तकनीकी शब्दों, जो अब तक विकसित और प्रकाशित हो चुके हैं, के सरलीकरण और समन्वय का कार्य बैठकों और सेमिनारों के माध्यम से किया जा रहा है। जैड अक्षर तक संपूर्ण शब्दावली का समन्वय और सरलीकरण करने का कार्य पूरा कर लिया गया है। विषयवार-विभिन्न शब्दकोष/शब्दावलियों का संशोधित संस्करण प्रकाशित किया जाएगा।

हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावली

अंग्रेजी के हिन्दी समतुल्य शब्दों के प्रकाशनों का उपयोग बढ़ जाने के साथ-साथ हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावलियां भी तैयार करना जरूरी समझा गया। मूल विज्ञानों से संबंधित इस प्रकार की एक हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावली पहले प्रकाशित हुई थी और मानविकी और सामाजिक विज्ञान से संबंधित दूसरी हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावली वर्ष के दौरान प्रकाशित की गई। इस क्रम में तीसरी हिन्दी-अंग्रेजी शब्दावली प्रयुक्त विज्ञान में तैयार की जा रही है।

डायजेस्ट/पाठ/मोनोग्राफ

निम्नलिखित विषयों में डायजेस्ट/पाठों/मोनोग्राफों का प्रकाशन किया गया है प्राणि विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गृह-विज्ञान, भौतिकी, वनस्पति शास्त्र (3 अंक), मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र (4 अंक), वाणिज्य-I, शिक्षा-I, तकनिशियनों के लिए डायजेस्ट (4 अंक), शारीरिक मानव-विज्ञान, शारीरिक विज्ञान, जीव-विज्ञान (2 अंक), भू-विज्ञान और राजनीति विज्ञान।

दक्षिणी और अन्य राज्यों में आम उपयोग में चिकित्सा शब्दावली व मुहावरों का उपयोग

दक्षिण भारतीय और अन्य राज्यों की भाषाओं में आम उपयोग में चिकत्सा शब्दावली और मुहावरों के समाकलन से संबंधित कार्य पिछले वर्ष के दौरान तेलगू, कन्ड़ और मराठी में शुरू किया गया। इस वर्ष मलयालम और तमिल के लिए क्रमशः त्रिवेन्द्रम और मद्रास में दो बैठकें आयोजित हुईं।

अखिल भारतीय शब्दावली

आयोग ने विभिन्न भारतीय भाषाओं में शब्दावलियों के समाकलन से संबंधित कार्य भी आरम्भ किया है और समान हिन्दी शब्दावलियों के साथ उनकी तुलना और एक राष्ट्रीय शब्दावली विकसित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय स्तर पर उनके उपयोग के लिए समन्वय का कार्य आरम्भ किया है। इस सन्दर्भ में 6 पाण्डुलिपियां प्रैस में हैं और 3 अन्य पाण्डुलिपियां मुद्रण के लिए भेजने हेतु तैयार हैं।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा

केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मंडल, शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय संविधान के अनुच्छेद 361 में दिए गए निर्देशों को आगे बढ़ाने में हिन्दी के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करने के लिए केन्द्रीय हिन्दी संस्थान (सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ हिन्दी) का संचालन करता है। भारत और विदेश में विभिन्न कार्यात्मक उद्देश्यों के लिए विभिन्न वर्गों को हिन्दी शिक्षण के लिए, हिन्दी शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रयुक्त हिन्दी भाषा विज्ञान और अनुवाद में उच्च डिप्लोमा, हिन्दी भाषा के मनो-भाषा विज्ञान और समाज-भाषा विज्ञान संबंधी पहलुओं में अनुसंधान, अनुदेशात्मक सामग्रियों का निर्माण, हिन्दी के महत्व पर अखिल भारतीय संचार माध्यम के रूप में प्रकाश डालते हुए भाषा सम्बन्धी सर्वेक्षण संचालित करता है और हिन्दी भाषा की आयोजना और विकास संबंधित राज्य और केन्द्र सरकार की एजेन्सियों को सहयोग और परामर्श देता है।

देश में हिन्दी शिक्षण प्रशिक्षण के सुधार में कार्यरत यह संस्थान प्रयुक्त हिन्दी-भाषाशास्त्र में अनुसंधान और विस्तार कार्य के लिए, हिन्दी और भारतीय भाषाओं आदि के तुलनात्मक और रचनात्मक अध्ययन के लिए एक संयुक्त निकाय है।

शिक्षण और प्रशिक्षण

वर्ष के दौरान संस्थान ने विभिन्न प्रकार के 18 पाठ्यक्रमों का संचालन किया। प्रशिक्षण के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम सहित और व्याख्यानों का अनुपालन तथा विश्वविद्यालयों, कालेजों और स्कूल स्तर के अध्यापकों, 26 विभिन्न देशों से छात्रों और अनुसंधान अध्येताओं के लिए हिन्दी भाषा और साहित्य में प्राथमिक स्तर से अनुसंधान स्तर तक के पाठ्यक्रमों, केन्द्रीय सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्मिकों के लिए कार्यात्मक हिन्दी पाठ्यक्रमों, प्रयुक्त हिन्दी भाषा विज्ञान और अनुवाद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा का संचालन करता है। यह अहिन्दी भाषी राज्यों के हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए बी. एड. स्तर के पत्राचार पाठ्यक्रम का भी संचालन करता है। नियमित परियोजनाओं में सेवाकालीन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या 283 थी, पत्राचार पाठ्यक्रमों में 436, और अल्पकालीन अनुस्थापन पाठ्यक्रमों में यह संख्या 950 थी।

सामग्री निर्माण अनुसंधान और सर्वेक्षण

उत्तर-पूर्वी राज्यों में हिन्दी शिक्षण के स्तर से संबंधित सर्वेक्षण के अंतर्गत एकत्र किए गए आंकड़ों का मूल्यांकन किया गया और इस वर्ष रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया गया। पूरक पाठों के निर्माण से संबंधित कार्य और राज्यों में बड़े पैमाने पर जनजातीय जनसंख्या वाले राज्यों में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए समृद्ध सामग्री निर्माण करने का कार्य शुरू किया गया।

औद्योगिक संस्थाओं में अखिल भारतीय संचार माध्यम के रूप में हिन्दी के कार्य और उसकी भूमिका से संबंधित सर्वेक्षण कार्य, जो पिछले वर्ष राउरकेला और बोकारो इस्पात कारखानों में संचालित किया गया था, उसे आगे बढ़ाया गया ताकि मोरमुगाओ, वेस्को, पौण्डा, बंगलौर, मैसूर और विशाखापट्टनम् में ऐसे संगठनों को भी शामिल किया जा सके। बोकारो और राउरकेला से प्रश्नावली के कोड बनाने का कार्य पूरा किया गया और आंकड़ों का संगणकीय विश्लेषण तैयार किया जा रहा है।

वैज्ञानिक हिन्दी रजिस्टर से सम्बन्धित रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और उद्योग और वाणिज्य (वाणिज्यिक हिन्दी) में उपयोग में लाए जाने के लिए हिन्दी रजिस्टर के स्वरूप और विशेषताओं का निर्धारण आरम्भ किया गया है।

विदेशी-भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के लिए अनुदेशात्मक सामग्री के निर्माण से सम्बन्धित कार्य पिछले वर्ष आरम्भ किए गए कार्य को आगे बढ़ाया गया। आधार पाठों, साहित्य में रिडिंग्स और अगले शिक्षण स्तर के लिए हिन्दी रचना संहिता तैयार की गई तथा संस्थान के दिल्ली केन्द्र में सामग्री प्रयोग की जा रही है।

भाषा प्रयोगशाला और श्रव्य-दृश्य एकक

मणिपुरी बोलनेवालों को हिन्दी उच्चारण सीखने के लिए, मणिपुरी और हिन्दी आवाज प्रणाली की निर्माण ढांचे को ध्यान में रखते हुए पाठ तैयार कर लिया गया है। हिन्दी पढ़ने और अभ्यास के लिए नागालैन्ड और मिजोराम के स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसेट किटों को तैयार करने का कार्य शुरू किया गया है।

भारत सरकार के "कवा" कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थान ने माइक्रो-संगणक के दो सैट प्राप्त किए हैं। इसे संस्थान के आगरा मुख्यालय और दिल्ली में स्थापित किया गया है। अनुदेशात्मक सामग्री के निर्माण और अहिन्दी भाषियों के लिए संगणक की सहायता से हिन्दी अनुदेश के पैकेज तैयार करने के लिए अपेक्षित आधार ढांचा तैयार किया जा रहा है। संस्थान के कुछ संकाय सदस्यों को संगणक के उपायोग में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

प्रकाशन

रिपोर्ट अवधि के दौरान संस्थान ने 10 पुस्तकें, गवेषणा के 3 अंक और न्यूज बुलेटिन के 6 अंक प्रकाशित किए। कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या लगभग 2800 थी।

जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों को हिन्दी पुस्तकों का वितरण

राष्ट्रीय विषयों से संबंधित विषयों पर प्रकाश डालते हुए कुल 80 हिन्दी पुस्तकें (प्रत्येक 300 प्रतियां) नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अंडमान और निको-

बार प्रशासन, सिक्किम, लद्दाख, राजस्थान और उड़ीसा स्थित जनजाति क्षेत्रों के स्कूलों को वितरित की गई हैं। वितरित की गई पुस्तकों की कुल लागत 1 लाख रुपये थी।

अखिल भारतीय प्रतियोगिताएं

रिपोर्ट अवधि के दौरान संस्थान द्वारा सेवारत हिन्दी शिक्षकों के लिए एक अखिल भारतीय हिन्दी निबन्ध प्रतियोगिता और दो हिन्दी वाग्मिता प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

सेमिनार, कार्यशालाओं और विस्तार व्याख्यान

संस्थान ने 6 सेमिनार और कार्यशाला तथा विस्तार व्याख्यानों की तीन श्रृंखलाओं का संचालन किया। सेमिनार-हिन्दी शिक्षण पर संचालित किए गए अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य (सितम्बर, 1985), भारतीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन (फरवरी, 1986) और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र शताब्दी सेमिनार (1985)। स्कूल स्तर पर हिन्दी शिक्षण के लिए श्रेणीबद्ध पाठ्यक्रम तैयार करने से सम्बन्धित तीन कार्यशाला (1985 अगस्त), प्रयुक्त भाषा-विज्ञान अनुसंधान (जुलाई, 1985) पर नया प्रतिबल, और हिन्दी के राजभाषा के रूप में शिक्षण से सम्बन्धित (फरवरी, 1986) हिन्दी अधिकारियों (अनुवादकों) के सेमिनार आयोजित किये गये।

हिन्दी साहित्य की श्रृंखला में विस्तार व्याख्यान प्रो. के. एम. लोधा, प्रो. और विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, कलकत्ता विश्वविद्यालय सुदूर शिक्षा और भाषा शिक्षण पर प्रो. ओ. एस. दवेल, केन्द्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान, रा. शै. अनु. व प्र. पी., नई दिल्ली और बहुभाषावाद और भाषा सम्प्रेषण पर प्रो. डी. पी. पटनायक, निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा दिए गए।

पुस्तकालय

संस्थान ने अपने पुस्तकालय के लिए लगभग 4500 नई पुस्तकें और खरीदीं जिसकी वजह से कुल संग्रह बढ़कर 41,650 हो गया। संस्थान लगभग 110 विदेशी और भारतीय पत्र-पत्रिकाएं तथा अनेक पत्रिकाएं और समाचार पत्रों का ग्राहक है।

विदेशों में हिन्दी का प्रचार-प्रसार

विदेशी में हिन्दी के प्रचार-प्रसार की योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, नई दिल्ली, में हिन्दी पढ़ने के लिए विदेशों के राष्ट्रिकों को प्रत्येक वर्ष 50 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। 1985-86 के दौरान 38 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई और संस्थान में दाखिला दिया गया। 9 छात्रों को अपने खर्च के आधार पर प्रवेश दिया गया। छात्रवृत्ति धारक को 650/- रुपये प्रति माह मिलता है और उसे अपने देश से दिल्ली और वापसी का वायुयान भाड़ा प्रदान किया जाता है।

मंत्रालय ने सूरीनाम, गयाना और त्रिनीदाद में 3 हिन्दी शिक्षकों, काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के पुस्तकालय में एक पूर्णकालीन पुस्तकालयाध्यक्ष और श्रीलंका में 2 अंशकालिक हिन्दी शिक्षकों को जारी रखा। हमारे विदेश स्थित दूतावासों/मिशनों को लगभग 2 लाख मूल्य की हिन्दी पुस्तकें दी जाती हैं।

ख. आधुनिक भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर, आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान विकास और विस्तार कार्य संचालित करता है। यह अपने क्षेत्रीय केन्द्रों के माध्यम से भाषा शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह जनजातीय भाषाओं के सर्वेक्षण में भी अनुसंधान कार्य में लगा हुआ है।

जनजातीय भाषाएं

जनजातीय और सीमावर्ती भाषाओं में मिश्मी व्याकरण, मिशमी स्वर-पाठ, आओ-अंग्रेजी शब्दकोश और कार-निकोवारी प्राईमर प्रकाशित किए गए। माओ व्याकरण और 11 स्तर के डूंगर वाली में प्राईमर, डावर वाली, जेनु कुरूबा और कार निकोवारी पूरे कर लिए गए। डोर्ली, बिस्न हार्न, मादिया, मूजीज, गुटोह और कार निकोबारी का व्याकरण तथा बिसन हार्न मीडिया के शब्दकोश इस वर्ष के अन्त तक पूरे हो जाने की आशा है।

वार्ली और जेनू कुरूबा में द्विवभाषायी प्राईमर राजस्थान, दादर व नगर हवेली और कर्नाटक में तैयार किया गया तथा द्विवभाषायी शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया। इन राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के शिक्षा विभाग के अधिकारियों और रा. शै. अनु. प्र. परि. की बैठक कार्य की समीक्षा करने तथा भावी प्रयोग के लिए योजना बनाने के लिए बुलाई गई ।

अरूणाचल प्रदेश के भाषा अधिकारियों को क्षेत्र भाषा-विज्ञान में प्रशिक्षित किया गया । नागालैंड सरकार के नए पाठ्यक्रम के अनुसार 16 नागा भाषाओं में प्राईमरों का संशोधन किया जाएगा । मणिपुरी में भाषा पाठ्य-पुस्तकों के मूल्यांकन के लिए संस्थान अपनी विशेषज्ञता प्रदान करता है। यह त्रिपुरा में कोक बेरोक के भाषा-शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करेगा ।

जनजातीय भाषाओं में शब्द निर्माण से सम्बन्धित एक सेमिनार, भारतीय भाषाओं में आम स्वर सम्बन्धी-विशेषताओं पर एक कार्यशाला, भारतीय भाषाओं में आम शब्दों पर एक सेमिनार आयोजित किए गए । भारतीय भाषाओं में आम शब्दों पर एक शब्दकोश का निर्माण शुरू किया जाएगा ।

एक स्वर विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई और स्वर-विज्ञान सम्बन्धी माओं और अपतानी समस्याओं का मूल्यांकन किया गया । प्रायोगिक स्वर-विज्ञान में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया । आवाज माडूकेशन से सम्बन्धित एक कार्यशाला और कार्य-वाचक नामों को उच्चारण शब्दकोश से सम्बन्धित कार्यशाला क्षेत्रीय स्वर पर आयोजित की गई।

माध्यम/ प्रौद्योगिकी सहायता

एक संगणक प्रयोगशाला स्थापित की गई और इप्सन माईक्रो संगणक और दो बी. बी. सी. कम्प्यूटर स्थापित किये गए । संस्थान के कर्मचारी बेसिक प्रोग्रामिंग में प्रशिक्षित किए गए । तमिल और कन्नड़ शिक्षण में नमूना साफ्टवेयर तैयार किया गया। संस्थान की शैक्षणिकपरियोजनाओं के अनुश्रवण और पुस्तकालयों में पुस्तक संग्रह करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे ।

4. भाषाओं में कैसेट पाठ्यक्रम पूरे किए गए और शिक्षा मंत्रालय द्वारा उनका विमाचन किया गया । भारतीय लिपि से सम्बन्धित एक विडीयो कार्यक्रम इस वर्ष के अन्त तक पूरा किया जाएगा ।

प्रकाशन

साक्षरता मानचित्र को 1981 के आंकड़ों के अनुसार संशोधित किया जाएगा और जनजातीय भाषा एटलस को पूरा किया जाएगा। मलयालय में माडल मातृभाषा रीडर कक्षा-1 तैयार किया गया और 27 स्कूलों में प्रायोजिक तौर पर उसे उपयोग में लाया गया। इस भाषा में स्तर-।। की पुस्तक इस वर्ष के अन्त तक तैयार की जाएगी। तमिल, बंगाली और तेलुगू में कक्षा-1 की पाठ्य-पुस्तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्कूलों के लिए तैयार की गई। इन भाषाओं में स्तर-2 की पुस्तकें इस वर्ष के अन्त तक तैयार की जाएगी। कन्नड में प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए हैंडबुक, भाषायी अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों के शिक्षकों के लिए तमिल और कन्नड़ में पुस्तकें तैयार की जाएगी। कर्नाटक सरकार के सर्वेक्षण और सैटिलमैन्ट अधिकारियों के लिए एक विशिष्ट उद्देश्यपूर्ण पाठ्यक्रम और तमिलनाडु के आई. ए. एस. तथा आई. पी. एस. प्रोबेशनरों के लिए तमिल में पाठ्यक्रम तैयार किए गए। सात भाषाओं में चित्रमय शब्दावलियां उड़िया और उर्दू सहित प्रकाशित की जाएगी ।

संस्थान ने तमिलनाडु सरकार के लिए ओपन स्कूल कार्यक्रम द्वारा तमिल शिक्षण के लिए एक पाठ्यचर्या तैयार की है। कक्षा-1 और 2 के शिक्षकों के लिए तमिल में रेडियो-सह-पत्राचार पाठ्यक्रम की सामग्री पूरी की गई।

हिन्दी राज्यों और पूर्वी राज्यों के सम्बन्धित दो अंकों के बाद अखिल भारतीय भाषाएं जैसे संस्कृत और उर्दू सहित भाषायी अनुसंधान की बिबलोग्राफी का दूसरा अंक पूरा किया गया। भारतीय भाषाओं पर संगणकीकृत आंकड़ों के विकास के लिए और पुस्तकालय सेवाओं का

स्वचालित करने के लिए योजना तैयार हेतु प्रलेखन से सम्बन्धित एक संगोष्ठी आयोजित की जानी है। दिसम्बर, 1985 तक 12 नई प्रकाशनें प्रकाशित की गई और इस वर्ष के अन्त तक 8 और प्रकाशन प्रकाशित किए जाएंगे ।

प्रशिक्षण

कर्नाटक सरकार के अनुदान से संस्थान ने कर्नाटक सरकार के उन कार्मिकों के लिए, जो कन्नड़ नहीं जानते हैं, कन्नड़ में एक मिश्रित पत्राचार पाठ्यक्रम का कार्यक्रम आरंभ किया है। इस पाठ्यक्रम के लिए लगभग 1000 नए कार्मिकों को पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त हस्तपुस्तिकाओं और प्राइमरों की तैयारी के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है के एक भाग के रूप में कन्नड़ के प्राथमिक स्कूल शिक्षकों, कर्नाटक और तमिलनाडु में भाषाई अल्पसंख्यकों के बच्चों के शिक्षकों तथा प्रायोगिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए जो माडल मातृभाषा रीडरों को इस्तेमाल करते हैं संस्थान द्वारा विकसित नए तरीकों और सामग्रियों का प्रशिक्षण दिया गया।

अनुसंधान और सर्वेक्षण

तमिलनाडु में शैक्षिक उपलब्धि में शिक्षा के माध्यम के प्रभाव से संबंधित एक अध्ययन और हिन्दी भाषी राज्यों के अनुसूचित जातियों के बच्चों पर भाषा के बोझ का अध्ययन पूरा किया गया।

भाषाई अनुसंधान की एक ग्रंथ सूची पूरी की गई और एक भाषा मूल्यांकन तथा जांच संबंधी ग्रंथ सूची पर इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जाएगी।

लगभग 10 भाषाओं में मानकीकृत भाषा-दक्षता जांच तैयार करने के विचार से एक कार्यशाला आयोजित की गई। भाषाई अनुसंधान के लिए गणित की एक पुस्तक तैयार की गई।

मारवाडी लोकगीत का एक अध्ययन पूरा किया गया। लोकगीत में दो प्रशिक्षण कार्यशाला मैसूर और असम में आयोजित की गई। बंगलौर में उद्योग में भाषा के प्रयोग का अध्ययन और मैसूर में भाषान्तरण और भाषा दृष्टिकोण से संबंधित अध्ययन पूरा किया गया। मणिपुर में भाषा प्रयोग का सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा।

क्षेत्रीय भाषा केन्द्र

6 क्षेत्रीय केन्द्रों, मैसूर, भुवनेश्वर, पुणे, पटियाला, सोलन और लखनऊ में 449 प्रशिक्षणार्थियों को 13 भाषाओं में प्रशिक्षण के लिए प्रवेश दिया गया है।

केन्द्र ने एक तृतीय भाषा के रूप में पढ़ने वाले छात्रों तथा भारतीय भाषा के लिए शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के वास्ते 10 पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा 7 राष्ट्रीय एकता और भाषा पर्यावरण शिविर आयोजित किए। महाराष्ट्र तथा असम में दो संपर्क कार्यक्रम तथा उड़ीसा में एक मूल्यांकन व परामर्शी कार्यक्रम आयोजित किया गया।

दक्षिणी प्रादेशिक भाषा केन्द्र, मैसूर द्वारा दूसरी भाषा शिक्षण में वर्तमान धारा से सम्बन्धित एक सेमिनार और पूर्वी प्रादेशिक भाषा केन्द्र द्वारा असमी, बंगाली और उड़ीसा तथा नैपाली के तुलनात्मक अध्ययन से सम्बन्धित सेमिनार आयोजित किया गया। अनुवाद से सम्बन्धित, विशिष्ट लेक्सिकन तथा शिक्षण में भाषा से सम्बन्धित एक सेमिनार इस वर्ष के दौरान आयोजित किए जाएंगे।

उर्दू तरक्की ब्यूरो

उर्दू भाषा और साहित्य की प्रोन्नति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के रूप में एक तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड का गठन 1969 में किया था जिसके अध्यक्ष शिक्षा मंत्री थे। बोर्ड का मुख्य कार्य उर्दू में शैक्षणिक साहित्य के निर्माण से सम्बन्धित सरकार को परामर्श देना है। उर्दू-प्रोन्नति ब्यूरो जो बोर्ड के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, की स्थापना 1975 में की गई थी। बोर्ड, तरक्की-ए-उर्दू बोर्ड द्वारा तैयार सिफारिशें, कार्यक्रमों और नीतियों को कार्यान्वित करता है।

पुस्तकों का निर्माण

उर्दू-प्रोन्नति ब्यूरो उर्दू में शैक्षणिक साहित्यों के प्रकाशन में संलग्न है। बोर्ड का मुख्य लक्ष्य छात्रों के सामान्य पाठकों और सभी विषयों में अध्ययन के लाभ प्रदान करने के अतिरिक्त देश में उर्दू भाषा की चहुंमुखी विकास के लिए सार्थक प्रयास करना है। 17

विषय पैनलों का पुनर्गठन किया गया है, जो प्रकाशन कार्यक्रम के लिए उर्दू की प्रोन्नति के लिए ब्यूरो को परामर्श देता है। देश के सभी भागों से प्रख्यात अध्येता इन पैनलों में शामिल हैं। ब्यूरो ने विभिन्न विषयों में अब तक 520 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिसमें पुर्नमुद्रण और रा.शै.अनु.प्र.परि. आदि के लिए प्रकाशित पुस्तकें शामिल हैं। फिलहाल ब्यूरो 500 से अधिक पुस्तकों को तैयार करने में लगा हुआ है।

तकनीकी शब्दावली

ब्यूरो विभिन्न विषयों में तकनीकी शब्दों को गढ़ने और अन्तिम रूप देने में भी लगा हुआ है। प्रारम्भ में विशेषज्ञों के साथ 18 शब्दावली समितियां गठित की गई थी। ब्यूरो ने अर्थशास्त्र, रसायन मानव विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति शास्त्र और राजनीति विज्ञान की शब्दावलियां प्रकाशित की हैं। भाषा-विज्ञान की तकनीकी शब्दों की शब्दावली मुद्रण के लिए प्रेस में भेज दी गई हैं। अन्य विषयों में शब्दावली को अन्तिम रूप देने का कार्य प्रगति पर है। हाल ही में, कृषि, समाजशास्त्र, पत्रकारिता और जनसंचार, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की शब्दावली समितियां गठित की गई हैं।

उर्दू विश्वकोश

12 अंकों में उर्दू विश्वकोश तैयार करने से सम्बन्धित कार्य जिसे 1973 में शुरू किया गया था, 1981 में पूरा कर लिया गया। इस विश्वकोश में 4 आरंभिक खण्ड होंगे जिन्हें प्रमुख अनुच्छेद शामिल होगा और इसके छोटी प्रविष्टियों और संदर्भों आदि के 8 अन्य अंक होंगे। पहला अंक इस वर्ष के दौरान प्रैस को सौंप दिया जाएगा।

शब्दकोश

निम्नलिखित शब्दकोशों में प्रगति नीचे दर्शायी गई है :—

(क) अंग्रेजी-उर्दू शब्दकोश 5 अंकों में प्रकाशनाधीन है।

(ख) उर्दू-उर्दू शब्दकोश पांच अंकों में संकलित की जा रही है। एक अंक मुद्रण के लिए तैयार है।

(ग) उर्दू-अंग्रेजी शब्दकोश 5 अंकों में संकलित की जा रही है।

(घ) उर्दू-उर्दू छात्र शब्दकोश जिसमें 42,000 प्रविष्टियां हैं, प्रैस को भेजी जा रही हैं।

(ङ) उर्दू पुस्तकों की ग्रंथ सूची :

भारत में मुद्रणालय के आरम्भ होने से ही उर्दू पुस्तकों की व्यापक ग्रंथ सूची के संकलित करने का कार्य आरम्भ किया गया है। ज्ञान के विभिन्न शाखाओं से सम्बन्धित 1947 तक मुद्रित उर्दू की पुस्तकें इस ग्रंथ सूची में शामिल होंगी। इस परियोजना से सम्बन्धित कार्य 6 केन्द्रों में आरम्भ किया जा रहा है, जिसमें से यह कार्य अलीगढ़ मौलाना आजाद पुस्तकालय में चल रहा है और 16,000 कार्डों को समाकलित किया गया है, वार्षिक ग्रंथ सूची जामिया मिलिया के सहयोग से समाकलित की जा रही है और 1976, 1977 और 1978 से सम्बन्धित ग्रंथ सूची प्रकाशित हो चुकी है।

सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्र

उर्दू सुलेखन की ललित कला को बनाए रखने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और उर्दू प्रकाशन उद्योग के लिए अच्छा सुलेखक प्रदान करने के लिए देश के प्रमुख उर्दू केन्द्रों में ब्यूरो ने सुलेख प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की है।

अब तक 30 केन्द्रों की स्थापना की गई है जिसमें सजावट सुलेखन के 2 केन्द्र और केवल महिलाओं के लिए बनाए गए 4 मौलिक सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्र। प्रत्येक केन्द्र में मौलिक सुलेखन प्रशिक्षण में छात्रों की संख्या 25 है और सजावटी सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 5 है।

उर्दू टंकण और आशुलिपि केन्द्र

गालिब अकादमी, दिल्ली में एक उर्दू टंकण और आशुलिपि केन्द्र स्थापित किया गया है। यह मंत्रालय द्वारा उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो के माध्यम से वित्तपोषित है। इसका उद्देश्य कार्मिकों को नई आशुलिपि और टंकण कला में प्रशिक्षण देना है।

उर्दू टंकण यंत्र

उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो का मुख्य लक्ष्य ऐसे कार्यक्रम और योजनाएं आरम्भ करना है जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में तकनीकी क्षेत्रों में भी उर्दू की प्रोन्नति के लिए कार्य करते हैं। कुछ वर्ष पहले भारत में उर्दू टंकण यंत्र तैयार नहीं किए जाते थे। किन्तु उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो ने देशी उर्दू टंकण यंत्रों के निर्माण में एक साधन का काम किया है। नए उर्दू टंकण यंत्र भारत में गोदरेज कम्पनी, बम्पर द्वारा तैयार किए जा रहे हैं।

बिक्री और प्रदर्शनी

उर्दू में शैक्षणिक साहित्य के निर्माण और प्रकाश के अलावा ब्यूरो 1976 से अपने प्रकाशनों की बिक्री में लगा हुआ है। अब तक 22 लाख रुपये से अधिक की पुस्तकें बेची जा चुकी हैं। विभिन्न स्थानों पर अनेक पुस्तक प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो राष्ट्रीय पुस्तक मेला और विश्व पुस्तक मेले में भी भाग लेता है।

उर्दू दुनियां

उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो के कार्यकलापों की तिमाही रिपोर्ट से सम्बन्धित उर्दू दुनिया के प्रकाशन में ब्यूरो ने शुरू किया है, जिसका देश में तथा देश के बाहर भी स्वागत किया गया है। अब तक ऐसे रिपोर्टों के 15 अंक निकाले जा चुके हैं।

उर्दू प्रोन्नति ब्यूरो और विभिन्न उर्दू अकादमियों के बीच समन्वय

घनिष्ठ सहयोग समन्वय के उद्देश्य से ब्यूरो उर्दू अकादमियों में समन्वय समितियां गठित करने की कार्रवाई आरम्भ की है और इसकी 3 ऐसी बैठकें अब तक हो चुकी हैं।

केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद

भारत सरकार द्वारा 1958 में केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान, एक स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, जो अंग्रेजी शिक्षण के स्तर को सुधारने के लिए केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान के रूप में कार्य करता है। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के शिक्षण को शामिल करने के लिए अप्रैल, 1972 में इसके कार्यकलापों का क्षेत्र बढ़ा दिया गया था। इसके बाद इसका पुनः केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान नाम दिया गया और जुलाई, 1973 में इसे संस्थान "विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था" के रूप मान्यता मिल गई।

इस संस्थान ने अपने सताईस वर्ष पूरे कर लिए इस संस्थान ने अंग्रेजी और विदेशी भाषा शिक्षण में इसके स्तरों में सुधार की दिशा में विविध शैक्षणिक कार्यक्रमों को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए अग्रणी प्रयास किया। शुभारम्भ से ही इसने विशिष्ट शिक्षक शिक्षा और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी और अरबी के क्षेत्रों में, एक सशक्त राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में संवारत उच्च शिक्षण की एक मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में धीरे-धीरे विकास किया है।

इसके शिक्षक शिक्षा के कार्यक्रमों में, जो सभी स्तरों पर अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के शिक्षकों के लिए उनकी शैक्षिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए तैयार किया गया है, यह बड़े पैमाने पर प्रमुख कार्मिकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित है, चूंकि केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान जैसे राष्ट्रीय केन्द्र के लिए देश में शिक्षकों के इतनी बड़ी संख्या को सीधे प्रशिक्षण देना सम्भव नहीं है।

जिला केन्द्र

संस्थान ने योजना अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार की वित्तीय सहायता से राज्यों और संघशासित प्रशासनों में "जिला केन्द्रों" की स्थापना को कार्यान्वित करने की योजना आरम्भ की है। ये केन्द्र अंग्रेजी शिक्षकों को आरंभिक स्तर की प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए माध्यमिक स्तर पर पुस्तकालय के लिए संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए और श्रव्य दृश्य सामग्रियों और प्रौढ़ शिक्षुओं के लिए अनौपचारिक शिक्षण के लिए केन्द्र के रूप में कार्य करने के लिए, स्कूल छोड़ जाने वाले और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए यह केन्द्र प्रशिक्षण देने के लिए बना है।

अंग्रेजी भाषा, शिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ किया जाना

विद्यमान अंग्रेजी भाषा शिक्षण की जरूरतों का मूल्यांकन करने के लिए समितियां गठित की गई थी और इस प्रकार की नई संस्थाएं स्थापित करने के लिए जरूरतों की जांच करना है। इन समितियों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के अनुसरण में अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता देने के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि वे प्रभावी रूप में अपनी भूमिका अदा कर सकें। अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों/क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान

के कर्मचारियों की एक कार्यशाला 9 से 13 दिसम्बर, 85 तक हुई। इन संस्थानों के ग्यारह प्रतिनिधियों और ब्रिटिश परिषद के एक प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया। सेमिनार ने अंग्रेजी भाषा शिक्षण के स्तर की समीक्षा की और हमारी बहुभाषायी व्यवस्था में अंग्रेजी के महत्व का ध्यान में रखते हुए, माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षकों के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को पुर्नगठित करने के लिए अनेक सिफारिशें की।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

संस्थान के भूतपूर्व सहभागियों के लिए 14 जुलाई से 27 जुलाई, 1985 तक एक दो सप्ताह का पुनश्चर्या-सह-सेमिनार का आयोजन किया गया। 29 भूतपूर्व सहभागियों ने जो 1970-80 में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूरा किया था, ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पहले सप्ताह में सैधान्तिक विषयों का दिग्दर्शन और दूसरे सप्ताह में पेडागोगिक मामलों पर प्रकाश डाला।

माध्यम सहायता

रेडियो कार्यक्रम के द्वारा अंग्रेजी आकाशवाणी, हैदराबाद से पांच प्रायोजिक प्रसारणों से 1963 में आरम्भ हुआ। अब प्रतिवर्ष प्रसारण कार्यक्रमों की संख्या 259 है। संस्थान में रा. शै. अनु. व प्र. परि. के पाठ्यक्रम का निर्माण किया। फिलहाल आकाशवाणी के 23 केन्द्रों पर 150 कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है।

इसके अलावा आकाशवाणी, हैदराबाद अंग्रेजी के माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए 57 कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।

1979 से आकाशवाणी, हैदराबाद स्कूल छोड़ जाने वालों के लिए ग्रीष्म के दौरान कालेज में प्रवेश लेने वालों के लाभ के लिए रेडियो कार्यक्रमों का भी प्रसारण करता है।

सामग्रियों का निर्माण

संस्थान ने शुरू से ही उपयुक्त कम लागत वाली शिक्षण सामग्रियों के निर्माण में अपने को लगा रखा है। पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के लिए अनेक परियोजनाएं राष्ट्रीय एजेन्सियों, जैसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से शुरू किया गया है। स्कूलों के लिए समेकित पाठ्य-पुस्तकों के दो सीरीज जिसे सामान्य सीरीज और विशेष सीरीज कहा जाता है, जो वर्कबुक और शिक्षक गाईड से सज्जित है, तैयार किया गया। इसका उपयोग केन्द्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों द्वारा उपयोग किया जा रहा है और यह केन्द्रीय माध्यमिक बोर्ड तथा अन्य राज्य बोर्डों द्वारा सम्बद्ध हैं। इसे अनेक राज्य सरकारों और अन्य शैक्षिक एजेन्सियों द्वारा अपनाया गया है।

संस्थान को देश में अंग्रेजी और विदेशी भाषा शिक्षण से सम्बन्धित मामलों में शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोनों द्वारा प्रमुख परामर्शी दायित्व सौंपा गया है। यह आशा की जाती है कि यह उपयुक्त योजना और सिद्धान्तों को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा तथा इन क्षेत्रों में शिक्षण और प्रशिक्षण के स्तरों में सुधार के लिए इसके प्रभावी कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

भारतीय भाषाओं में विश्व-विद्यालय स्तरीय पुस्तकों का निर्माण

1969 से चल रही योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में 15 सहभागी राज्यों और चार विश्वविद्यालयों (जैसे दिल्ली, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, जी. बी. पन्त, कृषि विश्वविद्यालय और हैदराबाद कृषि विश्वविद्यालय) को भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में धीरे-धीरे अपनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में निहित भारतीय प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए अनुदान का प्रावधान किया था। केन्द्रीय अनुदान का उपयोग करते हुए पुस्तक निर्माण का वास्तविक कार्य इन राज्यों में इस लक्ष्य के लिए गठित ग्रन्थ अकादमी/पुस्तक निर्माण बोर्ड द्वारा किया जाता है और संबंधित विश्वविद्यालय के सैलों द्वारा किया जाता है। 31-3-85 के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न भाषाओं में कुल 6932 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस योजना के संचलनात्मक पहलुओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली

आयोग द्वारा जांच की जाती है जो सम्बन्धित एजेन्सियों द्वारा सिफारिश की गई पुस्तकों को अनुमोदन प्रदान करता है और इसके बदले में जो पुस्तकें लिखने के लिए शैक्षणिक व्यवसाय में लगे लोगों का चयन करता है।

इस योजना के संबंध में आयोग के विशिष्ट दायित्व को ध्यान में रखते हुए आयोग ने बंगलौर में 27-2-1975 को राज्य सरकारों/विश्वविद्यालय एजेन्सियों की संचालन समिति की दूसरी बैठक आयोजित की जब इस सम्बन्ध में की गई प्रगति की समीक्षा की गई और साथ ही शब्दावली के कार्य तथा योजना के अन्तर्गत तैयार पुस्तकों को निपटान के कार्य की भी समीक्षा की गई।

औषधि से सम्बन्धित कोर-पुस्तकों का निर्माण

अनुमोदित योजना के अन्तर्गत जो छठी योजना अवधि में चल रही थी, भारतीय लेखकों द्वारा रचित औषधि से सम्बन्धित मौलिक कोर-पुस्तकों, सहायता प्राप्त कम कीमत की पुस्तक निर्माण के लिए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (भारत) को अनुदान दिए जाते हैं जो औषधि के क्षेत्र में स्पष्ट तौर पर व्यवसायी होते हैं। यह योजना, चूंकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक की अध्यक्षता में एक सलाहकार समिति सहित कठिन उड़ान की स्थिति में पहुंच गया है। योजना का महत्व वास्तव में इस बात में शामिल है कि भारतीय स्थितियों में गूंथी हुई चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख क्षेत्र में देशी प्रतिभा को प्रोत्साहित करेगा, और यह कम कीमतों पर पुस्तकों के साथ भारतीय चिकित्सा छात्रों के लिए बरदान होगा और प्रमुख चिकित्सा पुस्तकों पर होने वाली विदेशी मुद्रा के बहाव को कम करेगा। तदनुसार यह योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रहेगी।

अंग्रेजी के समान भारतीय भाषाओं में प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता

पहले से ही चल रही योजनाओं के आधार पर सुपरिभाषित कोटि की गुणात्मक पुस्तकों के प्रकाशन के लिए जिसके प्राय: प्रकाशक नहीं मिल पाये, व्यक्तियों और स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हाल ही में एकमात्र योजना को अन्तिम रूप दिया गया है। यह योजना पहली बार समान रूप से सभी भाषाओं में एक समान लागू करके दिया गया और यह आशा की जाती है कि भाषाओं को सुशोभित बनाने के लिए उपयुक्त पुस्तकों के निर्माण के लिए यह स्वैच्छिक क्षेत्र को अभी और प्रोत्साहित करेगा।

ग. संस्कृत और अन्य श्रेण्य भाषाओं की प्रोन्नति

राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ और हमारी सांस्कृतिक विरासत के मूल्यांकन तथा परिरक्षण के संबंध में संस्कृत के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने संस्कृत शिक्षा और अध्ययन के विकास के लिए कई योजनाएं आरम्भ की हैं। ये योजनाएं अधिक उत्साह और अधिक वित्त व्यवस्था के साथ जारी रखी जा रही है। सातवीं योजना के दौरान अरबी और फारसी और अन्य दो श्रेण्य भाषाओं के प्रचार और विकास का एक ऐसे ही कार्यक्रम को जारी रखा गया है।

संस्कृत की प्रोन्नति के लिए किए गए मुख्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :—स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता देना, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित कई संस्थाओं को अधिक वित्तीय सहायता देकर आदर्श संस्कृत पाठशालाओं में विकसित करना, युवा अध्यापकों को शास्त्रों की अच्छी जानकारी देने के लिए प्रख्यात प्रोफेसरों की व्यवस्था करना, दुर्लभ पाण्डुलिपियों और ग्रन्थ सूचियों का संपादन और प्रकाशन, मौखिक वेद पाठों की परम्पराओं की प्रोन्नति, अप्राप्य संस्कृत पाठों का पुन: मुद्रण करवाना, संस्कृत पाठशालाओं से उत्तीर्ण होकर निकले छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, प्रख्यात विद्वानों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित करना और मानक शब्दकोश तैयार करना और प्रकाशित करना।

स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता

पंजीकृत स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/संस्थाओं के कार्यकलापों में सहायता देने के कार्यक्रमों के अन्तर्गत शिक्षकों के वेतन, छात्रों को छात्रवृत्तियां, भवन निर्माण और मरम्मत, फर्नीचर, पुस्तकालय, अनुसंधान परियोजनाओं पर आवर्ती और अनावर्ती सहायता अनुदान दिए जाते हैं। उक्त सभी मदों पर स्वीकृत राशि की 75 प्रतिशत राशि मंत्रालय द्वारा

अनुदान के रूप में दी जाती है। 24 वैदिक संस्थाओं के मामले में जिनमें मौखिक वैदिक परम्परा को कायम रखा जा रहा है सरकार कुल स्वीकृत व्यय की 95% राशि अनुदान के रूप में देती है। इस वर्ष के दौरान लगभग 650 संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्थान योजना

स्वैच्छिक संगठनों में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनके विकास की सम्भावना है और जिनमें पहले से ही स्नातकोत्तर के अध्ययन चल रहे हैं, इन संस्थाओं को सरकार द्वारा सामान्य स्वैच्छिक संगठनों से अधिक वित्तीय सहायता दी जाती है। अभी तक 11 स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थाएं और 2 स्नातकोत्तर अनुसंधान संस्थाएं इस योजना के अन्तर्गत लाई गई हैं। इनमें से तीन उत्तर प्रदेश, बिहार और केरल में एक-एक, दो हरियाणा, दो महाराष्ट्र और तीन तमिलनाडु में हैं। इन संस्थाओं को सरकार द्वारा 95 प्रतिशत का अनुरक्षण अनुदान हेतु दिया जाता है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

यह संस्थान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना, संस्कृत के परिरक्षण तथा अभिवृद्धि हेतु, जिसमें शोध प्रकाशन से पाण्डुलिपियों का संग्रह तथा परिरक्षण और प्रशिक्षण कार्यकलापों का आयोजन शामिल है, के लिए की गई है। इसने 1970 से सात राज्यों में तिरुपति, दिल्ली, जम्मू, इलाहाबाद, पूरी, गुरूव्यूर और जयपुर में सात केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों की स्थापना की है। इसके अतिरिक्त लगभग 40 प्राइवेट संस्थाएं परीक्षा के कार्य हेतु इससे सम्बद्ध है। यह परीक्षाएं आयोजित करता है और प्रथम से विद्यावारिधि तक के प्रमाण-पत्र तथा डिग्रियां प्रदान करता है। यह स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरों पर शिक्षक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। इस समय संस्थान में विद्यापीठ में 1917 छात्र हैं जिनमें से 1238 छात्रों को उनके अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और छात्रावास सुविधाएं भी प्रदान की जाती है।

प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त विद्यापीठ ने अनेकों शोध, विकास तथा विस्तार कार्यकलाप शुरू किए हुए हैं। इन्की चर्चा नीचे की गई है :--

(क) इलाहाबाद विद्यापीठ जो पाण्डुलिपियों के संग्रह और परिरक्षण की विशेषज्ञ है, ने अब तक लगभग 40,000 पाण्डुलिपियों का संग्रह किया और अनेकों महत्वपूर्ण रचनाएं प्रकाशित की है। इसने कश्मीर विश्वविद्यालय से जिसमें काश्मीर शैववाद निहित है माइक्रो फिल्म पाण्डुलिपियों का एक कार्यक्रम भी शुरू कर रखा है।

(ख) तिरुपति विद्यापीठ निम्नलिखित परियोजनाएं चला रहा है :--

(i) **अग्म कोश** : "वैखानस अग्म कोश" पाण्डुलिपि मुद्रण के लिए तैयार है। इसका पंचतंत्र तथा "शैव्यीज्म कोश" द्वारा अनुसरण किया जाएगा।

(ii) **वेदों की टेप रिकार्डिंग** : विद्यापीठ ने देश में अब तक हजारों वर्षों से चल रहे वैदिक मंत्रों की विभिन्न मौखिक परम्पराओं को रिकार्ड किया। आगे तिरुपति-तिरूमूला देवस्थान्मस के सहयोग से रिकार्डिंग कार्य चल रहा है।

(iii) **मौखिक शास्त्रीय परम्परागत रिकार्डिंग** : मीमांसा परम्परागत की रिकार्डिंग प्रक्रिया में है।

(ग) **जम्मू विद्यापीठ** : यह विद्यापीठ काश्मीर शैव्य दर्शन की विशेषता प्रदान करता है और एक कोश के तैयार करने की परियोजना पूरी होने वाली है। इसका काश्मीर शैव्यीज्म परम्परा के अध्ययन और परिरक्षण हेतु श्रीनगर में एक स्थायी केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

(घ) **दिल्ली विद्यापीठ** : यह सांख्य और योग दर्शन सम्बन्धी एक कोश तैयार कर रहा है। इसने अस्वल्यान स्रोत सूत्र, कात्यायन स्रोत सूत्र, टीकाओं सहित सबृभाष्य, शास्त्र दीपिका, अधवर मीमांसा कोतूहल वृत्ति और अन्य मीमांसा रचनाएं भी प्रकाशित की हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने फोटो आफ सैट प्रक्रिया से चार खण्डों में भट्ट दीपिका

नामक मीमांसा पाठ्य-पुस्तकें हाल ही में प्रकाशित की हैं, जो काफी समय से अप्राप्य थी। अन्य कार्य जो छापने के लिए लिए हुए हैं वे हैं संकर्स काण्ड, न्याय विवेक, स्लोक वृत्तिका, स्रोत सूत्र आदि। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास भी संस्कृत में प्रकाशित हो चुका है। भारत के वर्तमान संस्कृत पंडितों के परिचय तैयार करने का एक परियोजना का कार्य भी प्रारम्भ हो गया है। संस्थान ने, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से परम्परागत तथा आधुनिक भारतीय दर्शन के अध्येताओं के मध्य लगभग एक कथोपकथन प्रकाशित करने की दृष्टि से न्याय दर्शन सम्बन्धी तीन सेमिनार आयोजित की हैं।

विभिन्न विद्यापीठों तथा संस्थानों ने, कुल मिलाकर लगभग 140 ग्रन्थ प्रकाशित किए हैं। दो परियोजनाएं अर्थात् के.जी. से लेकर 10वीं कक्षा तक के लिए शुरू बच्चों के लिए संस्कृत साहित्य और संस्कृत पाठ्यपुस्तकों के छात्रों के लिए सार-संग्रह खण्ड भी प्रारम्भ कर दिए गए हैं।

वर्ष 1985 के दौरान विभिन्न विद्यापीठों में विद्यावारिधि पाठ्यक्रम के लिए लगभग 200 छात्र पंजीकृत किए गए हैं और लगभग 30 अध्येताओं को विद्यावारिधि की डिग्रियां प्रदान की गईं।

छात्रवृत्तियां

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान शिक्षा मंत्रालय की ओर से निम्नलिखित योजनाओं का संचालन कर रहा है :—

(क) संस्कृत पाठशालाओं से उत्तीर्ण होकर निकले शोध अध्येताओं को छात्रवृत्तियां :—

शोध अध्येताओं को 2 वर्ष के लिए 300/- रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा, प्रत्येक छात्र को 500/- रुपये प्रतिवर्ष आनुषंगिक अनुदान भी दिया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत 120 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गई हैं।

(ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां :—

जिन छात्रों ने इन्टर, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर आधुनिक व्यवस्था में संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ा है, उन्हें क्रमशः 50 रुपए, 75 रुपए और 100 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इस योजना के अन्तर्गत 412 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

(ग) परम्परागत संस्कृत संस्थाओं के छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां :—

शास्त्रीय कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को 75/- रुपये प्रतिमाह और परम्परागत पाठशालाओं की आचार्य कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों को 100/- रुपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है। इस वर्ष इन दोनों क्रमशः वर्गों में 13 छात्रों को छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं।

दक्कन कालेज की शब्दकोश परियोजना

ऐतिहासिक सिद्धान्तों पर आधारित संस्कृत शब्दकोश के निर्माण के लिए दक्कन कालेज, पूना को सहायता दी जा रही है। इस शब्द से अनुसंधान छात्रों को प्राचीन और कठिन संस्कृत पाठों की व्याख्या करने में सहायता मिलेगी। खण्ड-1 और 2 और खंड-3 का भाग-1, प्रत्येक के तीन भाग पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।

शास्त्र चूड़ामणि योजना

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यापीठों और आदर्श पाठशालाओं को युवा प्राध्यापकों और स्नातकोत्तर छात्रों को विभिन्न विषयों में गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण विख्यात सेवा निवृत्त विद्वानों द्वारा किया जाता है और उनकी नियुक्ति 1000/- रुपये प्रतिमाह मानदेय पर की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत 1985-86 में 85 अध्येता कार्य करने के लिए अनुमोदित किए गए हैं।

संस्कृत के अलावा अन्य श्रेण्य भाषाओं के प्रचार और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

इस परियोजना के अन्तर्गत दो श्रेण्य भाषाओं, अरबी और फारसी के क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को वेतन छात्रवृत्तियां, फर्नीचर, पुस्तकालय इत्यादि तथा अन्य कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लगभग 150 संस्थानों को यह सहायता दी जा रही है। परम्परागत मदरसों और मक्तबों को अरबी और फारसी में उच्च शोध के लिए प्रत्येक वर्ष 20 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

शिक्षण स्तरों के मूल्यांकन हेतु मदरसों और मक्तवों का राष्ट्रीय सर्वेक्षण शुरू किया गया जिसमें सरकारी अनुदान के लिए संस्थाओं के वर्गीकरण में सहायता मिलेगी। इस्लामी कानून सम्बन्धी फलवा-अल-ततार खानिया का आलोचनात्मक संस्करण निकालने की एक वृहत् अनुसन्धान परियोजना, मंत्रालय द्वारा प्रायोजित की गई। इस परियोजना को दस वर्षों में पूरा किया जाना है।

संस्कृत, अरबी, फारसी भाषाओं के विद्वानों को सम्मान पत्र प्रदान करना

इस योजना के अन्तर्गत विख्यात संस्कृत, अरबी तथा फारसी विद्वानों को राष्ट्रपति का सम्मान पत्र प्रदान किया जाता है। हर वर्ष 14 विद्वान जिनमें 10 संस्कृत, 2 अरबी और 2 फारसी के विद्वान होते हैं, चुने जाते हैं। नामों की घोषणा स्वतंत्रता दिवस की पूर्ण संध्या पर की जाती है। इस पुरस्कार में प्रत्येक विद्वान को आजीवन 5,000/- रु. प्रतिवर्ष का वित्तीय अनुदान और सनद तथा एक दुशाला राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में दिया जाता है। पिछले वर्षों की तरह इस पुरस्कार के लिए 14 विद्वानों को चुना गया।

राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के माध्यम से संस्कृत के विकास की योजना

(क) अभावग्रस्त परिस्थितियों में रह रहे विख्यात संस्कृत विद्वानों को वित्तीय सहायता

इस योजना के अंतर्गत लगभग 1,700 प्रख्यात अध्येताओं को जिसकी आमदनी 250/- रु. प्रति माह से कम है, उन्हें 250/- रु. प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण

संस्कृत शिक्षा की परम्परागत और आधुनिक प्रणाली के बीच सम्पन्नता लाने के लिए भारत सरकार परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं में चुनिन्दा आधुनिक विषयों के शिक्षण के लिए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों को अनुदान देती है। 1985-86 के दौरान प्रत्येक में एक शिक्षक की नियुक्ति के लिए 10 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को सहायता दी जाने की आशा है।

(ग) उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत शिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना

ऐसे उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में जहां राज्य सरकार संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति में नहीं है, नियुक्त किए जाने वाले संस्कृत शिक्षकों के वेतन के लिए भारत सरकार का प्रयास है कि इस अन्तराल को पाटने के लिए 100% तक अनुदान सहायता दी जाए। 1985-86 के दौरान 36 अध्यापकों की नियुक्ति के लिए दस राज्यों ने इस सहायता का लाभ उठाया।

(घ) उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां

उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में संस्कृत अध्ययन के लिए उत्तम छात्रों को आकर्षित करने के उद्देश्य से संस्कृत छात्रों को कक्षा IX से XII कक्षाओं में योग्यता छात्रवृत्ति 10/- रु. प्रति माह की दर से दी जाती है। लगभग 3,000 छात्रों को इस योजना का लाभ पहुंच रहा है।

(ङ) संस्कृत की प्रोन्नति के लिए राज्य सरकारों को उनकी अपनी योजनाओं के लिए अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत संस्कृत के प्रचार-प्रसार जैसे शिक्षकों के वेतन को स्वरोन्नत करने, वैद्विक अध्येताओं को सम्मान देना, विद्वत सभाओं का संचालन करना, संस्कृत के लिए सांध्य कक्षाओं का आयोजन करना, कालीदास समारोह मनाने आदि के लिए राज्य सरकार अपना कार्यक्रम तैयार करने के लिए स्वतंत्र है। इस योजना के अन्तर्गत 1985-86 के दौरान नौ राज्यों को सहायता दिए जाने की आशा है।

संस्कृत साहित्य का निर्माण

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए सहायता दी जाती है:- (1) संस्कृत साहित्य की मूल रचनाओं का मुद्रण और प्रकाशन; (2) दुर्लभ संस्कृत पुस्तकों का मुद्रण; (3) संस्कृत संस्थाओं को निःशुल्क वितरण के लिए लेखकों और प्रकाशकों से संस्कृत की

पुस्तकें खरीदना (1) संस्कृत पत्रिकाओं की कोटि और विषय-वस्तु में सुधार (2) संस्कृत पाण्डुलिपियों की विवरणात्मक सूचियां तैयार करना और संस्कृत पाण्डुलिपियों के आलोचनात्मक संस्करण निकालना।

1985-86 के दौरान (दिसम्बर 1985 के अन्त तक) सरकार की सहायता से 30 प्रकाशन निकाले जा चुके हैं। 1985-86 में 20 और प्रकाशन निकालने की संभावना है। इसके अलावा धर्म कोश मण्डल द्वारा प्राचीन संस्कृत साहित्य का एक विश्वकोश धर्म कोश तैयार करने और उसके प्रकाशन में लगे अब तक 19 अंकों सहित 4 कांड प्रकाशित हो चुके हैं। पूरी वृद्धि में आशा है कि 44 अंक होंगे। प्रत्येक अंक लगभग सुपर रायल आकार का एक हजार पृष्ठों का होगा। 11वीं योजना के लिए इस परियोजना हेतु सहायता के ढांचे पर विचार किया जा रहा है। अखिल भारतीय काशीराज न्यास, वाराणसी सरकारी सहायता से भी महापुराणों का हिन्दी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद और आलोचनात्मक संस्करण प्रकाशित कर रहा है।

लगभग 31 पत्र-पत्रिकाओं को उनकी विषय-वस्तु में सुधार लाने के लिए 1500/- रुपये से 10,000/- रुपये तक अनुदान देकर भारत सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है। सरकार ने विभिन्न संस्थानों को निःशुल्क विवरण के लिए व्यक्तियों और प्रकाशनों से लगभग 175 पुस्तकें खरीदी हैं। 5 ग्रन्थसूचियां /पाण्डुलिपियों की आलोचनात्मक संस्करण 1985-86 में प्रकाशित की गई हैं। इन चार मामलों में आंशिक सम्पादन/ सम्पादकीय अनुदान जारी किया गया है और पुस्तकें तैयार की जा रही हैं तथा मुद्रणाधीन हैं।

कम कीमतों पर पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण संस्कृत पुस्तकों, जिनकी मुद्रित प्रतियां उपलब्ध नहीं हैं, के फोटो आफसैट पुनर्सम्पादन के लिए एक व्यापक कार्यक्रम आरंभ किया गया है। लगभग 80 पुस्तकें, स्वाध्याय मंडल की सभी वैदिक पाठों सहित, हिन्दी टीका सहित सभी वेदों का अनुवाद और 14 पुराणों का प्रकाशन अब तक हो चुका है।

वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा का परिरक्षण

वैदिक अध्ययन की मौखिक परम्परा के परिरक्षण के लिए एक विशेष प्रेरणा के रूप में 1978 के दौरान एक योजना शुरू की गई थी जिसके अन्तर्गत स्वाधियायिन को 12 वर्ष के कम उम्र के दो बच्चों को प्रशिक्षण देने के लिए कहा गया था। उनमें से एक उनका बेटा या निकट सम्बन्धी और किसी खास वेद शाखा में था। 1985-86 के दौरान ऐसे ग्यारह एकक सहायता प्राप्त कर रहे हैं। अध्येता का मानदेय 1000/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1250/- रु. प्रतिमाह कर दिया गया है और छात्रों के लिए अप्रैल, 1985 से 150/- रु. प्रतिमाह कर दिया गया है।

(2) वैसे क्षेत्रों और परिवारों को पता लगाने के उद्देश्य से जहां मौखिक वैदिक परम्परा अभी तक विद्यमान है, मंत्रालय प्रति वर्ष एक वैदिक सम्मेलन का आयोजन करता है जिसमें पूरे भारत से लगभग 100 अध्येताओं को आमंत्रित किया जाता है। इस वर्ष का वैदिक सम्मेलन 24 से 25 दिसम्बर, 1985 को कांचीपुरम् में आयोजित किया गया था।

(3) संस्कृत शिक्षण के विभिन्न शाखाओं में परम्परागत संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों में मौखिक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता का आयोजन करता है। एक शिक्षक सहित सभी राज्य सरकारों की ओर से आठ छात्रों के एक दल को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस वर्ष की प्रतियोगिता दिसम्बर, 1985 में हुई थी।

(4) वैदिक परम्परा का एक दूसरे कार्यालय पर सक्रिय रूप में विचार किया जा रहा है जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ने बहुत ही रुचि दिखाई है।

संस्कृत पाठशालाओं से उत्तीर्ण होकर निकले छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठों, आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों और अन्य परम्परागत संस्थाओं से उत्तीर्ण होकर निकले छात्रों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, 1982-83 में एक नई योजना आरम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत संस्कृत के छात्रों को संस्कृत के विषयों जैसे पुरालेख, पाण्डुलिपि विज्ञान, कर्मकांड, संस्कृत मुद्रण और कम्पोजिंग में अल्प व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इन पाठ्यक्रमों को संचालित करने के लिए पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। 1985-86 के दौरान ऐसे 8 पाठ्यक्रमों को संचालित करने की योजना है।

अध्याय 10

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

भारत और यूनेस्को के बीच सहयोग

भारत, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) का एक संस्थापक सदस्य है जिसकी स्थापना नवम्बर, 1946 में हुई थी तथा जिसका मुख्यालय पैरिस में है। आलोच्य अवधि के दौरान, यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने, न केवल राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वय एजेन्सी के रूप में अपनी भूमिका निभाई बल्कि क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने तथा यूनेस्को की परियोजनाओं और कार्यकलापों की बेहतर सूझबूझ पैदा करने के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र के अन्य राष्ट्रीय आयोगों तथा नई दिल्ली, बैंकाक, जकार्ता, कराची और अन्य स्थानों पर स्थित यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ भी सहयोग किया। आलोच्य अवधि के दौरान आरम्भ किए गए आयोग के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है।

शिक्षा मंत्रियों का पांचवा क्षेत्रीय सम्मेलन

एशिया और प्रशान्त महासागर में शिक्षा के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय ने एशिया और प्रशान्त महासागर के शिक्षा मंत्रियों तथा आर्थिक आयोजना के लिए उत्तरदायी मंत्रियों (एम.आई.एन.ई.डी.ए.पी. V) का पांचवा क्षेत्रीय सम्मेलन मार्च, 1985 में बैंकाक में आयोजित किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में शैक्षिक विकास के प्राथमिक लक्ष्यों, प्रौढ़ों के लिए साक्षरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीकों एवं साधनों तथा विकास की जरूरतों के सम्बन्ध में शिक्षा के नवीकरण के संदर्भ में प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ के लिए शिक्षा पर विचार करना था। सम्मेलन में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री के. सी. पन्त के नेतृत्व में उच्च अधिकार-प्राप्त एक छः सदस्यीय प्रतिनिधि-मंडल ने भाग लिया।

क्षेत्रीय सहयोग पर सलाहकार समिति का तीसरा सत्र

क्षेत्रीय सम्मेलन के तत्काल पश्चात् एशिया और प्रशान्त महासागर में शिक्षा के लिए यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित क्षेत्रीय सहयोग पर सलाहकार समिति के तीसरे सत्र में भारत के शिक्षा सचिव श्री आनन्द स्वरूप ने भाग लिया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यूनेस्को के महा-निदेशक को एम.आई.एन.ई.डी.ए.पी. V की सिफारिशों के आधार पर 1986-87 दो वर्षों के लिए यूनेस्को के शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के विषय में सलाह देना था।

यूनेस्को में प्रधानमंत्री का दौरा

यूनेस्को के महा-निदेशक के आमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने 7 जून, 1985 को पैरिस में यूनेस्को मुख्यालय का सरकारी दौरा किया और अन्यों के साथ, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों तथा इसके सचिवालय अधिकारियों को सम्बोधित किया। कुछ सदस्य राज्यों द्वारा यूनेस्को से वास्तविक निकास और निकास के नोटिस के संदर्भ में, प्रधानमंत्री ने उन सभी राष्ट्रों, जो एक स्वस्थ तथा संतुलित विश्व व्यवस्था के प्रति जिम्मेदार हैं, से इस विपत्ति के समय यूनेस्को की सहायता करने की अपील की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि भारत उस रचनात्मक प्रयास में सहयोग देगा जो यूनेस्को की दुविधा को दूर कर सके। उन्होंने आगे कहा कि यूनेस्को से विमुख होना सार्वभौमिक सहयोग से मुख मोड़ना तथा विश्व निकायों में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के प्रजातन्त्र को अस्वीकार करना है।

उप-आयोगों की बैठकें तथा भारतीय राष्ट्रीय आयोग का अठारहवां सत्र

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने अपने पांच उप-आयोगों की बैठकें जुलाई, 1985 में आयोजित की। बैठकों का उद्देश्य 1986-87 दो वर्षों के लिए यूनेस्को के प्रारूप कार्यक्रम तथा बजट (प्रलेख 23 सी/5) की जांच करना तथा इस प्रलेख के विषय में भारत की स्थिति तैयार करना था।

उप-आयोगों की बैठकें यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के 18वें सत्र के पश्चात, तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री और आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई जो 2 1सितम्बर, 1985 को नई दिल्ली में हुआ था। बैठक का मुख्य उद्देश्य 1986-1987 दो वर्षों के लिए यूनेस्को के प्रारूप कार्यक्रम और बजट पर विचार करना था। इसके अतिरिक्त, इसने अक्तूबर-नवम्बर, 1985 में सोफिया (बुल्गारिया) में हुए यूनेस्को महासम्मेलन के 23वें सत्र में भारत द्वारा पारित प्रारूप-संकल्पों पर भी विचार किया। सम्मेलन में शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्रों के 50 प्रसिद्ध व्यक्तित्वों एवं विशेषज्ञों ने भाग लिया जो भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सदस्य हैं।

यूनेस्को महा-सम्मेलन का 23वां सत्र

सोफिया (बुल्गारिया) में 8 अक्तूबर से 9 नवम्बर, 1985 तक हुए यूनेस्को के महा-सम्मेलन के 23वें सत्र में मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव के नेतृत्व में एक उच्च-अधिकार-प्राप्त शिष्ट-मंडल ने भाग लिया। शिष्ट-मंडल में वैकल्पिक नेता के रूप में सरदार स्वर्ण सिंह, राज्य शिक्षा और संस्कृति मंत्री, श्रीमति सुशीला रोहतगी, युवा कार्य, खेल-कूद और महिला कल्याण की राज्यमंत्री श्रीमति मारग्रेट एलवा, यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य श्री टी. एन. कौल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के सचिव श्री आनन्द स्वरूप संसद सदस्य डा. कर्ण सिंह, प्रो. एन. सी. परासर, शिक्षा विभाग के विशेष सचिव श्री किरीट जोशी, भारतीय राजदूत तथा यूनेस्को और भारत के स्थायी प्रतिनिधि श्री इनाम रहमान तथा बुल्गारिया में भारत के राजदूत श्री श्याम सुन्दर नाथ, शामिल थे। सम्मेलन की मुख्य कार्यसूची, वर्ष 1986-87 के लिए यूनेस्को के प्रारूप कार्यक्रम तथा बजट पर विचार करना और उसे लागू करना था। शिष्ट-मंडल के नेता को महासम्मेलन के उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया। भारत को सम्मेलन के प्रारूपण और वार्ता दल के अध्यक्ष के रूप में भी चुना गया। इसके अतिरिक्त, भारत को निम्नलिखित समितियों/अन्तर सरकारी निकायों के सदस्य के रूप में चुना गया :–

(1) कानूनी समिति

(2) मुख्यालय समिति

(3) संचार विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की अन्तर-सरकारी परिषद (आई.पी.डी.सी.)

(4) अन्तर-सरकारी सूचनात्मक कार्यक्रम के समन्वय के लिए जिम्मेदार समिति।

इसके अतिरिक्त, विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक दाय के संरक्षण से सम्बन्धित सभा जो 4 नवम्बर, 1985 को हुई थी, की राज्य पार्टियों की पांचवी महा-सभा में भारत को विश्व दाय समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया।

परिपूर्ण अधिवेशनों, कार्यक्रम आयोगों और प्रशासनिक आयोगों में हुई परिचर्चाओं में भारतीय शिष्ट-मंडल के सक्रिय रूप से भाग लेने के अतिरिक्त, भारतीय शिष्ट-मंडल ने विकासशील देशों के दृष्टिकोण पर बल देने तथा यूनेस्को के कार्य के लिए कुछ प्राथमिकताओं तथा कार्यक्रमों को प्रकाश में लाने के लिए, आठ प्रारूप संशोधन एवं संकल्प प्रस्तुत किए।

यूनेस्को का कार्यकारी बोर्ड

यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के भारतीय प्रतिनिधि श्री टी. एन. कौल ने, वर्ष के दौरान हुए इसके 121, 122 और 123 वें सत्रों में भाग लिया। संगठन के कार्यों में सुधार लाने के लिए तरीकों एवं साधनों के सम्बन्ध में महा-निदेशक को सलाह देने के लिए गठित एक अस्थायी समिति के एक सदस्य के रूप में श्री कौल को चुना गया। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में श्री टी. एन. कौल की अवधि यूनेस्को महा-सम्मेलन के 23वें सत्र की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गई।

सोफिया में 19 अक्तूबर, 1985 को यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड के चुनाव में भारतीय उम्मीदवार सरदार स्वर्ण सिंह को एक सदस्य के रूप में चुना गया। उन्होंने यूनेस्को के पुनर्गठित कार्यकारी बोर्ड की प्रथम बैठक जो सोफिया में 13 से 14 नवम्बर, 1985 तक हुई थी, में भाग लिया।

यूनेस्को बजट में योगदान

यूनेस्को के एक सदस्य राज्य के रूप में, भारत इसके बजट के लिए नियमित रूप से योगदान दे रहा है। प्रत्येक सदस्य राज्य के योगदान का हिस्सा यूनेस्को महा-सम्मेलन द्वारा निश्चित किया जाता है जो सामान्यत: प्रत्येक दूसरे वर्ष में होता है। वर्ष 1984-85 के लिए, यूनेस्को महा-सम्मेलन का 22वां सत्र अक्तूबर-नवम्बर, 1983 में हुआ जिसमें भारत का योगदान यूनेस्को के कुल बजट का 0.36% था। इस दर पर, वर्ष 1984 और 1985 के लिए भारत का योगदान 6,20,460 यू. एस. डालर प्रति वर्ष था जो लगभग 78,80,000 रुपए के बराबर है। यह राशि पहले से ही दे दी गई है।

सदस्य राज्यों के निकास के कारण संगठन के वित्तीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए तथा अपनी सहायता के प्रमाणस्वरूप भारत ने भी 407,245 यू. एस. डालर छोड़ दिए जो यू. एस. डालर के मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण तीन वर्षों 1981-1983 के लिए यूनेस्को बजट के वास्ते भारत के योगदान की बचत के रूप में प्राप्त हुए थे।

यूनेस्को सहभागिता कार्यक्रम

अपने सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत, यूनेस्को ने महा-निदेशक को राष्ट्रीय स्तर पर और उप-क्षेत्रीय, क्षेत्रीय अथवा अन्तर-क्षेत्रीय स्तर पर सदस्य राज्यों के कार्यकलापों में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया। सहभागिता कार्यक्रम, सदस्य-राज्यों को पूर्व-निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के विचार से महा-सम्मेलन द्वारा निश्चित क्षेत्रों में प्रारम्भ की गई, गतिविधियों के वास्ते यूनेस्को की सहायता से लाभान्वित करता है। सह-भागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1984-85 दो वर्षों के लिए भारत द्वारा प्रस्तुत 20 परि-योजनाओं में से अवधि के दौरान यूनेस्को की सहायता के लिए 12 परियोजनाओं को स्वीकार किया गया। इन परियोजनाओं के लिए यूनेस्को से प्राप्त वित्तीय सहायता की कुल मात्रा 1,42,000 यू. एस. डालर है। 1985 के दौरान पांच परियोजनाएं कार्यान्वित की गई।

यूनेस्को क्लब

यूनेस्को क्लब आन्दोलन की शुरूआत से ही भारत इसमें गहरी रुचि ले रहा है। एशिया में जापान के पश्चात भारत में ही यूनेस्को क्लबों की अधिकतम संख्या है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग इन क्लबों के लिए रोचक प्रकाशन तथा अन्य सामग्री प्रदान करता है। य.एन. दिवस, मानव अधिकार दिवस इत्यादि जैसे समारोहों को मनाने के लिए विशेष किटें भी भेजी जा रही हैं।

यूनेस्को कूपन

सूचना के मुक्त प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए यूनेस्को ने, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्रों में कार्य कर रहे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सहायता करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कूपन योजना प्रारम्भ की है जिससे कि वे विदेशी मुद्रा और निर्यात नियन्त्रण प्रक्रियाओं के बिना अपनी वास्तविक जरूरतों के अनुसार पुस्तकों, शैक्षिक सामग्री, वैज्ञानिक उपकरण और शैक्षिक फिल्मों को विदेश से आयात कर सकें। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, भारत में यूनेस्को कूपनों के बिक्री के लिए वितरण एजेन्सी के रूप में कार्य कर रहा है। 1985-86 के दौरान यूनेस्को कूपनों की कुल बिक्री लगभग 1,50,000 रुपए की होगी।

यूनेस्को दूत

यूनेस्को के सहयोग से, भारतीय राष्ट्रीय आयोग, 'कूरियर' नामक एक यूनेस्को मासिक पत्रिका हिन्दी और तमिल संस्करण निकाल रहा है जो विश्व की एक सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक और सांस्कृतिक पत्रिका है। प्रत्येक भाषा के अंक की प्रतियों की वर्तमान संख्या 3000 है जो भारत में स्कूल तथा कालेजों के छात्रों और शिक्षकों एवं यूनेस्को कार्यकलापों में रुचि लेने वालों को व्यापक रूप से बांटी जाती है।

न्यूजलैटर

भारतीय राष्ट्रीय आयोग अंग्रेजी भाषा में त्रैमासिक पत्रिका "न्यूजलैटर" नियमित रूप से निकाल रहा है। 1984 से आयोग ने इस बुलेटिन का प्रकाशन हिन्दी भाषा में भी शुरू कर दिया है। प्रत्येक भाषा में लगभग 2000 प्रतियां प्रकाशित की जाती है जो भारत तथा विदेश में उन विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को भेजी जाती है जो यूनेस्को के कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों से सम्बन्धित है। इस पत्रिका में तिमाही के दौरान यूनेस्को के कार्यकलापों एवं कार्यक्रमों तथा इसके साथ ही आयोग के कार्यकलापों के विषय में सूचना होती है।

सम्बद्ध स्कूल परियोजना

भारतीय राष्ट्रीय आयोग, यूनेस्को की सम्बद्ध स्कूल परियोजना में भाग लेता है जो भारत के लोगों के बीच यूनेस्को के उद्देश्यों एवं कार्यकलापों को जानकारी बढ़ाती है। यूनेस्को के संदेश को फैलाने के लिए आयोग का सचिवालय, स्वैच्छिक संगठनों को सहायक-अनुदान स्वीकृत करता रहा।

सम्बद्ध परियोजना के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय आयोग के विस्तृत कार्यक्रम

भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने भारत में एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है जो यूनेस्को द्वारा संचालित कार्यक्रम से भिन्न है किन्तु उसी के समान रूप रेखाओं पर आधारित है; यह कार्यक्रम देश में स्कूलों और शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाओं की एक बड़ी संख्या शामिल करने के लिए है। इस समय संस्थाओं की संख्या 738 है। क्योंकि यह कार्यक्रम भारत और विश्व के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है इसी कारण इसमें अधिक स्कूल शामिल हो रहे हैं।

भारतीय राष्ट्रीय आयोग को सुदृढ़ करना

यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग को अपने कार्यों एवं उत्तरदायित्वों को एक उपयुक्त तरीके से सम्पन्न करने में समर्थ बनाने के लिए योजना आयोग द्वारा इसके कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए एक योजनागत योजना का अनुमोदन किया गया है। 1985-86 के बजट प्राक्कलनों में 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है।

यूनेस्को द्वारा प्रायोजित अन्य सम्मेलनों/बैठकों में भाग लेना

एशिया और प्रशांत महासागर में यूनेस्को सांस्कृतिक कार्यकलापों में क्षेत्रीय सहयोग संबंधी विशेषज्ञों की सातवीं बैठक 14 से 18 मार्च, 1985 तक तोकियो, जापान में हुई। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव श्री डी. एस. मिश्रा को बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। उन्हें बैठक का उपाध्यक्ष चुना गया।

शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षा सलाहकार श्री जॉन जोसेवा को 29 अप्रैल से 5 मई, 1985 तक करांची, पाकिस्तान में हुए पुस्तक डिजाइन से संबंधित यूनेस्को के उप-क्षेत्रीय सेमिनार में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया ।

शिक्षा विभाग के विशेष सचिव, श्री किरीट जोशी ने हमबर्ग में हुए शिक्षा के अन्तर्राष्ट्रीय समीक्षा के सम्पादकीय बोर्ड के 31वें सत्र तथा शिक्षा के लिए यूनेस्को संस्थान के शासी मंडल के 37वें सत्र में जो क्रमशः 20 मई, 1985 तथा 21-23 मई, 1985 में हुए थे, में भाग लिया ।

भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने, उपरोक्त बैठकों के अतिरिक्त, यूनेस्को द्वारा अथवा उसके तत्वावधान में आयोजित लगभग 52 राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों, कार्य-शालाओं, सेमिनारों, सम्मेलनों इत्यादि में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को मनोनीत किया।

विदेशों के आगन्तुक

1985-86 के दौरान विभिन्न देशों, यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय आयोगों से कई आगन्तुकों ने भारत का दौरा किया। महत्वपूर्ण आगन्तुकों में मारीशस के कला और संस्कृति मंत्री श्री आर्मूगम परसुरमन, ने 19-25 सितम्बर, 1985 और नीदरलैंड के शिक्षा और विज्ञान मंत्री श्री विम. जे. डीटमैन, ने 3-9 नवम्बर, 1985 तक भारत का दौरा किया ।

विश्व विरासत समिति

विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय के प्रावधान के अन्तर्गत विश्व विरासत समिति नामक एक समिति जिसमें अभिसमय के 21 देशों के दल शामिल हैं, गठित की गई। समिति की मुख्य जिम्मेदारी उन प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थलों

की पहचान करता है जिनको विश्व विरासत सूची में शामिल करके विश्व विरासत अभिसमय के अन्तर्गत परिरक्षित किया गया है ताकि इन स्थलों को समूचे विश्व में जाना जा सके तथा विश्व विरासत निधि से विश्व विरासत स्थलों की संरक्षा के लिए देशों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया जा सके।

विश्व विरासत समिति के चुनाव देशों की महासभा के पांचवे सूत्र के दौरान नवम्बर, 1985 को हुआ । भारत को इस समिति के एक सदस्य के रूप में चुना गया है ।

विश्व विरासत सूची में अभिलेख के वास्ते अब तक भारत के निम्नलिखित छः सांस्कृतिक स्मारकों को स्वीकृत किया गया :--

(1) ताजमहल (2) अजन्ता की गुफाएं (3) एलोरा की गुफाएं, (4) आगरे का किला (5) कोणार्क का सूर्य मन्दिर (6) महाबलिपुरम के स्मारक ।

विश्व विरासत समिति द्वारा सूची में शामिल करने के लिए निम्नलिखित तीन प्राकृतिक स्थलों पर भी विचार किया गया :

(1) काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क ।
(2) क्योलदेव राष्ट्रीय पार्क ।
(3) मानस वन्य-जीवन सुरक्षित स्थल ।

यूनेस्को हाउस का निर्माण

जब भारत ने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए उपयुक्त,, बिना किराए के स्थान की सामान्य सुविधा प्रदान करने की सहमति प्रदान की तो 1965 में दक्षिण और केन्द्रीय एशिया के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करने के बहुत समय से आ रही इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अब नई दिल्ली में एक नया कार्यालय भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भूमि का एक प्लाट पहले ही आबंटित कर दिया गया है। यूनेस्को हाउस के निर्माण की योजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। इस भवन में, भारत में कार्य कर रहे यूनेस्को के दो कार्यालयों को ले जाने का प्रस्ताव है। वे हैं (1) भारत में यूनेस्को मिशन के प्रमुख का कार्यालय, और (2) दक्षिण और केन्द्रीय एशिया के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय।

राष्ट्रमंडल शिक्षा मंत्रियों की बैठक

मंत्रालय के यूनेस्को प्रभाग में राष्ट्रमंडल डेस्क, राष्ट्रमंडल सचिवालय के शिक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य का समन्वय करता है ।

राष्ट्रमंडल शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक यूनस्को महा-सम्मेलन के 23वें सत्र के अवसर पर 6 अक्तूबर, 1985 को सोफिया (बुल्गारिया) में हुई बैठक के भारतीय शिष्ट-मंडल का नेतृत्व मानव संसाधन विकास मंत्री श्री पी. वी. नरसिंह राव ने किया। इस सम्मेलन में, निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई--(1) राष्ट्रमंडल छात्र गतिशीलता तथा उच्च शिक्षा (2) 1987 में नैरोबी में होने वाले राष्ट्रमंडल शिक्षा मंत्रियों का दसवां सम्मेलन, तथा (3) यूनेस्को पर विचार-विनिमय।

ओरोविल परियोजना

1980 में केन्द्रीय सरकार ने ओरोविल (आपात व्यवस्था) अधिनियम नामक एक अधिनियम पारित किया जिसके अन्तर्गत ओरोविल दक्षिण भारत में स्थापित एक अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक बस्ती, का प्रबंध दो वर्षों के लिए केन्द्रीय सरकार को दिया गया। यह अवधि प्रति वर्ष के आधार पर 1985 तक बढ़ा दी गई संसद ने अब इस अधिनियम का संशोधन किया है । ओरोविल (आपात व्यवस्था) संशोधित अधिनियम, 1985 द्वारा ओरोविल का प्रबन्ध नवम्बर, 1985 से अगले दो वर्षों के लिए सरकार द्वारा ही देखा जाएगा।

ओरोविल के विकास की एक योजना को, 35.55 लाख रुपये के कुल व्यय के साथ सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। योजना में ओरोविल में निम्नलिखित केन्द्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है :--

(1) बाल विकास केन्द्र

(2) भारतीय अध्ययन केन्द्र

क–संस्कृति हाल

ख–इतिहास हाल

(3) दृश्य-श्रव्य शिक्षा सम्बन्धी सामग्री केन्द्र

(4) शारीरिक शिक्षा विकास केन्द्र

(5) विकासात्मक अध्ययन केन्द्र

क–मानव एकता केन्द्र

ख–मदर एजेंड़ा भवन

(6) शहरी विकास केन्द्र

(7) समुदाय सुविधा एवं सेवाएं

ओरोविल अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चौथी और पांचवीं बैठकें

ओरोविल (आपात व्यवस्था) अधिनियम, 1980 की धाराओं के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित ओरोविल अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की चौथी बैठक मई, 1985 में हुई थी । परिषद ने ओरोविल के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के प्रति अपना संतोष व्यक्त किया । ओरोविल अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की पांचवी बैठक भी 4 जनवरी, 1986 को हुई । बैठक में ओरोविल विकास में हुई प्रगति की समीक्षा की गई ।

अध्याय 11

अन्य कार्यकलाप

नई शिक्षा नीति

नई शिक्षा नीति तैयार करने के कार्य को एक प्राथमिक कार्य के रूप में आरंभ किया गया है। "शिक्षा की चुनौती" नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य नामक एक दस्तावेज अगस्त, 1985 में तैयार किया गया था जिस पर 29-30 अगस्त, 1985 को हुई सभी राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी और जो शिक्षा की राष्ट्रीय नीति पर राष्ट्र व्यापक परिचर्चा का आधार बना।

इस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने महत्त्वपूर्ण विषयों पर 11 राष्ट्रीय और 20 प्रायोजित सेमिनार आयोजित किए जबकि राज्य सरकारों ने राज्य स्तर तथा जिला स्तर के सेमिनार आयोजित किए। शिक्षा मंत्रालय, रा. शै. अनु. प्र.प. तथा रा.शि.आ.प्र.सं. के अधिकारियों को राज्य स्तर पर हुई परिचर्चा तथा विचार-विमर्श में सहायता करने के लिए मनोनीत किया। निम्नलिखित शिक्षक संगठनों से अपने-अपने सम्बन्धों के राज्य स्तर के सेमिनार तथा एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करने का अनुरोध किया गया :—

— अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ
— अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ
— अखिल भारतीय कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षकों के संगठन का संघ
— अखिल भारतीय शैक्षिक एसोसिएशन का संघ

राज्य शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में, राज्य शिक्षा मंत्रियों और कुछेक प्रतिष्ठित विशेषज्ञों को शामिल करने के लिए जन-शक्ति प्रक्षेपण तथा व्यावसायीकरण, और वित्तीय संसाधनों पर एक-एक, अर्थात् दो दल तैयार किए गए। इन दलों की बैठकें क्रमशः 25 और 26 नवम्बर 1985 तथा 25 और 26 फरवरी, 1986 को हुई। मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में शिक्षा सुधार पर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का एक राष्ट्रीय दल भी गठित किया गया है।

राज्य सरकारों के लगातार लिखा-पढ़ी के परिणामस्वरूप स्थानीय स्तर से आगे की परिचर्चा आयोजित करना संभव हो सका—ब्लाक, जिला, मंडलीय स्तर और राज्य स्तरों पर बैठकें हुई। शिक्षक संगठनों, विश्वविद्यालय संकाय, राजनीतिक पार्टियां एवं अभिभावकों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया। राज्य सरकारों से, जनता के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक परामर्श करने का अनुरोध भी किया गया और उनमें से अनेकों ने ऐसा किया। अधिकांश राज्यों से विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकारों के विचार प्रस्तुत करने वाले विस्तृत ज्ञापन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

सुविख्यात रुचियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक संगठनों ने अपने-अपने ज्ञापन औपचारिक रूप से भेजे हैं। इनमें, नई तालीम संघ (गांधीवादी मूल शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने वाला), अखिल भारतीय ईसाई उच्च शिक्षा एसोसिएशन, विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा एसोसिएशन, राष्ट्रीय महिला संगठन, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय विश्वविद्यालय एसोसिएशन, राष्ट्रीय अभिभावक शिक्षक एसोसिएशन इत्यादि शामिल हैं। अखिल भारतीय प्रबंध एसोसिएशन और अनेक जानी-मानी प्राइवेट कंपनियों (टाटा परामर्श-दाता और लार्सेन और टौबरो सहित) ने विस्तृत ज्ञापन भेजे। इसके अतिरिक्त, कई हजार व्यक्तिगत ज्ञापन भी प्राप्त हुए। ये-सभी दस्तावेज रा. शि. आ. प्र. सं. को भेजे

गए, जिन्होंने एक संक्षिप्त और वर्गीकृत रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रकाशित किए हैं :

(1) नागरिकों की दृष्टि में नई शिक्षा नीति–अवबोधन खण्ड । मई, 1985 तक प्राप्त व्यक्तिगत ज्ञापन ।

(2) नागरिकों की दृष्टि में नई शिक्षा नीति–अवबोधन खण्ड ।।–जून से अक्तूबर, 1985 तक प्राप्त व्यक्तिगत ज्ञापन ।

(3) केन्द्रीय शिक्षा मंत्री के जनवाणी कार्यक्रम के प्रति व्यक्तिगत प्रतिक्रिया ।

(4) प्रैस कतरनों का सारांश ।

(5) अक्तूबर, 1985 के अन्त तक प्राप्त सेमिनार रिपोर्टों और दल ज्ञापनों का सारांश ।

7 नवम्बर, 1985 को हुई परामर्शदात्री समिति की बैठक में नई शिक्षा नीति से संबंधित प्रश्न ही एकमात्र परिचर्चा का विषय था। लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 10 दिसम्बर और 19 दिसम्बर, 1985 को नई शिक्षा नीति पर चर्चा हुई।

राज्य सरकारों, शैक्षिक संस्थाओं, शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों ने शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन में गहरी रूचि ली तथा अपनी टिप्पणियां भेजी हैं। इस संबंध में प्राप्त सभी सुझावों पर विचार करने के बाद सरकार बजट सत्र में नई शिक्षा नीति का मसौदा संसद में प्रस्तुत करेगी ।

वार्षिक योजना और 20-सूत्री कार्यक्रम

नए बीस सूत्री कार्यक्रम के, प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित सूत्र सं. 16 की मानीटरिंग आलोच्य अवधि के दौरान जारी रही। मंत्रालय के आयोजना, मानीटरिंग और सांख्यिकी ब्यूरो ने, विभिन्न राज्यों/संघीय क्षेत्रों से अपेक्षित सूचना एकत्र करके योजना आयोग तथा प्रधान मंत्री के कार्यालय को आवधिक रिपोर्ट भेजी। इसके अतिरिक्त, वार्षिक और पंचवर्षीय शैक्षिक योजनाओं के समन्वय का कार्य करना तथा केन्द्रीय और राज्य क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति की मानीटरिंग जारी रखना। शिक्षा के मानीटरिंग और मूल्यांकन संबंधी कार्यकारी दल की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए मानीटरिंग, मूल्यांकन और सांख्यिकीय मशीनरी को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है। तदनुसार केन्द्रीय तथा राज्य दोनों ही क्षेत्रों की वार्षिक योजना में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।

वार्षिक योजना 1985-86 में, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए 972·31 करोड़ रुपये (केन्द्रीय क्षेत्र में 331·47 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 640·84 करोड़ रुपए) की धन-राशि की व्यवस्था की गयी। सातवीं योजना में 1985–90 तक के लिए 5457·09 करोड़ रुपये (केन्द्रीय क्षेत्र में 1738·64 करोड़ रुपये और राज्य क्षेत्र में 3718·45 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है । 1986-87 के लिए, शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के वास्ते, मंत्रालय ने 351·96 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

आलोच्य वर्ष के दौरान, 1982-83 से 1984-85 तक शिक्षा पर बजट व्यय का विश्लेषण तथा राज्य योजना 1985-86 का विश्लेषण प्रकाशित किया गया।

शैक्षिक सांख्यिकी

शैक्षिक सांख्यिकी से संबंधित स्थायी समिति की दसवीं बैठक संयुक्त सचिव (आयोजना) की अध्यक्षता में 12-9-1985 को हुई । समिति ने शैक्षिक सांख्यिकी में बकाया कार्य को पूरा करने में मंत्रालय द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की जो इस उद्देश्य के लिए गठित एक उप-समिति की सिफारिशों पर आधारित थी। इसने शैक्षिक सांख्यिकी संबंधी उच्च स्तरीय समिति की अन्य सिफारिशों के कार्यान्वियन के संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई प्रगति की भी समीक्षा की ।

चालू वर्ष के दौरान, उत्तर प्रदेश में शैक्षिक सांख्यिकी के संगणकीकरण के लिए प्रायोगिक परियोजना की बहुलताओं को उ. प्र. की सरकार के परामर्श से अन्तिम रूप दिया गया । इस प्रायोगिक परियोजना के लिए आंकड़े एकत्र करने के वास्ते विशेष सांकेतिक रूप तैयार किए गए । इन्हें मंत्रालय द्वारा मुद्रित कराया गया और क्षेत्र से आंकड़े एकत्र

करने के लिए राज्य सरकार को भेजा गया । प्रायोगिक परियोजना के परिणाम 1986-87 में उपलब्ध होने की आशा है तथा इनको अन्य राज्यों में शैक्षिक सांख्यिकीय संगणकीकरण को प्रारंभ करने के लिए उपयुक्त मार्गदर्शी रूपरेखा तैयार करने में इस्तेमाल किया जाएगा

आलोच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए गए :—

(i) जिला-वार शैक्षिक सांख्यिकी 1976-77 खण्ड XXI —उड़ीसा
(ii) स्कूल शिक्षा पर चुनिन्दा सूचना 1982-83
(iii) स्कूल शिक्षा पर चुनिन्दा सूचना 1983-84
(iv) जिला-वार शैक्षिक सांख्यिकी 1976-77 खण्ड XXII —महाराष्ट्र।
(v) जिला-वार शैक्षिक सांख्यिकी 1976-77 खण्ड XXIII तमिलनाडु
(vi) जिला-वार शैक्षिक सांख्यिकी 1977-78 खण्ड XXIV पश्चिम बंगाल।
(vii) विदेश जाने वाले भारतीय छात्र/प्रशिक्षार्थी 1979-80 और 1980-81
(viii) चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1982-83
(ix) चुनिन्दा शैक्षिक सांख्यिकी 1983-84
(x) भारत में शिक्षा खण्ड । 1978-79 और 1979-80 (मुद्रणाधीन)
(xi) भारत में शिक्षा खण्ड ।। 1977-78 (मुद्रणाधीन)
(xii) भारत में शिक्षा खण्ड ।।। 1976-77 (मुद्रणाधीन)

सांख्यिकी एकक ने मंत्रालय के गौरवपूर्ण दस्तावेज—"शिक्षा की चुनौती—नीति संबंधी ढांचा" को तैयार करने के संदर्भ में आधारभूत आंकड़े मुहैया किए।

सांख्यिकी एकक ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों संगठनों से सांख्यिकीय संबंधी अनेक प्रश्नों का समाधान किया। इसके अतिरिक्त, संसद प्रश्नों का उत्तर देने परामर्शदात्री समिति की बैठकों इत्यादि के लिए मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों को उपयुक्त सांख्यिकीय सामग्री प्रदान की गई ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षिक सुविधाओं की व्यवस्था उच्च प्राथमिकता प्राप्त कर रहा है। प्रधान मंत्री ने संसद के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की एक बैठक मई, 1985 को आयोजित की जिसमें इन समुदायों में शिक्षा की प्रगति एवं विकास में तेजी लाने के तरीकों एवं साधनों की चर्चा की । संसद के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर अत्यधिक ध्यान दिया जा रहा है और सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उनके कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए गए हैं ।

सातवीं योजना 1985–90 तथा वार्षिक योजना 1986-87 के लिए अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जनजातीय उप-योजना को अंतिम रूप दिया गया । वार्षिक योजना 1986-87 के लिए विशेष घटक योजना तथा जनजातीय उप-योजना का प्रारूप भी तैयार कर लिया गया है। वार्षिक योजना 1986-87 के लिए कुल विभाज्य परिणाम में से इन दोनों घटक योजनाओं के लिए कुल विभाज्य परिव्यय का क्रमशः 21.66% और 12.69% निर्धारित किया गया है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर एक पुस्तिका तैयार की गई है और मुद्रणाधीन है। इस पुस्तिका में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के विभिन्न-विभागों तथा संघीय क्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दी गई शैक्षिक सुविधाओं के ब्यौरे दिए गए हैं ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के विषय में राज्यवार सूचना देने वाला एक प्रकाशन प्रकाशित किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए छात्रावासों की योजना, जो कल्याण मंत्रालय की एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, का मूल्यांकन शिक्षा विभाग के तत्वावधान में किया जा रहा है। यह मूल्यांकन कार्य तीन अनुसंधान संगठनों को सौंपा गया है।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

अल्पसंख्यकों के कल्याण के विषय में भूतपूर्व प्रधान मंत्री के 15 सूत्री निदेश के अनुसरण में शिक्षा विभाग ने शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के बारे में अनेक प्रगतिशील कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

(i) सामुदायिक पालिटैक्निकों की योजना के अंतर्गत 10 पालिटैक्निक अल्पसंख्यक केन्द्रित क्षेत्रों में, अल्प-कालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न दक्षताओं/व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उपयुक्त अल्पसंख्यक केन्द्रीय क्षेत्रों में प्रत्येक सामुदायिक पालिटैक्निक के 4 विस्तार केन्द्र हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 1700 छात्र अंतर्गत लगभग 1700 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और लगभग 700 छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण के पश्चात्, स्व-रोजगार सहित लाभ कारी रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण कक्षाओं की एक योजना निकाली है ताकि उन्हें सिविल सेवा परीक्षाओं और अन्य सेवाओं में प्रवेश पाने के लिए तैयार किया जा सके। इस योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालयों/कालेजों को शिक्षण केन्द्र खोलने, के लिए अनुदान दिए जाते हैं ।

(iii) राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा की जा रही है। इतिहास और भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों के पुनरीक्षण का कार्य लगभग सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में पूरा हो चुका है। रा. शै. अनु, प्र. प. ने अब भूगोल, समाज-शास्त्र और राजनीति-विज्ञान में स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन का कार्य आरंभ कर दिया है। पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शी रूपरेखाएं और उपकरणों को राज्य एजेंसियों को उनके विचारों के लिए भेज दिया गया है।

(iv) रा. शै. अनु. प्र. प. व्यावसायिक मार्गदर्शन तथा अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं के शिक्षकों के लिए विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करती है । इसके अतिरिक्त रा.शै.अनु.प्र.प. ने, अल्पसंख्यक प्रबंधक स्कूलों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के वास्ते चुनिन्दा विश्वविद्यालयों में संसाधन केन्द्र स्थापित करने के संबध में कार्म प्रारंभ कर दिया है। अलीगढ़, जामिया मिलिया इस्लामिया, कश्मीर, मराठावाड़ा और उस्मानिया विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल है।

विद्यमान शैक्षिक प्रणाली को सुधारने तथा इस अल्पसंख्यकों के जीवन के अधिक सुसंगत बनाने की दृष्टि से, नई शिक्षा नीति के संदर्भ में अल्पसंख्यकों और शिक्षा से संबंधित एक दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया ।

मंत्रालय के लिए संगणकीकृत प्रबंधक सूचना प्रणाली का विकास

इस मंत्रालय के लिए संगणकीकृत प्रबंधक सूचना प्रणाली के विकास के वास्ते, मंत्रालय ने राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (इलैक्ट्रोनिक विभाग) के साथ एक समझौता किया है। इस संदर्भ में, रा.शु.के. ने मंत्रालय में एक लघु संगणक केन्द्र स्थापित किया है। यह केन्द्र राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र के बड़े संगणक के संयोग से इसके नेटवर्क के एक भाग के रूप में कार्य करता है।

सी.एम.आई.एस. के विकास में तेजी लाने तथा मंत्रालय में ही सुविज्ञता लाने की दृष्टि से आयोजना, शानीटरिंग और सांख्यिकी प्रभाग में एक सी.एम.आई.एस. एकक स्थापित किया गया है। सी.एम.आई.एस. एकक के नियंत्रण में एक वर्ड प्रोसेसर और फोटोकापियर है।

सी.एम.आई.एस. एकक ने संगणकीकरण के लिए मंत्रालय के विभिन्न प्रभा में विभिन्न परियोजनाएं प्रारंभ की है। जिन परियोजनाओं के लिए सोफ्टवेयर विकसि कर लिए गए हैं और जो पूरी कर ली गई हैं/पूरी हो रही हैं वे निम्नलिखित हैं :—

(i) भारतीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विदेशी छात्र
(ii) वेतन बिलों का संगणकीकरण
(iii) मंत्रालय के खातों का संगणकीकरण
(iv) विदेश जाने वाले भारतीय छात्र/प्रशिक्षणार्थी

"विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की योजनाएं" तथा "भाषा प्रभाग द्वा निकाले गए प्रकाशनों का संगणकीकरण" परियोजनाओं के संबंध में व्यवहार्यता अध्ययन पू कर लिया गया है तथा "प्रोफार्मा" तैयार कर लिया गया है।

"श्रेण्य भाषाओं में अनुसंधान के लिए छात्रवृत्ति योजना" तथा "विभिन्न विषय में शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण" नामक परियोजनाओं से सम्बन्धित प्रोफार्मा तैयार कर का कार्य प्रगति पर है।

इसके अतिरिक्त, सी.एम.आई.एस. एकक ने उप-सचिव और इससे उच्च स्त के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक दो दिवसीय संगणक संकेतन पाठ्यक्रम आयोजि किया। नई शिक्षा नीति पर महत्वपूर्ण दस्तावेजों "सातवीं पंचवर्षीय योजना पर टिप्पणियां" इत्यादि को तैयार करने के लिए वर्ड प्रोसेसर का व्यापक उपयोग किया गया है। फोटो कापियर का भी अधिकतम प्रयोग किया गया।

शैक्षिक प्रयोजनों के लिए नियंत्रित दरों पर सफेद मुद्रण कागज की आपूर्ति

आलोच्य वर्ष के दौरान राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों को नियंत्रित दरों प रियायती सफेद मुद्रण कागज के आवंटन की योजना जारी है। इस अवधि के दौरान सफे मुद्रण कागज की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है तथा अभ्यास पुस्तिकाओं क कीमतें भी स्थिर रही हैं। वर्ष 1985-86 के दौरान दिसंबर, 1985 तक राज्यों/संघी क्षेत्रों को शैक्षिक प्रयोजनों के लिए लगभग 1,00,055 मीट्रिक टन कागज आबंटित किय गया है।

नार्वे से उपहार स्वरूप प्राप्त कागज का आयात

नार्वे सरकार के साथ द्विपक्षीय करार के अंतर्गत, 1985 की कार्य संचाल योजना के दौरान 3200 मीट्रिक टन कागज की सहायता, जिसका मूल्य 3.10 करो रुपए है, प्राप्त होने की आशा है। यह निर्णय किया गया है कि उक्त मात्रा में से 1500 मीटर टन कागज रा.शै.अनु.प्र.प. को स्कूली पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण के लि आबंटित किया जाएगा। शेष कागज, आर्थिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों को, प्रौढ़ शिक्ष कार्यक्रमों के वास्ते सामग्री के मुद्रण हेतु देने का प्रस्ताव है।

उपहार स्वरूप प्राप्त कागज के सम्बन्ध में संशोधित बजट प्राक्कलन 1985-86 औ बजट प्राक्कलन 1986-87 निम्नलिखित है :—

(करोड़ रुपये

	संशोधित प्राक्कलन (1985-86)	बजट प्राक्कलन (1986-87)
1	2	3
(1) मुख्य शीर्ष "267" एं (i) उपहार कागज योजनेतर (वैचारिक मूल्य)	3.10	3.10
(2) मुख्य शीर्ष "277" बी० 6 (5) (4) नार्वे से प्राप्त उपहार कागज (प्रासंगिक व्यय)	1.90	1.90

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान (पहले का राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन तथा प्रशासक स्टाफ कालेज) एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना तथा सम्पूर्ण वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसका पंजीकरण, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 का 21वां के अन्तर्गत एक सोसाएटी के रूप में दिसम्बर, 1970 में हुआ था। शैक्षिक आयोजकों तथा प्रशासकों के लिए भारत में एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण संस्थान के रूप में इसके मुख्य कार्य, प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा प्रशासन है। संस्थान द्वारा शुरू किए गए मुख्य कार्यकलापों में शामिल है : केन्द्र तथा राज्यों के वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों का, उनकी जरूरतों तथा पृष्ठभूमि के अनुसार प्रशिक्षण तथा पुनर्स्थापन; शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन की समस्याओं में अनुसंधान; इस क्षेत्र में राज्यों तथा अन्य संगठनों को परामर्श तथा विस्तार सेवाएं; शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन में सामयिक रुचि के विषयों पर सेमिनार, कार्य-शालाएं तथा सम्मेलन; और अन्य देशों, विशेषकर, एशियाई क्षेत्र के देशों का प्रशिक्षण तथा अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना।

वर्ष 1985 के दौरान अर्थात् अप्रैल से नवम्बर 1985 तक संस्थान ने 39 प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित कीं। आठ अनुसंधान अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं तथा अन्य आठ प्रगति पर हैं।

नई शिक्षा नीति पर शिक्षा के विभिन्न आयोजना तथा प्रबन्ध मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए संस्थान ने उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए चार क्षेत्रीय सेमिनार तथा एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया। ये सेमिनार, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए "शिक्षा की चुनौती-नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य" नामक दस्तावेज के आधार पर आयोजित किए गए। चार क्षेत्रीय सेमिनारों में से तीन, भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता (पूर्वी क्षेत्र), सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर (दक्षिणी क्षेत्र), और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, दूनर, बम्बई (पश्चिमी क्षेत्र) के सहयोग से हुए। उत्तरी क्षेत्र व राष्ट्रीय सेमिनार नई दिल्ली में हुए।

पहले संस्थान ने शैक्षिक विकास : "एक स्थिति रिपोर्ट और नीति संबंधी प्रश्न" नामक एक विस्तृत दस्तावेज तैयार किया तथा मंत्रालय के "शिक्षा की चुनौती : एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य" नामक दस्तावेज में एक निवेश के रूप में शिक्षा प्रणाली के विश्लेषण की जांच भी की।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) के अनुरोध पर, संस्थान ने, मानव संसाधन विकास (शिक्षा विभाग) तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्री के जनवाणी कार्यक्रम में भाग लेने के संबंध में प्राप्त अनेक पत्रों की विषय-वस्तु तथा नई शिक्षा नीति को तैयार करने के लिए पृष्ठ भूमि सामग्री के रूप में शिक्षा प्रणाली के विषय में लोगों का मत जानने के लिए प्रेस कतरने तथा संगठनात्मक ज्ञापन का विश्लेषण किया।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग

स्कूल स्तर और उच्च शिक्षा स्तर के शिक्षक समुदाय के लिए सुसंगत विभिन्न पहलुओं पर सरकार को सलाह देने के लिए फरवरी, 1983 में राष्ट्रीय शिक्षक आयोग क्रमश: 1 और 2 स्थापित किए गए। दोनों आयोगों ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को 26 मार्च, 1985 को भेज दी।

राष्ट्रीय शिक्षक आयोग 1 और2 की सिफारिशों की जांच करने के लिए एक अधिकार-प्राप्त समिति स्थापित की गई है।

सतर्कता कार्यकलाप

मुख्यालय और अधीनस्थ कार्यालयों दोनों विभाग के स्टाफ के बीच प्रशासन में तेजी लाने तथा अनुशासन लागू करने के लिए सतत प्रयास किए गए। 31.12.84 तक अनिर्णीत 6 मामलों और 1985 के दौरान प्रारंभ किए गए 4 मामलों में से चार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई तथा प्रत्येक मामले के लिए प्रयुक्त आदेश दिए गए। तीन मामले अंतिम स्थिति में हैं।

शिकायत सुधार सैल में प्राप्त सभी शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दिया गया तथा उचित कार्रवाई की गई।

यद्यपि विभाग के मुख्यालय आम जनता के साथ व्यवहार केवल नाममात्र को है, नाजुक क्षेत्रों को निर्धारित किया गया तथा एहतियाती निरोधक उपाय किए गए। जहां आवश्यक समझा गया इन क्षेत्रों में कार्यरत स्टाफ के सदस्यों का तबादला किया गया।

मंत्रालय के प्रशासनात्मक नियंत्रण में 45 स्वायत्त संगठनों में से 31 ने केन्द्रीय सर्तकता आयोग की क्षेत्राधिकार स्वीकार कर लिया है। इनमें से चार संगठनों ने मुख्य सर्तकता अधिकारी भी नियुक्त कर लिए हैं, अन्यों को भी मुख्य सर्तकता अधिकारी नियुक्त करने के लिए राजी किया जा रहा है।

अनुशासन और समय की पाबन्दी कायम रखने के लिए ग्यारह बार अचानक जांच की गई।

पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित आदेशों का अनुपालन

सरकार में नियुक्तियों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के हितों पर निगरानी रखने के लिए शिक्षा विभाग में एक विशेष सैल विद्यमान है। शिक्षा विभाग में प्रशासन निदेशक, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों का ध्यान रखने के लिए, सम्पर्क अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों की भर्ती, पदोन्नति तथा स्थायीकरण के सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आरक्षण और निदेशों के सख्ती के साथ अनुपालन को सुनिश्चित किया गया।

रोस्टरों का नियमित रूप से निरीक्षण किया गया। अनुसूचित जातियों और अनु-सूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित निर्धारित रिपोर्ट और विवरण कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त को नियमित रूप से भेजी गई।

विभाग के अधीन अधीनस्थ कार्यालयों के सभी प्रमुखों से संपर्क अधिकारी के रूप में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मनोनीत करने तथा आरक्षण के लिए उचित रोस्टर रखने के लिए अनुरोध किया गया।

छात्र सूचना सेवा एकक

विदेशी छात्रवृत्ति प्रभाग के अंतर्गत छात्र सूचना सेवा एकक छात्रों के लाभ के लिए भारत और विदेश में उच्च शिक्षा के विषय में सूचना एकत्र, संकलित और प्रसारित करता है तथा छात्रों द्वारा स्वयं आकर अथवा पत्राचार द्वारा की गई पूछताछ का उत्तर देता है। उनके लाभ के लिए, पाठ्यचर्या, विवरणिकाएं, पुस्तिकाओं और वार्षिक रिपोर्ट इत्यादि से युक्त एक संदर्भ पुस्तकालय की भी व्यवस्था है। आलोच्य अवधि के दौरान, अध्येताओं की सुविधा के लिए शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर 30 सूचना-पुस्तिकाओं का संकलन/संशोधन किया गया। इसके अतिरिक्त, एकक ने भारत और विदेश में उच्च/तकनीकी शिक्षा के लिए सुविधाओं के विषय में मौखिक अथवा पत्राचार के माध्यम से पूछे गए 4980 से अधिक पूछताछों का उत्तर दिया। लगभग 4600 व्यक्ति, भारतीय/विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों से संबंधित कलेण्डरों/पुस्तिकाओं/विवरणिकाओं एवं अन्य सामग्री को पढ़ने के लिए पुस्तकालय में आए। यूनिट के संदर्भ पुस्तकालय में वर्ष के दौरान लगभग 1000 और प्रकाशन शामिल किए गए।

रोजगार अथवा उच्च शिक्षा के प्रयोजन से विदेशों में जाने वाले व्यक्तियों के शैक्षिक कागजात का प्रमाणीकरण भी छात्र सूचना सेवा एकक द्वारा किया गया। आलोच्य अवधि के दौरान, 3724 कागजात को अधिप्रमाणित किये गये।

पाकिस्तान और बंगलादेश से शैक्षिक प्रमाणपत्रों के मूल नमूनों को प्राप्त करने के अनुरोधों के सम्बन्ध में इन देशों में स्थित हमारे मिशनों के साथ पत्र-व्यवहार किया गया।

वर्ष 1985-86 के दौरान सरकारी अधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों के विदेशों में भेजे गए शिष्ट मंडल/प्रतिनिधि मंडल	शिष्ट मंडलों की की संख्या	प्रतिनिधि मंडलों/ शिष्ट मंडलों में शामिल व्यक्तियों की संख्या	कुल (रुपये में)	विदेशी मुद्रा (रुपयों में)
	1	2	3	4
	48	119	1,43,221	5,38,621

बजट प्राक्कलन: शिक्षा विभाग:

इस विभाग के सम्बन्ध में 1985-86 तथा 1986-87 के कुल बजट प्रावधान निम्नलिखित है:--

(लाख रुपये)

विवरण	बजट प्राक्कलन 1985-86	संशोधित प्राक्कलकन 1985-86	बजट प्राक्कलन 1986-87
1	2	3	4
मांग संख्या- 24-शिक्षा विभाग . .	3,65.25	3,61.88	--
मांग संख्या-- 57--मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) (विभाग का सचिवालय जिसमें वेतन तथा लेखा कार्यालय तथा मंत्री को विवेक अनुदान शामिल है)	--	--	3,65.14
मांग संख्या- 25-शिक्षा (वर्ष 1986-87 से बदलकर मांग संख्या-58 हो गई है)	5,13,78,47	5,87,73.19	6,61,84,09
केन्द्र केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/ योजनागत) पर राज्यों/संघीय क्षेत्रों को सहायता अनुदान की व्यवस्था तथा केन्द्र/ केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण की व्यवस्था सहित विभाग के लिए सामान्य शिक्षा अन्य राजस्व व्यय का प्रावधान			

हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग

राजभाषा अधिनियम तथा राजभाषा नियमों के प्रावधानों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वर्ष 1985-86 के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल मदों के भी कारगर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आलोच्य वर्ष के दौरान अनेक कदम उठाए गए थे। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रगति की समीक्षा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में की गई।

2. मन्त्रालय के पुनर्गठन के पश्चात्, सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग तथा सम्बन्धित मामलों में मन्त्रालयों को सलाह देने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई।

3. हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत, हिन्दी में प्रशिक्षण के लिए 15 व्यक्तियों, हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण के लिए 19 व्यक्तियों तथा हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण के लिए 5 व्यक्तियों को मनोनीत किया गया।

4. जैसा कि इस योजना में स्वीकृत है, सफल अधिकारियों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

5. हिन्दी टिप्पण तथा प्रारूप तैयार करने में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, हिन्दी जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला व्याख्यान आयोजित किए गए ताकि वे सरकारी कामकाज हिन्दी में कर सकें।

6. सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को सुकर बनाने के लिए, संदर्भ तथा सहायक साहित्य तैयार किया गया तथा इस विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों और इस विभाग के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों को भी उपलब्ध कराया गया।

7. इस विभाग की पत्रिकाएं तथा मैगजीन हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित की जा रही हैं।

8. राजभाषा नीति की विभिन्न सांविधिक तथा प्रशासनिक जरूरतों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए इस विभाग के अधिकारियों ने, विभाग के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा स्वायत्त संगठनों का निरीक्षण किया।

9. सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने, जिनमें विभिन्न प्रभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी शामिल हैं, इस विभाग तथा सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों में कार्य जारी रखा। राजभाषा नीति की विभिन्न सांविधिक तथा प्रशासनिक जरूरतों के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा करने के लिए इन समितियों की बैठकें समय-समय पर नियमित रूप से होती रहीं।

10. आलोच्य वर्ष के दौरान, राजभाषा पर संसद समिति की प्रथम उप-समिति ने, शिक्षा विभाग तथा मंत्रालय के अधीन कार्यालयों, अर्थात शैक्षिक परामर्शदाता भारत लिमिटेड, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, इत्यादि का निरीक्षण किया।

प्रकाशन एकक

प्रकाशन एकक ने, 1985-86 के दौरान 8 द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी शीर्षक) तथा दो त्रैमासिक पत्रिकाओं ''एज्यूकेशन क्वार्टरली'' तथा ''इण्डियन एज्यूकेशन एब्स्ट्रैक्ट'' सहित अंग्रेजी में 38 प्रकाशन निकाले। ''एज्यूकेशन क्वार्टरली'' पत्रिका अपने प्रकाशन के 37वें वर्ष में है। एक मासिक सारांश ''केन्द्र और राज्यों में शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास'' अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में प्रत्येक मास सीमित परिचालन से निकाला जाता है।

हिन्दी प्रकाशन एकक ने इस अवधि के दौरान दो त्रैमासिक पत्रिकाओं ''शिक्षा विवेचन'' और ''संस्कृति'' सहित 36 पुस्तकें निकाली। इसके अतिरिक्त इसने त्रैमासिक ''यूनेस्को न्यूजलैटर'' का रूपान्तर अनुवाद भी निकाला।

विभिन्न अध्यायों में वर्णित मदों का (लाख रुपयों में)

वित्तिय आबंटन

क्रम सं०	मद	योजनागत/ योजनेतर	बजट प्राक्कलन 1985-86		बजट प्राक्कलन 1986-87
			मूल	संशोधित	
1	2	3	4	5	6
स्कूल शिक्षा					
1.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	योजनेतर	5420.00	5600.00	6200.00
2.	केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन	योजनेतर	173.50	177.74	184.11
3.	बाल भवन	योजनागत	25.00	71.00	35.00
		योजनेतर	38-00	36-00	39-00
4.	खुला स्कूल	योजनागत	40.00	47.00	60.00
5.	सामुदायिक गान	योजनागत	32.00	25.00	25.00
6.	अनौपचारिक शिक्षा	योजनागत	880.00	1150.40	2015.00
		योजनेतर	16.00	14.40	15.00
7.	गैर-औपचारिक शिक्षा केवल लड़कियों के लिए	योजनागत	2070.00	400.00	715.00
8.	शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों में प्राथमिक स्कूलों में महिला शिक्षार्थियों की नियुक्ति	योजनागत	370.00	450.00	450.00
9.	शिशु शिक्षा	योजनागत	50.00	37.00	50.00
		योजनेतर	25.00	25.00	26.25
10.	शिक्षा में मूल्य निर्धारण	योजनागत	15.00	13.50	15.00
11.	स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठन	योजनागत	30.00	25.00	10 00
12.	जनसंख्या शिक्षा परियोजना	योजनागत	75.00	75.00	75.00
13.	रा०शै०अनु०प्र०परि०	योजनागत	250.00	250.00	200.00
		योजनेतर	1108.00	1093.59	1125.00
14.	स्कूल शिक्षा के क्षेत्र सांस्कृतिक में हित का आदान-प्रदान	योजनेतर	1.00	0.95	1.00
15.	विकलांग बच्चों को समेकित शिक्षा	योजनागत	25.00	25.00	100.00
16.	युद्धों के दौरान मारे गए अथवा विकलांग हुए सशस्त्र सैनिकों और अधिकारियों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें।	योजनेतर	1.85	1.80	1.95
17.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम जिनमें इन्सेट उपयोगिता शामिल है।	योजनागत	825.00	825.00	850.00
18.	शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार	योजनेतर	5.50	5.36	8.25
19.	स्कूलों में संगणक शिक्षा	योजनागत	3.00	58.75	100.00

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इसके अनुरक्षण के लिए कोई अनुदान सहायता नहीं दी जाती।

1	2	3	4	5	6
शारीरिक शिक्षा					
1.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा कालेज, ग्वालियर का विकास	योजनागत	25.00	25.00	61.00
		योजनेत्तर	49.60	50.08	56.63
2.	शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना	योजनागत	18.00	13.00	5.00
3.	योग की प्रोन्नति	योजनागत	7.00	7.00	15.00
		योजनेत्तर	12.00	12.00	13.00
4.	स्कूल स्तर पर शारीरिक शिक्षा और खेल कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना।	योजनागत	--	--	11.00
5.	पब्लिक/आवासीय/केन्द्रीय स्कूलों में एन०सी०सी० जूनियर डिवीजन दल	योजनेत्तर	5.50	6.00	9.15
	उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान			सामान्य	
1.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	योजनागत	7100.00	7400.00	7000.00
				एस०ए०सी० सी०	
				300.00	750.00
		योजनेतर	11267.00	12000.00	12200.00
2.	भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	योजनागत	40.00	28.74	40.00
		योजनेतर	39.20	35.72	38.00
3.	भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद	योजनागत	42.00	42.00	45.00
4.	भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद	योजनागत	40.00	35.00	40.00
		योजनेतर	71.26	69.09	76.33
5.	अखिल भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान	योजनागत	30.00	30.00	30.00
		योजनेतर	14.00	13.30	14.00
6.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद	योजनागत	150.00	150.00	160.00
		योजनेतर	238.30	248.80	252.30
7.	शास्त्री भारत कनाडा संस्थान	योजनेतर	30.00	28.50	28.00
8.	विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन	योजनेतर	100.00	50.00	95.00
9.	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर	योजनेतर	1.50	1.00	1.50
10.	पंजाब विश्वविद्यालय को ऋण	योजनागत	50.00	50.00	25.00
11.	व्यावसायिक संगठनों को सहायता	योजनागत	5.00	5.00	--
12.	डा० जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास	योजनागत	30.00	30.00	20.00
		योजनेतर	4.00	3.88	4.07
13.	भारतीय विश्वविद्यालयों का संगठन	योजनागत	5.00	5.10	8.00
		योजनेतर	10.64	10.00	10.64
14.	जामिया मिलिया इस्लामिया	योजनागत	32.00	32.00	50.00
		योजनेतर	44.00	46.50	48.50
15.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय	योजनागत	75.00	300.00	750.00
तकनीकी शिक्षा					
1.	कोटि सुधार कार्यक्रम	योजनागत	350.00	1250.00	600.00
	(सीधी केन्द्रीय सहायता तथा सामुदायिक पोलिटेक्निक)	योजनेतर	135.00	128.25	135.00
2.	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण स्थापना (स्थापना)	योजनागत	49.00	55.66	70.00
	वत्तिका कार्यक्रम	योजनेत्तर	102.75	26.24	29.69
		योजनागत	51.00	42.00	100.00
		योजनेतर	185.00	246.00	259.00

1	2	3	4	5	6
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	योजनागत	600.00	800.00	800.00
		योजनेतर	4455.84	4479.20	4875.43
4.	उत्तर स्नातक पाठ्यक्रमों का विकास	योजनागत	100.00	92.18	100.00
		योजनेतर	188.10	170.05	183.50
5.	क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज	योजनागत	600.00	600.00	600.00
		योजनेतर	1026.46	990.55	1040.10
6.	भारतीय प्रबंध संस्थान	योजनागत	400.00	540.00	500.00
		योजनेतर	449.69	445.99	469.54
7.	प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद	योजनेतर	--	--	
		योजनागत	2.50	2.37	2.50
8.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनाएं (तकनीकी)	योजनागत	525.00	525.00	550.00
			--	--	--
9.	गैर-विश्वविद्यालय केन्द्र पर प्रबंध शिक्षा का विकास	योजनागत	25.00	25.00	30.00
		योजनेतर	20.00	9.84	15.00
10.	उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम	योजनागत	50.00	60.00	50.00
		योजनेतर	8.00	7.60	8.00
11.	एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगकोक				
		योजनेतर	8.50	8.00	10.00
12.	राष्ट्रीय जनशक्ति सूचना पद्धति	योजनागत	50.00	50.00	50.00
		योजनेथर	20.00	19.00	20.00
13.	केन्द्रीय संस्थान				
(i)	तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान	योजनागत	200.00	205.65	300.00
		योजनेतर	226.00	195.34	218.22
(ii)	रा०प्रौ०शै०प्र०सं०, बम्बई	योजनागत	30.00	40.00	30.00
		योजनेतर	104.30	102.00	107.00
(iii)	रा०ग० और ढ०प्रौ०सं०, रांची	योजनागत	20.00	20.00	30.00
		योजनेतर	54.00	58.80	59.85
(iv)	एस०पी०ए०, नई दिल्ली	योजनागत	150.00	150.00	140.00
		योजनेतर	96.53	86.00	91.00
14.	नई योजनाएं				
(i)	अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र	योजनागत	50.00	50.00	100.00
(ii)	प्रयोगशाला/कार्यशाला का आधुनिकीकरण	योजनागत	500.00	1500.00	1650.00
(iii)	विकसित तकनीकी	योजनागत	550.00	550.00	700.00
		योजनेतर	600.00	400.00	600.00
(iv)	कमजोर क्षेत्र	योजनागत	550.00	750.00	700.00
(v)	सांस्थनिक नेट कार्य	योजनागत	100.00	100.00	100.00
		योजनेतर	10.00	9.50	10.00
(vi)	उपयुक्त तकनीकी और ग्रामीण विकास के लिए विशेष संस्थाएं	योजनागत	50.00	60.00	150.00
(vii)	समग्र ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान तथा तकनीकी उपयोग हेतु प्रायोगिक मार्गदर्शी परियोजनाएं	योजनागत	50.00	60.00	200.00

1	2	3	4	5	6
	प्रौढ़ शिक्षा				
1.	उत्तर साक्षरता तथा अनुवर्ती कार्यक्रम . . .	योजनागत	150.00	150.00	250.0
2.	राज्य तथा जिला स्तर पर प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करना । . . .	योजनागत	200.00	199.95	240.0
3.	ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाएं . . .	योजनागत	3070.00	3070.00	3070.0
		योजनेतर	130.00	118.50	130.0
4.	राज्य संसाधन केन्द्रों तथा मूल्यांकन सहित प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता	योजनागत	300.00	700.00	800.0
5.	श्रमिक विद्यापीठ	योजनागत	50.00	65.00	90.0
		योजनेतर	41.20	46.51	54.7
6.	साक्षरता गृह, लखनऊ	योजनेतर	10.71	10.41	10.7
7.	महिलाओं तथा लड़कियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की यूनिसेफ प्रायोजित परियोजना	योजनागत	8.00	8.00	12.00
8.	मुद्रण मुद्रणालय सहित प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	योजनागत	22.00	30.50	28.00
		योजनेतर	26.79	25.90	27.53
9.	कार्यात्मक साक्षरता के लिए जन आंदोलन . .	योजनागत	1000.00	240.00	1800.00
	छात्रवृत्तियां				
1.	राष्ट्रीय छात्रवृत्तियां योजना	योजनागत	275.00	275.00	350.00
2.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना . . .	योजनेतर	350.00	300.00	300.00
3.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना बट्टे खाते आदि	योजनेतर	8.00	8.00	10.00
4.	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वसूलियों में राज्य सरकारों का 50% हिस्सा . . .	योजनेतर	16.00	16.00	22.00
5.	ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों को माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्तियां	योजनागत	125.00	110.00	130.00
6.	संस्कृत को छोड़कर अन्य प्राचीन भाषाओं अर्थात् अरबी और फारसी के अध्ययन में लगी परम्परागत संस्थाओं से उत्तीर्ण छात्रों को अनुसंधान छात्रवृत्तियां	योजनागत	1.25	1.25	1.25
7.	विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियां	योजनेतर	80.00	76.00	80.00
8.	अनुमोदित आवासीय माध्यमिक स्कूलों में छात्रवृत्तियां	योजनेतर	125.00	125.00	140.00
9.	हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियों की सहायता योजना	योजनेतर	28.00	28.00	28.00
10.	सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति योजना . . .	योजनेतर	60.00	54.00	59.85
11.	विदेश मंत्रालय की निधि से बंगलादेश के राष्ट्रकों के लिए छात्रवृत्तियां	योजनेतर	25.00	25.00	25.00
12.	विदेश जाने वाले भारतीय अध्येताओं को अन्य छात्रवृत्तियां	योजनेतर	8.00	7.60	7.98
13.	विदेश जाने वाले अध्येताओं को आंशिक वित्तीय सहायता	योजनेतर	0.42	0.35	0.42
14.	भारत में अध्ययन के लिए विदेशी छात्रों को छात्रवृत्तियां	योजनेतर	24.00	27.00	29.00

1 2	3	4	5	6
पुस्तक प्रोन्नति तथा कापीराइट				
1. राष्ट्रीय पुस्तक न्यास				
(क) क्षेत्रीय कार्यालय तथा पुस्तक केन्द्र . . .	योजनागत	10.00	10.00	9.00
(ख) अनुरक्षण तथा स्थापना	योजनेतर	48.71	48.34	50.75
(ग) सामान्य प्रोन्नति/कार्यकलाप . . .	योजनेतर	35.00	33.25	34.91
2. आदान प्रदान	योजनागत	4.00	4.00	3.00
3. नेहरू भवन	योजनागत	10.00	10.00	15.00
4. नेहरू बाल पुस्तकालय	योजनागत	18.00	18.00	15.00
5. भारतीय विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के लिए आर्थिक सहायता की योजना . . .	योजनागत	30.00	37.00	35.00
6. विश्व पुस्तक मेला	योजनेतर	25.00	24.20	--
7. राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद् तथा पुस्तक प्रोन्नति कार्यकलाप	योजनागत	15.00	7.50	10.00
8. निर्यात प्रोन्नति कार्यकलाप . . .	योजनागत	8.50	7.50	8.50
9. डब्लू०आई०पी०ओ० तथा अंतर्राष्ट्रीय कापीराइट यूनिट को अंशदान . .	योजनेतर	7.05	6.44	8.30
10. विदेशी लेखकों द्वारा विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के सस्ते प्रकाशन	योजनागत	1.50	1.50	2.00
11. राजाराम मोहन राय राष्ट्रीय शैक्षिक स्रोत केन्द्र	योजनागत	2.00	2.00	1.50
12. संगीत कार्यों के लेखकों तथा संगीतकारों की राष्ट्रीय सोसायटी	योजनागत	1.00	0.10	1.00
भाषाओं का विकास				
क--सतत योजनाएं				
1. हिन्दी के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	योजनागत	12.00	12.00	20.00
	योजनेतर	47.00	44.65	47.00
2. विदेशों में हिन्दी का प्रचार	योजनागत	12.00	12.00	12.00
	योजनेतर	8.50	8.00	8.50
3. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	योजनागत	22.10	36.10	40.00
	योजनेतर	54.70	53.47	56.08
4. हिन्दी शिक्षण मंडल, आगरा को अनुदान	योजनागत	54.00	54.00	65.00
	योजनेतर	95.35	92.40	96.97
5. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग	योजनागत	10.00	10.00	12.00
	योजनेतर	25.72	24.85	26.10
6. आधुनिक भारतीय भाषाएं				
(क) क्षेत्रीय भाषाओं (प्रकाशनों) की प्रोन्नति तथा विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	योजनागत	34.00	26.00	35.00
(ख) अनुश्रवण	योजनागत	3.00	2.00	5.00
7. सिन्धी पुस्तकों का प्रकाशन	योजनागत	9.00	9.00	5.00
8. उर्दू की प्रोन्नति के लिए तरक्की . . .	योजनागत	26.00	26.00	36.50
ए-उर्दू बोर्ड ब्यूरो	योजनेतर	30.50	27.62	29.00

1	2	3	4	5	6
9.	केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर	योजनागत	66.66	32.60	45.00
		योजनेतर	55.40	53.00	55.55
10.	क्षेत्रीय भाषा केन्द्र	योजनागत	18.00	15.00	21.00
		योजनेतर	78.15	72.77	76.34
11.	गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति	योजनागत	20.00	20.00	70.00
12.	गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों की स्थापना	योजनागत	10.00	55.00	70.00
13.	भारतीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पुस्तकों के प्रकाशन				
	(i) राज्यों को अनुदान	योजनागत	---	--	10.00
		योजनेतर	--	20.00	20.00
	(ii) विश्वविद्यालयों को अनुदान	योजनागत	2.00	1.00	1.00
14.	औषध संबंधी कोर पुस्तकों के प्रकाशन तथा अनुवाद हेतु रा०पु० न्यास को अनुदान	योजनागत	--	7.50	5.00
		योजनेतर	30.00	8.50	10.00
15.	क्षे०अ०सं० तथा ई०एल०टी०आई० एम० को वित्तीय सहायता	योजनागत	85.00	60.00	103.50
	ख. नई योजनाएं				
16.	आधुनिक भारतीय भाषाएं शिक्षकों की नियुक्ति	योजनागत	--	--	1.00
17.	सिन्धी विकास बोर्ड की स्थापना	योजनागत	--	--	18.00
18.	प्रणाली विज्ञान शिक्षण में अनुसंधान	योजनागत	2.00	0.20	--
19.	स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों को वित्तीय सहायता	योजनागत	40.00	40.00	40.00
20.	आदर्श संस्कृत महाविद्यालय/शोध संस्था योजनाएं	योजनागत	1.00	1.00	1.00
		योजनेतर	37.00	35.15	37.01
21.	राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान	योजनागत	60.00	60.00	80.01
		योजनेतर	159.73	162.92	171.6
22.	छात्रों/संस्कृत पाठशालाओं से पढ़कर निकलने वाले छात्रों/उत्तर मैट्रिक संस्कृत छात्रों/शास्त्री तथा आचार्य छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना	योजनेतर	9.50	9.02	9.5
23.	दक्कन कालेज की संस्कृत शब्दकोश परियोजना	योजनेतर	9.00	8.73	9.00
24.	संस्कृत को छोड़कर अन्य प्राच्य भाषाओं, अर्थात् अरबी और फारसी के प्रचार और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता	योजनागत	12.00	12.00	12.0
25.	शास्त्र चूड़ामणि योजना	योजनागत	5.00	5.00	12.0
26.	संस्कृत/अरबी/फारसी विद्वानों को सम्मान प्रमाणपत्र प्रदान करना	योजनेतर	7.50	7.50	7.5
27.	अभावग्रस्त संस्कृत विद्वानों को वित्तीय सहायता	योजनागत	40.00	40.00	40.0
28	संस्कृत साहित्य का प्रकाशन	योजनागत	15.00	27.00	25.0
29.	वैदिक अध्ययनों की मौखिक परम्परा का परिरक्षण	योजनागत (i)	18.50	(i) 6.50	4.0
30.	संस्कृत पाठशालाओं से पढ़कर निकलने वालों को व्यावसायिक प्रशिक्षण	योजनागत	2.00	2.00	3.0

1	2	3	4	5	6
	यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग				
1.	भारत में यूनेस्को प्रकाशनों के परिपूर्ण प्रलेखन और संदर्भ केन्द्र के रूप में आई० एन० सी० लायब्रेरी का पुनर्गठन	योजनागत	0.50	1.00	1,00
2.	यूनेस्को के उद्देश्य तथा लक्ष्यों के प्रोत्साहन में प्रदर्शनियों की समितियों, सम्मेलनों और संगठनों की बैठकें सुदृढ़ करना		3.00	2.50	5.00
3.	यूनेस्को के कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सुदृढ़ करना		1.50	1.50	1.50
4.	यूनेस्को कुरियर के हिन्दी और तमिल संस्करणों के प्रकाशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग का खर्च	योजनेतर	9.00	9:00	10·55
5.	यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग .		0.60	0.60	0.60
	. यूनेस्को के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यक्रम के लिए गैर सरकारी संगठनों को अनुदान . . .		0.25	0.25	0.25
क.	अन्य कार्यक्रम–यूनेस्को से संबंधित मेजबानी एवं मनोरंजन योजनाएं		0.05	0.05	0.05
8.	यूनेस्को को अंशदान	योजनेतर	88.30	88.30	88.30
9.	विदेशों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधि मंडल . .		5.00	8.50	7.00
10.	ओरोविल प्रबंध	योजना	--	--	10.50
		योजनेतर	4.62	4.30	4.62
11.	विदेशी पदाधिकारियों का दौरा	योजनेतर	--	--	8.00
	अन्य कार्यकलाप				
1.	प्रकाशन	योजनेतर	10.50	9.97	10.50
2.	प्रगति मैदान में शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विषयों का मंडप .	योजनेतर	10.00	1.00	25.00
3.	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना, तथा प्रशासन संस्थान	योजनागत	25.20	25.20	25.20
		योजनेतर	62.90	63.27	66.43
4.	शैक्षिक नीतियों, आयोजना प्रबन्ध तथा मूल्यांकन अध्ययनों के लिए सहायता की योजना	योजनागत	4.00	4.00	4.00
5.	शास्त्री भवन में लघु संगमक टर्मीनल का लगाया जाना .	योजनागत	3.00	3.00	4.00

वर्ष 1984–85 के दौरान एक लाख रुपए से अधिक आवर्ती सहायता

वर्ष 1984-85 के दौरान एक लाख रुपए से अधिक आवर्ती सहायता अनुदान पाने वाले निजी और स्वैच्छिक संगठनों के नाम दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	निजी और स्वैच्छिक संगठनों का नाम और पता	संगठनों के संक्षिप्त कार्यकलाप	वर्ष 1984-85 के दौरान जारी की गई आवर्ती सहायता अनुदान की राशि (लाख रुपए)	प्रयोजन जिसके लिए अनुदान का उपयोग किया गया	कैफियत
1	2	3	4	5	6
स्कूल शिक्षा तथा शारीरिक शिक्षा					
1.	कैवल्यधाम श्रीमन माधव योग मंदिर, समिति लोनावाला, पुणे (महाराष्ट्र)	योग में अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना ।	7.95 लाख रु०	योग में अनुसंधान और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में समिति का अनुरक्षण खर्च	--
2.	वनस्थली विद्यापीठ, पो० वनस्थली विद्यापीठ (राजस्थान)	विद्यापीठ को एक विश्व-विद्यालय समझा जाने वाला स्तर प्राप्त हो गया है । विद्यापीठ का उद्देश्य ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान प्रदान करना और प्रोन्नत करना तथा भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन की पद्धति के आवश्यक मूल्यों और आदर्शों को छात्रों में उत्पन्न करना है ।	3 लाख रुपए	आवर्ती कमी को पूरा करना	--
3.	जन प्रबोधनी, 510, संदाशिव पेठ, पुणे (महाराष्ट्र)	यह संस्थान, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक चहुंमुखी विकास और छात्रों की इस प्रकार की अन्य योग्यताओं के प्रमुख उद्देश्य को लेकर मेधावी छात्रों की शिक्षा के लिए वर्ष 1962 में शुरू किया गया था । यह संस्थान छात्रों के एक हाई स्कूल, छात्राओं के लिए हाई स्कूल चला रहा है और इसने 1980 में एक जूनियर कालेज भी शुरू किया है ।	4.50 लाख रुपए	स्कूल भवन के निर्माण हेतु किए गए व्यय को पूरा करना	--
4.	रामकृष्ण नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा संस्थान, मैसूर (कर्नाटक)	यह कर्नाटक राज्य के सेवारत हाई स्कूल शिक्षकों के लिए नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा में नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा अल्पकालिक पाठ्यक्रम पर जोर देते हुए बी० एड० डिग्री पाठयक्रम प्रदान करता है । अखिल भारतीय कालेज छात्रों तथा आम जनता के लिए रिट्रिट (निवर्तन)	3.70 लाख रु०	नैतिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा में संस्थान को चलाने और रखरखाव के लिए तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु	--
5.	श्री सत्य साई बाल विकास शिक्षा न्यास, बम्बई (महाराष्ट्र)	यह सरकार अथवा प्राइवेट स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु मानव मूल्योन्मुख शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करती है ।	3,73,987 रु०	--वही--	
6.	बनगवनी नवद्वीप (पश्चिम बंगाल)	नैतिक शिक्षा हेतु शिक्षकों के अध्यापन के लिए समाज शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना । नैतिक शिक्षा प्रदान करने हेतु सेवा का विस्तार ।	1,00,000 रुपए	--वही--	

1	2	3	4	5	6
			रुपये		
7	रैयलस एमा सेवा समिति तिरूपति, (आंध्र प्रदेश)	यह एक गैर–साम्प्रदायिक संगठन है। यह सभी जातियों और अपने–अपने क्षेत्र के धर्मविलम्बियों के लिए खुला है और शैक्षिक तथा कल्याण कार्यकलापों के विकास में लगा हुआ है।	2,11,175	210 गैर–औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के चलाने हेतु।	--
8.	साक्षरता सदन, आंध्र महिला सभा, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	पूर्व प्राथमिक स्तर से कालेज स्तरीय, शिक्षक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता तक लड़कियों की शिक्षा के विकास हेतु।	1,03,950	100 गैर–औपचारिक शिक्षा केन्द्रों को चलाने हेतु।	--
9.	जिला प्रौढ़, शिक्षण समिति, कोटा (राजस्थान)	उन बच्चों के लिए, जो कभी स्कूल नहीं गए और जिन्होंने बीच में स्कूल छोड़ दिया, उन्हें शिक्षा प्रदान करने हेतु।	1,38,050	100 गैर–औपचारिक शिक्षा केन्द्रों के चलाने हेतु।	--
10.	रेयलसीमा सेवा समिति तिरूपति (आंध्रप्रदेश)	सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए बच्चों, महिलाओं, प्रौढ़ों के लिए सेवाएं प्रदान करने हेतु ग्रामीण निर्माण कार्यकलापों और कल्याण योजनाओं के विशेष उद्देश्य को लेकर रैवलसीमा सेवा समिति वर्ष 1981 में शुरू की गई थी।	6,85,500	100 ई०सी०ई० केन्द्रों को चलाने हेतु।	--
11.	जिला बाल कल्याण परिषद्, मिदनापुर पो० नन्दकुमार, मिदनापुर जिला पश्चिम बंगाल)	वास्तविक रूप में उपयुक्त मानवता की दृष्टि से बच्चों में प्राकृतिक मूल प्रवृत्तियों और आत्मविश्वास तथा देशभक्ति की भावना आत्मसात करने, समाज में आत्म-सम्मान, नैतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक मूल्य उत्पन्न करने हेतु स्थापना की गई।	2,70,225	100 ई०सी०ई० केन्द्रों के चलाने हेतु।	--
12.	भारत साक्षरता बोर्ड, साक्षरता सदन, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	कमजोर समाज की प्रथम पीढ़ी अध्ययन परिवारों को प्रेरित करने के लिए शारीरिक, मानसिक समाज मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में बच्चों के चहुंमुखी विकास हेतु।	1,20,000	40 ई०सी०ई० केन्द्रों के चलाने हेतु।	--
तकनीकी शिक्षा					
1.	प्रिंसिपल, वस्त्र तकनीकी संस्थान, भिवानी (हरियाणा)	इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्य का आयोजन।	3,48,381	इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्य का आयोजन	
2.	प्रिंसिपल, थापर इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, पटियाला (पंजाब)	--वही--	1,70,000	--वही--	
3.	निदेशक, हरकोर्ट, बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर (उ० प्र०)	इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तथा अनुसंधान कार्य का आयोजन।	5,80,000	--वही--	
4.	प्रिंसिपल, विक्टोरिया जुबली तकनीकी संस्थान, बम्बई (महाराष्ट्र)	--वही--	12,90,298	--वही--	
5.	प्रिंसिपल, जी०एस० प्रौद्योगिकी संस्थान, इन्दौर (मध्य प्रदेश)	--वही--	9,47,664	--वही--	
6.	प्रिंसिपल, एल० एम० फार्मेसी कालेज, अहमदाबाद (गुजरात)	--वही--	3,80,000	--वही--	

1	2	3	4	5	6
			रुपये		
7.	प्रिंसिपल, बाल चन्द इंजीनियरी कालेज, सांगली (महाराष्ट्र)	--वही--	5,50,000	--वही--	
8.	प्रिंसिपल, पी०एस०जी० प्रौद्योगिकी कालेज, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	--वही--	14,10,000	--वही--	
9.	प्रिंसिपल, कोयम्बटूर प्रौद्योगिकी संस्थान, कोयम्बटूर (तमिलनाडु)	--वही--	6,80,000	--वही--	
10.	प्रिंसिपल, त्यागराजा इंजीनियरी कालेज, मदुरै (तमिलनाडु)	--वही--	1,50,000	--वही--	
11.	प्रिंसिपल, राष्ट्रीय इंजीनियरी संस्थान, मैसूर (कर्नाटक)	--वही--	2,66,440	--वही--	
12.	प्रिंसिपल, बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, रांची (बिहार)	--वही--	13,47,973	--वही--	
13.	प्रिंसिपल, आयोजना स्कूल, अहमदाबाद (गुजरात)	--वही--	8,97,926	--वही--	
14	प्रिंसिपल, फार्मेसी कालेज, पुष्प विहार, नई दिल्ली	--वही--	1,30,000	--वही--	
15.	प्रिंसिपल, जे०सी०आर० इंजीनियरी कालेज, मैसूर	--वही--	4,15,000	--वही--	
16.	प्रिंसिपल, गुरुनानक इंजीनियरी कालेज, लुधियाना (पंजाब)	--वही--	1,00,000	--वही--	
17.	बी०एम०एस० इंजीनियरी कालेज, बंगलौर	--वही--	1,65,000	--वही--	
18.	प्रिंसिपल, बम्बई फार्मेसी कालेज, कलिना, बम्बई	--वही--	1,00,000	--वही--	
19.	प्रिंसिपल, टी०के०एम० इंजीनियरी कालेज, क्यूलोन ।	--वही--	1,00,000	--वही--	
20.	गुरु नानक पोलिटेक्निक, लुधियाना ।	--वही--	1,00,000	ग्रामीण प्रौद्योगिकी का विकास	
21.	इंजीनियरी तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद	(i) --वही-- सामुदायिक विकास कार्य	1,00,000	(i) --वही-- (ii) सामुदायिक विकास कार्य	
		(ii) उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम	2,00,000	(iii) उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम	
		(iii) कोटि सुधार कार्यक्रम	4,50,000	(iv) कोटि सुधार कार्यक्रम ।	
22.	एस०बी०एम० पोलिटेक्निक, बम्बई	उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम	3,19,000	उच्च तकनीशियन पाठ्यक्रम	
23.	सी०एम० कोठारी प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	--वही--	2,00,000	--वही--	
24.	वाई०एम०सी०ए० इंजीनियरी संस्थान, फरीदाबाद	--वही--	2,50,00	--वही--	

1	2	3	4	5	6
25.	थापर पोलिटेक्निक, पटियाला ।	सामुदायिक विकास कार्य	1,75,000	सामुदायिक विकास कार्य	
26.	डा० पंजाबराय देशमुख पोलिटेक्निक, अमरावती	--वही--	1,10,000	--वही--	
27.	रामगृह पोलिटेक्निक, फगवाड़ा	--वही--	1,25,000	--वही--	
28.	फिरोज गांधी पोलिटेक्निक, रायबरेली	--वही--	1,25,000	--वही--	
29.	पोलिटेक्निक, खुरई ।	(i) सामुदायिक विकास कार्य		(i) सामुदायिक विकास कार्य	
		(ii) ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास	1,21,000	(ii) ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास	
30.	अन्नामलाई पोलिटेक्निक, चित्तेनेड	सामुदायिक विकास कार्य	1,00,000	सामुदायिक विकास कार्य	
31.	भक्तवत्सलम पोलिटेक्निक, कांचीपुरम	--वही--	1,00,000	सामुदायिक विकास कार्य	
32.	पं० जे० एन० पोलिटेक्निक, सतवाद (म०प्र०)	--वही--	1,00,000	सामुदायिक विकास कार्य	
33.	एक्स एल आर आई, जमशेदपुर ।	गैर-विश्वविद्यालय केन्द्र में प्रबंध शिक्षा का समेकन और विकास ।	5,14,492	(i) वेतन (ii) पुस्तकालय	
34.	भारतीय समाज कल्याण और व्यापार प्रबंध संस्थान, कलकत्ता	--वही-- तदनन्तर संस्थान का राज्य सरकार ने उत्तरदायित्व ले लिया है ।	4,99,200	--वही--	
	भाषाओं की प्रोन्नति				
1.	राजा वेद काव्य पाठशाला, डी-76, III क्रास स्ट्रीट, श्रीनगर कालोनी, कुम्बोकनम-612001 (तमिलनाडु)	शिक्षण	1,51,585	वेतन तथा छात्रवृत्तियां, पुस्तकालय के कमरे की मरम्मत तथा फर्नीचर का खरीदना ।	
2.	संस्कृति और प्राचीन कलाओं की संकारा अकादमी	--वही--	2,69,610	वेतन तथा छात्रवृत्तियां	
3.	जे०एन०बी० आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, पो० लागमा, जिला दरभंगा (बिहार)	शिक्षण	2,91,338	वेतन, छात्रवृत्तियां तथा फुटकर खर्च ।	
4.	लक्ष्मी देवी शराफ़ आदर्श संस्कृत एम०बी० काली रेखा, ग्राम व पो० देवगढ़ (बिहार)	--वही--	2,08,200	--वही--	
5.	हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ, भागोला (हरियाणा)	--वही--	2,34,625	--वही--	
6.	दीवान कृष्ण किशोर, एस०डी० संस्कृत कालेज, अम्बाला छावनी (हरियाणा) ..	--वही--	2,15,995	--वही--	
7.	मुम्बादेवी संस्कृत महाविद्यालय, बम्बई (महाराष्ट्र)	--वही--	2,11,893	--वही--	
8.	वेदिका संशोधन मंडल पुणें (महाराष्ट्र)	शोध	2,41,000	--वही--	
9.	कालिकट आदर्श संस्कृत विद्यापीठ, पो० बालुस्सरी, जिला-कालिकट (केरल)	शिक्षण	2,88,082	वेतन तथा छात्र-वृत्तियां	
10.	मद्रास संस्कृत कालेज, मद्रास (तमिलनाडु)	--वही--	2,52,193	वेतन, छात्रवृत्तियां तथा फुटकर खर्च	
11.	श्री चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती न्यायशास्त्र एम० बी० कांचीपुरम (तमिलनाडु)	--वही--	1,52,235	वेतन, छात्रवृत्तियां तथा मिश्रित खर्च	
12.	कुप्पास्वामी शास्त्री शोध संस्थान, मैले पोर, मद्रास (तमिलनाडु)	शोध	1,20,000	वेतन, छात्रवृत्तियां तथा फुटकर खर्च	
13.	श्री भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)	शिक्षण	2,50,000	वेतन, छात्रवृत्तियां तथा मिश्रित खर्च ।	
14.	श्री एकरसानन्द संस्कृत महाविद्यालय, मणिपुर (उ० प्र०)	--वही--	2,58,242	--वही--	

1	2	3	4	5	6
15.	रंग लक्ष्मी आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, वृन्दावन, मथुरा (उ० प्र०)	--वही--	2,77,939	--वही--	
16.	मुख्य कार्यकारी, भारतीय चातुर्दम वेद भवन न्यास, स्वदेश हाउस, सिविल लाइन्स, कानपुर ।	--वही--	1,19,700	--वही--	
17.	सचिव, बुद्ध दर्शन संस्कृत विद्यालय, कैलोंग, पो० कैलोंग, जिला-लाहुल स्पीति (हि० प्र०)	--वही--	1,21,548	वेतन, छात्रवृत्तियां तथा मिश्रित खर्च	
18.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद शाखा, हैदराबाद ।	हिन्दी की प्रोन्नति।	3,32,550	हिन्दी अध्यापन केन्द्रों तथा टाइपिंग कक्षाओं का चलाना ।	राष्ट्रीय महत्व संगठन के रूप में मान्यता
19.	डी०बी०एच०पी० सभा, तमिलनाड़ शाखा मद्रास	--वही--	2,96,685	--वही--	--वही--
20.	डी०बी०एच०पी० सभा, केरल शाखा, इर्नाकुलेम	--वही--	99,135	--वही--	--वही--
21.	डी०बी०एच०पी० सभा, (कर्नाटक शाखा) बंगलौर	--वही--	1,61,790	--वही--	--वही--
22.	डी० बी० एच० पी० सभा, मद्रास सिटी मद्रास	हिन्दी की प्रोन्नति	रूपये 11,21,094	अनुदान, रखरखाव, उच्च शिक्षा स्तर आदि में हिन्दी कक्षाओं का चलाना ।	राष्ट्रीय महत्व संगठन के रूप में मान्यता
23.	नागरी हिन्दी प्रचारणी सभा, बाराणसी	--वही--	2,00,000	प्रकाशन कार्य तथा भवन अनुदान	अखिल भारतीय स्तरीय संगठन
24.	भुवन बेन ट्रस्ट, लखनऊ	--वही--	1,50,000	प्रकाशन कार्य	--
25	असम राष्ट्र भाषा प्रचार बोर्ड, गुहाटी	--वही--	2,00,000	हिन्दी कक्षाओं तथा टाइपराइटिंग कक्षाओं का चलाया जाना	--
26.	दैरातुल मासिफिल उस्मानिया (उस्मानिया) विश्वविद्यालय, हैदराबाद ।	उर्दू की प्रोन्नति तथा विकास	1,57,500	संगठन के अनुरक्षणी की कमी का 50%	—
27.	केरल हिन्दी प्रचार सभा, त्रिवेंद्रम	हिन्दी की प्रोन्नति	1,00,950	हिन्दी अध्यापन कक्षाओं का चलाया जाना ।	--
28.	अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली	हिन्दी प्रचार कार्यक्रम का कार्यान्वयन 117 स्वैच्छिक संगठनों का एक संगठन के रूप में कार्य करना	2,05,000	संगठन का रखरखाव और हिन्दी प्रचार कार्यक्रम का कार्यान्वयन	अखिल भारतीय महत्व के 17 स्वैच्छिक संगठनों का एक परिसंघ
29.	केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली	हिन्दी प्रचार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	1,70,000	हिन्दी प्रचार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन/पुस्तकों का प्रकाशन ।	--
30.	हिन्दी विद्यापीठ, देवघर (बिहार)	--वही--	1,27,200	हिन्दी प्रचार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन/हिन्दी संथाली और संथाली हिन्दी का आयोजन तथा प्रकाशन/शब्द कोश	
31.	कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति, बंगलौर (कर्नाटक)	--वही--	1,23,750	हिन्दी प्रचार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन	--
32.	कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति, बंगलौर (कर्नाटक)	--वही--	1,10,775	--वही--	—
33.	मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद्, बंगलौर (कर्नाटक)	--वही--	1,21,800	हिन्दी प्रचार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन	--
34.	बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, बम्बई	--वही--	1,07,775	महाराष्ट्र में --वही--	--
			15,0000	गोआ में --वही--	--
			1,22,775		

1	2	3	4	5	6
प्रौढ़ शिक्षा					
1.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात	समाज शास्त्र के क्षेत्र में शोध आयोजन	1.60	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु गहन अध्ययन में सर्वेक्षण मूल्य निर्धारण करने के लिए ।	--
2.	टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई, महाराष्ट्र	--वही--	1.03	--वही--	--
3.	सरदार पटेल आर्थिक तथा सामाजिक शोध संस्थान, अहमदाबाद, गुजरात	--वही--	1.00	--वही--	--
4.	राज्य संसाधन केन्द्र (बिहार) "दीपा भवन"	सभी स्तरों पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए	4·12	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को शिक्षण अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए	--
5.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	--वही--	5.55	--वही--	--
6.	राज्य संसाधन केन्द्र, मैसूर	--वही--	4.00	--वही--	--
7.	राज्य संसाधन केन्द्र, केरल (के० ए० एन० एफ० ई० डी०)	--वही--	6.39	--वही--	--
8.	उत्कल नवजीवन मंडल, उड़ीसा (अंगुल)	--वही--	3.12	--वही--	--
9.	भारतीय शिक्षा संस्थान, पुणे	--वही--	6.39	--वही--	--
10.	राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा परिषद् (राजस्थान)	--वही--	5.00	--वही--	--
11.	तमिलनाडु सतत शिक्षा बोर्ड, मद्रास	--वही--	6.10	--वही--	--
12.	साक्षरता हाउस, लखनऊ	--वही--	7.50	--वही--	--
13.	बंगाल समाज सेवा लीग, कलकत्ता	--वही--	5·00	--वही--	--
14.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	--वही--	5.00	--वही--	--
15.	ग्रामीण महिला संघ इन्दौर (म० प्र०)	--वही--	1.00	--वही--	
16.	आंध्र महिला सभा साक्षरता हाउस, आंध्र महिला सभा कालेज कैम्पस, विश्वविद्यालय बोर्ड हैदराबाद ।	यह नर्सिंग होम्स, अस्पताल, स्कूल और कालेज तथा महिलाओं के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती है ।	26,96,610	प्रौढ़ निरक्षरों के लिए कार्यात्मक तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना ।	इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला अनुदान अधिकतर आवर्ती स्वरूप होता है और आवर्ती अनुदान का अंश बहुत कम होता है जो परियोजना अवधि के पहले वर्ष में दिया जाता है ।
17.	विस्तृत ग्रामीण परिचालन सेवा सोसायटी सी० आर० ओ० एस० एस०), प्लाट नं० 47 (1-69), स्नेहपुरी, नाचरम, हैदराबाद-501507	मुख्य कार्यकलापों में सिंचाई के लिए पानी के स्रोतों का विकास, डेरा विकास ग्रामीण चिकित्सा सेवा, कृषि विस्तार सेवा शामिल है ।	4,08,100	--वही--	--वही--
18.	ग्रामीण शिक्षा सोसायटी, कोठपेर पुगनुर-517247 जिला-चित्तूर ।	इसके कार्यकलापों में अन्य शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त ग्रामीण गरीब लोगों के हितार्थ चमड़ा बनाने, ईंटे बनाने, चटाई बुनने जैसे आर्थिक विकास कार्यक्रम शामिल हैं ।	1,35,000	--वही--	--वही--

1	2	3	4	5	6
19.	**मोरी गांव महिला मंडल, ग्राम-मोरी, मुस्लिम गांव, पो० मोरीगांव जिला-नौगांव (असम)**	यह गरीब महिलाओं के लिए हथकर्घा, मुर्गीपालन और सिलाई के कार्यों में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है और महिलाओं के लिये प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन करता है।	2,00,200	प्रौढ़ शिक्षा निरक्षरों के लिए कार्यान्मिक तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना।	इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला अनुदान अधिकतर आवर्ती स्वरुप होता है और आवर्ती अनुदान का अंश बहुत कम होता है जो परियोजना अवधि के पहले वर्ष में दिया जाता है।
20.	**के० आर० शैक्षिक संस्था, बत्तिहा, जि० पश्चिमी चम्पारन (बिहार)**	इसके मुख्य कार्यकलाप ग्रामीण विकास तथा शिक्षा है जिनमें एक माडल फार्म डेयरी, सूअर-बाड़ा, हाई स्कूल और प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र का संचालन शामिल है।	3,96,900	--वही--	--वही--
21.	**अखिल नवसर्जन ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान मोरबी महिला परियोजना सवांद बंगला, मेहन्द्र रोड़, राजकोट (गुजरात)**	ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इसके मुख्य कार्यकलाप, पशुपालन, लघु तथा कुटीर उद्योग, स्वास्थ्य तथा औषध और शिक्षा है।			
22.	**आदिया केलवाणी उत्तेजक मंडल, अदिया, ता० हरिज जि० मेहसाना (गुजरात)**	यह एक स्कूल चलाता है और रात्रि कक्षाएं, हिन्दी कक्षाओं आदि का भी संचालन करता है।	1,66,000	--वही--	--वही--
23.	**आदिबासी सेवा समिति, एट एण्ड पो० ओ० सुकशर तालुक-सन्तरामपुर जिला-पंचमहल (गुजरात)**	यह एक हाई स्कूल, आश्रम स्कूल, बाल तथा गर्ल्स छात्रावास, बाल विकास तथा सामाजिक कल्याण केन्द्रों का संचालन करता है।	1,96,329	--वही--	--वही--
24.	**कल्याणी ट्रस्ट, मोडस, जिला-साबरकंठा (गुजरात)**	इसके मुख्य कार्यकलापों में खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग तथा प्रौढ़ शिक्षा शामिल है।	2,48,680	--वही--	-वही--
25.	**कापडवंज तालुक युवक मंडल संस्था, छिपडी, तालुक कापड़वंज जिला खेडा (गुजरात)**	यह पुस्तकालय सुविधायें प्रदान करता है, साक्षरता कार्यक्रम संचालित करता है और सांस्कृतिक तथा खेल कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है।	1,35,000	--वही--	--वही-
26.	**संस्कार भारतीय, अमरपुर, वाया-तालोद जिला साबरकंठा (गुजरात)**	यह स्कूलों, छात्रावासों, बालमंदिरों और स्वास्थ्य केन्द्रों का संचालन करता है।	1,20,000	--वही--	--वही--
27.	**श्री जामनगर जिला समाज कल्याण संघ, पंडित नेहरू मार्ग, जामनगर (गुजरात**	इसने अनेक परियोजनायें चलाई हुई हैं, इन कार्यकलापों में महिला मंडलों, किशोरी मंडलों, बाल मंदिरों, बचत तथा सिलाई कक्षाएं बच्चों को पोषण आहार प्रदान करना भी शामिल है।	1,64,400	--वही--	--वही--
28.	**श्री सिद्धार्थ अमजीवी विकास ट्रस्ट, मोती सरा, अघरा द्रङा, पाटन, जिला-मेहसाना (गुजरात)**	यह टी० आर० वाई० एस० ई० एम० के अन्तर्गत बालवाडी तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का भी संचालन करता है।	1,21,000	--वही--	--वही--

1	2	3	4	5	6
29.	वदोदरा तालुक युवक मंडल संस्था वरानम, तालुक वदोदरा, जिला-वदोदरा (गुजरात)	यह महिलाओं के लिए युवा केन्द्रों, रात्रि कक्षाओं, सिलाई कक्षाओं का संचालन और साक्षरता, सांस्कृतिक खेल तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है।	1,39,560	प्रौढ़ निरक्षरों के लिए कार्यात्मक तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना।	इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला अनुदान अधिकतर आवर्ती स्वरूप होता है और आवर्ती अनुदान का अंश बहुत कम होता है जो परियोजना अवधि के पहले वर्ष में दिया जाता है।
30.	वदोदरा जिला समाज कल्याण मंडल, सरदार भवन, वदोदरा (गुजरात)	मुख्य कार्यकलापों में बालवाडियों, महिला मंडलों, शिल्प कलाओं तथा शिशु सदनों के कार्यक्रम शामिल हैं।	2,10,156	--वही--	--वही--
31.	वदोदरा जिला पंचायत वर्ग सेवा मंडल, सरदार भवन, वदोदरा (गुजरात)	यह पिछड़ी जातियों के लिए आश्रम स्कूलों, प्राथमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, बालवाड़ियों, छात्रावासों का संचालन करता है।	1,87,720	--वही--	--वही--
32.	भील सेवा मंडल, दहोद, जिला-पंचमहल, गुजरात	यह प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अतिरिक्त आश्रम स्कूलों, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, बालवाड़ियों आदि का भी संचालन करता है।	1,34,900	--वही--	--वही--
33.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास दीर, जिला कुरुक्षेत्र (हरियाणा)	अखिल भारतीय महिला कल्याण कार्यकलापों के लिए प्रसिद्ध एक सुप्रसिद्ध संगठन जो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन भी करती है।	4,00,000	--वही--	--वही--
34.	जनता कल्याण समिति, रिवाड़ी बस स्टैण्ड के सामने, जिला-महेन्द्रगढ़	यह प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, बालवाड़ियों का संचालन करती है और अभावग्रस्त व्यक्तियों आदि को शिक्षा प्रदान करती है।	5,05,260	--वही--	--वही--
35.	हरियाणा राजकीय अध्यापक भवन न्यास, पवन, पवन अस्पताल, पिपली-132131	यह शिक्षकों के लाभार्थ कार्य कर रही है और चल रहे प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में उनके अनुभव का उपयोग करती है।	1,20,000	--वही--	--वही--
36.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ (कर्नाटक, शाखा बंगलोर) डा० अम्बेदकर रोड, नई दिल्ली	यह ग्रामीण महिलाओं के लिए शिशु सदन, बालवाड़ियां, प्रशिक्षण शिविर और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का भी संचालन करता है।	1,67,000	--वही--	--वही--
37.	आशा कला केन्द्र, 330, डा० खोसला मार्ग, महोव छावनी, जिला इन्दौर, 452441 (मध्य प्रदेश)	यह महिलाओं के लिए सिलाई और शिल्प कक्षाओं, बालवाड़ियों आदि में डिप्लोमा कंडेन्सड पाठ्यक्रम प्रदान करती है।	2,07,500	--वही--	--वही--
38.	विद्या प्रकाश मंडल, द्वारा अमोलक चन्द महा विद्यालय, यौतमाल (महाराष्ट्र)	रोजगार उत्पादन योजनाएं, परिवार नियोजन, ग्राम पंचायत कार्यकलापों में भाग लेना, अस्पृश्यता और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने जैसे कार्य-क्रमों को कार्यान्वित करना तथा साक्षरता और कुटीर उद्योगों का विकास	1,00,805	--वही--	--वही--

1	2	3	4	5	6
39.	जवाहर स्मृति शिक्षण समिति, मार्की शोलापुर (महाराष्ट्र)	यह आदिवासी आश्रमों का संचालन करती है।	1,01,500	प्रौढ़ निरक्षरों के लिए कार्यात्मक तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना।	इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला अनुदान अधिकतर आवर्ती स्वरूप होता है और आवर्ती अनुदान का अंश बहुत कम होता है जो परियोजना अवधि के पहले वर्ष में दिया जाता है।
40.	कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक न्यास, सरवाद पुणे (महाराष्ट्र)	यह पुणे के शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में कार्य करती है और बगैर घर वाले बच्चों तथा गरीबों के लिए घर का भी आयोजन करती है।	1,80,000	--वही--	--वही--
41.	मानवहित शिक्षण प्रसरक मंडल, समाधि वार्ड नं० 2, चन्द्रपुर (महाराष्ट्र)	यह आदिवासियों के लिये शिशु विहार, हाई स्कूल, वाचनात्मक, वाचनालय, बालवाड़ियों, प्रौढ़ शिक्षा तथा पोषण केन्द्रों का संचालन करता है।	1,01,500	--वही--	--वही--
42.	संत कबीर शिक्षण मंडल, घाटी, औरंगाबाद (महाराष्ट्र)	यह मंडल अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के सुधार के लिए अनुसूचित जाति के सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता है।	1,4,900	--वही--	--वही--
43.	समाज कल्याण मंडल, लालगंज, जिला-नागपुर (महाराष्ट्र)	यह एक प्राथमिक स्कूल, संस्कृति कला विकास केन्द्र, अध्ययन गृहों, नवयुवक मार्ग दर्शन केन्द्रों और बालवाड़ियों का संचालन करता है।	1,20,000	--वही--	--वही--
44.	सती माता शिक्षण संस्था, नागपुर--25 (महाराष्ट्र)	यह एक शिशु सदन, बालवाड़ी, बालमंदिर, हाई स्कूल और जूनियर कालेज चला रही है।	1,20,000	--वही--	--वही--
45.	विश्व सेवा संस्था, पी० ओ० जिला संबलपुर पिन-768001 (उड़ीसा)	प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के अलावा यह स्कूलों और कालेजों का भी संचालन करती है।	1,59,500	--वही--	--वही--
46.	वनवासी सेवा समिति, पी०ओ० ब्लाक बलिगुडा-726103, जिला-फुलबनी (उड़ीसा)	यह जनजातीय और गरीबों के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन करती है।	1,00,805	--वही--	--वही--
47.	खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल, फतेहगढ़ पी० ओ० सोरवार, जिला-अजमेर (राजस्थान)	यह खादी ग्रामोद्योग कार्यकलापों के विकास के लिए कार्य कर रही है।	1,35,444	--वही--	--वही--
48.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर--313001 (राजस्थान)	इसके मुख्य कार्यकलापों में औपचारिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।	1,43,000	वही--	--वही--
49.	राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा संस्था, सी-85, रामदास मार्ग, तिलक नगर, जयपुर-302004 राजस्थान)	इसके मुख्य कार्यकलापों में प्रौढ़ शिक्षा कार्यकर्त्ताओं का शिक्षण, कार्यशालाओं, सेमिनारों का आयोजन शिक्षण तथा अध्ययन सामग्री आदि का प्रकाशन। यह एक राज्य संसाधन केन्द्र भी है।	1,00,000	--वही--	--वही--

1	2	3	4	5	6
50.	जिला प्रौढ़ शिक्षा समिति, 597–ए-तलवण्डी, कोटा–324005 (राजस्थान)	टी० आर० वाई० एस० ई० एम० के अंतर्गत इसके कार्यकलापों में महिलाओं के लिए कंडेन्सड पाठयक्रमों का आयोजन प्रौढ़ तथा गैर प्रौढ़ तथा गैर औपचारिक शिक्षा, श्रमिक विद्यापीठ बालवाड़ी और कार्यक्रम शामिल है।	1,19,971	प्रौढ़ शिक्षा निरक्षरों के लिए कार्यात्मक तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना।	इस के योजना अंतर्गत दिये जाने वाला अनुदान अधिकतर आवर्ती स्वरूप होता है और आवर्ती अनुदान का अंश बहुत कम होता है जो परियोजना अवधि के पहले वर्ष में दिया जाता है।
51.	मानव संसाधन तथा सामाजिक परिवर्तन केन्द्र, 39/15, अप्पास्वामी कोइल स्ट्रीट, मद्रास–600019 (तमिलनाडु)	यह परामर्शी तथा सलाहकार सेवाएं विकास कार्य तथा सामुदायिक संगठन के लिए प्रशिक्षण, श्रव्य-दृश्य साधन प्रदान करता है और प्रकाशन आदि भी प्रकाशित करता है।	1,35,000	--वही--	--वही--
52.	कण्डास्वामी कण्डर का न्यास बोर्ड, वेलुर, जिला-सलेम–638182 (तमिलनाडु)	यह एक कालेज, कई स्कूलों, निःशुल्क छात्रावासों, साक्षरता-व-वाचनालयों नर्सरी स्कूलों आदि का संचालन करता है।	2,43,500	--वही--	--वही--
53.	समाज कल्याण सोसायटी, 2–ए, मेन रोड टिट्टागुडी तालुक जिला साउथ अर्कोट (तमिलनाडु)	यह सिलाई पाठयक्रम, हस्त-कौशल प्रशिक्षण शिशु सदनों, डेयरी योजनाओं तथा परिवार कल्याणोन्मुख शिविरों का भी संचालन करता है।	2,41,000	--वही--	--वही--
54.	आनंद वेल्लाह संगम, 1 व 2 सारथी स्ट्रीट, तिरुनकलि, तिरुची-620005 (तमिलनाडु)	यह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब दलित लोगों के उत्थान के लिए कार्य करता है। यह प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का भी संचालन करता है।	1,16,326	--वही--	--वही--
55.	मानव विकास कार्यक्रम पेरूमानि कुजही, कारिकत–629157 जिला कन्या कुमारी (तमिलनाडु)	इसका मुख्य उदेश्य गरीबी तथा दलित लोगों के जीवन स्तरों को उन्नत करने पर आधारित समाज सेवा में लगे रहना है।	1,20,000	--वही--	--वही--
56.	तिरुचिरापल्ली बहुउद्देश्यीय समाज कल्याण ए० सोसायटी, बिशप हाउस पो० बाक्स नं० 14, तिरुचिरापल्ली–620001 (तामलनाडु)	इसके कार्य-कलापों में माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल अनाथों शिशु सदनों स्कूलों में भोजन देना, जैसे कार्य के विभिन्न भोजन कार्यक्रम आदि शामिल हैं।	6,69,732	--वही--	--वही--
57.	पंजाब एसोसियेशन, 170–172, पिटर्स रोड, रायपेठ, मद्रास–600014 (तमिलनाडु)	यह स्कूलों, कालेजों, डिस्पेन्सरियों, डेयरी फार्मों, निर्माण केन्द्रों, महिला छात्रावासों का संचालन करता है।	1,32,000	वही--	--वही--
58.	मुथुलक्ष्मिया शैक्षिक तथा सांस्कृतिक दक्षिणी भारतीय प्रतिष्ठान, 186 विंग स्ट्रीट, त्रिपलीकेन, मद्रास–600005	इसके कार्यकलापों में औपचारक, गैर-औपचारिक, गैर-औपचारक तथा प्रौढ़ शिक्षा, बाल तथा विस्तार सेवाएं प्रदान करना और एक मध्याह्न भोजन केन्द्र का संचालन करना भी शामिल है।	2,87,010	--वही--	--वही--

1	2	3	4	5	6
59.	तमिलनाडु गांधी स्मारक निधि तालुक-कालुपट्टी मदुरै–625020 (तमिलनाडु)	यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य हेतु ग्राम सेवा केन्द्रों का संचालन करती है। विभिन्न विषयों की पुस्तकें प्रकाशित करती है और इसके अन्य कार्यकलापों में शिक्षा, आदिवासी और हरिजन सेवा आदि शामिल हैं।	1,20,000	प्रौढ़ निरक्षरों के लिए कार्यात्मक तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना।	इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला अनुदान अधिकतर आवर्ती स्वरुप होता है और आवर्ती अनुदान का अंश बहुत कम होता जो है परियोजना अवधि के पहले वर्ष में दिया जाता है।
60.	वाई० एम० सी० ए० मुल्लनगिना–629157 जिला कन्याकुमारी (तमिलनाडु)	इसके कार्यकलापों में मुर्गी पालन, किसानों को बीज वितरण कार्यक्रम शामिल है। यह नर्सरी स्कूल तथा सिलाई और प्रशिक्षण व-निर्माण केन्द्र का भी संचालन करता है।	1,20,000	–वही–	–वही–
61.	हरिजन सेवक संघ, वैक्कल रोड, गोवेवेतीपलयम जिला रेरियर–638452 (तमिलनाडु)	इसका कार्य अस्पृश्यता को दूर करना और कुएं, मंदिर, दुकानें आदि बनाना, हरिजनों, को कृषि, आवास, शिशु सदनों, रोजगार आदि में सहायता करना है।	1,20,000	–वही–	–वही–
62.	तमिलनाडु महिलाओं की स्वैच्छिक सेवायें, मद्रास–600013	यह एम्बुलेन्स सेवायें प्रदान करती है, सामु० केन्द्र, शिशुसदन, अस्पताल कल्याण सेवायें संचालित करता है तथा विकलांग व्यक्तियों को साधन तथा उपकरण भी प्रदान करती है।	7,57,740	–वही–	वही–
63.	चवनद की सिस्टरों की सभा के लिए समाज सेवा सोसायटी, होली क्रास कान्वेन्ट, कान्टीनमेंट, तिरुचिरापल्ली–620001 (तमिलनाडु)	इसके कार्यकलापों में माता, बच्चे के स्वास्थ्य की देखभाल, शिशु सदनों, अनाथों के लिए पूरक भोजन कम कीमत वाले आवास आदि का निर्माण शामिल है।	1,38,000	वही–	–वही–
64.	यू० पी० ब्रेणो माधव जन कल्याण समिति, ग्रामोद्योग भवन, गुलाब रोड, रायबरेली (उ०प्र०)	टी० आर० वाई० एस० ई० एम० योजना के अन्तर्गत यह ग्रामीण युवकों, महिलाओं तथा निरीक्षर व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।	1,23,000	–वही–	–वही–
65.	सर्वोदय सेवा संस्थान, मलिक मैन रोड, सत्य नगर, रायबरेली, (उत्तर प्रदेश)	संस्थान के मुख्य कार्यकलापों में खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों का विस्तार करने की दृष्टि से प्रशिक्षण, शिक्षा तथा रोजगार प्रदान करना शामिल है।	2,10,235	–वही–	–वही–
66.	खादी ग्रामोद्योग संघ, 5-बी, सरदार पटेल मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद (उ० प्र०)	संघ का मुख्य कार्य विभिन्न कौशलों, शिक्षा आदि में ग्रामीण व्यक्तियों को प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करना है।	1,23,000	–वही–	–वही–

1	2	3	4	5	6
67.	भारतीय महिलाओं का औद्योगिक प्रशिक्षण तथा पुनर्नियुक्ति संस्थान 460-देवपुर, पो० राजाजी पुरम, लखनऊ (उ० प्र०)	यह महिलाओं के प्रशिक्षण केन्द्र आदि की स्थापना करके महिलाओं के समाज कल्याणार्थ कार्य करती है।	1,28,250	प्रौढ़ निरक्षरों के लिए कार्यात्मक तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना।	इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला अनुदान अधिकतर आवर्ती स्वरुप होता है और आवर्ती अनुदान का अंश बहुत कम होता है जो परियोजना अवधि के पहले वर्ष में दिया जाता है।
68.	साक्षरता गृह, पो० आलम बाग, सरोजनी नगर ब्लाक, लखनऊ (उ० प्र०)	प्रौढ़ शिक्षा तथा गैर औपचारिक शिक्षा अथवा इससे संबंधित कोई अन्य औपचारिकता के कार्य को आगे चलाने तथा इससे संबंधित परियोजनाओं और कार्यक्रमों को शुरू करना।	1,28,700	--वही--	--वही--
69.	भारतीय आजीवन शिक्षा परिषद्, 647, कटरा इलाहाबाद–211002, (उ० प्र०)	शोध विकास तथा विस्तार कार्य आदि से संबंधित विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना।	1,23,000	--वही--	--वही--
70.	सर्वंदलीय मानव विकास केन्द्र, बहजोई जिला-मुरादाबाद (उ० प्र०)	यह एक उत्पादन केन्द्र, शिशु निकेतन नर्सरी स्कूल, डेयरी, समाचार एजेन्सी आदि का संचालन करता है।	1,62,530	--वही--	--वही--
71.	रामकृष्ण विवेकानन्द मिशन, 7, रीवर साइड रोड, बैरकपुर, जिला-24-परगना (प० बंगाल)	वह निराश्रय बच्चों के आवास, स्कूलों लड़कों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पुस्तकालय, डिसपेन्सरी आदि का संचालन करता है।	2,61,000	--वही--	--वही--
72.	कलकत्ता शहरी सेवा संघ, 16 सुधीर स्ट्रीट, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	संगठन के मुख्य कार्यकलापों में प्राथमिक, माध्यमिक, तकनीकी और गैर-औपचारिक शिक्षा को प्रोन्नत तथा बल प्रदान करना शामिल है।	1,35,920	--वही--	--वही
73.	प्रेरणा स्वतः रोजगार संस्थान, 53, रीपन स्ट्रीट, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	यह मुर्गी पालन, सूअर पालन का प्रशिक्षण प्रदान करता है, रोजगार संयुक्त कृषि और कृषि विज्ञान सेवायें तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि प्रदान करने के लिए मार्गदर्शी परियोजनायें संचालित करता है।	1,41,650	--वही--	--वही--
74.	झारग्राम महाकुमा जन-शिक्षा प्रसार समिति, रघुनापुर, झारग्राम, जिला-मिदनापुर (प० बंगाल)	संगठन के मुख्य कार्यकलापों में निरक्षरता से संबंधित व्याख्यान, वाक्-प्रतियोगिताओं, सेमिनारों का आयोजन करना शामिल है। यह एक हाई स्कूल भी चलाता है तथा एक पत्रिका का भी प्रकाशन करता है।	1,00,000	--वही--	--वही--
75	बाल स्वास्थ्य संस्थान, 11, ब्रजेश गुहा स्ट्रीट, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	यह एक समाकलित चाईल्ड केस शोध कार्यक्रम का संचालन करता है जिसमें प्रौढ़ तथा गैर-औपचारिक शिक्षा को महत्व दिया जाता है।	2,98,100	--वही--	--वही--
76	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, ठक्कर बापा स्मारक सदन, डा० अम्बेदकर रोड, नई दिल्ली-55	यह जनजातीय महिलाओं के लिए अनेक स्कूलों, आश्रमों, बालवाडियों पुस्तकालयों ,स्वास्थ्य शिविरों, प्रशिक्षण केन्द्र आदि का संचालन करता है।	3,61,315	--वही--	--वही--

1	2	3	4	5	6
77	डा० ए० वी० बालिक स्मारक ट्रस्ट लिंक लिंक हाउस, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002	यह एक मेडिकल क्लिनिक, बने बनाए वस्त्रों आदि के लिए उत्पादन यूनिट का संचालन करता है और छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता है।	2,33,432	प्रौढ़ निरक्षकों के लिए कार्यात्मक तथा उत्तर साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करना।	इस योजना के अंतर्गत दिया जाने वाला अनुदान अधिकतर आवर्ती स्वरूप होता है और आवर्ती अनुदान का अंश बहुत कम होता है जो परियोजना अवधि के पहले वर्ष में दिया जाता है।
78.	भारतीय सतत शिक्षा विश्वविद्यालय	यह कार्यशालाएं तथा सेमिनारों आदि आयोजित कर के विचारों के आदान-प्रदान करने हेतु एक निकासी गृह के रूप में कार्य करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है, सतत शिक्षा आदि से सम्बंधी साहित्य प्रकाशित करता है।	1,09,207	—वही—	—वही—
79.	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा एसोसिएशन, शफीका स्मारक, 17-बी, आई०पी० स्टेट, नई दिल्ली	यह प्रौढ़ शिक्षा सम्बंधी अनेक पत्रिकाएं प्रकाशित करता है, सूचना प्रसारण के लिए एक निकासी गृह के रूप में कार्य करता है, सेमिनारें, कार्यशालाएं, सम्मेलन आदि का आयोजन करता है, तथा प्रौढ़ शिक्षा की प्रोन्नति के लिए उत्कृष्ट लेखों के लिए नेहरू साक्षरता पुरस्कार भी प्रदान करता है।	1,57,499	--वही--	--वही--
उच्च शिक्षा					
1.	श्री अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक शोध संस्थान, आरोविल, कोट्टाकुप्पम- 605014 (तमिलनाडु)	यह संस्थान चार नियमित दिवा स्कूलों के द्वारा शिक्षा में नवीनता तथा शोध कार्य में कार्यरत है।	9,69,000	शैक्षिक शोध कर्ताओं बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम निःशुल्क शिक्षा तथा प्रशासनिक व्यय की टीमों का अनुरक्षण।	
2.	श्री अरविन्द अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक केन्द्र, पांडिचेरी- 605002	यह संस्थान श्री अरविन्द आश्रम का एक अभिन्न अंग है। इस संस्था में अध्ययन के बाल विहार से लेकर उच्चतर तथा उच्च श्रेणियों तक की शिक्षा के लिए व्यवस्था है। इस संस्था में मानविकियों, भाषाओं, विज्ञान, इंजीनियरी और शारीरिक शिक्षा की सुविधायें प्राप्त हैं।	10,50,000	व्यय का अनुरक्षण जिसमें स्टाफ के वेतन शामिल हैं।	
यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग					
1.	ऑरोविल ट्रस्ट ऑरोविल कोट्टाकुप्पम (तमिलनाडु)	आरोविल के अनुदान तथा विकास में सक्रिय भाग लेना।	2,00,000	फरवरी, 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष 1985 में "युवा तथा मानव एकता के आदर्श" संबन्धी सेमिनार आयोजित करना।	

प्रशासनिक चार्ट

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

शिक्षा विभाग

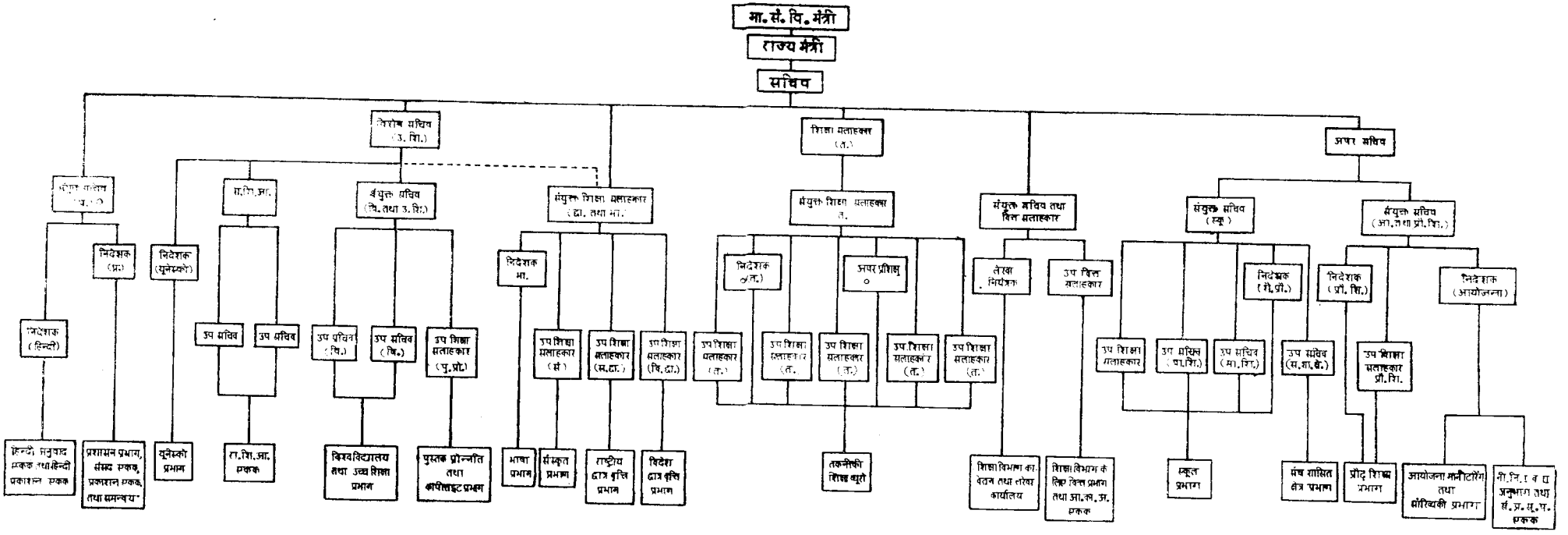

शीर्षक

प्र.	प्रशासन
पु.प्रो.	पुस्तक प्रोन्नति
रा.छा.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
वि.छा.	विदेश छात्रवृत्ति
नी.नि.	नीति नियम
उ.शि.	उच्च शिक्षा
वि. तथा उ. शि.	विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा
सं.प्र.सू.प.	संगणकीकृत प्रबंध सूचना पद्धति
०	रिक्त
अ.प्र.	अपर प्रतिसूता
द्वा. तथा भा.	छात्रवृत्ति तथा भाषाएँ
सं.	संस्कृत

टिप्पणी:—

संगणक शिक्षा (स्कूल प्रभाग) का कार्य संयुक्त सचिव (स्कूल) के माध्यम से शिक्षा सलाहकार (त.) द्वारा देखा जा रहा है। रोबिक प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के व्यावसायी करण से सम्बंधित कार्य के बारे में संयुक्त सचिव (स्कूल) द्वारा शिक्षा सलाहकार(त.) को भी स्थिति से अवगत कराया जाता है।

25.9.1985 की स्थिति

शीर्षक

प्रौ.शि.	प्रौढ़ शिक्षा
स्कू.	स्कूल
भा.	भाषाएँ
त.	तकनीकी
सम.	समन्वय
सं.ए.	संसद एकक
सं.शा.क्षे.	संघ शासित क्षेत्र
आ.का.अ.	आंतरिक कार्य अध्ययन
आ.तथा प्रौ.शि.	आयोजना तथा प्रौढ़ शिक्षा
रा.शि.आ.	राष्ट्रीय शिक्षक आयोग
प्रा.शि.	प्रारम्भिक शिक्षा
मा.शि.	माध्यमिक शिक्षा

प्रशासनिक चार्ट
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
शिक्षा विभाग

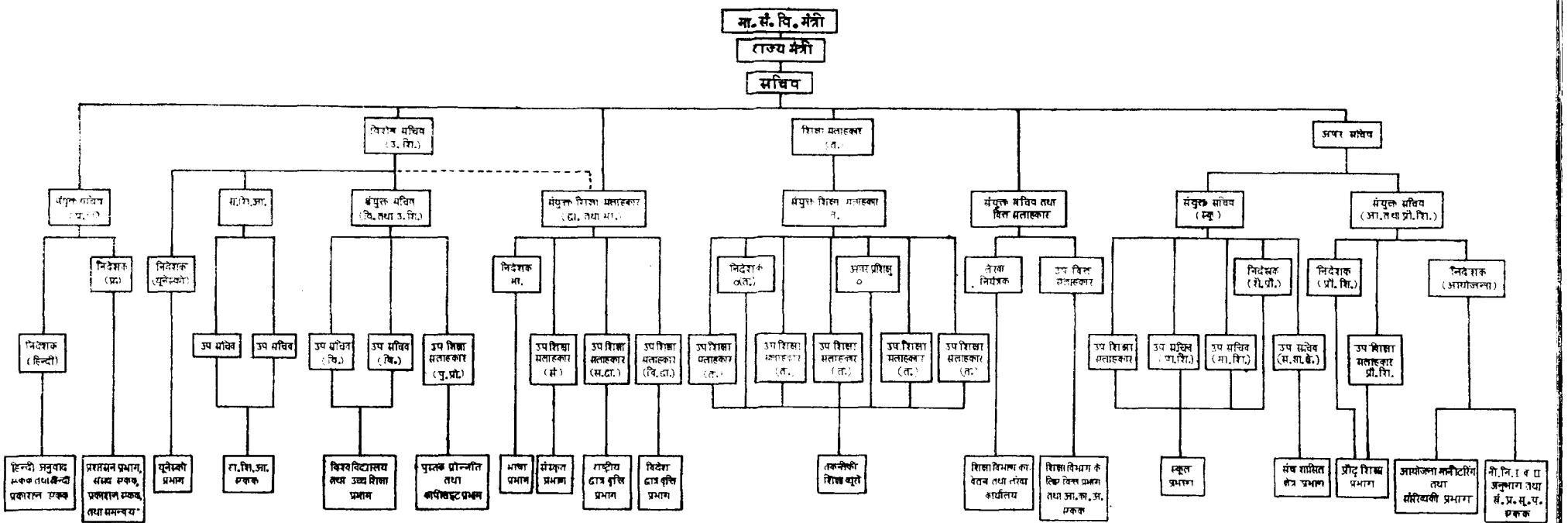

शीर्षक

प्र.	प्रशासन
पु.प्रो.	पुस्तक प्रोन्नति
रा.छा.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति
वि.छा.	विदेश छात्रवृत्ति
नी.नि.	नीति नियंत्रण
उ.शि.	उच्च शिक्षा
वि. तथा उ. शि.	विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा
सं.प्र.सू.प.	संगणकीकृत प्रबंध सूचना पद्धति
०	रिक्त
अ.प्र.	अपर प्रशिक्षुता
छा. तथा मा.	छात्रवृत्ति तथा माचार्य
सं.	संस्कृत

टिप्पणी:—

संगणक शिक्षा (स्कूल प्रभाग) का कार्य संयुक्त सचिव (स्कूल) के माध्यम से शिक्षा सलाहकार (त.) द्वारा देखा जा रहा है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के आपसदायी कारण से सम्बंधित कार्य के बारे में संयुक्त सचिव (स्कूल) द्वारा शिक्षा सलाहकार (त.) को भी स्थिति से अवगत कराया जाता है।

25.9.1985 की स्थिति

शीर्षक

प्रौ.शि.	प्रौढ़ शिक्षा
स्कू.	स्कूल
मा.	माचार्य
त.	तकनीकी
सम.	समन्वय
सं.ए.	संसद एकक
सं.शा.क्षे.	संघ शासित क्षेत्र
आ.का.अ.	आंतरिक कार्य अनुश्रवण
आ.तथा प्रौ.शि.	आयोजना तथा प्रौढ़ शिक्षा
रा.शि.आ.	राष्ट्रीय शिक्षक आयोग
प्रा.शि.	प्रारम्भिक शिक्षा
मा.शि.	माध्यमिक शिक्षा
यो.प्रो.	योजना प्रौद्योगिकी

CONTENTS

	Pages
Introductory	i
An Overview	iii
Chapter	
1. Organisation	1
2. School Education and Physical Education	3
3. Higher Education and Research	20
4. Technical Education	37
5. Adult Education	48
6. Education in the Union Territories	51
7. Scholarships	58
8. Book Promotion and Copyright	61
9. Promotion of Languages	65
10. Indian National Commission for Cooperation with UNESCO	81
11. Other Activities	86
Financial Allocations of items discussed	94
Statement showing the Names of Private and Voluntary Organisations which received Recurring Grant-in-aid of Rs. 1 lakh and more during 1984-85	99
Administrative Chart	111

1—759 Deptt. of Edu/85

INTRODUCTORY

There has been an increasing awareness that the people of the country should be looked upon as its valuable resource—indeed the most valuable resource—and that our growth process should be based on the integrated development of the citizen, beginning with childhood and going right through life. It is increasingly realised that all relevant instruments and agencies contributing to, or responsible for, this growth should be integrated in order to ensure all-round development. A wider approach needs, therefore, to be adopted in which science and technology, arts and crafts, humanities and human values should all be woven into a comprehensive pattern of development. In pursuance of this idea, a new Ministry was created under a suggestive name, Ministry of Human Resource Development, on 26 September, 1985, through 174th Amendment to the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961. The new Ministry of Human Resource Development constituted by this amendment, has five Departments namely, Department of Education, Department of Culture, Department of Arts, Department of Youth Affairs and Sports, and Department of Women's Welfare. The conceptual framework of this Ministry of Human Resource Development consists in building up the all-round personality of human beings and to this end, integrating under one umbrella as many relevant activities as possible, with a view to evolving a package of inputs. The process is not merely one of co-ordination, but real integration, so that all components are woven into a single, continuous, harmonious programme. This process has just started, and initial steps have been taken. The report of the Ministry that has been brought out in five parts covers an account of activities regarding the items and subjects allotted to each of the Departments.

A special activity of the Ministry during the year was to strengthen and re-orient activities relating to education, culture, arts, sports, youth welfare, women and children, towards an integrated approach so as to provide to the Ministry a sharper thrust for human resource development.

The process of formulating a new educational policy began last year. This process, however, became intensified during the course of the year. The draft policy is expected to be presented to the Parliament towards the end of the Budget Session 1986.

Dissemination of culture at the grassroot level being the main thrust of the activities of the Department of Culture, steps were taken by the Department of Culture for setting up seven Zonal Cultural Centres in different regions of the country. Three of these Zonal Centres, one each at Patiala (Northern Zone), Santiniketan (Eastern Zone), and Thanjavur (Southern Zone) were inaugurated by the Prime Minister on 6th November, 1985, 5th December, 1985 and 31st January, 1986, respectively. The main objective of these Centres is to emphasize cultural linkages that extend beyond territorial and linguistic boundaries.

Under the policy of promoting wider appreciation and international interaction of our culture, two Festivals of India were organized during the year, one in the USA and the other in France, which won profuse acclaim in art circles and also from the common citizens.

Another important activity of the Deparmtent of Culture during the year was to hold the first South Asian Archaeological Congress in New Delhi from January 13—20, 1986 under the banner of SAARC in which delegates from all SAARC countries except Maldives participated.

During the year, the work relating to Certification of Films for Public Exhibition was transferred from the Ministry of Information & Broadcasting to the Department of Culture.

The Department of Arts was created solely for undertaking the diverse programmes of the Indira Gandhi National Centre for Arts at the level of research, publication, training, creative activities and projections encompassing all arts, especially in their dimension of mutual inter-dependence within the natural human environment as an intrinsic part of life styles at all levels of society and regions. The IGNCA will serve as a major resource centre for the arts and is an important ingredient in the activities of the Ministry of Human Resource Development. Through its activities the IGNCA will catalyze an integrated perception of the Indian tradition in art and culture, stimulate awareness of and sensitivity to the precious heritage, and refine perception and understanding of the heritage. It thus aims at regenerating widespread appreciation of the depth and range of Indian tradition. A National Data Bank with a computerised storage and retrival system on arts, humanities and cultural heritage is a core programme of the IGNCA which would be accessible to scholars, academics, artists, school and college students and to laymen.

All round development of women and children constitutes an important component of the country's human resource development. Hence these two target groups deserve special treatment in addition to their legitimate share from the general developmental programmes. In order to revitalise the existing programmes for women and children, the governmental machinery at the national level was geared up and a separate Department of Women's Welfare was set up under the newly created Ministry of Human Resource Development. This Department is charged with the responsibility of functioning as the nodal agency to guide, coordinate and review the efforts in this area, both Governmental and non-Governmental.

The major thrust of the programme of this Department is to ensure a state of well-being for women and children, particularly those of the weaker sections of the society through integrated services. The programmes of integrated child development services is the basic support to human resource development. It aims to provide a package of early childhood services of non-formal pre-school education, health and nutrition, culminating in reduction in wastage and stagnation, school drop-out, infant mortality, disablement and mal-nutrition. Similarly, the programmes for women like socio-economic programmes, training-cum-employment programmes, condensed courses of education for adult women, etc., endeavour not only to provide economic independence to women but also to raise their quality of life.

Important among the major activities of the Department of Youth Affairs and Sports were the formulation of new schemes and expansion of the existing schemes for promotion of sports in the implementation of the National Sports Policy as a part of the Seventh Five-Year Plan. For undertaking these initiatives, the outlays for the Seventh Five-Year Plan for sports and games have been raised several times as compared to similar outlays for the Sixth Five-Year Plan. It is hoped that the increased activities will lead to broad-basing of participation in sports and games, improvement in the sports standards and generally contribute towards health fitness and strength of the nation. Greater emphasis was laid on the improvement of personality and skills of young people in programmes meant for the youth and new initiatives taken as part of the Seventh Five-Year Plan. The year of the Youth was celebrated in a befitting manner. The designation of a National Youth Day and Week and announcement of a National Youth Emblem were the durable gains of this endeavour.

The activities and achievements of the Department of Education are reported in the pages that follow.

AN OVERVIEW

DEPARTMENT OF EDUCATION

Formulation of New Education Policy

A status paper entitled "Challenge of Education—A Policy Perspective" was published by the Ministry in August 1985, copies of which were placed in the Parliament and circulated to all State Governments and Union Territory Administrations. This also formed the basis of discussions in the Conference of State Education Ministers held on August 29-30, 1985. The document has been translated practically into all regional languages through the State Governments and given wide circulation. In addition, 5,80,000 copies of this document in English, 2,40,000 in Hindi and 4,000 in Urdu have been distributed by the Ministry in response to requests received and also to different organisations. This document was intended to stimulate wide and intensive national debate on issues relating to Education Policy and alternatives. As a part of the nation-wide debate on the New Education Policy, 12 National Seminars and 17 sponsored Seminars have been organised by the Government of India and its agencies. All State Governments have taken keen interest in the organisation of debates on the New Education Policy. In addition to State level seminars, several seminars, symposia and discussions have taken place in different educational institutions and also at the block level. Representatives of number of teachers' organisations and students' organisations at all-India level have also been associated in discussions on the formulation of the New Education Policy. Under the joint auspices of the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) and the Government of Maharashtra, a Regional Conference for MLCs from teachers' constituencies and graduates' constituencies was organised at Nagpur on December 13-14, 1985 and a National Conference of Presidents, Zilla Parishads and Chairmen, Panchayat Samitis was organised at Pune on February 3-4, 1986.

A large number of suggestions from organisations and individuals have been received in the Ministry in response to the announcement by the Prime Minister relating to formulation of a New Education Policy. All communications received in the Ministry numbering more than 8,000 including letters, memoranda, recommendations of seminars, recommendations of State Governments have been carefully abstracted and classified; a detailed content analysis of all the suggestions has been made by the National Institute of Educational Planning and Administration which have brought out 13 volumes on the perceptions on education received from State Governments, individuals and organisations.

In pursuance of the recommendations of the Conference of State Education Ministers, National Groups of Ministers of Education on (i) Manpower Projections and Vocationalisation; (ii) Financial Resources and (iii) Examination Reforms have been constituted under the Chairmanship of the Union Minister for Human Resource Development to examine in depth the various issues relating to the formulation of New Education Policy and evolve strategies for their implementation.

The debate on the New Education Policy has involved all sections of the people and many useful ideas and approaches have emerged. Based on the suggestions received from various quarters the issues relating to New Education Policy were formulated for consideration of the Conference of Education Ministers of States and Union Territory Administrations held on January 23-24, 1986. A draft of the New Education Policy will be presented shortly in the Parliament.

Elementary Education

Provision of free and compulsory education for all children until they complete the age of 14 years is a constitutional goal. According to the

Policy frame of the Seventh Five-Year Plan, the target year for reaching the constitutional goal of universal elementary education is 1989-90. Elementary Education also continues to be part of the minimum needs programme of the Plan.

The programme of universalisation has been pursued during this year with vigour both at the central as well as State/Union Territory levels. Some of the important steps taken in this regard are listed below :

- Meeting of the National Committee on point 16 of the 20-Point Programme as part of the conference of Education Secretaries in February 1985 to review the progress of universalisation in the nine educationally backward States, in particular.
- Meetings of the State Task Forces on Elementary Education in the 9 educationally backward States were held to review the progress of efforts made by the State Governments for implementation of UEE and NFE programmes.
- Mounting of a National Campaign on Universalisation of Elementary Education, for intensifying efforts to increase the enrolment and retention at the elementary stage. Special emphasis in this year's campaign was laid on reducing the rate of drop-outs.

Additional enrolment target during 1985-86 in classes I—VIII is 52.71 lakhs. Comprehensive measures such as conversion of single teacher schools into two teacher schools, improvement of physical facilities of primary and middle schools, special attention to girls and disadvantaged groups like SC and ST, adequate provision of incentives like free textbooks and stationery, free uniforms specially for girls, attendance scholarships particularly for girls and mid-day meals etc, have been envisaged and undertaken in various states to reduce the high drop-out rates at the elementary stage.

Non-formal Education

The non-formal education programme forms the second major component of the strategy employed to achieve universalisation of education, since a large number of children are either not able or unwilling to attend school. The number of children to be covered by the NFE programme during the Seventh Plan is estimated at 2.5 crores. The programme has acquired good momentum in the 9 educationally backward States, and by the end of 1985-86, the coverage of the programme would be of the order of 41.41 lakhs in about 1.65 lakhs centres.

Free Education for Girls up to the end of the Higher Secondary Stage

In order to encourage the spread of education among the girls by providing free education, a scheme has been prepared under which the Government of India would re-imburse the States/Union Territories for foregoing revenue realized as tuition fees charged from girls at the Secondary/Higher Secondary stage. The Scheme will remain in operation for the entire Seventh Plan period.

Central Assistance is also being contemplated to assist States/Union Territories in strengthening of teacher training facilities, and for taking up a massive programme for re-orientation of existing teachers during the Seventh Plan period. A Scheme for improvement of science teaching is also being prepared.

Physical Education

Physical Education and Sports are today accepted as an integral part of education all over the world. The new National Sports Policy, covering *inter-alia* physical education and yoga, since placed before the Parliament as a Government Resolution makes it the duty of the Central and State Governments to accord a very high priority to promotion of sports and physical education in the process of all round development. The Policy also recognises the need of every citizen irrespective of age and sex to participate in and enjoy sports and recreational activities. The Policy, therefore, enjoins upon the Central and State Governments to promote and develop traditional and modern games and sports and also Yoga by providing necessary facilities and infrastructure on a large scale. As a follow-

up of the directives contained in the new Policy substantially higher investment on physical education and Yoga has been envisaged during the VII Five-Year Plan Period. A special thrust has also been proposed to the strengthening of teacher training programmes and in promotion of mass participation.

Higher Education

The student enrolment in universities and colleges increased from 33.59 lakhs in 1983-84 to 35.39 lakhs in 1984-85. The enrolment of women students during 1984-85 was 10.21 lakhs as against 9.77 lakhs during 1983-84. The UGC continued to pursue the policy of improvement of standards and quality of education and removal of disparities and regional imbalances in higher education, science education, and promotion of Gandhian and Nehru studies received special attention under UGC's programmes of quality improvement. The UGC has taken steps to develope facilities at the national level for use of university scientists in the field of Nuclear Science, Materials Research, Laser and Fibre Optics, Astrophysics, Astronomy, Biotechnology, and Mass Communication and Educational Technology. Higher Education among Scheduled Castes/Scheduled Tribes continued to receive emphasis with the financial assistance provided by the UGC for special programmes for these groups. The Indira Gandhi National Open University was established in Delhi in September, 1985 to disseminate and advance knowledge by providing instructional and research facilities. It will lay stress on continuing and vocational education with a view to improving knowledge and skills and promoting educational opportunities of the community in general and the disadvantaged groups in particular. Another Central University, namely Pondicherry University, has been established at Pondicherry on 16th October, 1985 to serve the needs of the Union Territory of Pondicherry.

Technical Education

Socio-economic progress of a country is intimately connected with the availability of properly trained technical manpower. Our country therefore accorded top priority in developing extensive facilities for technical education in the country since attainment of her independence. In 1947, there were facilities for admitting only 2940 students in engineering degree courses and only 3670 students in diploma courses. Through sustained efforts during the successive plan periods, our country has now developed extensive facilities of technical education and training and the system is now in a position to admit annually about 30,000 students in degree courses and about 60,000 students in diploma courses covering both conventional and new emerging areas. Postgraduate education and research in engineering and technology were practically absent at the time of attainment of our independence, but at present our technical institutions are in a position to offer well designed postgraduate courses to about 7,000 students each year. During the Seventh Plan period activities on consolidation and optimal utilisation of existing facilities are continued. During the current plan, steps have also been initiated, amongst others for modernisation and removal of obsolescence in the engineering colleges and polytechnics, application of science and technology for rural development, establishment of linkages between technical education system and the development sectors and providing computing facilities in technical institutions. With the implementation of schemes of the Seventh Plan period it is hoped that shortfalls in many critical areas of technical education facilities will be largely removed.

Adult Education

Seventh Five-Year Plan stipulates that Adult literacy programmes will be pursued with the objective of covering all illiterates in the age group 15—35 by 1990. Considering that adult education is an important component of the socio-economic development and also a crucial element in the family welfare programme, Government has accorded high priority to the adult education programme by including it in the Minimum Needs Programme and the 20-Point Programme. Keeping the major thrust areas in view, like development of a programme of continuing education, motivation, launching of mass programme, effective linkages with various developmental programmes of rural development and family welfare, larger involvement of voluntary agencies, NYKs, NSS, and the ICDS, the Government has decided to launch the Mass Programme for functional literacy alongwith existing on-going Schemes to achieve the goal of eradication

of illiteracy in the age group 15—35. The Government will continue to be guided by the para-meters of coverage of the districts having literacy rates below the national average; coverage of special target groups e.g. women, Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections of the society; larger participation of the youth and the students in universities and colleges in literacy programmes; mobilisation of voluntary agencies; strengthening of the post literacy and follow-up programme through a net work of village community life and education centres; use of mass media-folk, traditional and modern. Against the stipulated target of enrolment of 75.46 lakhs adult illiterates in 1985-86, the achievement upto the end of September 1985 is 70.43 lakhs. The implementation of the programme is being monitored regularly and quarterly progress reports on the performance under different sectors of the programmes are furnished to the Government. Several visits were made to different countries to study their programmes of adult education with a view to adopting their strategies to enrich the programme. The Directorate of Adult Education (National Resource Centre) and 17 State Resource Centres located in different States continue to provide technical and resource support to the programme through a net work of their activities. A National and several other seminars were organised by the Directorate and the State Resource Centres to provide input in the formulation of the New Education Policy.

Scholarships

The Government of India have been offering a large number of scholarships for enabling students to prosecute further studies both in India and abroad. Scholarships are generally awarded to meritorious students without adequate means. Under the National Merit Scholarships Programme, scholarships were given to 27,000 students for undertaking studies beyond the matriculation stage. 33,000 scholarships were awarded to talented children belonging to rural areas for education upto the higher secondary stage. Out of the 33,000 scholarships, 18,000 were awarded to students belonging to landless labour groups and Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Five hundred scholarships were awarded to poor but meritorious students for enabling them to receive good education in approved residential schools.

The Ministry has also been providing scholarships to Indian students for study abroad so that they can undertake research in newly emerging specialisations. On a reciprocal basis, 180 scholarships are offered to foreign nationals, thereby assisting the developing countries in their effort to train their manpower. Besides, Government of India offered 75 scholarships to nationals of commonwealth countries.

Book Promotion and Copyright

The programmes of this Ministry in the field of Book Promotion are aimed at facilitating the production of good literature at moderate prices, encouraging Indian authorship and the publishing industry, formulating book import policy, promoting export of Indian books and fostering book-mindedness among the people. The National Book Trust continued its publication programme and organised and participated in Book Fairs/ Exhibitions at international, national and regional levels. Outstanding events of the year were the organisation of the 12th National Book Fair in Patna in October, 1985, the Third International Children's Book Fair in Allahabad in November, 1985 and the Seventh World Book Fair in New Delhi in February 1986. The liberalised import policy announced during the year will be effective for a period of three years. Efforts were made to set up a National Society of Authors and Composers of Musical Works to protect their interests, as provided under the Copyright Act. The Copyright Office registered 1,908 literary and artistic works.

Propagation and Development of Languages

The Policy of the Government of India is to encourage the development of all Indian Languages including classical, modern and tribal. The activities and programmes undertaken during the year under report were intended to achieve the desired objectives with the emphasis on training of teachers for facilitating the implementation of the three-language formula and the production of university level textbooks with a view to facilitating switch over from English to regional languages as media of instruction. Assistance continued to be given to non-Hindi speaking States for appointment of Hindi teachers in Hindi teachers training colleges and establish-

ment of Hindi teachers training colleges, award of scholarships to students for the study of Hindi beyond the matriculation stage. Financial assistance was also given to voluntary organisations working for the development and promotion of Hindi to enable them to organise Hindi teaching classes, organisation of correspondence courses for teaching Hindi, conduct of research on the methodologies of teaching and for publication of Hindi books. For promotion and development of tribal, classical and modern Indian languages, a number of schemes for preparation/publication of books, dictionaries, research and instructional material, training of teachers etc., are being implemented by this Ministry through various subordinate offices and autonomous organisations. Thirty calligraphy centres in various parts of India are in operation.

Under the Cultural Exchange Programmes, languages dictionaries/conversional guides are also being prepared by the Central Hindi Directorate, New Delhi. Under the scheme of 'Propagation of Hindi Abroad' foreign students are awarded scholarships for study of Hindi. Hindi teachers are deputed to foreign countries and Hindi books are distributed through our Embassies/Missions abroad. Grant-in-aid were also provided to various voluntary organisations for promotion and development of all Indian languages.

Indian National Commission for Cooperation with Unesco

India continued to play a leading role in matters relating to Unesco and participated in many important international conferences/meetings organised under the auspices of Unesco. The Government of India sent high-powered delegations to the Fifth Regional Conference of Ministers of Education and Those Responsible for Economic Planning in Asia and the Pacific (MINEDAP V) held at Bangkok, and the Twenty-third Session of the General Conference of Unesco held at Sofia (Bulgaria).

Annual Plan and Twenty Point Programme

Monitoring of Point No. 16 of the New 20-Point Programme relating to universalisation of elementary education and adult education was continued during the year under report.

Educational Statistics

Follow-up action was taken to implement the recommendations made by the High Level Committee to review the Educational Statistics System in India.

A pilot project on computerisation of Educational Statistics in Uttar Pradesh has started. This project is expected to be completed by March 1986.

Nine Publications/reports were brought out during the current year.

Education of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

Special Component Plan for scheduled castes and Tribal Sub-Plan for scheduled tribes for the Seventh Plan 1985-90 and Annual Plan 1985-86 have been finalised. Draft Special Component Plan and Tribal Sub-Plan for the Annual Plan 1986-87 have also been prepared. 21.66% and 12.69% of the total divisible outlay have been earmarked for these two Component Plans respectively out of the total divisible outlay for the Annual Plan for 1986-87.

Education of Minorities

In pursuance of former Prime Minister's fifteen point directive on Welfare of Minorities, Schemes of Community Polytechnics in areas predominantly inhabited by Muslims, U.G.C. Scheme of Coaching Classes for Higher Level Competitive Examinations, Review of textbooks from the stand-point of National Integration, training programme for teachers from schools managed by Minority Communities are being implemented.

A two-day Seminar was held on "Minorities and Education" in the context of formulation of New Education Policy.

In Conclusion

The Government is of the view that in order to make education meaningful and relevant, the education process calls for a change for active and effective link with every developmental activity. It therefore becomes essential to improve the functional relevance of education at all levels and to provide opportunities for acquisition of productive skills and improved technologies. It is proposed to provide a vocational thrust to education to fulfil developmental needs, and to take up a massive, long-term,

nation-wide programme of school improvement and to support and stimulate it by starting a fair number of quality institutions which would serve as catalysts. It is also considered necessary to de-link degrees from jobs where possible and to establish greater relevance and complementarity between the content and processes of education on the one hand and the requirements of different client groups on the other. It will also be necessary to bring about national cohesion and integrity through a national system of education rooted firmly in secularism, democracy and socialism. It will be the endeavour of the Government to strive to meet the challenges ahead under the leadership of the dynamic and young Prime Minister for a new design of education and to provide a strong base for realising the objectives and goals enshrined in the Constitution.

CHAPTER 1

ORGANISATION

Organisational Structure

The Department of Education, one of constituent parts of Ministry of Human Resource Development, is under the charge of Minister of State with the overall charge of Minister for Human Resource Development. The Secretariat of the Department is headed by the Secretary who is assisted by one Special Secretary (Higher Education), Additional Secretary and Educational Adviser (Technical). The Department is organised into Bureaux, Divisions, Desks, Sections and Units. Each Bureau is under the charge of a Joint Secretary/Joint Educational Adviser assisted by Divisional Heads. The set-up of the Department is shown in the organisation chart appended to the report.

Subordinate Offices/ Autonomous Organisations

Over the years, a number of subordinate offices and organisations have come up under the Department. For coordination and determination of standards in higher education, the University Grants Commission was set up in 1956 by an Act of Parliament. Besides, a number of organisations have been set up to discharge specific responsibilities. Among them is the National Council of Educational Research and Training which strives to promote qualitative aspects of school education throughout the country. The other important organisations are :

(i) National Institute of Educational Planning and Administration, New Delhi.
(ii) Indian Institute of Advanced Study, Simla.
(iii) Indian Council of Social Science Research, New Delhi.
(iv) Indian Council of Historical Research, New Delhi.
(v) Indian Council of Philosophical Research, New Delhi.
(vi) Kendriya Vidyalaya Sangathan, New Delhi.
(vii) Central Board of Secondary Education, New Delhi.
(viii) Kendriya Hindi Sansthan, Agra.
(ix) Central Institute of Indian Langauges, Mysore.
(x) Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad.
(xi) Central Hindi Directorate, New Delhi.
(xii) Commission for Scientific & Technical Terminology, New Delhi.
(xiii) Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi.
(xiv) National Book Trust, New Delhi.
(xv) Lakshmibai National College of Physical Education, Gwalior.

In the field of Technical Education, there are : the Indian Institute of Science, Bangalore; Indian School of Mines, Dhanbad; National Institute of Training in Industrial Engineering, Bombay; National Institute of Foundry and Forge Technology, Ranchi; School of Planning and Architecture, New Delhi; Administrative Staff College of India, Hyderabad; four Indian Institutes of Management, at Ahmedabad, Bangalore, Calcutta and Lucknow; four Technical Teachers' Training Institutes, at Bhopal, Calcutta, Chandigarh and Madras; five Indian Institutes of Technology, at Bombay, Delhi, Kanpur, Kharagpur and Madras; and, fifteen Regional Engineering Colleges, spread all over the country. Approval has been accorded for setting up of two more Regional Engineering Colleges, at Hamirpur (HP) and Jalandhar (Punjab).

Functions

Important functions of the Department of Education are : to evolve educational policy in all aspects and to coordinate and determine the standards of higher education and technical education; to administer Copyright Act; to improve the quality of textbooks; to administer scholarships and other schemes; to coordinate programmes of assistance and other activities with the UNESCO; to develop and coordinate research in social sciences; to foster and encourage studies and research in Sanskrit and other classical languages; to develop activities in the field of non-formal education; and to promote adult education.

CHAPTER 2

SCHOOL EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION

SCHOOL EDUCATION

Universalisation of Elementary Education

With a view to realising the constitutional goal of Universalisation of Elementary Education (UEE), this Programme was accorded a very high priority under the Sixth Plan. Since 1982 Elementary Education has also been included in the New Twenty Point Programme of the Government as Point No. 16. The present target date for realising the constitutional goal is 1990 i.e. the end of the Seventh Plan Period. On the basis of 1981 census estimations, the total population in the 6-14 age group by 1989-90 would be 1510 lakhs. Providing for a margin of 10% for average and underage children the number of children to be covered by 1990 will be about 1660 lakhs. According to available reports the total enrolment in classes I—VIII upto 1984-85 is estimated at upto 1121.06 lakhs. Besides, 35-40 lakhs are expected to be covered through Non-formal Education.

The National campaign for UEE was launched for the first time during 1982. As in previous years, a nation wide campaign was launched in the current year, highlighting the need for community participation. The campaign, coinciding with the commencement of academic sessions in different States/Union Territories, is aimed to create a climate for enrolment, monitor school attendance, fill up the vacancies of teachers and popularising non-formal education. Special emphasis was laid on reducing dropout rates. Feedback received so far from the State Governments is quite encouraging. The State Governments are hopeful of achieving the targets of additional enrolment fixed for 1985-86.

The statement below shows the enrolment targets and achievements :

(Figures within brackets indicate-enrolment ratio)

(Figures in lakhs)

	1979-80 (Actuals)	1980-81 (Ache.)	1981-82 (Ache.)	1982-83 (Ache.)	1983-84 (Ache.)	1984-85 (Ache.)	1985-86 (Targets)
1	2	3	4	5	6	7	8
Age-group 6—11 Enrolment classes-I-V . .	710·02	727·16	753·25	775·93	805·97	853·76	906·81
Enrolment as percentage of age group population	(83·72)	(85·23)	(87·76)	(89·87)	(93·3)	(91·84)	(101.7)
Age group 11—14 Enrolment : classes VI-VIII .	194·01	204·31	218·13	235·81	254·78	267·30	285·17
Enrolment as % age group Population . .	(40·16)	(41·72)	(43·96)	(46·90)	(50·7)	(53·07)	(55·2)
Age group 6—14 Enrolment classes I-VIII .	904·03	931·47	971·38	1011·74	1060·75	1121·06	1191·98
Enrolment of percentage of age group population	(67·91)	(69·36)	(71·71)	(74·05)	(78·01)	(78·21)	(84·64)

With a view to improving the quality of teaching, a massive programme of reorientation of educational administrators, head of educational institutions and teachers is proposed to be launched in 1985-86 and funds are proposed to be provided to selected Primary and Secondary teacher training institutions to strengthen them in respect of staff, equipment and library facilities.

Free and Compulsory Education

Flowing from the constitutional directive in Article 45, education in all schools—government, local bodies and aided—at all the primary stage (classes 1-5) and at the middle stage (classes 6-8) is free in most States/Union Territories except for boys in classes 7-8 in Uttar Pradesh. Some

States and Union Territories have enacted legislation making elementary education free and compulsory. However, the penal provisions of the legislation have remained unenforceable in the prevailing socio-economic conditions.

Primary School Project with UK Assistance

The UK Government had agreed to provide assistance of one million pounds for construction of primary school buildings in Andhra Pradesh. Further allocation of 14 million pounds is agreed in principle subject to the outcome of phase one, for a subsequent phase or phases of this project.

Study on Impact of School Feeding Programme

A study to determine the impact of school feeding programme on enrolment, retention and achievement level among 0-5 age-group children has been commissioned in July, 1985. The study is being conducted by Asian Centre for organisation Research and Development under the supervision of NCERT.

Non-formal Part-time Education for Elementary Age-group Children

In order to bring educational facilities to children who cannot attend school, or have left school without completing the elementary stage, non-formal education is being developed as a massive alternate/supporting system of formal schooling. The main thrust and maximum extent of coverage is in the 9 educationally backward states, viz. Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Madhya Pradesh, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal, who were receiving special Central assistance under a Centrally Sponsored Scheme of Non-formal education for elementary age-group children. This scheme basically aims at providing the institutional infrastructure necessary for coverage of non-enrolled and non-attending children, and strengthening the academic inputs to the programme of non-formal education both under Central and under States initiatives. The cost of the scheme is being shared equally by the Central and State Governments. During the year a total grant of Rs. 11,15,39,142/- has been sanctioned to these States.

Voluntary organisations in the 9 educationally backward States running non-formal education Centres on the State Government pattern and academic institutions, Government or private, in any State/Union Territory taking up innovative and experimental non-formal Education projects are given Central assistance on 100% basis on the recommendations of State Governments. So far 55 voluntary organisations and 1 academic institution have been sanctioned grant of Rs. 17.64 lakhs during the current year.

Non-formal education programme has gained a good momentum particularly in the 9 educationally backward states. By the end of 1985-86 the total non-formal coverage in the 9 educationally backward states would be of the order of 42 lakhs through 1,65,648 Centres including 20500 existing centres exclusively for girls. Besides, the number of non-formal centres being run by voluntary organisations with central grant is 2424 with an estimated coverage of 60600.

Non-formal Education Centres Exclusively for Girls

The unsatisfactory position about girls' enrolment has affected/continues to affect targets of coverage to be realised by the end of 1989-90. In order to increase girls' enrolment, the on-going scheme of non-formal education was liberalised from 1983-84 under which financial assistance is given to 9 educationally backward states on 90 : 10 Centre-State sharing basis for establishment of non-formal education centres exclusively for girls. During the year a total grant of Rs. 2,67,75,483/- has been sanctioned only for 20,500 existing centres exclusively for girls.

Appointment of Women Teachers

A Centrally sponsored-scheme of assistance on 80 : 20 Centre-State sharing basis for appointment of Women teachers in primary schools in the 9 educationally backward states particularly in rural/backward/hill/tribal areas, was put into operation during 1983-84. The continuance of the scheme during the VII Plan is under consideration.

Early Childhood Education

Early Childhood (Pre-school) education in rural and backward areas specially for first generation learners was suggested under the Sixth Plan as distinct strategy for reducing drop-out rate and improving retention. The programme is designed towards improving their communication (language) and cognitive (social, emotional intellectual and personality development)

skills as a preparation for entry into primary schooling. Under the scheme, assistance is available to the voluntary organisations in nine educationally backward states and an amount of Rs. 34.47 lakhs was sanctioned during 1985-86.

National Awards to Teachers

The scheme of National Awards to Teachers was started in 1958-59 with the object of raising the prestige of teachers and giving public recognition to the meritorious services of outstanding teachers working in Primary/Middle/High/Higher Secondary schools. The scope of the scheme was later enlarged to cover the teachers of Sanskrit Pathshalas, Tols etc. and Arabic/Persian teachers of Madrasas run on traditional lines. Each award carries with it a certificate of merit, a silver medal and cash payment of Rs. 1500/- which has been raised to Rs. 2500/- from 1985 onwards.

Out of 186 National Awards for Teachers, 1985, the names of 136 teachers—74 Primary and 62 Secondary have been finalised and announced. These teachers are from Andhra Pradesh, Assam, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh, A & N Island, Arunachal Pradesh, Dadra & Nagar Haveli, Delhi, Chandigarh, Goa, Daman & Diu, Pondicherry, Mizoram and Kendriya Vidyalaya Sangathan. Selection of teachers from the remaining State/Union Territories is in the process of finalization.

Educational Technology Programme

The Educational Technology Programme aims to bring about a qualitative improvement in education and widen access to education through an integrated use of all instruction technology, including radio and television. The scheme is being implemented through the Educational Technology Cells in the States/Union Territories and the Central Institute of Educational Technology in NCERT. In view of the experience gained in the implementation of the Educational Technology Scheme during the 6th Plan, it is proposed to modify the assistance to the States/Union Territories under the Educational Technology Scheme to the creation of self-contained and fully provided audio programmes production facilities and related training programmes.

In the context of INSAT, State Institutes of Educational Technology are being set up in the 6 INSAT States, namely Andhra Pradesh, Bihar, Orissa, Gujarat, Maharashtra and Uttar Pradesh to enable them to take over the responsibility for the production of educational television programmes relevant to their specific needs. The ETV studio buildings in Bihar and Uttar Pradesh has been completed and handed over to the State authorities. The studio buildings at Poona and Hyderabad have also been completed. The building for the SIET at Bhubaneswar is likely to be ready in February, 1986. In Gujarat the SIET building is being constructed by the State PWD and is likely to be ready in February-March, 1986. A separate building for the CIET is also to be taken up for construction through the Department of Space who have initiated tender action.

The equipment for CIET and the 6 SIETS has been ordered on M/s. GCEL, Baroda and M/s. BEL, Bangalore, both public sector undertakings. The delivery of equipment by BEL has so far been on schedule, and it is expected that the studio equipment for 3 SIETs will be completed by March, 1986 and for the remaining three by March, 1987. Supply of equipment by GCEL has been beset with delays, and it is hoped that all deliveries will be completed within the financial year 1985-86. The CIET continuity studio is now fully functional with the installation and commissioning of the studio equipment by BEL.

The production of programmes for the INSAT ETV service is being shared on 50 : 50 basis between Doordarshan and CIET. The programmes are of general enrichment for the age-group 5 to 8 years and 9 to 11 years. The ETV service is available in the morning for 40 minutes each day for 5 days a week. Every Saturday the time is utilised for teacher training programmes. During this year 46 programmes have been produced by CIET upto November, 1985.

The recruitment of staff in the SIETs is in progress. A six week training course in ETV production was organised at the CIET in collaboration with the Asia Pacific Institute of Broadcasting Development, Kualalumpur from April, 22 to June 1, 1985. A similar course is proposed to be organised in April, 1986. An intensive training course in specific areas of ETV production has been commenced at the Space Applications Centre, Ahmedabad in February, 1986 for a duration of three months. The SIET personnel already trained at CIET are participating in this course.

Computer Education in Schools

The Pilot Project for introducing Computer Literacy And Studies in Schools (CLASS) launched during 1984-85 in collaboration with the Department of Electronics in 250 Higher Secondary Schools from all States/ Union Territories was continued in 1985-86 with an addition of 500 schools and 8 Resource Centres.

The Resource Centres continued to organise training of teachers and provide logistic and back-up support to the schools. The funds required for the project were made available through the Department of Electronics who are also looking after the procurement of hardware which is now being manufactured indigenously by Semi-Conductor Complex Ltd., Chandigarh. The responsibility for installation and maintenance of the computer systems continued to rest with the Computer Maintenance Corporation. The academic and management aspects of the project are looked after by the Ministry of Human Resource Development through NCERT which has been nominated as the nodal agency at the National level to provide academic input and supervision.

The first round of the training was organised at 41 Resource Centres in June-July, 1985 and about 700 teachers were trained. For the remaining teachers the training was held during September-October, 1985. The computer systems for the new schools and Resource Centres are being installed. The CMC has developed the Hindi ROM which is being supplied to all schools. Other language version ROMs are also being developed by CMC which will be supplied to the schools according to their requirement. Ten software packages developed by the IIT, Delhi, Regional College of Education, Mysore, CMC and some private agencies have been made available in 1985-86 in addition to 14 imported packages duplicated under a licence agreement. The manuals with the software packages are being translated into the regional languages for supply to the schools. Efforts are also being made for the development of a large number of indigenous software packages through Educational Consultants India Ltd., and State Governments for use in schools in the coming years.

Value Orientation in Education

In the context of the erosion of values that has taken place the need for value orientation in education at all levels has been urged. The Ministry of Education had appointed two Working Groups, one to review the teacher training programmes particularly with a view to inculcating moral and social values in the students and the other to consider setting up model schools for imparting moral education as a part of general education on a totally restructured basis. The reports of the Working Groups have been received.

The general approach while dealing with value orientation in education is the following :—

(a) preparation of new instructional materials;

(b) special preparation of teachers for introducing value orientation in education; and

(c) setting up of special institutions to give practical shape to this effort.

During 1984-85 the Ministry of Education has sanctioned grants to the Ramakrishna Institute of Moral and Spiritual Education, Mysore, Sri Sathya Sai Bal Vikas Education Trust, Bombay and to Bangavani, Nabadwip (West Bengal) for maintenance and running of these institutions for teacher training. The Ministry has also prepared a scheme for giving grant-in-aid to institutions working in the field of value-oriented education.

The NCERT has been working on preparation of a model scheme on moral education. A guide for the development of curriculum of moral education for schools has already been prepared for classes I-XII by the NCERT. NCERT propose to set up a separate cell for this purpose so that they act as the academic wing for introduction of moral education in the country. Pending the establishment of this cell, the Indian Council of Philosophical Research have taken over the task of organising seminars/ workshops in the field of value-orientation in education so as to prepare material for institutions. NCERT is also bringing out supplementary books on moral education. Steps have been initiated for developing instructional materials in the form of charts, films, etc.

Population Education Programme

The National Population Education Programme launched by the Government of India with effect from April 1, 1980 has been continued in the Seventh Five Year Plan. The Programme which is designed to introduce population education in the formal system of education with a view to creating in the younger generation an adequate awareness of the population problems and realisation in this regard of its responsibilities towards the nation is now being implemented in almost all the States/Union Territories.

The Government of India have set up a National Steering Committee with overall authority for coordination as well as implementation of the programme. Eight meetings of this Committee have been held so far.

At the National level, audio-visual materials including 264 slides and taped commentary in Hindi and English languages were prepared and distributed among the States.

A survey for development of curriculum on population education was conducted at the National level, the study of which could identify the status of population related materials in the school syllabus and textbooks both in school and teacher education areas. NCERT also published a document entitled "Plug Points for Population Education in School Curricula" and the same was placed before the States and Union Territories as models, on the basis of which the States/Union Territories, initiated the activities of curriculum development. Lessons on the themes of population education were also incorporated in NCERT textbooks at different school stages. Some sample lessons in population education were also developed at four National Workshops and they were circulated among States for their use in the development of such lessons for their textbooks. A publication entitled "Population Education" for Teachers was also brought out at the National level which contained the draft syllabus in population education for B.Ed./B.T. i.e. a pre-service teacher training course. A curriculum for Elementary Teacher Training Institute was also developed. In addition, guidelines, and curriculum outlines for B.Ed./M.Ed. courses were also developed at national level.

At the State level 25 States and Union Territories have developed comprehensive curriculum in population education for primary middle and secondary stages and 21 of them have been able to integrate population education elements into their on-going syllabus. Seventeen States have developed textbook lessons on population education either by revising the existing lessons or by preparing new lessons. Another audio-visual programme entitled "India, My Children, My Future" was also produced in collaboration with UNFPA. Taking into consideration the classes in which the textbooks with population education lessons are being used, about 77.01 million are being exposed to population ideas, which is 66.09% of total student population. Nearly 38 titles at National level and 300 at state level of instructional materials for different target groups have been printed and mimeographed and are being used. States have oriented nearly 5,63,261 key/resource persons and teachers of elementary and secondary schemes. In the non-formal education also they have developed considerable amount of material.

Review of School Textbooks

The programme of evaluation of textbooks from the standpoint of national integration was initiated in 1981, to ensure that the textbooks promote national integration and do not militate against the national unity. To begin with, the review of textbooks was confined to textbooks in history

and languages. The review is being undertaken on a decentralised basis by the State Governments on the guidelines prepared by the NCERT. The review is being undertaken with a view to identifying and eliminating materials and approaches which may directly or indirectly perpetuate untouchability, casteism, communalism, religious intolerance, linguism, racialism regionalism etc.

The programme has been completed in almost all the States/Union Territories, except Manipur and West Bengal where the evaluation work from class VI onwards is in progress.

The States/Union Territories have now been requested to extend the programme of evaluation of textbooks in other subjects also. They have been requested to have a built-in system for continuous evaluation of textbooks as a part of the system of textbook preparation and development.

Grant of Financial Assistance to Voluntady Organisations Working in the Field of school Education

The scheme for grant of financial assistance to voluntary organisations working in the field of school education, which was started in the First Five Year Plan, remained in operation till 31st March, 1972. Since 1972 no fresh grants are being given to voluntary organisations. Only old commitments are being honoured.

Under the above scheme, grants to such organisations which are doing prime work in the field of education, are also sanctioned on the basis of recommendations made by the Special Review Committee appointed for the specific purposes.

Central Scheme of Assistance to Voluntary Organisations Working in the Field of Moral Education

Government of India have laid great emphasis on building up of character of students through all curricular and extra-curricular activities. Various steps have been taken for inculcation of moral education both through Government and non-Government organisations. Keeping this in view, Government have formulated a scheme for grant of financial assistance to voluntary organisations engaged in the field of moral education. Under this scheme, the financial assistance is given to voluntary organisations not exceeding 50 per cent of the non-recurring expenditure, subject to a ceiling of Rs. 2.5 lakhs per approved project. For recurring expenditure, the assistance from the Central Government will be limited to 50% of the total estimated expenditure subject to a ceiling of Rs. 5.00 lakhs per annum.

NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH & TRAINING

National Council of Educational Research and Training (NCERT), established on September 1, 1961, is registered under the Societies Registration Act XXI (1860). The major objectives of the Council are to assist and advise the Ministry of Human Resource Development in formulating and implementing policies and programmes in the field of school education. NCERT undertakes and supports research, development, training and extension in the areas, such as, curriculum, examination reforms, talent search, non-formal education, textbooks, vocationalisation, value orientation, integrated education of disabled etc.

Unicef-assisted Projects

A new Master Plan of Operations (1985-89) has been launched from January, 1985 onwards. During the year, the following six projects have been implemented in the participating States and Union Territories with the help of SCERTs, SIEs, SISEs and some of the University departments.

Nutrition, Health Education and Environmental Sanitation (NHEES)

In seven States and one Union Territory, about 400 teachers were trained in the use of specially prepared instructional material. Sixteen different titles were prepared and community contact programmes were conducted in order to disseminate messages relevant to nutrition health and sanitation. Action has been initiated to integrate the curriculum and textual material developed into the existing primary curriculum/primary teacher education curriculum.

Primary Education Curriculum Renewal (PECR)

The project was continued in 18 States and 5 Union Territories. About 3000 teachers and teacher educators were trained, and one hundred and eighty eight publications covering textbooks, workbooks and teacher's guides have been brought out during the year. A national study has been undertaken to assess the impact of the project on enrolment, retention stagnation

and pupil achievement in the experimental schools in 24 participating States/ Union Territories. The data collected is being analysed.

Developmental Activities in Community Education and Participation (DACEP)

Activities related to the development and testing of educational programmes to meet the minimum educational needs of learners in the age group 3-6, 6-14 and 15-35 were continued in 18 States and 2 Union Territories. As a result(980 teacher educators, block-level officers and community workers were oriented, and 50 publications for use of learners in community centres were brought out. The evaluation report of the project carried out by the A. N. Sinha Institute of Social Studies of Patna has been received.

Children's Media Laboratory (CML)

The development of inexpensive material of educational and entertainment value at the pre-school stage was continued. Some more picture books, graphic materials, song books, audio and slide tape programmes on a variety of new themes were developed. Some of these materials have been tried out in tribal, rural and urban areas, and steps are being taken to disseminate these to ICDS centres in the selected States. National and State level toy making competitions were conducted during 1985.

Early Childhood Education (ECE)

Eight States were helped to organise training courses of pre-school teachers, orientation of headmasters and supervisors, and refresher courses of teachers for preparing the low cost learning materials. In addition, NCERT conducted several training programmes for supervisors, teachers and helpers for Municipal Corporation of Delhi in early childhood education and supplied play material to 10 experimental centres.

Comprehensive Access to Primary Education (CAPE)

Activities relating to the development of relevance based and problem centred curricula and learning episodes were continued in 16 States and 2 Union Territories. About 50 modules have been developed by the States/ Union Territories, while 11 modules for learning Hindi as the mother tongue in the self-learning format have been developed by DPSEE, NCERT.

In Bihar, Orissa and Tamil Nadu, 235 learning centres were established. The facilitators of these centres were oriented to the different aspects of running the centres, including content and teaching-learning process. The first phase of the project (1981-84) is being evaluated by Centre of Advanced Study in Education, M. S. University, Baroda.

Integrated Education for the Disabled (IED)

Activities under this project were initiated at NCERT during the second quarter of 1985. A National Conference of Coordinators/Officers-in-Charge of the IED scheme in the States/Union Territories was organised, in which 13 States/Union Territories participated. Some training modules have been prepared. A framework for the analysis of the content for the adaptation of instruction for visual and hearing impairment by teachers was developed.

In addition, a three month inservice training course for the key personnel in IED has been organised.

Teacher Education

A number of training programmes were organised for teacher educators and other personnel. About 266 teacher educators both at the elementary and secondary level were trained/oriented during the year. Several meetings were organised to develop textual/resource materials in respect of content-cum-methodology, value-oriented teacher education, SUPW and college teaching.

Education of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

Five orientation programmes were organised in which 71 elementary and secondary teacher educators were exposed to the tribal life, socio-cultural life, problems and tribals and tribal education and also the organisation of NFE programmes in the tribal areas.

Developmental and Extension Work in Social Science and Humanities

Special Projects on Reading to Learn in English and Hindi, National prize competition for children's literature, Seminar Reading competition for teachers and Evaluation of School textbooks from the view point of national integration were carried out. Status surveys of various school subjects, instructional materials and methods of teaching in the States/Union Territories were taken up. The development of the National Curriculum Framework was taken up during the year on a priority basis. One National seminar and four regional seminars were organised in this connection and a draft curriculum framework has been finalised. Steps have also been taken

to prepare/revise syllabi and instructional materials in different subjects for the primary and lower secondary stages of the school education.

For the elective and core courses at Class XII of CBSE, five books for Hindi as the Mother Tongue were prepared. A set of three workbooks in Hindi for developing writing skill in the beginners were developed. Two Hindi textbooks—One for class III in Arunachal Pradesh (alongwith a workbook) and another for class IV—were completed. An English supplementary Reader for class XII (core course of CBSE) and the New Dawn Readers II and Supplementary Reader II were prepared for Arunachal Pradesh. A new textbook in Sanskrit for class XII for CBSE was also submitted for publication. A teacher's guide to teach Sanskrit in classes V to VII was prepared. A textbook in Urdu for class IV has been prepared.

A publication entitled "India's Struggle for Independence : Visuals and Documents" was brought out comprising 62 visual panels covering the entire period and various facets of the freedom struggle. This has been brought out in two forms— a bound volume as an album and a portfolio of loose sheets for teaching.

A revised version of "Indian Constitution and Government" for classes XI—XII was brought out. Besides, two books in geography for class XI and four books in economics for classes IX and X were completed for publication. Under the special project "Reading to Learn" ten books in English and 20 books in Hindi have so far been prepared.

Developmental and Extension Work in Science and Mathematics

For the preparation of the Physics, Chemistry, Mathematics textbooks for class X for CBSE, four workshops were organised. The manuscripts of Teacher's Guides for class IX in Physics and Biology were also finalised in two separate workshops. Volume II of class X Biology book was completed. The existing Physics syllabi for classes I to X of 10 States was reviewed. A similar workshop was organised to examine horizontal and vertical linkages in the Chemistry and Mathematics syllabi.

More than 100 teachers from minority schools were trained in the new areas like Environmental Education, Individually guided system of instructions, Computer Literacy and out-of-school activities. Post training workshops of participants trained under All India Science Education Programme (AISEP), Pre-orientation of 18 fellows for AISEP was also conducted. NCERT organised seminars by prominent academics such as Prof. Peter Kelly, Dr. Ashok Khosla, Dr. M. Chakravarty. Twelve books in Physics, Chemistry, Biology and Mathematics for primary and middle levels and six brochures and journals were published.

National Science Exhibition

The fourteenth National Science Exhibition for children was held at Maharana Bhopal Stadium, Udaipur, in November, 1985. The main theme of the Exhibition was "Indigenous Technology in Development", and exhibits from all the States and Union Territories of the country (Excepting Lakshadweep) were displayed.

Educational Psychology, Counselling and Guidance

In the regular Diploma course in Educational and Vocational Guidance, 26 trainees, inclusive of four SC/ST trainees completed the course. They will work as counsellors in schools in their respective States/Union Territories or main agencies involved in guidance work or training in guidance and counselling. NCERT organised three seminar-cum-workshops of managers and principals of educationally backward minorities managed schools to orient them for the introduction of guidance services in their schools. In a refereshcr course, 22 participants were exposed to the application of communication and educational technology, elementary and secondary teacher educators and SCERT/SIE personnel from Maharashtra, Tamil Nadu and North Eastern States were trained in the area of learning and development.

Fifteen papers, comprising materials prepared for the guidance of primary school children for communication to teachers through mass media were prepared and will be published in the special issue of "Journal of Primary Teacher" under the title "Guidance in Primary Schools". The same material will be utilised for radio and TV presentation. A question bank for the psychology course at the +2 stage, consisting of about 1000 items, has also been prepared.

Improving Evaluation Practices and Examination Reform

A national seminar on open book examination was organised in which 21 officials from Boards, SCERTs/SIEs Directorates of Education and Colleges participated. Six workshops were conducted to develop objective type items, question banks, comprehensive exercises for various subjects and different classes.

Training related to the various aspects of examination reform such as education evaluation, improvement of external examination, item writing, paper setting, sample survey methods was imparted to 679—master teachers, teacher educators, board officials and other functionaries from different States/Union Territories. Two special training programmes in educational evaluation were conducted for senior army, navy and air force officers and teachers of minority community schools.

National Talent Search and Creativity

The National Level Examination for students in Class X was conducted at 29 centres for the candidates who were recommended by the States/Union Territories. On the basis of the results in this examination, about 1500 candidates were interviewed. Finally, 750 candidates were selected for the award of NTS scholarships.

A training course on identifying, encouraging and nurturing creative potential at the elementary stage was organised in which 32 elementary teacher educators from Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh participated. A similar course organised at the regional level was attended by 20 secondary teacher educators.

Vocationalisation of Education

Four short term courses for vocational teachers in Horticulture, Pedagogy, commerce and Electronics Technology were organised which were attended by 100 participants from Karnataka, Maharashtra and Andhra Pradesh. These helped in upgrading their knowledge and expertise.

Six orientation programmes—four on vocationalisation and two on SUPW—for 253 participants and officials from different States were conducted to familiarize them with the concept, objectives, annual plans, selection of activities and strategies for implementation of the scheme. Consultancy services were offered to various organisations.

Six instructional-cum-practical manuals each in the area of Dairying and Sericulture were brought out. Minimum competency based curricula in Plant protection, Plantation Crops and Management, Multi Rehabilitation worker and Ophthalmic Technician, were developed. Supplementary Readers in Micro Biology and Communication Diseases have also been prepared.

Non-formal Education

An annual conference of the educationally backward states on NFE was organised to highlight field problems relating to the implementation of the Centrally Sponsored Scheme. At the instance of the Ministry, a comprehensive study of academic aspects of NFE has been undertaken. Three science books, three social sciences books and three language books have been finalised for the learners at the middle level. Attempt has been made to cover all content of these three subjects in only three books for each equivalent class i.e. VI, VII and VIII in an integrated fashion.

Community Singing

NCERT continued to organise camps for imparting training in community singing. Eight hundred and sixty teachers from all over the country were trained. In addition, 140 teacher's trainers have been trained to act as key persons to propagate this movement further. A recorded cassette 'Childhood Memories of Smt. Indira Gandhi' is being distributed to all primary schools.

Educational Research and Innovations

At the recommendation of ERIC, approval has been accorded to 10 new research projects. Support to 97 ongoing projects continued, while seven research projects were completed. A new strategy for research has been implemented.

A national seminar-cum-workshop on problem and issues relating to Universalisation of Elementary Education was organised which was attended by 57 experts from different strata of the society concerned with elementary education. To attract and nurture young, bright and competent behavioural researchers, two research methodology courses were conducted. Two more

would be conducted before the end of the year. To disseminate research information, two special ERIC bulletins were brought out. Seminars on construction of test, workshops to review existing tests and national meets to edit these tests were organised.

Publications

NCERT has so far published 86 school textbooks, supplementary readers, teacher's guides and student workbooks. Another 36 monographs published pertain to research in education. Some of these were reprints. Six journals were continued to be published during the year. A national seminar was conducted together views and suggestions in order to improve upon the existing designs of publications.

Educational Documentation

A workshop was organised to train the library staff of Teacher Training Institutions in improving library services. Nineteen librarians attended the workshop. A curriculum for inservice training of librarians of schools and teacher training institutions has been developed. Five publications were brought out for disseminating information relating to new publications.

International Relations

Under UNESCO sponsored programmes, seven important projects/ studies in the areas of primary education, work and education, education of disadvantaged population, science education and teacher education were undertaken.

A regional seminar was held at TTI to discuss innovations in the school education. A Newsletter on educational innovations has been brought out periodically.

Bilateral cultural exchange programmes were undertaken in the areas of science equipment, educational technology and vocational education. Under this and UNESCO sponsored programme, 16 delegations from different countries were received and study programmes were organised.

Educational Journals

Six journals were brought out. In order to create a favourable climate for educational journalism three national seminar-cum-workshops were conducted which were attended by 50 experts and other participants. Some of them have opted to contribute to the Handbook of Educational Journalism and a Yearbook on Educational Journalism.

Field Services

Seventeen Field units of NCERT organised programmes in experimental projects in schools. A number of experimental projects were scrutinized and sanctioned to schools whose researchers were oriented for the purpose. SC/ ST programmes included orientation of their teachers, headmasters and supervisors. Four regional meetings were organised to study the needs, problems and progress achieved by different States in the priority areas of school education.

Educational Technology

Under project for 'Insat for Education', Forty six programmes for the age group 5—8 and 9—11 and primary school teachers were prepared to feed the satellite thrice a week. One hundred and eighty eight language versions were prepared in Oriya, Marathi, Telugu and Gujarati. Four transmissions were also prepared. Three studies on ETV utilization were undertaken in respect of Maharashtra, Andhra Pradesh and Orissa.

In collaboration with Asia Pacific Institute of Broadcasting Development (APIBD) a six-week training course in ETV production and technical operation was held in which fifty four officers participated.

CIET coordinated planning for building and equipment for SIETs. A national seminar on Educational Audio/Radio programmes for children was organised to share experiences among educationists and producers.

The project on teaching Hindi as the first language through Radio in lower primary schools continued in Jaipur district. Another project of Hindi as the second through Radio was taken up in Orissa.

Activities in the field of distance education and ET for teacher education, preparation of charts, tape slides and low cost aids, compilation of aids etc. were continued. Work on three films, viz., non-formal education, techniques of photography and solar eclipse is in progress. With the purchase of new

films, the total stands as more than 8200. Two educational film festivals were organised to popularise the use of films in teaching.

Regional Colleges of Education

Regional Colleges of Education in Ajmer, Bhopal, Bhubaneswar and Mysore conducted innovative pre-service teacher training courses; inservice orientations and extension programmes, besides research at M.Ed. and Ph.D. levels.

National Foundation for Teachers/ Welfare

The National Foundation for Teachers' Welfare was set up in 1962 with the main object of providing financial assistance to teachers and their dependents in indigent circumstances and to promote their welfare. A decision was taken to build a Corpus of Rupees five crores with the intention to provide a steady source of funds for financing teachers' welfare schemes. The target of Rupees five crores has since been achieved and the funds of the Foundation have now exceeded Rupees nine crores. A Committee has now been set up to suggest the programmes which could be taken up from the Corpus funds.

The Corpus of the Foundation comprises the contributions made by the Union and States/Union Territories and 20% of the collections made by States/Union Territories who retain the remaining 80%. At its meeting of July 1985, the General Committee decided that 90% of the collections made by the States/Union Territories would be retained by them for assistance to their teacher and only 10% would be transferred to the Central Corpus. A campaign for the collection of funds is organised by the Education Department and the States/Union Territories on the Teachers' Day which is celebrated on September 5, each year throughout the country. As usual collection drive was launched by the Education Department and the State/Union Territory Governments on the 5th September, 1985.

The Foundation also gives awards every year to three teachers who have rendered meritorious service of not less than 30 years. The award was instituted in memory of late Prof. D. C. Sharma, an eminent educationist and one of the founder members of the Foundation. The award consists of a certificate of merit and cash prize of Rs. 1000/-. Three teachers have been selected for the Prof. D. C. Sharma Memorial Award for the year 1985.

According to available information from 14 States/Union Territories, a sum of Rs. 15,76,237.00 was disbursed during 1984-85 to about 1168 teachers/dependents etc. as financial assistance by the Working Committees of National Foundation for Teachers' Welfare in the States/Union Territories. A sum of Rs. 27,77,833.58 was collected during 1984-85 by these States/Union Territories.

Cultural Exchange Programme in the field of School Education

The programme is being implemented by the Ministry in consultation with NCERT/State Governments etc.

The following deputations/delegations were sent abroad by the NCERT under the CEP.

— A 3-member delegation consisting of Dr. Braham Prakash, Lecturer, DESM, Shri B. K. Dutta, Work Experience Teacher, RCE, Bhubaneswar and Shri Harender Singh, Work Experience Teacher, RCE, Bhopal visited GDR from March 5—19, 1985 to study design and development of science equipment, educational technology and vocational education under item No. 23 of the INDO-GDR Cultural Exchange Programme for 1982-84.

— One-member Mauritius delegation visited NCERT in October 1985 to discuss problems relating to cooperation in the areas of teacher education, curriculum development, second language learning, appropriate pedagogy & development of a programme of Indian language, culture & civilisation under the provision of Indo-Mauritius Cultural Exchange Programme for 1984-86.

— A three-member Soviet delegation visited NCERT from November 14—23, 1985 under Indo-USSR Cultural Exchange Programme to study the modern state and tendencies of development of School Education in India and get acquinted with system of advanced studies for pedagogical staff under Item 35 of the Indo-USSR Cultural Exchange Programme for 1985-86.

Scheme of Integrated Education for Disabled Children

The Scheme of Integrated Education for Disabled Children provides financial assistance for education of handicapped children in schools meant for the normal children. Under the Scheme 100% financial assistance is available to the States/Union Territories to meet costs of salary of teachers, setting up of resource rooms and assessment rooms for the schools/institutes and equipment, stationery allowance, reader allowance (for blind students) transport allowance, escort allowance (for severely handicapped students) and hostel facilities for the disabled children. Assistance is also given through UGC to the selected Universities/Institutes, Colleges for running courses in Special Education for the teachers of the handicapped children. Facilities for training in Special Education are also available in NCERT and its Regional Colleges.

Grants under the Scheme have so far been given from time to time to the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Delhi and Mizoram as well as to all the State Governments except J & K, Meghalaya and Punjab.

Educational Concessions to the Children of Officers and Men of Armed Forces killed or Disabled during Hostilities

The Central Government and most State Governments and Union Territories continued to offer educational concessions to the children of Defence personnel and para-military forces killed or permanently disabled during Indo-china hostilities in 1962 and Indo-Pakistan hostilities in 1965 and 1971. In the year 1985-86, 23 students received such concessions.

Community Singing Movement

A Scheme for developing community singing as mass movement among school children was launched in 1983-84 with the objectives (i) to make the children sing in unison, songs in different Indian Languages, thus strengthening the spirit of national integration; (ii) to inculcate national perspective in children; (iii) to make them appreciate unity in diversity and imbibe in them love for country's cultural heritage; and (iv) to forge school children into a musical community.

The Scheme is being implemented through NCERT. Under the scheme, NCERT has been organising national integration camps on community singing for the music and music minded teachers drawn from different States of the country. Since June, 1982, NCERT has so far organised 61 camps in different parts of the country and more than 3000 teachers have been trained in community singing. According to the present syllabus 15 songs selected from different Indian languages are being taught to the teachers attending camps by the music experts.

NCERT has trained 860 teachers all over the country up to December 1985. Each one of the teachers receiving the training in the camp is expected to teach these songs to at least 1000 children of his/her school. NCERT has also been able to prepare 140 teachers trainers during this year from all States of the country. These trainers will act as key persons for their respective States in propagating the scheme of community singing.

To supplement the teaching of community songs to the children, the teachers participating in the camps are being provided free of cost a printed book with musical notations, a recorded cassette with 15 selected songs and a tape recorder with a view to developing teaching learning situations in their class rooms. Under this scheme a recorded cassette titled "Childhood Memories of Mrs. Indira Gandhi" is being distributed to all the primary schools.

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

The Board of High School and Intermediate Education, Rajputana including Aimer, Mewar, Central India and Gwalior, was established in 1929 by a Resolution of the Government of India. In 1952 the Board was given its present name "The Central Board of Secondary Education". From time to time its constitution was changed and jurisdiction extended so that the Board could play a useful role in the field of Secondary Education. Its jurisdiction extends to the whole of the country. Some of the main roles and functions of the Board are to affiliate institutions from all over the country for the purpose of examination, arrange inspection of schools for granting affiliation, conduct examinations, prescribe courses and syllabi, organise orientation programmes, undertake development and publication of text-books when found necessary.

The Board's affiliated schools include all the Kendriya Vidyalayas, all Sainik Schools, Schools managed by the Public Sector Enterprises, by the Defence Ministry, Government and aided schools of Union Territories of Delhi, Chandigarh, Arunachal and Andaman & Nicobar Islands, as well as most of the member schools of the Indian Public Schools Conference and schools under private management, and about 30 schools in foreign countries, catering to children of Indian diplomatic staff as well as other Indians working abroad. The total schools affiliated with the Board till November 1985 are 2047.

2,18,128 candidates appeared at the CBSE Examination in 1985. In order to ensure foolproof security of question papers, the conduct of examinations is carefully supervised to prevent leakage of question papers, and loopholes in the fair conduct of examinations or processing of results have been plugged. Through training and orientation programmes to paper-setters and examiners, the validity and reliability of the Board's examinations have been greatly strengthened. Centralised evaluation is in vogue for the Senior Secondary Examinations. Planning is afoot to introduce this at the Secondary level as well. Most aspects of the examination, both pre and post examination work, including Admission Cards, Marks Statements and Certificates are computerised and computer printed.

The Board has developed and brought out a number of publications, mainly Curriculum Guides, Learning Objectives for individual subjects for both secondary and senior secondary schools which identify specifically the learning outcomes for each topic/unit and Sample Question Papers. These publications have been much appreciated and well used by the schools, as evident from the large demand for them. Now the board has taken it as normative that every subject will have learning objectives developed. The Academic Branch of the Board also organised Orientation Programmes for Principals/Teachers and regional and national conferences.

Open School

To respond to the needs of a large and growing number of working adults and school drop-outs, Central Board of Secondary Education started the Open School in 1979. Registration followed two years later after materials were prepared and the first examination was conducted in 1983. Open School has been gaining popularity and practically every State and Union Territory has students of the Open School, though a sizeable number of students is from Delhi. Currently, the school has an enrolment of over 20,000 students. Examinations are conducted twice a year. Being an Open School, it has a flexible approach and credit accumulation facility, so that students can appear in 10 full examinations spread over five years to accumulate pass in five subjects for certification. Responding to the demand, recently Central Board of Secondary Education has begun preparations for introduction of course at the plus two stage.

Open School is also seeking the cooperation of established educational institutions and Shramik Vidyapeeths. The personal contact programme has also been considerably improved by fixing Resource-cum-study Centres in selected institutions for providing teaching to the students on a more regular basis on Sundays and other gazetted holidays spread over a period of 4—5 months. Fifteen such centres have been set up so far to cater to a population of about 6000 students.

A National Pilot Training Workshop on Distance Education was organised by the Open School in collaboration with the Department of Education and the UNESCO from August 26 to September 9, 1985, which was attended by senior level administrators and officers from 11 States.

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

To provide uniform facilities of education throughout the country for the children of transferable Central Government employees, including defence personnel, the scheme of Central Schools having a common syllabi and media of instruction was approved by the Government of India in November 1962. To start with 20 Regimental Schools, were taken over during the academic year 1963-64. Subsequently, in 1965, Kendriya Vidyalaya Sangathan was set up as an autonomous organisation to establish

—759 Deptt. of Edu/85

and run the Kendriya Vidyalayas. With the opening of 41 new schools during 1985-86 the total number of Kendriya Vidyalayas now is 540. The number of students on rolls in all Kendriya Vidyalayas was 3,66,885 (as on 1-4-1985).

Education is free in Kendriya Vidyalayas up to Class VIII. The amount of tuition fee for higher classes is linked to the pay of the parents in case they are employed in Central Government or Central Public Sector Undertakings/Autonomous Bodies. In other cases tuition fee at flat rate is charged. However, students belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and children of teaching and non-teaching staff of the Kendriya Vidyalayas are not charged any tuition fee. Although Kendriya Vidyalayas are not residential schools, hostel accommodation is available in 13 schools.

Kendriya Vidyalayas have been making concerted efforts to improve the professional competence of all categories of non-teaching, teaching and supervisory staff by organising in-service courses and workshops. During 1984-85 58 in-service courses were conducted which were attended by 3176 Principals, Assistant Commissioners, Education Officers, Teachers etc. Besides, about 216 teachers from different Kendriya Vidyalayas attended Orientation courses organised by the Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi. It has been proposed to conduct 72 In-service Education Courses for about 3460 teachers and 4 Orientation courses, during 1985-86. Two teachers of Kendriya Vidyalayas were included in the national awards for teachers during the year. Besides Kendriya Vidyalayas also give seven Incentive Awards every year to its teachers and various categories of non-teaching staff.

The pass percentage of the Kendriya Vidyalaya students in All India Secondary School Examination of CBSE in 1985 was 86.3% as compared to 77.% in the case of other students. At the All India Senior School Certificate Examination, 1985, the pass percentage of Kendriya Vidyalayas was 88.7 as compared to general pass percentage of 78.5. Kendriya Vidyalayas students got good positions in merit lists in all the examinations. A large number of students secured admissions in National Defence Academy, engineering and medical institutions.

Besides academic excellence, Kendriya Vidyalaya Sangathan emphasises on games and other activities for all-round growth of personality of students. Various games and sports events at school, regional and national levels were organised. Coaching camps in various games and sports were also organised. Physical Education Teachers were also trained in various disciplines both in India and abroad. Cash scholarships of Rs. 50/- per head per month were given to 90 students found talented in games and sports. A special cash prize of Rs. 100/- was awarded to a student for winning a bronze Medal in the School Games Federation of India Athletic Meet.

Troops of scouts, guides, clubs and bulbuls have been opened in most of the Vidyalayas. Preliminary training camps for the teachers were organised at regional level. Camps for advanced training was organised by the Sangathan at Pachmarhi in collaboration with Bharat Scouts and Guides. A number of trekking and mountaineering programmes were organised which were well participated by the students. More than 10,000 students underwent rock climbing training. 209 Adventure Clubs are functioning in different Kendriya Vidyalayas at present.

Kendriya Vidyalaya Sangathan also organised art and painting exhibitions and the best exhibits were sent for participation in exhibitions organised by the Republic of Korea and the Soviet Land Nehru Children's Art exhibition.

CENTRAL TIBETAN SCHOOLS ADMINISTRATION

Central Tibetan Schools Administration (CTSA) was set up in 1961 to run, manage and assist institutions for the education of children of Tibetan refugees in India. The Administration runs 4 residential Schools at Dalhousie, Darjeeling, Mussoorie and Simla and 32 days Schools (including 14

Branch Schools) in different parts of the country. Schools having Class IX and above and affiliated to the Central Board of Secondary Education prepare students for All India Secondary School Examination and All India Senior School Certificate Examination. NCERT curricula, courses and textbooks are followed up to Class VIII. In addition to English, students are taught Hindi and Tibetan languages. The Administration also gives assistance in the form of grant-in-aid to few institutions being run for the benefit of Tibetan Refugees Children.

The total number of students studying in the schools run by CTSA is 10212, of whom, 1599 are boarders and 8613 day scholars. In residential schools, apart from boarding and lodging, daily necessities and medical facilities are also provided free. Mid-day-meals, free textbooks, stationery etc., are also provided to all students including those studying in day schools. The Administration also awards 15 scholarships to Tibetan students for higher studies. The results of the CTSA schools in Secondary School Examination and All India Senior School Certificate Examination for the year 1985 was 65.9% and 63.3% respectively. For the benefit of teachers refresher courses, seminars and symposia are also organised from time to time. The Administration also arranges sports meet/educational tours (Zone-wise) for the benefit of the students.

BAL BHAVAN SOCIETY

The Bal Bhavan Society, India, is an autonomous organisation fully financed by the Government of India. The Society was established to provide facilities to the children during their free hours to pursue creative activities in Fine Arts, Science, Physical Education, Performing Arts, Museum Techniques, Photography, etc. In support of these basic activities, Bal Bhavan is running Vocational Training Resource Centre to train teachers, trainers, supervisors etc., in providing creative education through Bal Bhavan media. Camping hostel facilities are provided to the children and teachers coming from outside for participation in Bal Bhavan activities.

Against an enrolment of 11135 children in 1984-85, 10684 children (for 7 months only upto 10/85) were enrolled in 1985-86 in the Bal Bhavan. 12136 children (for 7 months only upto 10/85) were enrolled in 47 Bal Bhavan Kendras in 1985-86 against 17943 children enrolled in 1984-85 in 44 Bal Bhavan Kendras.

During June 1984, children between the ages 6-12 participated in the World Peace & The Round Table Foundation at San Francisco, USA and won award for a painting entitled "Love is Peace-Peace is Love". 41 children participated in the Workshop on Education through Nature in July 1984 and produced 22 models relevant to the Challenging theme. Bal Bhavan organised a six-day integration camp from September 9-14, 1984 for the Child Artisens which was attended by 2000 children from various part of Delhi. A special workshop was organised for the South Delhi Polytechnic Teacher Trainees "Music and Movements". The objective of the workshop was to bring home to the participants the need to understand children, and their requirement for a lively atmosphere where they can learn as well as express themselves freely. Bal Bhavan Society also organised a Rural Children's creativity fair from March 23-27, 1985 at Jawahar Bal Bhavan, Mandi. During 1984-85, 36 workshops were organised by the National Training Resource Centre.

To supplement school education and help a child to be rational, creative and constructive and develop a scientific temper, National Children Museum organised 4 Exhibitions entitled "Syllabus Oriented Exhibitions", "Thematic Exhibitions", "Exhibitions of Children's Work" and "Exhibitions of Rural Children's Work".

A nine-week children's Film Festival was organised by the National Children's Museum in collaboration with the Children's Film Society. The festival provided nearly 800 children every day, an opportunity to see a rare selection of films.

Physical Education and Yoga : Policy and Programmes

Physical Education and sports are today accepted as an integral part of Education all over the world. A new national sports policy, covering *inter-alia* physical education and yoga, recently adopted as a Government Resolution makes it the duty of the Centre and State Governments to accord very high priority to promotion of sports and physical education in the process of all round development. The new policy enjoins upon the Central and State Governments to provide necessary sports facilities and infrastructure on a large scale to fulfil the need of every citizen for participation in these activities.

In the context of the high priority attached for the first time to promotion of sports and physical education in the new national sports policy as well as the thrust of the approach paper of the VII Five Year Plan to upgrade our human resource, substantially higher investments on physical education and yoga have been envisaged in the VII Five Year Plan. A special thrust is proposed to be given to the strengthening of the teacher training programmes in physical education and in promotion of mass participation of students in physical education and sports programmes.

The salient features of the programmes of physical education and yoga implemented during the year are as under :

Development of Lakshmibai National College of Physical Education, Gwalior (LNCPE)

The LNCPE was established by the Government of India in 1957 as a national institute of physical education with the object of training high quality leadership in physical education for educational institutions and other agencies. The College is fully residential and co-educational institution, offering teacher training facilities at the graduate, post-graduate and doctoral level. During the year 1985-86, the total strength at the College was 407, including 97 girls. Since its inception in 1957 and upto the academic year 1984-85, the College has produced over 2,500 graduate and post-graduate teachers including 461 girls. The College alumn includes 37 M. Phils and 7 PhDs in Physical Education. Since 1982-83, it also enjoys the status of an autonomous college. Besides its regular teacher training programme, the College provides extension services and refresher courses for the in-service personnel. With a view to giving due emphasis on research programme a full-fledged research division established at the College continues to render useful services for promotion of research programmes. Further, the College continues to implement on agency basis the central programmes of national physical fitness programme, national prize competition for the published literature on physical education and sports on behalf of Central Government. The National Resource and Documentation Centre in Physical Education, established at the College during 1983-84, also continued to serve as the clearing house for professional information in physical education and sports.

On a suggestion from the Government, the Governing Body of the College, namely, the SNIPES set up a Review Committee to assess the working of the College and to make recommendations for its projected development during the coming years. The Report of the Committee has been approved by the College Governing Body.

Strengthening of Physical Education Teacher Training Institutions

This scheme is a continuing scheme from the Second Five Year Plan and provides finnancial assistance to physical education teacher training institutions, both Government as well as the non-government, to cover expenditure upto 75% on specified projects for improvement of physical facilities and other development expenditure, like construction of gymnasium hall, research laboratory, hostel building, administrative block, development of playground, purchase of sports/laboratory/research equipment, subject to specified ceilings of Central Government's grants for each project.

Keeping in view the rise in cost of construction and to ensure whether the deserving institutions are substantially assisted for improvement of their physical facilities, revised ceilings of Central Government's Grant are proposed to be adopted from the next year.

Promotion of Yoga

Taking cognisance of potentialities of Yoga in promotion of physical fitness, the Central Ministry of Human Resource Development has been implementing since the Second Five Year Plan a Scheme for Promotion of Yoga as a part of Ministry's over all programme of development of physical education in the country. The Scheme provides financial assistance to yoga institutions of all-India character for maintenance as well as development expenditure on promotion of basic research and/or for teacher training programmes in the various aspects of Yoga other than the therapeutical aspects. Financial assistance to yoga institutions for promotion of yoga therapeutical aspects is being extended by the Ministry of Health and Family Welfare. Kaivalayadhama Sriman Madhya Yog Mandir Samiti, Lonavla (PUNE), continues to be assisted under the scheme, both for its maintenance and developmental expenditure for research and teacher training programme. On a suggestion from the Government, the SNIPES, in its role as a national level advisory body on physical education and yoga, has set up a Review Committee to assess the working of the Samiti and to make recommendations for its projected developments during the coming years. The Report of the Committee has since been approved by the SNIPES.

NCC Junior Division Troops for Public/ Residential Central Schools

The expenditure on the maintenance of NCC Junior Division Troops in Central/Public and Residential Schools is shared between the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) and the Ministry of Defence on 40 : 60 basis. The Directorate General NCC is reimbursed by the Ministry for the expenditure incurred in this behalf in this ratio.

Society for the National Institutes of Physical Education and Sports (SNIPES)

The Society for the National Institutes of Physical Education and Sports (SNIPES) was set up in 1965 as an autonomous body to look after the administration of the two national institutes of physical education and sports, namely, the Lakshmibai National College of Physical Education, Gwalior and the Netaji Subhas National Institute of Sports (NSNIS), Patiala. The Board of Governors of the SNIPES is at present headed by Shri V. C. Shukla, Member of Parliament, who also enjoys the rank of a Cabinet Minister as Chairman, SNIPES which is personal to him. The SNIPES held during the year 4 regular meetings in addition to the Annual General Body Meeting. The Standing Committees of the SNIPES as well as other committees set up by it also met from time to time to attend to their assignments.

The SNIPES continues to function as a national level advisory body to Government on Physical Education and Yoga.

CHAPTER 3

HIGHER EDUCATION AND RESEARCH

Coordination and determination of standards in higher education is a subject in the Union List and is a special responsibility of the Central Government. This responsibility is discharged mainly through the University Grants Commission which was established in 1956 under an Act of Parliament. Nine Universities are at present functioning under Acts of Parliament. Besides, the Central Government have established agencies for promotion and coordination of research efforts in specialised fields. There are four such national agencies at present, namely the Indian Council of Social Science Research, Indian Council of Historical Research, the Indian Council of Philosophical Research and the Indian Institute of Advanced Study. The Central Government have also been implementing a number of schemes in the field of higher education and research, including those relating to academic collaboration between India and other countries.

A. UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

Trends and Growth of Higher Education

The student enrolment in universities and colleges increased from 33.59 lakhs in 1983-84 to 35.39 lakhs in 1984-85. The number of students in the University Departments was 5.95 lakhs and in the colleges 29.44 lakhs.

Enrolment in the Faculty of Arts constituted 40.4% of the total enrolment. In the Faculties of Science & Commerce the percentage was 19.7 and 21.0 respectively. Enrolment at the first degree level was 31.14 lakhs (88%); at post-graduate level 3.36 lakhs (9.5%); at research level 0.39 lakhs (1.17%); and at diploma and certificate level 0.49 lakhs (1.4%). Compared to 1983-84, the major increase was only at the first degree level.

The number of teachers increased to 2.25 lakhs. Of these, 0.49 lakhs were in the University Departments, University Colleges and the rest in the "Affiliated Colleges". Of the 48733 in the universities 5165 were professors, 11,159 were Readers, 30408 were Lecturers and 2001 Tutors and Demonstrators. In the affiliated colleges, the number of senior teachers was 26902 and 1,42,408 were Lecturers and 7,469 were tutors/demonstrators.

New Universities

During the year under report, two central universities, namely Indira Gandhi National Open University and Pondicherry University, and one State University, namely the Mother Teresa Women's University, Kodaikanal, were established. The two institutes, namely International Institute for Population Science, Bombay, and Thapar Institute of Engineering & Technology, Patiala, were declared as institutions deemed to be universities under Section 3 of the UGC Act.

Higher Education among Women

The enrolment of women students during 1984-85 was 10.21 lakhs as against 9.77 lakhs during 1983-84. At the post-graduate level the enrolment of women was 30.4% of the total enrolment. Enrolment of women students was the highest in Kerala (49.9%), followed by Punjab (43.9%), Delhi (43.6%) and J & K (37.3%). The percentage was the lowest in Bihar (14.7%).

Activities during 1984-85 : The activities implemented by the Commission broadly fall into the following categories :

(I) Special Programmes for improvement of quality.
(II) Support for Research.
(III) Development of Universities.
(IV) Development of Colleges.
(V) Other Schemes.

Special Programmes for Improvement of Quality of Special Assistance Study & Departments of Special Assistance

The Commission is at present providing assistance to 19 centres of Advanced Study and 65 Departments of Special Assistance in Science, Engineering & Technology and 10 centres of Advanced Study and 27 Departments of Special Assistance in Humanities and Social Sciences.

(b) Departmental Research Support

At present 45 Departmental Research Projects in Science and four in Humanities and Social Sciences are under implementation.

(c) College Science Improvement Programme (COSIP), College Humanities and Social Science Improvement Programme (COHSSIP) and University Leadership Programme (ULP)

The Commission is presently assisting 237 colleges under COSIP and 40 University Departments under ULP in Science. Similarly 400 colleges under COHSSIP and 16 University Departments under ULP in Humanities and Social Sciences are receiving assistance from the Commission.

(d) Panels in Science, Humanities & Social Sciences

During the year i.e. 1984-85, the various panels made a series of proposals for raising the standards of teaching, for example, the identification of talented students, summer schools for them, strengthening of infrastructure of libraries and laboratories, adoption of more effective teaching methods than the single method of lecturing used nowadays and improving professional competence of teachers. They have also suggested measures for improving research by increasing scholarship amounts to attract and adequately support talented scholars by improving supervision and evaluation at the Universities and by adequate monitoring by the Commission.

(e) Common Facilities and Services

The Commission has been trying to develop certain facilities at the national level for the use of University scientists. Details are as under :

(i) Nuclear Science Centre : A nuclear science centre in the university sector has been set up at the JNU campus. A technical committee has been constituted to formulate a plan of action. Orders have been placed for the import of pelletron. It is also proposed to send bright young scientists to Canada for receiving training in the area of accelerator physics.

(ii) Centres for Materials Research : The Commission has constituted a Committee to consider the steps that may be taken for the strengthening of Materials Research in the University sector. The Committee would also identify National Centres in some of the selected universities and also suggest training programmes/workshops to enable university scientists from the departments of Physics, Chemistry and Biology to interact with a view to developing materials of importance which are of wide applications in the industry.

(iii) Centre for Laser and Fibre Optics : Considering that the subjects of laser and fibre optics are very important and they play a vital role in the basic and research applications, the Commission constituted an expert committee to examine the feasibility of establishing a few national/regional centres in identified universities where the basic infrastructure is available. The Committee has recommended training programmes and workshops in the areas of laser and fibre optics particularly with regard to their application in diverse fields. The recommendations of the Committee will be considered by the Physics Panel and finally by the Commission.

(iv) Centre for Astrophysics & Astronomy : An expert committee has been constituted by the Commission for the promotion of Education and Research in the fields of Astronomy and Astrophysics in the universities. A National Workshop on future developments in astronomy education and research with a view to examining the various aspects and to prepare a plan of action is proposed to be organised.

(v) National Centre for Astronomy : The Commission has approved the setting up of a National Centre for Astronomy at the Rangapur Observatory, Osmania University, Hyderabad. This observatory will be developed as a National Centre which will be used by astronomers from universities and outside.

(vi) University Centre for Science Information : The Commission has approved the establishment of the University Centre for Science information at the Indian Institute of Science, Bangalore. The Centre would offer a current awareness service through computerised monthly abstracts in various subjects of science and technology in the Indian Universities. It would also provide authentic and up-to-date extracting services to the users of papers and educate the users in generating queries for their needs for optimal utilisation of the information services. The Centre will function as a national facility in order to serve the needs of research scientists in the university system.

(vii) Development of Multi-disciplinary Teaching and Training in Bio-technology (National Bio-technology Board—UGC Collaborative Programme) : At a joint meeting of the National Bio-technology Board (Department of Science and Technology, Government of India) held on 7th February, 1983 it was suggested that Universities which have active research groups in the area of Bio-technology may be strengthened on a selective basis for purposes of training manpower required at different levels as well as for undertaking research in well-defined areas of Bio-technology. Six universities have been identified for the implementation of the programme over a period of 5 years.

(f) Mass-Communication & Educational Technology Centres

With INSAT-1B becoming operational, a transmission time of one-hour every day in the afternoon on programmes of higher education has been ensured. The Commission has set up training and production facilities with standard equipment in six selected centres, namely, Mass Communication Research Centre, Jamia Millia Islamia, New Delhi; Educational Media Research Centres (EMRCs) at Poona University, Gujarat University and CIEFL, Hyderabad and Audio-Visual Research Centres (AVRCs) at Osmania and Roorkee Universities. A Central Programme Committee has been set up to coordinate and channelize suitable materials for daily telecast through Doordarshan.

A Standing Committee on Electronic Media/Mass Communication has also been constituted to advise on programmes to cover telecasting and using mass media for (i) Distance Education, (ii) Class room enrichment and (iii) Continuing Education.

(g) Promotion of Buddhist Studies

The Commission continued to provide assistance to three universities viz. Poona, Andhra and Saugar for appointment of staff and purchase of books for strengthening teaching and research related to Buddhist Studies.

(h) Promotion of Gandhian Studies

In view of the importance of Gandhian Studies in universities at the level of teaching and research as well as by way of extension activities, the Commission has been supporting the proposals from Universities for the introduction of courses in Gandhian Thought and Values, strengthening of Gandhi Bhavans and starting of programmes by way of peace research and other related activities. A Standing Committee has been set up to advise the Commission on the promotion of Gandhian studies in the universities.

(i) Nehru Studies

The Commission has, on the recommendations of an expert committee decided to promote Nehru studies in the universities.

During the year under report, National Fellowship for indepth study on Nehru was awarded to Professor M. N. Das, Vice-Chancellor, Utkal University.

The Commission has also set aside five research associateship and 10 Junior Research Fellows for undertaking post-doctoral and pre-doctoral studies on Nehru.

(j) Bilateral Exchange Programmes

The Commission continued to implement the various items under the Cultural Exchange Programme assigned to it by the Government of India from time to time. These programmes involve exchange of teachers, development of bilateral academic links between institutions of higher education, joint seminars, scholarships and fellowships and assignment of foreign

language teachers to universities in India. During the year 1984-85, 56 Indian teachers were able to undertake visits abroad under these programmes. The corresponding number of scholars coming to India under these programmes during the same period is 74.

(b) Adult, Continuing & Extension Education & Distance Learning

The Commission has been providing financial assistance to universities and colleges for adult and continuing education and extension programmes.

As on 31-3-85, 74 universities and 2080 colleges were involved in the programme and 36974 centres were sanctioned by the UGC.

During the year under report 54 universities and 18 colleges were assisted under the scheme. In order to ensure effective linkage of post-literacy with continuing education programme, the Commission has agreed to provide assistance to universities and colleges upto 31-3-1990.

The Commission also provides assistance for establishment of population education clubs in universities/colleges; as on 31-3-85, 49 universities and 814 college were assisted under the scheme.

Support for Research (a) Major Research Projects

The Commission approved 79 major research projects in Humanities and Social Sciences at a cost of Rs. 40.44 lakhs during the year, and 335 major research projects in science, engineering and technology at a cost of Rs. 316.79 lakhs.

(b) Minor Research Projects

The Commission approved 682 minor research projects in Humanities and social sciences at a cost of Rs. 45.59 lakhs during the year, and 335 projects in science, engineering and technology at a cost of Rs. 316.79 lakhs.

(c) Scholarships and Fellowships

For the development of research in universities and colleges, the Commission provides assistance every year towards 2896 junior research fellowships, 150 research associateships in sciences, humanities and social sciences and 60 research fellowships in engineering and technology. 30 national fellowships are available for teachers of outstanding eminence to take a year off from normal duties to devote themselves exclusively to research and writing of results of their study. During the year 1984-85, 12 research fellowships were awarded. The Commission also awarded a national fellowship for two years for the study of Jawaharlal Nehru and his contribution. Besides, the Commission has schemes of national associateships, emeritus fellowships, teacher fellowships etc.

(d) National Educational Testing

The University Grants Commission conducted a National Level Test as an eligibilty requirement for the award of Junior Research Fellowship on the 26th August, 1984 in 12 subjects—Physics, Chemistry, Mathematics Life-Sciences, Zoology, Geography, Economics, Political Science, Philosophy, Psychology, Sociology and History. The examination was conducted with the help of 72 university centres in universities which agreed to conduct the test on behalf of the Commission within the framework of rules and procedures laid down for the purpose. The results of the examination held on 26th August, 1984 were declared in December 1984 and 1205 candidates were declared eligible for award of fellowship out of 12,862 actually appeared.

Development of Universities

The developmental assistance of the Commission to the universities is determined on the basis of a number of factors like the size of the university, present stage of growth and development, goals & objectives, financial & human resources, etc. Specific allocation to universities are made on the basis of the recommendations of the Visiting Committees which assess the needs and requirements of the universities for a five-year period. The Commission's approach towards the development of universities in the Seventh Plan will be based on the following considerations : (a) the need for university development for on-going programmes and inputs for strengthening the existing courses in regard to new emerging areas of national importance; (b) the need to replenish the infrastructural facilities; and (c) provision for the growth of higher education by way of new institutions and increase in the intake capacity of existing institutions in order to have optional utilization of available resources.

(i) Campus development of universities : The Commission constituted a committee for working out a pattern of assistance for campus development of central universities and institutions deemed to be universities. In the light

of the recommendations of the Committee grants amounting to Rs. 143.16 lakhs were paid by the UGC for campus development of various universities. A sum of Rs. 1456.06 lakhs was provided as assistance to the universities for science education and research during 1984-85. Grants amounting to Rs. 702.35 lakhs were provided for the development of humanities and social sciences. Assistance was also provided to the various universities for (i) developing expertise in archaeology; (ii) development of performing arts; (iii) development of areas studies; and (iv) strengthening/establishment of archival cells.

(ii) Development of Engineering and Technology : The Commission provides financial assistance to university—maintained Institutes in Engineering & Technology for the development of higher education and research. At present, there are 32 universities/institutions deemed to be universities which are getting financial assistance. These institutions provide facilities for a variety of post-graduate courses besides offering facilities for under-graduate education.

The Commission has enhanced during the year the value of Post-Graduate Scholarship/Senior Research Fellowship with a view to attracting talented scholars in this field. The present value of the P.G. Scholarship is Rs. 1000/- p.m. and that of Senior Research Fellowship is Rs. 1200/- p.m. A Senior Research Fellow is also entitled to house rent allowance and medical facilities.

During the year 1984-85 the Commission released grants to the universities for the development of engineering and technology amounting to Rs. 307.96 lakhs.

(iii) Development of Computer Facilities and Computer Education for Manpower Training : The Commission, in consultation with the Electronics Commission, has agreed to provide medium-sized computers to selected universities.

The Computer Development Committee of the UGC has so far recommended installation of computer system in 58 universities. Computer systems which have already been installed in 35 universities are fully functional. The remaining 23 universities are in the process of procuring the system and getting them installed.

Development of Colleges

Development of affiliated colleges which are mainly responsible for undergraduate education and to a certain extent even for post-graduate education is an important area in higher education from the point of view of maintenance of proper standards, ensuring optimum utilisation of facilities, promoting innovation and change, relating education to emerging occupational pattern, viability and equalisation of eduactional opportunities for weaker sections of society, in particular the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in educationally backward areas of the country.

Grants paid to colleges for general development and other schemes during 1984-85 were as under :

Item	*Assistance Provided (in lakhs)*
Development of Affiliated Colleges	1778.59
College Science Improvement Programme	22.52
College Humanities & Social Science Improvement Programme	87.87
Centenary Grants	0.50
Development of Post-graduate studies in Humanities & Social Sciences	73.27
Development of Post-graduate Studies in Science	138.57
Strengthening of Under-graduate Teaching Institutions	0.90

The concept of autonomous colleges by which universities could give a few carefully selected colleges the much needed autonomy in formulating curricula and courses of study, evaluation methods and other related matters is an important step in the improvement of collegiate education. The Commission has agreed to provide assistance for another five years to the autonomous colleges of Madras University. Review of the autonomous colleges of other universities is under the consideration of the Commission. It is proposed to consolidate and strengthen the scheme during the years ahead and also to bring more universities within the fold of the scheme.

Other Schemes

Special assistance is provided for schemes instituted for (i) the welfare of the weaker sections of the minority communities; (ii) scheduled castes/ scheduled tribes; and (iii) development of programmes relating to women's studies. The details are as under :

Coaching Classes for Competitive Examinations for Weaker Sections Amongst Minority Communities

The Commission continued to provide assistance to universities/colleges for coaching classes for competitive examinations for weaker sections amongst minority communities.

Upto 31st March, 1985, as many as 19 universities and 15 colleges were receiving assistance from the UGC for running coaching classes for minorities and a grant of Rs. 23.77 lakhs was paid for the purpose during 1984-85.

Facilities for Scheduled Castes & Scheduled Tribes

The Commission has decided to provide assistance on cent per cent basis to the universities for the creation of special cells as a measure for strengthening the implementation machinery for planning, evaluation and monitoring the programmes for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Communities. The Commission has accepted the proposal of 65 universities for the setting up of special cells upto the period ending 31st March, 1985.

In addition to the Junior Research Fellowships reserved for SC/ST out of the total number of such fellowships available with the universities the Commission is awarding directly 50 junior research fellowships annually. The Commission has also reserved 40 research associateships for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes. During the year under review only 13 applications were received and all the applicants have been awarded research associateship. In order to provide opportunities to teachers of affiliated colleges belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe categories, for improving their qualifications by doing M.Phil. or Ph. D., 50 teacher fellowships are awarded annually to these candidates.

Women's Studies

The University Grants Commission has agreed to extend financial support to the universities for undertaking well-defined projects for research in Women's Studies as also for the development of curriculum and relevant extension activities. The UGC has accepted an offer of $ 1,00,000 made by Ford Foundation to be utilised to provide support largely for urban collections on Women's studies in a limited number of universities and colleges and also for consultancy by Indian scholars.

Five research projects on Women's Studies were assisted during the year and a grant of Rs. 0.38 lakhs was paid for the purpose. The Commission also agreed to the setting up of a Centre for Research in Women Studies at S.N.D.T. Women's University, Bombay, and a grant of Rs. 2.15 lakhs was paid for the purpose.

B. CENTRAL UNIVERSITIES

Aligarh Muslim University

The number of students on rolls during the academic year 1985-86 was 17,421, out of which about 7,000 were in residence in 55 hostels grouped in 13 Halls of Residences. The number of students in faculties was 6,041, in Colleges 5,511, in Schools 5,750, and in Professional Courses 119.

Shri Syed Hashim Ali, I.A.S., and ex-Vice-Chancellor, Osmania University, joined on 8th April, 1985, as its Vice-Chancellor. The atmosphere of normalcy in pursuit of studies and research continued to be maintained in the University. The University made endeavours to give more stress on research and publications.

During the year under report, the University introduced several new courses, viz., (i) Diploma in Engineering (Architectural Assistantship), (ii) Diploma in Engineering (Electrical Instrumentation), (iii) Diploma in Electronics Engineering (I.V. Technology), (iv) Postgraduate Diploma in Teaching English language and literature, (v) Post M.A. Diploma in Urdu Translation, (vi) M. D. (Kulliyat wa Ilmul Amraz), (vii) and M. D. Moalijat.

The Bio-Technology Institute, first of its kind in the country, started functioning during the current year. The Institute will concentrate in the thrust areas like, Genetic Engineering, Enzyme Engineering and Fermentation Technology to solve major problems of hunger, disease, population explosion, etc.

The University established a centre for promotion of science with a view to creating awareness among Indian Muslims about the developing scientific knowledge and for searching Muslim talent for scientific research .

The Protein Research Laboratory of the Department of Bio-Chemistry made significant contribution in the areas of protein conformation. It trained 73 students for their Ph.D. and M.Phil. degrees. The research activities in the Department of Microbiology have led to its recognition as a Sentinal Centre by the National Institute of Communicable Diseases (NICD) in collaboration with the World Health Organisation. The University has generated infrastructural base to develop Remote Sensing Application Centre for Resource Evaluation and Geo-engineering. The Fisheries Division of the Department of Zoology has earned recognition as a member of the "International Network of Feed Information Centres (INFIC)".

The Central Library of the University, which is amongst the best in the country, contains, inter-alia, very valuable manuscripts and rare books of Urdu, Persian and Arabic languages. The total collection of volumes in the library presently stands at 6,13,297.

Eight seminars/conferences were organised by the various Faculties of the University. Three Professors, one each from Saudi Arabia, U. K. and Canada, were invited to deliver lectures. The University celebrated Sir Syed Day on 17th October to perpetuate the memory of its Founder.

University of Delhi

During the year 1985-86 there were 95180 students on rolls in the regular courses offered by the University Departments and Colleges. The number of students on rolls as Non-Collegiate Women's students was 13175, while the External Candidates Cell registered 16,595 as private candidates. The School of Correspondence Courses and Continuing Education had an enrolment of 21355 students. Thus, the total number of students on the rolls of the University was 1,46,311, registering an increase of nearly 3500 students as compared to the enrolment in the year 1984-85. The number of students enrolled for Ph.D. students was 2481 and that for the M. Phil. Courses 802.

The total strength of the teaching staff of the University was as follows :—

Professors	228
Readers	302
Lecturers	157
Research Associates	11
TOTAL	698

The University started post-graduate inter-disciplinary courses in Bio-Chemistry, Electronics Science, Genetics, Micro-Biology and Master of Fine Arts. In addition, the Post-Graduate Diploma Course in International Marketing and the Post-Graduate Diploma in Administrative Management were introduced.

The University decided to introduce some new Courses, viz., Post-Graduate Course in Applied Psychology, Environmental Biology and Certi-

ficate, Diploma and Advanced Diploma Courses in Finnish and Spanish Languages.

A new Faculty of Inter-Disciplinary and Applied Sciences and Department of Adult Continuing Education and Extension, and Department of Punjabi were established during the year. The University approved the proposal to establish a Department of Electronics and Communication Engineering under the Faculty of Technology.

The University instituted some new medals, fellowships and scholarships donated by individuals and organisations.

The University continued to participate in the national and International games. Miss Asha Aggarwal of the University earned the unique distinction by winning a Gold Medal in the Eighth International Women's Marathon held at Hong Kong.

Prof. Moonis Raza, joined the University as Vice-Chancellor.

The University hosted the NAMYFEST and the 73rd Indian Science Congress Session and organised several lectures during the year by eminent scholars both from India and abroad. Several teachers of the University were honoured by professional organisations in their respective fields.

University of Hyderabad

During the year 1985-86 the student strength on rolls of the University recorded an increase to 928 as against 746 of the previous year (1984-85). Of these 98 belonged to Scheduled Caste, 13 Scheduled Tribes and 16 Physically Handicapped categories. 162 students qualified for the award of M.A./M.Sc. degree, 55 for M.Phil. degree, and 25 for Ph.D. degree.

The faculty strength of the University during the year was 128 included 31 Professors, 48 Readers, and 49 Lecturers. Many faculty members actively participated in collaborative research programmes and some of them were awarded national awards.

Financial assistance to the students in the form of Merit Scholarships, Merit-cum-Means Scholarships and Freeships was continued as in the previous years. Besides, 50 students were awarded Fellowships valued at Rs. 600/- per month and 40 students enjoyed Junior/Senior Research Fellowships under the UGC scheme of 'any given time basis'.

During the year 1985-86 a number of developmental projects were taken up. Three new hostel buildings, providing accommodation for 300 students, were completed. A building for the Health Centre at an estimated cost of Rs. 16.18 lakhs is in the advanced stage of construction. Construction of an Open Air Theatre at a cost of Rs. 7.25 lakhs was taken up and is progressing well. An additional hostel for 100 more students at a cost of about Rs. 31.00 lakhs was also approved during the year 1985-86. Construction work of several on-going projects, like the Administrative Building, Science School Complex, Computer Centre Building and Building for the School of Chemistry under the special assistance programme of University Grants Commission, was well under way.

The first convocation of the University was held on 6th April, 1985. Shri P. V. Narsimha Rao, the then Union Defence Minister, attended the function as the Chief Guest. As many as 1252 students were awarded degrees at the convocation.

Jawaharlal Nehru University

Since 1984-85, admissions to various programmes offered by the University are made on merit adjudged on the basis of a uniform all-India examination held at 21 centres throughout the country. 15% seats are reserved for Scheduled Castes, 7.5% for Scheduled Tribes, and 3% for physically handicapped students.

For the 1985-86 admissions, there were 16,596 applicants of whom 7,681 actually took the test. From among the candidates qualified in the test and offered admission, 856 candidates actually joined the University.

Out of them, 92 belonged to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and 9 were physically handicapped.

1125 students were awarded degrees/diplomas/certificates during the year by the University. These include 72 Ph.D., 209 M.Phil., 149 M.A./M.Sc., 689 B.A./B.Sc./B.A. Hons. degrees and 6 certificates/diplomas.

Honorary degree of Doctor of Law was conferred on President Julius K. Nyerere of Tanzania.

A three-year Master of Computer Applications programme which is designed to provide necessary theoretical background and practical experience for dealing with the future trends in computer technology has been introduced in the School of Computer and Systems Sciences.

A two-year M.Sc. Biotechnology Programme has been started in the School of Environmental Sciences from the academic year 1985-86. This programme will expose students to the recent developments in the areas of Genetic Engineering and Biotechnology which have significant potential for industry, agriculture, and medicine.

The University has decided to institute two new courses on Gandhian Studies from the next academic session; a Course on 'Gandhi and the World' at the M.Phil. level, and a course on 'Gandhi and Sarvodaya' at the M.A. level.

A proposal has been finalised to procure a fourth generation computer to meet the growing requirements in respect of the academic programmes of the University. It will further promote inter-disciplinary studies.

United National Industrial Development Organisation Project for the establishment of an Institute of Genetic Engineering and Biotechnology was assigned to India. This Institute will be located on the Campus of the University.

The Adult, Continuing Education and Extension Unit took various steps to involve women, Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Potters (traditional artisans) and class IV employees of the University to benefit from its programmes.

The Centre of Russian Studies of the School of Languages celebrated its XXth Anniversary on 14th November, 1985.

Research work on forty-five projects sponsored by the Government and other academic/research agencies was in progress during the year.

Spanish journal *Hispanic Horizon* has been brought out by the School of Languages to project literary and cultural aspects of the Spanish-speaking countries and the work of 'Hispanic Indologists'

The building for the laboratory for Nitrogen Fixation project has been completed. The work relating to the construction of a hostel for 200 students is in progress.

Visva-Bharati

The total student strength in the University during the year 1985-86 was 3,656. The total strength of teachers was 499, of whom 55 were Professors and 121 were Readers.

During the year under report, the University organised several lectures, seminars and conferences, in which distinguished educationists and scholars from India and abroad participated. Notable among these were the Workshop on Language Laboratory Technique, National Seminar on Sixty Years of Quantum Mechanics, and the All-India Seminar on Indian Spiritualism and National Integration. The Diamond Jubilee of the Vidya Bhavana was celebrated during the year. A cultural delegation from Visva-Bharati visited South-East Asia and presented several programmes of Tagore Songs, plays and dance recitals. It also organised an exhibition of original paintings of Tagore and an exhibition of his life.

The rural library service in collaboration with the Raja Rammohan Roy Library Foundation continued its activities for the benefit of the rural population. The Rural Extension Centre also functioned successfully during the year. The Indira Gandhi Centre for National Integration which was inaugurated during the year was a major step in Visva-Bharati's quest for achieving national integration and cohesion.

Banaras Hindu University

The academic schedule of some of the faculties which was lagging behind was restored to almost complete normalcy. Some faculties are, however, still in the process of covering their back-log.

During the year, the departments of Computer Engineering, Computer Science, Applied Physics, Applied Chemistry and Applied Mathematics were established.

The Centre for Research on Microwave Tubes in the Department of Electronics Engineering was approved by the University Grants Commission.

The proposal for the establishment of the School of Bio-Technology was approved. The primary function of the School is to impart training in Bio-technology and also to carry out advanced research. The University has also been assigned National Electron Microscope Facility Project. Besides, the Departments of Physics and Electronics Engineering have been included in the list of COSIST and Special Assistance Programme. Two courses in special education for training of teachers for physically handicapped children have been introduced. Department of Musiocology has introduced M. Phil. programme. A number of varieties of wheat were developed by the University and released for commercial cultivation. The University has also taken up research on Ganga pollution.

During the International Youth Year, a few students of the university participated in the International Youth Camps held at Moscow.

North-Eastern Hill University, Shillong

The jurisdiction of the North-Eastern Hill University extends to the two States of Meghalaya and Nagaland and the Union Territory of Mizoram with its Headquarters at Shillong. There are at present 17 Post-Graduate Departments and 5 Centres at the Headquarters with 4 Departments each in Nagaland and Mizoram Campuses. The Mizoram Campus has one Constituent College. The College of Agriculture in Nagaland Campus has been converted into the School of Agricultural Sciences with Principal as the Dean of the School.

292 students passed out in the 3-year degree course in honours, 24,752 students were enrolled to post-graduate and under-graduate courses during the year. 160 research scholars were admitted to the research programmes.

The construction of the Main Campus at Shillong, including hostels, for approximately 200 students, and the Seminar Complex-cum-Guest House is in full swing. Construction of 41 quarters and 2 blocks of Seminar Complex-cum-Guest House were completed during the year.

The University installed one teleprinter for the benefit of research scholars and students. A Central School was established during the year at the Main Campus of the University.

The Colleges in Nagaland were affiliated to the University during the year, raising the total number of affiliated colleges to 41.

The University hosted the following Conference/Seminars :—

(1) International Symposium on Life Sciences from November 14–16, 1985.

(2) Twentieth Anniversary Conference of Input-Output Association (International) from December 2–8, 1985.

(3) National Seminar on Education Policy in Higher Education from December 10–12, 1985.

(4) Workshop of R.S.I.C. from November 21–23, 1985

Indira Gandhi National Open University

The Indira Gandhi National Open University Bill was passed by Parliament in August 1985. The Act came into force on September 20, 1985. Prof. G. Ram Reddy assumed office of the Vice-Chancellor of the University. A detailed project Report of the University has been prepared by the Educational Consultants (India) Ltd. 100 acres of land has been acquired in South Delhi for the University. The foundation stone for the construction of buildings was laid by the Prime Minister on November 19, 1985. An international workshop in which Vice-Chancellor of major Open Universities in the world participated, was organised from November 20–22, 1985 to discuss the Project Report.

The University is proceeding with the initial recruitment of staff for preparation of its academic programmes. The first batch of programmes is expected to be announced before the middle of 1986. Till the construction programme is completed at its permanent site, the University will be functioning in hired accommodation.

The preparation work includes the provision of initial infrastructure for the University including construction of building, purchase of equipment, production of instructional material, appointment of staff, and setting up a network of study centres throughout the country.

Pondicherry University

The Pondicherry University Act establishing a central university at Pondicherry was passed by Parliament in September, 1985. The Act came into force on 16th October, 1985. Dr. K. Venkatasubramanian took over as the first Vice-Chancellor of the University on the same day. The University has established its camp office at Pondicherry. The University is in the process of acquiring necessary land and it is expected that by June, 1986 the total land available to the University would be 1,234 acres. Nine colleges in Pondicherry territory come under the jurisdiction of the University.

C. SPECIALISED RESEARCH ORGANISATIONS

Indian Institue of Advanced Study

The Indian Institute of Advanced Study, Shimla, was established in 1965 as an autonomous organisation fully funded by the Government. It aims at free and creative enquiry into fundamental themes and problems of life and thought. The Institute is a residential centre for research and provides an environment suitable for academic research, particularly in selected subjects in the humanities, Indian culture, comparative religion, social sciences and natural sciences.

2. The Institute revived its academic activities in May, 1984 and has at present 15 Fellows on its rolls. Fellowships for 1985-86 have been offered and another 10 Fellows are expected to join after winter vacation.

3. The Institute organised two seminars on "Alternative Economic Structures" during March 20–27, 1985 and "Place of Ends and Means in Private and Public Life" on November 4–9, 1985. The third seminar on Knowledge, Reality and Happiness is scheduled to be held in March, 1986. Proceedings of these seminars will be published by the Institute as Transaction Volumes.

4. Group discussion meetings of the Fellows is one of the salient features of the academic activities. Such meetings are held once a week and this generates a lot of interaction.

5. The Institute has decided to bring out its own journal and the first issue is expected to be brought out in March, 1986.

6. About 22 manuscripts are being evaluated and some of them will be published during the current financial year.

Indian Council of Philosophical Research

The Indian Council of Philosophical Research, which was registered as a society in March, 1977, under the Societies Registration Act, 1860, actually started functioning in July, 1981 under the Chairmanship of Professor D. P. Chattopadhyaya. The Council has been set up mainly to review the progress of research in Philosophy from time to time to

sponsor or assist projects or programmes of research in philosophy, to give financial assistance to institutions, organisations and individuals engaged in the conduct of research, to provide technical assistance and guidance, coordinate research activities, and to take all such measures as may be necessary to promote research in Philosophy and allied disciplines.

During 1985-86, the Council continued with one National fellowship, three senior fellowships and eight general fellowships, and awarded three new fellowships each in the senior and general fellowship categories.

The Council organised and assisted about 10 seminars, workshops, etc., besides a few monthly seminars at its academic Centre in Lucknow. The Council also continued its various scholarly projects, including academic publications, out of which six were completed during 1985-86.

The Council organised an All India Essay Competition followed by a seminar for the young scholars on the topic "Youth and the 21st Century", to promote talent among young scholars of the country.

Professor George Henrik von-Wright of Helsinki (Finland) and Professor T. R. V. Murty of Varanasi have been selected to deliver lectures during 1985-86 under the programme of Annual Lectures

Under the international collaboration programme, the first Cultural Exchange Programme in the field of philosophy between India and the USSR has been taken up for implementation during 1985-86.

The Council provided financial assistance to 17 scholars in the shape of travel grant for attending international conferences, seminars, etc.

Two issues of the ICPR Journal were brought out during 1985-86.

The Council continued to display various exhibitions at Butler Palace, Lucknow.

Indian Council of Historical Research

The Indian Council of Historical Research was set up in 1972 as an autonomous organisation for giving proper direction to historical research and for encouraging and fostering objective and scientific writing of history. The Council has been achieving the above objectives by sponsoring research programmes in different fields of history including the history of art, archaeology and philosophy, in general and by giving encouragement, in particular, to the development of historical research in the hitherto neglected areas such as social and economic history, history of sicence and technology, military history and history of ideas, etc.

During the period under report, the Council sanctioned 22 research projects, 115 fellowships and 66 study-cum-travel grants. 32 research theses, monographs and journals have been approved for publication subsidy. 35 professional organisations, such as South Indian History Congress, Indian History Congress, Indian Archaeological Society, Institute of Historical Studies, Numismatics Society of India etc., have been sanctioned grants to enable them to organise seminars/symposia etc. In connection with the Congress Centenary Celebrations a Panel Discussion to identify the areas of further research was organised.

As a step towards the fulfilment of its aim of compiling and publishing such source material as would facilitate historical research and writing, the Council has taken up a comprehensive programme which envisages a compilation of several volumes of sources covering all periods of Indian history. Under this programme, three volumes of documents on Nationalist Movement in India (1919-20), 1898-1902) and (1922-24) were sent to the press for publication. One volume edited by Professor V. N. Dutta has been published. *A Catalogue of Mughal Documents* (1526-1627) *and Catalogue of Marathi documents* along with the English translation of *Raj Tarangini* and *Russian Documents*—under the medieval sources programme have been compiled and will be sent to the press shortly.

6—759 Deptt. of Edu/85

Under the publication programme, the Council brought out Hindi edition of *The Classical Age* by Dr. R. C. Mazumdar and Urdu edition of *Chola Rajgan* by K. A. N. Shastri, *Inscriptions of the Mukharies and Kannauj* and *Topographical list of Inscriptions in Tamil Nadu and Kerala States*. Volume I of the Documents covering the period from January-December 1937 under the special project *Towards Freedom* has also been published. Besides, 20 monographs and thesis have been published under the publication subsidy programme of the Council. The Council also published an Accessions List of the additions to the Library for 1984-85 and another publication entitled *Current Awareness Service in Indian History* has been published. *The Indian Historical* Review volume VIII (Nos. 1-2) has been published and volume IX has been sent to the press.

Under the Cultural Exchange Programme between India and the U.S.S.R., the Council organised a symposium on *"Transition from Ancient to Medieval Periods : Problems of Economic and Social Organisation of the Society"* in April, 1985, in which eight historians from the Soviet Union participated. Under the Indo-GDR and Indo-Bulgarian Cultural Exchange Programmes the Council deputed Indian historians to attend the seminars held in Berlin in July, 1985 and in Sofia in November, 1985.

Indian Council of Social Science Research

The Indian Council of Social Science Research was established in 1969 as an autonomous organisation to promote and coordinate social science research in the country.

During the year, the Council continued to assist 21 research institutes. The Council also continued its support to six-regional centres.

Research grants were sanctioned by the Council for 56 research projects till December, 1985. The Council received completed reports in respect of 36 projects approved earlier. The programme of research on women's studies has been reactivated and eight research projects on common theme on women's work and family strategies have been sanctioned.

The Council awards various kinds of fellowshops to scholars in the field of social sciences. 86 fresh awards and 37 contingency grants were sanctioned till December, 1985.

3080 publications including 300 theses and 598 research reports were acquired. 163 Ph.D scholars were given study grants for visiting libraries for collection of material for their research work. Financial assistance was given for 18 bibliographical and documentation projects. 27 documentation lists in mimeographed form have been compiled and distributed to various libraries and institutions in India and abroad.

During the year, the Council brought out 4 publications. Under the scheme of publication grants, 16 theses and 11 research reports have been approved for providing financial assistance for publication during 1985-86. Under this scheme, six books have been published during the year.

The Council has also published 11 issues of journals in different disciplines such as geography, economics, political science, public administration, sociology and social anthropology.

The data archives acquired 10 data sets generated out of ICSSR-funded projects. 17 data sets were organised in machine readable form and documented to facilitate their retrieval and secondary analysis.

During the year, the Council provided financial assistance to 45 Indian scholars to go abroad for participation in various international conferences.

Three French scholars visited India and 10 Indian scholars were sponsored for visiting France under the Indo-French Cultural Exchange Programme. The Council also sponsored the visit of several distinguished foreign scholars for delivering lectures and for discussions with Indian scholars.

Under the Indo-Soviet Joint Commission for cooperation in social sciences, two Soviet academicians visited India to discuss the ongoing activities under the Joint Commission.

Under the Indo-Dutch programme on Alternatives in Development (IDPAD), five Indian scholars visited Holland and one Dutch scholar visited India. The Joint Committee on IDPAD has approved and submitted for Government approval 10 research projects pertaining to the following areas :—

(i) New international economic order
(ii) Comparative perspective Asian Rural transformation
(iii) Recent trends in European Societies

Nine projects have been approved by the Government and one is under consideration.

The Council co-sponsored the Seventh General Conference of the International Federation of Social Science Organisation held in New Delhi in December, 1985. A large number of participants from developed and developing countries, besides the representatives of United Nations University and UNESCO, attended the Conference.

Scheme for Grants to All India Institutions of Higher Learning

The objective of this Scheme is to provide assistance to certain voluntary organisations in the country which are functioning at the all-India level and are offering programmes of education different from the conventional pattern. The Scheme helps a small number of organisations which are not in the university system and are not able to raise resources for their maintenance and development but are offering useful programmes which are of particular interest to the rural community or which are innovative in character. At present, five such institutions, namely, Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry; Kanya Gurukul Mahavidyalaya, Dehradun; Tilak Maharashtra Vidyapith, Pune; Lok Bharati, Sanosra; and Sri Aurobindo International Institute of Educational Research, Auroville, are receiving assistance under this scheme.

It has been decided to declare the +2 Unit of Kanya Gurukul Mahavidyalaya as a constituent college of the Gurukul Kanya Vishwavidyalaya, Hardwar, and its second campus. The maintenance and development expenditure of the second campus will henceforth be met by the Vishwavidyalaya out of grants from the UGC.

D. BILATERAL/FOREIGN COLLABORATION PROGRAMMES

Shastri INDO-Canadian Institute

The Shastri Indo-Canadian Institute is an autonomous voluntary organisation incorporated in Canada which commenced its activities in India in November 1968, in pursuance of Memorandum of Understanding with the Government of India. The agreement with the Institute has been renewed upto the period ending 31st March, 1989. The objective of the Institute is to serve a two-fold purpose of supporting and promoting advancement of knowledge and understanding of one country among the scholars and students of the other.

The Institute awarded fellowships to 7 Canadian scholars during the year 1985-86 for undertaking research in humanities, learning Indian languages and in the field of performing arts.

Berkeley Professional Studies Programme in India

Under the programme 13 scholars came for study/research in the fields of medicine, law, agriculture and health.

American Institute of Indian Studies

The Institute is a cooperative organisation established by American Colleges and Universities interested in the study of Indian Culture and Civilization. The Institute which commenced operations in India in 1962 awarded fellowships (faculty/junior/ad-hoc short term and language) to 154 scholars, during the academic year 1985-86 for doing research in social sciences, humanities and language training etc.

United States Educational Foundation in India, New Delhi

The United States Educational Foundation in India was established in February 1950 under a bilateral agreement between the Government of India and the Government of United States of America to promote mutual understanding by exchange of knowledge and professional talents through educational programmes to be financed by funds made available by the

Government of the United States of America. 66 American scholars/students came to India during 1985-86 for doctoral and post-doctoral research under the Foundation's programme and also for assignment as Visiting Professors in the Indian universities. Similarly, about 135 Indian scholars were awarded lecturer/research/student fellowship and travel grants for studies/research and participation in short-term seminars/workshops in the USA.

8 short-term groups consisting of 133 academics including professors, teachers, educational administrators from the USA came to India for short durations to acquaint themselves with the latest developments in the field of education and culture in India. These group programme are organised in collaboration with the Indian universities.

American Studies Research Centre, Hyderabad

The American Studies Research Centre, Hyderabad continued to extend facilities to the Indian scholars and students in American Studies. The Centre has been permitted to allow scholars from neighbouring Asian countries also to avail themselves of these facilities at the Centre provided the US-held rupee funds in India are not utilised for the purpose.

Foreign Scholars Visiting India for Individual Research

Apart from the foreign scholars sponsored by the above-mentioned foreign agencies, applications from 63 research scholars from the various countries were received for undertaking doctoral and post-doctoral research work on their own or on grants from their universities.

E. OTHER ACTIVITIES

Revision of Salary Scales of Teachers in Universities and Colleges

The Central Government had reviewed its earlier decision on the revision of pay-scales of Librarians and Directors/Instructors of Physical Education in the Universities and Colleges and agreed to upgrade them. The upgraded scales are at par with teachers and are effective from 1-4-1980. The decision was communicated to all the State Governments in Dcember 1982. The State Governments were also offered financial assistance to the extent of 80 per cent of the additional expenditure involved in the implementation of the upgraded scales for the period 1-4-1980 to 31-3-1985. In pursuance of this decision, the State Governments of Punjab, Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat, West Bengal and Rajasthan have so far agreed to upgrade the pay-scales. Meanwhile, the residual claims of Central assistance received from the State Governments in respect of the revision of salary scales of teachers are also being met by the Central Government.

Dr. Zakir Hussain Memorial College, Delhi

Dr. Zakir Hussain Memorial College Trust was established in 1973 to take over the responsibility for the management and maintenance of Dr. Zakir Hussain College (formerly Delhi College). The maintenance expenditure of the College, which is a constituent college of the Delhi University, is shared by the University Grants Commission and the Trust in the ratio of 95 : 5. In addition, the U.G.C. sanctions to the College development grants according to the pattern of assistance laid down by the Commission for various types of programmes. Since the Trust has no resources of its own, grants are provided by the Government for meeting the matching contributions of the Trust to such development expenditure. The grants are also sanctioned by the Government for meeting the administrative expenditure of the Trust.

One of the major decisions taken by the Trust was to shift the College from its present premises (Ajmeri Gate) to Minto Road area. Necessary land has been acquired and the construction of the new building started. The construction of the Science Block has been completed. The Chemistry, Botany, Physics, Zoology and Psychology departments will be moved to the new building well before the commencement of the next academic session. Construction of the Academic Block and Administrative Block has been taken up.

Jamia Millia Islamia, New Delhi

The Jamia Millia Islamia, New Delhi, is an institution deemed to be a University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956. It is receiving recurring and non-recurring grants from the University Grants Commission for its university section. For its non-University Section, it has been getting grants from the Government of India.

The Senior Secondary School of the Jamia Millia Islamia has been strengthened and vocational courses under the commerce and engineering streams at the +2 stage have been started. An integrated schemes for handicapped children has been introduced in the IX class of the School. Jamia Millia Islamia has taken up extension of the existing school building.

The Department of Technology which is also financed by the Ministry has introduced a new course of Diploma in Electronics.

Association of Indian Universities

The Association of Indian Universities is a voluntary federal body of the universities in the country. It provides a forum to the university community to come together, exchange experiences and consider areas of common interest to them. It acts as a bureau of information on higher education and brings out a number of publications, research papers, books and journals.

The Association is substantially financed from membership fees collected by it. The Government has been sanctioning token grants for its maintenance expenditure. The Association has also been sanctioned grants for the Research Cell to undertake research activities concerning the university system. The Research Cell has undertaken studies in examination reforms, preparation of status reports, monographs on various aspects of economics of higher education and studies on placement of I.I.T. Graduates, Education and economic development, wastage and stagnation in higher education, etc.

An important status paper on infrastructure for higher education and university finance is expected to be brought out during the current financial year. The Association proposes to undertake translation into Hindi of some of the popular titles on Question Banks.

With the completion of its building with the help of grants from the Government of India and contributions of member-universities, the Association proposes to establish 'Information and Guidance Cell' for foreign students and to strengthen a number of other activities.

In addition to its sports promotion efforts, the Association has made a beginning in promoting cultural activities in universities. It played a key role in the holding of NAMYFEST, 1985 in collaboration with the Department of Youth Affairs and Sports and other organisations.

Scheme of National Research Professorship

The Scheme of National Research Professorship was instituted in 1948, to honour distinguished academics and scholars in recognition of their contribution to knowledge, in their respective fields. Between 1965 and 1981, no appointment of National Professors was made. In 1981, Dr. Salim Ali, a renowned ornithologist and Dr. T. M. P. Mahadevan, a distinguished Professor of Philosophy were awarded National Professorships. Prof. V. K. R. V. Rao has been appointed as National Research Professor from 3-2-1984. Prof.Mahadevan expired on 5th November, 1983. It has been decided to appoint Dr. Durga Das Bas as National Professor in Constitutional Law. One more appointment is under consideration. There are only two National Professors at present.

Scheme of Financial Assistance to Professional Organisations In Major Disciplines in the Universities

A new scheme for providing financial assistance to Professional Organisations working in the field of physical and Natural Sciences, Social Sciences and Humanities for organising conferences, seminars etc. was finalised in the Sixth Plan. The objective of the scheme is to bring about better communication among those who are engaged in teaching, research or independent scholarly pursuits by giving them opportunities to come together, exchange views, discuss new developments and share new discoveries and additions to knowledge. During 1985-86, seven organisations have been sanctioned financial assistance under this scheme.

Panjab University, Chandigarh

Following the reorganisation of the State of Punjab in 1966, the Panjab University was declared as an inter-State Body Corporate

under the provisions of the Punjab Reorganisation Act, 1966. The maintenance expenditure of the University is being shared at present by the Government of Punjab and the Union Territory of Chandigarh in the ratio of 40 : 60. The developmental expenditure of the University is met substantially from the grants sanctioned by the U. G. C. The matching share to such grants, as well as expenditure on development programmes, which do not qualify for grants from the Commission are met by the University from an annual loan sanctioned to it by the Central Government. During 1985-86, the University was sanctioned a loan of Rs. 50 lakhs for this purpose.

Special Cells for Scheduled Castes /Tribes

This Cell is responsible for the review of the policy regarding reservation in admission and appointment in the colleges and universities. The Cell also functions as a liasion unit for furnishing information regarding reservation to the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Parliament. Representations received from Scheduled Caste and Scheduled Tribe teachers/students/employees in colleges and universities were examined by the Cell and taken up with the concerned authorities, wherever necessary.

CHAPTER 4

TECHNICAL EDUCATION

Technical Education in India has been expanded to accelerate the Socio-economic progress of the country and today India has one of the largest pools of engineers and technicians at various levels. This expansion and diversification have been brought about systematically through the Five Year Plans. During the Sixth Five Year Plan major emphasis has been on (a) Optimum utilisation of existing facilities, (b) consolidation, (c) expansion of facilities in areas where weakness exists, (d) creation of infrastructure in area of emerging technologies, (e) improvement of quality and standards of technical education (f) efforts to develop and apply Science & Technology as an instrument of country's Socio-economic progress. Activities started on the above areas will be continued during the Seventh Plan period. In addition emphasis will be laid on the implementation of schemes for (i) modernisation and removal of obsolescence in the technical institutions, (ii) application of Science and technology for rural development, (iii) vocationalisation, (iv) institutional linkage between technical education and developmental sectors, (v) Providing computing facilities in technical institutions, (vi) Removal of regional imbalances.

Activities under the approved schemes and in the Central Institutions in the year under report are given below :—

Quality Improvement Programme

The programme of Quality Improvement was initiated in the year 1970-71 with a view to improving the quality and standards of technical education imparted in the various technical institutions in the country. Under the scheme the following programmes are conducted :

(i) Faculty Development

  (a) M. Tech. Programme and Doctoral Programmes;

  (b) Short-term courses at Quality Improvement Programme Centres;

  (c) Summer School Programmes through Indian Society for Technical Education;

(ii) Curriculum Development which includes preparation of instructional material, text-books and laboratory development; and

(iii) Practical training in Industrial Organisations to the teachers of Engineering Colleges and Polytechnics.

M. Tech. and Doctoral Programmes are implemented at the 5 Indian Institutes of Technology, University of Roorkeee, Indian School of Mines, Dhanbad, Indian Institute of Science, Bangalore, Banaras Hindu University, a few Regional Engineering Colleges, A. C. College of Technology, Guindy, Madras and Jadavpur University. The programme relating to short-term courses is implemented through above centres for the degree level teachers and for the diploma level teachers through the four Technical Teachers' Training Institutes and the Institute of Engineering & Rural Technology, Allahabad. The Programme of short-term training in Industry is organised by the regional offices of the Ministry and Summer/Winter schools are organised by Indian Society for Technical Education.

Till the year 1984-85, 940 teachers were trained for M. Tech. courses and 1000 teachers for Ph. D. Programme. Similarly 700 short-term courses were organised by QIP Centres at the degree level in which 10,000 teachers participated and 1200 courses were organised at the diploma level in which 22000 teachers participated. Under the short-term programme in industry, 1800 teachers at the degree level and 4000 teachers at the diploma level had benefited till the year 1984-85. Besides, nearly 1100 Summer/Winter schools were organised by Indian Society for Technical Education where 20,000 teachers participated.

The scheme continued during the year 1985-86. The target during the year under report was to train 100 teachers for M. Tech. and 150 for Ph. D. in addition to those continuing from the previous years. Through Summer School Programmes 1800 teachers were expected to be benefited. As in the past, curriculum development programmes were conducted by the 14 groups at the QIP Centres. About 210 teachers of degree and diploma level institutions were expected to be trained in the industrial organisations under the programme relating to short-term training in Industry.

National Information System

This scheme was instituted in the year 1983-84 with the objective of providing uptodate, meaningful manpower projections on a continuing basis to enable the concerned educational authorities to plan the areas of growth in the field of Engineering and Technology on a systematic basis to meet the technical manpower requirement in the country. The system comprises a lead centre in the Institute of Applied Manpower Research and 17 nodal centres at selected Engineering colleges and technological institutions/Boards of Apprenticeship training. The system has already made a good beginning in the year under report and it is hoped that this will immensely assist in proper planning for growth in technical education in a meaningful way oriented towards needful manpower generation.

Advanced Technician Course

The scheme was started in the year 1981-82 with the main objective of providing avenues for advancement of diploma holders. Under this scheme higher courses of studies at advanced level are provided to enable the technicians possessing diploma in various branches of engineering and technology to advance professionally in their respective lines. The quality of the pass-outs of these courses has been well appreciated by the industrial sector. The scheme is at present being implemented through the following 5 institutions :

1. YMCA Institute of Engineering, Faridabad.
2. CM Kothari Technological Institute, Madras.
3. SBM Polytechnic, Bombay.
4. Institute of Engineering & Rural Technology, Allahabad.
5. JC Ghosh Polytechnic, Calcutta.

It is proposed to set up one Institute in each State during the coming years.

Centres for Development of Rural Technology

Under the scheme of Direct Central Assistance, Centres for Development of Rural Technology (CDRTs) are being established at various diploma level institutions since 1980-81. Upto the end of 1984-85, 14 CDRTs were established. During 1985-86 one more CDRT has been established. The Centres established during the previous years were continued and necessary grants in accordance with the prescribed norms were given to these Centres to modify, adopt and manufacture technologies relevant to the rural needs.

Community Polytechnics

The scheme was instituted under the Central Sector in the year 1978-79 under which 36 polytechnics were selected to serve as Community Polytechnics. In addition to offering diploma courses in various branches of Engineering and Technology, these polytechnics are required to interact with environments and serve as focal points to promote transfer of technology to the rural sector. The activities

undertaken by these polytechnics include imparting of skill training to the rural youth, providing technical services to the rural people, installation and maintenance of relevant items of appropriate technology already developed and adopted, establishment of information and demonstration centres and undertake experimental model projects for rural development. During 1984-85, 10 polytechnics, situated in close proximity to predominantly minority concentrated areas, were added to the stream of Community Polytechnics to impart skill training to the youth from the neighbouring areas. During the year under report, 61 more polytechnics have been brought under the fold of "Community Polytechnic Scheme". In view of the impact produced through the implementation of the scheme, it is proposed to extend this scheme to the remaining polytechnics also in the years to come.

Technical Teachers' Training Institutes

Four Technical Teachers' Training Institutes at Bhopal, Calcutta, Chandigarh and Madras were established in 1966-67 to provide in-service training to polytechnic teachers and also to undertake various activities for the improvement of polytechnic education. These institutes offer long-term training programmes of 12 months/18 months duration to degree and diploma holding teachers of polytechnics in addition to providing short-term training to the teachers in curriculum development and co-related activities. Two of the institutes at Bhopal and Madras have come up to the level of offering post-graduate courses in technical teaching. Besides the normal activities, these institutes also undertake diverse activities under the UNDP project like Educational Film Production, National Testing Services. Instructional package etc. The TTTI, Madras hosted a regional workshop of UNESCO on "Initial and In-service training of technical and vocational education personnel."

Direct Central Assistance

This scheme was started in the year 1976-77 to extend central assistance on 100% basis to the selected Engineering Colleges and polytechnics for identified projects relevant and important for improvement of quality and standards of technical education. The scheme continued during the year under report. The National Expert Committee set up for selecting technical institutions both at degree and diploma levels have selected 30 Engineering Colleges and 41 polytechnics for assistance during the year under report.

Experimental Pilot Projects for Application of Science and Technology to total Rural Development

This is a new scheme instituted during the current year of the 7th Five Year Plan. The scheme is to help selected community polytechnics to take up experimental pilot projects for application of science and technology for total rural development to make our educational efforts more relevant to life situation in the rural areas. The present scheme envisages 100 villages as a single unit in a cluster to be taken up for total rural development. The project is to be implemented at block level, cluster of villages level and at individual village level. The project is to be managed by a team of professional managers who will be responsible for implementation of the whole project. The total project is to be administered taking into account the core managerial staff, government functionaries, technical institutions, village co-operatives, etc.

During the current year, one project in each of the four regions is proposed to be implemented. The current year's budget provision is Rs. 200 lakhs.

Special Institutes of appropriate Technology and Rural Development

This is also a new scheme being instituted from the current year of the 7th Five Year Plan. The Institutes are expected to be centre of excellence for development of new disciplines in appropriate technology and rural development through research, formal and non-formal training and extensive extension work in rural projects. In addition, the Institute will also become a focal point to provide back-up support to various institutions/organisations and agencies involved in rural development. The Institute will have three main wings viz. a Centre for Research & Development in appropriate Technology, a centre for training and a Centre for Integrated Rural Development. The Institute will be an autonomous one, fully financed by the Central Government. Since collaboration and co-operation is the key to success in rural development, these Institutes are expected to play the role of nodal centres which would provide new knowledge to all those concerned with technology transfer and rural development. There is a budget provi-

7—759 Deptt. of Edu/85

sion of Rs. 200 lakhs for the current year. To begin with, one such Institute in each of the four regions is proposed to be established during the current financial year.

Development of New Institutions

During the year under report, one Engineering College and seven Polytechnics have been started in the various States in the country with the approval of Union Minister for Human Resource Development who is also the Chairman, All India Council for Technical Education. The approval has been given keeping in view the guidelines laid down by the All India Council for Technical Education for establishment of new technical institutions and introduction of new courses. In the establishment of the new institutions, care has been taken as far as possible to remove regional imbalances.

Institutional Network Scheme

Institutional Network scheme which was introduced in 1981-82 continued during 1985-86, as Continuing Scheme. The Scheme attempted to bring developed institutions such as Indian Institutes of Technology, to collaborate with less developed institutions like Regional Engineering Colleges and private autonomous Colleges as a process of internal technical assistance in the area of Laboratory Development and faculty exchange programme. In accordance with the provision of the scheme, grant-in-aid of Rs. 2.50 lakhs was sanctioned for upgradation of each approved laboratory under the Scheme and an equal amount of Rs. 2.5 lakhs had to be spent by the concerned institutions from their normal budget. During the sixth plan period, a sum of Rs. 247.50 lakhs was spent for the development of 99 laboratories at the rate of Rs. 2.50 lakhs per laboratory. The break-up of the grant-in-aid release for upgradation of these laboratories was as under :—

Financial Year	No. of laboratories	Amount released (Rs. in lakhs)
1981-82	25	62·50
1982-83	32	80·00
1983-84	20	50·00
1984-85	22	55·00
		247·50

During 1985-86, there is budget provision of Rs. 100.00 lakhs under Plan for utilisation during this financial year.

Expansion of Facilities in Areas of Weakness

The scheme was instituted during the Sixth Plan period with the objective of filling up the gaps in certain identified areas to meet the National requirement in an adequate and effective manner through strengthening of infrastructure, diversification and further expansion of base for post-graduate education. The scheme was to improve the areas of Computer Science. Electronics, Maintenance Engineering, Instrumentation, Product Development, Bio-Sciences and Engineering, Material Science and Technology, Management Sciences etc., by providing Direct Central grant on 100% basis. The Details of grant-in-aid extended to Engineering and Technological institutions for various projects under this scheme are as follows :

Financial Year	*Amount released (Rs. in lakhs)*
1981-82	85.00
1982-83	285.00
1983-84	238.00
1984-85	448.90
	1056.90

There is a budget provision of Rs. 750.00 lakhs in 1985-86 which will be utilised in full by the end of the current financial year.

Creation of Infrastructure Emerging Technology

The Scheme was instituted during the Sixth Plan period with the objective of keeping pace with the advancement in important areas of emerging technologies. The areas include Microprocessor applications, Remote Sensing, Micro-Electronics, Atmospheric Sciences, Optical Communications, Fibre optics, Bio-Conversion, Laser Technology, Reliability Engineering, Transportation Engineering, Water Resources Management, Computer aided Design and Manufacture, Environmental Engineering, Energy Sciences, etc. The details of grant-in-aid extended to Engineering and Technological Institutions for various projects under the Scheme are as follows :

Financial Year	*Amount released (Rs. in lakhs)*
1981-82	115.00
1982-83	384.50
1983-84	350.00
1984-85	582.75
	1432.25

Modernisation of Engineering Laboratories and Workshops

There is a budget provision of Rs. 550.00 lakhs in 1985-86 which will be utilised in full by the end of the current financial year.

The Scheme was instituted during the Sixth Plan period with the objective to provide modern instruments and machines to meet the requirements of latest technological advancement and curricular changes on the basis of 100% direct Central assistance. The details of grant-in-aid extended to various Engineering and Technological institutions are as under :

Financial Year	*Amount released (Rs. in lakhs)*
1981-82	—
1982-83	120.00
1983-84	243.55
1984-85	398.85
	762.40

Indian Institutes of Technology

During 1985-86, there is budget provision of Rs. 1500.00 lakhs. The amount will be fully utilised during the current financial year.

The five Indian Institutes of Technology at Kharagpur, Bombay, Madras, Kanpur and Delhi were established as premier centres of education and training in engineering and applied sciences at the undergraduate level and to provide adequate facilities for post-graduate studies and research.

The Institutes conduct four-year undergraduate programmes leading to Bachelor's degree in Technology in various fields of Engineering and Technology. They also offer integrated Master's Degree Courses of five-years' duration in Physics, Chemistry and Mathematics, one and a half year M.Tech. degree courses in various specialisations and one year post-graduate Diploma Courses in selected areas. In addition, the Institutes offer Ph.D Programme in different branches of Engineering, Sciences, Humanities, and Social Sciences. There are also advanced centres of training and research in each Institute in identified areas of specialisation.

During the year under report, the Institutes further expanded their infrastructural facilities by way of sophisticated equipment and showed better involvement in the transfer of technology to the user agencies. The research projects of these institutes under the sponsorship of various agencies as also the consultancy assignments grew in number thereby bringing revenue to the respective Institutes. The relationship between these institutions and various other academic and commercial organisations assumed greater importance for exchange of technical know-how through workshops/conferences/seminars, etc.

The Humanities and Social Sciences Departments in each of those Institutes continued their efforts to bring on an engineering student an awareness of the significant social aspects of modern technology.

In IIT, Kharagpur 67 specialisations at M. Tech level are being offered. The Institute also offers M. Arch./MRP/MCP courses and M.Sc courses in five specialisations. The Regional Remote Sensing Centre at IIT, Kharagpur is the eighth and the latest addition to the list of its research centres. It is also one in the chain of five centres which the Government of India has decided to set up with a view to creating an infrastructure for training and servicing for remote sensing in the country. As visualised by the Department of Space, these centres would conduct short and long range training programmes from time to time, help users in solving their problems and would be engaged in R&D activities involving utilisation of remotely sensed data by different disciplines.

At IIT, Bombay, a new interdisciplinary M. Tech., programme in Reliability Engineering, a new 2-year Master of Design (M.Des.) programme in Visual Communication as well as a 5 year-Integrated cooperative M.Tech, programme in Chemical and Mechanical Engineering were started from the academic session 1984-85.

The Advanced Centre for Research in Electronics of IIT, Bombay carried out research work in the fields of radar and communication relevant to defence needs, undertaken nine important projects in the area of Antenna Signal Processing and Microwave Magnetic Material for Radar Communication.

Indian Institute of Technology, Madras and the Cement Research Institute of India, New Delhi have signed an agreement to establish a Joint Collaboration Unit devoted to undertake studies on topics connected with quality control and R&D problems pertaining to cement and cement products. The Joint Collaboration Unit has started functioning with effect from 1st October, 1984 and is located in the Structural Engineering Laboratory of the Department of Civil Engineering.

The Centre for Industrial Consultancy and Sponsored Research of IIT Madras organised an orientation programme for candidates to be admitted to M.S. in Entrepreneurship course of the Institute, with the financial support from Industrial Development Bank of India. A number of agencies like Industrial Development Bank of India, State Bank of India, State level organisations like ITCOT, SIPCOT, TIIC extended their support by lending their faculty for organisation of the course.

IIT Kanpur undertook and completed a socio-economic survey of a selected backward area in Uttar Pradesh, the Jamo Jagdishpur Block, which will help in carrying out some field work in collaboration with the local authorities and the State Council of Science and Technology. The faculty of IIT Kanpur continued to do interdisciplinary research contributing to the national needs. As a member of the Institutional Network Scheme between the Regional Engineering Colleges and the IITs, IIT, Kanpur contined to assist the Motilal Nehru Regional Engineering College, Allahabd and the Maulana Azad College of Technology, Bhopal in the area of Laboratory development.

IIT Delhi focussed its research thrust in several areas of paramount National importance, during the year under report. One such area is storm surge prediction and climate simulation studies. The outstanding problem of surgetide non-linear interaction in the Bay of Bengal has been resolved. Monsoon General Circulation Model has been developed which can be used both for climate simulation studies and the medium range weather prediction purposes. The model has been used in successfully forecasting the onset of the monsoon circulation during 1984. The Institute has been identified for collaboration with USSR in the area of Hydrology and Mathematics, collaboration has also been developed with some universities in USA under the scheme of Indo-US Science and Technology Sub-Commission.

A Special preparatory course of 10 months duration was continued to improve the intake of SC/ST students in the IITs. Those SC/ST students who fail to qualify in the Joint Entrance Examination for admissions to the IITs but score a certain minimum percentage of marks are offered admission in this preparatory course. At the end of the preparatory course, these

students are subjected to a qualifying test on the basis of which they are offered admission to the B.Tech programme of the five IITs, without having to appear in the JEE again. On the basis of this preparatory Course the IITs were able to admit 48 SC/ST students to the various IITs in addition to those who qualified through JEE.

The SC/ST students continued to get financial support from the institutes by way of pocket allowance, loans and discretionary grants apart from free messing.

In each of the five IITs one additional seat was made available as was done earlier for the physically handicapped students who qualified in JEE. They are given the Institute and course of their choice provided they were otherwise considered fit to pursue that course.

The Students strength and out-turn of the five institutes during 1984-85 is given below :

IIT	Undergraduates	Post-Graduate and research	Out-turn
Kharagpur . .	1411	1343	874
Bombay . .	1439	538	699
Madras . .	1089	970	650
Kanpur . .	1147	667	622
Delhi .	1256	1735	680

Indian Institutes of Management

The Government of India have established four Indian Institutes of Management at Calcutta, Ahmedabad, Bangalore and Lucknow in year 1961, 1962, 1972 and 1984 respectively in order to provide educational facilities for training of men and women for management centres and for developing experienced administrator; to conduct research and contribute to the growth of knowledge of management and administration and to provide for development of teachers in management and administration. The Institutes continued to conduct Post-Graduate Programme in Management as well as Fellowship Programmes and a number of Executive Development Programmes for managers in the industry. The Institutes also conducted in-company training programmes. The New Institute at Lucknow has started its academic session from July 1984 with the student intake of 30. The Institute will admit 180 students every year to its PGP programme when it is fully developed. The Institutes have made efforts to cater to the requirements of the small scale industry as well as the area of public sector. The collaboration between the Institutes and the industry was of a high order during the year under report.

Management Education at Non-University Centre

The objective of the programme is to provide assistance to certain non-university centres which are functioning at all India level and are offering two-year full time MBA programme and 3-year part-time post-graduate diploma course in management studies. The assistance is given to institutions on the recommendations of the Board of Management Studies of the All India Council for Technical Education. At present the Central Government is giving assistance to the following institutions for consolidation and development of management programme :—

1. PSG College of Technology, Coimbatore.
2. Xavier Labour Relations Institute, Jamshedpur.
3. B.I.T., Ranchi.
4. Indian Institute of Social Welfare and Business Management, Calcutta.
5. L. N. Misra Institute of Economic Development and Social Change, Patna.

National Institute for training in Industrial Engineering, Bombay

The Institute was set up in 1963 with the assistance of UNDP to provide facilities for training in industrial engineering and allied fields. The Institute conducts (i) Executive Development Programme, (ii) Unit based programme, (iii) Post-graduate Programme in Industrial Engineering (iv) Post-

Graduate programme by Research, (v) Fellowship programme (vi) Consultancy Services, (vii) Research Programme and (viii) Seminars and Conferences. The Institute carried on all these activities/programmes effectively during the year under report.

NITIE also published a journal called 'Udyog Pragati' in the area of development in industrial engineering and allied fields. By introduction of new techniques and programmes the Institute has contributed to the changing needs arising out of rapid technological development and socio-economic transformations.

International Centre for Science and Technology Education

The Government of India have decided to set up an International Centre for Science and Technology Education which will operate through a network of existing institutions in the country and will serve as a Resource Centre, and a Centre for Cooperative Research. This International centre will also co-ordinate research programmes in the area of Science and Technology Education for which no coordinated effort has been made in this country even though a number of institutions are engaged in this activity on individual basis. The Centre will work as an autonomous institution under the Ministry of Human Resource Development and will be fully financed by the Government of India. The Centre will also be catering to the needs of the developing countries and is likely to seek assistance for its programmes from international agencies like UNESCO, UNDP etc.

Assistance to Asian Institute of Technology, Bangkok

The AIT, Bangkok is an autonomous international post-graduate institute providing advanced education in engineering, sciences and allied fields. It enrolls about 600 students from more than 20 countries and has international faculty members. The institute is governed by an International Board of Trustees whose members come from different countries including India. It conducts academic programmes in nine disciplines, research by students and faculty staff on problems relevant to Asian countries and special programmes including short-courses, conferences etc.

The Government of India through this Ministry have agreed to provide the following assistance to the AIT :

(a) Deputation of Indian Teachers/Experts for a period upto 3 months in specialised areas of Engineering and Technology and meeting the entire cost of deputation;

(b) Donation of equipment including sports equipment manufactured in India, books and journals costing Rs. 1.00 lakh every year;

(c) An annual grant of upto Rs. 2.00 lakhs for financing its cooperative activities in India.

During the years 1983-84 and 1984-85 eight Indian experts have been deputed each year to the AIT in various specialised areas. In 1985-86, another 8 teachers are expected to be deputed. The budget provision during the current year is Rs. 8.50 lakhs under non-plan and the same has been utilised. For the next year viz. 1986-87 a budget provision of Rs. 10.00 lakhs has been made for providing assistance to the AIT.

Regional Engineering Colleges

Fourteen Regional Engineering Colleges were set up one each in the major states during the second and third plan periods to enable the country to meet the increased need for trained personnel during subsequent plan periods. The fifteenth college at Silchar (Assam) admitted the first batch of students in November, 1977. While all the colleges offer first degree courses in Civil, Mechanical and Electrical Engineering some of them also offer courses in Chemical, Metallurgical, Electronics, Mining and Architecture Engineering. Thirteen of these colleges are also conducting post-graduate courses. Of these, nine are conducting Industry-Oriented courses in specialised fields like Design and Production of high pressure boilers and accessories, Heavy machines for steel plant Transportation Engineering, Industrial and Marine Structures, Integrated Power System, etc. Establishment of two more Colleges has been approved and they are in

the process of being established at Hamirpur in Himachal Pradesh and Jalandhar in Punjab.

The Development of the Regional Engineering Colleges during the Sixth Plan period laid emphasis on the consolidation of existing facilities, establishment of computer centres at selected Colleges, modernisation of laboratories including replacement of obsolete equipment, construction of students Hostels (both for boys and girls) and development of students activity centres in all the colleges. During the year under report, the Regional Engineering Colleges made considerable progress in the implementation of their development plans. 82 laboratories are being developed in these colleges under the scheme of Institutional Network with I.I.Ts. Telecommunications and Electronics Engineering Course has been introduced in 12 Institutions located at Trichy, Kurukshetra, Srinagar, Allahabad, Jaipur, Durgapur, Silchar, Nagpur, Calicut, Bhopal, Surathkal, Warangal and a B. Tech. Course in Computer Science has been introduced at MNREC, Allahabad, REC, Warangal and REC, Calicut under the new plan scheme of Area of weakness. A large size computer has been installed at Regional Engineering College, Rourkela and three systems have been purchased for the Regional Engineering Colleges, Allahabad, Warangal and Durgapur. The one at Warangal has been installed. All Regional Colleges have been provided with atleast 'O' level computer. MCA courses have been started in the three Regional Engineering Colleges at Allahabad, Rourkela and Tiruchirapalli.

Development of Post-graduate Courses and Research Work

On the recommendation of the Review Committee on Post-graduate Education and Research which was set up under the Chairmanship of Dr. Y. Nayudamma, the duration of the Post-graduate courses has been reduced to three semesters and admission to approved post-graduate courses has been regulated through an All India test called Graduates Aptitude Test in Engineering (GATE). The first examination in GATE was conducted in February, 1983. During the year under report, the Screening Committee of the Post-graduate Board examined proposals of various institutions for conducting post-graduate courses and approved ten fresh courses. The rate of P.G. scholarship has been enhanced from Rs. 600/- P.M. to Rs. 1000/- P.M. During the year, the Ministry assisted 12 State Government institutions and 23 non-government institutions for the development of their post-graduate courses as part of the continuing scheme under the scheme of Development of Post-graduate courses and Research Work in Engineering and Technology. The names of 19 non-government institutions which have received grant of more than Rs. 1.00 lakh during the year under report for their post-graduate programmes have been furnished in the Annexure.

Computerisation in Technical Institution and Manpower Development

Under its scheme of Computerisation in Engineering and Technological Institutions, the Ministry has been getting indigenous 'O' level computers evaluated through National Centre for Software Development and Computing Techniques, Bombay. Four more systems on the basis of the evaluation report were approved during the year under report. Efforts have been made by the Ministry to provide atleast 'O' level computers in all approved Engineering Colleges during the 6th Plan period. This effort is continued during the Seventh Five-Year Plan to cover other technological institutions conducting courses in Management, Pharmacy etc. Nine more Polytechnics were also selected by the Ministry, in collaboration with the Department of Electronics, for starting 1½ year Post-Polytechnic Diploma Course in Computer Application bringing the total to 25. During 1985-86, a 3 year M.C.A. Course has been approved for Shri Jayachamarajendra College of Engineering, Mysore and Regional Engineering College, Warangal. Under graduate programme in Computer Science/Engineering have also been approved at additional 4 Centres during the year under report. Efforts are being made to meet the Manpower Shortage in this area under the joint programme of this Ministry and Department of Electronics.

National Institute of Foundary and Forge Technology, Ranchi

The National Institute of Foundry and Forge Technology, Ranchi is an autonomous institution fully funded by the Central Government. It was set up in 1966-67 in collaboration with UNDP-UNESCO in order to

provide requisite trained personnel for foundry and forge industry. The objectives of the Institute are to (i) provide training through short-term courses, long-term advanced diploma courses and unit based programmes required by the industries (ii) to guide and conduct applied industrial research and (iii) to provide consultancy, testing, documentation and information services to foundry, forge and allied industries.

The 12th Advanced Diploma course was started in June, 1984 and it concluded in 20th November, 1985. During 1984-85, one student qualified for the award of Post-Graduate Diploma in Foundry Technology by research. One student qualified for Ph.D. in Forge Technology. Four refresher courses were organised for the Technologists and personnel staff of Indian Industries wherein 25 persons participated. The testing facilities were extended to the needy industries in the areas of Chemical Metallurgical analysis, mechanical and non-destructive testing and evaluation of foundry raw materials.

School of Planning and Architecture, New Delhi

The School was established in July, 1955 as the School of Town and Country Planning to provide facilities for training in Rural, Urban and Regional Planning, to cater to the needs of Central, States and Local Departments of Town Planning. The Department of Architecture of Delhi Polytechnic was amalgamated with the School in October, 1959 and the School was renamed as the School of Planning and Architecture. A significant event in the development of this premier institution took place in 1979 when it was given the status of a "Deemed to be University" to broaden its horizon of academic programme and to further promote research and extension programmes and to award its own under-graduate, post-graduate and doctoral degrees.

The School is fully financed by the Central Government. It conducts Bachelor's degree course in Architecture with annual sanctioned intake of 68 in two shifts. From the academic session 1985-86, the seven years part-time (evening) course has been converted to regular five years full-time course as second shift. It has also been providing Master's degree courses in Urban and Regional Planning, Housing, Transport Planning, Building Engineering and Management, Landscape Architecture and Urban Design with the total intake of 82. From 1985-86, the School has started Ph.D. courses. The School has at present two Research Centres—one in Rural Development and the other in Environmental studies, and is organising workshops and conferences at National and International level.

Educational Consultants India Limited

The first public sector undertaking in this Ministry, Educational Consultants India Limited, New Delhi was incorporated under the Companies Act, 1956, on June 17, 1981 with the main objective to offer multidisciplinary consultancy service to organisations, agencies and government departments in India and abroad in the field of general, medical, agricultural and technical education and training.

The Corporation works under the guidance of a Board of Directors, with a part-time non-official Chairman and full-time Managing Director. Other Directors of the Board represent different Ministries and organisations of the Central Government.

During the period 1985-86, Educational Consultants India Limited prepared several project reports including Indira Gandhi National Open University, a report on establishment of an Engineering college and two Women's Polytechnic in J&K, a report for the establishment of Regional Engineering College at Jallandhur and a Master Plan for re-organisation of the University of Allahabad.

Programme of Apprenticeship Training

The programme of Apprenticeship Training for Engineering graduates and Diploma Holders under the Apprentices Act, 1961 (Amended in 1973) continued to be implemented through the four Boards of Apprenticeship Training located at Kanpur, Bombay, Calcutta and Madras. The Boards are having state level committees for better liaison. The cost of the stipend being paid to the apprentices is shared by the training establishments and the Central Government.

The number of apprentices engaged every year on 31st October for the last three years and as on 31st March, 1984 and 1985 are shown below :—

	Upto 31-10-83	31-10-84	31-10-85	31-3-84	31-3-85
Total Trainees	10910	12699	12761	12412	14605
Graduate trainees	3123	3946	3986	3817	4699
Diploma Holder	7787	8753	8775	8595	9906
Scheduled Caste	342	402	420	412	488
Scheduled Tribe	81	65	44	92	65
Minorities	713	806	756	759	818
Handicapped	2	7	7	4	5
Women	339	659	712	453	691

A number of supervisory development programmes for improving the quality of apprenticeship training and career guidance programme for the final year students of a few Engineering Colleges and Polytechnics have been organised by these Boards. The Boards are publishing journals where views of the Industries and educationists are being depicted. Some of the Boards have prepared training manuals.

The Special Vocational Education Training Scheme was launched in 1983-84 after a number of meetings with the State Governments for providing six months practical training to the students passing out from 10+2 vocational stream.

Administrative Staff College of India, Hyderabad

The College was set up in 1957 as a joint venture of the Government of India and the Industry. As a pace-setting institution for management development education in India and our neighbourhood, the College has been striving to preserve its role in this respect while at the same time widening its activities to cover those areas which are becoming increasingly important in the National context.

A distinctive feature of the College is its concentration on post-experience management development programmes in general management as well as in functional areas like production, marketing, finance, persons, material management, computer and investment planning. In 1984-85 the College conducted 86 courses attended by 1927 executives from Government, Public and Private Sectors including others. In addition, the college has completed 20 consulting assignments. It has also completed 34 research studies sponsored by Ford Foundation, Planning Commission, different Ministries of the Government of India, State Governments, and other Public and Private sector organisations and produced one book and published 49 papers/articles. The College plans to continue its International programmes on Regional Economic Management and South Asian Cooperation.

There is a budget provision of Rs. 2.50 lakhs under Non-Plan for the year 1985-86 for the College by the Department of Education to meet the differential in the cost and actual fees charged from the participants sponsored by the Central and State Governments and non-member organisations to the College programmes.

Board of Assessment of Educational Qualifications

The Board of Assessment for Educational Qualifications was set up by the Cabinet Secretariat under the Chairmanship of the Chairman, Union Public Service Commission. The Board advises the Government of India in all matters relating to recognition of Indian and foreign educational qualifications for purposes of recruitment to the posts and services under the Central Government in various fields excepting medical and allied subjects. The Bureau of Technical Education serves as the Secretariat for this Board.

8—759 Deptt. of Edu/85

CHAPTER 5

ADULT EDUCATION

The Seventh Five Year Plan document stipulates that adult literacy programme will be pursued with the objective of covering all illiterates in the age group 15—35 by 1990. The programme occupies an important position in the socio-economic developments of the country owing to its crucial role in human resource development and family welfare programmes. It forms an essential and integral part of the Minimum Needs Programme and the new 20-Point Programme. It has been envisaged to enroll all adult illiterates in the age group 15—35 by 1990. In the Sixth Plan period, significant strides have been made in enrolling 2.3 crores adult illiterates out of the estimated 11 crores in this age group; the remaining illiterates will have to be enrolled in the Seventh Plan period. An outlay of Rs. 360.00 crores—Rs. 130 crores under Central Sector and Rs. 230 crores in State Sector has been provided for the programme. Against the stipulated target of enrolment of 75.46 lakhs for 1985-86, the achievement upto September, 1985 is 70.43 lakhs i.e. 93.33 per cent.

In designing the Adult Education Programme, the Ministry of Human Resource Development is guided by the major thrusts visualised in the Seventh Plan, in addition to the parameters being followed in the Sixth Plan period. The major thrusts in the Seventh Plan include development of a programme of continuing adult education, launching of a mass movement involving voluntary organisations, students, teachers, employers, NYKs, NSS and the community; effective linkages with various developmental programme being administered by other Ministries/Departments, intensive utilisation of mass media—folk, traditional and modern; setting up of community life and continuing education centres in all the villages to provide effective and adequate post-literacy activities and hightened motivation. The parameters in vogue in Sixth Plan includes coverage of the districts having literacy rate below the national average, priority to the women, SC, ST and other weaker sections of the society, mobilisation and participation of voluntary agencies on large scale and involvement of students and teachers in the universities and colleges.

A brief description of the different schemes functioning, at present, is as under :

Rural Functional Literacy Project (RFLP)

This is a major Centrally Sponsored Scheme under which funds are provided on cent per cent basis, in accordance with the approved financial pattern to all the State Governments and Union Territory Administrations. Government has revised the pattern of financial assistance effective from February 1, 1984. The Scheme aims at setting up projects upto 300 centres covering one or two contiguous development blocks in each District and up to 100 centres in hilly area or areas with difficult terrain in some States. 513 RFLPs are, at present, functioning in all the States and Union Territories. Against stipulated target of 35 lakh adult illiterates to be enrolled during 1985-86, 32.74 lakh were enrolled by the end of September, 1985. A provision of Rs. 41.76 crores has been made under this scheme for the year 1985-86.

In addition to adult education centres sanctioned under the RFLP, State Government/Union Territory Administrations have also been requested from time to time to step up their own efforts under the State Adult Education Programme (SAEP) and establish at least an equal number of centres, matching those sanctioned under RFLP

Voluntary Agencies

The Ministry also provides financial assistance to voluntary agencies working in the field of adult education under which registered voluntary societies, public trusts and non-profit making companies are eligible to receive grants for projects of functional literacy and post-literacy, resource development, publications, holding of seminars etc. During 1985-86 projects were approved to 144 voluntary agencies to conduct 7,845 adult education centres and post literacy and follow up programmes, upto December 1985. A provision of Rs. 7.00 crore has been made under this scheme for 1985-86.

University and Colleges

With a view to promoting involvement of students and teachers from universities and colleges in the eradication of adult illiteracy in the age group 15—35 the University Grants Commission continued to provide financial assistance and support to 82 universities and 2151 colleges in 18 states/union territories. The number of Adult Education Centres sanctioned is 23,721.

Post-Literacy and Follow-up Programme

This Centrally Sponsored Scheme was put into operation in 1982-83 with the objective to ensure that the neo-literates who have completed basic literacy course do not relapse into illiteracy. According to the guidelines issued in 1982 the Adult Education Programme was required to be implemented in three phases, namely first phase of 300—350 hours spread over one year; second phase 150 hours spread over one year; and third phase of 100 hours spread over one year. The implementation of the Scheme as envisaged above has been reviewed and new guidelines have been evolved and communicated to all the State Governments/Union Territory Administrations. Under the new guidelines phase one and phase two have been combined to form a single learning continuum spread over one year, followed by phase three of 100 hours of post-literacy and follow up spread over the second year of the programme.

Fifteen States/Union Territories have been sanctioned grant during 1985-86 and the applications from 11 States/Union Territories are under consideration. A provision of Rs. 150 lakhs has been made under the scheme for 1985-86.

Shramik Vidyapeeth

The Vidyapeeths provide integrated non-formal education training facilities to the workers and their families both in the organised as well as in the un-organised sectors in the urban areas. Activities of these Vidyapeeths are polyvalent in nature catering to a wide range of requirements of beneficiaries and include training and development of skills. There are, at present, 36 Shramik Vidyapeeths. Three new SVPs at Paradeep, Aurangabad and Jodhpur have been set up during 1985-86. A provision of Rs. 75.00 lakh has been made during the year 1985-86.

Streagthening of Administrative Structures in States/Union Territories

For ensuring proper implementation of the programme in each State/Union Territory, financial assistance is provided to them for continuation/creation of necessary administrative structures, both at the State and the District level, in accordance with financial pattern approved under the Scheme. At present 26 States/Union Territories are receiving financial assistance under this Scheme. A budget provision of Rs. 250.00 lakh has been made during the year 1985-86.

State Resource Centre

There are 12 State Resource Centres which are being financed by this Ministry apart from five SRCs under State Governments/University Sectors. These State Resource Centres are responsible for providing teaching/learning material and organising training programmes for the field functionaries. The State Resource Centre at Indore (Madhya Pradesh) has been set up in 1985-86. In order to enable the State Resource Centres to function more efficiently and effectively, the existing administrative and financial pattern has been revised and a new pattern has been put into operation from 1-4-1985. Besides each of the four North Eastern States/Union Territories at Manipur, Tripura, Arunachal Pradesh and Sikkim has also been provided with a special cell to function, as Resource Centre from 1st April, 1985.

Evaluation and Monitoring

External Evaluation of the Adult Education programme is an important input to ensure the quality of the programme. It is proposed to entrust in-depth and purpose-built studies to established institutions of social sciences research to be chosen in consultation with the state governments. So far 59

studies have been conducted on different aspects of the Adult Education Programme. There is an inbuilt mechanism of monitoring and the programme is being monitored quarterly.

Mass Programme for Educational Literacy (New Scheme)

The scheme, envisages involvement of students and teachers in universities and colleges, NYKS, NSS, employers and individuals who are desirous to participate in the literacy campaign through "each one and teach one pattern. The scheme is based on voluntarism. However, literacy kits will be prepared and distributed by the State Resource Centres. The scheme will be administered and monitored through the existing structure by strengthening it.

New Education Policy

A nationwide debate has been initiated on the basis of document "Challenge of Education—a policy perspective" circulated by the Ministry in the context of formulation of new Education Policy on Education. In this context Directorate of Adult Education organised a National Seminar on Adult Education on 10—12 October, 1985 at New Delhi to elicit the views of the participants drawn from a wide cross sections of the society to recommend specific strategies for inclusion in the new Education Policy. Some of the State Resource Centres and State Directorates of Adult Education also organised seminars and submitted their reports to the Ministry. National Board of Adult Education met on 25-5-85 under the Chairmanship of the then Education Minister to review the adult education programme and to discuss mass movement for functional literacy, in order to recommend the dovetailing the existing adult education programme with the mass campaign to achieve the stipulated target of eradication of illiteracy.

International bilateral Cultural Exchange Programmes and Participation in UNESCOs Activities

A high powered delegation under the leadership of the then Education Minister participated in the Fourth International Conference on Adult Education in Paris. Delegations from India visited the Democratic and popular Republic of Algeria, USSR and Republic of Cuba to study programmes in the field of adult education under the Cultural Exchange Programmes. A two member delegation from German Democratic Republic visited India in January, 1986.

Directorate of Adult Education

The Directorate of Adult Education which serves as the National Resource Centre for the Adult Education Programme, has been conducting various programmes such as (i) Training, (ii) Preparation of teaching-learning material for illiterates and new-literates, (iii) monitoring, (iv) evaluation, (v) population education, (vi) research and (vii) media support to adult education programme. During 1985-86, the Directorate provided resource support to the newly established Shramik Vidyapeeth. The Directorate continued to provide guidance and leadership to the State Resource Centres and also monitored the activities by bringing out quarterly reports. Under the UNICEF assisted projects 'non-formal education for women and girls'; 17 kits of material were brought out. Under the UNFPA assisted project 'Integration of Population Education in Adult Education Programme' the preparatory project was implemented in collaboration with 12 SRCs by holding workshops/seminars and bringing out publications. Three National seminars at New Delhi, Lucknow and Pune were organised. A regional training workshop in literacy was jointly organised by UNESCO Regional Office for Education in Asia and the Pacific, the Ministry of Human Resource Development and the Directorate in New Delhi from October 23 to November 4, 1985. The Directorate continued to monitor the implementation of the Adult Education Programme and brought out quarterly progress reports in consultation with National Informaties Centre. The Directorate has computerised the monitoring system and 3 quarterly reports have been prepared with the help of the computer. Two monographs entitled "Evaluation of Adult Education Programme—A Synoptic Account". 'Issues and Approaches in the training of Adult Education Functionaries—A Synthesis of Findings' based on the evaluation report submitted by external agencies were brought out. Other two monographs are under preparation. Under the Scheme of financial assistance to the institutions and individuals desirous of conducting research in the area of adult education and six research studies are currently in progress. Directorate has also brought out software on motivational and promotional aspects of the programme. Thirteen publications were brought out during the year. Three more publications are at various stages of printing. Ten publications on different aspects of the programme were also brought out by the Ministry.

CHAPTER 6

EDUCATION IN THE UNION TERRITORIES

Education in the Union Territories constitutes a special responsibility of the Central Government. An account of the educational facilities and activities undertaken during the year in respect of each of the Union Territories is given in this Chapter.

DADRA AND NAGAR HAVELI

There are 160 Primary Schools with enrolment of 16,886 (10,223 boys and 6,663 girls) including Scheduled Castes 509 (279 boys and 230 girls) and Scheduled Tribes 13,759 (8,507 boys and 5,252 girls). There are 4 High Schools and 3 Higher Secondary Schools. The total student strength of High Schools and Higher Secondary Schools is 2,429 (1,531 boys and 898 girls) including Scheduled Castes 217 (138 boys and 79 girls) and Scheduled Tribes 1,187 (821 boys and 366 girls). Vocational, drawing, tailoring and technical as well as agricultural subjects are introduced in all High Schools and Higher Secondary Schools. Facilities like free education to all students upto higher secondary level, free mid-day meal to all students upto elementary education, free note-books, textbooks and other educational material to all SC/ST students are provided in the Union Territory. There are 10 Social Welfare Hostels including one Ashramshala and 2 Girls Hostels in which SC/ST as well as economically backward classes students are admitted and provided with free Boarding and Lodging. During 1985-86, there were 600 inmates in these hostels. A number of financial concessions like cash awards for punctual attendance to SC/ST students; incentive awards for standing Ist, IInd and IIIrd in Annual Examinations; incentives for securing more than 60% marks in Sanskrit subject in standard IX and X; reimbursement of examination fees paid by SC/ST students; incentives like cash awards to talented students who secured Ist, IInd and IIIrd rank in SSC/HSS examinations, national scholarships to students for higher education; Post Matric Scholarships to SC/ST students, etc., are being allowed in the Union Territory.

Under the Adult Education Programme during 1985-86, 66 centres are likely to be opened with about 2.000 adult learners.

Seats have been reserved for various courses like Medical, Engineering and other Technical courses for the students belonging to the Union Territory. The National Population Education project was introduced from October 1983 and under this programme 412 primary/middle school teachers, 89 secondary teachers have been covered so far. Various teachers of educational institutions of the Union Territory were deputed for in-service training programmes and seminars like computer literacy programme, subject orientation programme, vocational guidance and population education seminar etc.

PONDICHERRY

The Union Territory of Pondicherry occupies the pride of place among the educationally developed States/Union Territories in the country with an over all literacy rate of 54.23%. The literacy rate among the Scheduled Caste population in the Union Territory is 32.36%.

Educational facilities have been provided almost at the door step of the villagers in as much as there is now a primary school within 1 km., a middle school within 3 km. and a high school within 5 km. of every census habitation. There are 109 pre-primary schools with the enrolment of 5,730 students; 356 primary schools with the enrolment of 91,053 students; 103 middle schools with the enrolment of 44,521 students, 64

high schools with the enrolment of 16,447 students and 19 Higher Secondary Schools with the enrolment of 5,484 students in the Union Territory. Facilities like adequate qualified staff, library books, teaching aids and scientific equipments, etc. have been provided in the schools.

Special emphasis is being laid on a few extra curricular activities like opening of science corners and eco-clubs in the schools to which the response has been quite encouraging. In the wake of setting up of 1 KW T.V. centre in Pondicherry providing of T.V. sets to the schools has been taken up and this has gone a long way in making education more interesting for the children. Facilities like free uniforms, textbooks, items of stationery, cash grants to students and merit prizes and merit scholarships have been provided. Supply of free mid-day meals to children of primary classes continued to be one of the incentives provided by the Union Territory Administration. These have resulted in nearly cent per cent enrolment in the elementary level and cutting down of annual drop out rate at the primary level to 3.6% and at the middle school level is 6.2%.

University Education reached a climax with the establishment of the Pondicherry University as a Central University during the current year. The Union Territory now provides for almost all major courses for its students and to that degree its dependence on the neighbouring States has been reduced. A new innovation—opening of evening college mostly for working girls and housewives—has been attempted and this received quite encouraging response. As of previous years, the students belonging to weaker sections of the society continued to enjoy free education up to degree level.

Aspects like adult education, physical education, NCC, sports and youth welfare continue to receive the attention of Union Territory Administration.

The long cherished demand of setting up of an engineering college for Pondicherry was fulfilled with the commencement of classes for the first year students in Pondicherry Engineering College from the current academic year. The department also managed to obtain a few seats in various engineering disciplines not available in the Pondicherry Engineering College for the student aspirants in the Engineering Colleges of the neighbouring States. Establishment of pre-examination coaching centres for minority communities and establishment of district centres for teaching of English language are worth mentioning.

ARUNACHAL PRADESH

Arunchal Pradesh spreads over 83,578 square Kms. of lush green hills and dales. As per 1981 census 6,31,839 people live in 3,000 habitations. 110 tribes of this Territory speak different dialects and profess different faiths.

There are 249 pre-primary schools, 998 primary schools, 151 middle schools, 41 secondary schools, 23 higher secondary schools and 3 colleges in the Government sector. Besides, there are a number of aided schools. The enrolment in pre-primary schools is 6398, in primary schools (I-V) is 85,613, in middle schools (VI–VIII) is 20,993, in secondary schools (IX-X) is 5,484 and in higher secondary schools (XI–XII) is 2,184. A number of institutions have been opened/upgraded during 1985-86.

The target of cent per cent enrolment of children (age group 6 to 11 years) has already been achieved. To attract more children of school going age, various incentives like distribution of free text-books, school uniforms, stationery, clothings for the students residing in the hostels, stipend in lieu of ration for the students residing in the hostels attached to Primary, Middle and Secondary/Senior Secondary Schools, merit scholarships for talented students and mid-day meals, etc. have been provided.

491 centres were opened upto the end of 1984-85 under RFLP. Another 300 centres have been opened during the year thereby raising the total number to 791. Under the State Adult Education Programme, 370 centres with an enrolment of 7491 adults are functioning. At present, 13572 male and 7590 female adults are attending adult education centres

regularly. To attract more adults to the centres, certain incentives have been introduced. For the female adults, sewing machines and knitting machines have been supplied in the centres. For the males, games and sports are introduced and musical instruments have been supplied.

24 scout troops, guide companies, bulbul flocks and Cub-packs have been added to the existing strength. 150 scouts and guides have been deputed to participate in the National Jamboree at Bangalore. Training courses for patrol/leaders scouts and guides are being held regularly. Two junior division NCC units (girls) and nine junior division NCC units (boys) have been opened this year. The NCC Cadets are participating in the training courses organised by Directorate of NCC.

Enrolment in colleges is 983. The students residing in the hostels are provided stipends @ Rs. 210/- and 240/- per month. The colleges have been affiliated to Arunachal University which has started functioning w.e.f. 1st April, 1985.

To recognise the meritorious services rendered by the teachers in the different areas, the scheme of State Award to teachers was introduced in 1983-84. The selected teachers are awarded Rs. 1500/- cash and a merit certificate.

Hindi and English textbooks produced by NCERT are being adapted to suit the particular requirement of the territory. To make the teaching of Science and Mathematics popular in the territory, the teachers have been trained in the new techniques.

CHANDIGARH

There are 260 schools, including Government aided, recognised, central and un-recognised schools covering children from pre-primary to the senior secondary stage. All these schools cater to the educational needs of a little over 1,03,700 students at the elementary stage and about 18,400 at the secondary stage. The enrolment in the elementary stage (I-VIII) during 1985-86 is 1,03,700 and the enrolment in secondary stage (IX-XII) is 18,400.

All efforts are made for enrolling all the eligible children in the school going age group (6–14 years). 100% target has been achieved in so far as children in the age group of 6-14 are concerned and the new schools were opened to cover the additional enrolment of over 6,000 students.

Among the achievements of the Union Territory Administration, the following are worth mentioning :—

(a) There is a school within easy reach of every child.

(b) There is no single teacher school in the Union Territory.

(c) School buildings, by and large, are attractive and provide all the facilities which make the study of the little kids in the school comfortable.

(d) For the benefit of weaker sections of the society, Creches, Bal Wadis and Nurvsery classes have been started in most of the village and labour colony schools.

Incentives like attendance scholarships to girls (3,600 beneficiaries), attendance scholarships to scheduled caste children (82 beneficiaries), free stationery and uniforms to scheduled caste students (10,100 beneficiaries), free text-books to children (10,100 beneficiaries), talent scholarships to scheduled caste students (25 beneficiaries), extra coaching to scheduled caste students who are weak in studies 2,200 beneficiaries) and mid-day meals to children (34,500 beneficiaries) are available.

20 Centres of Non-formal Education are being run at present in the Union Territory against 12 in the preceding year. These centres are mostly attached with the Government schools. About 600 students have been admitted to these centres.

Vocational subjects have been introduced in two senior secondary schools during 1985-86 and the remaining schools would be covered during the subsequent years.

Sports and games are regular activities of schools in Chandigarh. To encourage school children's participation in sports activities, the Education Department organises regular tournaments and competitions in both major and minor games and athletics. The students also participate in national games and other tournaments which are held at national level. On-the-spot art competition is a regular feature of the schools in the Union Territory. More than 8,000 students participated during the year in various items of competition. Other co-curricular and cultural activities also constitute a regular feature of the schools.

State Institute of Education, Chandigarh provides qualitative improvement in school education through in-service courses, on-the-spot guidance in schools, orientation in teaching-aids, organising various co-curricular activities of students and their teachers at State level and publication of educational articles and write-ups.

In the field of adult education, against the target of 6,000 learners, 6,800 learners were covered through various projects.

DELHI

The Union Territory of Delhi is densely populated and is mostly urbanised. Out of the present population, the number of school age children constitutes well over 52%. The stage-wise enrolment in the primary, middle, secondary and senior secondary classes is as under :

(a) Primary Stage Classes I–V (age group 6–11 years)	8.02 lakhs.
(b) Middle Stage Classes VI-VIII (age group 11–14 years)	4.18 lakhs.
(c) Secondary Stage Classes IX–X (age group 14—16 years)	
(d) Senior Secondary Stage Classes (age group 16–18 years)	1.04 lakhs.

Education Department, Delhi Administration has to cater to the additional enrolment of about 33000 students at middle, secondary and senior secondary stage every year. 750 sections have been added during the year 1985-86 to the already existing 22443 sections by :

(i) Opening of 11 new Government Middle Schools.

(ii) Bifurcation of 8 urban schools.

(iii) Upgradation of 26 Government Middle Schools to Secondary Stage.

(iv) Upgradation of 18 Government Secondary Schools to Senior Secondary Stage.

Facilities like free transport for girl students of rural areas (4375 beneficiaries); free supply of school uniform (50,000 beneficiaries); merit and open merit scholarships to SC/ST students (682 beneficiaries); remedial/special coaching for SC/ST students and the students belonging to other weaker sections of society (400 beneficiaries); supply of exercise books on concessional rates (4600000 beneficiaries) have been provided.

The number of schools at the middle stage is 343, at the secondary level, 238 and at the Senior Secondary level 620. Each secondary school has a middle department and each Senior Secondary School has middle as well as Secondary Department.

Delhi Administration is running 68 regular female Social Education Centres and 25 part-time male Social Education Centres in the rural area of Delhi.

Under the scheme of urban project, Delhi Administration is running 20 adult education projects in the Urban Area of Delhi. Each project consists of 100 adult education centres with an enrolment of 20 learners at each

centre. Efforts are made to enrol maximum number of women in the centres.

The rural functional literacy project and non-formal educational centres are also being given due priority. A number of training courses and orientation programmes were held during the year and about 55 TGTs/ newly appointed EVG counsellors benefited by these programmes. The teachers training institutes continued imparting training during the year. The annual turn out of trained teachers is 100.

Physical Education aspect is also being given due consideration. Delhi Council of Sports organises several sports activities in the Union Territory of Delhi. Sahitya Kala Parishad has been giving grants to young and budding talents.

Programmes like adult literacy, non-formal education, tree-plantation, mid-day meals, free supply of textbooks, free supply of uniforms, etc. are being implemented by Delhi Administration.

GOA, DAMAN AND DIU

In Goa, Daman and Diu, enrolment in elementary education (Classes I-VII) during the year 1985-86 works out to 2,21,695 as against 2,19,917 during the year 1984-85. The enrolment for secondary education during the year 1985-86 has been 55,250 as against 54,288 during 1984-85. The enrolment in higher secondary classes has been 12,221 during 1985-86 as compared to 11,005 during 1984-85.

There are 18 colleges for general and professional education of which 9 colleges cater to general stream such as art, science and commerce, the remaining being professional colleges viz., Architecture, Medical, Pharmacy, Dental, Engineering, Fine-Arts, Law and Teachers Training College. The total enrolment of all these colleges during 1985-86 has been 8,974 as compared to 8,223 during 1984-85.

The scheme regarding pre-school education was implemented in the Union Territory in March 1983 and at the end of the year 1984-85, 68 centres had been opened, with 1,648 children. During the year 1985-86 the coverage has been extended to 1,410 children. Two Ashram Shalas are providing free lodging and boarding to tribal students.

Goa, Daman and Diu Board of Secondary and Higher Secondary Education has approved 19 vocational subjects for Higher Secondary Schools. Out of 22 Higher Secondary Schools/Units, 5 Higher Secondary Schools/Units have already started vocational courses. Some of the schools in the Union Territory have also been supplied with the Computer system and instructions are being imparted through these. Bal Bhavan Board has also been constituted and a Bal Bhavan at Panaji is being commissioned shortly.

During the year 1985-86, 390 Adult Education Centres have been opened in rural areas with an enrolment of 6,847 adults (2,571 male, 4,276 female).

Education is provided free to all the students from Primary to Standard X. Education is also provided free to students of class XI and XII whose parents income is upto Rs. 4800/- per annum.

School going children (6-11 years age group) are provided with mid-day meals and the number of students benefitting from the scheme is estimated as 10.000. Monetary incentives were given to 10534 students at Primary and Middle School level during 1984-85. About 10,000 students are likely to be covered during 1985-86. Book grants at Primary/Middle School level, Scholarships at Middle/Secondary and College level are awarded to students belonging to economically backward classes.

Goa College of Engineering is conducting courses in civil, mechanical and electrical engineering with an intake capacity of 40 students in each branch.

9—759 Deptt. of Edu/85

Physical education in schools is also being given due consideration and guidance is given in the implementation of physical education, scouts and guides, social services, N.C.C. and sports programmes. Refresher courses and seminars are also conducted for the benefit of in-service persons.

MIZORAM

In Mizoram the primary education is from classes Ist-IVth, Middle education from classes Vth-VIIth and high school education from classes VIIIth-Xth. During the recent years, several middle and high schools were taken over as Government schools and quite a number of schools were also brought under the deficit systems of grant. The intake capacity of the teachers training institute at Aizawl and Lunglei has also increased considerably. The usual criteria for opening of schools like the catchment area, distance etc. cannot be rigidly followed in Mizoram due to pecularity of the topography.

The number of trained persons in physical education has increased substantially. Under the science promotion, science motivation courses as also special training of teaching of science and mathematics were organised. The tribal research institute, Mizoram is catering to the requirements of reprinting of rare and old books, new books and is also training persons in traditional dances and music etc. Library services are also given due weightage and small rural libraries are functioning in Mizoram.

Scholarships like pre-martic scholarships, post-matric scholarships and talent search scholarships, sainik school stipends and hostel stipends are awarded to students and the number of beneficiaries has also increased substantially over the years.

Various literacy seminars and camps were organised during the period. The number of adult education centres, social education centres has also increased. Citizens aid service has already been set up to help people in various ways. Necessary grants-in-aid is given to various voluntary organisations functioning in the field of adult (social) education.

ANDAMAN & NICOBAR

The educational institutions in Andaman and Nicobar Islands comprise a Government College, one polytechnic, one B.Ed. College, one Teacher Training Institute besides senior secondary schools, secondary schools, middle schools, primary schools and pre-primary schools. In addition, a large number of private nursery schools and Bal Wadis are functioning in different parts of the Union Territory.

During the year 1985-86 a few new primary schools were opened and a few primary schools were upgraded to middle schools. Some middle schools were upgraded to secondary schools and some secondary schools were upgraded to the level of senior secondary schools. Additional sections in different media were also introduced according to the requirement of enrolment at various places.

Free textbooks were provided to the children at elementary stage as also to some children at secondary stage. Free mid-day meals to all children upto VIIIth standard as also free uniform to students belonging to weaker sections of the society besides free stationery to all tribal students, were given.

The Teacher Training Institutes continued to conduct B. Ed. and J.B.T. courses. Under the Adult Education Programme more than 200 centres are functioning in the Union Territory. The present enrolment in these Adult Education Centres is about 4,500.

Science seminars, workshops and exhibitions were organised during the year at different places. Under the scheme of integrated education, teachers were selected for undergoing the training and after completion of training they were posted as resource teachers for educating disabled.

LAKSHADWEEP

The Administrator is the head of all departments and Director of Education is the Controlling Officer of the Education Department.

The educational institutions consist of two colleges, besides high schools and senior basic schools, junior basic schools and nursery schools.

Primary education has been provided in all the islands. The number of students on roll in primary classes as also at high school has shown considerable improvement during the year over the previous year. Textbooks, writing materials and mid-day meals are provided to children in primary and middle school classes free of cost.

The scheme for payment of scholarship at the rate of Rs. 40/- per month to the native students studying in high schools is being continued Senior Division NCC and Junior Division NCC (Naval) are functioning in the Union Territory. Camps are regularly held both for Senior Division and Junior Division NCC cadets.

The two colleges namely Jawaharlal Nehru College, Kavaratti and Mahatma Gandhi College, Androth have more than 600 students on their rolls and these colleges run pre-degree classes. The students from the Lakshadweep Island are admitted to various educational institutions on the mainland and a number of seats are reserved for them in engineering and medical colleges etc. on the mainland. The expenses on education on mainland for Lakshadweep scheduled tribe students are met by the Administration as per the existing approved scholarship rules.

Parent-Teachers' Association and Teachers Forum are functioning in all islands. Scout troops and girl guides are functioning in different schools. Uniforms and training material are supplied to these troops. More than 30 Adult Education Centres are functioning in the island at present.

CHAPTER 7

SCHOLARSHIPS

The Department of Education under the Ministry of Human Resource Development administers a number of scholarships programmes including those offered by other countries to enable the Indian students to receive further education. The Department also provides scholarships to nationals of other countries on a bilateral basis or otherwise. The important schemes being implemented are mentioned below.

National Scholarships Scheme

Under this scheme, which is implemented through the State Governments/Union Territory Administrations, scholarships are awarded on merit-cum-means basis. During 1985-86, as many as 27,000 fresh scholarships were awarded. The rates of scholarships, which were increased with effect from July 1, 1981 vary from Rs. 60/- p.m. to Rs. 120/- p.m. for day scholars and Rs. 100/- p.m. to Rs. 170/- for hostellers depending on the course of study.

National Loan Scholarships Scheme

Under this scheme, 20,000 scholarships were awarded in 1984-85. The scholarships are awarded on merit-cum-means basis. The scheme is implemented through the State Government/Union Territory Administrations. The amount of loan varies from Rs. 720/- to Rs. 1720/- per year depending upon the course of study.

Government of India Scheme of Scholarships in Approved Residential Secondary Schools

The objective of the scheme is to provide educational facilities to talented but poor students who are otherwise unable to avail themselves of the opportunity of studying in good residential schools on their own. Every year 500 scholarships are awarded on merit-cum-means basis to students of the age group of 11 to 12 years whose parental/guardian income does not exceed Rs. 500/- p.m. Fifty per cent of the scholarships are awarded on all India merit basis and the remaining 50% are allotted to States and Union Territories on the basis of their population, subject to fulfilment of a prescribed minimum standard. The candidates are selected on the basis of two examinations, the preliminary examination conducted by the State/Union Territory Governments and the final examination conducted by the Central Board of Secondary Education, Delhi. 15% and 7½% of the scholarships are reserved for SC and ST candidates respectively. The scholarships are tenable for the entire period of secondary schooling, including the plus 2 stage of education in approved residential schools. Scholars are entitled to full amount of tuition fees, residential charges, cost of books and stationery, in addition to pocket money, uniform clothing allowance, and excursion charges at the rates/ceiling decided by the Government. A travel grant is also admissible to the scholars and their escorts according to the rates prescribed.

Scholarships to Students from Non-Hindi speaking States for post-Matric studies in Hindi 1985-86

The object of the scheme, which was started in 1955-56, is to encourage study of Hindi in non-Hindi States/Union Territories and to make available to the Governments of these States/Union Territories suitable personnel to man the teaching and other posts requiring a knowledge of Hindi. 2,500 scholarships were allocated among various non-Hindi speaking States/Union Territory Administrations during 1985-86. The rates of scholarships vary from Rs. 50/- to Rs. 125/- per month, depending upon the course of study and the States/Union Territories in which study of Hindi is pursued.

Research scholarships to products of Traditional Institutions engaged in the Study of Classical Languages other than Sanskrit like Arabic and Persian

Twenty scholarships are awarded every year under this scheme. In 1984-85, 20 candidates were selected for this award.

National Scholarships at Secondary Stage for Talented Children from Rural Areas

As in 1984-85, 33,000 fresh scholarships have been allocated in the year 1985-86. The break-up of these scholarships is given below.

			Total number of scholarships
(a)	General Category . .	Three scholarships per Community Development Block	15,000
(b)	Children of Landless Labourers	Two scholarships per Community Development Block	10,000
(c)	Scheduled Caste Children	One scholarship per community Development Block and one additional scholarship per Community Development Block having 20% or more scheduled caste/population	6,500
(d)	Scheduled Tribe Children	Three scholarships per Tribal Community Development Block	1,500

The scheme is implemented through State Governments and Union Territory Administrations.

General Cultural Scholarships Scheme

Under this scheme, 180 scholarships are awarded every year to nationals of selected African, Asian and other countries for higher education in India, so as to promote friendly relations between India and other countries. While a majority of the scholarships is earmarked for foreign students, some are awarded to students of Indian origin domiciled in other countries.

The value of a scholarship is Rs. 600/- p.m. for under-graduate courses and Rs. 750/- p.m. for post-graduate courses. In addition, students are paid Rs. 500/- p.m. as summer vacation allowance. The expenditure incurred by the scholars on medical treatment and study tours is also reimbursed. While expenditure on fees and other compulsory charges are borne by the Ministry, hostel and mess charges are borne by the scholars out of the allowance paid to them.

Scholarships/ Fellowships for Nationals of Bangladesh

Under this scheme, 100 scholarships are awarded every year to the nationals of Bangladesh. Selection is made by the Government of Bangladesh in consultation with the Indian High Commission in Dhaka. The rates of scholarships under the scheme have since been revised. Presently the amount of scholarship for under-graduate courses is Rs. 600/-p.m. and Rs. 750/- p.m. for post-graduate courses. In addition, 10 scholarships have been awarded during the year 1984-85 to Bangladesh students for pursing studies in Sanskrit and Pali languages.

Scholarships to the Nationals of Mauritius

The total number of scholarships awarded to nationals of Mauritius has been increased to 100, inclusive of the number of scholarships already awarded under various programmes of the Government of India. The value of scholarship is Rs. 600/- p.m. for under-graduate courses and Rs. 750/- p.m. for post-graduate courses besides summer vacation, book allowances, tution fee and other compulsory charges of the Institution, be sides expenditure on their two-way international journey. Since addition to the number of scholarships was effected at a time when the admissions to most universities had been finalised, the additional scholarship to Mauritius nationals could be awarded only during 1985-86.

Scholarships for Study Abroad

Fifty Indian scholars have been selected for award of scholarships in 1985-86 for study abroad. These scholarships are awarded for graduate study in printing technology, post-graduate studies in naval architecture and paper technology, besides doctoral and post-doctoral studies in humanities, science and technology. Only those candidates with a total parental income of Rs. 1,000/- p.m. or less, excluding standard rebates are eligible.

Scholarships/Fellowships offered by foreign Governments/ Organisations/Institutions

Nominations have been made by this Ministry to the following countries: Poland-7, USSR-8, GDR-10, Czechoslovakia-3, Bulgaria-4, FRD-11, Denmark-2, France-29, Japan-10, Matsumae International Scholarships

(Japan)-8, Hoise University Fellowship (Japan)-4, Netherland-4, Austria-2, Sweden-1, Spain-2, Norway-6, Italy-21, Mexico-4, Turkey-4, Korea-1, USA-3, Indonesia-2, Hungary-9, Trinidad and Tobago-2, Jamaica-3, Hongkong-1, New Zealand-5, Australia-4, Jawaharlal Nehru Memorial Trust, U.K.-2, Foreign and Commonwealth Scholarship-6, Science Research Scholarship-1, Agatha Harrison Memorial Fellowship-1, British Technical Cooperation-7.

Commonwealth Scholarships and Fellowships offered by the Government of U.K./Canada

Out of 138 nominations made, approval for 67 candidates has been received by December, 1985.

Commonwealth Education Cooperation Programme

Three Senior Educationists were selected from Nigeria, Malta and New Zealand for visitorship during 1985-86.

Partial Financial Assistance Scheme

Financial Assistance in the form of a loan limited to Rs. 6000/- is given to Indian students/academics desirous of going abroad and who have already obtained scholarships, Financial assistance from other sources but are short of funds to meet the cost of passage. During the period under report, 4 candidates were granted assistance.

British Council Visitorship Programme

More than 150 scientists, academicians and medical specialists have benefited under the British Council Visitorship Programme for mutual appreciation of important developments in their areas of speciality.

Scholarships for Foreign Students for Study/Training in India

During the year under report, India offered about 300 scholarships to the following countries for studies in various fields, as under the bilateral Cultural Exchange agreements :

Senegal, France, Federal Republic of Germany, USSR, Phillipines, Belgium, Norway, Iraq, Arab Republic of Egypt, Poland, Turkey, Czechoslovakia, Mexico, Afghanistan, Greece, Somalia, Italy, Yugoslavia, Syria. People's Democratic Republic of Yemen, Hungary, Vietnam, Bulgaria, Tunisia, Cuba, Portugal, Malaysia, Qatar, Sri Lanka, Bahrain, Burma, Iran, Kenya, Democratic People's Republic of Korea, Mauritius, Japan, Algeria, Australia, United Arab Emirates, Cyprus, Sudan, Ethiopia, Jordan.

Commonwealth/ Scholarships/ Fellowships Plan

Seventy-five scholarships are offered to various scholars coming from the following countries, viz., Australia, Barbados, Canada, Cyprus, Botswana, Fiji, Ghana, Kenya, Lesotho, Malaysia, Mauritius, Nigeria, New Zealand, Sri Lanka, Sierre Leons, Seychelles, Swaziland, St. Lucia, Grenada, Dominica, Tanzania, Tonga, Neore, Malawi, Papua New Guinea and other South Pacific Islands excluding Western Samoa, Trinidad and Tobago, the United Kingdom, Uganda and Zambia.

Dr. Amilcar Cabral Scholarship

Under the Dr. Amilcar Cabral Scholarship to African Students, one offer has been made.

Dr. Aneurian Bevan Memorial Fellowship

Under the Dr. Aneurin Bevan Memorial Fellowship Scheme to United Kingdom, one offer has been made.

Technical Cooperation Scheme of the Colombo Plan

Under the Technical Cooperation Scheme of the Colombo Plan, assistance is offered for placement of scholars coming from the following countries namely, Afghanistan, Burma, Bangladesh, Bhutan, Fiji, Iran, Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Nepal, Phillipines, Papua, New Guinea, Korea, Sri Lanka, Singapore and Thailand.

Special Commonwealth African Assistance Plan

Assistance offered to scholars coming from foreign countries under the Special Commonwealth African Assistance Plan includes those from Botswana, Zambia and Zimbabwe.

Commonwealth Education Co-operation Plan-Training of Craft Instructors

Ten bursaries have been offered to nationals of Commonwealth countries in Asia, Africa and Latin America for training of Craft Instructors in various trades at the Institutions under the control of Directorate General Employment and Training for a period of one year. These bursaries are not earmarked for any particular country.

CHAPTER 8

BOOK PROMOTION AND COPYRIGHT

Books are an essential instrument of education. With the expansion of educational facilities in the country, the demand for books has intensified both in terms of quality and quantity. Books in greater number as also books on various topics, have to be produced and made available to the public at moderate prices. In the area of book promotion, the steps taken by the Ministry are meant to promote the production of good quality books at reasonable prices, encourage indigenous authorship, help the Indian book industry in the solution of its problems and promote the reading habit among masses. Some of the important programmes undertaken in this regard are briefly described in the following paragraphs.

NATIONAL BOOK TRUST

The National Book Trust was set up in 1957, as an autonomous organisation with the objectives of producing and encouraging production of good reading material at moderate prices and fostering bookmindedness among the people. In pursuance of these objectives, the Trust has been producing books in Indian languages and English, in well defined series. To promote bookmindedness, the Trust organises Book Fairs at national and regional levels and holds seminars and symposia on various aspects of bookwriting. The Trust also participates (on behalf of Indian publishing industry) in book exhibitions held abroad to promote book exports. The Ministry and the Trust work in close association with each other. The Trust has two regional offices at Bangalore and Bombay and eight Book Centres at Amritsar, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Mysore, Santiniketan and New Delhi.

Publishing Programme

Some of the important series under which the Trust publishes books are : India—The Land and the People, National Biography, Young India Library, Folklore of India, Popular Science and World of Today. Since its inception till March 31, 1985, the Trust has brought out 2920 titles under these series (543 in English and 2377 in Indian languages). During 1985-86, the Trust has brought out 95 titles by the end of December.

Besides the above series, the Trust has two major publishing programmes for national integration, namely, Aadan Pradan and Nehru Bal Pustakalya Series. Under the Aadan Pradan series, the Trust has so far brought out 609 titles in various languages and 10 more titles out of projected 18 are likely to be published during the current financial year. Under the Nehru Bal Pustakalya series, 1139 titles have been brought out till December 31, 1985. In addition, 15 more titles are likely to be published by the end of the current financial year.

Book Fairs

The Trust also organises book fairs and book festivals at national and regional levels. The Trust has so far organised 12 National Book Fairs in important metropolitan cities of India and over 102 regional book exhibitions. During 1985, the Trust organised a Book Festival at Bhubaneshwar, a National Book Fair at Patna, a National Children Fair at Allahabad and an exclusive exhibition of books from Bangladesh at Calcutta and New Delhi. The Trust also organised the New Delhi World Book Fair in February 1986.

Subsidized Scheme of University Level Books

To encourage indigenous authorship, the Ministry has a Scheme of Subsidized Publication of University Level Books, written by Indian authors, with a view to making them available to the students at reasonable prices. This scheme is being implemented since 1970 through National Book Trust. The total number of books subsidized till March, 1985 is 696, and 46 more titles have been subsidized during April—December, 1985. 30 more books are likely to be subsidized by 31st March, 1986.

The scope of the Scheme which originally covered books in English has been extended to cover University level books in Hindi as well as technical books at Polytechnic level in both English and Hindi.

Publication of Low Priced University Level Books of Foreign Origin

The Ministry is operating 3 bilateral programmes, in collaboration with the Governments of the U.K., the U.S.A. and the U.S.S.R. to make available standard books of foreign origin to the Indian University students in low priced editions. Latest editions of books are considered for coverage under these programmes and are assessed by expert agencies from the standpoint of their suitability for Indian students. So far about 720 British, 1620 American and 530 Soviet books have been published under these programmes.

National Book Development Council

National Book Development Council was set up in 1983 as a representative body of the different interests connected with the book field with a view inter alia : (i) to lay down guidelines for the development of the book industry in the context of overall requirements of the country; (ii) to foster bookmindedness; (iii) to encourage authorship, particularly in Indian languages and suggest measures for safeguarding the interests of the authors; and (iv) to draft a national book policy.

The Council has made a large number of wide-ranging recommendations covering various aspects of the book industry, such as, shortage of paper and its non-availability, lack of credit facilities to the book industry, book import policy, the problem of book distribution, need for a comprehensive national book policy and the urgent need to improve author-publisher relationship. These recommendations have been taken up for implementation.

A Working Group which was set up in March, 1985 to draft a National Book Policy covering book production in all regional languages and inter-related aspects of book production, is likely to finalise its report by April, 1986.

Other Book Promotion Activities

Under the cultural exchange programmes, delegations of Indian and Soviet writers were exchanged during 1985. Another delegation of Indian writers also visited France during this period.

Indo-Soviet Literature Project

The Indo-Soviet Committee set up for the publication of contemporary creative works of both the countries had formulated a project to publish the translations of the 20th Century literature of India and Soviet Union in about 20 volumes each by 1995.

Import of Books

During 1985-86, the liberalised Import Policy was continued and import of educational, scientific and technical books and journals, news-magazines and newspapers and records for learning of languages were allowed under Open General Licence. This facility is subject to a ceiling of 1,000 copies of a single title per importer and in cases where more than 1,000 copies of a single title were required, the Ministry's prior permission had to be obtained. Recognised institutions could import teaching aids, micro-films and micro-fiches of educational nature under Open General Licence. The import of foreign editions of books for which editions of Indian reprints are available was not allowed. Import of foreign reprints of Indian publications was also not allowed.

Dealers in books with a purchase turnover of books valuing Rs. 3 lakhs or more, were eligible to apply for import licences on the basis of 10% of their purchase turnover for the import of books other than those covered by Open General Licence. In addition, recognised schools, colleges and libraries were allowed to apply for import licences upto a value of Rs. 25,000/- per institution for the import of licenceable items.

The concession for the release of post parcels containing books, magazines and periodicals without the importers having to produce the import licences continued to be available during 1985-86.

Book Export Promotional Activities

India is one of the 10 major book producing countries of the world, and ranks 3rd in production of English titles. To promote sale of Indian books and translation/reprinting rights abroad and for securing printing jobs from abroad, steps are being taken to publicise our books through participation in international book fairs and organising special exhibitions of Indian Books, by conducting market studies and commercial publicity through circulation of annotated catalogues, brochures etc.

In 1985-86 India participated in the International Book Fairs/Exhibitions held in London, Manila, Toronto, Kualalampur, Singapore, Frankfurt, Moscow, Belgrade and Cairo. Special exhibitions of Indian Books were organised in Indonesia, Traindad and Tobago, Ethiopia, Sudan, Bangladesh, German Democratic Republic, France and Kenya. Book exhibitions are also proposed to be organised in Iran and Burma during 1985-86.

As a result of participation in the International Book Fairs/exhibitions abroad, our export of books including the journals and periodicals for the year 1985-86 is estimated to be about 25 crores of rupees.

Raja Ram Mohan Roy National Educational Resources Centre

The Raja Ram Mohan Roy National Educational Resources Centre was established in July, 1972. The Centre functions as an information-cum-research Centre and provides documentation and statistical analysis facilities in regard to details of import of books. The Centre has under one roof, a large collection of University level books produced since 1965 in all Indian languages in various disciplines. The Centre conducts on-the-spot evaluation of indigenous books to assess their usefulness for University level students and organises exhibitions of these books in various Indian Universities. During 1985-86, the Centre organised 6 such exhibitions at Jammu, Siliguri, Patna, Kolhapur, Madras and Tirupati.

The Centre has been designated as a national agency for operating the International Standard Book Numbering System in India. In this connection, India participated in the Annual meeting of International Standard Book Numbering Agency held in Berlin on October 9-10, 1984. 130 Indian publishers have been given publisher's identifier numbers under this System. The Centre also prepares bibliographies of University level books and conducts sample surveys on various aspects of production and use of indigenously produced University level books.

COPYRIGHT

The Copyright Office was established in January, 1958, in pursuance of Section 9 of the Copyright Act, 1957 (14 of 1957). The Copyright Office during 1985 has registered 1,908 works, the break-up of which is 1,739 artistic works and 169 literary works. In addition to this, the Copyright office has registered changes in the particulars of copyrights entered in the Register of Copyrights in two cases of artistic works.

India is a member of 2 International Conventions on Copyright, namely, the Berne Convention (1948) and the Universal Copyright Convention (1952). Both these Conventions were revised at Paris in 1971, whereby special concessions were given to the developing countries to enable them to issue compulsory licences for reproduction/translation of books of foreign origin for educational purposes. The Indian Copyright Act, 1957 was amended in 1983 with the specific purposes of (a) incorporating the provision of the Paris Text of 1971 of the Berne Convention and Universal Copyright convention concerning the grant of compulsory licences for translation and reproduction of foreign works required for educational purposes; (b) providing adequate protection to authors' rights; and (c) removing administrative drawbacks and other lacunae experienced in the administration of the Copyright Act, 1957. The Copyright (Amendment) Act, 1983 came into force with effect from August 9, 1984.

10—759 Deptt. of Edu/85

The Copyright Act was further amended in 1984, in order to check the problem of widespread piracy in the country. The amended Act makes provisions to combat piracy by making punishment for various offences more stringent. Infringement of Copyright has been made a cognizable offence. The Act provides for enhanced punishment for the infringement of copyright, namely, imprisonment upto 3 years, with a minimum punishment of imprisonment of 6 months and a fine upto Rs. 2 lakh, with the minimum of Rs. 50,000/-. The Act came into force with effect from October 8, 1984.

During 1985 India participated in the following meetings, seminars etc. :

WIPO Permanent Committee Meeting—from February 4—8, Geneva.

Joint UNESCO/WIPO Consultation Committees on the Access by Developing Countries to Works Protected by Copyright—from April 22—26, Paris.

WIPO Budget Committee Meeting—from May 8-10, Geneva.

Extraordinary Session of the Executive Committee of the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works (BERN Union) and the Sixth Ordinary Session of the Inter Governmental Committee of Universal Copyright Convention—from 17—25 June, Paris.

1985 Session of Governing Bodies of WIPO and the Unions administered by WIPO—23rd September to 1st October, Geneva.

A 2-member delegation of Indian Copyright Specialists visited China in August, 1985 for exchange of experiences in the area of copyright.

Training facilities in Copyright

Under the Annual Copyright Training Programme 1985 of WIPO, India received 2 trainees one each from Malaysia and Phillipines for receiving training in Copyright from 6—17 November, 1985.

Under the WIPO Traineeship Programme, one officer participated in a specialised training course in Administration of Copyright and Neighbouring Rights held in Switzerland and another officer participated in a General Introductory Training Course on Copyright and Neighbouring Rights organised at Budapest followed by a Practical Training Course in London.

Since 1983, WIPO/UNESCO are associating Indian experts with the training courses organised by them for participants from developing countries. During 1985, three Indian experts were invited by them to give lectures in the training courses organised in Phillipines, China and Hungary.

National Society of Authors and Composers of Musical Works

Ministry is also proposing to set up a National Society of Authors and Composers of Musical Works to protect their Copyright interests. The Society when established, will also grant licences for public performances etc. of copyrighted works and to collect royalties from the users for the benefit of the copyright owners.

CHAPTER 9

PROMOTION OF LANGUAGES

The programmes undertaken for the development and promotion of languages can be broadly grouped as under :

Promotion of Hindi
Promotion of Modern Indian Languages
Promotion of English and other Foreign Languages
Promotion of Sanskrit and other classical languages, such as Arabic and Persian.

The following institutions/organisations which the Ministry has set up were concerned with the operation of various programmes of languages :

Central Hindi Directorate, New Delhi, and its regional officers at Calcutta, Gauhati, Madras and Hyderabad.
Commission for Scientific and Technical Terminology, New Delhi,
Kendriya Hindi Sansthan, Agra, and its Centres at New Delhi, Hyderabad and Gauhati.
Central Institute of Indian Languages, Mysore.
Bureau for Promotion of Urdu, New Delhi.
Central Institute of English & Foreign Languages, Hyderabad.
Kendriya Sanskrit Sansthan, New Delhi.

A. PROMOTION OF HINDI

The Department continued to provide facilities for the teaching of Hindi in non-Hindi speaking States by providing financial assistance for the appointment of Hindi teachers in schools, establishment of teacher training colleges for Hindi teachers, award of scholarships to students belonging to non-Hindi speaking States for the study of Hindi beyond matriculation stage, and organisation of correspondence courses for Hindi. Grants were given to voluntary organisations for establishing classes for teaching of Hindi shorthand and typewriting. These organisations were also assisted for bringing out publications of different kinds. Under another programme, Hindi books worth Rs. 2.00 lakhs were distributed among educational institutions. The Kendriya Hindi Sansthan, Agra, continued its training courses and research in the methodology of teaching Hindi.

Appointment of Hindi teachers in non-Hindi speaking States/Union Territories and Establishment of Teachers Training Colleges

Central aid on a matching basis is given to non-Hindi speaking States and 100% assistance to Union Territories for the appointment of Hindi teachers under a centrally sponsored Plan scheme.

Central assistance on 100% basis is given to non-Hindi speaking States and Union Territories for the establishment of Hindi teachers training colleges. So far 19 training colleges have been established in non-Hindi speaking States/Union Territories with Central assistance.

Financial Assistance to Voluntary Hindi Organisations

Over the years, the number of organisations seeking financial assistance under this scheme has increased. Some of these organisations have grown in importance operating simultaneously in more than one State. While grants were formerly sought for running of Hindi classes, courses in Hindi typewriting and shorthand, and establishment of libraries and reading rooms, a number of organisations are now coming up with proposals for

the training of teachers, publication of Hindi journals, conducting of Hindi examinations, instituting prizes, and for advanced research in Hindi. During the year 1985-86 financial assistance will be given to about 140 organisations.

Central Hindi Directorate

The Central Hindi Directorate undertakes a number of activities for the propagation and development of Hindi. These include teaching of Hindi to non-Hindi speaking Indians and foreigners through correspondence courses, preparation of bilingual and trilingual dictionaries of Indian and foreign languages and preparation of conversational guides etc. Some of the important programmes undertaken during the year are briefly described below.

Teaching of Hindi through Correspondence Courses

The Directorate has organised correspondence courses since 1968 for the teaching of Hindi to people belonging to non-Hindi speaking areas and to foreigners. Initially, these courses were offered through the English medium, but in the recent years Tamil, Malayalam and Bengali are also used for the purpose. During the year 14,394 students were enrolled. 2853 students have enrolled for the medium of English, 5120 for Tamil, 366 for Malayalam and 760 for Bengali. The Directorate provides instruction for Pravesh and Parichaya courses which are of two-year duration each, and Prabodh, Praveen and Pragya of one-year duration each. The last three courses are designed for government servants and the examinations are conducted by the Ministry of Home Affairs. During the year 5259 students were enrolled in these courses. The Directorate has also started a new course in October 1984 for teaching of Hindi through correspondence to the IAS probationers of the States/Union Territories in the Eastern Region. Teaching materials have been prepared and personal contact has also been organised.

As part of its correspondence courses, the Directorate organises personal contact programmes in different parts of the country for familiarising students with pronunciation and spellings of Hindi language. Nine such programmes were organised at Shillong, Madras, Kohima, Cochin, Hyderabad, Bangalore, Pondicherry, Trivandrum and Durgapur.

Glossaries, grammar, textual materials, response sheets and other literature have been published for students enrolled in various courses. A comprehensive consolidated glossary is to be brought out. The manuscript of the glossary has been prepared. Efforts are also being made to analyse and deal with the difficulties experienced by the students, and for this purpose films and Hindi records have been developed. Action is being taken to prepare audio cassettes. The second edition of the Bilingual Conversational Guide (Hindi-English) is under print. As many as 5367 students appeared in the Prabodh, Praveen and Pragya examinations held in November, 1985. One thousand and fifty-seven students took the Hindi Pravesh and Parichaya examinations, and 892 students were declared successful.

Extension Programmes

The Directorate undertakes various extension activities to popularise Hindi in the non-Hindi speaking regions of the country, so as to bring scholars, professors, students, and other citizens of the Hindi and non-Hindi speaking areas together. These activities include workshops for neo-Hindi writers of non-Hindi speaking areas, student tours, lecture tours by scholars, travel grants for research students of non-Hindi speaking areas, award of prizes to Hindi writers of non-Hindi speaking areas for their literary work in Hindi. The Directorate also organised two symposia on Indian literature.

Workshop for Hindi Writers of non-Hindi speaking Areas

Five such workshops were organised during the year at Warangal, Calicut, Hyderabad, Madras and Manipur. Another workshop is planned in Calcutta. More than 100 writers from non-Hindi speaking States participated in these workshops. These workshops provided for intensive orientation to writers in the latest trends of creative writing in respect of poetry, drama, fiction, one-act plays, novels etc.

Tours and Travel Grants

Two groups of 50 students each of non-Hindi speaking areas are taken on conducted tours to universities and voluntary organisations of Hindi speaking areas every year so as to enable them to acquire understanding of Hindi language as spoken in daily life and to gain knowledge of latest trends in Hindi literature. Two such tours were organised during 1985-86.

Travel grants of Rs. 450/- each are awarded to 20 research students every year. The students have been selected this year also. Eight professors visit Hindi and non-Hindi speaking areas to deliver lectures. Four Professors have completed their lecture tours, the remaining would be completed by March 1986.

Symposia

Every year two symposia on Indian literature are being held in the Universities. The symposia were held this year at the Udaipur and Osmania Universities.

Award of Prizes

Under this scheme, 16 prizes each of Rs. 2500/- are awarded annually to non-Hindi speaking writers for their books in Hindi. Eighteen prizes were awarded together during 1983-84 and 1984-85. For 1985-86, 15 writers have been selected.

Publications

The Directorate issues the quaterly journal 'Bhasha', and the monthly journal 'Unesco Doot', the latter being the Hindi version of the Unesco Courier published in 28 prominent languages of the world. During 1985-86 four issues of Bhasha (i.e. March-Dec.) were published, out of which the March and June issues were jointly published as the 'Silver Jubilee Issue'. The Unesco Doot has been brought out upto November 1985. The Directorate aslo publishes 'Varshiki', being a detailed survey of various disciplines of literature written each year. The Varshiki 1982-83 is with the press and work on Varshiki 1984 is progressing.

Under the scheme 'Bharatiya Sahitya Mala', the titles 'Bharatiya Bhashaon Ka Sankshipta Itihas', 'Bharatiya Kahaniyan' and 'Bharatiya Nibandh' have already been published. The manuscript of 'Bharatiya Kavita' is with the press. The manuscript of 'Bharatiya Ekanki' is being prepared.

To improve the sale of books, a number of activities were undertaken such as advertisement through the media, personal contacts with educational institutions and libraries and exhibition of books etc. Nine exhibitions of Hindi books of the Directorate were organised. The year's sale of books has exceeded Rs. 1 lakh.

The Directorate makes available useful Hindi books and magazines free of cost to readers in non-Hindi speaking areas and abroad, in order to create interest in reading and teaching of Hindi language and literature. Books purchased during the 1984-85 have already been distributed to beneficiary institutions, and sent to the Indian Missions abroad.

Production of Dictionaries

Six out of 26 bilingual dictionaries, viz. Hindi-Gujarati, Hindi-Sindhi, Hindi-Marathi, Hindi-Assamese, Hindi-Urdu and Hindi-Tamil, have been published and the material for Hindi-Telugu, Hindi-Malayalam and Hindi-Oriya dictionaries have been sent to the press. These are likely to be published this year. As regards trilingual dictionaries, Hindi-Gujarati-English (3 volumes) has already been published, and the manuscripts of Hindi-Tamil-English, Hindi-Kannada-English and Hindi-Malayalam-English have been sent to the press. Bharatiya Bhasha Kosh where equivalents to Hindi words have been given in 13 Indian languages has already been published.

The press copy of Tatsam Shabda Kosh is likely to be sent to press shortly. The manuscript of Bharatiya Bhasha Parichaya Kosh is being prepared.

The Central Hindi Directorate is also engaged in preparing Hindi and foreign language dictionaries. Since the last year, 2800 entries of the German-Hindi dictionary were finalised with more than 8000

entries having been edited earlier. The fair copy of the Czech-Hindi Dictionary has been transliterated in Devanagari script. The manusript of the Hindi-Czech Conversational Guide is ready for publication. The manuscript of Hindi-Russian Conversational Guide is press-ready and the USSR side is being contacted for its publication. The manuscript of Hindi-Hungarian Conversational Guide has been prepared and is being corrected by the Hungarian experts.

Bilingual dictionaries of Hindi-UNO Languages (except English and Russian) viz. Spanish, Chinese, Arabic and French are being prepared. Each bilingual dictionary will contain 2500 entries which include basic terms of Hindi vocabulary and diplomacy. The press copy of Hindi-Arabic Dictionary has been sent to Government Press, Faridabad, and the press copy of Hindi-Spanish and Hindi-Chinese are likely to be sent shortly. The Hindi-French dictionary will be press-ready shortly.

Production of Standard Literature in Sindhi

This scheme, started in 1975, aims at the production of standard literature in Sindhi, including reprinting of rare books, classicsal and text-books for secondary and university levels. Under this scheme, 20 books have been published. A seminar was organised in January 1985 in Ulhasnagar on Sindhi Press Writing. Another seminar was organised in September 1985 in Bhopal on the great Sindhi poet 'Saami'. A Neo-writers' workshop was also organised in 1985 in Delhi, to discuss 'Palaeography' in Sindhi. A neo-writers' workshop is planned in February 1986 at Agra. Meetings of the expert panel were held in August 1985 for selection of books under the scheme of Bulk Purchase of Sindhi books, and for selection of books under the scheme of Award of Prizes to Sindhi scholars. Sindhi books worth Rs. 20,000/- are likely to be imported from Pakistan for free distribution.

Commission for Scientific and Technical Terminology

The functions of the Commission for Scientific and Technical Terminology are : to evolve scientific and technical terminology in Indian languages; prepare reference material in Indian languages, survey, review and collect the available terminology in Indian languages and evolve a Pan-Indian terminology; foster the setting-up of language bodies at regional levels and prepare and publish definitional dictionaries, glossaries and lexicons.

The progress made by the Commission for Scientific and Technical Terminology in the implementation of various schemes during 1985-86 is as follows :—

Production of University-level books

Under this scheme, monitored by the Commission, 6675 books in Hindi and in the regional languages have been published on 30 subjects covering nearly all the disciplines of humanities, social sciences, basic sciences and applied sciences. Out of these 1,560 books have been published in Hindi by the various Hindi Granth Akademies, the Cells in the selected Universities, as well as by the Comisssion itself. So far 1700 books relating to agriculture, medicine and engineering have been published in Hindi together by the Commission, the various Hindi Granth Academies and University Book Production Units. During the year 14 books were published and some are under print. The titles include translations and original writing. The books in Hindi on Agriculture, Engineering, and Medical subjects are mainly produced by the Commission.

The off-take of the books produced under this scheme has been slow, partly because the tardy switch-over to Indian languages as media of instruction at the university stage. As on March 1985, the value of unsold books was around Rs. 647 lakhs.

Definitional Dictionaries

Once the terminology in various disciplines is evolved, it becomes necessary to explain them through definitions. Accordingly, the work was continued towards preparing definitional dictionaries on various disciplines of basic sciences, social sciences, humanities, medical sciences, pharmacy, agriculture and civil, mechanical and electrical branches of engineering. So far 16 definitional dictionaries on sciences-12 each on botany, chemistry, geology, mathematics and home science and one

each in zoology, geography, geology and medicine and 10 definitional dictionaries on social sciences and humanities in the subjects like education, economics, econometrics, social work, commerce, psychology, archaeology cultural anthropology and history have been published. Some dictionaries of Education, Economics, Social work, Commerce, Psychology, Archaeology, Social work, History and Philisophy, Sociology, Library Science & Western Music are in press. One definitional dictionary of Modern Algebra is likely to be published this year.

Seminars were held to discuss and finalise the definitions. Consolidation, co-ordination and compilation of basic definitional dictionaries of sciences and social sciences is also in progress.

Procurement of Copyrights

The Commission has been assigned the work of obtaining copyright of books being translated by the Granth Akademies, the Commission and the Book Production Boards taken together. So far, 1580 copyrights have been secured. The work relating to renewal of copyrights of 10 books has been completed. During the year the copyrights of 7 foreign publications have been procured.

Terminology

In the context of residual terminology, Hindi equivalents of terms were evolved in the branches of veterinary science, space science and management. The Space Dictionary was published last year. The work of Veterinary Science and Management is in progress.

Departmental Terminology

The work of departmental terminology is also progressing. During the year, the Commission conducted various meetings with the concerned Ministries/Departments and has finalised various terminologies. The revised edition of the consolidated administrative terminology is being prepared. Various meetings with the Languages Directors of Hindi speaking States, the Central Translation Bureau, and the Department of Official Language, were organised by the Commission for co-ordination of various terminologies. A consolidated Banking Terminology is also under preparation in consultation with the various nationalised banks, the RBI, and the Department of Official Language (Legislature).

Coordination and Simplification of Terminology

The work of simplification and co-ordination of the entire Hindi technical terms evolved and published so far is being done through meetings and seminars. Co-ordination and simplification of the entire terminology upto the alphabet 'Z' has been completed. The revised edition of various subject-wise dictionaries/terminologies will be published.

Hindi-English Glossaries

Following on the increased use of the publication of Hindi equivalents of English terms, it was considered necessary to prepare the counterpart Hindi-English glossary also. One such Hindi-English glossary relating to basic sciences was published earlier, and the other Hindi-English glossary pertaining to humanities and social sciences was published during the year. The third glossary in the series in respect of applied sciences is under preparation.

Digest/Reading/Monograph

Digests/Readings/Monographs on the following subjects have been brought out : Zoollogy Geology, Home Science, Physics, Botany (3 issues), Psychology, Economic (4 issues), Commerce-1, Education-1, Digest for Technicians (4 issues), Physical Anthropology, Physical Sciences, Biological Sciences (2 issues), Earth Sciences and Political Science.

Compilation of medical terms and phrases in common use in Southern and other States

The compilation of medical terms and phrases in common use in the South Indian and other State languages was initiated in Telugu, Kannada and Marathi during last year. This year, two meetings were held at Trivandrum and Madras for Malayalam and Tamil respectively.

All India Terminology

The Commission has also undertaken the work regarding compilation of terminologies in various Indian languages and their comparison with the equivalent Hindi terminologies and co-ordination work with a view to evolving a national terminology for their use at all India level. 6 manuscripts in this regard are in Press and 3 other manuscripts are ready to be sent for printing.

Kendriya Hindi Sansthan, Agra

The Kendriya Hindi Shikshan Mandal, an autonomous body established in 1961 by the Department of Education, Government of India, runs the Kendriya Hindi Sansthan (Central Institute of Hindi) for organising academic and research programmes for the development and propagation of Hindi in furtherance of directives contained in article 351 of the Constitution. The Sansthan organises programmes for teaching of Hindi to different clientele for different functional purposes in India and abroad. The programmes provide for Hindi teacher's training, advanced diploma in applied Hindi linguistics and in translation, research in psycholinguistics, Socio-linguistic aspects of Hindi language, production of instruction materials, conducting of language-related surveys focussing on role of Hindi as a pan-Indian communication medium and collaborates and provides consultation to Central and State Government agencies on planning and development of the Hindi Language. The Institute is the apex body working for the improvement of standards of Hindi teaching and training in the country and for research and extension work in Applied Hindi Linguistics, comparative and constrastive studies of Hindi and Indian Languages etc.

Teaching and Training

During the year the Institute conducted 18 different types of courses, including short-term courses for training and orientation of teachers at the universities, colleges and school levels, courses ranging from elementary stage to research in Hindi Language and literature for students and research scholars from 25 countries, functional Hindi courses for the officials of Central Government and of the public sector undertakings, post—M. A. Diploma courses in Applied Hindi Linguistics and in Translation. It also conducted a B.Ed. level correspondence course for training of Hindi teachers from non-Hindi speaking States. The number of in-service teachers trained was 283 in regular courses, 436 in correspondence courses, and 950, in short-term orientation courses.

Material Production, Research and Survey

Data collected under the survey on the status of teaching of Hindi in North-Eastern States were analysed and the report finalized this year. Work on preparation of supplementary and enrichment material for school-going children in States with large tribal population has been undertaken.

Survey work on function and role of Hindi as a medium of pan-Indian communication in industrial establishment, conducted last year in Rourkela and Bokaro Steel Plants has further been extended so as to cover similar organisations in Mormugao, Vasco, Ponda, Bangalore, Mysore and Vishakhapattanam. Coding of questionnaires from Bokaro and Rourkela has been completed and arrangements for computer analysis of data are being made.

The report on the scientific Hindi register is being finalized and work has been undertaken for determining the form and features of the Hindi register used in trade and commerce (commercialised Hindi).

Work on preparation of instructional material for teaching of Hindi as a foreign language initiated last year has been furthered. Structural readers, Readings in Literature and a manual of Hindi composition for the next level of instruction have been prepared and the material is being tried out at the Delhi Centre of the Sansthan.

Language Laboratory and Audio-Visual Unit

Lessons for teaching Hindi, pronunciation to Manipuri speakers have been prepared, taking into account the constrastive features of the sound systems of Manipur and Hindi. Preparation of cassette kits has been undertaken for training the school children of Nagaland and Mizoram in reading and comprehension of Hindi.

The Institute has acquired two sets of micro-computers under the "CLASS" programme of the Government of India. They have been set up at the Agra Headquarters and its Delhi Centre. The requisite infrastructure is being developed for preparation of instructional material and packages for computer-aided instruction of Hindi to non-native

speakers. Some faculty members of the Sansthan have been provided initial training in the use of computers.

Publications

During the period under report the Sansthan published 10 books, 3 issues of Gaveshana and 6 issues of the News Bulletin, together accounting for a total of 2800 printed pages.

Distribution of Hindi Books to Schools in Tribal Areas

A total of 80 Hindi books (300 copies of each) focussing on national themes, have been distributed to schools in tribal areas situated in Nagaland, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Manipur, Andaman and Nicobar Administration, Sikkim, Ladakh, Goa, besides Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Orissa. The total cost of the books distributed was Rs. 1 lakh.

All India Competitions

An All India Hindi Essay Competition and two Hindi elocution competitions for in-service Hindi teachers were organised by the Institute.

Seminars/Workshops and Extension Lectures

The Sansthan conducted 6 seminars and workshops and a series of 3 extension lectures. The seminars were on teaching of Hindi : International perspectives (September 1985), Constrastative Studies of Indian Languages (February 1986) and Bharatendu Harischandra Centenary Seminar (November 1985). Three workshops were organised on Preparation of Graded Syllabus for teaching of Hindi at school level (August 1985), New thrusts in Applied Linguistic Reearch (July 1985) and of Hindi Officers (Translators) on Teaching of Hindi as Rajbhasha (February 1986).

A series of extension lectures on Hindi literature were delivered by Prof. K M. Lodha, Prof. and Head, Department of Hindi Calcutta University, on Distance Education and Language Instruction by Prof. O. S. Deval, Central Institute of Education Technology, NCERT, New Delhi, and on Multilingualism and language Communication by Prof. D. P. Pattanyak, Director, CILL, Mysore.

Library

The Sansthan added 4500 new titles to the library of the Sansthan, there by increasing the total holdings to 41650. The Sansthan subscribes to approximately 110 foreign and Indian journals and news papers.

Propagation of Hindi Abroad

Under the scheme of propagating Hindi abroad, 50 scholarships are awarded every year to nationals of foreign countries for the study of Hindi at the Central Institute of Hindi, New Delhi. During 1985-86, 38 students were awarded scholarships and admitted to the Institutes; 9 have been admitted on a self-financing basis. A scholarship awarde gets Rs. 650/- per month and is provided air-fare from his/her home country to Delhi and back.

The Ministry continues to maintain 3 Hindi teachers in Surinam, Guyana, and Trinidad, 2 part-time teachers in Sri Lanka and one full-time Librarian in the Indian Embassy at Kathmandu. Hindi books worth Rs. 2 lakhs are supplied to our Embassies/Missions abroad.

B. PROMOTION OF MODERN INDIAN LANGUAGES

Central Institute of Indian Languages, Mysore

The Central Institute of Indian Languages, Mysore, undertakes training research development and extension functions for the development of modern Indian languages. Through its regional centres it provides in-service training to language teachers. It has also been engaged in research in and survey of tribal languages.

In tribal and border languages, Mishmi grammar, mishmi Phonetic Reader, Ao-Hindi-English Dictionary and Car Nicobarese Primer were published. Mao Grammar and II Level Primers in Dungar Warli, Davar Warli, Jenu Kuruba and Car Nicobarese were completed. Grammars of Dorli, Bison Horn, Madia, Bhujii, Gutob and Car Nicobarese and Dictionaries of Bison Horn, Madia are expected to be completed before the end of the year.

11—759 Deptt. of Edu/85

Bilingual Primers in Warli and Jenu Kuruba were tried out in Rajasthan, Dadra and Nagar Haveli and Karnataka and the bilingual education programme evaluated. A meeting of the officers of the Department of Education and NCERT from these States and Union Territory was called to review the work and plan for future experimentation.

Language officers of Arunachal Pradesh were trained in field linguistics. Primers in 16 Naga languages will be revised according to the new syllabus of the Government of Nagaland. The Institute is providing its expertise for the evaluation of language textbooks in Manipur. It will also train the language teachers of Kok Borok in Tripura.

A seminar on Word Formation in Tribal Languages, a Workshop on Common Phonological Features in Indian Languages, and a seminar on Common Words in Indian Languages were organised. Preparation of a dictionary on common words in Indian languages is also planned.

Media/Technology Support

A Phonetic Laboratory was established and phonetic problems of Mao and Apatani analysed. A training programme in experimental phonetics was conducted. A workshop on voice modulation and a workshop on pronunciation dictionary of proper names at the regional level will be organised.

A Computer Laboratory was established and EPSON micro-computer and two BBC computers were installed. The staff of the Institute were trained in BASIC programming. Sample software in teaching Tamil and Kannada were prepared. Programmes for monitoring of academic projects of the Institute and for book acquisition in the libraries will be prepared.

Cassette Courses in 4 languages were completed and released by the Ministry of Education. A video programme on Indian Scripts will be completed by the end of the year.

Publications

The Literacy Atlas will be revised with reference to the 1981 figures. The tribal language atlas will be completed.

Model Mother Tongue Reader for Class 1 in Malayalam was prepared and used on an experimental basis in 27 schools. Level II book in this language will be prepared by the end of the year. Standard 1 textbooks in Bengali, Tamil and Telugu were prepared for schools in Andaman & Nicobar Islands. Level 2 books in these languages will be prepared by the end of the year. Handbooks for teachers of primary schools in Kannada, teachers of children from linguistic minorities communities in Tamil and Kannada were prepared. A special purpose course for the officers of Survey and Settlement of the Government of Karnataka and in Tamil for the IAS and IPS probationers of Tamil Nadu were prepared. Pictorial Glossaries in Seven Languages including Oriya and Urdu will be published.

The Institute has prepared for the Government of Tamil Nadu a syllabus for teaching Tamil by the Open School programme. Materials for the Radio-cum-Correspondence Course in Tamil for Teachers of Standard 1 and 2 were completed.

Following the two volumes on Hindi speaking States and Eastern States, another volume of bibliography of linguistic research covering all-India languages like Sanskrit and Urdu was completed. A seminar on documentation is to be conducted to work out the scheme for the development of computerised data base on Indian languages and for automation of library services. Twelve new publications were brought out as of December 1985 and 8 more publications will be brought out before the end of the year.

Training

With a grant from the Government of Karnataka the Institute has launched a programme of Composite Correspondence Course in Kannada for those of the Karnataka Government officials who do not know Kannada. Over 1000 such officials have registered for this course.

As part of its training programmes, which result in handbooks and primers mentioned above, primary school teachers in Kannada, teachers of children of linguistic minorities in Karnataka and Tamil Nadu and teachers of the experimental school using the Model Mother Tongue Readers were trained in the new methods, and materials developed by the Institute.

Research and Surveys

A study on the effect of medium of instruction of academic achievement in Tamil Nadu and a study of language load among Scheduled Caste children in Hindi speaking States were completed.

A bibliography of linguistic research was completed and one on language evaluation and testing will be completed by the end of this year.

A workshop was conducted to prepare standardised language proficiency tests in about 10 languages. A book on Mathematics for Linguistic Research was completed.

A study of Marwari folklore was completed. Two training workshops in folklore were conducted in Mysore and Assam. A study of language use in industry in Bangalore and a study on convergence and language attitudes in Mysore were completed. A survey of language use in Manipur will be undertaken.

Regional Language Centres

In the six Regional Centres at Mysore, Bhubaneshwar, Pune, Patiala, Solan and Lucknow, 449 trainees have been admitted to the training in 13 languages.

The Centres conducted 10 refresher courses for the teacher trainees and 7 national-integration and language-environment camps for students learning an Indian language as a third language. Two contact programmes in Maharashtra and Assam and one evaluation-cum-consultancy programme in Orissa were conducted.

A seminar on current trends in second-language teaching by the Southern Regional Language Centre, Mysore, and a seminar on Contrastive Studies of Assamese, Bengali and Oriya and Nepali by Eastern Regional Language Centre were conducted. A course in linguistics in language teaching by Northern Regional Language Centre was conducted. A seminar on translation, on specialised lexicon and on language in education will be conducted this year.

Bureau For Promotion of Urdu

In order to promote Urdu language and literature, the Ministry of Human Resource Development, (formerly Ministry of Education) set up the Taraqqi-e-Urdu Board in 1969 with the Education Minister as its Chairman. The Board advises the Government on the production of academic literature in Urdu. The Bureau for Promotion of Urdu which functions as the Secretariat of the Board was set up in 1975. The Bureau implements the recommendations, programmes and policies formulated by the Taraqqi-e-Urdu Board.

Production of Books

The main object of the Board is to make meaningful efforts for the all-round development of Urdu language in the country, in addition to providing benefits of studies for students in all subjects as well as general readers. In its supportive function, the Bureau for Promotion of Urdu is bringing out academic literature in Urdu. 17 subject panels have been reconstituted to advise the Bureau for Promotion of Urdu regarding publication programme. Eminent scholars of subjects from all parts of the country are associated with these panels. The Bureau has brought out 520 books in various disciplines, including reprints, and books published for NCERT etc. Presently, the Bureau is engaged in the preparation of 500 more titles.

Technical Terminology

The Bureau is also engaged in the coining and finalising of technical terms in various disciplines. Initially, 18 Terminology Committees were constituted. The Bureau has published Glossaries of Economics, Chemistry, Anthropology, Zoology, Botany, and Political Science. Glossary of linguistics has been sent to the press. The finalisation of terminology in other subjects is at an advanced stage. Recently, Terminology Committees of Agriculture, Sociology Journalism and Mass Media, Engineering & Technology, have been constituted.

Urdu Encyclopaedia

The Urdu Encyclopaedia (in 12 volumes) taken up in 1973 was completed in 1981. This Encyclopaedia consists of 4 initial volumes comprising key-articles and 8 others consisting of small entries and references etc. The first volume will be entrusted to the press this year.

Dictionaries

The progress in respect of dictionaries is indicated below :

(a) English-Urdu Dictionary in 5 volumes is under printing.

(b) Urdu-Urdu Dictionary in 5 volumes is under compilation. One volume is ready for printing.

(c) Urdu-English Dictionary in 5 volumes is under compilation.

(d) Urdu-Urdu Students' Dictionary consisting of 42,000 entries is being sent to the press.

(e) Bibliography of Urdu Books :

The work of compilation of comprehensive bibliography of Urdu books since the inception of printing in India has been taken up. Urdu books relating to various branches of knowledge printed up to 1947 will be included in this bibliography. This project is being executed at 6 centres, out of which the work at the Aligarh Maulana Azad Library is going on, and 16,000 cards have been compiled. Annual bibliographies are compiled in collaboration with Jamia Millia and bibliographies pertaining to 1976, 1977 and 1978 have been published.

Calligraphy Training Centres

In order to revive and promote the fine art of Urdu calligraphy and to provide good calligraphists for Urdu publication trade, the Bureau has set up Calligraphy Training Centres at important Urdu centres. 30 Centres have so far been set up and these include 2 centres of Decorative Calligraphy and 4 Basic Calligraphy Training Centres exclusively for women. The duration of each course is 2 years. The number of students in basic Calligraphy Training in each centre is 25 and in the Decorative Calligraphy Training Centre, the number of trainees is 5.

Urdu Typewriting and Shorthand Centre

An Urdu typewriting and shorthand centre has been established at the Ghalib Academy, Delhi, and is financed by the Ministry through Bureau for Promotion of Urdu.

Urdu Typewriter

The main objective of BPU is to undertake programmes and plans to promote the cause of Urdu even in technical spheres. A few years ago, the Urdu typewriters were not being manufactured in India and BPU has been instrumental in the manufacture of indigenous Urdu typewriters. New Urdu typewriters are being manufactured in India by Godrej Company, Bombay.

Sales and Exhibition

Besides the preparation and production of academic literature in Urdu, the Bureau is also engaged in the sale of its publications since 1976. So far, books worth over Rs. 22 lakhs have been sold. A number of book exhibitions were organised at various places. BPU also participated in the World Book Fairs and Children Book Fairs organised by National Book Trust (India).

Urdu Duniya

The Bureau has started printing of Urdu Duniya, the quarterly report of its activities, which has been well received within the country as well as outside. So far, 15 issues have been brought out.

Coordination between BPU and Various Urdu Academies

In order to have close cooperation and coordination in Urdu Academies, the Bureau has constituted a Coordination Committee which has met thrice so far.

Central Institute of English and Foreign Languages, Hyderabad

The Central Institute of English and Foreign Languages, an autonomous institution, was set up by the Government of India in 1958, for improving the standards of teaching of English. The scope of its activities was amplified in April 1972 to include the teaching of major international languages. In July 1973 it was recognised as an Institute 'deemed to be a University'.

This Institute is now twenty seven years old, has made poineering efforts to devise and implement a variety of academic programmes directed towards improvement of standards of the teaching of English and foreign languages. From its modest beginnings, it has developed into an internationally recognised institution of higher learning, serving as a strong national centre for specialized teacher education, research, materials production and extension work in the fields of English, French, German, Russian and Arabic.

In its programmes of teacher education, designed to improve the professional competence of teachers of English and foreign languages at all levels, it has concentrated on the training of key personnel, since as a national centre it cannot train directly the vast number of teachers in the country.

District Centres

The Institute has started implementing the scheme of setting up 'District Centres' in the States and Union Territories with financial assistance from the Central Government during the Seventh Plan period. These Centres are meant to provide saturation-level training to teachers of English at the secondary level, to serve as resource centres of library and audio-visual materials, and to function as centres for non-formal instruction to adult learners, school dropouts and children from the weaker sections.

Strengthening of ELTIS

Committees were set up to assess the needs of the existing English Language Teaching Institutes (ELTIs) and examine the requirements for setting up of such new institutes. In pursuance of the reports submitted by these Committees steps are being taken to give financial assistance to ELTIs to enable them to play their role more effectively. A workshop for the staff of the ELTIs/Regional Institutes of English was held from 9th to 13th December, 1985. Eleven representatives of these institutes and one of the British Council participated in it. The seminar reviewed the present status of English Language Teaching and made a set of recommendations for restructuring the programme of training for teachers of English at the secondary level, keeping in view the place of English in our multi-lingual setting.

Refresher Course

A two-week refresher course-cum-seminar was conducted for ex-participants of the Institute from 14th to 27th July, 1985. 29 ex-participants who had completed the Post-Graduate Diploma course during 1970-80 attended this course. The course content covered theoretical and pedagogic issues.

Media Support

The 'English-by-Radio programme' was started in 1963 with five experimental programmes on the All India Radio, Hyderabad. The number of programmes broadcast per annum now is 259.

The Institute has produced a five-year course in English-by-Radio based on the NCERT syllabus. Currently 150 programmes are being broadcast nation-wide from 23 stations of the All India Radio.

In addition, the All India Radio, Hyderabad, broadcasts 57 programmes for secondary school teachers of English.

Since 1979, AIR Hyderabad has also been broadcasting programmes for the benefit of school leavers and college entrants during the summer. A series of 60 programmes were broadcast in May/June 1984.

Production of Materials

The Institute has, from the beginning, addressed itself to the task of preparation of suitable lowcost teaching materials. Several projects for the preparation of text-books were taken up in collaboration with national agencies such as the National Council of Educational Research and Training and the Central Board of Secondary Education. Two series of integrated text-books for schools the General Series and the Special Series complete with workbooks and teacher's guides, were prepared. These are being used in the schools of the Kendriya Vidyalaya Sangathan, and those affiliated to the Central Board of Secondary Education, and several State Boards. These have also been adapted by several State Governments and other educational agencies.

The Institute has been assigned a major advisory role both by the Central Department of Education and by the University Grants Commission in matters relating to the teaching of English and foreign languages in the country. It is expected to play a crucial role in devising suitable plans and strategies and in their effective implementation for the improvement of the standards in these areas.

Production of University-Level Books in Indian Languages

Under a Scheme in operation since 1969, the Union Ministry of Education had provided grants to 15 participating States and to four universities, (viz. Delhi, B.H.U., G.B. Pant Agricultural University and Haryana Agricultural University) for production of university-level books in Indian languages

to facilitate the implementation of the provision contained in the National Policy on Education (1968) for gradual adoption of Indian languages as the media of higher education. The actual job of book-production by utilizing the Central grant is handled by the Granth Akademi/Book Production Board set up for this purpose in each of these States, and by the Cell in the respective university. A total of 6932 titles have been produced in different languages under this scheme as of March 1985.

The Scheme in operational aspects is monitored by the Commission for Scientific and Technical Terminology which also approves the titles recommended by the respective agencies which, in turn, select the academic professionals to write the books.

In view of the Commission's special responsibility in respect of this scheme, the Commission held the second meeting of the Steering Committee of the State Governments/University Agencies at Bangalore on February 27, 1985 when the progress made in this respect was reviewed, besides the problems of the work of terminology as well as the disposal of books produced under the Scheme.

Production of Core Books on Medicine

Under an approved scheme which was in operation during the Sixth Plan Period, grants are given to National Book Trust (India) for production of subsidised and original core books on medicine written by Indian authors who obviously happen to be professionals in the field of medicine. The Scheme has since reached the critical take-off stage following the constitution of an advisory committee headed by the Director of All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. The importance of the Scheme consists in the fact that it would encourage indigenous talent in the important field of medical education tailored to Indian conditions, be a boon to the Indian medical students with books at subsidised prices and reduce our foreign exchange drain on the import of medical books. Accordingly, this scheme would be continued during the Seventh Plan period as well.

Financial Assistance for Publication in Indian Language as in English

Drawing upon several schemes already in operation, an exclusive scheme has recently been finalised for providing financial assistance to individuals and voluntary organisations for publication of well-defined categories of quality books which do not generally find a publisher. This Scheme is, for the first time, being made applicable uniformly to all of the languages and, it is expected, would further encourage the voluntary sector to produce suitable books for the enrichment of the languages.

C. PROMOTION OF SANSKRIT AND OTHER CLASSICAL LANGUAGES

Recognising the importance of Sanskrit in promoting national integration, international understanding and appreciation and preservation of our cultural heritage, several schemes have been introduced by the Government of India for the development and promotion of Sanskrit education and learning. They are being continued with greater vigour and larger financial outlays. A similar programme for the propagation and development of the other two classical languages, Arabic and Persian has also been continued during the Seventh Plan.

The main activities include financial assistance to voluntary Sanskrit organisations, development of some of the institutions run by voluntary organisations into Adarsh Sanskrit Pathshalas with enhanced financial assistance, employment of Professors emeritus to provide indepth knowledge in Shastras to younger teachers, editing and publication of rare manuscripts and catalogues of manuscripts, promotion of the oral Vedic tradition, reprinting of important out-of-print Sanskrit texts, vocational training to products of Sanskrit Pathshalas, national awards to eminent scholars, and preparation and publication of standard dictionaries.

Financial Assistance to Voluntary Sanskrit Organisations

In respect of registered voluntary Sanskrit organisations/institutions, recurring and non-recurring grants are given for salary of teachers, scholarships to students, construction and repair of buildings, furniture, library, research projects etc., to cover 75% of the approved expenditure

on these items. In the case of 24 Vedic institutions where the oral Vedic tradition is being preserved, the Government grant covers 95 per cent of the approved expenditure. About 650 Sanskrit organisations are covered this year.

Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya/Sodh Sansthas Scheme

Out of these voluntary organisations, a few which have the potentiality for development and which offer post-graduate level studies are provided with higher financial assistance. So far 11 post-graduate teaching institutions and two post-graduate research institutions have been brought under the purview of this scheme. Three of them are in U. P., one in Kerala, two each in Bihar, Haryana, Maharashtra and three in Tamil Nadu. These institutions are paid 95 per cent of maintenance grant.

Rashtriya Sanskrit Sansthan

The Sansthan, an autonomous organisation under the Ministry has been set up for preservation and propagation of Sanskrit including research, publication, collection and preservation of manuscripts and organising of training activities. Since 1970 it has established seven Kendriya Sanskrit Vidyapeethas situated at Tirupati, Delhi, Jammu, Allahabad, Puri, Guruvayoor and Jaipur. In addition it has about 40 private institutions affiliated to it for purposes of examination. It conducts examinations and awards certificates and degrees from Prathama to Vidyavaridhi. It also provides teachers' training at graduate and post-graduate levels. At present there are 1917 students on the rolls of these Vidyapeethas out of which 1238 students are given scholarships with hostel facilities.

The Vidyapeethas, apart from providing training have undertaken a number of research, development and extension activities. These are discussed below.

(a) The Allahabad Vidyapeetha has so far collected about 40,000 manuscripts and has published several important works. It has also launched a programme of micro-filming manuscripts from the Kashmir University pertaining to Kashmir Shaivism.

(b) The Tirupati Vidyapeetha has been working on the following projects :—

(i) Agama Kosha : The 'Vaikhanasa Agamakosha' manuscript is ready for printing. It will be followed by 'Pancaratra' and 'Shaivism Koshas'.

(ii) Tape Recording of Vedas : The Vidyapeetha has so far recorded different oral traditions of Vedic recitation accounting for a thousand hours duration. Further recording is going on with the help of the Tirupati-Tirumala Devasthanam.

(iii) Tape-recording of Oral Shastric Tradition : The recording of the Mimamsa tradition is in process.

(c) Jammu Vidyapeetha : Specialises in Kashmir Shaiva Darshan and a prroject of preparing a Kosha of that branch is nearing completion. It also proposes to establish a permanent centre at Srinagar for the study and preservation of the tradition of Kashmir Shaivism.

(d) The Delhi Vidyapeetha is preparing a Kosha on the Sankhya and Yoga Philosophy. It has also brought out the Aswalayana Srauta Sutras, 'Katyayana Srauta Sutras'. Sabarabhasya with commentaries, Shastra Deepika, the Adhwara Mimamsa Kutuhala Vritti and other Mimamsa works. The Rashtriya Sanskrit Sansthan has recently published by photo offset process the Mimamsa text-books called the Bhatta Deepika in four volumes, which was out of print for long. Other works taken up for printing are the Sankarsa Kanda, the Naya Viveka, Sloka Varttika, Srauta Sutras etc. A History of Indian Freedom Movement has also been published in Sanskrit. A project of preparation of a Who's—Who of living Sanskrit Pandits in India has also been undertaken. The Sansthan, in collaboration with the Indian Council of Philosophical Research has conducted three seminars on Nyaya philosophy with a view to bringing about a dialogue between traditional and modern scholars of Indian Philosophy.

In all about 140 publications have been issued from the different Vidyapithas and the Sansthan. Two projects namely compendia volumes for students of Sanskrit literature and Sanskrit text-books for children starting from KG to 10th standard have also been taken up.

During the year 1985 about 200 students have been registered for Vidyavaridhi course at different Vidyapeethas and about 30 scholars have been awarded the Vidyavaridhi degree.

Scholarships

The Rashtriya Sanskrit Sansthan has been operating the following schemes on behalf of the Ministry :

(a) Research Scholarships to Products of Sanskrit Pathshalas.

A monthly stipend of Rs. 300/- is given to research scholars for 2 years, in addition to a contingent grant of Rs. 500/- per year.

(b) Post-Matric Scholarships.

Students who study Sanskrit as a subject at the Intermediate, B. A. and M. A. levels in the modern stream are awarded scholarships at the rates of Rs. 50/-, Rs. 75/- and Rs. 100/- per month respectively. 412 students are being awarded scholarships under this scheme.

(c) National Scholarships for Students of Traditional Sanskrit Institutions.

A stipend of Rs. 75/- per month is paid to the students studying in Shastri and of Rs. 100/- in Acharya Classes of the traditional Pathshalas. 13 students are being paid stipends this year under the above two categories respectively.

Sanskrit Dictionary Project of the Deccan College

Assistance is being provided to the Deccan College, Pune, for preparing a Sanskrit Dictionary on historical principles. Three parts each of Volumes I and II and part I of Volume III have already been published.

Shastra Chudamani Scheme

Under this scheme young scholars are given in-depth coaching in the Kendriya Vidyapeethas/Adarsh Sanskrit Pathshalas etc. in various disciplines by utilising the services of eminent retired Sanskrit scholars. These scholars are appointed on a monthly honorarium of Rs. 1000/-. 85 such scholars have been approved for 1985-86.

Financial Assistance to Voluntary Organisations Working for the Propagation and Development of Classical Languages other than Sanskrit

Under this scheme, registered voluntary organisations working in the field of two classical languages, Arabic and Persian, are given financial assistance towards salary, scholarships, furniture, library etc. and other activities. About 150 institutions are being assisted. Twenty scholarships are awarded every year to traditional Madrasas and Maktabs to prosecute higher research in Arabic and Persian.

A national survey of Madrasas and Maktabs was undertaken to evaluate their standards of teaching as it would help in further classifying them for purposes of channelising Government assistance. A major research project of bringing out of a critical edition of Fatwal-Al-Tatar-Khania, a monumental work on Islamic law, has been sponsored by the Ministry. The project is to be completed in ten years.

Award of Certificate of Honour to Sanskrit, Arabic & Persian Scholars

This scheme provides for the award of President's Certificate of Honour to eminent Sanskrit, Arabic and Persian Scholars. Every year 14 scholars 10 in Sanskrit and 2 each in Arabic and Persian are selected and their names are announced on the eve of the Independence Day. The award carries an annual monetary grant of Rs. 5,000/- for life and besides a sanad and a shawl presented at a function held at the Rashtrapati Bhavan. As in the past, 14 scholars were selected for award this year also.

Scheme for Development of Sanskrit through State Governments/Union Territories

(a) Financial Assistance to Eminent Sanskrit Scholars in indigent Circumstances

About 1,700 eminent scholars whose income is below Rs. 250/- p.m. are receiving financial assistance up to Rs. 250/- p.m. under this scheme.

(b) Modernisation of Sanskrit Pathshalas.

To bring about a fusion between the traditional and modern system of Sanskrit education, Government of India is giving grants to State Governments for appointment of teachers for teaching selected modern subjects in the traditional Sanskrit Pathshalas. Assistance is expected to be released to 10 States and Union Territories for appointment of one teacher each during 1985-86.

(c) Providing Facilities for Teaching Sanskrit in High and Higher Secondary Schools.

The Government of India gives 100% grant towards salary of Sanskrit Teachers to be appointed in those High and Higher Secondary Schools where the State Government are not in a position to provide facilities to teach Sanskrit. Ten States availed of this assistance during 1985-86 for appointing 36 teachers.

(d) Scholarships to Students Studying Sanskrit in High and Higher Secondary Schools.

In order to attract good students to the study of Sanskrit in the high and higher secondary schools, merit scholarships are given to Sanskrit stupents in IX to XII classes @ Rs. 10/- p.m. About 3,000 students are benefited under this scheme.

(c) Grant to State Governments for their Own Schemes for Promotion of Sanskrit.

Under this scheme, a State Government is free to chalk out its own programme for development and propagation of Sanskrit like upgrading the salary of teachers, honouring of Vedic Scholars, conducting Vidwat Sabhas, holding evening classes for Sanskrit, celebrating Kalidasa Samaroh, etc. Nine States would be covered during 1985-86.

Production of Sanskrit Literature

Under this scheme, assistance is given for (i) printing and publication of original works relating to Sanskrit Literature, (ii) Printing of out-of-print Sanskrit books, (iii) Purchase of Sanskrit publications from authors and publishers for free distribution to various institutions, (iv) Sanskrit journals to improve their quality and contents, (v) preparation and publication of descriptive catalogues of Sanskrit Manuscripts and publishing critical editions of Sanskrit Manuscripts.

During 1985-86 (as of December 1985) 30 publications were brought out with Government assistance. About 20 more publications are expected to be brought out during 1985-86. Besides these, the Dharma Kosha Mandala, Wai, is engaged in the preparation and publication of Dharmakosha, an encyclopaedia of ancient Sanskrit Literature. So far 4 kandas comprising 19 volumes have been published. The whole work is expected to consist of 44 volumes, each volume of about thousand pages of super royal size. The pattern of assistance for this project for the VII Plan is under consideration. The All India Kashiraj Trust, Varanasi, is engaged in bringing out the Hindi translation, the English Translation and critical editions of all the Mahapuranas with Government assistance.

About 31 journals are being assisted by the Government of India with grants, ranging from Rs. 1,500/- to Rs. 10,000/- p.a. to improve their quality and contents. Government has also purchased about 175 books from individuals and publishers for free distribution to various institutions. 5 catalogues/critical editions of manuscripts have been brought out in 1985-86. In four cases partial editing/editorial grants have been released and the books are under preparation/printing.

A massive programme for photo-off-set reproduction of important out-of-print Sanskrit books has also been undertaken to make them available at low prices.

About 80 titles including all Vedic texts of Swachyaya Mandal, translation of all Vedas with Hindi commentries, and 14 Puranas have been brought out so far.

Preservation of Oral Tradition of Vedic Studies

As a special incentive to preserving the oral tradition of Vedic studies, a scheme was introduced during 1978 under which each Swadhyay in is expected to train two students each below the age of 12 one of them being their own son or near relative, in a particular Veda Shakha. During 1985-86 eleven such units are receiving assistance. The honorarium of the scholar has been raised from Rs. 1,000/- p.m. to Rs. 1,250/- and of the student from Rs. 150/- p.m. to Rs. 175/- p.m. from April 1985.

(ii) In order to locate and identify the areas and families where the oral Vedic tradition is still alive, the Ministry holds a Vedic convention every year, to which about 100 scholars from all over India are invited. This year's Vedic Convention was held on Kancheepuram on 24th & 25th December, 1985.

(iii) The Ministry holds an All India Elocution Contest to encourage oratorial talents in the students of traditional Sanskrit Pathshalas on various branches of Sanskrit learning. Teams of eight students along with a teacher from all States are invited to participate. This year's contest was held in December 1985.

(iv) Another programme of Vedic Endowment is being actively considered in which Prime Minister and Vice-President of India have evinced great interest.

Vocational Training to Products of Sanskrit Pathshalas

In order to enhance the employment possibilities of students passing out of the Kendriya Sanskrit Vidyapeethas, the Adarsh Sanskrit Mahavidyalayas, and other traditional Sanskrit institutions, a new scheme was introduced during 1982-83 to provide short-term vocational training to those students in subjects allied to Sanskrit studies, namely, Epigraphy, Manuscriptology, Ritualogy, Sanskrit printing and composing etc. For conducting these courses, registered voluntary organisations receive cent per cent grant. During 1985-86 about eight such courses are planned.

CHAPTER 10

INDIAN NATIONAL COMMISSION FOR COOPERATION WITH UNESCO

Co-operation Between India and Unesco

India is one of the founder members of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) which was established with headquarters in Paris in November, 1946. During the period under report, the Indian National Commission for Cooperation with Unesco performed its role not only as a coordinating agency at the national level but also collaborated with the other National Commissions of Asia and the Pacific region and with Unesco's Regional Offices in New Delhi, Bangkok, Jakarta, Karachi and other places in fostering regional and sub-regional cooperation and for bringing about better understanding of Unesco projects and activities.

The following account gives a brief resume of the activities of the Commission undertaken during the period under review.

Fifth Regional Conference of Ministers of Education

Unesco Regional Office for Education in Asia and the Pacific organised the Fifth Regional Conference of Ministers of Education and those responsible for Economic Planning in Asia and the Pacific (MINEDAP-V) at Bangkok in March, 1985. The main objectives of the conference was to consider the priority goals of educational development in the region, the ways and means of attaining the goals of literacy for adults and universilization of primary education in the context of the renewal of education in relation to development needs and education for international understanding. The Conference was attended by a high-powered six-member delegation headed by the former Minister of Education, Shri K. C. Pant.

Third Session of the Advisory Committee on Regional Cooperation

The third session of the Advisory Committee on Regional Cooperation, organised by the Unesco Regional Office for Education in Asia and the Pacific, Bangkok, immediately following the Regional Conference, was attended from India by Shri Anand Sarup, Education Secretary. The main purpose of the meeting was to advise the Director-General of Unesco on Unesco's Programme in Education for the biennium 1986-87 in the light of the recommendations of MINEDAP-V.

Prime Minister's Visit to UNESCO

At the invitation of the Director-General of Unesco, the Prime Minister of India, Shri Rajiv Gandhi, paid an official visit to Unesco Headquarters in Paris on June 7, 1985, and addressed, among others, the members of the Executive Board of Unesco and officials in its Secretariat. With reference to actual withdrawal and notice of withdrawal from Unesco by few Member States, the Prime Minister appealed to all nations, who cared for a saner and equitable world order, to come to the help of Unesco in its hour of trial. He assured that India would support any constructive effort which would resolve Unesco's dilemma. He further stated that to turn away from Unesco was to turn away from universal cooperation and to reject the democracy of international relations in world bodies.

Meetings of the Sub-commissions and the Eighteenth Session of the Indian National Commission

The Indian National Commission for Cooperation with Unesco convened meetings of its five Sub-Commissions in July, 1985. The purpose of the meetings was to examine Unesco's Draft Programme and Budget (Document 23 C/5) for the biennium 1986-1987 and to formulate India's stand in respect of this document.

The meetings of the Sub-Commissions were followed by the Eighteenth Session of the Indian National Commission for Cooperation with Unesco which was held in New Delhi on September 21, 1985, under the

chairmanship of the then Union Education Minister and President of the Commission. The main purpose of the meeting was to consider Unesco's Draft Programme and Budget for the biennium 1986-1987. In addition, it also considered the draft resolutions to be moved by India at the Twenty-third session of the General Conference of Unesco held in Sofia (Bulgaria) in October-November, 1985. The Conference was attended by 50 eminent personalities and experts in the fields of education, social sciences, natural sciences, culture and communication who are members of the Indian National Commission.

Twenty-third Session of the General Conference of UNESCO

A high-powered delegation led by Shri P. V. Narasimha Rao, Minister for Human Resource Development, attended the 23rd session of the General Conference of Unesco held at Sofia (Bulgaria) from 8th October to 9th November, 1985. The delegation included Sardar Swaran Singh as the alternate leader, Smt. Sushila Rohatgi, Minister of State for Education and Culture, Smt. Margaret Alva, Minister of State for Youth Affairs, Sports and Women's Welfare, Shri T. N. Kaul, Member, Executive Board of Unesco, Shri Anand Sarup, Secretary Department of Education, Ministry of Human Resource Development, Dr. Karan Singh, Prof. N.C. Prashar, Member of Parliament, Shri Kireet Joshi, Special Secretary, Department of Education, Shri Inam Rahman, Ambassador and Permanent Representative of India to Unesco and the Indian Ambassador to Bulgaria, Shri Sham Sunder Nath. The main agenda of the Conference was to consider and adopt the Draft Programme and Budget of Unesco for 1986-1987. The leader of the delegation was elected as one of the Vice-Presidents of the General Conference. India was also elected as Chairman of the Drafting and Negotiating Group of the Conference. In addition, India was elected as member of the following committees/intergovernmental bodies :

1. Legal Committee.
2. Headquarters Committee.
3. Intergovernmental Council of the International Programme for the Development of Communication (IPDC).
4. Committee responsible for coordinating the Intergovernmental Informatics Programme.

Besides, India was elected as a member of the World Heritage Committee at the Fifth General Assembly of State Parties to the Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage which took place on 4th November, 1985.

Apart from the active participation of the Indian delegation in the discussions held in the plenary sessions, Programme Commissions and Administrative Commission, the Indian delegation submitted eight Draft Amendments and Resolutions to emphasise the point of view of developing countries and to highlight certain priorities and programmes for Unesco's work.

Executive Board of Unesco

Shri T. N. Kaul, India's representative on Unesco's Executive Board, participated in its 121st, 122nd and 123rd Sessions held during the year. Shri Kaul was also elected a member of the Temporary Committee constituted to advise the Director-General on the ways and means for improving the functioning of the Organisation. The term of Shri T. N. Kaul as member of the Executive Board of UNESCO expired at the close of the 23rd Session of General Conference of Unesco.

India's candidate Sardar Swaran Singh was elected as member of the Executive Board of Unesco in the election held on October 19, 1985, in Sofia. He attended the first meeting of the reconstituted Executive Board of Unesco held in Sofia from November 13-14, 1985.

Contribution to Unesco's Budget

As one of the Member-States of Unesco, India has been contributing regularly towards its budget. The share of contribution of each member State is fixed by the General Conference of Unesco which is normally held every alternate year. For the years 1984-1985, the Twenty-second Session of the General Conference of Unesco held in October-November, 1983,

fixed India's share of contribution as 0.36% of Unesco's over-all budget. At this rate, India's contribution for 1984 and 1985 amounted to US $ 6,20,460 per annum which is equivalent to Rs. 78,80,000/- approx. This amount has already been paid.

In view of the financial constraints encountered by the Organisation due to withdrawal of a Member-State and as a token of its support, India also surrendered an amount of US $ 407,245 which had accrued as surplus from India's contribution to Unesco budget for the triennium 1981-1983, due to fluctuation in value of US dollar.

Unesco Participation Programme

Under its Participation Programme, Unesco authorises the Director-General to participate in the activities of the Member States at national level and at the sub-regional, regional or inter-regional level. The Participation Programme enables Member States to benefit from Unesco's assistance for activities undertaken on their own initiative within the fields specified by the General Conference with a view to attaining the objective it has laid down. Out of 20 projects submitted by India under the Participation Programme for the 1984-85 biennium, 12 projects have been approved for Unesco assistance during the period. The total quantum of financial assistance received from Unesco for these projects comes to US $ 1,42,000. Five projects have been implemented during 1985.

Unesco Clubs

Since the inception of Unesco Clubs Movement, India has been taking great interest in it. After Japan, India is having the largest number of Unesco Clubs in Asia. The Indian National Commission continued to supply publication and other materials of interest to these clubs, special kits are being sent to enable them to celebrate such events as UN Day, Human Rights Day, etc.

Unesco Coupons

In order to ensure free flow of information, Unesco has devised International Coupons Scheme to assist individuals and institutions working in the fields of education, science and culture, to import their bonafide requirements of books, educational materials, scientific equipment and educational films from abroad without undergoing foreign exchange and import control procedures. The Indian National Commission for Co-operation with Unesco has been functioning as the distributing agency for the sale of Unesco coupons in India. The total sale of Unesco Coupons during 1985-86 will amount to Rs. 1,50,000 approximately.

Unesco Courier

The Indian National Commission, in collaboration with Unesco, is bringing out Hindi and Tamil editions of Unesco monthly magazine entitled 'Courier' which is the most outstanding educational and cultural periodical of the world. The present number of each language issue is 3,000 copies which are distributed widely amongst school and college students and teachers in India and other interested in Unesco's activities.

Newsletter

The Indian National Commission has been bringing out regularly, the quarterly journal 'Newsletter' in English. Since 1984, the Commission has also started the publication of this bulletin in Hindi version. About 2000 copies in each version are produced which are distributed to various non-governmental organisations in India and abroad who are connected with the programmes and activities of Unesco. Tis journal contains information about the activities and programmes of Unesco as well as activities of the Commission undertaken during the quarter.

Associated Schools Project

The Indian National Commission participates in Unesco's Associated Schools Project which promotes understanding of the aims and activities of Unesco among the people of India. The Secretariat of the Commission continued to sanction grant-in-aid to voluntary organisations in spreading the message of Unesco.

Indian National Commission's Expanded Programme under the Associated Project

The Indian National Commission has prepared an expanded programme in India as distinct from the programme operated by Unesco but based on similar lines, to cover a large number of schools and teacher training institutions in the country. The number of institutions at present is 738. Since the programme is of vital importance for India and the world, more schools are being brought within its fold.

Strengthening of the Indian National Commission

In order to enable the Indian National Commission for Unesco to discharge its functions and responsibilities in an adequate manner, a plan scheme for strengthening the activities of the Commission has been approved by the Planning Commission. A provision of Rs. 5 lakhs has been included in the budget estimates 1985-86.

Participation in other Conferences/Meetings Sponsored by Unesco

Seventh Meeting of Experts on Regional Cooperation in Unesco Cultural Activities in Asia and the Pacific was held at Tokyo, Japan from March 14-18, 1985. Shri D. S. Misra, Joint Secretary, Department of Education, was deputed to attend the meeting. He was elected Vice-Chairman of the meeting.

Mr. John Joshua, Assistant Educational Adviser, Department of Education, was deputed to participate in Unesco's Sub-regional Seminar on Book Design held in Karachi, Pakistan, from April 29 to May 5, 1985.

Shri Kireet Joshi, Special Secretary, Department of Education, participated in the 31st Session of the Editorial Board of the International Review of Education and 37th Session of the Governing Board of the Unesco Institute for Education held in Hamburg on May 20, 1985 and on May 21-23, 1985, respectively.

In addition to the above-mentioned meetings, the Indian National Commission nominated experts to participate in about 52 national, regional, international meetings, workshops, seminars, conferences etc., convened by or under the auspices of Unesco.

Visitors from Abroad

A number of visitors from various countries, Unesco Regional Offices, National Commissions, visited India during 1985-86. The important visitors included Mr. Armoogum Parsuraman, Mauritius Minister of Art and Culture who paid a visit to India from September 19-25, 1985 and Mr. Wim J. Deetman, Netherlands Minister of Education and Science from November 3-9, 1985.

The World Heritage Committee

Under the provision of the convention concerning the protection of the World Cultural and Natural Heritage, a committee called the World Heritage Committee, comprising 21 state parties to the convention has been constituted. The main responsibilities of the Committee are to identify those natural and cultural sites which are protected under the World Heritage Convention by inscribing them on the World Heritage list to make the sites known throughout the world and to provide technical cooperation to states for safe-guarding of World Heritage sites from the World Heritage Fund.

The election to the World Heritage Committee was held during the fifth Session of the General Assembly of the State parties in November, 1985. India has been elected as one of the members of the Committee.

Following six cultural monuments from India have so far been approved for inscription on the World Heritage list :

(1) Taj Mahal

(2) Ajanta Caves

(3) Ellora Caves

(4) Agra Fort

(5) Sun Temple at Konarak

(6) Monuments of Mahabalipuram.

Following three natural sites have also been considered by the World Heritage Committee for inscription on the list :

(1) Kaziranga National Park,

(2) Keoladeo National Park

(3) Manas Wild Life Sanctuary.

Construction of Unesco House

The Unesco Regional Office of Science and Technology for South and Central Asia was set up in 1965 after India agreed to provide the normal facility of adequate, rent-free accommodation for the Regional Office. To meet this long-standing obligation of providing suitable accommodation to the Regional Office, it is now proposed to construct a new office-building in New Delhi. A plot of land has already been allotted for the purpose by the Ministry of Urban Development. The scheme for construction of Unesco House has been included in the Seventh Five-Year Plan. The building is proposed to house two offices of Unesco functioning in India, viz. (i) the office of the Chief of Unesco Mission in India, and the (ii) Unesco Regional Office of Science and Technology for South and Central Asia.

Commonwealth Education Ministers' Meeting

The Commonwealth Desk in the Unesco Division of the Ministry coordinates the work-relating to Commonwealth Secretariat's education programme.

A meeting of the Commonwealth Education Ministers was held at Sofia (Bulgaria) on 6th October, 1985 on the eve of the 23rd Session of the Unesco General Conference. The Indian delegation to the meeting was led by Shri P. V. Narasimha Rao, Minister of Human Resource Development. The Conference discussed matters relating to (i) Commonwealth Student Mobility and Higher Education (ii) Tenth Commonwealth Education Ministers' Conference to be held in Nairobi in 1987, and (iii) Exchange of views on Unesco.

Auroville Project

In 1980, the Central Government passed an Act called the Auroville (Emergency Provisions) Act under which the management of Auroville—an international cultural township, established in South India was vested in the Central Government for a period of two years. This period was extended on a year to year basis upto 1985. The Parliament has now amended this Act. By the Auroville (Emergency Provisions) Amendment Act 1985, the management of Auroville will continue to vest in the Government for another two years from November, 1985.

A scheme for the development of Auroville has been included in the Seventh Five-Year Plan with a total outlay of Rs. 35.55 lakhs. The scheme envisages setting up of the following centres at Auroville :

(1) Centre of Child Development

(2) Centre for Indian Studies
  (A) Hall of Culture
  (B) Hall of History

(3) Centre for Audio-visual Educational Materials

(4) Centre for Development of Physical Education

(5) Centre for Evolutionary Studies
  (A) Centre of Human Unity
  (B) House of Mother's Agenda

(6) Centre for Urban Development

(7) Community Facilities and Services.

Fourth and Fifth Meetings of the Auroville International Advisory Council

The fourth meeting of the Auroville International Advisory Council set up by the Central Government under the provisions of the Auroville (Emergency Provisions) Act, 1980, was held in May, 1985. The Council expressed its satisfaction over the steps taken by the Central Government for the development of Auroville. The fifth meeting of the Auroville International Advisory Council was also held on 4th January, 1986. The meeting reviewed the progress made in the development of Auroville.

CHAPTER 11

OTHER ACTIVITIES

New Education Policy

The formulation of the New Education Policy has been taken up as a priority task. A document 'Challenge of Education—A Policy Perspective' was prepared in August, 1985 which was discussed in the Conference of Education Ministers of all States and Union Territories held on 29-30 August, 1985 and formed the basis of nation-wide debate on the national policy on education.

In accordance with the decisions taken in that Conference, the Central Government organised 11 National and 20 Sponsored Seminars on important subjects while the State Governments organised State level and District level Seminars. Officers of the Ministry of Education, NCERT and NIEPA were designated to assist the debates and deliberations held at the State level. The following Teachers organisations were requested to organise State level Seminars of their affiliates as well as a National Seminar :—

— All India Primary Teachers' Federation.

— All India Secondary Teachers' Federation.

— All India Federation of College & University Teachers organisation.

— All India Federation of Educational Associations.

As a follow-up of the decision taken in the Conference of State Education Ministers, two Groups, one each on Manpower Projections and Vocationalization, and on Financial Resources were set up for involvement of State Education Ministers and a few distinguished Experts. A meeting of these Groups took place on 25 and 26 November 1985 and 25 and 26 February respectively. A National Group of State Education Ministers on Examination Reforms has also been set up under the chairmanship of Minister, Human Resource Development.

As a result of the close follow-up with State Governments it has been possible to organise discussions from the local level upwards—meetings having taken place at the block, district, divisional and State levels. Teachers' organizations, university faculty, political parties and parents have been involved in this debate. State Governments were also requested to have informal consultations with peoples representatives and a number of them have done so. Detailed memoranda representing the views of State Governments on various issues have been received from most of the States.

A large number of organizations representing well-known interests have formally sent their memoranda. These include the Nai Talim Sangh (representing Gandhian basic education), All India Association for Christian Higher Education, various Adult Education Associations, National Organizations of Women, Council of Social Sciences Research, Association of Indian Universities, National Parents Teachers Association, etc., the All India Management Association and a number of well-known private companies have sent detailed memoranda (including Tata Consultants and Larsen & Toubro). In addition, several thousand individual memoranda have been received. All these documents have been remitted to NIEPA which has brought out, in an abstracted and classified form, the following documents :

(i) Citizens' Perception on New Education Policy Vol. I—Individual memoranda received till May 1985.

(ii) Citizens' Perceptions on New Education Policy Vol. II—individual memoranda received from June to October 1985.

(iii) Individual responses to Janvani Programme of Union Education Minister.

(iv) Summary of Press Clippings.

(v) Summary of Seminar reports and group memoranda received till the end of October 1985.

Issues relating to New Education Policy were the exclusive subject of discussion in the meeting of Consultative Committee held on 7th November, 1985. A debate on the New Education Policy was held in Lok Sabha and Rajya Sabha on 10th December and 19th December, 1985 respectively.

State Governments, educational institutions, teachers, students, parents and people in all walks of life have evinced keen interest in the reorganisation of the educational system and have sent their comments. After taking into consideration all the suggestions received in this behalf, the Government will present the draft of the New Education Policy to the Parliament in the Budget Session.

Annual Plan & 20 Point Programme

Monitoring of Point No. 16 of the New 20-Point Programme relating to universalisation of elementary education and adult education was continued during the year under report. The Bureau of Planning, Monitoring & Statistics of the Ministry submitted periodical reports to the Planning Commission and Prime Minister's Office after collecting the requisite information from various States/Union Territories. In addition, it continued to discharge its function of co-ordination of Annual and Five Year Educational Plans and monitoring Progress of implementation of the schemes in the Central as well as State Sectors. In the light of the report of the Working Group on Monitoring & Evaluation for Education, it is proposed to strengthen the monitoring evaluation and statistical machinery. Accordingly, Special provisions are being made in the Annual Plan both in the Central and State Sectors.

In the Annual Plan 1985-86, a sum of Rs. 972.31 crores (Comprising Rs. 331.47 crores in the Central Sector and Rs. 640.84 crores in the State Sector) was provided for development of various sectors of Education. In the Seventh Plan for 1985-90, a provision of Rs. 5457.09 crores has been made (Comprising Rs. 1738.64 crores in the Central Sector and Rs. 3718.45 crores in the State Sector). For 1986-87, the Ministry has made a provision of Rs. 351.96 crores in the Central Sector for various sectors of Education.

Analysis of Budgeted Expenditure on Education 1982-83 to 1984-85 and analysis of State Plan 1985-86 was brought out during the year under report.

Educational Statistics

The Xth meeting of the Standing Committee on educational statistics held on 12-9-1985 under the Chairmanship of Jt. Secretary (Plg.), reviewed the progress made by the Ministry in clearing the backlog of arrears in educational statistics as per recommendation of a Sub Committee constituted for this purpose. It also reviewed the progress made by the Ministry in regard to implementation of the other recommendations of the High Level Committee on educational statistics.

The modalities of the Pilot Project for computerisation of educational statistics in U.P. were finalised in consultation with the Government of U.P., during the current year. Special coded forms were designed for the collection of data for this Pilot Project. The same were got printed by the Ministry and supplied to the State Government for the collection of data from the field. The results of the Pilot Project are expected to be available during 1986-87 and these will be utilised for formulating suitable guidelines for introducing computerisation of educational statistics in other states.

During the year under report, the following publications were brought out :—

(i) District-wise Educational Statistics 1976-77 Vol. XXI-Orissa.

(ii) Selected Information on School Education 1982-83.

(iii) Selected Informaton on School Education 1983-84.

(iv) District-wise Educational Statistics 1976-77 Vol. XXII-Maharashtra.

(v) District-wise Educational Statistics 1976-77 Vol. XXIII-Tamil Nadu.

(vi) District-wise Educational Statistics 1977-78 Vol. XXIV-West Bengal.

(vii) Indian Students/Trainees going Abroad 1979-80 & 1980-81.

(viii) Selected Educational Statistics 1982-83.

(ix) Selected Educational Statistics 1983-84.

(x) Education in India Vol. I 1978-79 & 1979-80 (Under Print).

(xi) Education in India Vol. II 1977-78 (Under Print).

(xii) Education in India Vol. III 1976-77 (Under Print).

Statistical Unit supplied the necessary data base in context with the preparation of the prestigious document of the Ministry viz. "Challenge of Education—a policy perspective".

Large number of statistical enquiries were under taken by the Statistical Unit both from National and International organisations. Besides relevant statistical material was supplied to various divisions of the Ministry for answering Parliament Questions, meetings of Consultative Committee etc.

Education of Scheduled Castes/ Scheduled Tribes

Provision of educational facilities to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is receiving high priority. The Prime Minister took a meeting with Members of Parliament belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in May, 1985 to discuss ways and means to accelerate the progress and development of education among these communities. Suggestions given by members of parliament is receiving utmost attention and efforts have been made to implement them by various departments of the Government.

Special Component Plan for Scheduled Castes and Tribal Sub-Plan for Scheduled Tribes for the Seventh Plan 1985-90 and Annual Plan 1986-87 have been finalised. Draft Special Component Plan and Tribal Sub-Plan for the Annual Plan 1986-87 have also been prepared. 21.66% and 12.69% of the total divisible outlay have been earmarked for these two Component Plans respectively out of the total divisible outlay for the Annual Plan for 1986-87.

A brochure on Scheduled Castes & Scheduled Tribes has been prepared and is under print. The brochure gives details of the educational facilities given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes by various departments of the Central Government and of the State Governments and Union Territory Administration.

A Publication giving state-wise information on Education of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been brought out. The scheme of girls hostels for Scheduled Castes and Scheduled Tribes which is a centrally sponsored scheme of Ministry of Welfare is being evaluated under the aegis of Department of Education. The evaluation work has been assigned to three research organisations.

Education of Minorities

In pursuance of former Prime Minister's 15 Points directive on the Welfare of Minorities a number of promotional steps have been taken by the Department of Education in respect of educationally backward minorities. Some of them are :—

(i) Under the scheme of Community Polytechnics, 10 polytechnics impart training in various skills/trades through short-term train-

ing courses in minority-concentration areas. Each of these Community Polytechnics have 4 Extension Centres at suitable minority concentration pockets. About 1700 candidates have undergone training and about 700 are undergoing training under this programme. Efforts are also made in getting gainful employment including self-employment after the training.

(ii) University Grants Commission has a scheme of coaching classes for educationally backward minorities to prepare them for admission to Civil Service Examinations and other recruitments. Grants are given under the scheme to universities/ colleges for opening coaching centres.

(iii) Text-books are being reviewed from the stand point of national integration. Work of revision of text-books of History and Languages has been completed in almost all the States and Union Territories. The NCERT has now initiated action for evaluation of school text-books in Geography, Sociology and Political Science. The guidelines and tools for evaluation of text-books have been sent to state agencies for their views.

(iv) NCERT conducts training courses for vocational guidance and for training of teachers trainers in Science, Mathematics and English for teachers belonging to minority educational institutions. Besides this, NCERT has initiated action regarding setting up of resources centres in selected universities for organising training programmes for teachers from minority managed schools. Universities of Aligarh, Jamia Millia Islamia, Kashmir, Marathwada and Osmania are actively involved in this programme.

A two-day national seminar on Minorities and Education in the context of New Education Policy was organised with a view to improving the existing educational system and to make it more relevant to the lives of the Minorities.

Development of Computerised Management Information System for the Ministry

The Ministry has entered into an agreement with the National Informatics Centre (Deptt. of Electronics) for developing Computerised Management Information System for the Ministry. In this context, NIC has installed a mini computer terminal in the Ministry. This terminal works in conjunction with the Maxi Computer of the National Informatics Centre as part of its network.

With a view to accelerating the growth of CMIS and creation of expertise within the Ministry, a CMIS Unit within the Planning, Monitoring and Statistics Division has been created. Under the control of CMIS Unit there is a Word Processor and a Photo copier.

The CMIS Unit has undertaken various projects in different Divisions of the Ministry for Computerisation. The projects for which the software has been developed and which have been completed/under completion are as follows :—

(i) Foreign Students studying in Indian Universities.

(ii) Computerisation of pay bills.

(iii) Computerisation of accounts of the Ministry.

(iv) Indian Students/trainees going abroad.

In respect of the projects "Schemes of Scholarships for study abroad" and "Computerisation of Publications brought out by Language Division" feasibility study has been completed and the proforma has been designed.

Design of proforma in respect of the projects "Scheme of Scholarship for Research in Classical Languages" and "Training imparted to teachers in various disciplines" is under progress.

In addition, the CMIS Unit has arranged a two-day Computer Awareness Course for the senior officers of the level of Deputy Secretary and above. Intensive use of Word Processor has been made for creating important documents on New Education Policy, "Notes on Seventh Five Year Plan", etc. Photocopier has also been used to its maximum capacity.

Supply of white printing paper at control rate for educational purposes

The Scheme for allocation of concessional white printing paper at the control rate to State Governments and Union Territories has been continued during the year under report. The price of white printing paper during the period has not increased and the price of the exercise books have also remained fixed. About 1,00,055 MTs of paper has been allotted to the States/Union Territories for educational purposes during the year 1985-86 upto December 1985.

Import of Gift Paper from Norway

Under the bilateral agreement with the Government of Norway, commodity assistance of paper worth 3200 MTs valued at Rs. 3.10 crores is expected to be received during the plan of operation 1985. Out of the said quantity, it has been decided that 1500 MTs of paper will be allotted to NCERT for the printing of School text-books. The balance paper is proposed to be allotted to nine economically backward States for the printing of materials for Adult Education Programmes.

The following are the Revised Estimates 1985-86 and Budget Estimates 1986-87 in respect of the gift paper :—

(Rupees in crores)

		R.E. (1985-86)	B.E. (1986-87)
(1)	Major Head '267' A.I(1)-Gift Paper Non-Plan (National Value)	3·10	3·10
(2)	Major Head '277' B6(5)(4)-Gift Paper from Norway (Incidental Expenses)	1·90	1·90

National Institute of Educational Planning and Administration

The National Institute of Educational Planning and Administration (formerly the National Staff College for Educational Planners and Administrators) is an autonomous institution set up and fully financed by the Government of India. It is registered as a Society under the Societies Registration Act XXI of 1860 in December, 1970. As the apex training institute in India for educational planners and administrators, its main functions are training, research and administration. The main activities undertaken by the Institute include; Training and reorientation of senior educational administrators from the centre and the states, according to their needs and backgrounds. Research in problems of educational planning and administration, consultancy and extension services in this field to the states and other organisations; Seminars, workshops and conferences on themes of topical interest in educational planning and administration, and provision of training and research facilities to other countries specially of Asian region.

During 1985 i.e. from April-November 1985, the Institute conducted 39 training programmes/seminars/workshops. 8 Research studies have been completed and another 8 are in progress.

The Institute organised four Regional Seminars for Northern, Southern, Eastern and Western Regions and a National Seminar on the New Educational Policy to discuss the various Planning and Management Issues of Education. These Seminars, were conducted on the basis of the document prepared by the Union Education Ministry, "Challenge of Education : A Policy Perspective". Out of the four Regional Seminars, three were held in collaboration with Indian Institute of Management, Calcutta (Eastern Region), Institute for Social and Economic Change, Bangalore (Southern Region), and Tata Institute of Social Sciences, Doonar, Bombay (Western Region). The Northern Region and National Seminars were held at New Delhi.

Earlier the Institute prepared a comprehensive paper entitled "Educational Development : A Status Report and Policy Issues" and also scrutinise analysis of the Education System as an input in the Ministry's paper on "Challenge of Education : A Long Term Perspective".

At the request of Ministry of Human Resource Development (Department of Education), the Institute undertook the content analysis of a large number of letters received by the Ministry of Human Resource Development (Department of Education) and by the Ministry of Information and Broadcasting on Education Minister's participation in Janvani Programme. Press Cuttings and Organisational Memoranda to discern people's opinion on the Education System as background material for formulation of the New Education Policy.

National Commission on Teachers

The National Commissions on Teachers-I & II were set up in February, 1983 to advise the Government on various aspects relevant to the teaching community at the school stage and at the higher education level respectively. The two Commissions submitted their final reports to the Government on 26th March, 1985.

An Empowered Committee to examine the recommendations of the National Commission on Teachers I&II has been set up.

Vigilance Activities

Sustained efforts were made to tone up the administration and to enforce discipline amongst staff of the Department, both at Headquarters and in subordinate offices. Of the 6 cases pending as on 31-12-1984 and 4 cases initiated during 1985, disciplinary proceedings against four erring officials were concluded and appropriate orders were passed in each case. Three cases are in the advanced stage of finalisation.

All complaints received in the Grievances Redressal Cell were promptly attended to and appropriate action taken.

Although only nominal public dealings are involved at the Headquarters of the Department, vulnerable sectors were identified and precautionary preventive measures were taken. Members of staff working in these sectors were shifted, where necessary.

Of the 45 autonomous organisations under the administrative control of the Ministry, 31 have accepted the jurisdiction of the Central Vigilance Commission. Four of these organisations have also appointed Chief Vigilance Officers. Others are being pursuaded to appoint Chief Vigilance Officers.

To enforce discipline and punctuality, 11 surprise checks were organised.

Observance of orders regarding representation in Posts and Services for Scheduled Castes and Scheduled Tribes

A special cell exists in the Department of Education to watch the interest of members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for appointments in the Government. The Director of Administration in the Department of Education acts as Liaison Officer to watch the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Strict compliance with reservation orders and instructions issued by the Government from time to time for Scheduled Castes/Scheduled Tribes in respect of recruitment, promotion and confirmation in the services under the Central Government was ensured.

Rosters were inspected regularly. Prescribed Returns and Statements regarding representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes were sent to the Department of Personnel and Training and Commissioner of Scheduled Castes and Scheduled Tribes regularly.

All Heads of Subordinate Offices under the Department have been requested to nominate their senior officers as Liaison Officer and also to maintain proper Rosters for reservation.

Students /Information Service Unit

Under the External Scholarships Division, the Students/Information Service Unit collects, compiles and disseminates information on higher education in India and abroad for the benefit of the students and attends to their enquiries made either across the table or through correspondence. A reference library comprising syllabi, prospectuses, handbooks and annual

reports etc. is also maintained for their benefit. During the period of the report 30 information leaflets on different aspects of education were compiled/revised for the convenience of scholars. Besides, the Unit attended to over 4980 enquiries pertaining to facilities for higher/technical education in India and abroad either orally or through correspondence. About 4600 persons visited the library to consult the calendars/handbooks/prospectuses and other material on courses offered by Indian/Foreign Universities. About 1000 additions were made during the year to the Reference Library of the Unit.

Authentication of educational documents of persons going abroad for purposes of employment or higher education is also attended to, in the Student Information Service Unit. 3724 documents were authenticated during the period under report.

Requests for procurement of original specimens of educational certificates from Pakistan and Bangladesh were taken with our missions in those countries.

Deputation/delegations sent abroad of Government officials and non-officials during the year 1984-85

No. of delegations	No. of persons including the delegation/deputations	Total (in Rs.)	Foreign Exchange component (in rupees)
1	2	3	4
48	119	143221	538621

Budget Estimates

Department of Education : The total budget provision for 1985-86 and 1986-87 in respect of this Department are as under :

(Rupees in lakhs)

Particulars	Budget Estimates 1985-86	Revised Estimates 1985-86	Budget Estimates 1986-87
Demand No. 24-*Department of Education*	3,65·25	3,01·88	—
Demand No. 57—*Ministry of Human Resources Development* (*Department of Education*) (Secretariat of the Department including the pay and Accounts Offices and Discretionary Grant by Minister). . .	—	—	3,65·14
Demand No. 25—*Education* . . (Changed to Demand No. 58—From 1986-87)	513,78·47	587,73·19	661,84·09

Provisson for General Education, other revenue expenditure of the Department including provisions for grants in aid to States/Union Territories on Central/Centrally sponsored schemes (Plan) and also provision for loans for Central/Centrally sponsored Schemes.

Progressive use of Hindi

1. A number of steps were taken during the year under review to ensure effective implementation of the provisions of the Official Languages Act and Official Language Rules as also the items included in the Annual Programme, 1985-86 issued by the Deptt. of Official Language. The Progress achieved in this regard was reviewed in the meetings of the Official Language Implementation Committee.

2. After the reorganisation of the Ministry, action was intiated for the reconstitution of the Hindi Salakhar Samiti for the Ministry of Human Resource Development to advise the Ministry on matters relating to the progressive use of Hindi for Official purposes and related issues.

3. Under the Hindi Teaching Scheme, 15 persons were nominated for training in Hindi, 19 persons were nominated for training in Hindi Typewriting and 5 persons were nominated for training in Hindi Stenography.

4. Financial incentives are given to the successful official as approved under the Scheme.

5. Hindi Workshop/Lectures were organised for Hindi Knowing Officers/employees for imparting training in Hindi noting and drafting to enable them in doing their official work in Hindi.

6. For facilitating the use of Hindi in transacting official work, reference and help literature was prepared and made available to the officers/employees of the Department and also to the Attached/Subordinate Offices and Autonomous Organisations under the Department.

7. Periodicals and magazines in the Department are being continued to be published in Hindi as well as in English.

8. Officers in the Department carried out inspections of the Attached/Subordinate Offices and Autonomous Organisations under the Department to ensure compliance of various statutory and administrative requirements of the Official Language Policy.

9. Official Language Implementation Committees comprising Officers, representing various Divisions constituted to review the progress made in the use of Hindi in Official work continued to function in the Department as well as in Attached/Subordinate Offices and Autonomous Organisations. These Committees met at regular intervals to review the progress of the implementation of the various statutory and administrative requirements of the Official Language Policy.

10. During the year under review the First Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Languages inspected the Department of Education and Offices under the Ministry, namely Educational Consultants India Ltd., Commission for Scientific and Technical Terminology, Central Hindi Directorate, Kendriya Vidyalaya Sangathan, etc.

Publication Unit

The Publication Unit brought out 38 publications in English, including 8 bilingual (English and Hindi titles) and the two quarterly journals "The Education Quarterly" and the 'Indian Education Abstracts' during 1985-86. The Education Quarterly journal entered its 37th year of publication. A monthly resume "Educational and Cultural Developments at the Centre and in the States" with restricted circulation is brought out every month both in English and Hindi.

The Hindi Publication Unit brought out during this period 36 titles including the two quarterly journals "Shiksha Vivechan" and "Sanskriti". Besides, it also brings out Hindi version of the quarterly 'Unesco Newsletter'.

FINANCIAL ALLOCATIONS (IN LAKHS OF RUPEES) OF ITEMS DISCUSSED IN VARIOUS CHAPTERS

Sl. No.	Item	Plan/Non-Plan	Budget Estimates 1985-86		Budget Estimates 1986-87
			Original	Revised	
1	2	3	4	5	6
	SCHOOL EDUCATION				
1.	Kendriya Vidyalaya Sangathan	Non-Plan	5420·00	5600·00	6200·00
2.	Central Tibetan Schools Administration	Non-Plan	173·50	177·74	184·11
3.	Bal Bhawan	Plan	25·00	71·00	35·00
		Non-Plan	38·00	36·00	39·00
4.	Open School	Plan	40·00	47·00	60·00
5.	Community Singing	Plan	32·00	25·00	25·00
6.	Non-formal Education	Plan	880·00	1150·40	2015·00
		Non-Plan	16·00	14·40	15·00
7.	Non-formal Education Centres Exclusively for Girls	Plan	280·00	400.00	715·00
8.	Appointment of Women Teachers in Primary Schools in Nine Educationally backward States	Plan	370·00	450·00	450·00
9.	Early Childhood Education	Plan	50·00	37·00	50·00
		Non-Plan	25·00	25·00	26·25
10.	Value Orientation in Education	Plan	15·00	13·50	15·00
11.	Voluntary Organisations working in the Field of School Education	Plan	30·00	25·00	10·00
12.	Population Education Project	Plan	75·00	75·00	75·00
13.	N. C. E. R. T.	Plan	250·00	250·00	200·00
		Non-Plan	1108·00	1093·59	1125·00
14.	Cultural Exchange Programme in the field of schhool Education	Non-Plan	1·00	0·95	1·00
15.	Integrated Education for Disabled Children	Plan	25·00	25·00	100·00
16.	Education Concessions to the Children of Officers and Men of Armed Forces killed or disabled during hostilities	Non-Plan	1·85	1·80	1·95
17.	ET Programme including INSAT utilisation	Plan	825·00	825·00	850·00
18.	National Awards to Teachers	Non-Plan	5·50	5·36	8·25
19.	Computer Education in schools	Plan	3·00	58·75	100·00
	PHYSICAL EDUCATION				
1.	Development of Lakshmibai National College of Physical Education, Gwalior	Plan	25·00	25·00	61·00
		Non-Plan	49·60	50·08	56·63
2.	Strengthening of Physical Education Training Institutions	Plan	18·00	13·00	5·00
3.	Promotion of Yoga	Plan	7·00	7·00	15·00
		Non-Plan	12·00	12·00	13·00
4.	Strengthening of Physical Education and Sports Programmes at School Level	Plan	—	—	11·00
5.	NCC Junior Division Troupes in Public/Residential/Central schools	Non-Plan	5·50	6·00	9·15

1	2	3	4	5	6
HIGHER EDUCATION AND RESEARCH					
1.	University Grants Commission	Plan GENERAL	7100·00	7400·00	7000·00
		S. A. C. C.		300·00	750·00
		Non-Plan	11267·00	12000·00	12200·00
2.	Indian Institute of Advanced Study	Plan	40·00	28·74	40·00
		Non-Plan	39·20	35·72	38·00
3.	Indian Council of Philosophical Research	Plan	42·00	42·00	45·00
4.	Indian Council of Historical Research	Plan	40·00	35·00	40·00
		Non-Plan	71·26	69·09	76·33
5.	All India Institutions of Higher Learning	Plan	30·00	30·00	30·00
		Non-Plan	14·00	13·30	14·00
6.	Indian Council of Social Science Research	Plan	150·00	150·00	160·00
		Non-Plan	238·30	248·80	252·30
7.	Shastri Indo-Canadian Institute	Non-Plan	30·00	28·50	28·00
8.	Revision of Salary Scales of teachers in Universities and Colleges	Non-Plan	100·00	50·00	95·00
9.	National Research Professors	Non-Plan	1·50	1·00	1·50
10.	Loan to Punjab University	Plan	50·00	50·00	25·00
11.	Assistance to Professional organisations	Plan	5·00	5·00	—
12.	Dr. Zakir Hussain Memorial College Trust	Plan	30·00	30·00	20·00
		Non-Plan	4·00	3·88	4·07
13.	Association of Indian Universities	Plan	5·00	5·10	8·00
		Non-Plan	10·64	10·00	10·64
14.	Jamia Millia Islamia	Plan	32·00	32·00	50·00
		Non-Plan	44·00	46·50	48·50
15.	Indira Gandhi National Open University	Plan	75·00	300·00	750·00
TECHNICAL EDUCATION					
1.	Quality Improvement Programme (Direct Central Assistance & Community Polytechnic)	Plan	350·00	1250·00	600·00
		Non-Plan	135·00	128·25	135·00
2.	Programme of Apprenticeship Training	Esstt.			
		Plan	49·00	55·66	70·00
		Non-Plan	102·75	26·24	29·09
		Stipend			
		Plan	51·00	42·00	100·00
		Non-Plan	185·00	246·00	259·00
3.	Indian Institutes of Technology	Plan	600·00	800·00	800·00
		Non-Plan	4455·84	4479·28	4875·43
4.	Develoment of P. G. Courses	Plan	100·00	92·18	100·00
		Non-Plan	188·10	170·05	183·50
5.	Regional Engineering Colleges	Plan	600·00	600·00	600·00
		Non-Plan	1026·46	990·55	1040·10
6.	Indian Institutes of Management	Plan	400·00	540·00	500·00
		Non-Plan	449·69	445·99	469·54
7.	Administrative Staff College, Hyderabad	Non-Plan	2·50	2·37	2·50
8.	University Grants Commission Scheme (Technical)	Plan	525·00	525·00	550·00
9.	Development of Management Education at Non-University Centres	Plan	25·00	25·00	30·00
		Non-Plan	20·00	9·84	15·00
10.	Advanced Technician Course	Plan	50·00	60·00	50·00
		Non-Plan	8·00	7·60	8·00
11.	Asia Institute of Technology, Bangkok	Non-Plan	8·50	8·00	10·00
12.	National Manpower Information System	Plan	50·00	50·00	50·00
		Non-Plan	20·00	19·00	20·00
13.	Central Institutes				
	(i) TTTIs	Plan	200·00	205·65	200·00
		Non-Plan	226·00	195·34	218·22
	(ii) NITIE, Bombay	Plan	30·00	40·00	30·00
		Non-Plan	104·30	102·00	107·00
	(iii) NIFFT, Ranchi	Plan	20·00	20·00	30·00
		Non-Plan	54·00	58·50	59·85
	(iv) SPA, New Delhi	Plan	150·00	150·00	140·00
		Non-Plan	96·53	86·00	91·00

1 2	3	4	5	6
14. New Schemes				
(i) International Centre for Science & Technology	Plan	50·00	50·00	100·00
(ii) Modernisation of Lab/Workshop	Plan	500·00	1500·00	1650.00
(iii) Emerging Technology	Plan	550·00	550·00	700·00
	Non-Plan	600·00	400·00	600·00
(iv) Areas of Weakness	Plan	550·00	750·00	700·00
(v) Institutional Net Work	Plan	100·00	100·00	10·00
	Non-Plan	10·00	9·50	100·00
(vi) Special Institutions for Appropriate Technology & Rural Development	Plan	50·00	60·00	150·00
(vii) Experiment Pilot Projects for Application of Science & Technology for total Rural Development	Plan	50·00	60·00	200·00
ADULT EDUCATION				
1. Post Literacy and Follow-up Programme	Plan	150.00	150.00	250·00
2. Strengthening of Administrative Structure at the State and District Level	Plan	200·00	199·95	240·00
3. Rural Functional Literacy Projects	Plan	3070·00	3070·00	3070·00
	Non-Plan	130·00	118·50	130·00
4. Assistance To Voluntary Agencies Working in the Field of Adult Education including State Resource Centres and Evaluation	Plan	300·00	700·00	800·00
5. Shramik Vidyapeeths	Plan	50·00	65·00	90·00
	Non-Plan	41·20	46·51	54·75
6. Literacy House, Lucknow	Non-Plan	10·71	10·41	10·71
7. UNICEF-Sponsored Project of Non-Formal Education for Girls and Women	Plan	8·00	8·00	12·00
8. Directorate of Adult Education including Printing Press	Plan	22·00	30·50	28·00
	Non-Plan	26·79	25·90	27·53
9. Mass Movement for Functional Literacy	Plan	1000·00	240·00	1800·00
SCHOLARSHIPS				
1. National Scholarships Scheme	Plan	275·00	275·00	350·00
2. National Loan Scholarships Scheme	Non-Plan	350·00	300·00	300·00
3. National Loan Scholarships Scheme—write-off etc.	Non-Plan	8·00	8·00	10·00
4. 50% share of the State Governments in respect of recoveries under National Loan Scholarships Scheme	Non-Plan	16·00	16·00	22·00
5. Scholarships at Secondary Stage for talented children from rural areas	Plan	125·00	110·00	130·00
6. Research Scholarships to Products of Traditional Institutions in the Study of Classical Language other than Sanskrit like Arabic, Persian	Plan	1·25	1·25	1·25
7. Scholarships for Study Abroad	Non-Plan	80·00	76·00	80·00
8. Scholarships in approved Residential Secondary Schools	Non-Plan	125·00	125·00	140·00
9. Grant-in-aid scheme of Scholarships to Students from non-Hindi Speaking States for Post-Matric Studies in Hindi	Non-Plan	28·00	28·00	28·00
10. General Cultural Scholarship Scheme	Non-Plan	60·00	54·00	59·85
11. Scholarships for Nationals of Bangladesh (funds with Ministry of External Affairs)	Plan	25·00	25·00	25·00
12. Other scholarships Indian Scholars going abroad.	Non-Plan	8·00	7·60	7·98
13. Partial Financial Assistance to Scholars going abroad	Non-Plan	0·42	0·36	0·42
14. Scholarships for Studies in India	Non-Plan	24·00	27·00	29·00
BOOK PROMOTION AND COPYRIGHT				
1. National Book Trust :				
(a) Regional Offices and Book Centres	Plan	10·00	10·00	9·00

1	2	3	4	5	6
	(b) Maintenance & Establishment	Non-Plan	48·71	48·34	50.75
	(c) Normal Promotional Activities	Non Plan	35·00	33·25	34·91
2.	Adan Pradan	Plan	4·00	4·00	3·00
3.	Nehru Bhavan	Plan	10·00	10·00	15·00
4.	Nehru Bal Pustakalaya	Plan	18·00	18·00	15·00
5.	Subsidy Scheme for Indian University level books	Plan	30·00	37·00	35·00
6.	World Book Fair	Non-Plan	25·00	24·20	Nil
7.	National Book Development Council and Book Promotional Activities	Plan	15·00	7·50	10·00
8.	Export Promotional Activities	Plan	8·50	7·50	8·50
9.	Contribution to WIPO and International Copyright Unit	Non-Plan	7·05	6·44	8·30
10.	Publication of Low-priced University level books of Foreign Origin	Plan	1·50	1·50	2·00
11.	Raja Rammohan Roy National Educational Resources Centre	Plan	2·00	2·00	1·50
12.	National Society of Authors & Composers of Musical Works	Plan	1·00	0·10	1·00
	PROMOTION OF LANGUAGES				
	A. Continuing Schemes				
1.	Grants to Voluntary Organisations Working in the field of Hindi	Plan	12·00	12·00	20·00
		Non-Plan	47·00	44·65	47·00
2.	Propagation of Hindi Abroad	Plan	12·00	12·00	12·00
		Non-Plan	8·50	8·00	8·50
3.	Central Hindi Directorate	Plan	22·10	36·10	40·00
		Non-Plan	54·70	53·47	56·08
4.	Grants to Hindi Shikshan Mandal, Agra	Plan	54·00	54·00	65.00
		Non-Plan	95·35	92·40	96.97
5.	Commission for Scientific and Technical Terminology	Plan	10·00	10·00	12·00
		Non-Plan	25·72	24·85	26·10
6.	Modern Indian Languages				
	(a) Grants to Voluntary Organisations for Promotion and Development of Regional Languages (Publication)	Plan	34·00	26·00	35·00
	(b) Monitoring	Plan	3·00	2·00	5·00
7.	Production of Books in Sindhi	Plan	9·00	9·00	5·00
8.	Traqqui-e-Urdu Board-Bureau for Promotion of Urdu	Plan	26·00	26·00	36·50
		Non-Plan	30·50	27·62	29·00
9.	Central Institute of Indian Languages, Mysore	Plan	60·00	32·00	45·00
		Non-Plan	55·40	53·00	55·55
10.	Regional Languages Centres	Plan	18·00	15·00	21·00
		Non-Plan	78·15	72·77	76·34
11.	Appointment of Hindi Teachers in non-Hindi Speaking States/Union Territories (CSS Scheme)	Plan	20·00	20·00	70·00
12.	Establishment of Hindi Teachers Training Colleges in non-Hindi Speaking States/Union Territories	Plan	10·00	55·00	70·00
13.	Production of University Level Books in Indian Languages :				
	(i) Grants to States	Plan	—	—	10·00
		Non-Plan	—	20·00	20·00
	(ii) Grants to Universities	Plan	2·00	1·00	1·00
14.	Grants to NBT for production and translation of Core books on Medicine	Plan	—	7·50	5·00
		Non-Plan	30·00	8·50	10·00
15.	Financial assistance to Regional Institute English and Eltis	Plan	85·00	60·00	103·50

1	2	3	4	5	6
	B. New Schemes				
16.	Modern Indian Languages-Appointment of Teachers	Plan	Nil	Nil	1·00
17.	Establishment of Sindhi Vikas Board	Plan	—	—	18·00
18.	Research in Teaching Methodology	Plan	2·00	0·20	—
19.	Financial Assistance to Voluntary Sanskrit Organisations	Plan	40·00	40·00	40·00
20.	Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya/Sodh Sansthans Schemes	Plan	1·00	1·00	1·00
		Non-Plan	37·00	35·15	37·00
21.	Rashtriya Sanskrit Sansthan	Plan	60·00	60·00	80·00
		Non-Plan	159·73	162·92	171·62
22.	Award of Scholarship to the Students/Products of Sanskrit Pathashalas/Post-Matric Sanskrit Students/Shastri & Acharya Students.	Non-Plan	9·50	9·02	9·50
23.	Sanskrit Dictionary Project of Deccan College	Non-Plan	9·00	8·73	9·00
24.	Financial Assistnace to Voluntary Organisations for the Propagation and Development of Classical Languages other than Sanskrit i. e. Arabic and Persian	Plan	12·00	12·00	12·00
25.	Shastra Chudamani Scheme	Plan	5·00	5·00	12·00
26.	Award of Certificate of honour to Sanskrit/Arabic/Persian Scholars	Non-Plan	7·50	7·50	7·50
27.	Financial Assistance to Sanskrit Scholars in indigent circumstances	Plan	40·00	40·00	40·00
28.	Production of Sanskrit Literature	Plan	15·00	27·00	25·00
29.	Preservation of Oral Tradition of Vedic Studies	Plan	18·50	6·50	4·00
30.	Vocational Training to Products of Sanskrit Pathashalas	Plan	2·00	2·00	3·00
	INDIAN NATIONAL COMMISSION FOR COOPERATION WITH UNESCO				
1.	Reorganisation of INC Library into a fulfledged documentaton and Reference Centre for Unesco Publications in India	Plan	0·50	1·00	1·00
2.	Strengthening of Meetings of Committees/Conferences and Organisations of Exhibitions in furtherences of Unesco's aim and objectives	Plan	3·00	2·50	5·00
3.	Strengthening of Voluntary Organisations engaged in Unesco's Programme and Activities	Plan	1·50	1·50	1·50
4.	Expenditure of International Commission for publication of Hindi and Tamil Editions of Unesco Courier	Non-Plan	9·00	9·00	10·55
5.	Indian National Commission for Cooperation with Unesco		0·60	0·60	0·60
6.	Grants to Non-Governmental Organisation for the Programmes of Indian National Commission for Unesco	Non-Plan	0·25	0·25	0.25
7.	Other Programmes—Hospitality and Entertainment Schemes connected with Unesco	Non-Plan	0·05	0·05	0·05
8.	Contribution to Unesco	Non-Plan	88·30	88·30	88·30
9.	Deputations/Delegations Abroad	Non-Plan	5·00	8·50	7·00
10.	Auroville Management	Plan	Nil	Nil	10·50
		Non-Plan	4·62	4·38	4·62
11.	Visits of Foreign Dignitaries	Non-Plan	—	—	8·00
	OTHER ACTIVITIES				
1.	Publications	Non-Plan	10·50	9·97	10·50
2.	Educational and Culturail Themes Pavilion at Pragati Maidan	Non-Plan	10·00	1·00	25·00
3.	National Institute of Educational Planning and Administration	Plan	25·20	25·20	25·20
		Non-Plan	62·90	63·27	66·43
4.	Scheme of Assistance for Studies in Educational Policies, Planning Management and Evaluation	Plan	4·00	44·00	4·00
5.	Installation of Mini-Computer Terminal at Shastri Bhavan	Plan	3·00	3·00	4·00

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF PRIVATE AND VOLUNTARY ORGANISATIONS WHICH RECEIVED RECURRING GRANT-IN-AID OF RS. 1 LAKH AND MORE DURING 1984-85

Sl. No.	Name of the Private and Voluntary Organisation with address	Brief activities of the organisation	Amount of recurring grant-in-aid released during 1984-85 (Rs.)	Purpose for which the grant was utilised	Remarks
1	2	3	4	5	6
	SCHOOL EDUCATION AND PHYSICAL EDUCATION :				
1.	Kaivalayadham Shreeman Madhava Yoga Mandir Samiti, Lonavala, Pune (Maharashtra)	Promotion of Research and Teacher Training programme in Yoga.	7,95,000	Maintenance expenditure of the Samiti on Research and Teacher Training Programmes in Yoga.	
2.	Banasthali Vidyapith, P.O. Banasthali Vidyapith (Rajasthan)	Vidyapith has obtained status of a deemed University. The aim of Vidyapith is to provide for and promote education, training and Research in different areas of knowledge and to inculcate amongst students the essential values and ideals of Indian Culture and Indian way of life.	3,00,000	To meet the recurring deficit.	
3.	Jana Prabodhini, 510, Sadashiv Peth, Pune, (Maharashtra)	The Institute was started in 1962 for education of gifted boys with the main objective of all round development physical, mental, intellectual, spiritual and such other abilities of students. It is running a High School for boys, High School for Girls and has started a Junior College in 1980.	4,50,000 (one-time-grant)	To meet the liabilities incurred for the construction of School Building.	
4.	Ramakrishan Institute of Moral & Spiritual Education, Mysore (Karnataka)	Conducting of B.Ed. degree course in Moral and Spiritual Education, Short-term course in Moral & Spiritual Education for inservice high school teachers of Karnataka State. The Retreat for College Students from all over India and for General Public.	3,70,000	For maintenance & runnuing of the Institute and for training of teachers in Moral & Spiritual Education.	
5.	Sri Sathya Sai Bal Vikas Education Trust, Khar, Bombay (Maharashtra)	To conduct training of primary teachers of govt. or private schools which conduct the course of education in Human Values.	3,73,987	Do.	
6.	Bangavani Nabadwip (West Bengal)	Establishment of Social Teachers Training Centre for educating teachers for Moral Education Extension of Service for imparting moral education.	1,00,000	Do.	

1	2	3	4	5	6
7.	**Rayalaseema** Seva Samiti, Tirupathi (Andhra Pradesh)	This is non-communnal service organisation. It is open for all caste and creed irrespective of their religion and is engaged with promotion of educational and welfare activities.	2,11,175/-	For running 210 NFE centres.	
8.	Literacy House, Andhra Mahila Sabha, Hyderabad (Andhra Pradesh)	For the promotion of education of girls from pre-primary level to college level, teachers education, adult literacy.	1,03,950/-	For running 100 NFE centres.	
9.	Zila Prod Shikshan Samiti, Kota, (Rajasthan)	To impart education to children, who have never been to school and to drop-outs.	1,38,050/-	For running 100 NFE centres.	
10.	Rayalaseema Seva Samiti, Tirupathi (Andhra Pradesh)	Rayalaseema Seva Samiti started in 1981 to achieve specific goal of Rural Construction activities and welfare schemes for children, women aged and rendering services for socially and economically backward people. It is non-communal service organisation.	6,85,500/-	For running 170 ECE centres	
11.	District Council for Child Welfare, Midanapore P. O. Nandakumar, Midanapore (Distt.) (West **Bengal**)	Established to manifest natural instincts and self confidence and imbibe patriotic sense, self respect social, moral economic and cultural values in children to develop them in proper manhood in true sense of the terms.	2,70,225/-	For running 100 ECE centres.	
12.	India Literacy Board, Literacy House, Lucknow (Uttar Pradesh)	For all round development of children; physical, mental, social-psychological field, to motivate first generation learning families of weaker society.	1,20,000/-	For running 40 ECE centres.	
	TECHNICAL EDUCATION :				
1.	**The Principal,** **Technical Institute of Textiles,** **Bhiwani (Haryana)**	Conduct of approved post-graduate courses and Research Work in Engineering & Technology	3,48,381/-	Conduct of approved P. G. Courses and Research Work in Engineering and Technology.	
2.	**The Principal,** **Thapar Institute of Engineering & Technology,** **Patiala (Punjab)**	Do.	1,70,000/-	Do.	
3.	**The Director,** **Harcourt , Butler Technological Institute,** **Kanpur (U.P.)**	Do.	5,80,000/-	Do.	
	The Principal, **Victoria Jubilee Technological Institute Bombay,** **(Maharashtra).**	Do.	12,90,298/-	Do.	
	The Principal, **G. S. Technological Institute,** **Indore (M.P.)**	Do.	9,47,664/-	Do.	

1	2	3	4	5	6
6.	The Principal, L. M. College of Pharmacy, Ahmedabad (Gujarat)	Conduct of approved post-graduate courses and Reserch Work in Engineering & Technology	3,80,000/-	Conduct of approved PG Courses and Reserch Work in Engineering and Thchnology	
7.	The Principal, Walchand College of Engineering, Sangali (Maharashtra)	Do.	5,50,000/-	Do.	
8.	The Principal P. S.G. College of Technology, Coimbatore (Tamil Nadu)	Do.	14,10,000/-	Do.	
9.	The Principal, Coimbatore Institute of Technology, Coimbatore (Tamil Nadu)	Do.	6,80,000/-	Do.	
10.	The Principal, Thiagarajar College of Engineering, Madurai (Tamil Nadu)	Do.	1,50,000/-	Do.	
11.	The Principal, National Institute of Engineering, Mysore (Karnataka)	Do.	2,66,448/-	Do.	
12.	The Principal, Birla Institute of Technology, Ranchi (Bihar)	Do.	13,47,973/-	Do.	
13.	The Principal, School of Planning, Ahmedabad (Gujarat)	Do.	8,97,926/-	Do.	
14.	The Principal, College of Pharmacy, Pushap Vihar, New Delhi	Do.	1,30,000/-	Do.	
15.	The Principal, J. C. R. College of Engineering, Mysore	Do.	4,15,000/-	Do.	
16.	The Principal, Guru Nanak College of Engineering Ludhiana (Punjab)	Do.	1,00,000/-	Do.	
17.	B. M. S. College of Engineering, Bangalore	Do.	1,65,000/-	Do.	
18.	The Principal, Bombay College of Pharmacy, Kalina, Bombay	Do.	1,00,000/-	Do.	
19.	The Pricipal, T. K. M. College of Engineering, Quilon	Do.	1,00,000/-	Do.	
20.	Guru Nanak Polytechnic, Ludhiana	Development of rural technology.	1,00,000/-	Development of rural technology.	
21.	Institute of Engineering & Rural Technology, Allahabad	(i) Development of rural technology.	1,00,000/-	(i) Developement of rural technology.	
		(ii) Community Development Work.	1,25,000/-	(ii) Community Development Work.	
		(iii) Advanced Technician Course	2,00,000/-	(iii) Advanced Technician Course.	
		(iv) Quality Improvement Programmes	4,50,000/-	(iv) Quality Improvement Programme.	
22.	S. B. M. Polytechnic, Bombay	Advanced Technician Course	3,19,000/-	Advanced Technician Course.	
23.	C. M. Kothari Technological Institute, Madras	Do.	2,00,000/-	Do.	
24.	Y. M. C. A. Institute of Engineering, Faridabad.	Do.	2,50,000/-	Do.	
25.	Thaper Polytechnic, Patiala	Community Development Work.	1,75,000/-	Community Development Work.	

1	2	3	4	5	6
26.	Dr. Panjabrao Deshmukh Polytechnic, Amaravati	Community Develoment Work.	1,00,000/-	Community Development Work	
27.	Ramgarhia Polytechnic, Phagwara	Do.	1,25,000/-	Do.	
28.	Feroz Gandhi Polytechnic, Raibareli	Do.	1,25,000/-	Do.	
29.	(*) Polytechnic, Khurai	(i) Community Development Work. (ii) Development of Rural Technology.	1,21,000/-	(i) Community Development Work. (ii) Development of Rural Technology.	
30.	Annamalai Polytechnic, Chettained.	Community Development Work	1,00,000/-	Community Development Work.	
31.	Bhaktavatsalam Polytechnic, Kancheepuram	Do.	1,00,000/-	Community Development Work.	
32.	Pt. J .N Polytechnic, Sanawad (M.P.)	Do.	1,00,000/-	Do.	
33.	XLRI, Jamshedpur.	Consolidation and Development of management education at non-university centre.	5,14,492/-	(i) Salaries. (ii) Libraries.	
34.	Indian Institute of Social Welfare & Business Management, Calcutta	Consolidation and Development of management education at non-university centre.	4,99,200/-	Do.	
	PROMOTION OF LANGUAGES :				
1.	Raja Veda Kavya Pathshala, D-76/111, Cross Street, Srinagar Colony, Kumbokanam-612001 (Tamil Nadu)	Teaching	1,51,585/-	Salary and scholarships. Repair of ibrary room and purchase of furniture.	
2.	Sankara Academy of Sanskrit Culture and Classical Arts, 17-A/1, W. E. A. Karol Bagh New Delhi-110005	Do.	2,69,610/-	Salary and scholarships.	
3.	J. N. B. Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, P. O. Lagma, Distt. Darbhanga (Bihar)	Do.	2,91,338/-	Salary, scholarships and contingencies.	
4.	Lakshmi Devi Shroff Adarsh Sanskrit M. V. Kali Rekha, V. & P.O. Deogarh (Bihar)	Do.	2,08,200/-	Do.	
5.	Haryana Sanskrit Vidyapeetha , Bhagola, (Haryana)	Do.	2,34,625/-	Do.	
6.	Dewan Krishan Kishore S. D. Sanskrit College, Ambala Cantt. (Haryana)	Do.	2,15,995/-	Do.	
7.	Mumbadevi Sanskrit Mahavidyalaya, Bombay (Maharashtra)	Do.	2,11,893/-	Do.	
8.	Vaidika Samsodhana Mandal,. Puna, (Maharashtra)	Research	2,41,000/-	Do.	
9.	Calicut Adarsh Sanskrit Vidyapeetha, P. O. Balussery, Distt : Calicut, (Kerala)	Teaching	2,88,082/-	Salary and scholarships.	
10.	Madras Sanskrit College, Madras (Tamil Nadu)	Do.	2,52,193/-	Salary, scholarships and contingencies.	
11.	Sri Chandrasekharendra Saraswati Nyaya Sastra, M. V. Kancheepuram (Tamil Nadu)	Do.	1,52,235/-	Saiary, scholarships and miscellaneous.	
12.	Kuppuswamy Sastri Research Institute, Mylapore, Madras (Tamil Nadu)	Research	1,20,000/-	Salary, scholarships and contingencies.	

(*) The institution has been, subsequently, taken over by the State Government.

1	2	3	4	5	6
13.	Shree Bhagwan Dass Sanskrit Mahavidyalaya, Haridwar (Uttar Pradesh)	Teaching	2,50,000/-	Salary, scholarships and miscellaneous.	
14.	Shri Ekrasanand Sanskrit Mahavidyalaya, Mainpuri (Uttar Pradesh)	Do.	2,58,242/-	Do.	
15.	Ranga Lakshmi Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, Vrindaban, Mathura (Uttar Pradesh)	Do.	2,77,939/-	Do.	
16.	The Chief Executive, Bharatiya Chaturdam Ved Bhawan Nayas Swadesh House, Civil Lines, Kanpur.	Do.	1,19,700/-	Do.	
17.	The Secretary, Bodh Darshan Sanskrit Vidyalaya, Keylong, P. O. Keylong, Distt. Lahaul, Spiti (H.P.)	Do.	1,21,548/-	Salary/Scholarships and Miscellaneous	
18.	Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha, Hyderabad Branch, Hyderabad.	Promotion of Hindi	3,32,550/-	Running of Hindi Teaching Centres and typing classes.	Recognised as an organisation of National Importance.
19.	D. B. H. P. Sabha, Tamilnadu Branch, Madras	Do.	2,96,685/-	Do.	Do.
20.	D. B. H. P. Sabha (Kerala Branch) Ernakulam	Do.	99,135/-	Do	Do.
21.	D. B. H. P. Sabha, Karnataka Branch, Bangalore.	Do.	1,61,790/-	Do.	Do.
22.	D. B. H. P. Sabha, Madras City, Madras	Do.	11,21,094/-	Maintenance grant, running of Hindi classes at Higher Education level etc.	Do.
23.	Nagari Hindi Pracharni Sabha, Varanasi	Do.	2,00,000/-	Publication works and Building grants.	All India level organisation.
24.	Bhuvan Vain Trust, Lucknow	Do.	1,50,000/-	Publication works.	
25.	Assam Rashtrabhasha Prachar Board. Gauhati	Do.	2,00,000/-	Running of Hindi classes, typewriting classes.	
26.	Dairatul Maarifil Osmania (Osmania University), Hyderabad	Promotion & Development of Urdu.	1,57,500/-	50% of the deficit on maintenance of the organisaton.	
27.	Kerala Hindi Prachar Sabha, Trivandrum	Poromotion of Hindi.	1,00,950/-	Running of Hindi Teaching Classes,	
28.	Akhil Bharatiya Hindi Sanstha Sangh, New Delhi	Implementation of Hindi propagation programmes. To act as a confederation of 17 voluntary Hindi Organisations.	2,05,000/-	Maintenance of the organisation and implementation of Hindi propagation Programmes.	A confederation of 17 voluntary Hindi organisations of all India importance
29.	Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, New Delhi	Implementation of Hindi propagation programmes.	1,70,000/-	Implementation of Hindi propagation programmes. Publication of books.	
30.	Hindi Vidyapeeth, Deoghar (Bihar)	Do.	1,27,200/-	Implementation of Hindi propagation programmes and preparation & publication of Hindi-Santhali and Santhali-Hindi Dictionaries.	
31.	Karnataka Mahila Hindi Seva Samiti, Bangalore (Karnataka)	Do.	1,23,750/-	Implementation of Hindi Propagation programmes and publication of Hindi magazine.	
32.	Karnatak Hindi Prachar Samti, Bangalore (Karnataka).	Do.	1,10,775/-	Do.	
33.	Mysore Hindi Prachar Parishad, Bangalore (Karnataka)	Implementation of Hindi propagation programmes	1,21,800	Implementation of Hindi propagation programmes.	
34.	Bombay Hindi Vidyapeeth, Bombay.	Do.	1,07,775 15,000	Implementaton of Hindi propagation programmes in Maharashtra and Goa.	
			1,22,775		

1	2	3	4	5	6
ADULT EDUCATION					
1.	Indian Institute of Management, Ahmedabad, Gujarat	Conduct Research in the field of Social Science	1,60,000	For conducting survey appraisal and in depth studies for evaluation of Adult Education Programme.	
2.	Tata Institute of Social Sciences, Bombay, Maharashtra.	Do.	1,03,000	Do.	
3.	Sardar Patel Institute of Economic and Social Research Ahmedabad, Gujarat.	Do.	1,00,000	Do.	
4.	State Resource Centre (Bihar) "Deepayatan".	To provide tech. support to adult education programme at all levels.	4,12,000	For providing teaching learning material to adult educaton programme.	
5.	Gujarat Vidyapeeth, Ahmedabad.	Do.	5,55,000	Do.	
6.	State Resource Centre, Mysore	Do.	4,00,000	Do.	
7.	State Resource Centre, Kerala (KANFED)	Do.	6,39,000	Do.	
8.	Utkal Navjeevan Mandal, Orissa (Angul)	Do.	3,12,000	Do.	
9.	Indian Institute of Education, Pune	Do.	6,39,000	Do.	
10.	Rajasthan Adult Education Council, (Rajasthan)	Do.	5,00,000	Do.	
11.	Tamil Nadu Board of Continuing Education, Madras.	Do.	6,10,000	Do.	
12.	Literacy House, Lucknow.	Do.	7,50,000	Do.	
13.	Bengal Social Service League, Calcutta.	Do.	5,00,000	Do.	
14.	Jammia Milia Islamia, New Delhi	Do.	5,00,000	Do.	
15.	Grameen Mahila Sangh, Indore(M. P)	Do.	1,00,000	Do.	
16.	Andhra Mahila Sabha Literacy House, Andhra Mahila Sabha College, Campus, University Road, Hyderabad.	It runs Nursing Homes, Hospitals, Schools and Colleges and a number of training programmes for women	6,96.610	To conduct Functional and Post-literacy programmes for adult illiterates.	The grants released under the scheme is mostly of recurring nature and the non-recurring grant constitutes a very small portion which is released only in the first year of the project period.
17.	Comprehensive Rural Operations Service Society (CROSS), Plot No. 47(1-69), Snehapuri, Nacharam, Hyderabad-501507	Its main activties are development of irrigation, water resources, dairy development, rural medical services, agricultural extension services etc.	4,08,100	Do.	Do

1	2	3	4	5	6
18.	Rural Education Society, Kothapet Punganur-517247, Distt. Chittoor	Its activities include economic development programmes like calf rearing brick making, mat weaving for the benefit of rural poor apart from other educational and cultural programmes.	1,35,000	To conduct Functional and Post-literacy programmes for adult illiterates.	The grants released under the scheme is mostly of recurring nautre and the non-recurring grant constitutes a very small portion which is released only in the first year of the project period.
19.	Morigaon Mahila Mandal, Vill-Mori, Muslimgaon P. O. Morigaon Distt : Nowgong (Assam)	It runs adult education centres for women and provides training facilities in loom, poultry and tailoring for poor women.	2,00,200	Do.	Do.
20.	K. R. Educational Association, Battiah, West Champaran Distt. (Bihar)	Its main activities are rural development and education which includes running a model farm, dairy, piggery, high school and also adult education centre.	3,96,900	Do.	Do.
21.	Acil Nawasarjan Rural Development Foundation, Morbi Malia Project, Sarwad Bungalow, Mahendra Road, Rajkot (Gujarat)	Its main acivitires in the field of rural development, animal husbandry, small and cottage industries, health and medicines and education.	1,20,000	Do.	Do.
22.	Adia Kelavani Uttejak Mandal, Adia, Ta. Harij, Dt. Mehsana (Gujarat)	It runs a school and also conducts night classes, Hindi classes etc.	1,66,000	Do.	Do.
23.	Adivasi Seva Samiti, At. & P. O. Sukshar, Santrampur Taluk Dt. Panchmahal (Gujarat)	It runs a high school, Ashram school, boys and girls hostel, children development and social welfare centres.	1, 96,329	Do.	Do.
24.	Kalyani Trust, Modasa, Distt : Sabarkantha, Gujarat	Its activities mainly pertain to Khadi Gramodyog. Cottage industries and adult education.	2,48,680	Do.	Do.
25.	Kapadwanj Taluka Yuvak Mandal Association, Chhipdi, Ta. Kapadwanj, Dt. Kheda (Gujarat).	It provides library facilities, conducts literacy programmes and also organise cultural and sports activities.	1,35,000	Do.	Do.
26.	Sanskar Bharati, Amrapur Via-Talod, Dt. Sabarkantha (Gujarat)	It runs schools, hostels, Balmandirs and Health Centres.	1,20,000	Do.	Do.
27.	Shri Jamnagar Zilla Samaj Kalyan Sangh, Pandit Nehru Marg, Jamnagar (Gujarat)	It runs several projects whose activities include organising Mahila Mandals, Kishori Mandals, Bal Mandirs, Saving and tailoring classes and also providing nutritions diet for children.	1,64,400	Do.	Do.
28.	Shri Siddharth Shramjivi Vikas Trust, Motisara, Aghara Darwaja, Patan, Dt. Mehsana (Gujarat)	It undertakes various programmes under TRY SEM as also Balwadies and adult education programmes.	1,21,000	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6
29.	Vadodara Taluka Yuvak Mandal Association, Varnama, Ta. Vadodara, Dt. Vadodara, Gujarat.	It runs youth centres, night classes, tailoring classes for women, organizes literacy cultural sports and free plantation programmes.	1,89,560	To conduct Functional and post literacy programmes for adult illiterates.	The grants released under the scheme is mosty of recurring nature and the non-recurring grant constitutes a very small portion which is released only in the first year of the project period.
30.	Vadodara Zilla Samaj Kalyan Mandal, Sardar Bhavan, Vadodara, (Gujarat).	Main activity includes running Balwadies, Mahila Mandals, Craft classes and creches.	2,10,156	Do.	Do.
31.	Vadodara Zilla Pachhat Varg Seva Mandal, Sardar Bhawan, Vadodara (Gujarat)	It runs Ashram Schools, Primary & Higher Secondary Schools. Balwadies. Hostel for back ward classes.	1,87,720	Do.	Do.
32.	Bhil Seva Mandal, Dahod, Dt. Panchamahal, Gujarat.	It runs Ashram Schools, higher secondary schools, balwadies etc. apart from adult education.	1,34,900	Do.	Do.
33.	Kasturba Gandhi National Memorial Trust, Radaur, Distt. Kurukshetra (Haryana)	A well known organisation renowned for its women welfare activities all over India including running of adult education centres.	4,00,000	Do.	Do.
34.	Janta Kalyan Samiti, Opposite Bus Stand Rewari, Distt : Mahindergarh.	It runs adult education centres, balwadies, provides education to destitutes etc.	5,05,260	Do.	Do.
35.	Haryana Rajkiya Adhyapak Bhawan Trust, Pawan Hospital, Pipli-132131	It is working for the welfare of the teachers and utilises their experience in running adult education centres.	1,20, 000	Do.	Do.
36.	Bharatiya Adimjati Sevak Sangh for (Karnataka Branch, Bangalore) Dr. Ambedkar Road, New Delhi	It runs creches, Balwadies. training camp for rural women and also adult education programme.	1,67,000	Do.	Do.
37.	Asha Kala Kendra, 330-Dr. Khosla Marg, Mahow Cantt. Distt Indore 453441 (Madhya Pradesh)	It imparts diploma and condensed courses for women tailoring and craft classes, balwadies etc.	2,07,500	Do.	Do.
38.	Vidya Prasarak Mandal, C/o Amolak Chand Mahavidyalya Yeotmal, (Maharashtra).	To implement employment generating schemes family planning, take part in gram panchayat activities, remove social evils of untouchability and dowry system, impart literacy and develop cottage industries.	1,00,805	Do.	Do.
39.	Jawahar Smriti Shikshan Samiti, Marki Sholapur (Maharashtra)	It mangages Adivasi Ashrams.	1,01,500	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6
40.	Kasturba Gardhi National Memorial Trust, Sarwad, Pune (Maharashtra	It works in the educationally backward area of Pune and also runs a home for the homeless children and destitutes.	1,80,000	To conduct Functional and Post-literacy programmes for adult illiterates.	The grants released under the scheme is mostly of recurring nature and the non recurring grant constitutes a very small portion which is released only in the first year of the project period.
41.	Manavhit Shikshan Prasarak Mandal Samadhi Ward No. 2, Chandrapur (Maharashtra)	It runs Shishu Vihar High School, Vachnalaya, Balwadies Adult Education & Nutrition Centres for Adiwasies.	1,01,500	Do.	Do.
42.	Sant Kabir Shikshan Mandal, Ghati, Aurangabad (Maharashtra)	The Mandal is run by Scheduled Caste members to ameliorate the lot of Scheduled Caste and Scheduled Tribe Communities.	1,49,500	Do	Do.
43.	Samaj Kalyan Mandal, Lalganj, Distt. Nagpur, (Maharashtra)	It runs a Primary shcool, Sanskritik Kala Vikas Kendra, Study Homes, Juvenile guidance, Centres and Balwadies.	1,20,000	Do.	Do.
44.	Sati Mata Shikshan Sanstha, Nagpur-25, (Maharashtra)	It is running a creche, Balwadies, Balmandir, High School and Junior College.	1,20,000	Do.	Do.
45.	Viswa Seva Institution, P O & Distt. Sambalpur, Pin-768001 (Orissa)	It runs schools and colleges in addition to adult education programmes.	1,59,500	Do.	Do.
46.	Banabasi Seva Samiti, P .O & Block Baliguda:726103 Distt. Phulbani (Orissa)	It runs Adult Education Centres for tribals and poor.	1,00,805	Do.	Do
47.	Khadi Gramodyog Vikas Mandal, Fatehgarh, P. O. Serwar, Distt. Ajmer (Rajasthan)	It is working for the development of Khadi and Gramodyog Activities.	1,35,444	Do.	Do.
48.	Rajasthan Vidyapeeth, Udaipur-313001 (Rajasthan)	Its activities are formal education. teachers training, vocational training research training etc.	1,43,000	Do.	Do.
49.	Rajasthan Adult Education Association, C-85, Ramdas Marg, Tilak Nagar, Jaipur -302004 (Rajasthan).	Its main activities include training of adult education workers, holding workshops, seminars, publication of teaching and learning material etc. It is also a State Resource Centre.	1,00,000	Do.	Do.
50.	Jila Proudha Shiksha Samiti, 597-A, Talwandi, Kota-324005, (Rajasthan).	Its activities include conducting condensed courses for women, adult and non-formal education, Shramik Vidyapeeths, Balwadies and programmes under TRYSEM.	1,19,971	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6
51.	Centre for Human Development & Social Changes, 39/15-Appa Swami Koil Street, Madras -600019 (Tamil Nadu)	It provides consultancy and Advisory services, training for development work and community organisation, Audio visual aids and brings out publication etc.	1,35,000	To conduct Funotional and Post-literacy programmes for adult illiterates.	The grants released under the scheme is mostly of recurring nature and the non-recurring grant constitutes a very small portion which is released only in the first year of the project period.
52.	Kandaswami Kandar's Trust Board Velur, Salem Distt. -638182 (Tamil Nadu)	It runs a college, several schools, free hostels, literacy-cum-reading rooms, nursery schools etc.	2,43,500	Do.	Do.
53.	Social Welfare Society, 2-A, Main Road, Tittagudi Taluka South Arcot Distt. (Tamil Nadu)	It conducts a tailoring course, handicrafts training, creches, dairy schemes and also family welfare orientation camps.	2,41,000	Do.	Do.
54.	Arnad Vellalar Sangam, 1&2 Sannathi Street, Tirunanaikail Tiruchy-620005 (Tamila Nadu)	It works for the uplift of poor and downtrodden people of rural areas. It runs Adult Education Centres.	1,16,326	Do.	Do.
55.	Programme for Human Development, Perumanikuzhi, Karinkal-629157 Kanyakumari Distt. (Tamil Nadu)	Its main objective is to engage in social service aimed at improving the living conditions of the poor and downtrodden.	1,20,000	Do.	Do.
56.	Tiruchirapalli Multipurpose Social Welfare Society, Bishops' House, P.B. No. 14 Tiruchirapalli-620001	Its activities include mother and child health care, orphanages. creches, school feeding various food for work programmes etc.	1,32,000	Do.	Do.
57.	Punjab Association, 170-172, Peters Road, Rayapattah, Madras-600014 (Tamil Nadu)	It runs schools, colleges, dispensaries, dairy farm, production centres, women's hostel etc.	6,69,7 2	Do.	Do.
58.	Murthuzaviya Educational & Cultural Foundation of South India 186 Big Street, Triplicane, Madras-600005 (Tamil Nadu)	Its activities include formal, non-formal and adult education, providing child and extension services and also running a Mid-day Meal Centre.	2,87,010	Do.	Do.
59.	Tamil Nadu Gandhi Samarak Nidhi T. Kallupatti, Madurai-625020 (Tamil Nadu)	It runs gramseva centres in Rural areas for development work, publishes books on various topics and its other activities include education, adivasi and harijan seva etc.	1,20,000	Do.	Do.
60.	Y. M. C. A., Mullangina-629157, Kanyakumari Distt. (Tamil Nadu)	Its activities include poultry farming, distribution of seeds to farmers. It also runs nursery schools and tailoring and a training-cum-production centre.	1,20,000	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6
61.	Harijan Sewak Sangh, Vaikkal Road, Gopichettipalyam, Periyar Distt -638452 (Tamil Nadu)	It works for the eradication of untouchability and making wells, temples, shops etc. accessible to Harijans and also assists them in agriculture, housing, creches, employment etc.	1,20,000	To conduct Functional and Post-literacy programmes for adult illiterates.	The grants released under the scheme is mostly of recurring nature and the non-recurring grant constitute a very small portion which is released only in the first year of the project period.
62.	Women's Voluntary Services of Tamil Nadu, Madras-600013	It provides ambulance services, runs a community centre, creches, hospital welfare services and also provides aids and appliances to disabled persons.	7,57,740	Do.	Do.
63.	Social Service Society for the Congregation of the Sisters of Chavnad, Holy Cross Convent, Cantonment, Tiruchirapalli-620001 (Tamil Nadu)	Its action include mother, child health care, Supplementary fooding in creches, orphanages, construction of low cost housing etc.	1,38,000	Do.	Do.
64.	U. P. Rana Beni Madhav Jan Kalyan Samiti, Gramodyog Bhavan Gulab Road, Rai Bareli (Uttar Pradesh)	It conducts training programmes under TRYSEM scheme for Rural Youths, Women and illiterate persons.	1,23,000	Do.	Do.
65.	Sarvodaya Seva Sansthan, Malik Main Road, Satya Nagar, Rai Bareli (Uttar Pradesh)	The main activities of the Sansthan are to provide training, education and employment with a view to expand Khadi Village Industries programme.	2,01,235	Do.	Do.
66.	Khadi Gramodyog Sangh 5-B, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad (Uttar Pradesh)	The main work of the Sangh is to provide facilities for training to the villagers in different crafts education etc.	1,23,000	Do.	Do.
67.	Indian Womens' Industrial Training Institute & Rehabilitation 460, Deopur, P.O. Rajajipuram Lucknow (Uttar Pradesh)	It works for the social welfare of women by settingup Women's Training Centre etc.	1,28,250	Do.	Do.
68.	Literacy House, P. O. Alam Bagh. Sarojini Nagar Block, Lucknow (Uttar Pradesh)	To further the cause of adult literacy and non-formal education or any other form thereof and to undertake projects and programmes connected there with.	1,28,700	Do.	Do,
69.	Bhartiya Ajiwan Shiksha Parishad, 647, Katra, Allahabad-211002 (U. P.)	To provide a National Forum for the exchange of ideas related to Research, Development and extension work etc.	1,23,000	Do.	Do.
70.	Sarvadaliya Manav Vikas Kendra, Bahjoi, Dt. Muradabad (Uttar Pradesh)	It runs a production centre, Sishu Niketan Nursery School Dairy, News Agency etc.	1,62,530	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6
71.	Ramakrishnai Vivekananda Missioncs7, Riverside Road, Barrackpore Distt. 24-Paraganas (West Bengal)	It runs a home for destitute children, schools, vocational training centre for boys, library, dispensory etc.	2,61,000	To conduct Functional and Post-literacy programmes for adult illiterates.	The grants released under the scheme is mostly of recurring nature and the non-recurring grants constitutes a very small portion which is released only in the first year of the project period
72.	Calcutta Urban Service Consortium, 16, Sudder Street, Calcutta (West Bengal)	The main activities of the organisation are to promote and support primary, Secondary, technical and non-formal education.	1,35,920	Do.	Do.
73.	Institute for motivating self-employment, 53, Ripon Street, Calcutta (West Bengal)	It gives training in poultry, piggery undertakes pilot projects to provide employment, joint farming and agro-services as well as health programmes etc.	1,41,650	Do.	Do.
74.	Jhargram Mahakuma Janasiksha Prasar Samiti, Raghunathpore, Jhargram, Distt. Midnapur (West Bengal)	The main activities of the organisation are to organise lectures, debates, seminars on illiteracy. It also runs a High School and publishes a magazine.	1,00,000	Do.	Do.
75.	Institute of Child Health, 11, Dr. Biresh Guha Street, Calcutta (West Bengal)	It runs an integrated child-case research programme in which adult and non-formal education are giv en importance.	2,98,100	Do.	Do.
76.	Bharatiya Adimjati Sevak Sangh, Thakkar Bapa Smarak Sadan Dr. Ambedkar Road New Delhi-55.	It runs several schools, Ashrams, Balwadies, Libraries, Health Campus Training Centre for tribal women etc	3,66,315	Do.	Do.
77.	Dr. A.V. Baliga Memorial Trust Link House, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002	It runs a Medical clinic, production unit for ready made garments etc. and also awards scholarships	2,34,462	Do.	Do.
78.	Indian University Association for Continuing Education, 17-B, I. P. Estate, New Delhi	It serves as a clearing house for exchange of ideas by holding workshops, seminars etc. organises training programmes. publishes literature on continuing education etc.	1,0 9,207	Do.	Do.
79.	Indian Adult Education Association Shaiq Memorial 17-B, I. P. Estate, New Delhi	It publishes various tournals on adult education, acts as a clearing house for dissemination of information, organises seminars, workshops, conferences etc. and also gives the 'Nehru Literacy Award' for outstanding contribution for promotion of adult education	1,57,499	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6
HIGHER EDUCATION :					
1.	Sri Aurobindo International Institute of Educational Research. Auroville Kottakuppam-605014 (Tamil Nadu)	The Institute is engaged in innovation and research in education through a chain of four-regular day schools	9,69,000	Maintenance of Teams of educational researchers, nutrition programme for children freeships and administrative expenditure	
2.	Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry -605002	The institution is an integral part of Sri Aurobindo Ashram. It has provision for education from the Kindergarten to higher and advanced levels of study. It has the facilities of humanities, languages, science, engineering and physical education.	10,50,000	For maintenance expenditure including payment of salaries of staff	
INDIAN NATIONAL COMMISSION FOR COOPERATION WITH UNESCO					
1.	Auroville Trust , Auroville, Kottakuppam (Tamil Nadu)	To participate actively in the grant & development of Auroville.	2,00,000	Holding the Seminar on "Youth and the Ideal of Human Unity"., in Februrary. 1985 in the international Youth Year 1985.	

NUEPA DC
D13537

MGIPF— 759, Dept. of Edu./85 3,000—17-4-86